चीनी नव-जनवादी क्रान्ति का इतिहास

चीनी नव-जनवादी क्रान्ति का इतिहास

(1919–1956)

हो कान च

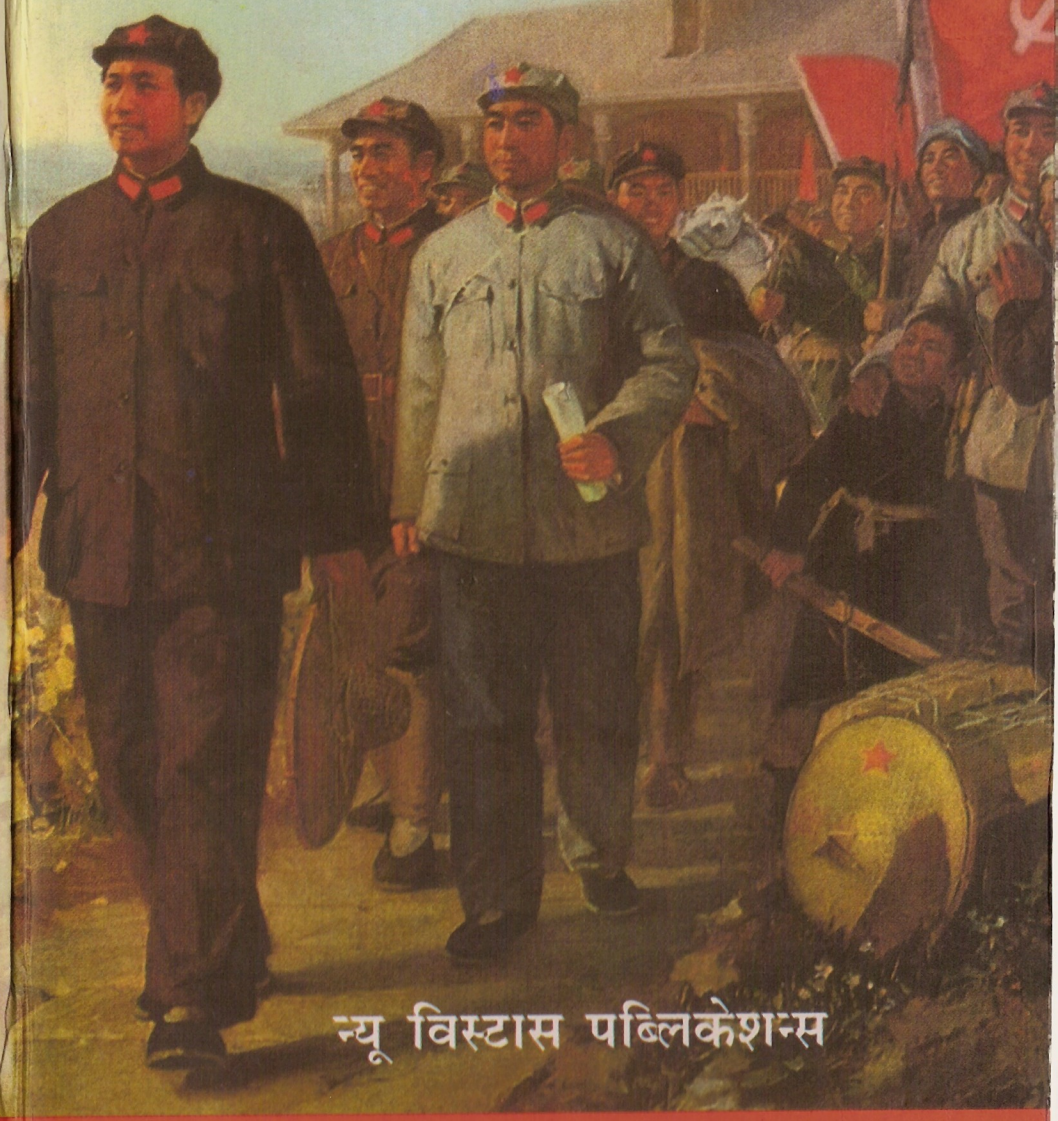

न्यू विस्टास पब्लिकेशन्स

चीनी नव-जनवादी क्रान्ति का इतिहास

(1919 - 1956)

THE HISTORY OF MODERN CHINESE REVOLUTION

का हिन्दी अनुवाद

लेखक : हो कान च

न्यू विस्टास पब्लिकेशन्स, दिल्ली

चीनी नव-जनवादी क्रान्ति का इतिहास

{ The History of Modern Chinese Revolution } का हिन्दी अनुवाद

हिन्दी अनुवाद : सोमप्रकाश चसवाल

प्रथम हिन्दी संस्करण : 1 अक्तूबर, 1999
(चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की स्वर्ण-जयन्ती पर)
पुनर्मुद्रण : 27 सितम्बर, 2004
(शहीद भगतसिंह के जन्मदिन पर)

प्रकाशक :
न्यू विस्टास पब्लिकेशन्स
U-57, शकरपुर, गुरुद्वारा लेन, दिल्ली-110092
e-mail : newvistaspublications@rediffmail.com
new_vistas@rediffmail.com

मूल्य : 75 रुपये (पिचहतर रुपये केवल)

इस सम्पूर्ण पुस्तक या इस पुस्तक के किसी भी अंश का इस्तेमाल जनहित में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा पार्टी द्वारा किया जा सकता है।

दो शब्द

यह पुस्तक विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा 1959 में प्रकाशित-'हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइनीज रेवोल्यूशन'—पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है । पाठकों की सुविधा के लिए कुछ शब्दों व घटनाओं आदि की व्याख्या के लिए कुछ नोट अलग से जोड़ दिये गये हैं । सामग्री को रोचक व सरलता से ग्राह्य बनाने के लिए कुछ तस्वीरें, तालिकाएं, मानचित्र तथा विवरणिका भी अलग से जोड़े गए हैं । अलग से जोड़े गए लगभग सभी नोटों व विवरणिका के स्त्रोत, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा हिन्दी में प्रकाशित ''माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाओं'' के ग्रन्थ-1,2,3 तथा 4 है । हमें आशा है कि पाठकों को हमारा यह प्रयास पसन्द आएगा । अन्त में पाठकों से अनुरोध है कि वे पुस्तक के बारे में अपने सुझाव, विचार व आलोचनाएं भेजकर इसे और अधिक जनोपयोगी बनाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।

1 अक्तूबर, 1999 न्यू विस्टास पब्लिकेशन्स, दिल्ली

पुस्तक के बारे में

यह पुस्तक 4 मई, 1919 के आन्दोलन से लेकर 1956 के पूर्वार्द्ध के समाजवादी रूपान्तरण तक के कालखण्ड के दौरान चीनी जनता द्वारा की गई नव जनवादी क्रान्ति का ब्यौरेवार विवरण है । पुस्तक हमें बताती है कि किस प्रकार चीनी जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के झण्डे तले गोलबन्द होकर साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा अफसरशाह-पूँजीवाद के खिलाफ एक जुझारू संघर्ष चलाया । अन्त में जनता ने तीन क्रान्तिकारी गृहयुद्धों तथा जापानी-आक्रमण विरोधी प्रतिरोध युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते हुए साम्राज्यवादियों तथा क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी शासन का तख्ता पलट दिया, तथा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की । इसमें मुक्ति के बाद के वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा कृषि, हस्तशिल्पों तथा निजी उद्योग व वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण का भी ब्यौरा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके नेता कामरेड माओ त्से-तुङ द्वारा मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों की रोशनी में चीनी क्रान्ति की समस्याओं के समाधान के विस्तृत विवरण ने पुस्तक की विषय वस्तु को समृद्ध बना दिया है ।

प्रकाशक

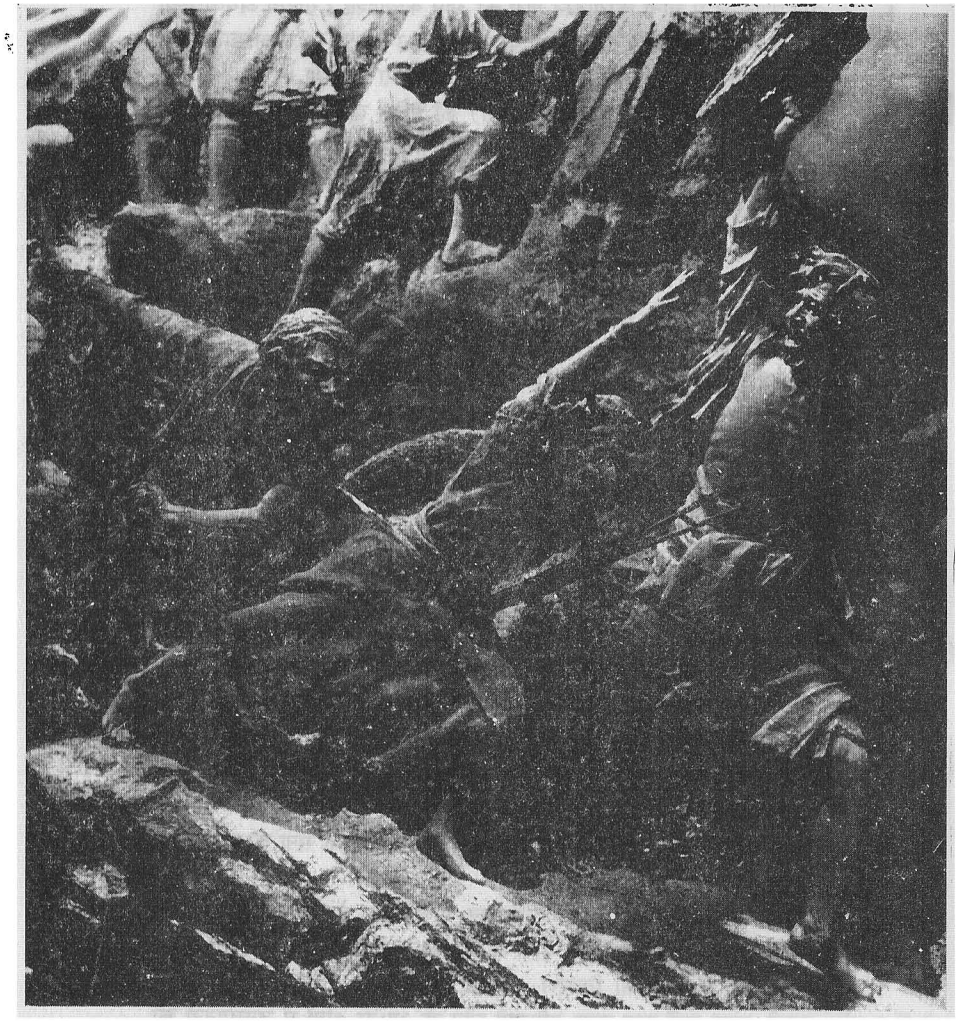

विषय सूची

पहला अध्याय

चीन में 4 मई आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन का उत्थान (मई 1919-जून 1921) 1

1. चीन में विदेशी-पूँजीवाद का प्रवेश । चीन का सामन्ती समाज से अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामन्ती समाज में प्रवेश। पुरानी जनवादी क्रान्ति एवम् उसकी असफलता । 1
2. चीनी औद्योगिक पूँजीवाद का आविर्भाव तथा प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उसका और आगे विकास । चीनी औद्योगिक सर्वहारा का विकास । चीनी मजदूर वर्ग की विशिष्टताएं । मजदूर-वर्ग का प्रारंभिक आंदोलन । 6
3. अक्तूबर समाजवादी क्रांति का चीनी क्रांति पर प्रभाव । 11
4. 4 मई का देशभक्तिपूर्ण आंदोलन ।3 जून का आंदोलन तथा चीनी श्रमिक वर्ग की संघर्ष में भागेदारी । नई संस्कृति आंदोलन तथा इसका विकास । चीन में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रसार । 12
5. चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का मार्क्सवाद-लेनिनवाद के साथ एकीकरण। साथी माओ त्से-तुङ की शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियां । 18

दूसरा अध्याय

चीन कम्युनिस्ट की स्थापना। चीनी श्रमिक वर्ग आंदोलन का विकास (जुलाई 1921-दिसम्बर 1923) 24

1. 1921 तथा 1923 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति । वाशिंगटन कान्फ्रेंस तथा साम्राज्यवादी देशों में चीन के बंटवारे को लेकर समझौता । 24
2. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के संगठनात्मक सिद्धान्तों का अभिग्रहण । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के कार्यक्रम तथा दिशा-निर्देशों का सूत्रीकरण । 26
3. चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का उदय । हुनान में श्रमिक-वर्ग आंदोलन । पेकिङ-हानखओ रेलवे के श्रमिकों की विशाल राजनीतिक हड़ताल । 32
4. संयुक्त-मोर्चा बनाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मूल कार्यनीतिक सिद्धांत । 39

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आरंभिक वर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा । 42

तीसरा अध्याय

क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे का गठन। क्रांतिकारी आंदोलन का उत्थान (जनवरी 1924-जुलाई 1926) 44

1. सन् 1924 से 1927 तक की अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू स्थिति । 44
2. क्वोमिंताङ की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस । श्रमिक-वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन का पुनरुत्थान । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी राष्ट्रीय कांग्रेस ।

राष्ट्रीय असेम्बली बुलाने के लिए आंदोलन । 47
3. चीनी श्रमिकों की जापान-विरोधी हड़तालें । द्वितीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस । शंघाई में 30 मई का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन । हांगकांग तथा कैंटन में विशाल हड़ताल । क्वाङतुङ क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण । किसान आंदोलन का और ज्यादा विकास । 53
4. नवजनवादी क्रांति के मूल-सिद्धान्तों पर माओ त्से-तुङ के विचार । ताए ची-थाओ के प्रतिक्रियावादी हथकंडे । च्याङ के दक्षिणपंथियों द्वारा क्रान्ति का नेतृत्व हथियाने का षड्यन्त्र । छन तू-श्यू के दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट द्वारा च्याङ को दी गई रियायतें । 61

चौथा अध्याय

उत्तरी अभियान । प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध में गंभीर स्थिति (जुलाई 1926-जुलाई 1927) 71
1. उत्तरी अभियान से पूर्व घरेलू स्थिति । उत्तरी अभियान सेना का याङत्सी घाटी की ओर प्रस्थान । उत्तरी अभियान के दौरान वर्ग संबंधों में नए परिवर्तन । 71
2. राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन तथा हुनान उसके केन्द्र की भूमिका में । किसान समुदाय की क्रान्ति में भूमिका के संबंध में माओ का सिद्धान्त। 77
3. चीनी क्रांति में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप में बढ़ोतरी । ऊहान तथा च्योच्याङ में ब्रिटिशों द्वारा पट्टे पर लिये गए क्षेत्रों की वापसी के लिए मज़दूरों का आंदोलन । शंघाई के श्रमिकों की तीन बगावतें । नानकिङ पर कब्जा तथा ब्रिटिश-अमरीकी बमबारी की घटना। 12 अप्रैल 1927 का च्याङ काई-शेक का प्रति-क्रांतिकारी राज़विप्लव । 85
4. ऊहान की क्रान्तिकारी सरकार के काल में मजदूरों तथा किसानों का बढ़ता जन-आंदोलन । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पाँचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस । 92
5. ऊहान पर प्रतिक्रान्तिकारी हमले के दौरान क्वोमिंताङ का दुलमुलपन । छन तू-श्यू की आत्मसमर्पणवादी कार्यदिशा द्वारा क्रान्ति को पहुँचाई गई क्षति । वाङ चिङ-वेइ गुट की गद्दारी । प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध की असफलता । 96
प्रथम क्रांतिकारी गृह-युद्ध का सारांश । 102

पाँचवां अध्याय

चीनी क्रांति का उतार। क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों की स्थापना व विकास । (अगस्त 1927-सितम्बर 1931) 104
1. सन् 1927 में क्रांति की पराजय के बाद की राजनीतिक परिस्थिति । क्रांति की लहर उतार पर । 104
2. चीनी क्रांति का आगे बढ़ने के दौर से पीछे लौटने के दौर में संक्रमण । कम्युनिस्ट पार्टी में पहली "वामपंथी" कार्यदिशा में संशोधन । 110
3. चिङकाङशान पहाड़ों में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना । 115
4. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस । चीन में लाल सत्ता का अस्तित्व कायम रखने तथा उसके विकास के बारे में कामरेड माओ का

पंद्रहवां अध्याय

आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रान्ति की बुनियादी विजय । (1953 से जून 1956) 371
1. संक्रमणकाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आम कार्यदिशा । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-1957)। काओकाङ तथा राओ शू-श के पार्टी-विरोधी गिरोह का पार्टी द्वारा सफाया । 371
2. चीन की शान्ति नीति । थाएवान (तैवान) की मुक्ति के लिए चीनी जनता का संघर्ष । प्रथम राष्ट्रीय जन-कांग्रेस । चीनी लोक-गणराज्य का संविधान । 378
3. समाजवादी क्रांति में राष्ट्रव्यापी उभार । 384

मानचित्र

लम्बे अभियान का मार्ग - 1 152-153
लम्बे अभियान का मार्ग - 2 168-169
जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के दौरान आधार-क्षेत्र 273
जन-मुक्ति सेना का प्रत्याक्रमण मोर्चा-(1947-1950) 318
ह्वाए-हाए मुहिम 328-329
पेकिङ थ्येनचिन मुहिम 344-345
चीन का राजनीतिक मानचित्र 392-393
चीन का भौगोलिक मानचित्र 404-405

तालिकाएं

1. 1921 से 1949 के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या । 391
2. पाँचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक ढाँचा, (अप्रैल-मई, 1927) । 391
3. छठी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक ढाँचा—जून, 1928 । 391
4. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना का सांगठनिक ढाँचा । 394
5. तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के दौरान जन-मुक्ति सेना के विस्तार का ब्यौरा । 394
6. पाँचवें दशक के उत्तरार्द्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक ढाँचा । 395
7. लाल सेना में भर्ती का विवरण—1934 396
8. उत्तरी, उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी चीन के आधार-क्षेत्रों में जनसंगठनों की सदस्य संख्या । 396

विवरणिका 397-403 एवं 406-407

विफल कर दिया जाना । 304
3. क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों का और ज्यादा औपनिवेशीकरण । क्वोमिंताङ की राजनीतिक धोखाधड़ी का दिवालियापन । 307
4. देशभक्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलन का उत्थान । 312

तेरहवाँ अध्याय

तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध में रणनीतिक आक्रमण । जनक्रान्ति की देशव्यापी विजय । (जुलाई 1947 से अक्तूबर 1949) 317

1. देशव्यापी रणनीतिक आक्रमण की शुरुआत । मुक्त क्षेत्रों में कृषि-सुधार । जनता के जनवादी संयुक्त मोर्चे का गठन । देशव्यापी विजय हेतु जनता का मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी की कार्यवाही- योजना । 317
2. नए मुक्त क्षेत्रों तथा नगरों के विषय में पार्टी की नीतियाँ । पार्टी के अनुशासन को मजबूती प्रदान करना तथा पार्टी कमेटी प्रणाली को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना । 326
3. तीन बड़ी मुहिमें : ल्याओशी-शनयाङ, ह्वाए-हाए तथा पेकिङ-थ्येनचिन । सारे देश में जनता के क्रान्तिकारी युद्ध की मौलिक विजय । पार्टी के नेतृत्कारी केन्द्र का देहाती इलाके से शहर में स्थानांतरण । जन क्रान्ति की विजय के बाद समाजवाद में संक्रमण की बुनियादी नीति । 330
4. पार्टी का मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवादी अधिनायकत्व वाले राज्य का सिद्धान्त । चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन तथा आम कार्यक्रम का निर्धारण । चीनी लोक गणराज्य की स्थापना । चीनी क्रान्ति की विजय का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व । 339

तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध का सारांश । 347

चौदहवां अध्याय

पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति की विजय के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुनः बहाली तथा रूपान्तरण । (अक्तूबर 1949 से 1952) 349

1. चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के बाद समाजवादी शिविर की बढती शक्ति । दो विश्व बाजारों का प्रादुर्भाव । 349
2. मुक्ति के बाद शुरू के वर्षों में आर्थिक परिस्थिति ।राज्य के वित्तीय तथा आर्थिक काम में एकीकृत प्रबन्धन तथा नेतृत्व को लागू करना । राज्य के वित्त तथा अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु मौलिक मोड़ के लिए बुनियादी नीति । 353
3. अमरीका के प्रतिरोध तथा कोरिया की सहायता के लिए महान आन्दोलन । जनता के जनवादी अधिनायकत्व का सुदृढ़ीकरण । 355
4. कृषि-सुधारों का संपूर्ण होना । उद्योग एवम् वाणिज्य का रूपान्तरण । ''सान फान'' तथा ''ऊ फान'' आन्दोलन । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कार्य का समापन । 361
5. ट्रेड यूनियन आन्दोलन का नव विकास । पार्टी का सुदृढ़ीकरण तथा निर्माण। 368

सिद्धान्त । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस । चीन में लाल सत्ता का अस्तित्व कायम रखने तथा उसके विकास के बारे में कामरेड माओ का सिद्धान्त । 119
5. केन्द्रीय तथा दूसरे आधार-क्षेत्रों की स्थापना । कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दूसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा में सुधार । कृषि-क्रान्ति के लिए निर्देशक कार्यदिशा तथा लाल इलाकों में कृषि-नीति । 124
6. लाल सेना के निर्माण तथा उसकी रणनीति व कार्यनीति के बुनियादी सिद्धान्त। लाल इलाके में च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रियावादी गुट द्वारा की गई तीन घेराबंदी मुहिमों का सफाया । चीनी क्रान्ति का नया उभार । 131

छठा अध्याय

जापान-विरोधी जनवादी आन्दोलन का उदय । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ''वामपंथी'' भटकावों का सुधार । पार्टी का बोल्शेवीकरण के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होना । (सितम्बर 1931-दिसम्बर 1935) 140

1. 1929 से 1932 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा एक नए युद्ध की आशंका। 140
2. उत्तर पूर्वी चीन पर जापानी साम्राज्यवादियों का कब्जा । देश भर में राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन का उत्थान । 142
3. तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा का उद्भव ।''वामपंथी'' कार्यदिशा के निर्देशन में क्रान्ति के लिए एक लाभकारी परिस्थिति की क्षति । 146
4. क्रान्ति के अस्थाई उतार के दौरान जापान व च्याङ काई-शेक के विरुद्ध संघर्ष । 149
5. तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा के निर्देशन में पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम की असफलता । चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना का लम्बा रणनीतिक स्थानांतरण । 158
6. चुनई कान्फ्रेंस का संघर्ष । लाल सेना के जापान-विरोधी उत्तर की ओर अभियान में चाङ क्वो-थाओ की गलत कार्यदिशा का विरोध । लम्बे अभियान में लाल सेना की विजय । 164

सातवां अध्याय

जापान-विरोधी जन-आंदोलन का नया उभार । आन्तरिक शांति की स्थापना। (दिसम्बर 1935-जुलाई 1937) 172

1. 1933 से 1935 तक की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति । एक नए साम्राज्यवादी युद्ध की शुरुआत । 172
2. चीनी अफसरशाह-पूँजीवाद की उत्पत्ति । क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों का औपनिवेशीकरण । चीन में अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान के बीच संघर्ष । 174
3. उत्तरी चीन पर जापानी साम्राज्यवादी हमला । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जापान का प्रतिरोध करने तथा राष्ट्र को बचाने की घोषणा । जापान का प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में नया उभार । 178

4. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का दिसंबर सम्मेलन । पार्टी द्वारा जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति को मंजूरी । 182
5. च्याङ काई-शेक को जापान का प्रतिरोध करने के लिए बाध्य करने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति । शीआन घटना—परिस्थिति का मोड़-बिन्दु । जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का प्रारंभिक चरण । उत्तरपूर्वी जापान-विरोधी संश्रयकारी सेना का संघर्ष । 187
द्वितीय क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के काल का सारांश । 194

आठवां अध्याय

जापानी हमले के विरुद्ध प्रतिरोध-युद्ध का आरंभिक काल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चे के अन्दर सर्वहारा वर्ग की स्वतन्त्रता व पहलकदमी तथा जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देना । (जुलाई 1937 से दिसंबर 1940) 197

1. 1937 से 1939 तक की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति । दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत । 197
2. राष्ट्रीय प्रतिरोध-युद्ध छिड़ने पर जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का गठन । प्रतिरोध-युद्ध में सोवियत-संघ द्वारा चीन को समर्थन । 199
3. जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे के अन्दर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतन्त्रता तथा पहलकदमी की नीति । पार्टी द्वारा छापामार लड़ाई आरंभ करना तथा शत्रु की पाँतों के पीछे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना करना । 205
4. राष्ट्रीय आत्मसमर्पणकारियों तथा तुरत-फुरत विजय के पैरोकारों का शोर शराबा । चीनी-जापानी युद्ध के विकास को लेकर कामरेड माओ त्से-तुङ की दूरदर्शिता । 211
5. रणनीतिक ठहराव के आरंभिक काल के दौरान प्रतिरोध-युद्ध । पहली कम्युनिस्ट विरोधी बगावत तथा उसकी पराजय । चीनी क्रान्ति के मूलभूत सिद्धान्त तथा एक नये चीन के निर्माण के लिए कार्यक्रम। 216
6. जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे की कार्यनीतिक कार्यदिशा का दृढ़ता से पालन करना । **दूसरी कम्युनिस्ट-विरोधी बगावत एवं उसकी पराजय ।** 226

नौवां अध्याय

प्रतिरोध-युद्ध की सर्वाधिक नाजुक मंजिल । संघर्ष के दौरान शत्रु की पाँतों के पीछे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण । (जनवरी 1941 से दिसंबर 1942) 234

1. द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभिक काल में फासिस्ट ब्लॉक की अल्पकालिक फौजी श्रेष्ठता । जनता के प्रतिरोध-युद्ध का अत्यधिक नाजुक दौर । 234
2. जापान-विरोधी जनवादी राजनीतिक-सत्ता की बुनियादी नीति । कम्युनिस्ट पार्टी का दोष-निवारण आंदोलन । मुक्त-क्षेत्रों में व्यापक उत्पादन मुहिम । 237
3. जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों में शत्रु से लड़ने के लिए रणनीति । शत्रु की "सफाया करो," "कुतरने की," तथा "गांव तलाशी" की मुहिमों के खिलाफ संघर्ष । 247
4. शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में मिलिशिया (नागरिक सेना) की भूमिका । 252

दसवां अध्याय

मुक्त क्षेत्रों द्वारा आंशिक प्रत्याक्रमण की शुरुआत । प्रतिरोध युद्ध में अन्तिम विजय । (जनवरी 1943 से सितंबर 1945) 257

1. फासीवाद-विरोधी युद्ध का रक्षात्मक कार्यवाही से आक्रमणात्मक कार्यवाही में बदलना । शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में जनता के जापान-विरोधी संघर्ष । मुक्त क्षेत्रों की पुनर्स्थापना तथा विकास । 257
2. चीनी अफसरशाह-पूँजीवाद का भ्रष्ट प्रतिक्रियावादी शासन । तीसरी कम्युनिस्ट-विरोधी बगावत की रोकथाम । देशभर में जनवादी आंदोलन का उत्थान । चीन के घरेलू मामलों में अमरीका का हस्तक्षेप । 261
3. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जापान-विरोधी युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए निर्धारित बुनियादी नीतियां तथा युद्धोपरान्त बुनियादी कार्यभार । 267
4. जनता के मुक्त क्षेत्र प्रत्याक्रमण की मुख्य-शक्ति के रूप में । मैत्री तथा संश्रय की चीनी-सोवियत सहयोग संधि पर हस्ताक्षर । 270
5. सोवियत-संघ द्वारा जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा । चीनी सेना द्वारा मुक्त क्षेत्रों से प्रत्याक्रमण की शुरुआत । जापानी प्रतिरोध-युद्ध का विजयी समापन । 276
जापान के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध का सारांश । 279

ग्यारहवां अध्याय

जापान के आत्मसमर्पण के बाद घरेलू शांति तथा जनवाद के लिए जनता का संघर्ष । (सितंबर 1945 से जून 1946) 281

1. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति । 281
2. एक नए गृहयुद्ध का खतरा । 284
3. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शान्ति, जनवाद, भाईचारे व एकीकरण की नीति। क्वोमिंताङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बातचीत । युद्ध-विराम समझौता तथा राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन । 287
4. अमरीका सरकार के समर्थन से क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों द्वारा कम्युनिस्ट-विरोधी गृहयुद्ध की तैयारियाँ । 291

बारहवां अध्याय

तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध में रणनीतिक रक्षा । जन-मुक्ति सेना द्वारा क्वोमिंताङ के फौजी हमलों का मुँह-तोड़ जवाब । (जुलाई 1946 से जून 1947) 299

1. क्रान्तिकारी युद्ध के राजनीतिक तथा फौजी सिद्धान्त । 299
2. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सक्रिय रक्षा की रणनीति अपनाया जाना । क्वोमिंताङ के चौतरफे तथा केन्द्रित हमलों को जन-मुक्ति सेना द्वारा पूर्णतया

कार्य जारी रखा। जापानी साम्राज्यवादियों के आदेश पर पेकिङ सरकार ने 3 जून को काफी बड़ी तादाद में सशस्त्र पुलिस तथा पुलिस को, विद्यार्थियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, (दूसरे दिन और एक हजार पुलिस को भेजा) तथा 300 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया तथा सभी देशभक्तिपूर्ण आंदोलनों पर पाबन्दी लगा दी। गद्दार सरकार द्वारा अपनाई गई इस हठ्धर्मितापूर्ण नीति का परिणाम यह निकला कि छात्र आंदोलन और अधिक तेजी से पूरे देश में फैल गया।

3 जून के बाद, देशभक्तिपूर्ण आंदोलन का केंद्र पेकिङ से शंघाई स्थानांतरित हो गया तथा विद्यार्थियों की जगह श्रमिक वर्ग, आंदोलन की मुख्य शक्ति के रूप में आगे आया। शंघाई में, जो चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केंद्र है, 5 जून से 11 जून तक सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, परिवहन तथा सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले 70,000 श्रमिक हड़ताल पर चले गए । हड़ताल में जापानी स्वामित्व की सूती कपड़ा मिलों तथा अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी उद्यमों के श्रमिकों की भागेदारी से हड़ताल का साम्राज्यवाद-विरोधी स्वरूप प्रकट हुआ। पेकिङ-मुकदन रेलमार्ग पर स्थित थाङशान, तथा पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग पर स्थित चाङशिनथ्येन के श्रमिकों ने देशभक्तिपूर्ण जुलूस निकाले।

चीन के इतिहास में श्रमिक वर्ग की यह पहली साम्राज्यवाद-विरोधी हड़ताल थी। 4 मई के आंदोलनकारियों की कतारों में सबसे ताकतवर जत्था श्रमिक वर्ग का था। इसने शंघाई (चीन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक शहर), चाङशिनथ्येन और थाङशान (उद्योगों तथा खनन के दो महत्त्वपूर्ण केन्द्र) में तथा शंघाई-नानकिङ रेलमार्ग (यातायात की एक महत्त्वपूर्ण लाइन) के इलाकों में हड़तालों द्वारा युद्ध-सरदारों की सरकार को भारी क्षति पहुंचाई। इस जत्थे की अगुवाई ने 4 मई आंदोलन की सफलता में एक महत्त्वपूर्ण तत्व की भूमिका निभाई। इसने लोगों को उत्साह से भर दिया तथा अन्य सामाजिक तबकों को जनशक्ति के विकास का, उसकी वृद्धि का आभास कराया।

चीनी पूँजीपति वर्ग भी देशभक्तिपूर्ण आंदोलन की पांतों में सम्मिलित हो गया। चूंकि 4 मई आंदोलन के बाद चीनी उत्पादकों के लिए बाजार का विस्तार हो गया था, इसलिए शंघाई के पूँजीपति वर्ग ने भी छात्र आंदोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। श्रमिकों की हड़ताल से प्रभावित होकर, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों ने एक साथ 5 जून को कामकाज ठप्प कर दिया, तथा इसके तुरंत पश्चात आस-पास के कस्बों तथा देश भर के बड़े-बड़े नगरों ने उनका अनुसरण किया।

फिर भी शंघाई के पूँजीपति वर्ग ने आंदोलन के आरंभ में ही अपनी कमजोरी दिखा दी। "हंगामे" का विरोध किया तथा "सभ्य तरीके से विरोध" की पैरवी की, अर्थात् श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा व्यापारियों की सभी हड़तालें "कानूनी" ढंग से तथा साम्राज्यवादियों व युद्ध-सरदारों की सरकार द्वारा मान्य सीमाओं के भीतर चलाई जानी चाहिएं थीं ।

4 मई आंदोलन पेकिङ से शुरू होकर देशभर में फैल गया तथा श्रमिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और अन्य सामाजिक तबकों को समाविष्ट करता हुआ एक व्यापक देशभक्तिपूर्ण जन-आंदोलन बन गया।

चीनी जनता द्वारा अपने संघर्ष में प्रदर्शित अत्यधिक शक्ति ने प्रतिक्रियावादी सरकार को, गिरफ्तार किए गए विद्यार्थियों को मुक्त करने तथा गद्दार अफसरों—छाओ रू-लिन, चाङ

पहला अध्याय

चीन में 4 मई आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन का उत्थान

(मई 1919-जून 1921)

1.

- **चीन में विदेशी-पूँजीवाद का प्रवेश।**
- **चीन का सामन्ती समाज से अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामन्ती समाज में प्रवेश।**
- **पुरानी जनवादी क्रान्ति एवम् उसकी असफलता।**

सामन्ती चीन में लघु स्तर की कृषि तथा घरेलू हस्तशिल्पों का सम्मिश्रण, उत्पादन की मुख्य प्रणाली थी। चीनी किसान एक हस्तशिल्पकार भी था जो अपनी जरूरत की कृषि उपज तथा हस्तशिल्प के अधिकतर माल की आपूर्ति स्वयं करता था। प्राकृतिक अर्थव्यवस्था मुख्य थी। लेकिन सामंती समाज के धीमे विकास के बावजूद, कुछ बड़े-बड़े कारखानों का आविर्भाव हुआ जिनका राष्ट्रव्यापी बाजार था, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन तथा रेशम उद्योग। उत्पादन-प्रणाली एक प्रकार का बड़े पैमाने पर पूँजीवादी उत्पादन था जो श्रम विभाजन, सहयोग तथा मजदूरों की हस्तशिल्प तकनीक पर आधारित था । एक तरफ तो यह प्रणाली हस्तशिल्प तकनीक पर आधारित होने के कारण हस्तशिल्प उत्पादन के समान थी तथा दूसरी तरफ पूँजीवादी उत्पादन के समान थी क्योंकि इसमें मजदूरों का शोषण करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। साधारण हस्तशिल्प उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर मशीनी उत्पादन के बीच की यह संक्रमणकालीन मंजिल थी। चूंकि इसका आविर्भाव तथा फलना-फूलना मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से ज्यादा विकसित क्षेत्रों में हुआ था, जैसे कि याङत्सी नदी के दक्षिण के क्षेत्र; इसलिए सामंती चीन में यह कभी भी उत्पादन की प्रधान प्रणाली नहीं बन सकी। न ही यह कहा जा सकता है कि इसने हस्तशिल्प उत्पादन के समस्त अधिकार-क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त कर ली थी, क्योंकि हस्तशिल्प की कई मुख्य शाखाओं ने तो अभी अपने निर्माण-कारखाने भी स्थापित नहीं किए थे। इसलिए कुल मिलाकर **अफीम युद्ध**[1] के समय तक चीनी उद्योग अभी निर्माण की अवस्था में नहीं पहुंचा था। फिर भी जो निर्माण-कारखाने अस्तित्व में थे, उनमें पूँजीवाद का भ्रूण विद्यमान था। यदि विदेशी पूँजीवाद द्वारा उसके स्वतंत्र विकास में बाधा न पहुंचाई गई होती तो बहुत से अन्य देशों की तरह चीन में भी अनिवार्य रूप से, यद्यपि धीरे-धीरे ही सही, एक पूँजीवादी समाज का विकास हुआ होता।

19वीं सदी के मध्य में विदेशी पूँजीवाद के चीन में प्रवेश से चीनी समाज के सामंती ढांचे में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्होंने उसे अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती समाज की

ओर अग्रसर होने को बाध्य किया और इस प्रकार उसके स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई।

विदेशी पूँजीवाद द्वारा चीन में प्रवेश की प्रक्रिया, खुद विदेशी पूँजीवाद के विकास के अनुरूप थी। 1840 के अफीम युद्ध से लेकर **1894 के चीन-जापान युद्ध**[2] तक पूँजीवादी शक्तियों ने चीन के विरुद्ध हमलावर युद्धों की झड़ी लगा दी। इन युद्धों में चीन की हार के पश्चात्, उसे अपने क्षेत्रों का सत्तान्तरण करने, हर्जाना देने, व्यापारिक बन्दरगाहों को खुला रखने, पारंपरिक सीमा-शुल्क प्रणाली स्वीकार करने, वाणिज्यिक अधिकार प्रदान करने तथा मिशनरी गतिविधियों को मान्यता प्रदान करने वगैरा-वगैरा के लिए विवश किया गया। यह मुक्त पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा का काल था जिसमें आर्थिक आक्रमण का मुख्य पहलू माल का निर्यात था। असमान संधियों ने पूँजीवादी ताकतों के लिए अपने सामान से चीन के बाजार को भर देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कीं।

जब 19वीं सदी के अंत में विश्व पूँजीवाद, साम्राज्यवाद की मंजिल में पहुंचा एवं एकाधिकारवाद ने मुक्त प्रतिस्पर्धा का स्थान ले लिया, तब साम्राज्यवादी आक्रमण के नए लक्षण प्रकट हुए, जैसे कि पूँजी के निर्यात में लगातार वृद्धि तथा आक्रमण का वृहत्तर एकाधिकारवादी स्वरूप। इससे साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन को बांटने के प्रयासों ने और तीव्र संघर्ष का रूप धारण कर लिया। और ये लक्षण 1894 के चीन-जापान युद्ध तथा सन् 1900 में हुए **आठ शक्तियों की संयुक्त सेना के आक्रमणकारी युद्ध**[3] (Eight Powers Allied Army of 1900) में भली-भांति प्रकट हुए। चीन-जापान युद्ध के बाद चीन को शिमोनोशकी की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जिसके अंतर्गत जापान को चीन में फैक्ट्रियां लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद चीन में फैक्ट्रियां लगाने, उत्खनन, रेल निर्माण तथा बैंक स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादियों की बाढ़ सी आ गई, और उन्होंने चीनी उद्योग तथा बैंक प्रणाली पर नियंत्रण कर लिया। इसके अतिरिक्त चीन को राजनीतिक ऋण देने का सिलसिला शुरू करके वे चीनी वित्त एवम् सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम हो गए। चीन में उनके अगले आक्रमण के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त होने वाले "प्रभाव क्षेत्रों" के बंटवारे ने उन्हें परस्पर संघर्षों में धकेल दिया।

साम्राज्यवादी शक्तियों ने चीनी सामंती शासकों को अपने एजेन्टों के रूप में सहारा देने का भरसक प्रयास किया ताकि वे चीन पर अपने प्रभुत्व की स्थापना एवं विकास कर सकें और उधर चीनी सामंती शासक भी अपनी ओर से चापलूसी की हद तक बढ़-चढ़ कर साम्राज्यवादियों के सामने अपने आपको बेचने व उनके हितपोषण के लिए तत्पर थे, ताकि वे खुद जनता का दमन, तथा उत्पीड़न जारी रख सकें। साम्राज्यवादियों ने पहले **थाएफिङ क्रान्ति**[4] को कुचलने के लिए छिङ (मांचू) सरकार का समर्थन किया और फिर **1911 की क्रान्ति**[5] का गला घोंटने के लिए अव्वल नम्बर के गद्दार **च्यान श-खाए**[6] का साथ दिया। चीन के प्रतिक्रियावादियों तथा साम्राज्यवादी देशों के पूँजीपति वर्ग में एक गठजोड़ हुआ। साम्राज्यवादियों के समर्थन से शोषण की सामंती प्रणाली न केवल अक्षुण्ण रही, बल्कि **दलाल-पूँजीवाद**[7] के साथ मिलकर चीनी अर्थव्यवस्था में प्रधान भूमिका भी अदा करती रही।

1840 के बाद विदेशी पूँजीवाद के प्रवेश ने चीन पर दोहरा प्रभाव डाला। पहली बात तो यह कि इसने चीन की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा पूँजीवाद के आविर्भाव तथा विकास को प्रेरित एवं तीव्र किया। इस प्रकार विदेशी पूँजीवाद ने चीन को

4 मई, 1919 के महान देशभक्तिपूर्ण छात्र आन्दोलन का एक दृश्य

4 मई, 1919 के महान देशभक्तिपूर्ण आंदोलन के दौरान शंघाई के मजदूरों का जुलूस

उसका प्रतिनिधित्व भी था। जनमत के दबाव के तहत, चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कांफ्रेंस से अपील करते हुए चीन में साम्राज्यवादियों के विशेषाधिकारों के उन्मूलन, ग्वान श-खाए तथा जापानी साम्राज्यवादियों के बीच हुए "21 मांगों" वाले समझौते को रद्द करने तथा युद्ध के दौरान शानतुङ में जापान द्वारा छीने गए जर्मन विशेषाधिकारों की वापसी की मांग प्रस्तुत की।

इससे पहले, अमरीका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी, 1918 में तथाकथित "शांति शर्तों के चौदह सूत्र" में शेखी बघारते हुए घोषणा की थी कि उपनिवेशों की जनता की मांगों का आदर किया जाना चाहिए और यह भी कि प्रत्येक राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता की सभी द्वारा गारंटी की जानी चाहिए। इससे अमरीका की "खुला दरवाजा नीति" तथा जापान की एकाधिकार की नीति में अंतर्विरोध प्रकट हुआ, और यह अन्तर्विरोध उस समय खुल कर सामने आया जब जापानी प्रतिनिधिमंडल ने कांफ्रेंस के सामने अपनी यह मांग पेश की कि शानतुङ में सभी जर्मन अधिकार जापान द्वारा अपने अधिकार में ले लेने चाहिएं। चूंकि जापान की मांग को ब्रिटेन तथा फ्रांस का समर्थन प्राप्त था और अमरीका प्रति-क्रांतिकारी साम्राज्यवादी मोर्चे को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने जापान के इस अन्यायपूर्ण दावे का समर्थन करते हुए उसके साथ समझौता किया तथा चीन की न्यायोचित मांगों को ठुकरा दिया। जर्मनी के साथ शांति-संधि में यह निर्धारित कर दिया गया था कि शानतुङ में सभी जर्मन अधिकार जापान को हस्तांतरित किए जाने थे। जहां तक चीन में विदेशी शक्तियों के विशेषाधिकारों के उन्मूलन तथा "21 मांगों" को रद्द करने की चीनी मांग का संबंध था, कांफ्रेंस ने उस पर चर्चा तक करने की जहमत न उठाई। इस प्रकार पेरिस कांफ्रेंस से साम्राज्यवादियों के हिंसक मन्सूबों का पर्दाफाश हो गया, जो चीन को लूटने के लिए तो एक-दूसरे से लड़ते थे, परन्तु उसके हितों की बलि चढ़ाते वक्त सांझे मोर्चे का प्रदर्शन करते थे।

चीन की कूटनीतिक पराजय से चीनी जनता का, विशेषकर प्रगतिशील तत्वों तथा उनके प्रभाव में नौजवान विद्यार्थियों का मोहभंग हो गया, उन्हें पेरिस कांफ्रेंस से काफी आशाएं थीं, वे महसूस करने लगे कि केवल अपने बलबूते पर ही वे अपने देश के भाग्य का फैसला कर सकते थे।

4 मई, 1919 को पेकिङ के विद्यार्थियों ने एक विशाल देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया। भूतपूर्व शाही महल के सामने के प्रवेश द्वार, थ्येन आन-मन के सामने तीन हजार विद्यार्थी इकट्ठे हो गए, उन्होंने सभा करने के पश्चात तीन मंत्रियों को सजा देने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। ये मंत्री थे—संचार-मंत्री छाओ रू-लिन, जिसने ग्वान श-खाए की सरकार में उपविदेश मंत्री के नाते "21 मांगों" पर हस्ताक्षर किए थे; मुद्रा ब्यूरो का निदेशक लू चुङ-ग्वी, जो "इक्कीस मांगों" पर हस्ताक्षर होने के वक्त जापान में चीनी मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था; तथा उस समय (यानी थ्येन आन-मन प्रदर्शन के समय) जापान में चीनी मंत्री चाङ चुङ-श्याङ, जिसने अनेकों रेलवे अधिकार जापान को बेच दिये थे। जब विद्यार्थी छाओ रू-लिन के निवास स्थान को तहस-नहस कर रहे थे, सशस्त्र पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंची तथा तीस से अधिक विद्यार्थियों को मौके पर हिरासत में ले लिया गया। पेकिङ सरकार ने पेकिङ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छाए ग्वान-फेइ को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पेकिङ के विद्यार्थियों ने तुरन्त हड़ताल कर दी तथा गलियों में देशभक्तिपूर्ण प्रचार

सामंती से अर्ध-सामंती समाज में परिवर्तित कर दिया। अपनी जिन्सों का ढेर लगाकर तथा कच्चे माल का दोहन करके पूँजीवादी देशों ने चीन की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया तथा चीनी किसानों को अधिकाधिक बाजार पर निर्भर होने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार चीन में पूँजीवाद के लिए जिन्सों के बाजार का निर्माण हुआ। इसी बीच मशीनी उत्पादों द्वारा हस्तशिल्प के सामान को बाजार से बाहर धकेल देने के साथ ही हर्जानों के भारी बोझ तथा बेतहाशा लेवियों व करों ने किसानों तथा हस्तशिल्पियों के विशाल जनसमूहों को दिवालिया बना दिया। इस प्रकार पूँजीवाद के लिए एक श्रम-बाजार का निर्माण किया गया। संक्षेप में, साम्राज्यवादी आक्रमण ने न केवल चीन की आत्मनिर्भरता वाली प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, बल्कि पूँजीवाद के आविर्भाव एवम् विकास के लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कीं।

सामंती समाज के टूटने-बिखरने से पूँजीवाद के कुछ तत्वों का जन्म एवं विकास होने लगा। चीन अब किसी तरह भी एक शुद्ध व सहज सामंती समाज नहीं था, बल्कि एक अर्ध-सामन्ती समाज था।

दूसरे, साम्राज्यवादियों का इरादा चीन को एक उपनिवेश में परिवर्तित करने का था। अपनी फौजी, राजनीतिक, आर्थिक एवम् सांस्कृतिक ताकत के बल पर उन्होंने चीन के फौजी तथा राजनीतिक मामलों पर प्रभुत्व जमा लिया तथा उसके अर्थतन्त्र के मुख्य सूत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने चीन की कृषि अर्थव्यवस्था को अपनी सेवा में लगा लिया तथा उसके राष्ट्रीय उद्योग पर कब्जा कर लिया, जो कभी भी मजबूत स्थिति में नहीं रहा था, और इस प्रकार उन्होंने उसकी उत्पादन शक्तियों के विकास को बाधित किया। परिणामवश चीनी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वह साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा भर बनकर रह गई। चीन की आत्मरक्षा की सामर्थ्य तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता खत्म हो गई, तथा वह नाममात्र को अपनी आजादी तथा संप्रभुता कायम रख सका। असल में उसका दर्जा घटकर एक अर्ध-उपनिवेश के बराबर का रह गया था।

अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती चीनी समाज में मूलभूत अंतर्विरोध इस प्रकार थे : साम्राज्यवाद तथा चीनी राष्ट्र के बीच का अंतर्विरोध एवं सामंतवाद व व्यापक जन समुदाय के बीच का अंतर्विरोध। इनमें पहला अंतर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध था। चीन को अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती समाज में परिणत करने के लिए साम्राज्यवाद की सामंतवाद के साथ गठजोड़ की प्रक्रिया तथा साम्राज्यवाद व सामंतवाद के विरुद्ध चीनी जनता के अदम्य संघर्ष की प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं। सन् 1840 के अफीम-युद्ध से लेकर 1949 में चीनी लोक गणराज्य की स्थापना होने तक के 109 वर्षों में चीनी जनता ने वीरता तथा निर्भीकता से साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के खिलाफ संघर्षों की एक लंबी शृंखला जारी रखी। चीनी क्रान्ति को दो कालखण्डों में विभक्त किया जा सकता है और प्रत्येक काल की अपनी ऐतिहासिक विशिष्टताएं हैं : 4 मई 1919 के आंदोलन से पहले के 80 वर्षों के दौरान की क्रान्ति, पुरानी जनवादी किस्म की थी जिसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग द्वारा किया गया था तथा वह विश्व-पूँजीवादी क्रान्ति का अंग थी; 4 मई आंदोलन से लेकर 1949 तक की अवधि की क्रान्ति का स्वरूप नव-जनवादी था, जिसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग द्वारा किया गया था तथा यह विश्व-सर्वहारा क्रान्ति का हिस्सा थी।

पुरानी जनवादी क्रान्ति के काल में चीनी जनता ने निरंतर क्रांतिकारी संघर्ष किए, जिनमें थाएफिङस का किसान युद्ध तथा 1911 की क्रान्ति, जिसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग ने डॉ० सुन यात-सेन की रहनुमाई में किया, विस्तार तथा प्रभाव की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे। इन क्रान्तिकारी संघर्षों ने सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद को भारी क्षति पहुंचाई।

थाएफिङ क्रान्ति के नेता हुङ श्यू-छ्वान ने भगवान की पूजा के लिए पाए शाङ ती ह्वेइ नामक संस्था की स्थापना की तथा पश्चिमी मिशनरियों द्वारा लाए गए ईसाई धर्म में किसानों की स्वतंत्रता एवम् समानता के विचारों के अनुरूप संशोधन किया, इस प्रकार उसने किसान क्रान्ति के आदर्शों को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया। पाए शाङ ती ह्वेइ के द्वारा हुङ श्यू-छ्वान ने गरीबी के मारे किसानों तथा हस्तशिल्पकारों को संगठित करके सशस्त्र विद्रोह किया। थाएफिङ क्रान्ति 1851 से लेकर 1864 तक, यानि कि 14 वर्ष तक चली तथा एक समय तो इसका विस्तार तथा प्रभाव 17 प्रान्तों में फैल गया था। थाएफिङ क्रान्ति के नेताओं ने नानकिङ में एक क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की। उन्होंने सामंती संस्कृति के बुनियादी विचारों को चुनौती दी तथा भूमि संबंधी सामंती-प्रणाली को समाप्त करके **थाएफिङ स्वर्गिक-राज्य** के भूमि-संबंधी कानूनों को लागू किया। लेकिन क्रान्ति विफल हो गई, क्योंकि यह प्रगतिशील मजदूर वर्ग के नेतृत्व के बिना, मुख्यत: पुराने किस्म का एक किसान विद्रोह ही थी। किसान वर्ग एक क्रान्तिकारी वर्ग है जो सामंती शासन तथा राष्ट्रीय दमन का विरोधी है, लेकिन उत्पादन की पिछड़ी प्रणाली इस छोटे उत्पादकों के वर्ग के मार्ग में बाधाएं खड़ी करती है तथा इस वर्ग की कुछ खास कमजोरियां देखने को मिलती हैं, जैसे बिखरी गतिविधियों के प्रति रुझान, रूढ़िवाद तथा स्वार्थपरता। थाएफिङ भूमि कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी कि जमीन का बंटवारा बराबर-बराबर हो तथा प्रत्येक परिवार को एक समान संख्या में शहतूत के पेड़, चूजे तथा सूअर मिलें व एक समान भूमि-क्षेत्र। प्रत्येक किसान को एक समान मात्रा में उत्पादन-श्रम करना था तथा एक समान मात्रा में ही कृषि-उपज का हिस्सा प्राप्त करना था। ऐसा सोचा गया कि बिखरी हुई कृषि तथा लघु-कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रत्येक किसान के पास सदा एक समान संपत्ति रहेगी। वास्तव में, यदि इस कार्यक्रम को लागू भी कर दिया जाता, तो भी किसानों का भविष्य काफी निराशाजनक ही रहता, क्योंकि उत्पादक शक्तियों के विकास की बजाय यह व्यवस्था उन्हें पिछड़ी लघु-कृषि अर्थ-व्यवस्था के रूप में एक ही जगह पर खड़ा रखती। अत: सामंतवाद-विरोधी क्रान्तिकारी चरित्र होते हुए भी, थाएफिङ भूमि कार्यक्रम अव्यावहारिक कृषि समाजवाद की रंगत लिए हुए था। इसके अतिरिक्त थाएफिङ सेना अपने अधिकृत इलाकों में भी मजबूत आधार-क्षेत्र स्थापित करने में विफल रही। नानकिङ में सरकार स्थापित करने के बाद इसके नेताओं ने एक के बाद दूसरी, अनेक फौजी व राजनीतिक गलतियां कीं, मसलन उनके नेतृत्वकारी केन्द्र में विभाजन, व अन्य किसान विद्रोहों के साथ ताल-मेल बिठाने में उनकी विफलता। इसका नतीजा यह हुआ कि वे छिङ के प्रतिक्रान्तिकारी शाही सैनिकों तथा अमरीकी, बरतानवी व फ्रांसीसी आक्रमणकारियों के संयुक्त हमले के सामने टिक नहीं सके।

पूँजीवादी क्रान्तिकारी जनवादियों के नेता डॉ० सुन यात-सेन ने सन् 1905 में तुङ मङ-ह्वेइ (क्रान्तिकारी लीग) की स्थापना की तथा पूँजीपति वर्ग व निम्न-पूँजीपति वर्ग के

मुखिया के रूप में स्थापित कर दिया।

1916 में राजशाही की पुनर्स्थापना के असफल प्रयास के फलस्वरूप य्वान श-खाए का पतन हो गया। चूंकि उस समय यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियाँ आपस में इतनी बुरी तरह युद्ध में उलझी हुई थीं कि उनके लिए चीन में हस्तक्षेप करना संभव न था, जापानी साम्राज्यवादियों ने मौके का फायदा उठाते हुए, एक अन्य उत्तरी युद्ध-सरदार त्वान छी-रुइ को अपने पालतू कुत्ते के रूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार य्वान श-खाए की मृत्यु के तत्काल बाद त्वान छी-रुइ पेकिङ सरकार का सर्वेसर्वा बन गया।

चूंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने य्वान श-खाए को अपने सांझे एजेंट के तौर पर स्वीकृत किया था, इसलिए उसने सत्ता में आने के तत्काल बाद छिङ सरकार द्वारा की गई सभी देशद्रोहात्मक संधियों के अनुपालन का बीड़ा उठा लिया। 1913 में अमरीका की अगुवाई में **'छ: शक्तियों के संकाय'** (Six-Power Consortium) ने य्वान श-खाए को अढ़ाई करोड़ पौंड का एक बड़ा ऋण चीन में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए इस शर्त पर प्रदान किया कि चीनी वित्त विभाग प्रत्यक्ष रूप से संकाय के निरीक्षण में रहेगा। 1915 में जापान ने य्वान श-खाए को **''इक्कीस मांगों''**[15] पर हस्ताक्षर करने को विवश किया तथा इस प्रकार उसका चीन में एकाधिकार स्थापित हो गया। य्वान श-खाए की मृत्यु के पश्चात जापान समर्थित त्वान छी-रुइ ने कुल मिलाकर 50 करोड़ येन का ऋण जापान से किस्तों में प्राप्त किया। इसके एवज में चीन ने जापान को **मन्चूरिया**[16], मंगोलिया तथा शानतुङ प्रदेशों का शोषण करने, चीनी सेना व पुलिस पर नियंत्रण रखने व नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की छूट दे दी।

लेकिन त्वान छी-रुइ की सरकार ने जापानी सैन्यवादियों द्वारा सोवियत-संघ पर आक्रमण के दौरान अत्यधिक घृणित भूमिका निभाई तथा जापानियों के पालतू कुत्ते के रूप में कार्य किया। सोवियत विरोधी युद्ध के परिणामस्वरूप, जापानी सेना चीन में प्रविष्ट हो गई तथा उसने चीन के उत्तरपूर्वी प्रदेशों तथा उसके सैन्य-तंत्र पर अधिकार कर लिया।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, अमरीका तथा जापान के बीच का विवाद और ज्यादा गहरा हो गया। उनमें चीनी अफसरशाहों, युद्ध-सरदारों और दलालों में से नए एजेन्टों की तलाश करने की होड़ सी लग गई और उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के लिए उनका अपनी कठपुतलियों के रूप में इस्तेमाल किया। चीन में जापानी एकाधिकार को अपनी आर्थिक शक्ति के बल से कुचलने तथा संकाय में अपने लिए मार्गदर्शक भूमिका अर्जित करने के लिए अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान को मिलाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय संकाय के गठन का प्रस्ताव रखा। इस संकाय का गठन 1920 में किया गया, किन्तु चारों देशों में आपसी अन्तर्विरोधों के कारण, विशेष रूप से जापान तथा अमरीका के बीच के अंतर्विरोधों के कारण, कोई सहमति नहीं हो सकी ।

प्रथम विश्वयुद्ध का अंत जर्मनी और आस्ट्रिया की पराजय में हुआ। 18 जनवरी, 1919 को पेरिस में 'वार्सेल्स शांति कांफ्रेंस' का आयोजन किया गया। यह कांफ्रेंस लूट का बंटवारा करने के लिए थी, तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के छल-कपट के तहत इसका उद्देश्य पराजित देशों की कांट-छांट कर उन्हें छोटा करना तथा उपनिवेशों का पुनर्विभाजन करना था।

क्योंकि चीन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका के पक्ष में लड़ा था, इसलिए कांफ्रेंस में

नौजवान विद्यार्थियों तथा समाचार-पत्रों ने स्वत: अक्तूबर क्रांति की विजय का प्रचार-कार्य आरंभ कर दिया। इस बात को आत्मसात करते हुए कि सोवियत विदेशनीति ने विश्व कूटनीतिक इतिहास में एक नई पहल की थी, चीनी जनता ने **नवोदित सोवियत राष्ट्र का ''न्याय तथा मानवता के प्रिय शिशु'', तथा रूसी श्रमिकों, किसानों तथा सैनिकों का ''दुनिया के सर्वप्रिय लोगों''** के रूप में स्वागत किया। चीनी जनता, जिसमें इस प्रकार जागृति पैदा हो गई थी, ने स्वयं को युद्ध-सरदारों तथा अफसरशाहों की प्रतिक्रियावादी सरकार के खिलाफ एक जुझारू संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया।

3. अक्तूबर क्रान्ति ने मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद को चीनी जनता तक पहुंचाया तथा उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाया। **''अक्तूबर क्रान्ति के सैलाब ने हमें मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के प्रति जागृत किया''**[13] इस विश्वव्यापी सत्य ने प्रगतिशील चीनी बुद्धिजीवियों को अपने देश का भविष्य देखने में मदद की तथा सर्वहारा के विश्व दृष्टिकोण की रोशनी में अपनी समस्याओं पर पुनर्विचार करने में सहायता की। उन्होंने मार्क्स-एंगेल्स-लेनिनवाद को गले लगाना आरंभ कर दिया तथा श्रमिक-वर्ग के आंदोलन के आधार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। **''चीनी क्रांति के ठोस व्यवहार से एकबद्ध होकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य ने चीनी क्रांति को एक नया स्वरूप प्रदान किया।''**[14]

अक्तूबर क्रांति द्वारा लाए गए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद ने चीनी जनता के मुक्ति-अभियान का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए वह लेनिन तथा रूसी बोलशेविक पार्टी की गणना अपने महानतम शिक्षकों तथा मित्रों के रूप में करती है। यह उनकी शिक्षाएं हैं, जिनसे उसे सैद्धांतिक शक्ति प्राप्त होती है।

4.

- **4 मई का देशभक्तिपूर्ण आंदोलन।**
- **3 जून का आंदोलन तथा चीनी श्रमिक वर्ग की संघर्ष में भागेदारी।**
- **नई संस्कृति आंदोलन तथा इसका विकास।**
- **चीन में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रसार।**

4 मई 1919 के देशभक्तिपूर्ण आंदोलन से एक नया क्रांतिकारी तूफान फूट पड़ा तथा चीनी क्रांति ने एक नए दौर में प्रवेश किया।

1911 की क्रान्ति का स्वरूप पूँजीवादी-जनवादी था। सशक्त नेतृत्व के अभाव तथा अन्य कमजोरियों के चलते क्रांति ने चीनी सामंती शक्तियों तथा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बचाव के कुछ रास्ते खुले छोड़ दिए थे। साम्राज्यवादियों ने य्वान श-खाए का नए शासक के रूप में समर्थन किया तथा इस षड्यन्त्रकारी-गद्दार को अपनी नई कठपुतली के रूप में प्रयोग किया। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुऐ, य्वान ने छिङ सरकार तथा क्रांतिकारियों के साथ घृणास्पद, दोगला खेल खेला । उसने छिङ सम्राट को सिंहासन त्यागने के लिए विवश किया तथा नानकिङ में क्रांतिकारियों को समझौता करने के लिए राजी किया। साम्राज्यवादियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके कुचक्रों का समर्थन किया तथा उसे चीनी प्रतिक्रियावादियों के

नेतृत्व में एक जनवादी क्रान्ति की शुरूआत की। लीग ने छिङ राजशाही का तख्ता पलटने तथा फ्रांसीसी क्रान्ति के नारे **'स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुता'** के आधार पर एक जनवादी गणराज्य स्थापित करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जनवादी क्रान्ति का झण्डा ऊँचा उठाए, लीग ने संवैधानिक राजशाही के समर्थकों का खुलकर विरोध किया तथा 1905 से 1911 के बीच अनेक क्रान्तिकारी विद्रोहों का नेतृत्व किया।

डॉ० सुनयात-सेन (1866-1925)
प्रसिद्ध तीन जन-सिद्धान्तों के प्रणेता

छिङ वंश का तख्ता पलटकर, 1911 की क्रान्ति ने, चीन में पिछले 2000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही सामंती राजशाही का अंत कर दिया तथा चीनी गणराज्य को जन्म दिया व नानकिङ में एक अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की गई। लेकिन राजसत्ता शीघ्र ही प्रति-क्रान्तिकारी य्वान श-खाए के हाथों में चली गई। अत: 1911 की क्रान्ति की परिणति भी पराजय में ही हुई। इसकी पराजय का मूल कारण चीनी पूँजीपति वर्ग की दुर्बलता थी, उसने साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी एक पुख्ता कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। वह चीन की सबसे विशाल तथा सबसे शक्तिशाली जनवादी शक्ति—किसान समुदाय को—प्रभावी ढंग से लामबंद करने व संघर्ष में उतारने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, डॉ० सुन यात-सेन के नेतृत्व वाली 1911 की क्रान्ति में ठोस आधार की कमी थी, क्योंकि यह क्रान्ति जमीन के सवाल को हल करने में विफल रही थी, जो किसी भी जनवादी क्रान्ति का बुनियादी सवाल होता है। इसलिए, हालांकि इसने भ्रष्ट छिङ सरकार का तख्ता पलट दिया था, परन्तु यह उत्तरी युद्ध सरदार य्वान श-खाए के नेतृत्व में चलने वाली साम्राज्यवाद समर्थित, सामंतवादी, दलाल सरकार से सामना हो जाने पर शक्तिहीन सिद्ध हुई। चीन में पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व में होने वाली किसी भी क्रान्ति का विफल होना तय था।

डॉ० सुन यात-सेन का विचार था कि. पूँजीवाद तथा उसकी बुराइयों को चीन में फलने-फूलने से रोका जा सकता था। उनके अपने शब्दों में- **''राजनीतिक तथा सामाजिक, दोनों स्तरों पर क्रान्ति एक ही झटके में संपन्न हो जाएगी।''** यानि कि जनवादी तथा समाजवादी क्रान्ति के कार्य एक ही समय में पूरे किए जा सकते थे। डॉ० सुन यात-सेन ने पूँजीवाद को रोकने के लिए ''भू-स्वामित्व के समकरण'' का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ऐसे भू-स्वामित्व कार्यक्रम की वास्तविक प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह पूँजीवाद को रोकने की बजाय प्रोत्साहित करने का काम ही करता है और उस समय यूरोप में समाजवादी क्रान्ति हो रही थी। यह स्वाभाविक ही है कि सर्वहारा क्रान्ति के उस प्रचण्ड तूफान से प्रेरित हो, डॉ० सुन यात-सेन ने समाजवाद का सपना संजोया होगा तथा सोचा होगा कि चीन की पिछड़ी परिस्थितियां ''सामाजिक क्रान्ति'' को और भी आसान बना देंगी, लेकिन यह निरा व्यक्तिपरक

समाजवाद था। यदि 1911 की पूँजीवादी क्रान्ति सफल हो जाती तो वह पूँजीवाद के विकास तथा पूँजीवादी समाज की स्थापना के लिए रास्ता तैयार करती। लेकिन साम्राज्यवाद के युग में अर्ध-औपनिवेशिक चीन में ऐसा होना कतई नामुमकिन था।

अफीम युद्ध के बाद के सभी पुरानी किस्म के किसान विद्रोह तथा पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व में हुई सभी क्रांतियां समान रूप से विफल रहीं तथा साम्राज्यवाद व सामंतवाद विरोधी आंदोलन का कार्य अधूरा रह गया। अब जब तक एक नया वर्ग अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ नेतृत्व के लिए आगे नहीं आ जाता, तब तक जनवादी क्रान्ति लाना और समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ना असंभव था। **और यह नया वर्ग—चीन का मजदूर वर्ग था, और इसकी पार्टी तथा हरावल दस्ता था—चीनी कम्युनिस्ट पार्टी।** ●

2.

- **चीनी औद्योगिक पूँजीवाद का आविर्भाव तथा प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उसका और आगे विकास ।**
- **चीनी औद्योगिक सर्वहारा का विकास ।**
- **चीनी मजदूर वर्ग की विशिष्टताएं ।**
- **मजदूर वर्ग का प्रारंभिक आंदोलन ।**

चीन के आधुनिक उद्योग का आविर्भाव 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुआ। विदेशी पूँजीवाद के आगमन के शीघ्र बाद ही चीन में कुछ आधुनिक उद्यम स्थापित किए गए। चौथे दशक से बरतानिया ने हांगकांग में आधुनिक उद्योग स्थापित करना आरंभ किया। बरतानवी, अमरीकी, फ्रांसीसी तथा जर्मन व्यापारियों ने शंघाई, कैंटन तथा अमेइ में शिपयार्ड, स्टीमर कंपनियां, रेशम तैयार करने के कारखाने, ब्रिक-टी फैक्ट्रियां और छापेखाने शुरू किये। ये कंपनियां माल के निर्यात, कच्चे माल की लूट तथा पूँजीवादी राष्ट्रों के सांस्कृतिक आक्रमण से गहराई से जुड़ी हुई थीं। इन विदेशी उद्यमों में ही औद्योगिक मजदूरों के पहले दस्ते का जन्म हुआ, जिनमें मुख्य रूप से नाविक तथा गोदी कर्मचारी थे। छठे दशक में चीनी सामंती शासकों ने, चङ क्वो-फान तथा ली हुङ-छाङ के नेतृत्व में फौजी साजोसामान के उद्योग लगाने आरंभ कर दिए तथा इन उद्योगों ने कोयला तथा लोहा उद्योग के विकास में उत्प्रेरक का काम किया। 80 के दशक में इनका विस्तार करके लाभकारी नागरिक उद्योगों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। इसी दौरान चीनी व्यापारियों, जमींदारों तथा अफसरों के एक हिस्से ने भी आधुनिक उद्योगों में पूँजी लगानी शुरू कर दी, इससे औद्योगिक मजदूरों के एक और दस्ते का जन्म हुआ।

1849 के चीन-जापान युद्ध के बाद, साम्राज्यवादियों ने चीन पर अपने आर्थिक आक्रमण की गति, पैमाना तथा कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया। रेलवे, खनन तथा अन्य उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेश में काफी वृद्धि हुई। युन्नान-वियतनाम, पूर्वी चीनी, छिङताओ-चीनान, पेकिङ-हानखओ, पेकिङ-**फङथ्येन**[6], थ्येनचिन-फूखओ, शंघाई-नानकिङ और पेकिङ-स्वेय्वान नामक सभी रेलमार्ग इसी समय के दौरान बिछाए गए। इनमें या तो सीधे ही साम्राज्यवादियों की पूँजी लगी हुई थी और वे ही प्रत्यक्ष रूप से इनका संचालन करते थे, या फिर इन्हें उनके नियंत्रण में दे

समाज) तथा अन्य, एवम् शिल्पी संघ व क्षेत्रीय संघ। लेकिन ये संस्थाएं जीत हासिल करने में श्रमिकों का नेतृत्व नहीं कर पाईं, क्योंकि उन पर आमतौर से दलालों तथा स्थानीय गुंडे-बदमाशों का नियंत्रण होता था।

चीनी श्रमिक वर्ग अपनी बढ़ती हुई शक्ति के कारण देश के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। साम्राज्यवादी तथा सामंती जुल्म और शोषण में तेजी आते ही तथा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के प्रभाव से चीनी श्रमिक वर्ग की राजनीतिक चेतना बड़ी तेजी से उभरी। ●

3.

- **अक्तूबर समाजवादी क्रांति का चीनी क्रांति पर प्रभाव ।**

1917 की अक्तूबर समाजवादी क्रांति से चीन तथा दुनिया के इतिहास में मौलिक परिवर्तन आया। चीनी क्रांति पर इसका दूरगामी तथा गहरा प्रभाव पड़ा।

1. अक्तूबर क्रांति ने चीनी जनता में उसके मुक्ति संघर्ष के लिए अत्यधिक विश्वास भर दिया। रूसी सर्वहारा की अगुवाई में रूसी जनता द्वारा प्राप्त जीत और सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत राजसत्ता की स्थापना से, भूतपूर्व दबी-कुचली राष्ट्रीयताओं को सोवियत रूस में हासिल आजादी तथा स्वावलंबन से, जर्मन-आस्ट्रियन साम्राज्यवाद के पतन तथा इन दो देशों में क्रांतियों के फूट पड़ने से तथा ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के कमजोर पड़ने से चीनी जनता को अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए एक नई आशा की किरण दिखाई दी । रूसी सर्वहारा ने सामाजिक प्रगति की सभी बाधाओं—जैसे ज़ार, कुलीनों, अफसरशाहों, सैनिकवाद और पूँजीवाद को दूर कर दिया था तथा साम्राज्यवादी विश्व-व्यवस्था के अवश्यम्भावी विनाश की घोषणा कर दी थी। उसकी जीत ने चीनी जनता की लड़ने की इच्छा शक्ति के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया।

2. अक्तूबर क्रांति ने पश्चिम के सर्वहारा तथा पूर्व की दबी-कुचली जनता के मध्य पुल का काम किया। इसका अर्थ है कि अक्तूबर क्रांति के पश्चात विश्व-क्रांति की रूपरेखा का निर्माण हुआ जिसने लेनिनवाद के झण्डे तले राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों की भरपूर सहायता की। समाजवादी सोवियत-संघ की सहायता मिलने पर उपनिवेशों में चल रही क्रांति, विश्व सर्वहारा क्रांति का हिस्सा बन गई। लेनिन तथा रूस की जनता, चीनी जनता से अत्यधिक प्यार करते थे तथा उनका मानना था कि चीनी क्रांति में असीम शक्ति है। चीनी जनता के क्रांतिकारी संघर्ष के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए तथा सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के अनुरूप, उन्होंने चीनी जनता के मुक्ति-आंदोलन की अंत तक निरंतर सहायता की। सन् 1919 तथा 1920 में सोवियत सरकार ने चीन के संबंध में दो वक्तव्य जारी किए—जारशाही रूस द्वारा चीन में जबरन प्राप्त किये गए सभी विशेषाधिकारों को रद्द करना तथा जार के समय के अधिकारियों का चीन से निष्कासन। इस प्रकार सोवियत-संघ ऐसा पहला देश था जिसने चीन में प्राप्त विशेषाधिकारों की बपौती का परित्याग किया। सोवियत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रवाद की शानदार भावना के प्रदर्शन का चीनी जनता ने अत्यधिक उत्साह के साथ स्वागत किया।

आँकड़ों के अनुसार देश के 13 प्रान्तों में 144 फैक्ट्रियां ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक फैक्ट्री में 500 से अधिक मजदूर कार्यरत थे और 29 फैक्ट्रियां ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक में 1000 से ऊपर मजदूर थे। मजदूर वर्ग के केन्द्रीकरण ने उसकी वर्ग-चेतना को जागृत करने में और संघर्षों में मजदूरों के विवेक और शक्ति को एकजुट करने में योगदान दिया। फलतः चीनी मजदूर वर्ग के पास लड़ने की अथाह शक्ति केन्द्रित हो गई। इसके अतिरिक्त चीन में, शहर, साम्राज्यवादी प्रभुत्व के केन्द्र थे, अतः मजदूरों का संघर्ष साम्राज्यवादियों के लिए स्पष्ट रूप से खतरा था।

तीसरे, चीनी औद्योगिक मजदूरों की संख्या चाहे सिर्फ 20 लाख के लगभग थी, लेकिन अन्य कामगार लोग जैसे कि लगभग एक करोड़ से ऊपर हस्तशिल्पकार और दुकान-नौकर, और दसियों करोड़ की तादाद में खेत-मजदूर और गरीब किसान उनके स्वाभाविक संश्रयकारी थे। क्योंकि अधिकतर श्रमिक मूलतः दिवालिया किसान थे, इसलिए किसान वर्ग से उनके स्वाभाविक संबंध थे। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ये सर्वहारा तथा अर्ध-सर्वहारा, देश की जनसंख्या के आधे भाग से अधिक थे तथा एक ठोस आधार थे, जिसके बल पर श्रमिक वर्ग अपने क्रांतिकारी संघर्षों को जारी रख सकता था तथा किसान वर्ग के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर सकता था।

चीनी श्रमिक वर्ग की उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि कैसे उसने अपने संघर्षों को अदम्य इच्छाशक्ति तथा व्यापक भागेदारी से संचालित किया और अत्यंत केंद्रित जुझारू शक्ति का प्रदर्शन किया। ज्यों ही चीनी श्रमिक वर्ग मार्क्सवाद-लेनिनवाद के संपर्क में आया और उसने अपनी राजनीतिक पार्टी—**चीनी कम्युनिस्ट पार्टी**—का गठन किया, पार्टी नेतृत्व के तहत वह फौरन चीनी क्रांति का अगुवा वर्ग बन गया।

4 मई, 1919 के आंदोलन से काफी पहले ही चीनी श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी संघर्षों में भाग ले चुका था, लेकिन तब इसकी भूमिका पूँजीपति वर्ग के अनुयायी मात्र की थी, जो अपनी खुद की राजनीतिक मांगों और संघर्ष के कार्यक्रम से अनभिज्ञ था। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं : 1906 में आनय्वान कोयला-खदान के खनिकों ने तुङ मङ ह्वेइ के नेतृत्व में फिङश्याङ (च्याङशी प्रान्त), ल्यूयाङ तथा लीलिङ (दोनों हुनान प्रान्त) में हुई बगावत में हिस्सा लिया। 1911 की क्रांति में छुङकिङ-हानखओ रेलमार्ग का निर्माण कर रहे श्रमिकों ने छिङ सरकार द्वारा "रेलवे का राष्ट्रीयकरण" करने के प्रयास के विरुद्ध बगावत की। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों ने जीवन-यापन की स्थितियों में सुधार के लिए अनेक आर्थिक संघर्ष किए, जैसे कि 1913 में पेकिङ के डाक श्रमिकों द्वारा दैनिक चक्करों में वृद्धि के विरुद्ध हड़ताल, हानयाङ शस्त्रागार के श्रमिकों द्वारा अवमूल्यन की हुई मुद्रा में वेतन के भुगतान के विरुद्ध हड़ताल, शंघाई में *चाइना मर्चेन्टस स्टीम नेविगेशन कंपनी*, ब्रिटिश स्वामित्व की *बटरफील्ड एण्ड स्वायर कंपनी, जारडाइन और मैथसन एण्ड कंपनी* के श्रमिकों द्वारा 1914 में वेतनवृद्धि की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे श्रमिकों के समर्थन में आम हड़ताल। 1916 से लेकर 1919 तक शंघाई तथा दूसरी जगहों पर वेतन वृद्धि के लिए और भी बहुत सी हड़तालें हुईं।

जीत हासिल करने के लिए, श्रमिकों ने हर संभव किस्म की संस्थाओं की स्थापना की, जैसे गुप्त समितियां—**ख लाओ ह्वेइ** (भाइयों का समाज), **लाओ चुन ह्वेइ** (ताओवादी

दिया गया था। खनन उद्योग में तो विदेशी पूँजी का ही एकाधिकार था। 1913 में सारे देश में कोयले का कुल उत्पादन 1,28,79,770 टन था, जिसमें से 71,36,545 टन, यानि 55.4 प्रतिशत पर साम्राज्यवादियों का एकाधिकार था। लोहे के उत्पादन पर तो साम्राज्यवादी एकाधिकार और भी ज्यादा मजबूत था। 1913 में लोहे का 4,59,711 टन का कुल राष्ट्रीय उत्पादन, सारे का सारा जापानी पूँजी के नियंत्रण में था।

निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की लगातार वृद्धि के साथ ही चीन के राष्ट्रीय उद्योग का भी कुछ शुरुआती विकास हुआ। 1911 में चीन की फैक्ट्रियों तथा खानों की कुल पूंजी 15,96,54,812 चांदी के डॉलर थी, जिसमें से निजी स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों तथा खानों की पूँजी 8,85,52,367 चांदी के डालर थी, जो सारी पूँजी का लगभग आधा थी। चीन के राष्ट्रीय उद्योग में कोयला और लोहा उत्खनन तथा सूती वस्त्र उद्योग अग्रणी थे। उद्योग की इन दो शाखाओं में पूँजी का विभाजन इस प्रकार था : खनन तथा धातु कर्म—4,13,15,992 डॉलर तथा सूती वस्त्र उद्योग 4,07,88,689 डॉलर।

चीनी तथा विदेशी स्वामित्व के उद्यमों से औद्योगिक मजदूरों के एक और दस्ते का जन्म हुआ।

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ जाने पर यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां फौजी कार्यवाहियों में उलझ गईं तथा उन्होंने अस्थाई तौर पर चीन पर हमले में ढील दे दी। इस प्रकार चीन के राष्ट्रीय उद्योग तथा व्यापार को विकसित होने का अवसर मिला। सूती कपड़ा मिलों में तकलों की संख्या 1914 के 5,44,780 से बढ़कर 1919 में 6,58,748 हो गई। कच्चे रेशम का निर्यात 1913 के 70,150 **तान**[9] से बढ़कर 1919 में 1,18,028 तान हो गया। शंघाई में चीनी सूती कपड़ा मिलों में तकलों की संख्या 1914 में 1,60,900 थी, जो 1919 में बढ़कर 2,16,236 हो गई। रेशम की फैक्ट्रियों में चरखियों की संख्या 1914 में 14,424 थी जो 1919 में बढ़कर 18,306 हो गई। इस अवधि के दौरान सूती मिलों का मुनाफा 1914 में 19.58 चांदी के डॉलर प्रति गांठ था, जो कि 1919 में बढ़कर 70.58 डॉलर प्रति गांठ हो गया। जहां तक विदेशी व्यापार का संबंध था, 1913 में हुए आयात-निर्यात का सूचकांक यदि 100 मान लिया जाए तो 1919 में यह सूचकांक था : आयात—156.4 तथा निर्यात—113.5 ।

चूंकि चीनी राष्ट्रीय पूँजीवाद केवल तभी विकसित हो पाया था, जब साम्राज्यवादियों ने अस्थाई तौर पर अपने हमलों में ढील दे दी थी, अतः यह स्वाभाविक था कि चीनी राष्ट्रीय उद्योग अविकसित अवस्था में था। 1920 में सूती कपड़ा मिलों में लगे कुल 15,50,840 तकलों में से 41.9 प्रतिशत पर साम्राज्यवादियों का स्वामित्व था, तथा कोयले के 2,13,18,825 टन के कुल उत्पादन में से 50.9 प्रतिशत पर साम्राज्यवादियों का स्वामित्व था। लोहे का कुल उत्पादन, जो कि 2,58,868 टन था, सारे का सारा जापानी पूँजी के नियंत्रण में था।

1915 के आँकड़ों के अनुसार चीन में हस्तशिल्पकारों को मिलाकर कुल एक करोड़ मजदूर थे, जिनमें से 6 लाख, यानी कि 6 प्रतिशत कारखानों में काम करते थे। आधुनिक कारखानों में से ज्यादातर छोटे थे। 1913 में 565 पंजीकृत कारखानों की कुल पूँजी 5 करोड़ चांदी के डॉलर थी। इनमें से 479 फैक्ट्रियों में से प्रत्येक की पूँजी एक लाख डॉलर से कम थी; 66 फैक्ट्रियों में से प्रत्येक की पूँजी एक लाख से पाँच लाख डॉलर के बीच थी तथा केवल 20 (4% से भी कम) में से प्रत्येक की पूँजी ही 5 लाख डॉलर से अधिक थी।

जब बरतानवी, फ्रांसीसी तथा जर्मन साम्राज्यवादी युद्ध में उलझे हुए थे, जापानी तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों ने चीन के विरुद्ध आक्रमण तेज करने में तत्परता दिखाई। यद्यपि युद्ध के दौरान, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने चीन पर अपना शिकंजा अस्थाई तौर पर ढीला कर दिया था, लेकिन यहां पर उनकी शक्ति वैसी की वैसी बनी रही थी और युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपना आक्रमण पुनः शुरू करने तथा उसे और तीव्र करने में तनिक भी समय नहीं गंवाया।

चीन के विरुद्ध साम्राज्यवादी आर्थिक आक्रमण के मुख्य लक्षण इस प्रकार थे :

पहला, ज्यादातर विदेशी पूँजी निवेश प्रत्यक्ष निवेश के रूप में था। साम्राज्यवादियों ने जो फर्में चीन में खोली थीं, उनके माध्यम से उन्होंने चीन के समूचे उद्योग को अपने कब्जे में ले लिया तथा उनकी फैक्ट्रियां, चीनी पूँजीपतियों द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्रियों पर छा गईं। साम्राज्यवादियों द्वारा चीन के औद्योगिक कच्चे माल की लूट के फलस्वरूप चीन के संसाधनों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था तथा उसका भारी उद्योग बहुत ही पिछड़ा रह गया। 1919 में लौह अयस्क का राष्ट्रीय उत्पादन 10,09,542 टन था, जिसमें से 6,62,632 टन निर्यात कर दिया गया। लोहे का उत्पादन 4,42,594 टन था, लेकिन लोहे का आयात 3,25,158 टन था, यानि कुल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत।

दूसरे, विदेशी निवेश मुख्य रूप से वाणिज्यिक होता था। सन् 1914 में विदेशी उद्यमों की कुल पूँजी 100 करोड़ अमरीकी डॉलर थी। इसमें से 83.1 प्रतिशत का निवेश वाणिज्य में किया गया था। औद्योगिक निवेश, यानी उत्पादन व खनन में निवेश केवल 16.9 प्रतिशत था। अधिकतर फैक्ट्रियां माल को संसाधित करने वाली तथा आयातित कलपुर्जों को जोड़ने व उनकी मरम्मत का काम करने वाली फैक्ट्रियां थीं। विदेशी निवेश की बाढ़ ने, जो कि अधिकतर वाणिज्यिक निवेश होता था, चीन की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था के आधार को खोखला कर दिया तथा पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहन दिया, लेकिन सच तो यह है कि चीन के आधुनिक उद्योगों में केवल सूती वस्त्र उद्योग ही कुछ हद तक विकसित हो पाया था।

तीसरे, चीन उस समय कई साम्राज्यवादी देशों के प्रभुत्व में था, लेकिन चीन में उनके आर्थिक आक्रमण का विकास असमान था। 19वीं सदी के अंत तक चीन पर नियंत्रण वाले मुख्य साम्राज्यवादी देश थे : बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस तथा जारशाही रूस। 20वीं सदी के आरंभ में अमरीकी तथा जापानी साम्राज्यवादियों ने अपने आक्रमण तेज कर दिए, जिसके फलस्वरूप चीन पर छः शक्तियों का प्रभुत्व कायम हो गया। ये थीं : ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमरीका तथा जापान। अक्तूबर क्रान्ति के बाद, सोवियत-संघ ने चीन में जारशाही विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया तथा दोनों देशों के बीच सभी असमान संधियों को रद्द कर दिया। युद्ध में पराजय के कारण जर्मनी भी पीछे हट गया। इस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात चीन चार साम्राज्यवादी देशों ब्रिटेन, अमरीका, जापान व फ्रांस की लूटस्थली रह गया।

चीन में पूँजीवाद का विकास तथा चीनी मजदूर वर्ग का विकास एक साथ हुआ। युद्ध के दौरान चीनी मजदूर वर्ग ने अपनी पांतों का विस्तार किया तथा अपनी ताकत में वृद्धि की। चीन में साम्राज्यवादियों द्वारा संचालित उद्यमों की स्थापना के साथ ही पैदा हुआ चीनी मजदूर वर्ग, चीन के राष्ट्रीय पूँजीवाद से पहले अस्तित्व में आया और इस प्रकार चीनी मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की तुलना में अपने लम्बे इतिहास तथा ज्यादा शक्ति पर गर्व है। **साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों ने, चीनी मजदूर वर्ग के रूप में अपनी कब्र खोदने वालों**

को जन्म दिया और इसे दिन-ब-दिन ताकतवर बनाया।

चीनी मजदूर वर्ग, द्रुत गति से 20 लाख की संख्या वाला एक प्रगतिशील वर्ग बन गया, जिसमें राजनीतिक सूझ-बूझ तथा लड़ने की इच्छाशक्ति थी। सामान्य रूप से, मजदूर वर्ग की खास-खास विशेषताएं इसमें विद्यमान थीं, मसलन अत्यधिक विकसित किस्म की अर्थव्यवस्था के साथ इसका संबंध, संगठन के प्रति जोरदार समझ तथा व्यक्तिगत स्वामित्व के उत्पादन साधनों की कमी। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली विकसित किस्म की अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों ने इसे उज्जवल भविष्य वाला वर्ग बना दिया था। फैक्ट्रियों में काम करते हुए, जहां उत्पादन एक संगठित तथा योजनाबद्ध ढंग से होता था और जहां सभी क्रियाकलाप मशीन द्वारा किये जाते थे तथा एक दूसरे पर निर्भर थे, मजदूर वर्ग ने बड़ी जल्दी स्वयं को संगठित कर लिया। मजदूर वर्ग उन वेतनभोगी मजदूरों से बना था जिनके पास उत्पादन के कोई साधन न थे। वे अपनी श्रमशक्ति बेचते थे तथा वेतन से गुजारा करते थे। यही कारण था जिसने मजदूर वर्ग को अन्य सभी वर्गों से अधिक क्रांतिकारी बना दिया। ये बुनियादी विशेषताएं दुनिया भर के मजदूर वर्ग में समान रूप से विद्यमान थीं।

सभी देशों के मजदूरों में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त, चीनी मजदूर वर्ग में बहुत सी विशेषताएं ऐसी भी थीं, जिनका संबंध केवल उसी से था।

प्रथम, चीनी मजदूर वर्ग ने साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा पूँजीवाद का तिहरा जुल्म झेला। आधुनिक उद्यमों में से भी सामंती शोषण की बू आती थी, जैसा कि **श्रम-अनुबन्ध प्रणाली**[10] तथा **शिक्षार्थी प्रणाली**[11] आदि में देखा गया। कार्यदिवस बहुत लंबा होता था, कम से कम 10 घंटे, और कहीं-कहीं तो 16 घंटे। वेतन बहुत थोड़ा था, एक दिन में सिर्फ 20 या 30 **फन**[19], जो एक मजदूर और उसके परिवार को जिन्दा रखने के लिए नाकाफी होते थे। औरतों तथा बच्चों को तो और भी कम वेतन दिया जाता था, हालांकि उन्हें भी दूसरों की तरह ही काफी घंटे काम करना पड़ता था। विदेशी तथा चीनी मजदूरों के वेतन में बहुत ज्यादा असमानता थी। कुछ विदेशी (अंग्रेज) मजदूरों को चीनी मजदूरों से सात गुना तक वेतन मिलता था। फैक्ट्रियों तथा खानों में किसी प्रकार के कोई सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे, क्योंकि पूँजीपति, इंसानों की अपेक्षा अपनी मशीनों को अधिक महत्त्व देते थे। परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होना आम बात थी और असंख्य मजदूर अपंग हो जाते थे अथवा मारे जाते थे। क्योंकि श्रमिक बीमा नहीं था, अतः मजदूरों पर निरन्तर भुखमरी, बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु तथा विकलांगता का साया मंडराता रहता था। स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने, सभा करने, संगठन बनाने और हड़ताल करने पर पूरी पाबंदी थी और उन्हें किसी प्रकार के कोई भी जनवादी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस तिहरे जुल्म तथा शोषण के कारण चीनी मजदूर वर्ग में क्रान्तिकारी संघर्षों के प्रति किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में अद्वितीय दृढ़ इच्छाशक्ति तथा स्पष्टता थी।

दूसरे, चीनी मजदूर वर्ग अत्यंत संकेंद्रित था। ऐसा चीनी उद्योगों के संकेंद्रण से हुआ। जहां तक उद्योगों का संबंध है, रेलवे, खनन, जहाजरानी, सूती वस्त्र उद्योग तथा जहाजरानी निर्माण उद्योग में मजदूर संगठित हुए। भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से वे शंघाई, थ्येनचिन, छिङताओ, ऊहान[12] और कैंटन जैसे बड़े-बड़े शहरों में केंद्रित थे। अंत में, जहां तक कारोबारों का संबंध है, वे आम तौर से बड़े कारोबारों में काम करते थे जहां प्रत्येक कारोबार में 500 से अधिक कामगार होते थे। पेकिङ सरकार के कृषि तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 1919 में संकलित

3.

- **चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का उदय ।**
- **हुनान में श्रमिक-वर्ग आंदोलन ।**
- **पेकिङ-हानखओ रेलवे के श्रमिकों की विशाल राजनीतिक हड़ताल ।**

जुलाई 1921 में स्थापना के बाद पार्टी ने अपने प्रयासों को श्रमिक-वर्ग के आंदोलन के मार्गदर्शन पर केन्द्रित किया । पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्काल बाद श्रमिकों के संघर्षों का मार्गदर्शन करने के लिए चीनी ट्रेड यूनियन सचिवालय (The Chinese Trade Union Secretariat) की स्थापना की गई । इसके मुख्य कार्य समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित करना, श्रमिकों के लिए क्लब तथा रात्रि-स्कूल स्थापित करना तथा दिन-प्रतिदिन के संघर्षों में उनका मार्गदर्शन करना था । पार्टी के सही नेतृत्व तथा चीनी श्रमिक वर्ग के क्रांतिकारी उत्साह की बदौलत जनवरी 1922 से लेकर फरवरी 1923 तक श्रमिकों की हड़तालों का पहला विशाल उभार आया । यह जनवरी 1922 में हांगकांग के नाविकों की हड़ताल से आरंभ हुआ तथा फरवरी 1923 में पेकिङ-हानखओ रेलवे के श्रमिकों की विशाल राजनीतिक हड़ताल के साथ चरम बिन्दु पर पहुँच गया । कुल मिलाकर यह लहर तेरह महीनों तक चली तथा इसके दौरान छोटी-बड़ी लगभग 100 हड़तालें हुईं तथा इनमें 3,00,000 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया । इनमें से अधिकतर हड़तालों को पूर्ण सफलता का श्रेय प्राप्त हुआ । इन विजयों से प्रोत्साहित होकर श्रमिक, कम्युनिस्टों द्वारा मार्गदर्शित ट्रेड-यूनियनों में शामिल होने के लिए टूट पड़े । श्रमिक-वर्ग आंदोलन तथा श्रमिक संगठनों के निरंतर विस्तार से चीन के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में श्रमिक-वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका और भी स्पष्ट हो गई ।

12 जनवरी, 1922 को हांगकांग की विदेशी जहाजरानी कंपनियों के नाविक हड़ताल पर चले गए । चीनी नाविक तरह-तरह के दमन झेलते आ रहे थे । उन्हें बहुत ही तुच्छ वेतन मिलता था, जो स्वयं निर्वाह के लिए भी अपर्याप्त था तथा फोरमैन भी उन्हें लूटते थे, क्योंकि उनके पास पूँजीपतियों के साथ मिलीभगत के कारण मज़दूरों को ठेके पर लेने तथा उनकी सिफारिश करने का एकमात्र विशेषाधिकार था । वेतनमानों में अत्यधिक पक्षपात था। एक चीनी नाविक को एक विदेशी नाविक के वेतन का केवल पाँचवां हिस्सा मिलता था । सबसे बड़ी बात राजनीतिक असमानता की थी । युद्धेतर विश्व के उमड़ते क्रांतिकारी ज्वार के प्रभाव से चीनी नाविकों में बड़ी जल्दी वर्ग चेतना आ गई । वेतनमानों में वृद्धि तथा श्रमिकों की अनुशंसा का अधिकार ट्रेड-यूनियनों को देने की मांगों के लिए हड़ताल हो गई । चीनी नाविकों के संघ के नेतृत्व में 30,000 से भी अधिक नाविकों तथा ट्रांसपोर्ट श्रमिकों ने हड़ताल की । नाविकों की हड़ताल आरंभ होने के बाद, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट श्रमिकों ने सहानुभूति दर्शाते हुए हड़ताल की, फिर हांगकांग के सभी श्रमिकों की आम हड़ताल का आह्वान किया गया । हड़ताल को देश भर के श्रमिकों से भी समर्थन मिला । हड़ताल तोड़ने के लिए हांगकांग सरकार ने सभी संभव हथकण्डे अपनाए, जैसे रिश्वत, बल-प्रयोग, मध्यस्थता, श्रमिकों में फूट के बीज बोना तथा हड़ताल-भेदिये श्रमिकों की नियुक्ति करना । लेकिन हड़तालियों ने इन सभी चालबाजियों को चकनाचूर कर दिया । नाविकों की मुख्य रणनीति हांगकांग की नाकेबन्दी करना थी, जो

चुङ-श्याङ तथा ली चुङ-च्यी को पदच्युत करने पर विवश कर दिया। इसने पेरिस कांफ्रेंस में गए चीनी प्रतिनिधिमंडल को भी वार्सेल्स की संधि पर हस्ताक्षर न करने को विवश किया। इस प्रकार 4 मई के देशभक्तिपूर्ण आंदोलन ने एक महान विजय प्राप्त की।

4 मई आंदोलन के दौरान हुई श्रमिकों की विशाल राजनीतिक हड़तालों ने चीनी जनता के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की विजय को और नजदीक ला दिया तथा चीनी श्रमिक वर्ग की विशाल शक्ति का प्रदर्शन भी किया । ऐसे में एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता महसूस हुई जो श्रमिक वर्ग के हितों का पक्ष लेती तथा जिसे यह मालूम होता कि संघर्ष में उनका नेतृत्व कैसे किया जाए । इसी कारण से चीन में श्रमिक वर्ग के आंदोलन के साथ मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत का शीघ्र एकीकरण हुआ, तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए वर्ग-आधार तैयार हुआ ।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के आगमन से पूर्व चीन के क्रांतिकारी निम्न-पूँजीपति वर्ग ने तथा पूँजीपति वर्ग के बुद्धिजीवियों ने बड़े जोर-शोर से जनवादी संस्कृति का प्रचार किया था । उन्होंने लोकतन्त्र की पैरवी की तथा राजशाही व युद्धपतिवाद का विरोध किया । पुरानी परिपाटियों तथा अनाप-शनाप अंधविश्वासों, अंधश्रद्धा, हठधर्मिता तथा प्राचीन नैतिक आचार-संहिता जिससे सामन्ती शासक वर्ग का हितपोषण होता था, की बजाय उन्होंने विज्ञान को अधिमान दिया । सैद्धांतिक मोर्चे पर संघर्ष ने सैद्धांतिक अभिव्यक्ति के दो माध्यमों—भाषा तथा साहित्य—में अनिवार्य रूप से सुधार किए । परिणामस्वरूप उन्होंने लिखने की शास्त्रीय शैली के स्थान पर देशी भाषा तथा प्राचीन साहित्य के स्थान पर नए साहित्य की पैरवी की ।

'न्यू यूथ' (New Youth) तथा **'वीकली रीव्यू' (Weekly Review)** अत्यधिक प्रभावशाली पत्रिकाएं थीं जिन्होंने जनवादी संस्कृति का प्रचार किया । पहली पत्रिका सितंबर 1915 तथा दूसरी दिसम्बर 1918 में आरंभ की गई । इन दो पत्रिकाओं ने प्राचीन सामंती सिद्धातों तथा मतवादों पर निरंतर प्रहार किया । जनवादी संस्कृति के समर्थकों में **ली ता-चाओ**[17], छन तू-श्यू तथा **लू शुन**[18] प्रमुख थे ।

ली ता-चाओ चीन में मार्क्सवाद को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे । 1918 के अंत में, उन्होंने अक्तूबर समाजवादी क्रांति का प्रचार करना शुरू किया **तथा** पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि रूसी क्रांति की विजय बोल्शेविकवाद (BOLSHEVISM) की विजय थी, क्योंकि जिस सिद्धांत ने सर्वहारा समाजवादी क्रांति को विजय दिलाने में अगुवाई की, वह बोल्शेविकवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अतिरिक्त कोई अन्य न था । यह घोषणा अत्यधिक महत्त्व की थी ।

उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि प्रथम विश्वयुद्ध पूँजीवाद के पतन व पराजय तथा जनसाधारण व लोकतंत्र की विजय का द्योतक था, जनता के नये लोकतंत्र का द्योतक था ।

उन्होंने **'मार्क्सवादी अर्थ-सिद्धांत'** तथा **'इतिहास के भौतिकवादी अवलोकन'** की व्याख्या की । उनका कहना था कि इतिहास का भौतिकवादी अवलोकन एक मार्गदर्शक शक्ति था जो व्यक्ति को सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष करने के योग्य बनाता था तथा उसे कार्योन्मुख करने के लिए जुझारू शक्ति प्रदान करता था । ली ता-चाओ को चीनी श्रमिक वर्ग की जागरूकता का पूर्वाभास हो गया था तथा उन्होंने अपने तथा अन्य मार्क्सवादियों के चीनी

श्रमिक वर्ग के आंदोलन के प्रति समर्पित होने के संकल्प की घोषणा की ।

1918 से 1919 तक 'न्यू यूथ' में मार्क्सवाद के अध्ययन, सोवियत-संघ व चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन आदि पर काफी लेख छपे । अक्तूबर क्रांति के प्रभाव में आकर, चीन में क्रांतिकारी बुद्धिजीवी जागृत होने लगे तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रसार एक सचेतन आंदोलन बन गया ।

नया सांस्कृतिक आंदोलन तीन विचारधाराओं के बुद्धिजीवियों के संयुक्त सांस्कृतिक मोर्चे के क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, ये थे : साम्यवादी, निम्न-पूँजीपति तथा पूँजीपति। संयुक्त मोर्चे में सर्वहारा सिद्धांत तथा पूँजीवादी सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी थे ।

'न्यू यूथ' तथा 'वीकली रीव्यू' के समाजवादी रुझानों ने पूँजीपति वर्ग का असंतोष भड़का दिया । सर्वहारा दृष्टिकोण का निरंतर विस्तार होने से संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया । 4 मई, 1919 के आंदोलन के थोड़े समय पश्चात्, दक्षिणपंथी पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हू-श ने वीकली रीव्यू के जुलाई अंक में *''समस्याओं के विषय में ज्यादा तथा 'वादों' (isms) के विषय में कम''* शीर्षक से एक लेख छापा, जिसमें उसने चीन के अन्दर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रचार-प्रसार का खुलकर विरोध किया ।

ली ता-चाओ ने हू-श का सशक्त प्रतिवाद करते हुए साफ-साफ कहा कि ''वाद'' समस्याएं हल करने के लिए एक दृष्टिकोण, एक सिद्धांत तथा एक ढंग होता है । तथा ''वादों'' की अनभिज्ञता का अर्थ—वस्तुनिष्ठ यथार्थता के नियमों की अनभिज्ञता होना है तथा इन नियमों की जानकारी के बिना कोई भी, किसी भी प्रकार की ''समस्याएं'' हल करने की आशा नहीं कर सकता । चीन की समस्या को एक बुनियादी समाधान की दरकार है । यह बुनियादी समाधान व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का अनिवार्य आधारतत्व है । चीन की बुनियादी समस्या का अध्ययन करने तथा उसे हल करने में जो ''वाद'' लोगों की सहायता करेगा वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अलावा और कोई न था, यही एकमात्र सही ''वाद'' था जो चीनी क्रांति का मार्गदर्शन कर सकता था ।

''समस्याओं'' तथा ''वादों'' के विषय में हू-श के विचारों का ली ता-चाओ द्वारा खण्डन, सर्वहारा सिद्धान्त का पूँजीवादी सिद्धांत के विरुद्ध पहला जवाबी हमला था । इसने पूँजीवाद द्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद की तोड़-मरोड़ तथा मिथ्यापवाद को भारी क्षति पहुंचाई तथा हठवाद की आलोचना की, जो साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद-सुधारवाद के युग में पूँजीवाद का प्रतिक्रियावादी दर्शन था । इस प्रकार चीन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रभाव का विस्तार हुआ। इस वाद-विवाद के पश्चात हू-श के प्रतिनिधित्व वाले पूँजीपति वर्ग के दक्षिण पक्ष ने समझौते तथा आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया । ●

5.

● चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का मार्क्सवाद-लेनिनवाद के साथ एकीकरण।
● कामरेड माओ त्से-तुङ की शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियां ।

मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के और ज्यादा प्रसार के लिए तथा श्रमिकों के बीच प्रचार एवं

केन्द्रीय युद्ध-सरदारों के हाथों के औजार भर बन कर रह जाने थे तथा प्रादेशिक स्वायत्तता स्थानीय युद्ध-सरदारों में तू-तू, मैं-मैं तथा युद्धों का बहाना बन जानी थी । वे युद्ध-सरदार, जिनका लक्ष्य अपनी सत्ता का विस्तार करना था, बल प्रयोग द्वारा चीन के एकीकरण की पैरवी करते या एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की पैरवी करते जब कि प्रादेशिक नियंत्रण वाले युद्ध-सरदार स्वायत्तशासी प्रदेशों के संघ की पैरवी करते । अत: युद्ध-सरदार प्रणाली के तहत केन्द्रीय या स्थानीय सरकारों के लिए, स्वयं को युद्ध-सरदारों की तानाशाही से मुक्त रखना असंभव था ।

इस प्रकार चीनी साम्यवादियों ने पूँजीवादी सुधारवाद की विभिन्न गलतियों की आलोचना की तथा स्पष्ट किया कि क्वोमिंताङ का जनवादी गुट अपने क्रांतिकारी प्रयासों में निश्चित रूप से इसी स्पष्टता की कमी के कारण लगातार असफल हुआ था । इस क्रांतिकारी जनवादी कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी जनवादियों का आह्वान किया, ताकि साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा जा सके।

दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम तथा राजनीतिक कार्यदिशा की आधारशिला रखी, जब कि पहली राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसके संगठनात्मक सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। तथापि, दूसरी कांग्रेस में भी कई कमजोरियां थीं—विशेषकर सर्वहारा नेतृत्व के प्रश्न को लेकर। यद्यपि इसने यह तो स्पष्ट किया कि अन्ततोगत्वा सर्वहारा वर्ग, क्रांति का अगुवा वर्ग बन जाएगा, फिर भी तात्कालिक पूँजीवादी-जनवादी क्रांति में सर्वहारा नेतृत्व की आवश्यकता पर बल देने में यह कांग्रेस असफल रही, उलटे यह मत व्यक्त किया गया कि ''पार्टी का कार्य मजदूरों का केवल इस बात के लिए मार्गदर्शन करना था कि वे जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग दें ।'' इसका अर्थ था—जनवादी क्रांति में सर्वहारा की नेतृत्वकारी भूमिका छीनकर उसे पूँजीपति वर्ग के सहायकमात्र की भूमिका प्रदान करना । इसके साथ ही यह कांग्रेस श्रमिकों तथा किसानों की राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की मांग तथा किसानों की जमीन के लिए मांग को पेश करने में असफल रही, क्योंकि इसने केवल इतना विचार किया था कि जनवादी क्रांति की सफलता के बाद श्रमिकों तथा किसानों को ''कुछ अधिकार'' प्राप्त हो जाएंगे । इसने इस तथ्य को ओझल होने दिया कि सर्वहारा वर्ग की अगुवाई में तथा श्रमिक-किसान संश्रय पर आधारित जनता के जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना न केवल अत्यंत आवश्यक तथा संभव थी बल्कि चीन में समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना का एकमात्र रास्ता भी यही था, तथा इसके बीच पूँजीपति वर्ग की तानाशाही की कालावधि के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी । छन तू-श्यू के दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट द्वारा 1924 से 1927 तक के क्रांतिकाल के दौरान, इन कमजोरियों को और बढ़ावा दिया गया तथा पार्टी की नीति में गंभीर भटकाव आया, जिसके परिणामस्वरूप क्रांति को भारी क्षति उठानी पड़ी ।

कांग्रेस ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में सम्मिलित होने तथा 'दि गाइड' के शीर्षक से पार्टी का साप्ताहिक मुखपत्र छापने का निर्णय लिया । 'दि गाइड' का शुभारंभ सितंबर 1922 में हुआ तथा इसने क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे की पैरवी करने तथा साम्राज्यवाद-विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी विचारों के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । ●

अफीम-युद्ध से शुरू हुई थी, अब तक बहुत से संघर्षों से गुज़र चुकी थी, लेकिन 4 मई आंदोलन से पहले इसके किसी भी नेता ने स्पष्ट रूप से यह महसूस नहीं किया था कि इसका बुनियादी कार्यभार साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध करना था । इन नारों को पहली बार दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी की मूलभूत राजनीतिक कार्यदिशा तथा चीनी जनता के मुक्ति-आंदोलन के लिए आधारभूत कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया । इस प्रकार पार्टी ने स्वयं को चीनी क्रांति का एक सुयोग्य नेता साबित किया, जो उसे विजय दिलाने में समर्थ था ।

चूँकि यह क्रांतिकारी जनवादी कार्यक्रम किसी पूँजीवादी सुधारवादी कार्यक्रम से मूलतः भिन्न था, स्वभावतः पूँजीवादी सुधारवादियों की ओर से इसका विरोध भी किया गया ।

जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में प्रथम बार साम्राज्यवाद के बिरोध का नारा प्रस्तुत किया, हू-श तत्काल चिल्ला पड़ा, ''ऐसा अवलोकन पूर्णरुपेण आधारहीन है, यह ऐसे ही है जैसे ग्रामीण लोग एक अद्‌भुत संसार के रहस्यों की बात करते हैं ।'' अपने विशेष प्रकार के तर्क से उसने साम्राज्यवाद का बचाव करने का प्रयास किया तथा जोर देकर कहा किं अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देश, सभी ''शांतिपूर्ण तथा एकताबद्ध'' चीन देखना चाहते थे तथा वाशिंगटन कांग्रेस वास्तव में ''चीन को अमरीकी सहायता'' की अभिव्यक्ति थी, कि अमरीका द्वारा संगठित नया बैंकिग सहायता-संघ ''नुकसान'' पहुँचाने के इरादे से नहीं था, कि चीन में साम्राज्यवादी निवेश का मकसद ''चीन की भलाई'' के लिए था तथा इस प्रकार और भी बहुत कुछ उसने कहा । उसने इस निरर्थक दलील को कि ''अब चीन में विदेशी आक्रमण का ज्यादा खतरा नहीं है'' चीनी जनता के गले मढ़ने का प्रयास किया; अतः उसने समाचार-पत्रों में ''विदेशी साम्राज्यवाद के उल्लेख'' का विरोध किया । साम्राज्यवाद के इस पालतू कुत्ते ने उस समय अपना मुखौटा उतार फेंका जब उसने यह दावा किया कि चीन का जनवाद के लिए संघर्ष तथा विदेशी साम्राज्यवाद दोनों एक-दूसरे से जरा भी संबन्धित नहीं थे ।

पूँजीवादी सुधारवादी, जनवाद को किसी संसद, राष्ट्रपति, संविधान, ''शरीफजादों की सरकार'', स्वायत्तशासी प्रदेशों के संघ या इसी प्रकार के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा प्राप्त करने की सोचते थे । वे इस बात को संभव मानते थे कि युद्ध-सरदारों की सरकार के तहत एक पूँजीवादी संसदीय प्रणाली कायम की जा सकती थी । संसद की पुनर्स्थापना करने, संविधान का निर्माण करने, तथा उत्तरी दक्षिणी चीन में शांति-वार्ता को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने पेकिङ की केन्द्रीय सरकार में एक सुधारवादी मंत्रीमण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा (जिसे वे ''शरीफजादों की सरकार'' के समकक्ष मानते थे)। स्थानीय सरकारों के संबंध में उन्होंने प्रादेशिक स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा क्योंकि उनका विचार था कि एक ''एकताबद्ध सरकार'' चीन के लिए अनुपयुक्त थी । उनका कहना था कि सबसे अच्छा तरीका स्थानीय विधान पालिकाओं की शक्ति में वृद्धि करना था, जिससे वे युद्ध-सरदारों को ''नियन्त्रण में रख'' सकती थीं ।

ऐसी योजना द्वारा पूँजीवादी सुधारवादियों ने युद्ध-सरदारों की सरकार से कुछ राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास किया । वे इस इच्छाजनित धारणा के भी शिकार हुए कि जमींदार, अफसरशाह तथा युद्ध-सरदार, पूँजीपति वर्ग के सदस्य बन जाएंगे । निस्सन्देह यह खाका, जिसमें सामंती युद्ध-सरदारों का प्रतिक्रियावादी शासन अक्षुण्ण रखा गया था, कहीं भी नहीं ले जा सकता था । तथाकथित संसद, राष्ट्रपति, संविधान, शरीफजादों की सरकार वगैरा-वगैरा,

संगठन संबंधी कार्य जारी रखने के लिए, चीनी कम्युनिस्टों ने 1918 में शंघाई में एक *मार्क्सवादी अध्ययन समिति* की स्थापना की तथा 1919 में पेकिङ में भी ऐसी ही एक अन्य समिति की स्थापना की । इसी आधार पर सारे देश में एक के बाद एक *'साम्यवादी तथा समाजवादी नौजवान लीग'* के ग्रुपों की स्थापना की गई । मई 1920 में शंघाई में एक कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना की गई, सितम्बर में पेकिङ में एक और, तथा इसी वर्ष के अंत में कैंटन में भी एक ग्रुप की स्थापना की गई । ये तीनों शहर उस समय चीन के खूब विकसित राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र थे । बाद में हुनान, हुपे तथा शानतुङ प्रांतों में तथा टोकियो एवं पेरिस में पढ़ रहे चीनी विद्यार्थियों में भी कम्युनिस्ट ग्रुपों की स्थापना की गई ।

मार्क्सवादी अध्ययन समितियों तथा कम्युनिस्ट ग्रुपों के नेतृत्व में मार्क्सवाद-लेनिनवाद का एक राष्ट्रव्यापी प्रचार आंदोलन आरंभ किया गया । 'न्यू यूथ' प्रैस ने योजनाबद्ध तरीके से मार्क्स तथा ऐंगल्स के **''कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र''** तथा ऐंगल्स के **''समाजवाद, आदर्श तथा विज्ञान''** जैसे कम्युनिस्ट शास्त्रीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करना आरंभ कर दिया । उसने समाजवादी सिद्धांत की पुस्तकें, मसलन **''वर्ग संघर्ष''** तथा **''समाजवाद का इतिहास''** आदि भी प्रकाशित कीं । 1 मई 1920 को 'न्यू यूथ' ने मई दिवस विशेषांक निकाला, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रमिक-वर्ग के आंदोलनों पर लेख, शंघाई स्थित हओशङ सूती कपड़ा मिल में कार्यरत हुनान की महिला श्रमिकों के बीच की परिचर्चा पर सामग्री तथा चीन के विभिन्न भागों में श्रमिकों के हालात पर खोजपूर्ण रपटें थीं । उस पत्रिका में एक लड़ी के रूप में, **'रूस का अध्ययन'** शीर्षक से एक लेखमाला भी प्रकाशित की गई । शंघाई के कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना के उपरान्त, न्यू यूथ इसका आधिकारिक मुखपत्र बन गया । नवम्बर 1920 में शंघाई के कम्युनिस्ट ग्रुप ने **''दी कम्युनिस्ट पार्टी''**, नामक एक मासिक पत्र निकाला, जिसमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद, रूसी क्रान्ति, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों पर लेख थे ।

चीनी कम्युनिस्टों ने श्रमिकों के बीच प्रचार तथा संगठनात्मक कार्य भी जारी रखा । पेकिङ ग्रुप ने पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर श्रमिकों के लिए रात्रि स्कूल खोले तथा **''श्रमिक की आवाज''** नामक श्रमिकों की पत्रिका निकाली । 1 मई 1920 को चाङशिनथ्येन के श्रमिकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया तथा एक श्रमिक संघ (ट्रेड-यूनियन) बनाने का निर्णय लिया, जो कि बाद में ''मजदूर क्लब'' के नाम से स्थापित किया गया । चाङशिनथ्येन की गतिविधियों ने उत्तरी चीन के अन्य भागों में भी श्रमिक संघ (ट्रेड-यूनियन) आंदोलन को प्रोत्साहित किया ।

पश्चिमी उपनगरों में श्याओशातू को आरंभिक बिंदु मानते हुए शंघाई के कम्युनिस्ट ग्रुप ने श्रमिकों के स्कूल चलाए तथा **''श्रमिक विश्व''** नामक पत्रिका निकाली । मजदूर इसके पाठक थे । इसने सीधी-सादी, स्पष्ट तथा हृदयग्राही भाषा में लेख छापे । इसने समाजवाद तथा मार्क्सवाद के आर्थिक सिद्धांतों की सामान्य भाषा में व्याख्या की । संगठनात्मक कार्य करने के लिए कम्युनिस्ट, मेहनतकश जनता के बीच में गए । सबसे पहले, ''श्रमिक विश्व'' के एक विशेष स्तंभ में श्रमिकों के पत्र नियमित रूप से छापे गए, जिससे श्रमिकों के बीच आपस में तथा श्रमिकों और कम्युनिस्टों के बीच संपर्क स्थापित हुए । शंघाई के कम्युनिस्ट ग्रुप के नेतृत्व में **'यांत्रिकों के श्रमिक संघ'** (The Machinist's Trade Union) की स्थापना हुई । यह

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के श्रमिक-वर्ग आंदोलन के साथ संश्लेषण की उपज थी । बाद में छापाखाना तथा सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की ट्रेड-यूनियनों की स्थापना हुई ।

चाङशिनथ्येन तथा श्याओशातू ऐसे आधार-स्थल थे, जहां से चीनी कम्युनिस्टों ने श्रमिक संघ आंदोलन आरंभ किया । फिर कैंटन ग्रुप ने श्रमिक-स्कूल स्थापित करके तथा **''श्रमिक की गूंज''** नामक पत्रिका प्रकाशित करके उनके उदाहरण का अनुसरण किया । हुनान तथा अन्य स्थानों के ग्रुपों ने भी श्रमिकों के बीच प्रचार तथा संगठनात्मक कार्य जारी रखा ।

इन गतिविधियों ने चीनी श्रमिक वर्ग को जागृत किया तथा शक्तिशाली बनाया, तथा इस प्रकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक व संगठनात्मक स्तर पर आधार तैयार कर दिया तथा इसके लिए आवश्यक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया ।

इस समय के दौरान कामरेड माओ हुनान में क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे । 1917 में हुनान में प्रथम प्रोविंशियल नॉर्मल स्कूल में अपने अध्ययन काल के दौरान उन्होंने नई संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए **''न्यू पीपल्स स्टडी सोसाइटी''** का गठन किया । अगले वर्ष वे पेकिङ गए तथा वहां पेकिङ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कार्य किया । राजनीतिक सिद्धांतों में उनकी अटूट दिलचस्पी ने उन्हें मार्क्सवाद अपनाने को प्रेरित किया । इस प्रकार इस नौजवान बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में साम्यवाद के बुनियादी सिद्धांत घर कर गए ।

माओ त्से-तुङ 1919 में हुनान लौटे । 4 मई आंदोलन के फूटते ही उन्होंने प्रांतीय राजधानी छाङशा में साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का मुस्तैदी से नेतृत्व किया । उन्होंने **'श्याङ-च्याङ रीव्यू'** नामक पत्रिका की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा युद्धपतिवाद का विरोध किया तथा लोकतन्त्र और नई संस्कृति की पैरवी की । इस पत्रिका का प्रभाव दक्षिणी चीन के सभी प्रांतों में पहुंच गया । साथ ही उन्होंने हुनान के विद्यार्थियों तथा क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को, हुनान से युद्ध-सरदारों को खदेड़ बाहर निकालने के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए संगठित किया ।

1920 में उन्होंने हुनान में **'मार्क्सवादी अध्ययन समिति'** की आधारशिला रखी तथा **'समाजवादी यूथ लीग'** की स्थापना की, जिसने उनके नेतृत्व में श्रमिक वर्ग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे मार्क्सवाद-लेनिनवाद के साथ जोड़ दिया ।

उनके नेतृत्व की बदौलत हुनान में एक सुदृढ़ सैद्धान्तिक तथा सांगठनिक आधार तैयार हुआ तथा कम्युनिस्ट पार्टी की हुनान शाखा स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये गए ।

नोट

1. **अफीम युद्ध :-** अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन ने विशाल मात्रा में अफीम चीन भेजनी शुरू कर दी । 19 वीं सदी के मध्य में जाकर चीनी जनता को अपनी राष्ट्रीय जीवन शैली पर इस मादक-द्रव्य व्यापार के घातक प्रभावों तथा मुद्रा-भंडार में इसके द्वारा लगाई जा रही सेंध का पता चला तथा उसने इसका जोरदार प्रतिरोध किया । अपने व्यापार की सुरक्षा करने का बहाना बनाकर ब्रिटेन ने सन् 1840 में चीन पर आक्रमण कर दिया । चीनी फौज ने लिन त्से-श्वी के नेतृत्व में प्रतिरोध किया तथा कैंटन के लोगों ने तुरत-फुरत ''बरतानिया-दमन-कोर'' का गठन किया । परन्तु 1842 में भ्रष्ट

गया।

पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस जुलाई 1922 में शंघाई में हुई । इसमें 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 123 पार्टी-सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे । कांग्रेस ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों को लागू करके, चीनी क्रान्ति के कार्यक्रमों की समस्या को सही तौर से निपटाया । कांग्रेस के घोषणापत्र में चीनी क्रान्ति की समस्याओं से संबंधित पार्टी की टिप्पणियां तथा निष्कर्ष थे ।

इस घोषणापत्र के तीन हिस्से थे । पहले भाग में, पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक बाजारों पर अनिवार्य निर्भरता तथा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया था कि अस्सी वर्षों से विदेशी आक्रमण में पिसने के बाद चीन उनके सबसे बड़े साँझे उपनिवेश में परिवर्तित हो गया था । इसमें पेरिस कांफ्रेंस तथा वाशिंगटन कांफ्रेंस की साम्राज्यवादी प्रकृति का, विशेषकर साम्राज्यवादियों के **''साँझे आक्रमण''** की नई परिस्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया जो वाशिंगटन कांफ्रेंस के बाद चीन में उत्पन्न हो गई थी । युद्धेतर विश्व में दो प्रतिद्वन्द्वी शिविरों के अस्तित्व पर भी इसमें प्रकाश डाला गया । प्रति-क्रांतिकारी साम्राज्यवादी शिविर—जिसकी मन्शा एकजुट होकर सर्वहारा तथा दबे-कुचले राष्ट्रों को लूटने की थी तथा सर्वहारा क्रांति की राष्ट्रीय क्रांति के साथ एकता के द्वारा बनाया गया क्रांतिकारी शिविर । क्रांतिकारी शिविर, साम्राज्यवाद की कब्र खोदने के लिए कृत-संकल्प था ।

दूसरे भाग में चीनी समाज की प्रकृति, चीनी क्रांति की प्रकृति तथा उसकी प्रेरक शक्तियों का विश्लेषण किया गया था । चीन एक अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सांमती समाज था जिसका सामना एक साम्राज्यवाद-विरोधी तथा सामंतवाद-विरोधी क्रांति से, एक राष्ट्रीय जनवादी क्रांति से था । क्रांति की प्रेरक शक्तियों ने श्रमिक वर्ग, किसान समुदाय तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग को अंगीकार किया । राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग भी एक क्रांतिकारी ताकत था।

घोषणापत्र के तीसरे भाग में पार्टी के अधिकतम तथा न्यूनतम कार्यक्रमों को रखा गया था, जो कि कांग्रेस में विचार-विमर्श का मुख्य मुद्दा था । घोषणापत्र में कहा गया **''चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी है । इसका लक्ष्य सर्वहारा को संगठित कर वर्ग-संघर्ष द्वारा मेहनतकशों तथा किसानों का राजनीतिक अधिनायकत्व स्थापित करना, निजी संपत्ति की प्रणाली का उन्मूलन करना तथा धीरे-धीरे एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है ।''** यह पार्टी का अधिकतम कार्यक्रम था जो इस विश्वास पर आधारित था कि इस देश में केवल साम्यवादी समाज की स्थापना द्वारा ही चीनी जनता पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकती है। घोषणापत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि मौजूदा ऐतिहासिक परिस्थितियों में, चीनी जनता की क्रांति के बुनियादी कार्य थे : **(1) जनता में आपसी फूट का उन्मूलन, युद्ध-सरदारों का तख्ता पलटना तथा आंतरिक शांति की स्थापना करना । (2) अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का जुआ उतार फेंकना तथा चीनी जनता के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना । (3) चीन को सही मायनों में एक जनवादी गणतंत्र में एकबद्ध करना।** यह पार्टी का न्यूनतम कार्यक्रम था । इस प्रकार पार्टी द्वारा चीनी जनता के समक्ष एक वास्तविक क्रांतिकारी जनवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था ।

''साम्राज्यवाद का नाश हो !'' ''सामंती युद्ध-सरदारों का नाश हो !'' ''एक जनवादी गणराज्य का निर्माण करो !'' —ये चीन की जनवादी क्रांति के मुख्य नारे थे । यह क्रांति जो

उसके ये भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण, 1924-27 की क्रान्ति के दौरान पार्टी की भ्रान्तिपूर्ण नीति के रूप में विकसित हुए । चीनी क्रांति की प्रक्रिया के साथ मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त को एकात्म करने के लिए जो व्यापक तथा सही समझ दरकार थी, वह पूरी तरह उसके बस से बाहर की बात थी ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत से ही, कामरेड माओ ने एक नए ढंग की पार्टी के निर्माण की जरूरत पर विशेष ध्यान दिया था ।

पहली राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद कामरेड माओ को हुनान प्रान्त के पार्टी सचिव का पदभार ग्रहण करने के लिए वहाँ वापिस भेज दिया गया । जब वे वहाँ श्रमिक आंदोलन का विस्तार कर रहे थे, उन्होंने न केवल गहरी जांच-पड़ताल की प्रक्रिया द्वारा मौजूदा क्रांतिकारी संगठनों तथा समाजवादी नौजवान लीग के प्रगतिशील तत्वों को पार्टी में समाविष्ट किया बल्कि प्रगतिशील श्रमिकों को भी पार्टी में शामिल किया ।

कामरेड माओ ने पार्टी के सैद्धांतिक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दिया । पार्टी तथा नौजवान लीग के सदस्यों का सैद्धांतिक तथा राजनीतिक स्तर ऊँचा उठाने तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद में पारंगत होकर, जनता के बीच साम्यवादी शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने अगस्त 1921 में **'स्वाध्ययन यूनिवर्सिटी'** (Self Study University) तथा **'नया जमाना'** (New Times) नामक दो मासिक पत्रिकाएं शुरू कीं ।

स्वाध्ययन यूनिवर्सिटी का प्रभाव पेकिङ, शंघाई तथा अन्य दूर-दूर के स्थानों तक फैल गया । देश के बहुत से प्रगतिशील समाचार-पत्रों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । पार्टी की स्थापना के बाद चीनी क्रांति ने मूलत: नया स्वरूप ग्रहण कर लिया ।

जनवरी 1922 में मास्को में लेनिन के मार्गदर्शन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों तथा राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठनों की पहली कांग्रेस का आयोजन किया । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस कांग्रेस में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा । कांग्रेस ने वाशिंगटन कांग्रेस की साम्राज्यवादी प्रकृति का पर्दाफाश किया तथा स्पष्ट किया कि चीन तथा पूर्व के अन्य दबे-कुचले राष्ट्रों के सबसे बड़े शत्रु साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद थे । इसने पूर्व के दबे-कुचले राष्ट्रों तथा पश्चिम के सर्वहारा वर्ग के बीच मैत्री की आवश्यकता पर बल दिया । इसलिए चीनी जनता तथा अन्य पूर्वी देशों की जनता का कार्य रूसी सर्वहारा तथा पश्चिमी देशों के सर्वहारा की मदद से एक साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी राष्ट्रीय जनवादी क्रांति लाना था ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इस कांग्रेस का अत्यधिक महत्त्व था । यद्यपि पार्टी का अंतिम लक्ष्य जैसा कि इसकी स्थापना के समय घोषित किया गया था, चीन में साम्यवाद की स्थापना करना रखा गया था, पर इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अभी अस्पष्ट ही था, तो भी लेनिनवाद के अनुसार, अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती देशों में एक समाजवादी तथा फिर साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए तात्कालिक कार्य एक साम्राज्यवाद-विरोधी तथा सामंतवाद-विरोधी क्रांति लाना था ।

मास्को कांग्रेस से लौट कर, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया, जिसमें उपनिवेशों तथा अर्ध-उपनिवेशों में क्रान्ति करने के लिए लेनिनवादी सिद्धांतों के आधार पर पार्टी का अधिकतम तथा न्यूनतम प्रोग्राम निर्धारित किया

मंचू सरकार ने ब्रिटेन के साथ नानकिङ की संधि पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके तहत उसने ब्रिटेन की क्षतिपूर्ति की; हांगकांग उसके हवाले कर दिया; शंघाई, फूचओ, अमेइ, निङपो तथा कैंटन की बंदरगाहें ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दीं तथा ब्रिटेन से आयातित सामान पर संयुक्त रूप से टैक्स लगाना निश्चित किया ।

2. 1894 का चीन-जापान युद्ध :- यह युद्ध कोरिया पर हमला करने तथा चीन की जल तथा थल सेनाओं को उकसाने के कारण छिड़ा । यद्यपि चीनी सशस्त्र सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ीं, परन्तु मंचू सरकार के भ्रष्टाचार, एवं हमले के खिलाफ दृढ़तापूर्वक लड़ाई करने के लिये तैयार न होने के कारण, चीन अगले साल ही पराजित हो गया और इसका नतीजा शिमोनोशकी (बकान) की अपमानजनक संधि के रूप में निकला, जिसके तहत मंचू सरकार ताएवान तथा फङहू द्वीप समूह को जापान के हवाले करने; 20 करोड़ ताइल चांदी (1 ताइल=1.33 आउंस) क्षतिपूर्ति के रूप में देने; जापानियों को चीन में फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत देने; शासी, छुङकिङ, सूचओ तथा हाङचओ बंदरगाहों को सन्धि बंदरगाहों के रूप में खोलने तथा कोरिया को जापान की गुलामी के तहत रखने पर सहमत हो गई ।

3. आठ शक्तियों की संयुक्त सेना का आक्रमणकारी युद्ध :- सन् 1900 में उत्तरी चीन में किसानों तथा हस्तशिल्पकारों का एक विशाल स्वत: स्फूर्त जन आंदोलन—**ई हो थ्वान (बॉक्सर) आंदोलन**—फूट पड़ा । धर्म तथा अन्धविश्वासों के आधार पर ये किसान तथा दस्तकार स्वयं को गुप्त संस्थाओं में संगठित कर लेते थे तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाते थे । इस पर आठ साम्राज्यवादी शक्तियों—ब्रिटेन, अमरीका, जापान, जर्मनी, जारशाही रूस, फ्रांस, इटली तथा आस्ट्रिया—की संयुक्त फौजों ने पेकिङ तथा थ्येनचिन पर कब्जा कर लिया और बेहद निर्ममतापूर्वक आन्दोलन का दमन कर दिया । आखिरकार मंचू सरकार को 1901 की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े।

4. थाएफिङ क्रान्ति :- थाएफिङ का क्रांतिकारी युद्ध, छिङ वंश के सामंती शासन तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ 19वीं सदी के मध्य में किया गया एक क्रांतिकारी किसान युद्ध था । जनवरी 1851 में हुङ श्यू-छ्वान, याङ श्यू-छिन तथा इस क्रान्ति के अन्य नेताओं ने क्वाङशी प्रान्त की क्वेइफिङ काउन्टी के चिनथ्येन गांव में विद्रोह कर दिया तथा थाएफिङ स्वर्गिक राज्य की स्थापना की घोषणा की । 1852 में विद्रोही सेना ने क्वाङशी से उत्तर की ओर बढ़कर हुनान, हुपे, च्याङशी और आनह्वेइ से गुजरते हुए अभियान किया तथा 1853 में नानकिङ शहर पर कब्जा कर लिया । इसके बाद इस सैन्य-दल का एक हिस्सा नानकिङ से उत्तर की ओर बढ़ता गया तथा थ्येनचिन के निकट पहुंच गया। परन्तु थाइफिङ सेना ने अनेक राजनीतिक तथा फौजी गलतियां कीं तथा वह छिङ सरकार की प्रतिक्रान्तिकारी सेना व साम्राज्यवादियों के आक्रमण का मुकाबला न कर सकी और 1864 में पराजित हो गई । ('माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1971, पृष्ठ-304) ।

5. 1911 की क्रान्ति :- यह छिङ वंश की तानाशाह सरकार का तख्ता उलटने के लिए छेड़ी गई क्रान्ति थी । 10 अक्तूबर 1911 को "नई सेना" के एक हिस्से ने पूँजीपति वर्ग और निम्न-पूँजीपति वर्ग के क्रान्तिकारी संगठनों से प्रेरित होकर ऊहाङ में विद्रोह कर दिया । इसके बाद दूसरे प्रान्तों में भी एक के बाद एक विद्रोह छिड़ गये । परिणामस्वरूप छिङ वंश के शासन का पतन हो गया और 1 जनवरी 1912 को डॉ० सुन यात-सेन के नेतृत्व में नानकिङ में चीनी गणराज्य की अस्थाई सरकार की स्थापना की गई । यह क्रान्ति किसानों, मजदूरों और शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग के साथ पूँजीपति वर्ग द्वारा कायम किये गए संश्रय के जरिये सफल हुई थी । लेकिन इस क्रान्ति के नेता-दल में सुलह-समझौता करने की प्रवृत्ति मौजूद थी; उसने किसानों के असली हितों की रक्षा नहीं की और साम्राज्यवाद व सामंती शक्तियों के दबाव के सामने सिर झुका दिया । इसके फलस्वरूप राजसत्ता य्वान

श-खाए के हाथ में चली गई और क्रान्ति असफल हो गई । (माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण - 1971, पृष्ठ-83) ।

6. य्वान श-खाए :- वह छिङ वंश के अन्तिम वर्षों में उत्तरी युद्ध-सरदारों का मुखिया था । 1911 की क्रान्ति में छिङ वंश का तख्ता उलट दिए जाने के बाद वह गणराज्य का राष्ट्रपति बन बैठा और उसने उत्तरी युद्ध-सरदारों की पहली सरकार बनाई, जो बड़े जमींदारों के वर्ग तथा बड़े दलाल-पूँजीपतियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी । यह सब उसने प्रतिक्रान्तिकारी सशस्त्र सैन्य-शक्ति के सहारे तथा साम्राज्यवादियों के समर्थन से और उस समय क्रान्ति का नेतृत्व करने वाले पूँजीपति वर्ग के समझौतापरस्त स्वरूप का फायदा उठाकर किया । 1915 में उसने अपने को सम्राट बनाना चाहा और जापानी साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जापान की 21 मांगों को भी स्वीकार कर लिया, जिनके द्वारा जापान तमाम चीन पर एकछत्र अधिकार जमाना चाहता था । उसी वर्ष दिसम्बर में उसके सम्राट बनने के विरुद्ध युन्नान प्रान्त में विद्रोह हो गया और तुरन्त ही उस विद्रोह को राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ । जून 1916 में य्वान श-खाए की पेकिङ में मृत्यु हो गई । (माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह पेकिङ, पहला संस्करण, पृष्ठ-292,93)

7. दलाल-पूँजीपति :- ये विदेशी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चीनी प्रबंधक अथवा वरिष्ठ अधिकारी थे, जिन्होंने साम्राज्यवाद तथा विदेशी पूँजी के साथ अपने निकट संबधों का फायदा उठाकर चीनी उद्योग तथा वाणिज्य पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था ।

8. फङथ्येन :- यह शनयाङ (मुकदन) का पुराना नाम था ।

9. तान :- एक तान 50 किलोग्राम के बराबर होता है ।

10. श्रम-अनुबन्ध प्रणाली :- इसके तहत, एजेन्ट, ग्रामीण इलाकों से लड़कियों को मुख्यतया कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए तीन से पांच तक साल की अवधि के लिए अनुबन्धित कर लेते थे। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के समय मामूली सी रकम लड़की के परिवार को दे दी जाती थी । अनुबन्ध की पूरी अवधि के लिए लड़की को किसी भी प्रकार की आजादी से वंचित कर दिया जाता था । उसके रहने एवम् खाने के खर्च के बाद जो भी कमाई बचती थी वह सब एजेन्ट की जेब में चली जाती थी । इस प्रणाली का एक और रूप भी था—जिसमें श्रम-ठेकेदार या गैंग-मास्टर, मजदूरों को नौकरी पर रख लेते थे तथा फिर उन्हें पूँजीपतियों को किराये पर दे देते थे तथा मजदूरों के वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कमीशन के रूप में रख लेते थे ।

11. शिक्षार्थी प्रणाली :- यह मुफ्त में श्रम करवाने का तथा व्यस्कों की मजदूरी की दर कम रखने का तरीका था । "प्रशिक्षण" की अवधि के दौरान, जो कि आमतौर पर तीन से पाँच साल तक होती थी, शिक्षार्थी को खाने व कपड़े की कीमत के अलावा और कोई वेतन नहीं मिलता था । प्रशिक्षण समाप्ति पर भी वह मालिक के लिए बेहद कम मजदूरी पर कार्य करने को बाध्य होता था ।

12. ऊहान :- यह हुपे प्रान्त में ऊछाङ, हानखओ तथा हानयाङ का संयुक्त नाम है ।

13. माओ-त्से-तुङ, "जनता के जनवादी अधिनायकत्व" के बारे में, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, पेकिङ, 1959.

14. माओ त्से-तुङ, सेलेक्टिड वर्क्स, लारैन्स एण्ड विशारट, लंदन, 1956 वाल्यूम-4, पृष्ठ-13.

15. इक्कीस मांगें :- 18 जनवरी 1915 को जापानी साम्राज्यवादियों ने य्वान श-खाए की सरकार के सामने 21 मांगें प्रस्तुत कीं । ये मांगें पाँच भागों में बांटी गई थीं । पहले चार भागों में निम्नलिखित मांगे थीं : जर्मनी ने शानतुङ में जो अधिकार हथिया लिए थे, वे जापान को दे दिए जाएं तथा उस प्रान्त में जापान को दूसरे नए अधिकार भी दिए जाएं ; जापानियों को दक्षिणी मंचूरिया और पूर्वी मंगोलिया में भूमि पट्टे पर लेने या उसके मालिक बनने का अधिकार दिया जाए और उन्हें वहां अपने निवास-स्थान बनाने का अधिकार दिया जाए, उद्योग-धन्धे चलाने तथा व्यापार करने का अधिकार

कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधारवाद से दूषित हुए बिना रूसी बोल्शेविक पार्टी की शानदार परंपराओं को आत्मसात किया । पार्टी के जन्म की यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशिष्टता है । पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की उपलब्धि यह थी कि इसने पार्टी के सही संगठनात्मक सिद्धांतों की आधारशिला रखी ।

चूँकि अर्ध-औपनिवेशिक चीन एक ऐसा देश था जिसमें निम्न-पूँजीपति वर्ग काफी बड़ी संख्या में था । इसलिए पार्टी के ज्यादातर सदस्य शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग या किसान-वर्ग से थे । अत: यह अवश्यम्भावी था कि उनके साथ विभिन्न प्रकार के निम्न-पूँजीपति वर्गीय विचार भी पार्टी में आने थे जो कि "वामपंथी" तथा "दक्षिणपंथी" अवसरवाद का सामाजिक उद्गम थे । अत: सभी गैर सर्वहारा विचारों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुरूप ढालना तथा समूची पार्टी का सामान्य तौर पर सैद्धांतिक स्तर ऊँचा करना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य बन गया ।

पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस ने दो भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोणों का विरोध किया । एक था "कानूनी मार्क्सवाद" का दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य पार्टी को एक शैक्षिक संस्थान में बदल देना था, जहाँ बुद्धिजीवी मार्क्सवाद का अध्ययन कर सकें । "कानूनी मार्क्सवादियों" का विचार था कि श्रमिक वर्ग का आंदोलन चलाने के लिए एक सही तथा नियमनिष्ठ संगठन की स्थापना करने की बजाय, चीन के मार्क्सवादियों को स्कूल आदि स्थापित करके तथा समाचार-पत्र प्रकाशित करके केवल प्रचार आदि का कार्य करना चाहिए तथा संसदीय संघर्षों में भाग लेना चाहिए । दूसरा, "वामपंथी दुस्साहसवादी दृष्टिकोण" था, जिसके अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम करना पार्टी का फौरी लक्ष्य था, और यह पार्टी को पूँजीवादी-जनवादी आंदोलनों में भागेदारी का, वैध गतिविधियों को चलाने का तथा बुद्धिजीवियों के पार्टी में प्रवेश का विरोध करता था ।

छन तू-श्यू ने कांग्रेस में भाग नहीं लिया । वह चीन में मार्क्सवाद के पदार्पण से भी पूर्व का एक उग्र जनवादी था, तथा बाद में एक प्रभावशाली समाजवादी प्रचारक व कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवर्तकों में से एक बना । पहली राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसे पार्टी की केन्द्रीय समिति का प्रधान चुना । इतना सब कुछ होते हुए भी वह एक अच्छा मार्क्सवादी नहीं था । यद्यपि उसने चीन में मार्क्सवादी दर्शन का प्रचार किया था, फिर भी उसकी मानसिकता में पूँजीवादी आदर्शवाद का काफी सम्मिश्रण था । उदाहरण के लिए, उसका कहना था कि मार्क्सवादी दर्शन तथा कठमुल्लावाद वाला प्रतिक्रियावादी पूँजीवादी दर्शन **"आधुनिक काल में सोचने के दो महत्त्वपूर्ण ढंग थे"** तथा इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संयुक्त मोर्चे के गठन का प्रस्ताव रखा । उसके इस विचार ने कि मार्क्सवाद सामाजिक घटनाओं की केवल व्याख्या भर प्रस्तुत कर सकता था; उनका सार नहीं; उसे अज्ञेयवाद की दलदल में फंसा दिया । यह सच है कि उसने चीन में समाजवादी विचारों का प्रचार किया, लेकिन चीन समाजवादी क्रांति में कैसे प्रवेश करेगा, इसके बारे में उसकी कोई स्पष्ट समझ नहीं थी, आरंभ में उसने सोचा कि चीन को समाजवादी क्रांति एकदम शुरू कर देनी चाहिए, जिससे यह प्रकट हुआ कि उसने चीनी क्रांति की अलग-अलग मंजिलों को उलझा दिया था । बाद में उसका विचार बना कि चीनी क्रांति दो चरणों में होनी चाहिए । पहला, पूँजीपति वर्ग की अगुवाई में जनवादी क्रांति तथा दूसरा सर्वहारा वर्ग की अगुवाई में समाजवादी क्रांति ।

2.

- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के संगठनात्मक सिद्धान्तों का अभिग्रहण ।**
- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के कार्यक्रम तथा दिशा-निर्देशों का सूत्रीकरण ।**

1 जुलाई 1921 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सहयोग से शंघाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया । विभिन्न कम्युनिस्ट ग्रुपों द्वारा चुने गए 12 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया । उनमें माओ त्से-तुङ, तुङ फी-ऊ, छन तू-श्यू तथा हो शू-हङ शामिल थे । कुल मिलाकर वे 57 कम्युनिस्ट सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे । पहली कांग्रेस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को पारित किया तथा पार्टी की नेतृत्वकारी समिति का चुनाव किया । इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना कर दी गई ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एक नए ढंग की क्रांतिकारी पार्टी, रूसी बोल्शेविक पार्टी के नमूने पर की गई । **ऐसी पार्टी श्रमिक वर्ग का हरावल तथा वर्ग चेतना से भरपूर दस्ता होती है, जो कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान से सुसज्जित होता है । यह श्रमिक वर्ग की एक सुसंगठित टुकड़ी होती है, जिसके सदस्य एकात्म संकल्प, कर्म तथा अनुशासन द्वारा एक लड़ी में पिरोकर रखे होते हैं । श्रमिक वर्ग के सभी संगठनात्मक रूप-विधानों में यह सर्वोच्च होती है तथा इसका कर्त्तव्य श्रमिक वर्ग के सभी दूसरे संगठनों का मार्गदर्शन करना होता है।**

ऐसी पार्टी बनाने की बुनियादी शर्त होती है कि इसकी सदस्यता के लिए कड़े मानदंडों पर बल दिया जाए, इसके सदस्यों को ऊँचे स्तर पर लाया जाए तथा श्रमिक वर्ग व सामान्य मेहनतकश जनता के श्रेष्ठतम, अत्यधिक प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी तत्वों को इस में समाहित किया जाए ।

श्रमिक वर्ग की संगठित टुकड़ी बनने के लिए, पार्टी का क्रांतिकारी सिद्धांतों तथा समाज और क्रांति के विकास को नियंत्रित करने वाले नियमों की जानकारी से सुसज्जित होना अनिवार्य है । पार्टी के अंदर मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सैद्धांतिक एकता पर बल दिया जाना चाहिए तथा वर्ग-संघर्ष की विभिन्न स्थितियों में अनिवार्य रूप से मार्क्सवाद-लेनिनवाद को प्रयोग में लाना चाहिए । अत: पार्टी के लिए अपनी पांतों में विभिन्न प्रकार के अवसरवाद के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना अनिवार्य है ।

उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर पार्टी के गठन की संभावना के कई कारण थे । पहला, क्योंकि इसका जन्म अक्तूबर सामाजिक क्रांति के बाद हुआ था, इसलिए यह स्वयं को रूसी बोल्शेविक पार्टी के नमूने पर ढाल सकती थी तथा कम्युनिस्ट-इंटरनेशनल से सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती थी । दूसरे, यूरोपीय देशों की भांति, न तो चीन में पूँजीवाद के 'शांतिपूर्ण' विकास की अवस्था थी, जो श्रमिक वर्ग को शांतिपूर्ण संसदीय संघर्ष जारी रखने की इजाजत देती, न ही यहाँ श्रमिक कुलीनता थी । कहने का तात्पर्य यह है कि **चीन में सुधारवाद का सामाजिक आधार अस्तित्व में न था। इस प्रकार शुरू से ही चीनी**

दिया जाए, और रेलें व खानें निर्मित करने का एकछत्र अधिकार दिया जाए ; हान-ये-फिङ लोहा-इस्पात कम्पनी चीनी-जापानी संयुक्त कारोबार के रूप में संगठित की जाए ; और चीन अपने समुद्रतट के बन्दरगाहों या द्वीपों को किसी तीसरी ताकत को पट्टे पर या और किसी तरह से न दे । पाँचवें भाग में ये मांगें की गई थीं : जापान को चीन के राजनीतिक, वित्तीय, पुलिस और फौजी मामलों पर नियंत्रण कायम करने दिया जाए तथा जापान को हुपे, च्याङशी और क्वाङतुङ प्रान्तों को मिलाने वाली महत्त्वपूर्ण रेलवे-लाइनों का निर्माण करने दिया जाए । य्वान श-खाए ने पाँचवे भाग की मांगों को छोड़कर, जिनके बारे में उसने "और बातचीत" के लिए प्रार्थना की, अन्य सब मांगों को मंजूर कर लिया । जनता द्वारा एकमत से विरोध करने के कारण जापान अपनी मांगों को कार्यान्वित नहीं कर सका ।

16. मन्चूरिया :- यह उस समय उत्तरपूर्वी चीन का नाम था ।

17. ली ता-चाओ :- वे चीन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सबसे पहले प्रचारकों में से थे तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे । अप्रैल 1927 में युद्ध-सरदार चाङ च्वो-लिन द्वारा उन्हें कत्ल कर दिया गया ।

18. लू-शुन (1881-1936) :- वे आधुनिक चीनी साहित्य के जनक थे तथा चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति के महानतम तथा सर्वाधिक जुझारू ध्वज-वाहक थे । **'आह क्यू की सच्ची कहानी', 'एक पागल आदमी की डायरी'** तथा, **'नव-वर्ष का बलिदान'** नामक अपनी प्रसिद्ध रचनाओं के अलावा उन्होंने अनेक लघु-कथाएं एवम् निबंध लिखे, जिनमें वे उग्रता के साथ सामंतवाद व साम्राज्यवाद पर हमला करते हैं, दबे-कुचले लोगों की भावनाओं को आवाज देते हैं तथा जनता के शत्रुओं को उनके असली रूप में नंगा करते हैं । उन्होंने हमेशा अपने काम को चीनी जनक्रान्ति के साथ जोड़ा तथा उसके लिए अक्तूबर 1936 में अपनी मृत्यु तक, दृढ़तापूर्वक अथक संघर्ष किया ।

19. फन :- चीनी मुद्रा-प्रणाली की एक इकाई । दस फन का एक च्याओ होता था और दस च्याओ का एक य्वान होता था । एक य्वान में 24 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी ।

●●●

दूसरा अध्याय

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चीनी श्रमिक वर्ग आंदोलन का विकास

(जुलाई 1921-दिसंबर 1923)

1.

- 1921 तथा 1923 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ।
- वाशिंगटन कान्फ्रेंस तथा साम्राज्यवादी देशों में चीन के बंटवारे को लेकर समझौता।

अमरीका ने प्रथम विश्वयुद्ध में अत्यधिक लाभ कमाया । वह लड़ाई के अंतिम चरण में जाकर उसमें शामिल हुआ, जिस समय युद्धरत शक्तियाँ लगभग थक चुकी थीं, और इस प्रकार उसने अन्य शक्तियों पर निर्विवाद रूप से सैनिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता अर्जित कर ली। युद्धरत शक्तियों तथा स्वयं अमरीका को सैन्य-सामग्री की बड़े पैमाने पर आवश्यकता ने एक विशाल बाज़ार का सृजन किया तथा युद्ध के दौरान व बाद में भी अमरीकी उद्योग के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया । युद्ध में यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक शक्ति तथा श्रम शक्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ, केवल अमरीका ही युद्ध की विपत्तियों से अछूता रहा । वास्तव में, उसने उसी युद्ध से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी की, जिसने दूसरे राष्ट्रों के संसाधनों को चूस लिया था । यह अमरीका की युद्धेतर आर्थिक समृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारक था ।

फलतः, साम्राज्यवादी देशों की तुलनात्मक शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया । 1913 में अमरीका के इस्पात का उत्पादन पूँजीवादी विश्व के कुल उत्पादन का 40% था तथा अपनी बढ़त कायम रखते हुए यह 1929 में 50% तक जा पहुँचा । इस प्रकार शीघ्र ही अमरीका एक अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया तथा पूँजीवादी विश्व का सरगना बन गया । क्योंकि अमरीका के युद्धेतर विस्तार की पीठ पर उसकी अथाह आर्थिक शक्ति थी, चीन स्वभावतः उसके मुख्य औपनिवेशिक बाज़ारों में से एक बन गया, जिसे लूटने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए।

युद्ध के पश्चात पूर्व में साम्राज्यवादी शक्तियों में मुख्य अन्तर्विरोध अमरीका तथा जापान के बीच था । पेरिस शांति कांफ्रेंस में अमरीका ने चीन में जापान की एकाधिकारवादी स्थिति को कमजोर बनाने की बजाय उसके विशेषाधिकारों तथा हितों को मान्यता दी थी, परन्तु इससे दोनों के बीच के अंतर्विरोध शिथिल होने की बजाय और तेज हो गए ।

युद्धेतर काल में सुदूर पूर्व के ब्रिटिश बाजारों में जापान की घुसपैठ ने ब्रिटिश बाजार के

विस्तार को रोक दिया और ब्रिटेन तथा जापान के बीच के अंतर्विरोध भी तेज हो गए ।

चीन के चारों ओर केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने अमरीका तथा ब्रिटेन को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया । इस प्रकार एक संघर्ष आरंभ हो गया जिसमें एक ओर अमरीका तथा ब्रिटेन थे एवं दूसरी ओर जापान था । यह संघर्ष मुख्य रूप से शस्त्रीकरण की होड़ के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ । तीनों ने नये साम्राज्यवादी युद्ध की तैयारी के लिए अपनी जल-सेनाओं, खासकर प्रशान्त महासागर में अपने बेड़ों का विस्तार किया ।

यह संघर्ष चीन में युद्ध-सरदारों के आपसी युद्धों में भी प्रतिबिम्बित हुआ । अपनी आक्रामक शक्ति को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति को चीनी युद्ध-सरदारों की आवश्यकता थी, जबकि चीनी युद्ध-सरदार अपने प्रभाव-क्षेत्रों को कायम रखने तथा उनका विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर रहना चाहते थे । इस प्रकार उत्तरी युद्ध-सरदारों का एक ग्रुप—चली गुट, ऊ फेइ-फू तथा छाओ खुन की अगुवाई में ब्रिटेन तथा अमरीका का पिट्ठू बन गया, जबकि दूसरे गुट—आनह्वेइ गुट, त्वान छी-रुइ की अगुवाई में, तथा फङथ्येन गुट, चाङ च्वो-लिन की अगुवाई में जापान के प्रभाव में आ गये। विभिन्न गुटों के ये युद्ध-सरदार निरंतर एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत रहते थे । जुलाई 1920 का चली-आनह्वेइ युद्ध, अप्रैल 1922 का प्रथम चली-फङथ्येन युद्ध तथा सितंबर 1924 का दूसरा चली-फङथ्येन युद्ध, चीन में अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान के संघर्षों का प्रतिबिम्ब मात्र थे; तथा विभिन्न युद्ध-सरदारों की विजय या पराजय, इन तीनों साम्राज्यवादी शक्तियों के विशेषाधिकारों तथा हितों के संकुचन या विस्तार को चिन्हित करती थी ।

जापान पर दबाव डालने के लिए तथा सुदूर पूर्व में उस पर कुछ पाबन्दियाँ थोंपने के लिए, अमरीका तथा ब्रिटेन ने नवम्बर 1921 में 'वाशिंगटन कान्फ्रेन्स' का आयोजन किया, जिसमें अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, चीन, हालैण्ड, पुर्तगाल तथा बेल्जियम ने भाग लिया । इसमें युद्ध-सामग्री के संबंध में, अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान के नौसेना पोतों का टन भार—5 : 5 : 3 के अनुपात में निश्चित किया गया । इन नौ शक्तियों के बीच एक संधि हुई जिसमें चीन-समस्या के संबंध में कुख्यात **''खुला दरवाजा''** नीति का पुनः समर्थन किया गया। यह समझौता तभी संभव हुआ जब अमरीका तथा ब्रिटेन ने चीन में जापान के विशेषाधिकारों तथा हितों को मान्यता दे दी । इस प्रकार एक नई स्थिति उभर कर सामने आई। जापान के चीन पर एकमात्र आधिपत्य का स्थान साम्राज्यवादी शक्तियों के चीन पर साँझे आधिपत्य की पुरानी प्रक्रिया ने ले लिया, तथा चीन पर अमरीकी इजारेदारी का मार्ग प्रशस्त हो गया । वाशिंगटन कांफ्रेंस, साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन के बंटवारे की कांफ्रेंस थी ।

वाशिंगटन कांफ्रेंस के समय चीनी कम्युनिस्टों द्वारा प्रकाशित 'न्यू यूथ', 'दी कम्युनिस्ट पार्टी' तथा 'वैनगार्ड' नामक तीन पत्रिकाओं ने चीन की समस्या पर केन्द्रित युद्धेतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण किया, इस कांफ्रेंस की लूटने तथा विभाजित करने की प्रवृत्ति तथा जापानी, ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा चीन के विभाजन के खतरे का पर्दाफाश किया तथा स्पष्ट किया कि चीनी जनता के सामने मुख्य राजनीतिक कार्य एकजुट हो कर साम्राज्यवाद तथा युद्ध-सरदारों की सरकार के विरुद्ध लगातार संघर्ष करने का था।

●

महत्त्व है—इसमें डॉ० सुन यात-सेन ने अपने **''तीन जन-सिद्धान्तों''** की नयी व्याख्या प्रस्तुत की, अर्थात् उपरोक्त तीन बुनियादी नीतियों पर आधारित **''नये तीन जन-सिद्धान्त''** ।

इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में क्वोमिंताङ संयुक्त मोर्चे का एक संगठन बन गयी, एक ऐसा संगठन, जो चार वर्गों के संश्रय से बना था—श्रमिक वर्ग, किसान समुदाय, निम्न-पूँजीपति वर्ग तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ।

नये तीन जन-सिद्धान्तों तथा पुराने तीन जन-सिद्धान्तों में कुछ आधारभूत अंतर थे । पुराने तीन जन-सिद्धान्तों में पुरानी जनवादी क्रान्ति की ऐतिहासिक विशिष्टताओं की झलक थीं, जिसका लक्ष्य पूँजीपति वर्ग की अगुवाई में एक पूँजीवादी तानाशाही तथा एक पूँजीवादी समाज की स्थापना करना था। नव-जनवादी क्रांति के काल में वे पुराने पड़ चुके थे तथा नए तीन जन-सिद्धांत अस्तित्व में आए । **राष्ट्रवाद का नया सिद्धांत साम्राज्यवाद का विरोधी था तथा इसने ''चीनी राष्ट्र की स्वःमुक्ति'' तथा ''चीन की सभी राष्ट्रीयताओं के लिए पूर्ण समानता'' की पैरवी की । जनवाद के नए सिद्धांत में जनवादी अधिकारों में जनसाधारण की भागेदारी की पैरवी की गई तथा उन सभी व्यक्तियों व संस्थाओं की हिस्सेदारी की भी पैरवी की गई जो साम्राज्यवाद व सामंतवाद का विरोध करते थे । इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इन अधिकारों पर मुट्ठी भर पूँजीपतियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए । आजीविका के नए सिद्धांत में ''जमीन के मालिकाना हक का समान बंटवारा,'' ''जमीन जोतने वाले को,'' ''पूँजी पर नियन्त्रण'' तथा श्रमिकों के रहन-सहन के हालात में सुधार आदि की पैरवी की गई तथा मुट्ठीभर पूँजीपतियों तथा जमींदारों द्वारा राष्ट्रीय कल्याण तथा लोगों की आजीविका पर कब्जे का विरोध किया गया ।**

क्योंकि नए तीन जन-सिद्धांत, तीन आधारभूत नीतियों पर आधारित थे, तथा इनमें साम्राज्यवाद व सामंतवाद का विरोध किया गया था तथा सभी क्रांतिकारी वर्गों की जनवादी सांझा सरकार बनाने की पैरवी की गई थी, अतः ये सिद्धांत मूलतः, पूँजीवादी-जनवादी क्रांति की कालावधि के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के अनुरूप थे । इस प्रकार ये सिद्धांत क्वोमिंताङ-कम्युनिस्ट सहयोग का राजनीतिक आधार बने ।

अतः क्वोमिंताङ की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कम्युनिस्टों ने भाग लिया तथा मार्गदर्शक भूमिका निभाई, चीनी क्रांति में एक नए उभार का आरंभ बिंदु बनी ।

दो अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाएँ जिन्होंने क्रांति की गति को तेजी प्रदान की, इसी कालावधि के दौरान घटित हुईं : सोवियत-संघ तथा चीन के दरम्यान मैत्री संधि का सम्पन्न होना तथा क्रांतिकारी सेना का निर्माण । 31 मई, 1924 को हस्ताक्षरित चीनी-सोवियत मैत्री-सन्धि, चीन के राजनीतिक इतिहास में ऐसी पहली संधि थी जो सही मायनों में समानता तथा मित्रता पर आधारित थी ।

सोवियत-संघ द्वारा, चीन सम्बन्धी अपने वक्तव्यों में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित करने की पेशकश को पेकिङ सरकार दो बार ठुकरा चुकी थी । जब सोवियत सरकार का प्रतिनिधि 1922 में पेकिङ पहुँचा, पेकिङवासियों ने तो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन पेकिङ सरकार ने उसके प्रति पूर्ण उदासीनता दिखाई । तथापि, इन दो देशों की जनता के बीच की महान मैत्री अविभाज्य थी । जब सोवियत सरकार ने सितम्बर 1923 में चीन में

एक अलग-थलग द्वीप होने के कारण अपने निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकता था । सारी भोजन-सामग्री तथा दैनिक जरूरत की बहुत सी वस्तुएँ क्वाङतुङ से आयात करनी पड़ती थीं । अब, हड़ताल के कारण हांगकांग व क्वाङतुङ में संचार प्रणाली टूट गई थी तथा हांगकांग में अनाजों तथा अन्य खाद्य-सामग्री की सख्त तंगी आ गई और कीमतें आकाश छूने लगीं : चावल का भाव 60 प्रतिशत बढ़ गया तथा माँस की कीमत में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई ।

हांगकांग के मज़दूरों के शौर्यपूर्ण संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को सुवि देने पर विवश कर दिया । 6 मार्च को हांगकांग के अधिकारियों ने नाविकों के संगठन क ा करने संबंधी आदेश को रद्द करने की घोषणा की । गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा कर दिय , तथा वेतनमानों में 15 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी की गई । यह विशाल हड़ताल ार्च को एक शानदार जीत के साथ समाप्त हुई । एक सौ वर्ष से चले आ रहे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में चीनी जनता की यह प्रथम विजय थी तथा यह विजय उसने अपने बाहुबल पर अर्जित की थी और इससे यह भी प्रकट हो गया कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में, चीनी श्रमिक वर्ग, जनता का सबसे दृढ़प्रतिज्ञ हरावल दस्ता था ।

हांगकांग के नाविकों की हड़ताल में विजय ने कुल मिलाकर देशभर में श्रमिकों के संघर्षों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया । हड़तालों के उमड़ते आवेग के मद्देनजर तथा श्रमिक-वर्ग आंदोलन के नेतृत्व को मज़बूत बनाने के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया । चीनी ट्रेड यूनियन सचिवालय के तत्वाधान में 1 मई, 1922 को कैंटन में प्रथम राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया । इसमें 12 नगरों, 100 से ऊपर श्रमिक संगठनों तथा 2,70,000 श्रमिक-संघ सदस्यों की तरफ से 162 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । उपस्थित सदस्यों में कम्युनिस्ट पार्टी, क्वोमिंताङ व अराजकतावादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल थे तथा वे लोग भी शामिल थे जो किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं थे । सम्मेलन में निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई : जनवादी क्रांति में श्रमिकों की भागेदारी; स्थानीय श्रमिक-संघों में श्रेणी-समाजवाद के दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए श्रमिक-संघों की अखिल चीनी फेडरेशन की स्थापना तथा श्रमिकों में समाजवादी शिक्षा की व्यवस्था । सम्मेलन ने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत नारों ''साम्राज्यवाद का नाश हो !'' तथा ''युद्ध-सरदारों का नाश हो !'', को अंगीकार कर लिया, आठ घंटे के कार्य-दिवस तथा हड़तालों के दौरान पारस्परिक सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृत किया तथा श्रमिक-संघों की अखिल चीनी फेडरेशन की स्थापना होने तक चीनी ट्रेड यूनियन सचिवालय को राष्ट्रीय संपर्क केन्द्र के रूप में काम करने के लिए मान्यता प्रदान की । इस अंतिम प्रस्ताव तथा सम्मेलन की तमाम कार्यवाही से यही संकेत मिला कि सभी भाग लेने वालों ने एकमत से कम्युनिस्ट पार्टी को चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का नेता स्वीकार कर लिया था। साथ ही सम्मेलन से चीनी श्रमिक-वर्ग की राष्ट्रव्यापी एकता की शुरुआत हुई और इस प्रकार मौजूदा हड़ताल-आंदोलन को एक महान प्रेरक शक्ति मिली ।

इस तथ्य से कि सभी जगह हड़तालों का दमन युद्ध-सरदारों तथा साम्राज्यवादियों ने किया था, श्रमिकों के हृदय में, राजनीतिक स्वतंत्रता की चाह तथा संकल्प घर कर गया । तदनुसार, पार्टी के मार्गदर्शन में उन्होंने श्रम-कानून के लिए आंदोलन आरंभ किया । **''श्रम-कानून की**

रूपरेखा", जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों तथा आजादी की रक्षा करना था, का प्रारूप, ट्रेड यूनियन सचिवालय द्वारा तैयार किया गया तथा पेकिङ में संसद के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया । इसमें 19 धाराएँ थीं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य धाराएँ थी : (1) श्रमिकों को सभा करने तथा संगठन बनाने की आजादी, (2) आम हड़ताल पर जाने का श्रमिकों का अधिकार (3) सामूहिक सौदाकारी का अधिकार (4) आठ घण्टे के कार्य-दिवस की स्वीकृति, (5) महिला तथा बाल श्रमिकों की सुरक्षा; (6) न्यूनतम वेतनमान की स्थापना तथा (7) अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के श्रमिकों के अधिकार को मान्यता देना । यह रूपरेखा सारे देश के समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई तथा श्रमिकों में इसका व्यापक प्रचार किया गया। सारे देश के श्रमिकों ने श्रमिक-संघ सचिवालय द्वारा श्रम-कानून के लिए आंदोलन में भाग लेने के आह्वान का पूरे जोशोखरोश से स्वागत किया। निस्संदेह युद्ध-सरदारों द्वारा नियंत्रित संसद से यह उम्मीद करना कि वह श्रमिकों का मताधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान करेगी या एक ऐसा श्रम-कानून स्वीकार करेगी जो उनके (श्रमिकों के) हित में हो, भोलेपन की पराकाष्ठा थी । फिर भी इन 19 धाराओं ने श्रमिकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला तथा हड़तालों में ये उनके संघर्ष का कार्यक्रम बन गईं । आंदोलन ने श्रमिक-वर्ग को सिखाया कि दृढ़ संघर्ष के बिना कोई राजनीतिक आजादी प्राप्त नहीं हो सकती थी ।

राष्ट्रव्यापी हड़तालें धीरे-धीरे और ज्यादा व्यापक होती चली गईं । उस वक्त हुनान, उन प्रांतों में से एक था जहाँ श्रमिक-वर्ग आंदोलन ने खूब प्रगति की । 1921 में पार्टी की प्रथम कांग्रेस के पश्चात् कामरेड माओ त्से-तुङ पार्टी के काम का नेतृत्व करने के लिए वापिस हुनान लौट गए थे । मई 1922 में प्रथम राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस के बाद, श्रमिक संघ सचिवालय शंघाई से पेकिङ चला गया तथा देश के बड़े-बड़े शहरों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर दीं । कामरेड माओ को हुनान शाखा का अध्यक्ष चुना गया । उन्होंने मज़दूर-वर्ग आंदोलन के लिए कड़ी मेहनत की, तथा छाङशा, आनय्वान कोयला-खदान तथा श्वेइकओशान सीसा खान की हड़तालों का नेतृत्व किया । माओ त्से-तुङ, ल्यू शाओ-ची तथा दूसरे कार्यकर्ता, मजदूर-समुदायों से घनिष्ठ तालमेल बनाए रखते थे, उन्हें उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी होती थी तथा वे उनके संघर्षों में सदैव बढ़-चढ़कर भाग लेते थे ।

वर्ष 1922 तथा 1923 के शुरू के दिनों में हुनान तथा देश भर में श्रमिक-वर्ग आंदोलन में जोरदार प्रगति हुई। वेतन-वृद्धि तथा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सारे प्रान्त में जबरदस्त हड़तालें हुईं । आनय्वान कोयला खान की विशाल हड़ताल ने हुनान तथा देश के बाकी हिस्सों में श्रमिक-वर्ग आंदोलन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला ।

उन दिनों च्याङशी प्रान्त की फिङश्याङ काउंटी में स्थित आनय्वान कोयला-खान का दैनिक उत्पादन 2000 टन था । यह उन दिनों तायेह लोहा खान तथा हानयाङ लोहा कारखाने (दोनों हुपे प्रांत में स्थित थे) को उनकी आवश्यकतानुसार ईंधन सप्लाई करती थी । खानों तथा च्वीचो-फिङश्याङ रेलमार्ग, दोनों में कुल मिलाकर लगभग 20000 मज़दूर काम करते थे ।

आनय्वान कोयला-खान एक ऐसा कारोबार था, जिसका स्वामित्व जापानी साम्राज्यवाद के नियंत्रण के तहत, नौकरशाह-पूँजीपतियों के हाथ में था । एक के बाद एक जितने भी संचालक आए, सभी भ्रष्ट नौकरशाह थे, खदानों से संबंधित वास्तविक अधिकार विदेशी सुपरवाइजरों के हाथ में होते थे । सारे का सारा कारोबार सामंती गुट मुखिया व्यवस्था (Feudal Gang-master

लोगों की सेना को लामबन्द करता था । सितम्बर 1924 से दिसंबर 1925 की कालावधि के दौरान इन युद्धों के कारण उद्योग तथा वाणिज्य को 79 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध-सरदार सरकारों के शासन में, जनता पर भारी करों का बोझ लाद दिया गया, तथा किसानों का लगान व सूदखोरी द्वारा बर्बरतापूर्वक शोषण किया गया ।

साम्राज्यवादी आक्रमण तथा युद्ध-सरदारों के आपसी युद्धों ने चीन की सामाजिक उत्पादक शक्तियों के मार्ग में गंभीर गतिरोध उत्पन्न किया तथा उन्हें विघटित किया । उद्योग तथा वाणिज्य का भट्ठा बैठ गया तथा लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए । इस स्थिति ने देश की समस्त जनता को साम्राज्यवादियों तथा युद्ध-सरदार सरकारों के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष छेड़ने की प्रेरणा दी ।

2.

- **क्वोमिंताङ की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस ।**
- **श्रमिक-वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन का पुनरुत्थान ।**
- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी राष्ट्रीय कांग्रेस ।**
- **राष्ट्रीय असेम्बली बुलाने के लिए आंदोलन ।**

साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरुद्ध डॉ० सुन यात-सेन के जनवादी रुख का तथा क्वोमिंताङ का श्रमिकों तथा अन्य जनवादी शक्तियों के गठबन्धन के रूप में रूपान्तरण होने की संभावना का सही मूल्यांकन कर के, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे की नीति को स्वीकृति प्रदान की ।

कांग्रेस से कुछ समय पहले से ही पार्टी एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना तथा क्वोमिंताङ-कम्युनिस्ट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काफी दौड़ धूप कर रही थी । पार्टी ने अपने कई सदस्यों, विशेषकर ली ता-चाओ तथा लिन पो-च्वी के माध्यम से डॉ० सुन यात-सेन पर सकारात्मक प्रभाव डाला था । इन पार्टी सदस्यों ने पार्टी के निर्देशन में अत्यधिक उपयोगी काम किया ।

मार्च 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से डॉ० सुन यात-सेन ने क्वाङतुङ में क्रांतिकारी सरकार का गठन किया । अक्तूबर में उन्होंने क्वोमिंताङ के पुनर्गठन के बारे में एक घोषणापत्र जारी किया । पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा पेश किया, तथा अपनी तीन बुनियादी नीतियों—**(1) सोवियत-संघ के साथ मैत्री, (2) कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग** तथा **(3) श्रमिकों व किसानों की सहायता** को परिभाषित किया ।

जनवरी 1924 में कैंटन में क्वोमिंताङ की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई । ली ता-चाओ, माओ त्से-तुङ तथा अन्य साम्यवादियों ने कांग्रेस में भाग लिया तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भूमिका निभाई । कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी नौजवान लीग के सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत हैसियत से क्वोमिंताङ में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया, नये पार्टी कार्यक्रम तथा संविधान को स्वीकृति प्रदान की, तथा क्वोमिंताङ के पुनर्गठन के लिए विभिन्न ठोस तथा निश्चित उपायों को मन्जूरी दी । इसने *"चीनी क्वोमिंताङ की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणापत्र"* को भी मन्जूरी दी । इस दस्तावेज का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक

System) के आधार पर चलाया जाता था । मजदूर साम्राज्यवाद, नौकरशाह-पूँजीवाद और सामंतवाद के तिहरे दमन की चक्की में पिस रहे थे । इसलिए आनय्वान कोयला-खदान में असीम क्रांतिकारी संभावनाएँ मौजूद थीं ।

1921 के बाद पार्टी ने, शुरू में, खान में खाली समय में चलने वाले स्कूल चलाए ताकि मज़दूरों को मार्क्सवाद की शिक्षा दी जा सके, फिर एक श्रमिक-संघ का गठन किया गया जिसकी विधिवत् स्थापना 1 मई 1922 को हुई । इसी दौरान समाजवादी नौजवान संघ की एक शाखा मजदूरों में स्थापित की गई, जिसके सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को बाद में पार्टी में शामिल कर लिया गया ।

आनय्वान कोयला-खनिकों की विशाल हड़ताल, जिसकी सारे देश में प्रतिक्रिया हुई, 10 सितंबर, 1922 को आरंभ हुई । खान तथा रेलवे के अधिकारियों ने कई महीनों से मजदूरों का वेतन रोक रखा था तथा उन्होंने उनकी यूनियन को भंग करने का प्रयास किया । इसके अतिरिक्त 'हानयाङ लोहा कारखाने' की हड़ताल में विजय प्राप्ति से मजदूरों के हौसले बुलन्द थे । उन्होंने अपने राजनीतिक हितों की रक्षा, काम-काज के हालातों में सुधार तथा वेतन में वृद्धि की माँग की । खनन क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने के लिए मजदूरों की टुकड़ियाँ गठित की गईं । जब च्याङशी प्रांत के युद्ध-सरदारों ने हड़ताल का दमन करने के उद्देश्य से अपने सैनिक भेजे, तब पार्टी के मार्गदर्शन में मजदूर सैनिकों में प्रचार कार्य करने के लिए गए तथा इस हद तक उनकी सहानुभूति अर्जित करने में सफल हो गए कि सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया । अधिकारियों ने बोगस "सन्धि वार्ताओं" द्वारा हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कामरेड ल्यू शाओ-ची को गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन हजारों हड़तालियों ने वार्ता-स्थल को घेर लिया तथा युद्ध-सरदारों के इस षड्यन्त्र को नाकाम कर दिया ।

मजदूरों की पूर्ण एकता तथा दृढ़ संघर्ष के कारण, अधिकारियों को हड़ताल के पाँचवें दिन उनकी माँगें मानने पर विवश होना पड़ा और इस प्रकार हड़ताल की विजयपूर्ण समाप्ति हुई ।

हड़ताल की सफलता के बाद श्रमिक-संघ को नए तरीके से गठित किया गया । संगठन की मूल इकाई 10 आदमियों की एक टोली थी । हर टोली का एक प्रतिनिधि था, हर दस टोलियों का एक मध्यवर्ती-प्रतिनिधि तथा हर खान या वर्कशाप का एक मुख्य-प्रतिनिधि होता था । हर खान तथा वर्कशॉप का अपने प्रतिनिधियों या मध्यवर्ती-प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि-मण्डल होता था तथा इन सबसे ऊपर मुख्य प्रतिनिधियों की सर्वोच्च कांग्रेस होती थी । इस प्रकार श्रमिकों को और ज्यादा कारगर तथा सुनिश्चित ढंग से संगठित किया गया। उनके राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि हुई तथा उनके रहन-सहन में सुस्पष्ट सुधार हुआ । मजदूरों के स्कूलों का भी विस्तार हुआ तथा सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी खोले गए । आनय्वान श्रमिक-संघ उस समय देश के अत्यन्त शक्तिशाली संगठनों में से एक था । 7 फरवरी 1923 को पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के श्रमिकों के नरसंहार के बाद, श्रमिक-वर्ग आंदोलन क्षीण होने पर जब दूसरे विशाल कारोबारों के लगभग सभी संगठन नष्ट कर दिए गए थे, उस वक्त केवल यही संगठन अडिग खड़ा रहा था । 1926 में उत्तरी अभियान के दौरान आनय्वान के श्रमिकों ने अभियान-सेना को जबरदस्त सहयोग दिया । उन्होंने 1927 के "शरद फसल विद्रोह" के सशस्त्र संघर्ष में भी भाग लिया । सन् 1928 से आनय्वान चिङकाङ पहाड़ों में स्थित क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र का सम्पर्क केन्द्र बन गया ।

सर्वहारा तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की ताकत में वृद्धि के कारण, मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा जनवादी विचारों के प्रचार-प्रसार के कारण तथा क्रूरतापूर्ण साम्राज्यवादी दमन एवं शोषण के कारण, विभिन्न औपनिवेशिक देशों में आर्थिक तथा क्रांतिकारी संकट और ज्यादा गहरा गए थे।

ब्रिटेन के विरुद्ध भारत तथा मिस्र के संघर्ष, फ्रांस के विरुद्ध सीरिया तथा मोरक्को के संघर्ष तथा सबसे बढ़ कर, ब्रिटेन, अमरीका तथा जापान के विरुद्ध चीनी जनता के सशस्त्र संघर्ष ने साम्राज्यवादी शक्तियों से उनका **"पृष्ठभाग"** (backyard) छिन जाने का खतरा उत्पन्न कर दिया था । कहने का तात्पर्य यह कि जब यूरोपीय सर्वहारावर्ग द्वारा राजसत्ता पर कब्ज़ा करना अभी साकार होता दिखाई नहीं दे रहा था, दबे-कुचले राष्ट्रों की मुक्ति पहले से ही एक ज्वलंत समस्या बन चुकी थी, क्योंकि उपनिवेशों तथा अर्ध-उपनिवेशों में स्थिरता का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था । दबे-कुचले राष्ट्रों तथा विशेषकर चीन के युद्धेतर मुक्ति आंदोलन ने साम्राज्यवादी शासन को भारी क्षति पहुँचाई ।

युद्धेतर कालावधि में बढ़ते साम्राज्यवादी दमन तथा शोषण ने चीन के राष्ट्रीय उद्योग को अत्यधिक दुर्बल कर दिया । उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग पर दृष्टि डालते हैं जो चीन के राष्ट्रीय उद्योग का मुख्य अंग था । सन् 1919 से 1927 तक वास्तव में यह एक ठहराव की अवस्था में रहा । निम्नलिखित आँकड़ों से पता चलता है कि चीनी स्वामित्व की मिलों में धागा तकलों तथा सूती तकलों व करघों का अंश कुल संख्या में इस प्रकार था : सूती तकले—1919 में 53.3 प्रतिशत तथा 1927 में 57.4 प्रतिशत, धागा तकले—सन् 1919 में 88.7 प्रतिशत तथा 1927 में 45.8 प्रतिशत; करघे 1919 में 40.8 प्रतिशत तथा 1927 में 50.3 प्रतिशत । सन् 1922 से 1927 तक के समय में चीनी स्वामित्व की मिलों द्वारा उत्पादित सूती धागे का प्रतिशत सारे देश के कुल उत्पादन के 92 प्रतिशत से घट कर 58 प्रतिशत रह गया, जबकि विदेशी स्वामित्व की मिलों द्वारा उत्पादित सूती धागे का अंश 8 प्रतिशत से बढ़ कर 42 प्रतिशत हो गया । 1925 से 1927 के दौरान चीनी स्वामित्व की मिलों द्वारा तैयार किए गए सूती कपड़े का अंश, सारे देश के कुल उत्पादन के 83 प्रतिशत से घट कर 47 प्रतिशत रह गया, जबकि विदेशी स्वामित्व की मिलों द्वारा तैयार सूती कपड़े का अंश कुल उत्पादन के 17 प्रतिशत से बढ़ कर 53 प्रतिशत हो गया ।

जहाँ तक विदेशी व्यापार का संबंध है, इसमें प्रतिकूल सन्तुलन, जिसमें युद्ध के दौरान काफी कमी आई थी, पुनः तेज़ी से वृद्धि की ओर अग्रसर हुआ । वर्ष 1919 में लगभग संतुलन वाली स्थिति थी और मात्र 1,61,88,270 चाँदी के डॉलरों का अंतर था, 1920 में निर्यात की अपेक्षा आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा 22,06,18,930 डॉलर के प्रतिकूल संतुलन की स्थिति बन गई तथा आने वाले कुछ वर्षों में इस प्रतिकूल संतुलन में और अधिक वृद्धि हुई।

इस कालावधि में साम्राज्यवादियों ने अपनी पुरानी नीति का अनुसरण करते हुए चीन के विभिन्न युद्ध-सरदारों की सरकारों की पीठ थपथपाई तथा भिन्न-भिन्न गुटों के युद्ध-सरदारों में परस्पर गृहयुद्ध की आग सुलगाई । सन् 1924 में च्याङसू-चच्याङ युद्ध तथा द्वितीय चली-फङथ्येन युद्ध हुआ । 1925 में चच्याङ-फङथ्येन युद्ध हुआ तथा फङथ्येन व चली गुटों द्वारा संयुक्त रूप से क्रान्तिकारी रुझान वाली "राष्ट्रीय सेना" पर हमला किया गया ।

उत्तरी युद्ध-सरदारों के मध्य अधिकतर लड़ाइयाँ ल्याओनिङ, हपे, जेहोल, शानतुङ, च्याङसू, चच्याङ तथा हुपे प्रान्तों में लड़ी गईं । प्रत्येक पक्ष एक लाख से लेकर चार लाख

दो वर्ष तक हुनान के श्रमिकों ने सभी संघर्षों में विजय प्राप्त की । उनकी सफलता के दो कारण थे : पहला, हड़ताल आंदोलन का राष्ट्र-व्यापी विस्तार तथा दूसरा, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण था—चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मार्गदर्शन।

पार्टी ने हुनान के श्रमिकों को उनके संघर्षों में किस प्रकार संगठित किया तथा उनका मार्गदर्शन किया ?

पहला, उसने सैद्धांतिक काम की तरफ पूरा ध्यान दिया । श्रमिकों के घरों में सांध्यकालीन कक्षाएँ चला कर उन्हें मार्क्सवाद-लेनिनवाद में शिक्षित किया, उनकी वर्ग-चेतना को उजागर किया, तथा उनके जीवन, विचारों और भावनाओं का परिचय प्राप्त किया । जब तैयारी हो गई तो पार्टी ने तत्काल उनकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माँगों को वाणी प्रदान की तथा उन्हें संघर्ष में उतार दिया । संघर्ष के दौरान तथा विजय के पश्चात, पार्टी ने एक क्षण के लिए भी, श्रमिकों की राजनीतिक सोच को दृढ़ करने तथा विकसित करने में ढील नहीं दी ।

दूसरे, उसने श्रमिकों में बेहद अनुशासनबद्ध संस्थाओं की स्थापना की, सबसे महत्त्वपूर्ण यह कि श्रमिक-संघ तथा उसकी बुनियादी संस्थाओं की स्थापना की । संघर्ष को चलाने के लिए, पार्टी को दोनों पक्षों की ताकत तथा संघर्ष के दौरान सभी संभव उतार-चढ़ावों का सही आकलन करना पड़ा । हड़ताल की माँगों तथा संघर्ष के लिए नारों की जनता में स्पष्ट व्याख्या करनी पड़ी । संक्षेप में किसी भी संघर्ष को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद अनुशासनबद्ध संगठन, दूरदर्शी नेतृत्व और अच्छी तरह सोची समझी योजना का होना जरूरी है । सब-कुछ पूरी तरह तैयार होना चाहिए, तथा परिणाम के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए । संघर्ष के दौरान मज़दूरों में से नेताओं को प्रशिक्षित करने तथा श्रमिक संगठनों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया ।

तीसरी बात, पार्टी ने लचीली कार्यनीति अपनाई । उसने शत्रु के बीच के अंतर्विरोधों का पूरा लाभ उठाया, **''प्रान्तीय संविधानों''** का लाभ उठाया तथा व्यापक जन-समुदाय पर निर्भर रहते हुए शासक-वर्ग की चालों का पर्दाफाश किया तथा सभा करने व संगठन बनाने की आज़ादी देने के लिए तथा हड़ताल के अधिकार व सरकार से संधि-वार्ता करने के लिए श्रमिक-संगठन के प्रतिनिधियों को भेजने के अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य किया। विभिन्न प्रभावशाली सामाजिक संस्थाएँ भी श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को किसी न किसी अंश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देने के लिए खिंची चली आईं ।

इन विजयों तथा जन-समुदाय की पूर्ण एकता के आधार पर, नवंबर 1922 में **''हुनान प्रांतीय श्रमिक संघ फेडरेशन''** की स्थापना की गई जो सारे प्रांत का एक संयुक्त श्रमिक-वर्ग संगठन था, यही संगठन वह ध्वजा बना, जिसके नीचे हुनान की जनता ने अपने क्रांतिकारी संघर्षों को आगे बढ़ाया ।

7 फरवरी, 1923 के नरसंहार के समय जब पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के श्रमिक युद्ध-सरदार ऊ फेइ-फू की सरकार की निरंकुश नीतियों के विरोध में उठ खड़े हुए थे, हड़ताल-आंदोलन अपने चरम बिन्दु पर पहुँच गया । घटना का कारण, ऊ द्वारा **''पेकिङ-हानखओ रेल मजदूर श्रमिक-संघ''** (Peking-Hankow Railway Workers Trade Union) की स्थापना का दमन करना था । 1921 से ही रेल कर्मचारियों ने स्वयं को श्रमिक संगठनों में संगठित करना आरंभ कर दिया था । 1922 के अंत तक, पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग पर पहले से ही 16 छोटे

विश्व के विभिन्न पूँजीवादी देश भी अस्थायी स्थिरता के दौर से गुजर रहे थे । 1924-27 की कालावधि में ये राष्ट्र अपने युद्धेतर आर्थिक तथा राजनीतिक संकटों से अस्थायी तौर पर उबरे, उनका उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर को छूने लगा था, व कहीं-कहीं युद्ध-पूर्व के स्तर को भी पार कर गया था । क्रांति की लहर उतार पर थी ।

सन् 1926 में पूँजीवादी देशों में लोहे का उत्पादन युद्ध-पूर्व स्तर का 100.5 प्रतिशत, इस्पात 122.6 प्रतिशत, कोयला 96.8 प्रतिशत तथा पाँच अलग-अलग किस्म के अनाजों का उत्पादन 110.5 प्रतिशत था । लेकिन कई पूँजीवादी देशों (उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान) में संतुलित विकास की बजाय उत्पादन में दिन दुगुनी व रात चौगुनी वृद्धि हुई। यह पूँजीवाद के असमान विकास के लक्षण थे ।

पूँजीवादी विश्व की अस्थायी स्थिरता, मुख्यत: अमरीकी ''सहायता'' से, तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का वित्तीय मामलों में अमरीका पर निर्भर होने की कीमत पर अर्जित की गई थी। युद्धोपरान्त विश्व-वित्त-पूँजी का केन्द्र (Centre of World finance capital) यूरोप से अमरीका में स्थानान्तरित हो गया था । यह केवल अमरीकी पूँजी का आयात ही था जिसके बल पर यूरोपीय देश अपने आपको घसीट रहे थे । इस प्रकार अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता (साहूकार) बन गया था, जिसे लगभग हर यूरोपीय देश, हर वर्ष एक बहुत बड़ी राशि उधार तथा ब्याज के रूप में चुकाता था । परिणामस्वरूप, इन देशों को अपनी जनता पर लगातार बढ़ते करों का बोझ लादने को बाध्य होना पड़ा, इस प्रकार मेहनतकश जनता के हालात और ज़्यादा खराब हो गए; जर्मनी को क्षतिपूर्ति (130 अरब मार्क) के लिए बाध्य किया गया, जिससे जर्मन अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा देश में बेरोजगारों की तादाद में भारी वृद्धि हुई; तथा उपनिवेशों की जनता का और अधिक क्रूरतापूर्ण ढंग से शोषण किया गया, जिससे उन देशों में आर्थिक संकट और अधिक गहरा गया तथा वहां की जनता के रहन-सहन के हालात में बेहद गिरावट आ गई। इन सब कारणों से पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा के आपसी विरोधों, स्वयं साम्राज्यवादियों के मध्य संघर्षों तथा साम्राज्यवादियों और औपनिवेशिक जनता के मध्य संघर्षों में अनिवार्य रूप से तेजी आई । ऐसे आधार पर टिकी हुई पूँजीवादी विश्व की स्थिरता केवल अस्थायी तथा अनिश्चित ही हो सकती थी ।

स्थिरता की इन दो किस्मों से अत्यंत महत्त्व के एक नए तथ्य का जन्म हुआ । सोवियत-संघ तथा पूँजीवादी देशों के मध्य हुए इस अस्थायी शक्ति-संतुलन से ''शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व'' के एक दौर का सूत्रपात हुआ ।

क्योंकि इस कालावधि के दौरान साम्राज्यवादी देशों को निर्बल करने के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ था, तथा क्रांतिकारी और प्रति-क्रांतिकारी खेमों में एक अस्थायी शक्ति-संतुलन अस्तित्व में आ गया था, इसलिए साम्राज्यवादियों के लिए, चीनी क्रांति का विरोध करने तथा उसका गला घोंटने के लिए और ज़्यादा ताकत जुटाना तथा एक अस्थाई किन्तु शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी गठजोड़ बनाना संभव हो गया था । इससे चीनी क्रांति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । वास्तव में, अंतिम विजय-प्राप्ति से पूर्व चीनी क्रांति को रूसी क्रांति की अपेक्षा कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

दूसरी ओर, उपनिवेशों तथा अर्ध-उपनिवेशों में क्रांतिकारी संघर्षों में तेजी आना भी इस कालावधि की मुख्य विशेषता थी । प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तथा उसके पश्चात्, औद्योगिक

तीसरा अध्याय

क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे का गठन
क्रांतिकारी आंदोलन का उत्थान

(जनवरी 1924-जुलाई 1926)

1.

● सन् 1924 से 1927 तक की अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू स्थिति ।

सन् 1924 से 1927 तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की खास बात यह थी कि समाजवादी सोवियत-संघ में स्थिरता तथा पूँजीवादी देशों में अस्थायी स्थिरता रही । स्थिरता की ये दो किस्में मूलतः भिन्न थीं ।

साम्राज्यवादी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा ''श्वेत गार्ड'' विद्रोहों को कुचलने के बाद सन् 1921 में सोवियत-संघ ने राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण के दौर में कदम रखा । 1927 तक सोवियत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपने युद्ध-पूर्व स्तर को पार चुकी थी । 1926-27 में औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व स्तर का 100.9 प्रतिशत तथा कृषि उत्पादन 108.3 प्रतिशत था । सोवियत-संघ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास समाजवादी औद्योगीकरण की नीति के अनुरूप किया गया था। 1926-27 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होने से सोवियत-संघ धीरे-धीरे एक औद्योगिक देश बनता जा रहा था । इसी कालावधि में उसके कुल औद्योगिक उत्पादन का 86 प्रतिशत समाजवादी सेक्टर द्वारा उत्पादित होना यह परिलक्षित करता था कि वह समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए तेजी से प्रगति कर रहा था ।

सोवियत-संघ की शक्ति में वृद्धि के संकेत इस तथ्य से भी प्रकट होते थे कि सभी देशों के श्रमिकों ने अपने भाग्य को सोवियत-संघ के साथ जोड़ दिया था तथा उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि संसार में यही एक ऐसा देश था जिसका नेतृत्व श्रमिक-वर्ग के हाथों में था और यह कि रूसी श्रमिक वर्ग न केवल पूँजीवादी प्रणाली को समाप्त करने में, बल्कि राजसत्ता पर कब्जा करने के बाद एक समाजवादी प्रणाली को निर्मित करने में भी सक्षम था । दूसरा संकेत यह था कि दबे-कुचले राष्ट्रों के मन में सोवियत-संघ की प्रतिष्ठा बढ़ी थी तथा उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि सोवियत-संघ ही दबे-कुचले राष्ट्रों के मुक्ति आंदोलनों की सहायता कर सकता था तथा उन्होंने उसका मित्र बनने की इच्छा जतलाई । उन्हें यह भी पक्का यकीन हो गया था कि केवल सोवियत-संघ ही अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या का सही समाधान ढूँढ़ पाया था ।

इसका अर्थ यह हुआ कि सोवियत-संघ की स्थिरता एक मजबूत आधार पर टिकी थी, तथा दिन-प्रतिदिन और ज्यादा दृढ़ होती जा रही थी ।

संगठन कार्यरत थे, जबकि 1 फरवरी, 1923 को हुनान प्रान्त के चङचओ नामक स्थान पर एक **''आम श्रमिक-संघ''** (General Trade Union) के उद्घाटन का निर्णय लिया गया । इससे पूर्व हपे, हुनान तथा हुपे प्रान्तों के मुख्य युद्ध-सरदार ऊ फेइ-फू ने ''श्रम का संरक्षण'' करने की पाखंडपूर्ण घोषणा की थी । जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने एक श्रम-विभाग खोलने तथा श्रम-कानून को स्वीकृति प्रदान करने की अपनी आकांक्षा भी जतलाई। अब चूँकि श्रमिकों का संगठन दिन-प्रतिदिन मज़बूत होता जा रहा था, उसने श्रमिक-संघ की स्थापना पर रोक लगाने का आदेश देकर अपने प्रतिक्रियावादी चरित्र को नंगा कर दिया । लेकिन इस सब के बावजूद, श्रमिकों ने योजनानुसार सभा करने का फैसला किया । निश्चित दिन को श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने सेना तथा पुलिस का घेरा तोड़कर सभा की तथा पेकिङ-हानखओ रेल-मजदूर श्रमिक-संघ की स्थापना की घोषणा की । सभा में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनकी प्राप्ति के लिए श्रमिक-संघ को संघर्ष करना था : श्रमिकों के रहन-सहन के हालातों में सुधार, श्रमिक-वर्ग की राजनीतिक चेतना को विकसित करना, एवम् देश के तथा सारी दुनिया के श्रमिक-वर्ग के साथ एकता स्थापित करना। सभा के बाद, प्रतिनिधियों को चङचओ छोड़ जाने को विवश किया गया । युद्ध-सरदार के इस स्वेच्छाचारी कृत्य के विरोध में उसी शाम श्रमिक-संघ ने 4 फरवरी को पेकिङ-हानखओ रेलवे के श्रमिकों की आम हड़ताल का फैसला किया । श्रमिक-संघ के मुख्यालय को तब हानखओ में च्याङन नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया तथा श्रमिकों से मानवाधिकारों तथा स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने की अपील की गई ।

4 फरवरी को समूचे पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के साथ लगते इलाके में आम हड़ताल हो गई । हड़ताल के तीसरे दिन ऊहान के श्रमिक-संघों के प्रतिनिधियों तथा च्याङन क्षेत्र के श्रमिकों ने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें 10,000 से ऊपर लोगों ने भाग लिया । यही समय था जब साम्राज्यवादियों ने चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन में खुलकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया । विदेशी ''राजनयिक-समुदाय'' ने एक संयुक्त-पत्र पेकिङ सरकार को दिया तथा उसे श्रमिकों को कुचलने के लिए उकसाया । हड़ताल को कुचलने के उद्देश्य से हानखओ में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूत ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें युद्ध-सरदार श्याओ याओ-नान के प्रतिनिधियों तथा विदेशी पूँजीपतियों ने भाग लिया । 7 फरवरी को कत्लेआम शुरू हो गया । विवाद में मध्यस्थता करने की आड़ में श्याओ के अफसरों ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को च्याङन स्थित रेल-मजदूर श्रमिक-संघ के मुख्यालय पर बातचीत करने का प्रलोभन दिया, जहाँ उन पर घात लगाकर आक्रमण करने की योजना थी। उनके पहुँचने से पहले ही, श्याओ के सैनिकों ने ट्रेड-यूनियन मुख्यालय के बाहर मौजूद निहत्थी मजदूर-टुकड़ियों पर आक्रमण कर दिया तथा 37 मजदूरों को भून डाला तथा 200 से भी अधिक मजदूर घायल हो गए । यूनियन की च्याङन शाखा के प्रधान लिन श्याङ-च्येन को गिरफ्तार करके रेलवे स्टेशन के एक खम्भे से बाँध दिया गया तथा उन पर हड़ताल वापिस लेने के लिए दबाव डालने का प्रयास किया गया । पर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ इन्कार कर दिया, जिससे उन्हें उसी समय मौत के घाट उतार दिया गया । इसी प्रकार के जुल्म चाङशिनथ्येन, चङचओ, शिनयाङ, क्वाङश्वेइ तथा च्यूमाथ्येन नामक स्थानों पर भी हुए । ऊहान ट्रेड-यूनियन फेडरेशन के कानूनी सलाहकार श याङ को गिरफ्तार करके 15 फरवरी,

1923 को ऊछाङ में कत्ल कर दिया गया । उस समय तक हुपे प्रांतीय ट्रेड-यूनियन फेडरेशन तथा ऊहान के अन्य श्रमिक-संघ बंद कर दिए गए थे ।

कत्लेआम वाले दिन ही, हुपे प्रांतीय ट्रेड-यूनियन फेडरेशन ने आम हड़ताल का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप ऊहान की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने काम बन्द कर दिया। आह्वान के जवाब में ताओखओ-छिङह्वा, चङतिङ-थाएय्वान, थ्येनचिन-फूखओ तथा कैंटन-हानखओ रेलमार्गों के श्रमिकों ने हड़तालों की झड़ी लगा दी । पेकिङ-फङथ्येन तथा पेकिङ-स्वेय्वान रेलमार्गों पर भी हड़तालों का माहौल उबाल खा रहा था । पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग की हड़ताल के समर्थन के लिए देश के सभी बड़े-बड़े नगरों में सभाएं बनाई गईं । **'अखिल चीनी विद्यार्थी फेडरेशन'** तथा विभिन्न सामाजिक समुदायों की संस्थाओं ने श्रमिकों के न्यायोचित संघर्ष के समर्थन में वक्तव्य जारी किये ।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भी इस घटना पर एक घोषणापत्र जारी किया ।

पेकिङ-हानखओ रेलवे के श्रमिकों की विशाल हड़ताल बहुत बड़े राजनीतिक महत्त्व की घटना थी । इसने सारे देश तथा सारी दुनिया को हिला कर रख दिया ।

कत्लेआम के बाद युद्ध-सरदार सरकार की सेना तथा पुलिस श्रमिकों पर टूट पड़ी और उन्हें रस्सियों से बाँध कर संगीनों और बंदूकों से धमकाते हुए दोबारा काम शुरू करवाने का प्रयास किया, लेकिन श्रमिकों ने ट्रेड-यूनियन मुख्यालय के आदेश के बिना काम पर लौटने से दृढ़तापूर्वक इंकार कर दिया । दूसरे शहरों में स्थित ट्रेड-यूनियन की शाखाओं ने भी ट्रेड-यूनियन मुख्यालय के निर्णयों के प्रति निष्ठा दिखाई तथा स्थानीय अधिकारियों से अलग से वार्ता करने से इन्कार कर दिया । यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि पेकिङ-हानखओ रेल-मजदूर श्रमिक-संघ तथा ऊहान ट्रेड-यूनियन फेडरेशन के मुख्यालयों ने श्रमिक-वर्ग की ताकत बचाए रखने के लिए हड़ताल वापिस लेने का फैसला नहीं कर लिया । उसके बाद भी श्रमिक अनिच्छा से काम पर लौटे । इस हड़ताल-आंदोलन में सारे रेलमार्ग पर 40 से ऊपर श्रमिक मारे गए, सैंकड़ों ज़ख्मी हुए, 40 से अधिक को जेल में डाल दिया गया तथा 1000 से ऊपर नौकरी से निष्कासित कर दिए गए या देश के दूसरे हिस्सों में प्रवास में रहे । पेकिङ स्थित चीनी श्रमिक-संघ सचिवालय के सारे स्टाफ की गिरफ्तारी के आदेश भेजे गए । सचिवालय तब पेकिङ से शंघाई चला गया । सभी रेलवे संगठनों को बन्द कर दिया गया । इस प्रकार प्रतिक्रियावादी सरकार की निरंकुश नीति के तहत, श्रमिकों के संघर्ष में अस्थायी क्षीणता का दौर आया ।

अपने आरंभिक दौर में ही चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन साम्राज्यवादियों तथा युद्ध-सरदारों की सरकार के वहशियाना दमन का शिकार हुआ । इससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनवादी क्रांति लाकर ही चीनी श्रमिक-वर्ग अपने आपको स्वाधीन कर सकता था, और यह कि समूचे चीनी राष्ट्र के मुक्ति-आंदोलन के हित तथा चीनी श्रमिक-वर्ग के हित अभिन्न थे। इस संघर्ष में श्रमिक-वर्ग ने पूर्णतया दृढ़ संकल्प, स्पष्ट समझ तथा अनुशासन का प्रदर्शन किया तथा इससे समूची चीनी जनता में श्रमिक-वर्ग व कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक प्रतिष्ठा खूब बढ़ गई तथा यह प्रकट हो गया कि चीनी जनवादी क्रान्ति में एक महान पथ-प्रदर्शक शक्ति का अर्विभाव हो चुका था । इसके अतिरिक्त इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि चीनी जनवादी-क्रांति में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रमिक-वर्ग के पास अपनी सशस्त्र सेना होना

कार्यदिशा—जिसका प्रतिनिधित्व कामरेड माओ त्से-तुङ करते थे, तथा मेनशेविक कार्यदिशा—जिसका प्रतिनिधित्व छन तू-श्यू करता था । ●

नोट

1. **प्रान्तीय संविधान** :- अपने शासन को कायम तथा सुदृढ़ रखने के लिए कुछ प्रांतों के युद्ध-सरदारों ने स्थानीय स्वायत्तता की पैरवी की । उन्होंने ''प्रान्तीय संविधानों'' का निर्माण किया तथा इस ''जनवाद तथा स्वायत्तता'' के नाम पर अपने सैन्यवादी नियंत्रण पर पर्दा डाला। हुनान का युद्ध-सरदार छाओ हङ-थी ऐसा पहला शासक था जिसने ''प्रांतीय संविधान'' लागू किया ।

●●●

● चीनी कम्युनिस्ट—पार्टी के आरंभिक वर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा ।

इस समय चीनी जनता की बुनियादी मांग साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी क्रांति द्वारा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा जनवाद की प्राप्ति करना थी । ऐसे महान कार्य को पूरा करने के लिए, उसे चीनी श्रमिक-वर्ग तथा उसके हरावल दस्ते, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की जरूरत थी ।

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के पश्चात् तथा अक्तूबर समाजवादी क्रांति व 4 मई के आंदोलन के बाद चीनी श्रमिक-वर्ग की ताकत में वृद्धि होने लगी तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई । प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान, तुलनात्मक दृष्टि से चीन के राष्ट्रीय उद्योगों के तीव्र गति से विकास के साथ-साथ चीनी श्रमिक-वर्ग की पांतों तथा उसके संघर्षों का भी विस्तार हुआ । अक्तूबर समाजवादी क्रांति के पदचिन्हों पर चलते हुए चीन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रवेश हुआ, तथा 4 मई आंदोलन ने चीनी श्रमिक-वर्ग आन्दोलन तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के एकीकरण की गति को तीव्रता प्रदान की ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसी एकीकरण की उपज थी । जुलाई 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई । पार्टी की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी के संगठनात्मक सिद्धांतों को, बोल्शेविक नमूने पर निर्धारित किया । इस प्रकार चीन में श्रमिक-वर्ग की एक पूर्णरुपेण नए किस्म की पार्टी, एक लेनिनवादी पार्टी का जन्म हुआ । पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीनी क्रांति के फौरी मूलभूत कार्यों को परिभाषित किया तथा सही मायनों में एक क्रान्तिकारी जनवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया ।

सर्वप्रथम पार्टी ने श्रमिक-वर्ग आंदोलन के मार्गदर्शन तथा आंदोलन को साम्यवाद के साथ एकीकृत करने को अपना प्रमुख कार्यभार माना । फलतः चीन में श्रमिक वर्ग-आंदोलन का पहला उभार सन् 1922 से फरवरी 1923 के दौरान आया तथा इसने चीन के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में श्रमिक-वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह प्रमाणित कर दिया ।

जब चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन के उभार को प्रतिक्रियावादियों के हाथों भारी क्षति उठानी पड़ी, तब पार्टी इस नतीजे पर पहुँची कि शत्रु से अकेले लड़ने के बजाय, श्रमिक-वर्ग को सभी जनवादी शक्तियों के साथ सहयोग तथा व्यापकतम संभव संश्रय स्थापित करना चाहिए । पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति तय की, तथा क्वोमिंताङ का एक क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे वाले संगठन के रूप में रूपान्तरण करने के लिए डॉ० सुन यात-सेन की बढ़-चढ़कर सहायता करने का फैसला किया, अर्थात् श्रमिक-वर्ग तथा अन्य जनवादी शक्तियों का साँझा मोर्चा बनाने का फैसला किया ।

आधुनिक चीन के इतिहास में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तथा पार्टी के संगठनात्मक सिद्धांतों, कार्यनीतिक सिद्धांतों तथा कार्यक्रम का निर्धारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं । तब से चीनी क्रांति के रूपाकार में एक मौलिक परिवर्तन आया । परन्तु इस अवधि के दौरान पार्टी, पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति में सर्वहारा वर्ग द्वारा नेतृत्व, जनता की राजसत्ता, किसानों की जमीन की मांग, क्रान्तिकारी फौज जैसी समस्याओं पर समयानुसार उचित ध्यान नहीं दे पाई थी, या इनका सही समाधान नहीं ढूँढ पाई थी । क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार के साथ-साथ ये समस्याएँ और संगीन होती चली गईं तथा इसकी परिणति पार्टी के अन्दर दो बुनियादी रूप से पूर्णतया भिन्न कार्यदिशाओं के जन्म के रूप में हुई : बोल्शेविक

जरूरी था, क्योंकि एक ऐसे देश में, जहाँ लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही न था, पूर्णतः सशस्त्र प्रतिक्रियावादियों को पराजित करने का और कोई रास्ता नहीं हो सकता था । अन्ततः, इसने यह भी स्पष्ट किया कि क्रांति में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए, श्रमिक-वर्ग के लिए एक व्यापक संश्रय कायम करना जरूरी था, अर्थात् किसानों के साथ—जो देश की कुल आबादी का 80 प्रतिशत थे; शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग के साथ—जिसकी तादाद करोड़ों में थी तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के उन जनवादी धड़ों, जिनकी प्रवृतियां साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी थीं, के साथ संश्रय कायम करना जरूरी था ।

इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने डॉ० सुन यात-सेन के नेतृत्व वाली क्वोमिंताङ के साथ एक क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा बनाने, तथा साम्राज्यवादियों और सामंती युद्ध-सरदारों के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई शुरू करने के लिए सेना गठित करने में उसकी सहायता करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने शुरू कर दिए । ●

4.

● संयुक्त-मोर्चा बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के मूल कार्यनीतिक सिद्धांत।

जून, 1923 में कैंटन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया । इसमें 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 432 पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । विचार-विमर्श का केन्द्र बिंदु था : डॉ० सुन यात-सेन के नेतृत्व वाली क्वोमिंताङ के साथ एक क्रांतिकारी संयुक्त-मोर्चे की स्थापना ।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा मुक्ति प्राप्त करने से पहले, एक दुर्जेय तथा खूंखार शत्रु से टक्कर लेने के लिए श्रमिक-वर्ग को व्यापक जन-समुदाय को लामबन्द व संगठित करना तथा साम्राज्यवाद व सामंतवाद का विरोध करने के इच्छुक सभी वर्गों, पार्टियों, संगठनों तथा व्यक्तियों से जुड़ना और एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाना जरूरी था ।

राष्ट्रीय दमन सबसे बड़ा दमन था, जिसकी चीनी जनता उस समय शिकार थी । फिर भी, साम्राज्यवादियों तथा चीन में उनके पिट्ठुओं को अलग-थलग कर दिया गया था, क्योंकि अधिसंख्य जनता उनका विरोध करती थी । श्रमिक-वर्ग, किसान-समुदाय तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग, ये सभी उनके विरुद्ध थे । इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के भी अपरिहार्य परिस्थितियों में एक निश्चित सीमा तक विरोध में शामिल होने की संभावना थी । इसलिए चीन में क्रांतिकारी संयुक्त-मोर्चे का गठन स्पष्टतया संभव था ।

पार्टी ने इस प्रश्न के महत्त्व को पहचानने में तनिक देर न की । तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस के मौके पर यह बिल्कुल ठीक निर्णय लिया गया कि चीन में क्रांति लाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के मध्य सहयोग पर आधारित एक क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा बनाया जाए । कांग्रेस ने इस प्रकार पार्टी के मूल कार्यनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित कर दिया।

तुङ मङ-ह्वेइ, जो क्वोमिंताङ की पूर्ववर्ती संस्था थी, 1911 की क्रांति की मुख्य संगठक थी । राजनीतिक दृष्टि से यह पूँजीपति एवम् निम्न-पूँजीपति वर्ग के उग्र सुधारवादियों, उदार पूँजीपतियों तथा मंचू विरोधी जमींदारों का ढीला-ढाला गठबन्धन था । 1911 की क्रांति की असफलता के पश्चात् यह दो हिस्सों में बंट गया । एक हिस्सा समझौतावादियों के कई

छोटे-छोटे राजनीतिक गुटों, मुख्यतः आरंभिक मंचू-विरोधी जमींदारों तथा उदारवादी पूँजीपतियों से मिलकर बना था, जो साम्राज्यवादियों तथा चीनी प्रतिक्रियावादियों से जा मिले । दूसरा भाग, जिसका नेतृत्व डॉ० सुन यात-सेन के हाथों में था, पूँजीवादी जनवादियों का था, जो यद्यपि अभी भी लोकतांत्रिक संघर्ष पर डटे हुए थे लेकिन निरंतर आ रहे गतिरोधों के कारण तेजी से विघटित हो रहे थे, क्योंकि वे क्रांति का सही रास्ता ढूँढ़ने में विफल रहे थे तथा उन्हें यह मालूम नहीं था कि क्रांतिकारी शक्ति स्रोत कहाँ ढूँढे जाएँ । तथापि, रूस में अक्तूबर सामाजिक जनवादी क्रांति की सफलता, चीन तथा अन्य पूर्वी देशों की दबी-कुचली जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के प्रति सोवियत-संघ की सही नीति, सुन यात-सेन की क्रांतिकारी गतिविधियों में सोवियत-संघ की दिलचस्पी तथा सहायता, 4 मई आंदोलन के पश्चात चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन का उत्थान तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना—इन सभी तथ्यों ने डॉ० सुन तथा क्वोमिंताङ के अन्य प्रगतिशील सदस्यों का, धीरे-धीरे ध्यान आकर्षित किया तथा उन्हें चीन में क्रान्ति लाने के लिए सोवियत-संघ से संश्रय कायम करने व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करने को प्रेरित किया ।

क्योंकि डॉ० सुन यात-सेन के नेतृत्व वाली क्वोमिंताङ में पूँजीवादी क्रांतिकारी जनवादी थे तथा भूतपूर्व मंचू-विरोधी संयुक्त-मोर्चे के घटक के रूप में कार्य करने के कारण उसकी व्यापक ख्याति थी, इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके साथ सहयोग करने, उसे क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के रूप में बदलने तथा कम्युनिस्टों की अगुवाई में उसे श्रमिक-वर्ग व अन्य क्रांतिकारी शक्तियों का साम्राज्यवाद व सामंतवाद विरोधी जनवादी क्रांतिकारी गठबंधन बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए ।

साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरुद्ध डॉ० सुन की जनवादी सोच तथा क्वोमिंताङ का श्रमिक-वर्ग, किसान समुदाय, निम्न-पूँजीपति वर्ग तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के गठबन्धन के रूप में रूपान्तरण करने की संभावनाओं का भली-भांति आकलन करके कांग्रेस ने क्वोमिंताङ के साथ सहयोग करने की नीति निर्धारित की ।

कांग्रेस में इस नीति पर विचार-विमर्श करने पर कटु-संघर्ष छिड़ गया । जिसके चलते पार्टी में दो अवसरवादी रुझानों का पर्दाफाश हुआ तथा उनका खण्डन किया गया ।

पहला रुझान आत्मसमर्पणकारी रुझान था, जिसका प्रतिनिधित्व छन तू-श्यू करता था। इन आत्मसमर्पणकारियों का विचार था—कि मौजूदा क्रांति के पूँजीवादी-जनवादी प्रकृति की होने के कारण, उस का नेतृत्व पूँजीपति वर्ग को ही करना चाहिए, कि "सारा काम क्वोमिंताङ के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए", और यह कि "जनवादी क्रांति के सफल होने पर सर्वहारा-वर्ग को थोड़े से अधिकारों तथा आज़ादी के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा ।" अतः उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इस पहली क्रांति में सर्वहारा को निष्क्रिय तथा अनुपूरक भूमिका निभानी चाहिए, न कि एक नेता की । उनके मतानुसार सर्वहारा को पूँजीवादी जनतंत्र की स्थापना होने तथा पूँजीवाद के और अधिक विकसित होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए; तथा इसके बाद पूँजीवादी जनतंत्र को उखाड़कर उसके स्थान पर सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना करनी चाहिए तथा इस प्रकार समाजवाद साकार हो सकेगा । अतः उनका सिद्धात "द्वैत क्रांति का सिद्धांत" (दो मंजिलों में क्रांति करने का सिद्धान्त) नाम से जाना गया ।

छन-तू-श्यू ने चीनी क्रांति के लिए एक फार्मूला भी पेश किया । उसने कहा,

"क्वोमिंताङ का मौजूदा काम क्रान्तिकारी सर्वहारा-वर्ग के सहयोग से क्रांतिकारी पूँजीपति वर्ग का मार्गदर्शन करना है ताकि पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति लाई जा सके ।" उसकी राय में चीनी क्रांति का नेता क्वोमिंताङ को होना था, जो मुख्यतः पूँजीपति वर्ग द्वारा संगठित थी, तथा क्रांति को मुख्य शक्ति राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से प्राप्त करनी थी, जबकि श्रमिक वर्ग को केवल उसकी रिजर्व सेना के रूप में काम करना था। जहाँ तक किसानों का सवाल था, उन्हें तो क्रांति की प्रेरक शक्तियों में शामिल तक नहीं किया गया, बल्कि पूर्ण विस्मृति के गर्त में धकेल दिया गया।

दूसरा रुझान कट्टरतावादी रुझान था, जिसका नेतृत्व चाङ क्वो-थाओ करता था । कट्टरतावादियों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी को क्वोमिंताङ के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्वोमिंताङ क्रांतिकारी नहीं थी और यह कि श्रमिक-वर्ग को अकेले ही कम्युनिस्ट पार्टी के झण्डे तले क्रांति लानी चाहिए थी । उनका तर्क था कि क्वोमिंताङ के साथ सहयोग करने से श्रमिकों में सैद्धांतिक भटकाव पैदा होना था । इसी कारण से उन्होंने साम्यवादियों, श्रमिकों तथा किसानों के क्वोमिंताङ से सम्बद्ध होने का विरोध किया ।

चाङ क्वो-थाओ का विचार भी पहले वाले विचार की तरह पूर्णरुपेण भ्रांतिपूर्ण था। कट्टरपंथी यह समझने में चूक कर गए कि संश्रयकारियों का प्रश्न क्रान्ति के सर्वहारा नेतृत्व की कुंजी था तथा यह कि सर्वहारा को अपने संश्रयकारियों के साथ सम्बद्ध होने के सभी मौकों का पूरा उपयोग करना चाहिए, चाहे ये कितने भी अस्थायी और अविश्वसनीय क्यों न हों । वे यह नहीं जानते थे कि अर्ध-औपनिवेशिक चीन में श्रमिक वर्ग के लिए राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग के साथ सम्बद्ध होना संभव तथा अनिवार्य था । यह सोचना कि यदि साम्यवादी तथा श्रमिक, अपनी पार्टी के झण्डे तले क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं करेंगे तो सैद्धांतिक भ्रान्ति फैल जाएगी, वास्तव में क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे में पार्टी तथा श्रमिक-वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को नकारना था ।

कांग्रेस ने दक्षिण तथा "वाम", दोनों तरह के भटकावों की आलोचना की । इसने फैसला किया कि पार्टी को क्वोमिंताङ के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पार्टी सदस्यों के एक भाग को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से क्वोमिंताङ में शामिल हो जाना चाहिए । इस प्रकार अपनी सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता बरकरार रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को क्वोमिंताङ का राष्ट्रीय जनवादी क्रांतिकारी गठबन्धन के रूप में पुनर्गठन करने में सहायता करनी थी । कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि इस सहयोग के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी क्रांतिकारी दृढ़ता तथा सोच का प्रदर्शन करना था और अपने संश्रयकारी की समझौतावादी तथा सुधारवादी प्रवृत्तियों पर काबू पाना था । इसने ध्यान दिलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी को क्वोमिंताङ के संगठन का विस्तार करने में सहायता करनी थी तथा साथ ही प्रगतिशील श्रमिकों तथा किसानों को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल करना था । इतना सब होते हुए भी पार्टी क्रांति के नेतृत्व के प्रश्न को पूर्णरुपेण हल करने में विफल रही तथा न ही इसमें किसान समस्या तथा क्रांतिकारी सेना के सवाल पर उचित ध्यान दिया गया । कामरेड माओ त्से-तुङ ने कांग्रेस में भाग लिया तथा सही दलीलों का समर्थन व गलत का विरोध किया । इस कांग्रेस में उन्हें पार्टी की केन्द्रीय समिति का सदस्य चुन लिया गया । ●

के स्तर तक पहुँचने की जबरदस्त इच्छा रहती थी, और इस कारण इसमें क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता का अभाव रहता था । खासकर, **''जब देश में सर्वहारा वर्ग क्रान्ति में जुझारूपन के साथ हिस्सा लेता है और देश के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग इस क्रान्ति को सक्रिय रूप से सहायता देता है, उससे इसे यह महसूस होने लगता है कि एक वर्ग के रूप में आगे बढ़कर बड़े पूँजीपतियों के स्तर तक पहुँचने की इसकी इच्छा के विफल होने का खतरा पैदा हो गया है, तो क्रान्ति के प्रति यह संदेह का रुख अपना लेता है ।''**[11] यह वर्ग संपूर्ण क्रान्ति से भय खाता था । इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समझौतापरस्ती एवम् ढुलमुलपन से भी नीचे गिरकर क्रान्ति से विश्वासघात करके प्रतिक्रान्ति की पाँतों में जाकर मिल सकता था । अतः पार्टी के लिए बेहद चौकस रहना तथा इसके समझौतावादी चरित्र के खिलाफ लगातार दृढ़, किन्तु संयत संघर्ष करते रहना बेहद जरूरी था।

सन् 1911 की क्रान्ति से लेकर **30 मई 1925 के आंदोलन**[12] तक घटी घटनाओं के दौरान राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का यह दोहरा चरित्र साफ तौर से प्रकट हो गया । 1925 में तो कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने यहाँ तक हायतौबा मचाई, *''अपना बायाँ घूंसा साम्राज्यवाद को मार गिराने के लिए उठाओ और दायाँ घूंसा कम्युनिस्ट पार्टी को मार गिराने के लिये उठाओ,''*—कहने का मतलब कि पागलों की तरह दाएं-बाएं हाथ-पाँव चलाने लगो ।

कामरेड माओ ने राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का अवश्यम्भावी ध्रुवीकरण पहले से ही भाँप लिया था तथा भविष्यवाणी की कि इसका एक हिस्सा बाएं मुड़ेगा तथा क्रांति की पाँतों में शामिल हो कर, श्रमिक वर्ग का नेतृत्व स्वीकार कर लेगा तथा इसका दूसरा हिस्सा दाएं मुड़ेगा तथा प्रति-क्रांति की पाँतों में शामिल होकर दलाल-पूँजीपति वर्ग के साथ मिल जाएगा । सन् 1927 की घटनाओं ने उनकी इस वैज्ञानिक भविष्यवाणी को पूरी तरह सही सिद्ध कर दिया ।

दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि **अक्तूबर समाजवादी क्रांति** के पश्चात् विश्व दो बड़ी शक्तियों में विभाजित हो गया था—समाजवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति । चीन को उनमें से एक के पक्ष में खड़े होना होगा और दूसरी का विरोध करना होगा । और केवल समाजवादी शक्ति के साथ मिलकर तथा लेनिनवाद के झण्डे तले साम्राज्यवाद-विरोधी शिविर का अंग बन कर ही चीनी क्रांति को विजय प्राप्त हो सकती थी । ऐसा इसलिए क्योंकि अफीम युद्ध से लेकर अब तक के सभी चीनी क्रांतिकारी आंदोलनों को साम्राज्यवादियों द्वारा ही कुचला गया था, जबकि सोवियत-संघ ने अपने अस्तित्व तथा उपलब्धियों द्वारा साम्राज्यवादी प्रति-क्रांतिकारी ताकतों पर न केवल अंकुश ही लगाया था बल्कि अपने अनुभव तथा निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति द्वारा दबे-कुचले लोगों (राष्ट्रों) के संघर्ष को प्रोत्साहन एवं समर्थन भी दिया था ।

इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू स्थिति की रोशनी में, क्रांति की निम्नलिखित बुनियादी राजनीतिक दिशा निर्धारित की गई : **चीनी क्रांति विश्व सर्वहारा समाजवादी क्रांति का अंग थी। इस का नेतृत्व श्रमिक वर्ग ने करना था, जिसे किसान समुदाय तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग को अपना सर्वाधिक विश्वसनीय संश्रयकारी समझना चाहिए तथा क्रांतिकारी राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से मिलकर चलना चाहिए । इसका उद्देश्य साम्राज्यवादियों, जमींदार तथा दलाल-पूँजीपतियों के विरुद्ध लड़ना, जनवादी क्रान्ति की संपूर्ण विजय के लिए संघर्ष करना तथा समाजवाद की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करना**

अपने सभी जारशाही विशेषाधिकारों को त्यागने की उत्सुकता दोहराते हुए तथा चीन सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए पुनः अपने प्रतिनिधि को पेकिङ भेजा, तो पेकिङ के पास इन्कार करने का कोई बहाना नहीं था । संधि-वार्ता का परिणाम एक मैत्री-संधि में निकला—*''चीनी गणराज्य तथा सोवियत-संघ के बीच महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के समाधानार्थ सामान्य सिद्धांतों पर समझौता ।''*

चीन के संबंध में सोवियत वक्तव्यों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार सोवियत सरकार ने समझौते में, जारशाही तथा चीनी सरकारों के बीच सम्पन्न सभी असमान संधियों को बिना शर्त रद्द करने, चीन में मिले सभी छूट के अधिकारों (विशेषाधिकारों) व पट्टे पर लिए गए क्षेत्रों वगैरा तथा ''बॉक्सर'' क्षतिपूर्ति ('Boxer' Indemnity) व **राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों**[1] के रूसी भाग तथा चीनी पूर्वी रेलवे से संबंधित सभी विशेषाधिकारों का, (व्यापार-प्रक्रियाओं संबंधी बातों को छोड़ कर) परित्याग करने की घोषणा की । यह संधि, चीन के विदेश संबंधों के इतिहास में अभूतपूर्व थी तथा चीनी जनता ने बड़ी गर्मजोशी से इसका स्वागत किया ।

इसके अतिरिक्त सोवियत सरकार ने क्रांतिकारी सेना की स्थापना करने में डॉ० सुन यात-सेन की सहायता की । भूतपूर्व क्रांतिकारी प्रयासों की निरंतर असफलता से डॉ० सुन यात-सेन ऐसी सेना की अपरिहार्यता के कायल हो चुके थे । नतीजतन, उन्होंने सोवियत लाल सेना के नमूने पर एक ''फौजी अकादमी'' स्थापित करने का निर्णय लिया । इस फैसले के फलस्वरूप, सन् 1924 में कैंटन में ह्वाङफू फौजी अकादमी की स्थापना की गई । इस अकादमी के कैडेट हाल में स्थापित राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की रीढ़ की हड्डी बने, यह वह मुख्य लड़ाकू सेना थी, जिसने बाद के वर्षों में सारे क्वाङतुङ को क्रांतिकारी सरकार के नियंत्रण में ला दिया था तथा **'उत्तरी अभियान'** को कार्यान्वित किया था ।

क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे की स्थापना से साम्राज्यवादी, युद्ध-सरदार तथा दलाल-पूँजीपति वर्ग जल-भुन तथा भयभीत हो गए, उन्होंने इसका विरोध करने के लिए संयुक्त प्रयास आरंभ कर दिए । क्वोमिंताङ के भीतर भी यह संघर्ष फङ जू-ग्वी तथा अन्य प्रतिक्रियावादियों की गतिविधियों में प्रतिबिंबित हुआ, जिन्होंने क्वोमिंताङ-कम्युनिस्ट सहयोग, कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत-संघ तथा श्रमिक हड़तालों का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया तथा साम्राज्यवादियों एवं अन्य सभी प्रतिक्रियावादियों से साँठ-गाँठ करके एक साम्यवाद-विरोधी गठजोड़ बनाना आरंभ कर दिया । बाद में उनका अनुसरण, चाङ ची, शिह च, छओ ल्यू तथा क्वोमिंताङ में मौजूद अन्य साम्यवाद-विरोधी तत्वों ने किया, जो कि क्वोमिंताङ-कम्युनिस्ट सहयोग तथा क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे का भी विरोध करते थे ।

क्रांतिकारियों तथा प्रति-क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष ने 1924 में क्वाङतुङ व्यापारी स्वयंसेवक कोर की घटना के समय भीषणतम रूप धारण कर लिया, यह कोर जमींदारों तथा दलाल-पूँजीपतियों का एक सशस्त्र गिरोह थी, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश स्वामित्व वाले हांगकांग एवम् शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन के दलाल-पूँजीपति छन लिम-पाक के हाथों में था । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की मदद से तथा युद्ध-सरदार छन चियुङ-मिङ के साथ मिलकर, कोर ने क्वाङतुङ स्थित डॉ० सुन यात-सेन की क्रांतिकारी सरकार पर अन्दर और बाहर से हमला करके तख्ता पलटने का षड्यन्त्र रचा । लेकिन डॉ० सुन यात-सेन ने संघर्ष में दृढ़ निश्चय का परिचय दिया । श्रमिकों तथा किसान समुदाय के सहयोग से क्रांतिकारी सरकार ने व्यापारी

स्वयंसेवक कोर के सशस्त्र उपद्रव को सफलतापूर्वक दबा दिया ।

चीनी क्रांति के उत्थान से श्रमिक-वर्ग आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ ।

7 फरवरी के नरसंहार के बाद पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग तथा ऊहान शहर के श्रमिक-संघों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा कैंटन एवं हुनान के श्रमिक-संघों को छोड़कर, शेष अन्य श्रमिक-संघों को भी भूमिगत होने को विवश होना पड़ा । यद्यपि कैंटन की क्रांतिकारी सरकार ने श्रमिक-संघों को मान्यता दे दी थी, तथा आनय्वान श्रमिक-संघ ने जो कि संघर्ष में डटा रहा था, काफी सफलता प्राप्त की थी, फिर भी कुल मिलाकर देश का श्रमिक-वर्ग आंदोलन अस्थायी तौर से उतार पर था । उस समय श्रमिक-संघों का अत्यावश्यक कार्य श्रमिकों को राहत प्रदान करना तथा संघर्ष को पुनः आरंभ करना था । श्रमिक-संघ सचिवालय ने एक विशेष कमेटी बनाई जिसका काम दमन के शिकार श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए चन्दा इकट्ठा करना था । अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक-वर्ग आंदोलन के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हुए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फैक्ट्री ट्रेड-यूनियन ग्रुपों को संगठित करने के काम को अपने मुख्य कार्य के रूप में लिया, अर्थात् श्रमिक-वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से फैक्ट्री वर्कशापों में दस सदस्यों से कम के गुप्त ग्रुप बनाए गए । फरवरी 1924 में पेकिङ में **राष्ट्रीय रेल-मजदूर ट्रेड-यूनियन फेडरेशन** की स्थापना की गई ।

क्वोमिंताङ के राजनीतिक कार्यक्रम में ''श्रम-कानूनों को लागू करने'' तथा ''**श्रमिक संगठनों** की रक्षा करने'' का प्रावधान था । इस प्रकार कैंटन में श्रमिक-वर्ग आंदोलन आगे बढ़ने में कामयाब हुआ तथा एक श्रमिक-सेना भी स्थापित की गई ।

कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलाई 1924 में शाम्येन नामक बरतानवी छूट वाले (विशेषाधिकार वाले) क्षेत्र में स्थित विदेशी कारखानों में नए पुलिस-कानून—जिसके अनुसार प्रत्येक चीनी को उस क्षेत्र में प्रवेश करते तथा बाहर आते समय अपना परिचय देना होता था—के विरोध में हुई श्रमिकों की एक विशाल हड़ताल का नेतृत्व किया । हड़ताल एक महीने से ऊपर चली तथा साम्राज्यवादियों को अंततः यह भेदभावपूर्ण नियम वापिस लेने को बाध्य होना पड़ा । हड़ताल से केवल स्थानीय स्तर पर ही सनसनी नहीं फैली, बल्कि इसकी प्रतिध्वनि मध्य तथा उत्तरी चीन तक गूँजी । इसके बाद शंघाई स्थित नानयाङ तम्बाकू फैक्ट्री में हड़ताल हुई, हानखओ के रिक्शा चालकों, सूचओ के बुनकरों तथा चच्याङ स्थित ख्वीयाओ के नमक-श्रमिकों ने भी हड़ताल की । इनमें से प्रत्येक हड़ताल में 10,000 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया । इस सब से, देश में श्रमिक-वर्ग आंदोलन के पुनरुत्थान का संकेत मिला ।

इसी समय के दौरान दक्षिण में किसान-आंदोलन भी लगातार विकसित होता रहा । सन् 1921 में **फङ पाए**[2] ने पहले से ही क्वाङतुङ के किसानों में काफी क्रांतिकारी काम किया हुआ था । हाएफङ किसान सभा—जिसकी स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी तथा जिसकी सदस्य संख्या 1,00,000 थी—ने निरंकुश जमींदारों के विरुद्ध तथा लगान में कमी के लिए संघर्ष किए थे । यद्यपि प्रतिक्रियावादी युद्ध-सरदार छन चियुङ-मिङ ने फरवरी 1924 में इसे भंग कर दिया, फिर भी किसान संगठन का यह रूप जल्दी ही हाएफङ और लूफङ से छाओचओ तथा शानथओ तक और फिर सारे क्वाङतुङ प्रान्त में फैल गया । अक्तूबर 1923 में पार्टी ने हुनान प्रान्त में हङशान में एक लाख किसानों को किसान सभाओं में संगठित किया तथा हुनान के युद्ध-सरदारों तथा जमींदारों के खिलाफ भीषण संघर्ष छेड़ने में उनका मार्गदर्शन

के कारण चीनी क्रांति के नेतृत्व का भार स्वाभाविक रूप से श्रमिक वर्ग के कंधों पर आ पड़ा था ।

श्रमिक वर्ग चीन की नई उत्पादक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था तथा आधुनिक चीन में सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग था । यह अत्यधिक केन्द्रित वर्ग था, इसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, फलतः क्रांतिकारी संघर्ष में यह अपने आपको सर्वाधिक जुझारू सिद्ध करता था । हाल ही में हुई ऐतिहासिक महत्त्व की कई हड़तालों, जैसे कि नाविकों, रेलवे कर्मचारियों, कोयला खनिकों और विशेषकर शंघाई तथा हांगकांग के श्रमिकों की हड़तालों ने इसकी शक्ति को पूर्णतया ठोस रूप में सिद्ध कर दिया था ।

इन तथ्यों से कामरेड माओ ने निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि श्रमिक वर्ग को ही चीनी क्रान्ति का नेता होना चाहिये ।

किसान समुदाय तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग के विशालतम तथा सर्वाधिक विश्वसनीय संश्रयकारी थे । कामरेड माओ ने किसान समुदाय तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के आर्थिक स्तर तथा क्रान्ति के प्रति उनके अलग-अलग रुझान का ठोस रूप से विश्लेषण किया, तथा उनके क्रान्तिकारी रुझान के विभिन्न स्तरों को भी स्पष्ट किया । उनका एक छोटा हिस्सा—**भूमिधर किसान**[7], दस्तकार तथा छोटे बुद्धिजीवी वर्ग—सामान्य हालात में साम्राज्यवादियों एवम् युद्ध-सरदारों के खिलाफ संघर्ष की विजय के बारे में संदेहशील हो सकता था लेकिन ज्योंही क्रान्तिकारी उभार के समय विजय की लालिमा दिखाई देने लगती, इसने क्रान्ति की पांतों में शामिल हो जाना था । उनमें से **अर्ध-भूमिधर किसानों**[8], गरीब किसानों, छोटे दस्तकारों तथा दुकान-कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सदा से बेहद दबी-कुचली तथा शोषित अवस्था में रहता आ रहा था । फलतः इन श्रेणियों पर क्रान्तिकारी प्रचार का असर बड़ी जल्दी होना था और इन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रान्ति के संघर्ष में कूद पड़ना था । **''अर्ध-भूमिधर किसानों की भारी बहुसंख्या और गरीब किसान, ये दोनों मिलकर देहात की आम जनता का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते थे । किसान समस्या मूलतः इन्हीं की समस्या थी ।''**[9] एक वर्ग के रूप में किसान समुदाय के पास विशाल क्रान्तिकारी शक्ति-स्रोत था । इस प्रकार कामरेड माओ ने क्रान्ति में सबसे मुख्य संश्रयकारी की समस्या, दूसरे शब्दों में, श्रमिक-किसान संश्रय की समस्या को हल कर दिया।

राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का क्रान्ति के प्रति असंगत रुख था, क्योंकि इसमें क्रान्तिकारी एवम् समझौतापरस्त, दोनों पक्ष थे । इसका यह दोहरा चरित्र इसकी अपनी आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित किया गया था ।

साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद ने चीन के राष्ट्रीय पूँजीवाद का विकास अवरुद्ध कर दिया था । कामरेड माओ त्से-तुङ के शब्दों में, **''जब वह विदेशी पूँजी की मार और युद्ध-सरदारों के उत्पीड़न से त्रस्त होता है, तो उसे क्रान्ति की जरूरत महसूस होती है और वह साम्राज्यवाद व युद्ध-सरदारों के खिलाफ क्रान्तिकारी आंदोलन का पक्ष-पोषण करता है ।''**[10]

अतः इसके क्रान्ति में शामिल होने की संभावना थी और इसलिए पार्टी को इसके साथ अवश्य ही संश्रय कायम करना चाहिये था । परन्तु दूसरी ओर, इसका विकास किसी हद तक साम्राज्यवाद व सामन्तवाद से जुड़ा हुआ था, और इसकी हमेशा आगे बढ़कर बड़े पूँजीपतियों

क्रान्ति का नेतृत्व कौन करेगा—सर्वहारा या पूँजीपति वर्ग ? श्रमिक-वर्ग का बुनियादी संश्रयकारी कौन होगा—किसान समुदाय या पूँजीपति वर्ग ? बहुत से कम्युनिस्ट अभी इन सवालों का सही जवाब नहीं ढूंढ़ पाए थे । छन तू-श्यू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट का मानना था—कि पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति का नेतृत्व पूँजीपति वर्ग को ही करना चाहिये, कि इस क्रान्ति का लक्ष्य एक पूँजीवादी गणराज्य स्थापित करना था और यह कि केवल पूँजीपति वर्ग ही एक ऐसी जनवादी शक्ति था जिसके साथ मजदूर-वर्ग को संश्रय स्थापित करना चाहिये था । वे पूँजीपति वर्ग के साथ सहयोग करने के विचार में इतने खोए हुए थे वे अपने विशालतम, सबसे विश्वसनीय तथा बुनियादी संश्रयकारी—किसान समुदाय को बिल्कुल ही भूल गए थे, जिसके फलस्वरूप क्रान्तिकारी संघर्ष में उन्होंने स्वयं को असहाय तथा कमजोर पाया । दूसरी ओर, चाङ क्वो-थाओ "वामपंथी" अवसरवादियों को केवल श्रमिक-वर्ग आन्दोलन ही दिखाई दे रहा था; उन्होंने भी किसान-समुदाय को अनदेखा किया। दोनों प्रकार की अवसरवादी विचारधाराओं वाले गुट अपनी-अपनी कमंजोरी से वाकिफ थे, फिर भी उन्हें यह मालूम नहीं था कि एक शक्तिशाली संश्रयकारी कहां ढूंढ़ा जाए ।

पार्टी में उत्पन्न इन दोनों भ्रांतिपूर्ण धारणाओं का विरोध करने के लिए कामरेड माओ ने मार्च 1926 में **"चीनी समाज में वर्गों का विश्लेषण"** शीर्षक से एक लेख लिखा ।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख, दृष्टिकोण तथा तरीके, एवं उपनिवेशों में राष्ट्रीय क्रान्ति के बारे में लेनिनवादी सिद्धान्त को आधार बनाकर; कामरेड माओ त्से-तुङ ने नवजनवादी क्रान्ति पर, यानि कि मज़दूर-किसान संश्रय पर आधारित सर्वहारा के नेतृत्व में होने वाली जनसाधारण की क्रान्ति पर अपने बुनियादी विचार रखे । ये विचार निम्नलिखित दो तथ्यों पर आधारित थे:

पहला, घरेलू स्थिति के बारे में, कामरेड माओ ने चीनी समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक रुझानों के बारे में पहला वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया ।

".....वे सभी लोग जो साम्राज्यवाद से मिले हुए हैं—युद्ध-सरदार, नौकरशाह, दलाल-पूँजीपति वर्ग, बड़े जमींदारों का वर्ग और उन पर निर्भर बुद्धिजीवियों का प्रतिक्रियावादी तबका—हमारे दुश्मन हैं । औद्योगिक सर्वहारा वर्ग हमारी क्रान्ति की नेतृत्वकारी शक्ति है । अर्ध-सर्वहारा वर्ग और निम्न-पूँजीपति वर्ग की सभी श्रेणियां हमारे सबसे नजदीकी दोस्त हैं । जहां तक ढुलमुल मध्यम-पूँजीपति वर्ग (यहां कामरेड माओ का तात्पर्य राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से था) का संबंध है, उसका दक्षिण पक्ष हमारा शत्रु बन सकता है और वाम पक्ष हमारा दोस्त बन सकता है । लेकिन उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिये और हमारी पांतों में उन्हें उलझन पैदा नहीं करने देना चाहिये।"[6]

चीनी जमींदार वर्ग तथा दलाल-पूँजीपति वर्ग, चीन में उत्पादन के अत्यधिक प्रतिक्रियावादी और पिछड़े सम्बन्धों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा ये चीन की सामाजिक उत्पादक शक्तियों के विकास में भारी गतिरोध उत्पन्न करते थे । अपने अस्तित्व तथा विकास के लिए वे साम्राज्यवादियों पर पूर्णरुपेण निर्भर थे तथा वास्तव में वे उनके पिछलग्गुओं के अतिरिक्त और कुछ न थे । अत: उनके अस्तित्व का चीनी क्रांति के उद्देश्यों से कतई मेल नहीं बैठता था। दूसरे शब्दों में, वे प्रतिक्रियावादी थे तथा चीनी क्रांति के शत्रु थे और उसका मुख्य निशाना थे।

श्रमिक वर्ग, किसान समुदाय, निम्न-पूँजीपति वर्ग तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग चीन में क्रांतिकारी वर्ग थे । श्रमिक वर्ग की विशाल शक्ति तथा पूँजीपति वर्ग की अत्यधिक कमजोरी

किया । दक्षिण में क्वाङतुङ तथा हुनान में केन्द्रित किसान-आंदोलन ने न केवल अपने संगठनों का विस्तार किया तथा आर्थिक संघर्ष चलाए, बल्कि राजनीतिक संघर्षों में भी भाग लिया । कैंटन के इर्द-गिर्द किसानों के आत्म-रक्षा दस्तों ने व्यापारी स्वयंसेवक कोर द्वारा मचाए जा रहे दंगे-फसाद को कुचलने में सुन यात-सेन की सहायता भी की ।

अक्तूबर 1924 में दूसरी चली-फङय्येन लड़ाई के दौरान फङ ग्वी-श्याङ ने चली गुट का तख्ता पलट दिया । उसने अपनी फौज का **राष्ट्रीय सेना** के नाम से पुनर्नामकरण किया तथा चली युद्ध-सरदारों को पेकिङ से निष्कासित कर दिया ।

राज-विप्लव के परिणामस्वरूप, फङय्येन युद्ध-सरदारों का प्रभाव उत्तरी चीन में भी फैल गया तथा अन्ततः उन्होंने पेकिङ की राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली । चली गुट की मुख्य सेनाएँ, ऊ फेइ-फू की हार के बाद याङत्सी नदी की घाटी में पीछे हट गईं तथा वापिस लौटने के लिए अपनी शक्ति बटोरने में जुट गईं । पेकिङ शासन ने, गठबन्धन सरकार का रूप ले लिया, जिस पर तीन गुटों का कब्जा था : चाङ च्वो-लिन, त्वान छी-रुइ तथा फङ ग्वी-श्याङ । त्वान छी-रुइ मुखिया था, उसे अंतरिम कार्यकारी जनरल की उपाधि दी गई ।

चूंकि पेकिङ में नई युद्ध-सरदार सरकार अभी अस्थिर थी, इसलिए श्रमिक-दमन में अस्थाई रूप से ढील आ गई थी । इससे पार्टी को 7 फरवरी के नरसंहार के समय से कैद श्रमिक नेताओं को छुड़वाने, रेलवे श्रमिक-संघों को पुनः स्थापित करने तथा बेरोजगार श्रमिकों के लिए काम ढूंढ़ने का मौका मिला । सन् 1925 के फरवरी माह में पेकिङ में रेलवे श्रमिक-संघों की द्वितीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, जिसके परिणामस्वरूप छिङताओ-चीनान के रेल कर्मचारियों की विशाल हड़ताल हुई तथा इसके पीछे-पीछे पेकिङ, ऊहान, शनयाङ तथा ताङशान आदि स्थानों में भी हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा ।

इन हालात के चलते, पार्टी ने राष्ट्रीय असेम्बली बुलाने तथा असमान संधियों को रद्द करने के लिए राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन शुरू करके, व्यापक जनसमुदाय को जनवादी क्रांति के झण्डे तले लामबन्द तथा संगठित करने का निर्णय लिया । पार्टी के आह्वान पर क्रमशः शंघाई, चच्याङ, क्वाङतुङ, हुपे, हुनान तथा अन्य स्थानों पर "राष्ट्रीय असेम्बली के प्रोत्साहन के लिए संस्थाएँ" स्थापित की गईं ।

जनवरी 1925 में जब जन-आंदोलन पहले से ही पूरे जोरों पर था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी राष्ट्रीय कांग्रेस शंघाई में आयोजित की गई । इसमें 20 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो 980 पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

कांग्रेस ने उस समय की राजनीतिक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया तथा पार्टी के राजनीतिक कार्य क्या हों ?—इसका निर्णय लिया । यह एक ऐसा समय था जब युद्ध-सरदारों का शासन तीव्र गति से पतनोन्मुख हो रहा था, क्योंकि पुराने शासक युद्ध-सरदारों का तख्ता पलट दिया गया था, तथा नए शासक युद्ध-सरदारों ने अभी अपनी स्थिति सुदृढ़ न की थी । यह परिस्थिति चीन में जन-आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल थी । जैसा कि आंदोलन की सफलता पूरी तरह पार्टी की नीतियों तथा जनता के बीच उसके संगठनात्मक कार्य तथा प्रचार पर निर्भर थी, इसलिए राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन को विकसित करने की समस्या स्वभावतः, कांग्रेस में विचार-विमर्श का केन्द्र बनी ।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पूँजीवादी-जनवादी क्रांति में भाग लेने के पीछे श्रमिक-वर्ग का

अपना एक लक्ष्य था, और वह था—जनवादी क्रान्ति की पूर्ण सफलता के पश्चात् जनता को सर्वहारा-क्रांति की ओर ले जाना । अत: इस क्रांति में श्रमिक-वर्ग की भूमिका अन्य वर्गों से भिन्न थी । श्रमिक-वर्ग को किसी भी कीमत पर पूँजीपति-वर्ग का दुमछल्ला नहीं बनना था, बल्कि उसे अपनी स्वयं की स्वतंत्रता तथा लक्ष्य बरकरार रखने थे, केवल श्रमिक-वर्ग द्वारा नेतृत्व हाथ में लेने से ही चीनी जनवादी क्रांति को पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती थी ।

कांग्रेस ने ध्यान दिलाया कि ट्रेड-यूनियन आंदोलन, दोबारा आगे बढ़ रहा था तथा इसके लिए एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था । राष्ट्रीय असेम्बली बुलाये जाने की उस वक्त सुस्पष्ट तथा निश्चित संभावना थी । इसलिए श्रमिक-वर्ग को राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन में अपने लिए नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त करने के लिए आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभानी थी तथा अपने खुद के शक्तिशाली लोकप्रिय संगठन स्थापित करने थे । युद्ध-सरदारों के कब्जे वाले क्षेत्रों में ये संस्थाएँ ट्रेड-यूनियन ग्रुपों के रूप में होनी चाहिएं । जिस भी फैक्ट्री या वर्कशॉप में तीन से ऊपर श्रमिक हों, वहाँ ट्रेड-यूनियन ग्रुप बनाया जाए, हर फैक्ट्री में विभिन्न विभागों के अनुसार इन ग्रुपों को शाखाओं में संगठित किया जाए, इन शाखाओं के ऊपर फैक्ट्री श्रमिक-संगठन होने चाहिएं, जिन्हें क्षेत्रीय श्रमिक-संगठनों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

संगठनात्मक कार्य, सबसे पहले, रेलवे, खदानों, तथा सूती वस्त्र जैसे उद्योगों में, तथा शंघाई, हानखओ और थ्येनचिन जैसे नगरों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

कांग्रेस ने आगे स्पष्ट किया कि किसान समुदाय चीन के राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन की बुनियादी शक्ति तथा श्रमिक-वर्ग का मुख्य संश्रयकारी था । इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को, राजनीतिक तथा आर्थिक संघर्ष चलाने के लिए, किसानों को संगठित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए । अन्तत: जमींदारी शासन-व्यवस्था तथा उसके सशस्त्र सैन्य-दलों से लड़ने के लिए किसान-सभाओं तथा किसान आत्मरक्षा दलों का गठन करने का निर्णय लिया गया । साथ ही किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए दक्षिणी प्रान्तों में हुए किसान आंदोलनों से प्राप्त अनुभवों का पूरा प्रचार तथा इस्तेमाल करना था ।

पिछले एक साल के दौरान संयुक्त मोर्चे के काम में "वामपंथी" तथा दक्षिणपंथी अवसरवाद की गलतियों की कांग्रेस ने आलोचना की तथा क्वोमिंताङ के पुनर्गठन के बाद से मोर्चे में वामपंथी, मध्यमार्गी तथा दक्षिपंथी गुटों के आविर्भाव की ओर ध्यान दिलाया । कांग्रेस ने वामपंथी गुट को बढ़ावा देने, मध्यमार्गियों की आलोचना करने व दक्षिणपंथियों का विरोध करने की नीति को अपनाया ।

पार्टी की चतुर्थ राष्ट्रीय कांग्रेस की उपलब्धि खासतौर से यह थी कि इसने पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर जन-आन्दोलनों की एक नई लहर के लिए तैयार किया ।

कृषि-संबंधी कार्यक्रम पेश करने में यह कांग्रेस भी असफल रही ।

पेकिङ में राज्य-विप्लव के दौरान फङ ग्वी-श्याङ का क्रांति की ओर झुकाव था तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उसने डॉ० सुन यात-सेन को उत्तर की तरफ आने का आमन्त्रण भेजा । त्वान छी-रुइ तथा चाङ च्वो-लिन, इन दोनों ने भी लोकप्रियता अर्जित करने के लिए, राष्ट्रीय मसलों पर परामर्श करने के बहाने डॉ० सुन यात-सेन को वैसा ही प्रस्ताव भेजा । कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत समर्थन के साथ 1924 के अक्तूबर माह में डॉ० सुन क्वाङतुङ से पेकिङ के लिए रवाना हुए तथा **"मेरी उत्तर की यात्रा के बारे में**

सहयोग प्रदान किया ।

उस समय, क्वाङतुङ उन प्रदेशों में से एक था, जहाँ किसान आंदोलन ने काफी प्रगति की थी । श्रमिक-किसान आन्दोलन के फलस्वरूप ही क्वाङतुङ की सरकार स्थापित तथा सुदृढ़ की जा सकी ।

उत्तरी अभियान की पूर्ववेला पर हुनान, हुपे तथा च्याङशी में किसान आंदोलन का विकास होना आरंभ हो गया । हुनान में लगभग 10 लाख के करीब किसान पार्टी के प्रभाव में थे, तथा इनमें से चार लाख से अधिक संगठित थे । हुपे में किसान सभाओं की सदस्य संख्या 72,000 थी । इन प्रांतों के किसान आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे तथा क्रान्तिकारी सेना के उत्तर की तरफ बढ़ने के अभियान में सहायक तथा मार्गदर्शक की भूमिका अदा करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे ।

हनान, शेनशी, शानतुङ, हपे व दूसरे उत्तरी प्रान्तों में युद्ध-सरदारों के बीच के गृहयुद्धों, बेहिसाब लेवियों, विभिन्न प्रकार के टैक्सों, लगान की अग्रिम अदायगी तथा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह लगातार भड़क रहे थे । अपने संघर्षों में किसान प्राचीन संगठनों जैसे—*'लाल भाला समाज'* आदि के नाम का इस्तेमाल करते थे, परन्तु चूंकि ऐसे संगठन आमतौर से जमींदारों तथा धनी-किसानों के प्रभुत्व में होते थे, इसलिए वे अक्सर जमींदार वर्ग के हितों का ही पोषण करते थे । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों द्वारा, उत्तरी चीन में पाए जाने वाले ऐसे प्राचीन संगठन, धीरे-धीरे प्रगतिशील संगठनों यानि कि किसान सभाओं में परिवर्तित हो गए । अप्रैल 1926 में हनान की प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी सदस्य संख्या 2,70,000 थी तथा किसान आत्म-रक्षा दस्तों की सदस्य संख्या एक लाख थी । युद्ध-सरदारों के शासन के दौरान, किसानों ने लेवियों तथा करों के भुगतान के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा । ●

4.

- **नवजनवादी क्रांति के मूल-सिद्धान्तों पर माओ त्से-तुङ के विचार ।**
- **ताए ची-थाओ के प्रतिक्रियावादी हथकंडे ।**
- **च्याङ काई-शेक के दक्षिणपंथियों द्वारा क्रान्ति का नेतृत्व हथियाने का षड्यन्त्र।**
- **छन तू-श्यू के दक्षिणपंथी अवसरवादी गुट द्वारा च्याङ काई-शेक को दी गई रियायतें।**

सन् 1924 से 1926 के आरंभिक दिनों तक चीनी क्रांति ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की । क्वाङतुङ में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र के सुदृढ़ होने तथा राष्ट्रव्यापी श्रमिक-वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन के उत्थान से, सारे देश में क्रांति तथा प्रतिक्रांति के बीच निर्णायक युद्ध की घड़ी आ पहुँची थी । क्रांतिकारी खेमे के भीतर भी क्रांति तथा प्रतिक्रांति के बीच एवं सर्वहारा तथा पूँजीपति वर्ग के बीच संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया था ।

1926 में उत्तरी अभियान की पूर्ववेला पर कुल मिलाकर यह स्थिति थी ।

इस नाजुक मोड़ पर, कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी इसी मूलभूत प्रश्न को लेकर बैठी हुई थी कि क्रान्ति को विजयश्री किसके नेतृत्व में मिल सकती थी । और भी स्पष्ट शब्दों में यह कि

अक्तूबर 1925 में क्रान्तिकारी सेना ने छन चियुङ-मिङ के विरुद्ध **द्वितीय पूर्वी अभियान** छेड़ा । युद्ध-सरदार के गढ़ ह्वेइचओ पर कब्जा करके यह अभियान शुरू किया गया। अक्तूबर के अंत तक, क्रांतिकारी सेना ने छन की सारी की सारी फौज को कुचल दिया तथा तुङच्याङ का सारा इलाका पुनः प्राप्त कर लिया ।

इसके बाद **दक्षिणी अभियान** आरंभ हुआ । दिसंबर में क्रान्तिकारी सेना ने काओचओ, लेइचओ, चिनचओ तथा ल्येनचओ पर कब्जा कर लिया तथा फरवरी 1926 में हाएनान द्वीप में शत्रु की बची-खुची फौज का सफाया कर दिया । इस प्रकार क्वाङतुङ का समूचा प्रदेश क्रांतिकारी सेना के कब्जे में आ गया ।

मई 1925 से जुलाई 1926 तक किसान आंदोलन ने भी सारे देश में तेज़ी से प्रगति की। 30 मई के आंदोलन ने देश भर में किसान आंदोलन को ज़ोरदार गति प्रदान की । साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के बाद किसान संघर्ष राष्ट्रीय क्रांतिकारी संघर्ष के साथ जुड़ गया तथा चीनी क्रांति में एक नई शक्तिशाली फौज की भाँति उठ खड़ा हुआ ।

'राष्ट्रीय किसान आंदोलन संस्थान' किसान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का मुख्य केन्द्र था । इसके थोड़े से स्नातकों को क्वाङतुङ में छोड़कर बाकी सभी को दूसरे प्रान्तों में किसानों के बीच काम करने के लिए भेज दिया जाता था ।

20 अप्रैल, 1926 को प्रथम राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया । केन्द्रीय समिति ने कांग्रेस को भेजे अपने पत्र में स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन को श्रमिक वर्ग आंदोलन तथा राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के साथ पूरी तरह सम्बद्ध किया जाना चाहिए और यह कि संघर्ष की असली विजय श्रमिक-वर्ग के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती थी ।

जून 1926 तक, देश में किसान सभाओं की सदस्य संख्या 9,80,000 तक पहुँच गई थी, जिनमें से अधिकतर-(6,47,000), क्वाङतुङ प्रदेश में थे । क्वाङतुङ में, जो कि उस समय चीन का क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र था, किसान आंदोलन का विस्तार होना आरंभ हो गया था ।

1925 में प्रथम प्रान्तीय किसान कांग्रेस तथा 1926 में दूसरी कांग्रेस आयोजित की गई । इन कांग्रेसों में भ्रष्ट अफसरों को बाहर निकाल फेंकने, स्थानीय निरंकुश तत्वों, बुरे-शरीफजादों का सफाया करने, **पाओनुङ**[5] प्रणाली का उन्मूलन करने, लगान में कटौती तथा जमींदारों के पास जमा किसानों की धरोहरों को वापिस वसूल करने, किसान आत्म-रक्षा दल गठित करने, जमींदारों के 'रक्षा-दस्ते' भंग करने तथा मजदूर-किसान संश्रय स्थापित करने आदि के प्रस्ताव पास किए गए । इस कालावधि के दौरान क्वाङतुङ के किसान बेहिसाब लेवियों तथा विभिन्न टैक्सों को खत्म करने, लगान में कमी करने तथा अपनी जमानतों को वापिस वसूल करने के लिए संघर्ष करने के स्तर से बढ़कर स्थानीय निरंकुश तत्वों, बुरे शरीफजादों तथा जमींदारों के 'रक्षा-दस्तों' से लड़ने तक के स्तर तक पहुँच चुके थे ।

क्वाङतुङ के किसान युद्ध-सरदारों तथा साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में भी कूद पड़े। तुङच्याङ अभियान में हाएफङ, लूफङ, ऊह्वा तथा अन्य काउंटियों के किसानों ने छन चियुङ-मिङ को हराने में राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की सहायता की । कैंटन के इर्द-गिर्द के बाहरी क्षेत्रों के किसानों ने क्रान्तिकारी सेना के साथ समन्वय स्थापित करते हुए याङ शी-मिन तथा ल्यू छन-ह्वान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी । हांगकांग की नाकेबंदी के दौरान, किसानों ने श्रमिकों का साथ दिया तथा इस प्रकार उन्होंने कैंटन-हांगकांग की विशाल हड़ताल को सक्रिय

घोषणापत्र, (Manifesto Concerning My Trip to North)" जारी किया । इसमें उन्होंने सभी असमान संधियों को रद्द करने तथा राष्ट्रीय असेम्बली बुलाये जाने की आवाज उठाई । परन्तु पेकिंङ पहुँचने पर उन्हें मालूम पड़ा कि त्वान छी-रुइ की राष्ट्रीय असेम्बली बुलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी । असल बात तो यह थी कि त्वान **"राष्ट्रीय पुनर्स्थापना पर सम्मेलन (Cenference on National Rehabilitation)"** का आयोजन करके राष्ट्रीय असेम्बली का विरोध करने का प्रयास कर रहा था । मार्च 1925 में डॉ० सुन यात-सेन और ली ता-चाओ ने त्वान की योजना के विरोध में "राष्ट्रीय असेम्बली के संस्थापन के लिए संस्थाओं" की राष्ट्रीय कांग्रेस बुलाई । कांग्रेस ने "राष्ट्रीय पुनर्स्थापना के लिए सम्मेलन" का भण्डाफोड़ करने, क्रांतिकारी विचारों के प्रचार-प्रसार तथा जनसाधारण को राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए आंदोलित करने में असरदार भूमिका निभाई ।

उत्तर के दौरे के दौरान ज्यादा काम और थकान की वजह से डॉ० सुन यात-सेन का स्वास्थ्य दोबारा बिगड़ गया तथा 12 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हो गई । मृत्यु-शैय्या से उन्होंने सोवियत-संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने दो महान राष्ट्रों, चीन तथा सोवियत-संघ में मैत्रीपूर्ण सहयोग की अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की । सोवियत-संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने कामरेड स्तालिन की तरफ से उनकी मृत्यु पर शोक-संवेदना का तार भेजा । तार में कहा गया कि डॉ० सुन यात-सेन की महान उपलब्धि की स्मृति चीनी श्रमिकों तथा किसानों के मन में सदैव बनी रहेगी तथा क्वोमिंताङ के जनवादी गुट को डॉ० सुन यात-सेन का झण्डा बुलन्द रखने की प्रेरणा देगी, जब तक कि जनवादी क्रान्ति की पूर्ण विजय नहीं हो जाती ।

इस जनवादी क्रांतिकारी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के महान मित्र की अचानक मृत्यु पर सारा राष्ट्र गहरे शोक में डूब गया तथा राजनीतिक प्रचार का एक विशाल आंदोलन पैदा हुआ । कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के सहयोग के कारण तथा दोनों पार्टियों के क्रान्तिकारी सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से तीन जन-सिद्धान्तों, जो साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी तीन बुनियादी नीतियों पर आधारित थे, की जानकारी देश के कोने-कोने में फैल गई । ●

3.

- **चीनी श्रमिकों की जापान-विरोधी हड़तालें ।**
- **द्वितीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस ।**
- **शंघाई में 30 मई का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन ।**
- **हांगकांग तथा कैंटन में विशाल हड़ताल ।**
- **क्वाङतुङ क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण ।**
- **किसान आंदोलन का और ज्यादा विकास ।**

चीन में, साम्राज्यवादियों के आर्थिक आक्रमण का एक मुख्य तरीका फैक्ट्रियाँ, खासतौर से सूती कपड़े की मिलें, स्थापित करना था । युद्धेतर काल में विदेशी पूँजीपतियों, विशेषकर, जापानी पूँजीपतियों द्वारा चीन में लगाई जाने वाली सूती कपड़े की मिलों में काफी वृद्धि हुई। वस्त्र-उद्योग के लिए घरेलू-बाज़ार के सदैव सिकुड़ते रहने के डर से जापानी पूँजीपतियों ने

अपने देश में एकाधिकार की तथा चीन में अपना पूँजी-निवेश बढ़ाने की नीति अपना कर स्वयं को बचाने का प्रयास किया, तथा जापान के लिए चीन में फैक्ट्रियाँ स्थापित करने हेतु, अनेक अनुकूल परिस्थितियाँ भी थीं । वह चीन के सस्ते श्रम का अनुचित लाभ उठा सकता था, जापानी छूट (Japanese Concession) के कारण प्राप्त विशेषाधिकारों से फायदा उठा सकता था तथा चीनी युद्ध-सरदार सरकार की मिलीभगत से चीनी श्रमिकों के विरुद्ध दमनकारी नीतियां अपना सकता था । जापानी वस्तुएँ पारंपरिक सीमा-शुल्क प्रणाली के तहत संरक्षित थीं। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी चीन में वह सारे सूती-वस्त्र उत्पादन को अपने कब्ज़े में किए हुए था तथा चीन में परिवहन का एक सम्पूर्ण तंत्र उसके नियंत्रण में था । इसके अतिरिक्त, जापानी पूँजीपतियों के पास पूँजी के बाहुल्य तथा विकसित उत्पादन प्रणाली होने के कारण वे अपनी फैक्ट्रियों का संचालन सुचारू ढंग से कर सकते थे । फलतः, वे न केवल उच्च लाभ ही प्राप्त कर सकते थे बल्कि प्रतिस्पर्धी चीनी उद्यमों को भी धराशायी कर सकते थे । 1913 से 1925 तक के समय में जापानी स्वामित्व की फैक्ट्रियों में तकलों का अंश, चीन में कुल तकलों के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 45.3 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि चीनी स्वामित्व की मिलों का अंश 58.8 प्रतिशत से गिर कर 44 प्रतिशत रह गया । जापानी सूती कपड़ा मिलें शंघाई तथा छिङताओ में केन्द्रित होने के कारण चीनी मिलें किसी भी हालत में उनसे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थीं ।

इन सूती-वस्त्र मिलों के जापानी मालिकों ने चीनी श्रमिकों से अधिक समय काम लेकर तथा उनके वेतनों में कटौती करके उनका नृशंसतापूर्वक शोषण तथा दमन किया । सर्वाधिक क्रूरतापूर्ण तथा निंदनीय बात तो यह थी कि शंघाई की जापानी मिलों ने वयस्क श्रमिकों का स्थान ग्रहण करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि उनका शोषण तथा दमन तीव्र किया जा सके । जापानी पूँजीपतियों की इन क्रूरतापूर्ण कार्यवाहियों के विरोध में फरवरी 1925 में एक विशाल हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें शंघाई स्थित जापानी स्वामित्व की लगभग सभी मिलों के श्रमिकों ने भाग लिया । इस पर जापान ने "सशस्त्र प्रदर्शन" के लिए अपने युद्धपोत चीन की ओर रवाना कर दिए; तथा साथ ही चीन स्थित जापानी राजदूत ने पेकिङ सरकार को सख्त चेतावनी दी । इस घटना ने समस्त सुदूर पूर्व को स्तब्ध कर दिया ।

हड़ताल ने श्रमिकों को अपने वर्ग की शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त कर दिया, तथा श्रमिक-संगठनों में श्रमिकों की तादाद बढ़नी आरंभ हो गई । उन्होंने प्रत्येक फैक्ट्री में स्वयं को संगठित करना आरंभ कर दिया, इस प्रकार संगठनों के लिए मजबूत आधार बना । संगठनों की बढ़ती ताकत से भयभीत हो कर, जापानी पूँजीपतियों ने उन पर प्रतिबन्ध लगाने, तथा संगठनकर्ताओं को बर्खास्त करने का निर्णय लिया । इस पर शंघाई में श्रमिकों की एक और हड़ताल हुई । 15 मई, 1925 को एक जापानी फैक्ट्री के सन्तरी ने हड़तालियों पर गोली चला दी, जिससे कू चङ-हुङ नामक एक श्रमिक मारा गया तथा एक दर्जन श्रमिक घायल हो गए।

छिङताओ स्थित कुछ मिलों के जापानी मालिकों द्वारा इसी तरह की दमनात्मक कार्यवाहियों के कारण 19 अप्रैल, 1925 को वहां एक विशाल हड़ताल हुई । 28 मई को जापानी मालिकों ने फैक्ट्रियों में तालाबन्दी लागू कर दी तथा श्रमिकों को परिसर छोड़ने के लिए बाध्य किया । जापानी सैनिकों ने श्रमिकों पर बिल्कुल पास से गोलियाँ दागीं तथा अनेकों को

कैंटन-हांगकांग के हड़तालियों तथा क्वाङतुङ के किसानों के समर्थन तथा मदद से क्वाङतुङ का क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र और अधिक मजबूत होता चला गया । हड़ताल के आरंभ में, क्रांतिकारी सरकार बहुत कठिन स्थिति में थी । याङ शी-मिन तथा ल्यू छन-ह्वान नामक दो युद्ध-सरदार, जो सरकार में थे, क्वोमिंताङ के दक्षिणपंथियों से साँठ गाँठ कर के तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहे थे । बाहर से छन चियुङ-मिङ तथा तङ पेन-इन नामक युद्ध-सरदारों की फौजें घेरा डालने के लिए तैयार बैठी थीं । लेकिन श्रमिकों तथा किसानों के समर्थन से संकट पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया ।

जब डॉ० सुन यात-सेन उत्तर की ओर गए, लगभग उसी समय से छन चियुङ-मिङ, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों तथा त्वान छी-रुइ की पेकिङ सरकार की फौजी सहायता से ह्वेइचओ-छाओचओ-शानथओ सेक्टर को, कैंटन सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियां करने के लिए अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था । इसलिए फरवरी 1925 में क्रांतिकारी सेना ने **प्रथम पूर्वी अभियान** आरंभ किया । ह्वाङफू सैनिक अकादमी के कैडेट इसकी मुख्य सैन्य थे, तथा कुल मिलाकर केवल 3000 सैनिक थे, जिन्होंने छन और उसके सहयोगियों की 90,000 सैनिकों की विशाल फौज का मुकाबला किया । ह्वाङफू सैनिक अकादमी में पार्टी की राजनीतिक शिक्षा तथा कैडेटों के साहस व कार्यनीतिक दक्षता के फलस्वरूप क्रान्तिकारी सेना ने छन की सिरफिरी (क्रैक) फौजों का सफाया कर दिया तथा मार्च के अन्त तक छाओचओ व शानथओ पर अधिकार कर लिया।

जून 1925 के शुरू में, याङ शी-मिन तथा ल्यू छन-ह्वान नामक युद्ध-सरदारों ने क्रांतिकारी सरकार का तख्ता पलटने की योजना बनाई । क्रांतिकारी सेना ने, जो उस समय युद्ध-सरदार छन चियुङ-मिङ से पूर्वी क्वाङतुङ में दो-दो हाथ कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वाम-पक्ष द्वारा समर्थित नीति का दृढ़तापूर्वक पालन किया तथा तेज़ी से कैंटन वापिस लौटकर, याङ व ल्यू पर आक्रमण किया तथा उनकी प्रतिक्रियावादी सेनाओं का सफाया कर दिया । इस प्रकार क्रांतिकारी सरकार बचाई गई ।

इस लड़ाई के बाद, 1 जुलाई, 1925 को कैंटन में राष्ट्रीय सरकार की विधिवत् स्थापना कर दी गई । जिन सैन्यदलों ने क्रान्ति में भाग लिया था, उन सभी को मिलाकर एक **राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना** का गठन किया गया तथा ह्वाङफू फौजी अकादमी के कैडेट उसकी रीढ़ बने ।

यद्यपि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी, फिर भी क्वोमिंताङ में अंदर-खाते जबरदस्त संघर्ष चल रहा था । हड़ताल समिति को यह बात पता चल चुकी थी कि हू हान-मिन तथा श्वी छुङ-च विद्रोह करने का षड्यन्त्र रच रहे थे । इसलिए 11 अगस्त को क्वाङतुङ के श्रमिकों ने सरकार के अन्दर मौजूद गद्दारों का सफाया करने के लिए एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया । इससे क्वोमिंताङ के वामपक्ष को जबरदस्त सहारा मिला । फिर भी वाम-पक्ष हिचकिचाता रहा तथा हड़ताल से डरता रहा । परिणामस्वरूप, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई । आखिर में यह हुआ कि क्वोमिंताङ के वाम पक्ष के नेता ल्याओ छुङ-खाए का प्रति-क्रांतिकारियों द्वारा वध कर दिया गया । तब क्वाङतुङ की क्रांतिकारी सरकार ने जन समर्थन से प्रतिक्रियावादी फौज को भंग कर दिया तथा हू हान-मिन तथा श्वी छुङ-च को कैंटन से निष्कासित कर दिया ।

की घोषणा कर दी तथा क्वाङतुङ की क्रांतिकारी सरकार पर, जिसने हांगकांग के श्रमिकों की न्यायसंगत कार्यवाही का समर्थन किया था, नाकेबंदी थोंप दी । 23 जून को कैंटन में 1,00,000 श्रमिकों, विद्यार्थियों, सैनिकों तथा अन्य निवासियों द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी—30 मई आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया गया । जब प्रदर्शनकारी शाकी नामक गली में से गुजर रहे थे तब शाम्येन नामक विदेशी छूट वाले इलाके में स्थित बरतानवी तथा फ्रांसीसी सैनिकों ने उस तंग गली के आर-पार उन पर गोलियाँ चलाई, जिससे 50 व्यक्ति मौके पर ही मारे गए तथा 100 से अधिक घायल हो गए । शाकी नरसंहार के तत्काल बाद, क्वाङतुङ की क्रांतिकारी सरकार ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने की घोषणा की तथा बन्दरगाहों की नाकेबंदी कर दी । हांगकांग में, **सू चाओ-चङ**[3] तथा **तङ छुङ-श्या**[4] के नेतृत्व में एक और हड़ताल फूट पड़ी, जिसमें 2,50,000 श्रमिकों ने भाग लिया। इन हड़तालियों में से 1,30,000 अलग-अलग ग्रुपों में कैंटन लौट आए और वहाँ के श्रमिकों के साथ मिलकर, कैंटन-हांगकांग हड़ताल समिति के नेतृत्व में उन्होंने 2000 से अधिक श्रमिकों की एक नियमित धरना कोर स्थापित की, ताकि अंग्रेजी तथा जापानी माल के पूर्ण बहिष्कार को लागू किया जा सके ।

कैंटन-हांगकांग हड़ताल समिति के ऊपर एक **हड़तालियों की कांग्रेस** का गठन किया गया, जो 800 से अधिक प्रतिनिधियों की एक विचारक संस्था थी; इसके अधीन कार्यकारी विभाग, विधान विभाग, न्यायिक विभाग, एक लेखा-परीक्षण विभाग, वित्त समिति, जेलें, सशस्त्र धरना कोर, अस्पताल तथा स्कूल वगैरा थे । वास्तविक अर्थों में कुल मिलाकर यह संस्था एक सरकार के समान थी । हड़ताल कमेटी के नेतृत्व में, कैंटन के श्रमिकों ने क्वाङतुङ के सभी बन्दरगाहों तथा पूर्व में शानथओ से लेकर पश्चिम में पाखोइ तक सारी की सारी तटवर्ती-सीमा की नाकेबंदी कर दी तथा हांगकांग व मकाओ से सभी संपर्क तोड़ दिए ।

हड़ताल ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारी क्षति पहुँचाई ।

पहली बात यह कि इस हड़ताल से उन्हें हांगकांग में भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी ।

हड़ताल की कालावधि के दौरान हांगकांग के निर्यात में आधे से ज्यादा कमी आई । बहुत सी दुकानें बंद हो गई थीं । लोगों ने हांगकांग की मुद्रा का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तथा हांगकांग सरकार घोर वित्तीय संकट में फंस गई । रोज का घाटा 35 लाख हांगकांग डॉलर था ।

दूसरी ओर, हड़ताल ने क्वाङतुङ की आर्थिक आजादी तथा विकास को प्रोत्साहित किया। जब हड़ताल कमेटी द्वारा कैंटन तथा शंघाई के बीच जहाजरानी शुरू की गई, तब जो व्यापारी पहले सीधे हांगकांग से माल खरीदते थे, अब सामान खरीदने कैंटन आने लगे जिससे कैंटन में थोक-व्यापार न केवल हड़ताल पूर्व के स्तर तक जा पहुँचा, बल्कि उसमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती चली गई । क्वाङतुङ सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा की साख पुनः बहाल हो गई, तथा सरकारी आय में काफी वृद्धि हुई ।

दूसरी बात यह हुई कि हड़ताल ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया ।

जून 1925 से लेकर दिसम्बर 1926 तक सोलह महीने चली यह हड़ताल, चीनी क्रांति के इतिहास में ही एक महान घटना नहीं थी, बल्कि विश्वभर में श्रमिक-हड़तालों के इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं ।

मौत के घाट उतार दिया ।

इन अत्याचारों से चीनी जनता का रोष और भड़क उठा तथा संघर्ष जारी रखने के उनके संकल्प में और दृढ़ता आई ।

इस वक्त चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य कार्य श्रमिक-वर्ग को मज़बूत तथा सुदृढ़ बनाना था । 1 मई, 1925 को, आसन्न राष्ट्रव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी तूफान की पूर्वसंध्या पर, कैंटन (क्वाङचओ) में पार्टी के नेतृत्व तथा चीन के चार सबसे बड़े संगठनों—1. राष्ट्रीय रेल-मजदूर ट्रेड-यूनियन फेडरेशन, 2. हानखओ-तायेह-फिङश्याङ ट्रेड यूनियन फेडरेशन, 3. क्वाङतुङ कर्मचारी कान्फ्रेंस तथा 4. चीनी नाविक महासंघ—के तत्वाधान में दूसरी राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस का आयोजन किया गया । कांग्रेस में 281 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 166 श्रमिक-संघों तथा 5 लाख 40 हजार संगठित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मज़दूर-वर्ग को राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति में भाग लेना चाहिए तथा उसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए । साथ ही मजदूर-वर्ग को अपने संश्रयकारियों की तलाश करनी चाहिए, और यह कि किसान-समुदाय उसका सबसे अधिक विश्वसनीय संश्रयकारी था । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि मौजूदा संघर्ष में श्रमिकों की फौरी आर्थिक मांगें—न्यूनतम वेतनमान निश्चित करवाने, आठ घण्टे का कार्य-दिवस, स्त्रियों तथा बच्चों के काम करने के हालात में सुधार, श्रमिक तथा सामाजिक बीमा योजना लागू करवाने तथा श्रमिक अनुबंध प्रणाली के उन्मूलन की थीं । कांग्रेस ने घोषणा की कि श्रमिकों को श्रमिक-वर्ग के व्यापकतम जन-संगठनों—ट्रेड-यूनियनों—में भर्ती करने के सभी उपाय किये जाने चाहिएं और यह कि औद्योगिक आधार पर संगठित श्रमिक-संघ सबसे ज्यादा सही थे । अन्त में कांग्रेस ने श्रमिकों का आह्वान किया कि वे अपनी पाँतों में छिपे हड़ताल भेदियों, गद्दारों तथा जासूसों को निकाल बाहर फेंकें ।

कांग्रेस की निम्न उपलब्धियाँ थीं : पहली, इसने श्रमिक-संघों के अखिल चीनी महासंघ की स्थापना की, उसका संविधान पारित किया तथा उसकी नेतृत्वकारी संस्था—कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया । दूसरे, श्रमिक-संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन—लाल इंटरनेशनल—में शामिल होने का निर्णय लिया, इसका अर्थ था कि चीनी श्रमिकों ने विश्व-क्रांति को साकार करने के लिए सभी देशों के श्रमिकों के साथ हाथ मिलाना आरंभ कर दिया था । चीनी श्रमिक-वर्ग आंदोलन के इतिहास में इस कांग्रेस का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

कांग्रेस सम्पन्न होने के बीस दिन के अंदर ही 30 मई आन्दोलन फूट पड़ा ।

शंघाई में अनेक कॉलेज विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था । कुछ को तो उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे मारे गए या जख्मी श्रमिकों के परिवारों के लिए गलियों में चन्दा इकट्ठा कर रहे थे और कुछ को तब, जब वे कू चङ-हुङ नामक श्रमिक की स्मृति-सभा में भाग लेने जा रहे थे । साम्राज्यवादियों ने मिश्रित अदालत में उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए 30 मई का दिन तय किया । साथ ही चीन के राष्ट्रीय उद्योग को अवरुद्ध करने की दृष्टि से "अंतर्राष्ट्रीय बस्ती" (विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बस्ती-अनु०) की नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत दमनकारी कानूनों को दो जून को पारित करने की योजना बनाई । इन प्रस्तावों में घाट-शुल्क में वृद्धि, प्रेस पर अंकुश तथा स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकरण की व्यवस्था करने को कहा गया था । घाट-शुल्क में वृद्धि का मकसद चीनी आयात तथा निर्यात

पर भारी कर थोंपना था । "अंतर्राष्ट्रीय बस्ती" की नगर परिषद में स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकरण के पीछे विदेशी "छूटों" वाले क्षेत्रों में रहने वाले चीनियों के जनवादी अधिकारों पर अंकुश लगाने तथा चीनी पूँजीपतियों को भारी क्षति पहुँचाने की मंशा थी । प्रेस अधिनियम—जिनमें सभी प्रकाशनों के नगर परिषद में पंजीकरण का प्रावधान था तथा किसी प्रकार के उल्लंघन पर जुर्माने तथा कैद का प्रावधान था—न केवल चीनी प्रकाशकों के काम में बाधा डालते थे बल्कि ये चीनी जनता के अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी डाका डालते थे । इसलिए इन प्रस्तावों से शंघाई की जनता में भारी रोष की लहर दौड़ गई ।

कू चङ-हुङ की मृत्यु के पश्चात् शंघाई के पश्चिमी हिस्से के सूती-वस्त्र उद्योग के 20,000 श्रमिकों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल की । जापानी मालिकों ने तालाबन्दी द्वारा हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया । 28 मई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी क्रांतिकारी ताकतों को अपनी तरफ करने के लिए, श्रमिकों के आर्थिक संघर्षों को नित्यप्रति बढ़ते साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों के साथ सम्बद्ध किया जाए तथा इसे सुस्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित किया जाए । "अंतर्राष्ट्रीय बस्ती" में 30 मई को एक साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया गया । उस दिन तीन बजे जब 10,000 प्रदर्शनकारी नानकिङ मार्ग पर चल रहे थे, बरतानवी पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे लगभग एक दर्जन प्रदर्शनकारी मौके पर ही मारे गए तथा 50 से अधिक गिरफ्तार कर लिये गए ।

शहर में खलबली मच गई, जगह-जगह जन-सभाएँ हुईं तथा भाषण दिए गए । केन्द्रीय समिति के एक सम्मेलन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शंघाई के सभी श्रमिकों, व्यापारियों, तथा छात्रों से हड़ताल करने तथा हड़ताल-आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक कार्यवाही समिति गठित करने का आह्वान किया। 31 मई को पार्टी के मार्गदर्शन में दो लाख संगठित श्रमिकों वाली शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन की साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के केन्द्रक के रूप में स्थापना की गई । एक जून से एक विशाल हड़ताल-आंदोलन आरंभ हो गया । दो लाख से भी अधिक श्रमिकों ने अपने औजार रख दिये, 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिये, व्यापारियों ने बड़ी तादाद में अपनी दुकानें बन्द कर दीं तथा "अंतर्राष्ट्रीय बस्ती" में तैनात चीनी पुलिस तक ने भी हड़ताल की । बाद में श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा व्यापारियों के एक संघ का गठन किया गया। इस संघ के अंग थे—शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन, शंघाई व्यापारी संघ, अखिल चीनी छात्र संघ तथा शंघाई छात्र संघ । केवल दलाल-पूँजीपति वर्ग के संगठन—शंघाई वाणिज्य मंडल ने इससे सम्बद्ध होने से इंकार किया । 6 जून को पार्टी ने जनता के नाम अपील जारी करते हुए दृढ़ता से स्पष्ट किया कि **शंघाई की घटना का समाधान "कानून में नहीं, राजनीति में निहित था"**, तथा संघर्ष का मुख्य उद्देश्य—*"चीन में साम्राज्यवादियों के सभी विशेषाधिकारों का उन्मूलन"* होना चाहिए । 11 जून को शंघाई के दो लाख से अधिक श्रमिकों, व्यापारियों तथा विद्यार्थियों ने एक जन सभा की जिसमें साम्राज्यवाद-विरोधी सत्रह माँगों को पारित किया गया। इन मांगों में—सभी विदेशी जल तथा थल सेनाओं की चीन से वापसी, वाणिज्यिक क्षेत्राधिकार की समाप्ति, "बस्ती" में रहने वाले सभी चीनी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, प्रकाशन तथा सभा करने की स्वतन्त्रता, श्रमिकों को श्रमिक-संघ बनाने तथा हड़ताल पर

जाने का अधिकार, "बस्ती" की "नगर परिषद" में चीनी प्रतिनिधित्व तथा मिश्रित अदालत की चीन को वापसी की मांग शामिल थीं । 30 मई के साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन में शंघाई के श्रमिकों ने हरावल दस्ते तथा नेता की भूमिका अदा की ।

इस क्रांतिकारी तूफान से सामना होने पर साम्राज्यवादियों ने पहले तो अपने शक्ति-प्रदर्शन से चीनी जनता को भयभीत करने का प्रयास किया । अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान ने एक बड़ी तादाद में ह्वाङ्फू नदी में अपने युद्धपोतों को एकत्र किया तथा अपने नौ-सैनिकों को शंघाई में उतार दिया, जिन्होंने गलियों में घुसकर चीनी जनता को मारना शुरू कर दिया, परन्तु नृशंस ताकत द्वारा क्रांति के दमन की असंभाव्यता को महसूस करने पर, साम्राज्यवादियों ने कपटपूर्ण षड्यन्त्रों का सहारा लिया तथा बड़े दलाल-पूँजीपतियों से गठजोड़ करके, "बस्ती" की "करदाता सभा" के निर्देशकमण्डल में चीनी प्रतिनिधियों की सीटों में वृद्धि करके तथा "मिश्रित अदालत" की चीन को वापसी का वचन देकर, साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे में दरार डालने का प्रयास किया । एक ओर तो उन्होंने शंघाई के राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग पर "न्यायिक जाँच" तथा "सीमा-शुल्क सम्मेलन" के प्रस्तावों पर समझौता करने का जाल फेंका तथा दूसरी ओर उन्हें ऋण देना, उनकी अपनी जमा की गई रकमें, विद्युत आपूर्ति तथा उनके परिवहन आदि को रोकने की धमकी दी । इसी दौरान साम्राज्यवादियों ने ताए ची-थाओ तथा हू श को "मित्रतापूर्ण बातचीत" द्वारा हल निकालने का आदेश दिया । इस साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप, शंघाई के राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया तथा ग्वी श्या-छिङ नामक एक बड़े दलाल-पूँजीपति को सत्रह माँगों में फेरबदल करने, अपने प्रभाव क्षेत्र, के बाजारों में हड़ताल वापिस लेने, दूसरे शहरों के लोगों द्वारा शंघाई के श्रमिकों के लिए इकट्ठे किए गए चन्दे को हड़पने तथा श्रमिकों को काम पर लौटने के लिए बाध्य करने का मौका मिल गया । फङथ्येन गुट के युद्ध-सरदारों ने छिङताओ, थ्येनचिन तथा नानकिङ में हड़तालों का दमन किया; श्रमिकों, छात्रों तथा व्यापारियों की शंघाई फेडरेशन तथा शंघाई ट्रेड-यूनियन फेडरेशन पर पाबन्दी लगा दी तथा अनेकों क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया । श्रमिक-वर्ग के संगठनों तथा पहले हासिल की गई उपलब्धियों को बचाए रखने के लिए, शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने इस शर्त के साथ आम हड़ताल वापिस लेने का निर्णय लिया कि श्रमिकों की आर्थिक माँगों तथा क्षेत्रीय विवादों पर संतोषजनक समझौता किया जाए। जुलाई तथा अगस्त में श्रमिक धीरे-धीरे काम पर लौट आए ।

30 मई को शंघाई में हुए चीनी जनता के कत्लेआम ने सारे देश में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध रोष की आग भड़का दी । पेकिंङ, हानखओ, छाङशा, च्योच्याङ, हाङचओ तथा अन्य स्थानों पर श्रमिकों, छात्रों तथा व्यापारियों के प्रदर्शनों, जलसों तथा हड़तालों का तांता लग गया। कैंटन (क्वाङचओ)-हांगकांग की विशाल हड़ताल इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली तथा बड़ी थी । यह प्रसिद्ध हड़ताल श्रमिकों द्वारा शंघाई कांड के विरोध में शुरू की गई । 19 जून को हांगकांग में एक लाख चीनी श्रमिकों ने हड़ताल कर दी । श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा व्यापारियों की शंघाई फेडरेशन की सत्रह मांगों के प्रति एकमत समर्थन के अतिरिक्त हड़तालियों ने अपनी ओर से छः मांगें और रखीं : राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानून के समक्ष समानता, आम चुनाव करवाना, श्रम-कानून बनाना, मकानों के किरायों में कमी तथा देश में कहीं भी रहने-बसने की आजादी। इन मांगों का जवाब देने की बजाय, हांगकांग के अधिकारियों ने तत्काल मार्शल-लॉ

अभियान सेना के प्रतिक्रियावादी अफसरों से सांठ-गांठ करके किसान आंदोलन को तहस-नहस करने का प्रयास किया ।

प्रतिक्रियावादियों के हमले के मद्देनजर, पार्टी में छन तू-श्यू के नेतृत्व वाला अवसरवादी गुट, जवाबी हमला करने की बजाय, लगातार क्रान्ति में किसानों की भूमिका को नकारने पर जोर देता रहा तथा किसानों के क्रान्तिकारी संघर्ष का विरोध करता रहा ।

जुलाई 1926 में पार्टी ने तीसरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की विस्तृत मीटिंग बुलायी तथा छन तू-श्यू द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव को पास कर दिया, जिससे उसके दक्षिणपंथी विचार विकसित होते-होते पार्टी की दक्षिण अवसरवादी कार्यदिशा में बदल गए ।

छन तू-श्यू ने देहात में संयुक्त मोर्चे की स्थापना पर जोर दिया तथा कहा कि किसान सभा को *"वर्ग भेद का रंग"* नहीं दिया जाना चाहिये तथा इसमें गरीब किसानों, खेत-मजदूरों व मध्यम किसानों के अलावा, छोटे तथा मध्यम दर्जे के जमींदारों को भी शामिल किया जाना चाहिये । यदि इस नीति पर अमल किया जाता तो जमींदार तंथा धनी किसान, किसान सभा में घुसपैठ कर जाते तथा उसे अपने कब्जे में कर लेते । किसानों की क्रांतिकारी सरकार का विरोध करते हुए, छन तू-श्यू ने शरीफजादों (यानि कि बुरे शरीफजादों) की सत्ता के स्थान पर सुधरे हुए शरीफजादों (यानि कि तथाकथित अच्छे शरीफजादों) को सत्तासीन करने के दृष्टिकोण का समर्थन किया । इसका अर्थ, वास्तव में सामंती जमींदार वर्ग की सत्ता को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त और कुछ न था । उसने आगे तर्क पेश किया कि किसानों के सशस्त्र दस्तों को केवल प्रतिक्रियावादी "रक्षा कोरों" की तरह ही कार्यवाही करनी चाहिए, यानि कि उनका काम आक्रमण करना कदापि न था क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा करना था । वास्तव में, छन तू-श्यू द्वारा किसानों की सशस्त्र सेनाओं का "रक्षा कोर" तथा प्रतिक्रियावादी सैन्य-दलों के खिलाफ लड़ सकने वाली स्थायी सेना के रूप में गठन किये जाने का विरोध करना किसानों की सशस्त्र सेनाओं को नेस्तनाबूद कर देने के बराबर था ।

उपरोक्त रूपरेखा का अनुसरण करते हुए, छन तू-श्यू ने कोई क्रान्तिकारी कृषि-कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि कुछ सुधारवादी नीतियां पेश कीं—मसलन *"लगान की अधिकतम सीमा का निर्धारण"* तथा *"सूदखोरों द्वारा की जा रही लूट-खसोट पर अंकुश"* । एकमात्र पूँजीपति वर्ग से सहयोग करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के कारण वह किसान समुदाय को पूरी तरह भूल गया । जिसके फलस्वरूप उसने किसान क्रांति का नेतृत्व करने की सर्वहारा की जिम्मेदारी को तिलांजलि दे दी । केन्द्रीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में उसने स्पष्ट तौर से कहा कि—*"यदि चीनी पूँजीपति वर्ग ने क्रान्ति में सक्रिय भूमिका अदा नहीं की तो चीनी राष्ट्रीय क्रान्ति बहुत बड़ी मुश्किलों में ही नहीं, बल्कि खतरों में फंस जाएगी ।"* उसका यह भी मत था कि पूँजीवादी-जनवादी क्रांति की कालावधि में कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए क्वोमिंतांङ से लड़ाई नहीं करेगी । **"केवल सर्वहारा क्रांति के समय ही कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करेगी । राष्ट्रीय क्रांति की कालावधि में ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।"**

छन तू-श्यू की नजरों में पूँजीवादी-जनवादी क्रांति में सर्वहारा नेतृत्व का प्रश्न ही नहीं उठता था, तथा न ही यह कभी "पैदा" होना था । अतः उसने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि चीनी क्रांति द्वारा चीन में "राष्ट्रीय पूँजीवादी समाज" की स्थापना होनी थी तथा जोर देकर

था।

यह लेख, चीन का सबसे पहला तथा सर्वाधिक स्पष्ट मार्क्सवादी-लेनिनवादी दस्तावेज था। इस लेख में एकदम ठोस, तथा वैज्ञानिक ढंग से चीनी क्रांति के अनेक आधारभूत प्रश्नों का विश्लेषण तथा व्याख्या की गयी थी तथा विभिन्न राष्ट्रीय कांग्रेसों में जो बुनियादी समस्याएँ हल किए बिना छोड़ दी गई थीं या ठीक तरीके से हल न की गई थी—जैसे कि क्रांति में सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व का सवाल, किसान समस्या तथा यह समस्या कि राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के प्रति किस तरह का नजरिया अपनाया जाए—इन सभी को सही ढंग से हल किया गया। इसने दृढ़ता से उस समय पार्टी में मौजूद "वाम" तथा दक्षिण अवसरवादी विचारों का खण्डन किया तथा बड़े ही स्पष्ट ढंग से, जनवादी क्रांति की कालावधि में पार्टी की सामान्य कार्यदिशा तथा मुख्य कार्यभारों की व्याख्या की ।

इस लेख का उद्देश्य क्वोमिंतांङ के दक्षिणपंथियों के प्रतिक्रियावादी विचारों का खण्डन करना भी था, जिनका मुख्य प्रवक्ता ताए ची-थाओ[13] था । उसकी धारणाएं *"राष्ट्रीय क्रांति तथा क्वोमिंतांङ"* एवं *"सुन यात-सेन के सिद्धांतों का दार्शनिक आधार"* जैसे पर्चों में संग्रहीत थीं । इस साम्यवाद-विरोधी "प्रवक्ता" को क्वोमिंतांङ के दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों का "सिद्धांतकार" माना जाता था ।

ताए ची-थाओ के सिद्धांतों की मुख्य धारणाएँ तथा प्रतिक्रियावादी विषय-वस्तु क्या हैं ?

पहला, वह वर्ग-संघर्ष का प्रबल विरोधी था तथा चीनी श्रमिक वर्ग द्वारा चीनी पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध चलाए गए संघर्ष का विरोध करता था । उसकी दलील थी कि श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में कूदना जरूरी नहीं था । दया तथा प्यार द्वारा पूँजीपतियों का दिल जीता जा सकता था तथा उन्हें श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए मनाया जा सकता था । कुल मिलाकर सार यह था कि श्रमिकों तथा किसानों से कहा जाए कि वे अपना संघर्ष बन्द कर दें तथा गुलामों की तरह पूँजीपतियों की "भीख" पर गुजर बसर करें ।

दूसरे, ताए ची-थाओ का मानना था कि "राज्य" तथा "राष्ट्र" सर्वोच्च राजनीतिक कसौटियां थे । लेकिन उसके "राज्य" तथा "राष्ट्र" में पूँजीपतियों को मालिकों का दर्जा प्राप्त था तथा श्रमिक और किसान केवल मातहतों व प्रजा की भूमिका निभा सकते थे । वास्तव में वह इन दो भारी-भरकम लगने वाले शब्दों द्वारा श्रमिक वर्ग तथा किसान समुदाय को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे क्रांति की अपनी न्यायोचित मांग को त्यागने को तैयार हो जाएँ । उसका अंतिम लक्ष्य पूँजीपति वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था।

तीसरे, ताए ची-थाओ का विचार था कि क्वोमिंतांङ के अंदर जो कम्युनिस्ट हैं, उन्हें साम्यवाद की बजाय **तीन जन-सिद्धान्तों** में विश्वास करना चाहिए, तथा मात्र उन्हें ही सही राजनीतिक सिद्धान्त मानना चाहिए व क्वोमिंतांङ को ही एकमात्र ऐसी पार्टी मानना चाहिए, जो देश को बचा सकती थी । इसलिए वह कम्युनिस्टों के क्वोमिंतांङ में शामिल होने के विरुद्ध था तथा उसने माँग की कि उन्हें या तो वापिस भेज दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए। उसकी कोशिश थी कि सर्वहारा वर्ग के हरावल दस्ते—कम्युनिस्ट पार्टी को अपने कब्जे में किया जाए या फिर यदि संभव हो सके तो उसे सैद्धांतिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक स्तर पर समाप्त कर दिया जाए ।

यद्यपि ताए ची-थाओ ने वर्ग-संघर्ष की निन्दा करने में कोई कसर न उठा रखी, तथापि

असल में अपनी धारणाओं तथा कृत्यों द्वारा उसने इसे पूरे जोर-शोर से कार्यान्वित किया । अन्तर केवल इतना था कि उसके वर्ग-संघर्ष ने पूँजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग के दमन का रूप धारण कर लिया । उसने *"हर कीमत पर तानाशाही"* के लिए हायतौबा मचाई । यह एक खुला युद्धघोष था, जिसका उद्देश्य क्वोमिंताङ के दक्षिणपंथियों को प्रति-क्रांतिकारी राज्य-विप्लव के लिए उकसाना था ।

सन् 1925 के उत्तरार्द्ध से क्वोमिंताङ में ताए ची-थाओ की धारणाओं के प्रचार-प्रसार के लिए, एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन चलाया गया । आंदोलन की परिणति पश्चिमी पहाड़ियों के गुट (Western Hills Chique) की स्थापना के रूप में हुई । गुट का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि क्वोमिंताङ में मौजूद प्रतिक्रियावादियों के एक हिस्से ने पेकिङ के समीप पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित पी युन मंदिर में डॉ० सुन यात-सेन के ताबूत के सामने एक सभा की थी तथा उसमें चिल्ला-चिल्ला कर सोवियत-संघ तथा कम्युनिस्ट पार्टी की निन्दा की थी । बाद में उन्होंने शंघाई में दूसरी क्वोमिंताङ की स्थापना की तथा प्रतिक्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से पेकिङ तथा अन्य स्थानों में संगठन स्थापित किये ।

ताए ची-थाओ की परिकल्पनाओं से प्रभावित होकर, कैंटन में "सुन यात-सेन के सिद्धांतों के अध्ययन के लिए समिति" (Society for the Study of Sun Yat-sen's Doctrines) के नाम से एक अन्य सोवियत-विरोधी तथा साम्यवाद-विरोधी प्रतिक्रियावादी संस्था की स्थापना की गई ।

जनवरी 1926 में, जब क्वोमिंताङ के अंदर क्रांति तथा प्रतिक्रान्ति के बीच का संघर्ष गंभीर रूप धारण करता जा रहा था, कैंटन में क्वोमिंताङ की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया । इस कांग्रेस में कम्युनिस्ट तथा क्वोमिंताङ के वाम-पक्ष के सदस्य हावी रहे तथा डॉ० सुन यात-सेन की वसीयत तथा उनके तीन आधारभूत जन-सिद्धांतों को दृढ़ता से लागू करने, दक्षिणपंथियों को उनकी प्रतिक्रियावादी गतिविधियों के लिए फटकार लगाने तथा पश्चिमी पहाड़ियों के गुट के नेताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रस्ताव पारित किए गए । लेकिन इस कांग्रेस की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने में कम्युनिस्ट पार्टी के अवसरवादियों ने बहुत सी गंभीर गलतियां कीं । दक्षिणपंथी नेताओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने तथा उन्हें क्वोमिंताङ से निष्कासित करने के कुछ कामरेडों के सही मत को स्वीकार करने की बजाय अवसरवादियों ने सिद्धान्तहीन समझौते किये तथा रियायतें दीं । उन्होंने ताए ची-थाओ, सुन फो तथा दूसरे दक्षिणपंथियों, जिन्हें क्रान्तिकारियों ने क्वाङतुङ से खदेड़ दिया था, को कांग्रेस में भाग लेने के लिए शंघाई से वापिस बुलाया तथा उन्हें क्वोमिंताङ की केन्द्रीय समिति के लिये चुना । इसके साथ ही उन्होंने ऊ च-ह्वेइ व ली श-छङ नामक दक्षिणपंथियों को पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्यों के रूप में चुना । चुनावों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय समिति के 36 सदस्यों में से केवल सात कम्युनिस्ट थे तथा 14 का सम्बन्ध क्वोमिंताङ के वाम पक्ष से था जब कि 15 सदस्य दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी थे । पर्यवेक्षक समिति में दक्षिणपंथियों ने बहुमत अर्जित कर लिया था । इस प्रकार क्वोमिंताङ में अपने सरकारी पदों का लाभ उठाते हुए दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी गतिविधियाँ चलाने में सक्षम हो गए । परन्तु सबसे बड़ी गलती च्याङ काई-शेक का केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना जाना था, इस प्रकार क्रांतिकारी पाँतों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई ।

3. उन्होंने बिरादरी की सत्ता (बिरादरी की व्यवस्था जो पुरखों के केन्द्रीय मंदिरों और उनकी शाखाओं से लेकर घर के मुखिया तक थी), धार्मिक सत्ता (जिसमें देवी-देवताओं, दैत्य-दानवों, यमराज से लेकर नगर-देवताओं और स्थानीय देवताओं तक की तरह-तरह की व्यवस्था शामिल थी), तथा पति की सत्ता का विरोध किया और निडरतापूर्वक स्वयं को इन आध्यात्मिक बेड़ियों से मुक्त कर लिया । किसान सभाओं ने किसानों को पढ़ना व लिखना सिखाने के लिए रात्रि-स्कूल खोले । 1926 के दिसंबर में छाङशा में एक प्रान्तीय किसान कांग्रेस आयोजित की गई जिसने लगान में कमी तथा जमानत राशियों को वापिस करने, सूदखोरी पर पाबंदी लगाने, भारी लेवियों तथा टैक्सों का विरोध करने; भ्रष्ट अधिकारियों, स्थानीय निरंकुश तत्त्वों तथा बुरे शरीफजादों को निकाल बाहर करने, किसान सरकारें स्थापित करने, जमींदारों की "रक्षा कोर" का उन्मूलन करने तथा आत्म रक्षा के लिए किसान मिलिशिया का गठन करने संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये । समूचे प्रान्त के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक संगठन की स्थापना भी की गई ।

कुछ ही महीनों में हुनान के करोड़ों किसानों ने, जिनकी रीढ़ की हड्डी दस लाख से भी अधिक सदस्य संख्या वाली शक्तिशाली किसान सभा थी, एक महान क्रान्ति, एक अभूतपूर्व क्रान्ति कर डाली ।

इस प्रकार किसान समस्या को लेकर क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति में एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई । जमींदार, स्थानीय निरंकुश तत्व, क्वोमिंताङ के दक्षिणपंथी तथा उत्तरी अभियान सेना के प्रतिक्रियावादी अफसर, सबके सब प्रतिक्रियावादी प्रचार तथा अन्य माध्यमों से क्रान्तिकारी किसानों पर टूट पड़े ।

प्रतिक्रियावादियों ने किसान आंदोलन की झूठी निंदा करते हुए इसे "आलसी" किसानों तथा "अवारागर्दों" का आंदोलन बताया तथा किसानों के क्रान्तिकारी संघर्ष को ऐसा "सत्यानाश हो गया" बताया, जिसने कृषि उत्पादन को रोक देना था । अपने अत्यधिक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने क्रान्ति में किसान आंदोलन द्वारा निभाई जा रही भूमिका को ही नकार दिया ।

प्रतिक्रियावादियों ने एक अन्य द्वेषपूर्ण प्रचार यह गढ़ा कि किसान आंदोलन ने धनी लोगों को भगा दिया था तथा इस कारण राजस्व में भारी गिरावट आ गई थी तथा सैनिक खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी । किसान आन्दोलन पर सरकारी राजस्व में गिरावट लाने तथा उत्तरी अभियान सेना के युद्ध में अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाकर उन्होंने किसानों के सिर पृष्ठभाग को अस्त-व्यस्त करने का अपराध मढ़ने की कोशिश की ।

जमींदारों की सशस्त्र सेनाओं, जिन्हें "रक्षा कोर" के रूप में जाना जाता था, का इस्तेमाल करते हुए, प्रतिक्रियावादी इस हद तक चले गए कि उन्होंने किसान नेताओं तथा क्रांतिकारी किसानों का खुल्लम-खुल्ला नरसंहार किया । दूर दराज के इलाकों में, उन्होंने दंगा-फसाद शुरू कर दिया, पिछड़े किसानों को गलियों में प्रदर्शन करने तथा किसान सभाओं के दफ्तरों, क्वोमिंताङ मुख्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों को तहस-नहस करने के लिये भड़काया । इसके अतिरिक्त उन्होंने नकली किसान सभाओं का गठन करके, जमींदारों के दबदबे तथा सशस्त्र सेनाओं का इस्तेमाल करके, बदमाशों व स्थानीय धूर्तों को किसान सभाओं में घुसपैठ करने के लिये घूस खिलाकर, क्वोमिंताङ के निचले स्तरों पर कब्जा करके तथा उत्तरी

अलग करके नहीं देखा जा सकता था । उन्होंने 1925 से 1926 तक कैंटन में किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संस्थान का संचालन किया था । उत्तरी अभियान के आरंभ होने पर वे कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की किसान आंदोलन से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए शंघाई चले गए । इसके बाद वे राष्ट्रीय किसान सभा के महासचिव का कार्यभार संभालने के लिए ऊहान चले गए ।

1925 के अंत में, क्रान्तिकारी स्थिति में उभार आने पर किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संस्थान में पढ़ रहे हुनान के छात्र, रेलमार्गों के साथ लगते इलाकों में काम करने के लिए अपने प्रान्त में वापिस लौट गए । किसानों के बीच में जाकर सबसे पहले उन्होंने अनेक सक्रिय तत्वों के साथ संपर्क स्थापित किया जिनमें से अधिकतर, थोड़ा-बहुत पढ़े-लिखे गरीब किसान तथा अन्य गरीब लोग थे, और फिर उन्होंने कस्बों में किसान सभाएं स्थापित कीं । जब काफी संख्या में कस्बों में ऐसी सभाएं स्थापित हो गईं, तब उनके मार्गदर्शन के लिये जिला स्तर पर किसान सभाओं का गठन किया गया । इस प्रकार उन्होंने हुनान में किसान आंदोलन के लिए निचले स्तर पर एक ठोस आधार तैयार किया ।

हुनान में उत्तरी अभियान सेना के पहुँचने पर, युद्ध में किसानों की सचेतन भागेदारी ने उनके संगठन--किसान सभा का तेजी से विस्तार किया । किसानों ने स्वयं ही पहलकदमी करते हुए राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के दृढ़ इरादे के साथ अपनी फौरी राजनीतिक तथा आर्थिक मांगें सामने रखीं ।

नवंबर 1926 तक हुनान की 50 से अधिक काउंटियों में, किसान सभाएं गठित की जा चुकी थीं, जिनकी सदस्य संख्या 13,67,000 थी ।

देहाती इलाके में किसान सभाएं सत्ता का एकमात्र प्रतीक बन गई थीं । **''सारी सत्ता किसान सभा के हाथ में हो''** का लोकप्रिय नारा एक वास्तविकता बन गया था । यह वास्तव में ही किसानों के क्रान्तिकारी अधिनायकत्व के अन्तर्गत, राजनीतिक सत्ता का एक रूप था । अपनी किसान सभाओं के माध्यम से किसानों ने राजनीतिक, आर्थिक तथा विचारधारात्मक संघर्षों को सशक्त तथा दृढ़तापूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया ।

1. उन्होंने जमींदार वर्ग की राजनीतिक तथा सामाजिक सत्ता को ध्वस्त करके किसान सभा का प्रभुत्व कायम किया, कस्बों तथा जिलों की शासकीय संस्थाओं, जिन पर स्थानीय निरंकुश तत्वों तथा बुरे शरीफजादों का प्रभुत्व था, को समाप्त कर दिया तथा काउंटी की सरकार का संचालन मजिस्ट्रेट तथा क्रान्तिकारी जनसंगठनों की संयुक्त परिषद के माध्यम से लागू किया; अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए स्वयं के लिए शिक्षण कार्यक्रम तैयार किये; तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगाकर व डकैती उन्मूलन करके एक क्रान्तिकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की ।

2. उन्होंने इलाके से बाहर अनाज भेजने तथा इसकी कीमत बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी; लगान में कमी की गई तथा जमींदारों द्वारा असामी किसानों से जबरन वसूल की गई जमानत राशि किसानों को वापिस लौटा दी गई ; पट्टों को रद्द करने पर पाबंदी लगा दी तथा भारी लेवियों की वसूली को समाप्त कर दिया; उपभोक्ता, क्रय-विक्रय तथा ऋणदाता, इन तीन तरह की सहकारी समितियों की स्थापना की तथा दलालों द्वारा शोषण व सूदखोरी की सीमा निर्धारित कर दी ।

च्याङ काई-शेक एक सट्टेबाज तथा स्वार्थजीवी मनुष्य था जो क्रांतिकारी शिविर में छिपा बैठा था । जब 1911 की क्रांति विफल हुई, उन दिनों वह शंघाई के स्टॉक एक्सचेंज में दलाल के रूप में काम कर रहा था । जब डॉ० सुन यात-सेन ने सोवियत-संघ से संश्रय की नीति अपनाई, तब च्याङ ने यह सोचते हुए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं, कि यह एक लाभकारी सट्टा होगा । वह एक बार सोवियत-संघ भी हो आया था तथा ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह क्रान्तिकारी उत्साह से लबालब होकर लौटा हो । उसे एक सच्चा क्रांतिकारी समझने की भूल करते हुए, डॉ० सुन यात-सेन ने उसे ह्वाङ्फू सैनिक अकादमी का कमाण्डेंट नियुक्त कर दिया। इस महत्त्वपूर्ण ओहदे को प्राप्त करने के पश्चात च्याङ काई-शेक ने अपना दोहरा खेल खेलना जारी रखा तथा क्रांतिकारी उद्देश्य की खूब ठकुरसुहाती की । वास्तव में वह किसी भी तरह से क्रांति का नेतृत्व हड़पने तथा अंत में इससे विश्वासघात करने की तैयारियाँ कर रहा था ।

क्वोमिंताङ की केन्द्रीय समिति में चुने जाने के तत्काल बाद च्याङ काई-शेक को राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना का प्रधान पर्यवेक्षक (General Supervisor) नियुक्त कर दिया गया । उसके बाद सभी साम्राज्यवादियों तथा बड़े पूँजीपतियों में उसकी इज्जत बढ़ गई, जोकि उसे एक शक्तिशाली राजनीतिक दलाल के रूप में देख रहे थे । इस प्रकार उसका दुस्साहस बढ़ गया, और उसने क्रान्ति का नेतृत्व हथियाने के लिए एक षड्यन्त्र रचा ।

मार्च 1926 में ''सुन यात-सेन के सिद्धांतों के अध्ययन के लिए समिति'' के नेताओं की सहायता से च्याङ ने **''चुङशान युद्धपोत कांड''** का षड्यन्त्र रचा, जो कि कम्युनिस्टों पर उसके हमले की शुरुआत थी ।

18 मार्च, 1926 को च्याङ काई-शेक ने अपने पिट्ठुओं के साथ मिलकर ह्वाङ्फू सैनिक अकादमी के कैंटन ऑफिस की तरफ से ली च-लुङ नामक कम्युनिस्ट को, जो कि उस समय जल सेना ब्यूरो का कार्यवाहक निदेशक था, चुङशान युद्धपोत को किसी नियत कार्य के लिए ह्वाङ्फू बंदरगाह पर भेजने का आदेश देने का षड्यन्त्र रचा । ज्योंही युद्धपोत ह्वाङ्फू पहुँचा, षड्यन्त्रकारियों ने अफवाह फैला दी कि कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलटने के लिए दंगा-फसाद शुरू करने जा रहे थे । इसलिए 20 तारीख की सुबह को यह दावा करते हुए कि कम्युनिस्टों द्वारा दंगा-फसाद शुरू किया ही जाने वाला था, च्याङ काई-शेक ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को बुला लिया, मार्शल-लॉ की घोषणा कर दी, कैंटन के अन्दर तथा बाहर की संचार-व्यवस्था को भंग कर दिया, तथा 'कैंटन-हांगकांग हड़ताल समिति' व सोवियत सलाहकारों के दफ्तरों तथा घरों को घेरे में ले लिया । 50 से अधिक कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें ली च-लुङ भी था; इसके अतिरिक्त ह्वाङ्फू सैनिक अकादमी तथा राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की पहली फौज, जिसका नेतृत्व कामरेड चाओ एन-लाई कर रहे थे, के सभी कम्युनिस्ट सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया । बाद में उसने कम्युनिस्टों को पहली फौज छोड़ने पर बाध्य कर दिया तथा इस प्रकार उसकी कमान पर काबिज हो गया ।

15 मई, 1926 को क्वोमिंताङ की केन्द्रीय समिति की एक बैठक में च्याङ काई-शेक ने *''पार्टी के कामकाज के पुनर्गठन के बारे में विधेयक''* का प्रस्ताव किया जिसका उद्देश्य कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था । इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार थीं—क्वोमिंताङ की उच्चतर संस्थाओं में कम्युनिस्टों को एक तिहाई से अधिक प्रशासनिक पदों पर नहीं लगाया जाना चाहिये, किसी भी कम्युनिस्ट को केन्द्रीय विभागों के निदेशक के

रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये, क्वोमिंताङ के किसी भी सदस्य को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, तथा वर्तमान में जो कम्युनिस्ट क्वोमिंताङ के सदस्य थे, उनकी सूची क्वोमिंताङ के अध्यक्ष को सौंपी जानी चाहिये । इस विधेयक का वास्तविक महत्त्व च्याङ काई-शेक के गुट द्वारा क्वोमिंताङ का नेतृत्व हथियाने के षड्यन्त्र में निहित था । उस मीटिंग के बाद, च्याङ ने क्वोमिंताङ की केन्द्रीय समिति की सभी शक्तियों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया ।

च्याङ काई-शेक के ये षड्यन्त्र, छन तू-श्यू, जिसका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्वकारी संगठनों पर व्यापक नियंत्रण था, के दक्षिणपंथी अवसरवाद के कारण संभव हो पाए । चुङशान युद्धपोत वाले हादसे के बाद कामरेड माओ त्से-तुङ तथा अन्य साथियों ने च्याङ काई-शेक की विश्वासघाती गतिविधियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा तथा उसके सभी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रों का मुँहतोड़ जवाब देने की पैरवी की । ऐसे आक्रमण की सफलता की पूरी संभावना थी, क्योंकि च्याङ काई-शेक उस समय बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया था, राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की क्वाङतुङ स्थित सेना का केवल छोटा सा ही भाग उसकी कमान में था तथा सभी जन-आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण प्रभाव में थे । यदि पार्टी ने दृढ़ नीति अपनाई होती तो च्याङ के साम्यवाद-विरोधी षड्यन्त्रों को विफल किया जा सकता था । तथापि छन तू-श्यू अवसरवादियों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तथा दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की जगह लगातार "सहयोग" का राग अलापते रहे । उनका मत था कि क्रांति का उभार उतार पर था एवं कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वाम पक्ष की ताकत च्याङ काई-शेक को काबू करने के लिए काफी न थी । दूसरी ओर, उन्होंने तर्क दिया कि च्याङ काई-शेक के पास न केवल एक शक्तिशाली सेना थी बल्कि सारा पूँजीपति वर्ग भी उसके साथ था, इसलिए पूँजीपति वर्ग को संयुक्त मोर्चे में टिकाए रखने के लिए पार्टी को रियायत देनी ही पड़ेगी । "चुङशान युद्धपोत हादसे" के बाद छन तू-श्यू ने च्याङ को चीन के राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का "स्तंभ" तथा उस का विरोध करने वालों को साम्राज्यवादियों के "औजार" कहने की भूल की । "एकीकरण" के चक्कर में छन तू-श्यू अवसरवादियों ने पीठ में छुरा घोंपे जाने पर भी जवाबी कार्यवाही करने का साहस नहीं दिखाया । असल में ऐसा करने की उनकी मंशा ही नहीं थी । 4 जून को छन ने च्याङ के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी जिसमें उसने च्याङ के अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश की । छन के अपने शब्दों में—"तथ्यों से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ह्वाङफू सैनिक अकादमी की स्थापना से लेकर 20 मार्च 1926 तक, च्यांङ ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसे प्रति-क्रांतिकारी की संज्ञा दी जा सके ।" चूंकि छन तू-श्यू, तिकड़मी तथा स्वार्थजीवी च्याङ काई-शेक को एक क्रान्तिकारी समझता था, अतः कोई हैरानी की बात न होती यदि वह च्याङ का विरोध करने को प्रति-क्रान्तिकारी कार्य मानने की सीमा तक जा पहुँचता ।

समझौते तथा रियायत की इस नीति ने च्याङ की प्रति-क्रांतिकारी आकांक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दिया ।

लेकिन, जैसा कि च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रियावादी गुट की योजना श्रमिकों तथा किसानों की ताकत को अपने लिए अधिक से अधिक माल बटोरने में इस्तेमाल करने की थी, इसलिए वे अभी कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध करने से हिचकिचा तथा डर रहे थे ।

स्थापित कर लिया । लेकिन दूसरी ओर, सेनाओं, खासतौर से चौथी सेना, जोकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वाम पक्ष के नेतृत्व तथा प्रभाव में थी, ने अपने उत्तर की ओर अभियान के दौरान ऊ फेइ-फू तथा सुन छ्वान-फाङ की मुख्य सैन्य-शक्ति को नेस्तनाबूद कर दिया । हुनान व हुपे में श्रमिकों तथा किसानों का जन-आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था । इसका परिणाम यह निकला कि ऊहान पर कब्जे के पश्चात दो केन्द्रों का जन्म हुआ । कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वामपक्ष के नेतृत्व में ऊहान क्रान्ति का केन्द्र बना, जबकि नानछाङ च्याङ के नेतृत्व वाले प्रतिक्रान्तिकारियों का केन्द्र बन गया ।

दूसरे, फूच्येन, चच्याङ, च्याङशी तथा आनह्वेइ की लड़ाई में सुन छ्वान-फाङ के सैनिकों की बगावत ने क्रान्तिकारी सेना की निर्विघ्न प्रगति का मार्ग लगभग साफ कर दिया । बहुत से दक्षिणी युद्ध-सरदार भी क्रान्ति की तरफ आ गए थे । फलतः नई फौजी यूनिटों के जुड़ने से राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना के आकार में काफी वृद्धि हुई, इन यूनिटों में से अधिकतर अभी भी युद्धपतिवाद के तौर-तरीकों के आधार पर संगठित थीं । भाड़े के सिपाहियों की प्रणाली का लाभ उठाते हुए, सेनापति अभी भी अपनी सैनिक सत्ता सुरक्षित रखे हुए थे, उन्होंने कैंटन की क्रान्तिकारी सरकार को आत्मसमर्पण केवल अपनी ताकत बचाए रखने की इच्छा के वशीभूत हो कर किया था न कि क्रांति के प्रति किसी वास्तविक झुकाव के कारण ।

जैसे-जैसे श्रमिकों तथा किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन का निरंतर विस्तार होता गया, श्रमिक वर्ग, आंदोलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गया ।

क्रांतिकारी पाँतों में मौजूद पूँजीपति वर्ग तथा युद्ध-सरदारों ने जब देखा कि श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी तथा उत्तरी युद्ध-सरदार विरोधी संघर्ष आगे बढ़ता हुआ उनके नियंत्रण से बाहर हो चला है तथा उनके ही वर्ग हितों को चुनौती दे रहा है, तो उन्होंने साम्राज्यवादियों के दबाव व बहकावे में आकर क्रान्ति की जड़ें खोदने के लिए एक-दूसरे से गुप्त रूप से सहयोग करना तथा क्रान्ति के नेतृत्व को हड़पने की तैयारियां करना शुरू कर दिया ।

अतः शंघाई तथा नानकिङ पर क्रान्तिकारी सेना के कब्जे की पूर्व वेला पर ही क्रान्तिकारी पाँतों के भीतर वर्गों के एक नये समीकरण का जन्म हो रहा था । ●

2.

- **राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन तथा हुनान उसके केन्द्र की भूमिका में ।**
- **किसान समुदाय की क्रान्ति में भूमिका के संबंध में कामरेड माओ का सिद्धान्त ।**

उत्तरी अभियान सेना के याङत्सी घाटी की ओर विजयी प्रस्थान ने हुनान को राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन का केन्द्र बना दिया तथा एक ऐसा रणक्षेत्र बना दिया, जहाँ क्रांति तथा प्रति-क्रांति के मध्य प्रचण्ड संघर्ष हुआ । अतः, हुनान में किसान आंदोलन का विकास चीनी क्रांति की सामान्य परिस्थिति से निकट से जुड़ा हुआ था ।

राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के उभार को कामरेड माओ की क्रांतिकारी गतिविधियों से

छाङशा के नागरिकों ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने **''हुनान जनवादी अंतरिम समिति''** (Hunan People's Provisional Committee) का गठन किया । फिर उन्होंने एक प्रदर्शन का आयोजन किया । जनसाधारण के दबाव से डरकर युद्ध-सरदार चाओ हङ-थी छाङशा से भाग खड़ा हुआ । उत्तरी अभियान सेना की सभी लड़ाइयों में हुनान के श्रमिकों तथा किसानों ने हरावल दस्तों के लड़ाकों, गाइडों, संदेशवाहकों तथा परिवहन कर्मचारियों के रूप में काम करते हुए; भागते हुए शत्रु को छिपकर गोली का निशाना बनाते हुए तथा प्रचार ब्रिगेडें व मनोरंजन दलों का गठन करते हुए सक्रिय रूप से भाग लिया । जब युद्ध-सरदार ये खाए-शिन उत्तरी अभियान सेना के आने पर छाङशा से बच कर भाग निकला, प्रान्तीय ट्रेड यूनियन महासंघ ने शहर के अन्दर तथा बाहर की गलियों व सड़कों की चौकसी तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हजार से ऊपर लोगों की श्रमिक रक्षा कोर का गठन किया । छाङशा, च्याङशी में आनय्वान तथा अन्य स्थानों के श्रमिकों ने कई हजार लोगों के दल का गठन करके अपने वाहनों द्वारा क्रान्तिकारी सेना की परिवहन में सहायता की । कैंटन-हानखओ रेलवे के श्रमिकों ने रेलवे विध्वंसक कोर का गठन किया तथा हानयाङ शस्त्रागार के श्रमिकों ने क्रान्तिकारी सेना के उत्तर की ओर अभियान के साथ तालमेल स्थापित करते हुए आम हड़ताल का आयोजन किया ।

उत्तरी अभियान सेना द्वारा छाङशा, य्वेयाङ तथा ऊहान पर जल्दी से अधिकार करने में सफलता प्राप्त करने में श्रमिकों तथा किसानों के समर्थन का बहुत बड़ा योगदान था ।

छः महीने से भी कम समय में (जुलाई से दिसंबर 1926 तक) क्वाङतुङ क्रान्तिकारी सेना ने हुनान, हुपे, फूच्येन, चच्याङ, च्याङशी तथा आनह्वेइ पर अधिकार कर लिया, ऊ फेइ-फू की सेना को निरस्त्र कर दिया तथा सुन छ्वान-फाङ के मुख्य सैन्य-दल को परास्त कर दिया । च्याङसू के शंघाई, नानकिङ तथा दूसरे नगरों की घेराबंदी कर ली गई । चली युद्ध-सरदारों—ऊ फेइ-फू तथा सुन छ्वान-फाङ के क्रान्तिकारी सेना की प्रगति को रोकने के प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया गया था । चली गुट के पतन से राष्ट्रीय स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया जो कि क्रांति के अनुकूल था और वह था—दक्षिण में राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना का उत्तर में फङथ्येन गुट के विरुद्ध शक्ति संतुलन । ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना और आगे बढ़ती गई तथा और ज्यादा विजयें प्राप्त करती गई, तो यह निश्चित तौर पर प्रतीत होने लगा कि व्यापक जनसमुदाय के समर्थन से यह साम्राज्यवादियों तथा उत्तरी युद्ध-सरदारों को पराजित करके चीन की स्वतंत्रता और एकीकरण के सपने को साकार करेगी।

लेकिन क्रांतिकारी सेना के विजय अभियान में गंभीर संकट घात लगाए बैठे थे । पहला, क्रांतिकारी शिविर में फूट पड़ गई । उत्तरी अभियान के आरंभ में च्याङ काई-शेक ने प्रधान सेनापति का पद हड़प लिया था तथा राष्ट्रीय सरकार के तहत सारी की सारी थल, जल तथा वायुसेना को उसके नियंत्रण में दिये जाने के साथ-साथ राजनीतिक विभाग, जनरल स्टाफ तथा फौजी रसद विभाग को भी उसके नियंत्रण में दिये जाने का दावा पेश कर दिया था । अभियान आरंभ होने के पश्चात, राष्ट्रीय सरकार के सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय विभाग प्रधान सेनापति के नियंत्रण में कर दिए गए तथा सभी नागरिक व सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार भी उसे मिल गया । इस प्रकार प्रधान सेनापति के रूप में प्राप्त अधिकारों के फलस्वरूप, च्याङ काई-शेक ने प्रति-क्रांतिकारी तानाशाही का एक संपूर्ण ढांचा

फलतः ''पार्टी के कामकाज के पुर्नगठन के बारे में विधेयक'' के स्वीकृत होने के पश्चात् च्याङ ने अपनी प्रति-क्रान्तिकारी दोहरी नीति जारी रखी । प्रकट में तो उसने कम्युनिस्टों के साथ सहयोग की रट लगाए रखी, परन्तु असल में वह पूरी तरह एक बड़े प्रति-क्रान्तिकारी राज-विप्लव की तैयारी में जुटा हुआ था । ●

नोट

1. **राज्यक्षेत्रातीत अधिकार** :- इससे तात्पर्य है कानसुलर-न्यायाधिकार । साम्राज्यवादी आक्रमणकारी शक्तियों ने चीन से जो विशेषाधिकार ऐंठ रखे थे, यह भी उन्हीं में से एक था । तथाकथित कानसुलर-न्यायाधिकार के अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि साम्राज्यवादी देशों के चीन स्थित नागरिकों पर चीनी कानून लागू नहीं होगा ; अपराध करने पर या दीवानी मुकद्दमों में प्रतिवादी होने पर उन्हें केवल उनके अपने देश के चीन स्थित कानसुलर-न्यायालयों में ही पेश किया जा सकता था, चीन सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी ।

2. **फङ पाए** :- कामरेड फङ पाए चीन के शुरुआती दौर के किसान आंदोलन के कम्युनिस्ट नेता थे तथा क्वाङतुङ के हाएफङ व लूफङ के देहात में क्रान्तिकारी सरकार के संस्थापक थे । उन्हें 1927 तथा 1928 में लगातार पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा इसके राजनीतिक ब्यूरो के लिये चुना गया। सन् 1929 में शंघाई में क्वोमिंताङ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनकी हत्या कर दी ।

3. **सू चाओ-चङ** :- कामरेड सू चाओ-चङ चीन में शुरुआती दौर के श्रमिक-वर्ग आंदोलन के एक कम्युनिस्ट नेता थे, तथा 1922 में हुई हांगकांग के नाविकों की विशाल हड़ताल तथा 1925 की कैंटन-हांगकांग हड़ताल के संगठनकर्ता तथा नेता थे । 1927 में उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का सदस्य तथा राजनीतिक ब्यूरो का वैकल्पिक सदस्य चुना गया । 1928 में उन्हें पार्टी के केन्द्रीय राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य चुना गया तथा जनवरी 1929 में शंघाई में उनकी मृत्यु हो गई।

4. **तङ छुङ-श्या** :- तङ चीन में प्रारंभिक श्रमिक वर्ग आंदोलन के एक कम्युनिस्ट नेता थे। वे 1922 में चीनी ट्रेड-यूनियन सचिवालय के चेयरमैन तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य थे । 1928 में ट्रेड-यूनियनों के अखिल चीनी महासंघ ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में ट्रेड-यूनियनों की लाल इंटरनेशनल (Red International of Trade Unions) में भेजा। तथा ट्रेड-यूनियन इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस में उन्हें लाल इंटरनेशनल की कार्यकारी कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया । 1930 में वे वापिस चीन लौट आए तथा पश्चिमी हुपे-पश्चिमी हुनान के क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र में स्थित लाल सेना की दूसरी फौजी कोर के राजनीतिक कमिसार के रूप में कार्य किया । 1933 में शंघाई में क्वोमिंताङ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके, उसी साल नानकिङ में उनकी हत्या कर दी ।

5. **पाओनुङ प्रणाली** :- इस प्रणाली के तहत पूँजीपति एक कंपनी का गठन करके जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े जमींदारों से लगान पर ले लेते थे तथा फिर उसके छोटे-छोटे टुकड़े आगे लगान पर दे देते थे। इस प्रकार असामी किसानों को शोषण की दोहरी चक्की में पिसना पड़ता था ।

6. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1971, पृष्ठ-15 ।

7. **भूमिधर किसान** :- ये मध्यम किसान होते हैं । इनमें से अधिकांश के पास अपनी खुद की जमीन होती है । कुछ के पास सिर्फ एक हिस्सा खुद का होता है तथा बाकी जमीन वे लगान पर लेते हैं । इनके पास खेती के औजार पर्याप्त मात्रा में होते हैं । इनकी आमदनी का जरिया मुख्यतः अपना ही श्रम होता है तथा आमतौर पर वे दूसरों का शोषण नहीं करते ।

8. अर्ध-भूमिधर किसान :- वे गरीब किसान जो अंशतः अपनी जमीन पर काम करते हैं और अंशतः दूसरों से लगान पर ली हुई जमीन पर ।

9. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ 1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1971, पृष्ठ-9

10. —वही—पृष्ठ-5

11. —वही—पृष्ठ-5

12. 30 मई आंदोलन :- यह आन्दोलन, 30 मई, 1925 को शंघाई में बरतानवी पुलिस द्वारा किए गए, चीनी जनता के संहार के विरुद्ध छेड़ा गया देशव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन था । मई 1925 में छिङताओ और शंघाई की उन सूती कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने की हड़तालें हुईं जिनके मालिक जापानी थे । जापानी साम्राज्यवादी और उनके पालतू कुत्ते—उत्तरी युद्ध-सरदार—उन्हें दबाने में जुट गए । 15 मई को शंघाई की एक जापानी सूती-कपड़ा मिल के पूँजीपति ने कू चङ-हुङ नाम के एक मजदूर को गोली से मार डाला और दस से ज्यादा मजदूरों को घायल कर डाला । 28 मई को छिङताओ में प्रतिक्रियावादी सरकार ने आठ मजदूरों की हत्या कर डाली । 30 मई को शंघाई के दो हजार से अधिक विद्यार्थियों ने विदेशियों को पट्टे पर दी गई बस्तियों में मजदूरों का समर्थन करने के लिए प्रचार किया और पट्टे पर दी बस्तियों को वापस लेने का आह्वान किया । बरतानिया को पट्टे पर दी गई बस्ती के पुलिस-केन्द्र के सामने दस हजार से अधिक जनता इकट्ठी हो गई । उसने "साम्राज्यवाद का नाश हो !" और "चीनी जनता एक हो !" आदि नारे लगाए । बरतानवी साम्राज्यवाद की पुलिस ने जनता पर गोली चलाई तथा बहुत से विद्यार्थियों को मार डाला और घायल कर दिया । यही वारदात **30 मई का हत्याकाण्ड** कहलाती है । इस वारदात से सारे देश की जनता में रोष भड़क उठा । जगह-जगह प्रदर्शन हुए और मजदूरों, विद्यार्थियों व दुकानदारों की हड़तालें हुई, जिन्होंने अन्त में एक बहुत बड़े पैमाने के साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया ।

13. ताए ची-थाओ :- ताए ची-थाओ अपनी युवावस्था में ही क्वोमिंताङ में शामिल हो गया था और च्याङ काई-शेक के सांझीदार की हैसियत से सट्टा बाजार में मुनाफाखोरी करता था । 1925 में सुन यात-सेन के देहान्त के बाद, उसने कम्युनिस्ट-विरोधी तहरीक छेड़कर 1927 में हुए च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रान्तिकारी राजविप्लव के लिए विचारधारात्मक आधार तैयार किया । लंबे अरसे तक वह प्रतिक्रान्तिकारी कामों में च्याङ काई-शेक का वफादार कुत्ता बना रहा । च्याङ काई-शेक के शासन का विनाश निकट देखकर, उसने हताश होकर फरवरी 1949 में आत्महत्या कर ली ।

●●●

के हाथ में थी, सुन छ्वान-फाङ की सेना से पहली ही मुठभेड़ में धराशायी हो गया, क्योंकि इस दस्ते में से कम्युनिस्टों को निकाल दिये जाने के कारण इसकी लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी । आनह्वेइ में उत्तरी अभियान सेना च्योच्याङ से प्रस्थान करके, याङत्सी नदी की धारा के साथ-साथ नीचे की तरफ आगे बढ़ी तथा युद्ध-सरदारों की उन सेनाओं के साथ मिलकर, जो क्रान्ति की तरफ आ मिली थीं, हफी, फङफू, आनकिङ तथा ऊहू पर कब्जा कर लिया तथा नानकिङ के प्रवेश द्वार पर पहुँच गईं । इस प्रकार नानकिङ उत्तर तथा दक्षिण की तरफ से एक प्रकार की कैंची में फंस गया था ।

बाद में कुछ समय के लिए नानछाङ पर च्याङ काई-शेक की सेनाओं ने कब्ज़ा कर लिया तथा उसने इसे प्रति-क्रांतिकारी केन्द्र में परिवर्तित कर दिया ।

तीसरा युद्ध मोर्चा फूच्येन-चच्याङ मोर्चा था । जब उत्तरी अभियान आरंभ हुआ, च्याङ काई-शेक की अपनी पहली सेना का एक अन्य दस्ता, जिसकी कमान हो इङ-छिन के हाथ में थी, शत्रु को फूच्येन में प्रविष्ट होने से रोकने के उद्देश्य से क्वाङतुङ स्थित छाओचओ तथा शानथओ में घुस गया । जब च्याङशी का युद्ध जोरों पर था, फूच्येन के युद्ध-सरदार चओ इन-रन की सेनाएं क्वाङतुङ में मेइश्येन के एक जिले सुङखओ में घुस गईं, जबकि हो इङ-चिन ने अपने सैन्य-दलों को क्वाङतुङ के पूर्व से छाङचओ, छ्वानचओ तथा फूचओ पर धावा बोलने के लिए भेजा । सुन छ्वान-फाङ की मुख्य सैन्य-शक्ति के अभाव में फूच्येन की लड़ाई ने कोई भयंकर रूप धारण नहीं किया । चच्याङ की लड़ाई दिसंबर में शुरू हुई जब सुन छ्वान-फाङ की फौजों ने स्थानीय विद्रोही सैनिक दस्तों को चूचओ में पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए हो इङ-चिन तथा पाए छुङ-शी च्याङशी की ओर से शहर में प्रविष्ट हो गए तथा वहां से हाङचओ तथा शाओशिङ की ओर बढ़े तथा फरवरी 1927 में उन पर कब्जा कर लिया ।

श्रमिकों तथा किसानों ने उत्तरी अभियान सेना को याङत्सी घाटी में उसके अभियान के दौरान सक्रिय सहयोग प्रदान किया ।

जब अभियान सेना ने कूच किया, तब कैंटन-हांगकांग हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों ने परिवहन, प्रचार तथा चिकित्सा यूनिटों का गठन किया तथा हजारों लोगों ने सेना के साथ-साथ उत्तर की ओर प्रस्थान किया । उत्तरी अभियान सेना द्वारा ऊहान पर कब्जा करने के पश्चात कैंटन-हांगकांग हड़ताल समिति ने क्रान्ति की प्रगति को तीव्रता प्रदान करने के लिए स्वेच्छापूर्वक हड़ताल समाप्त कर दी ।

हुनान तथा हुपे के श्रमिकों तथा किसानों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में क्रान्तिकारी सेना को सशक्त सहयोग प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप क्रान्तिकारी सेना तेजी से दोनों प्रान्तों में घुसने में कामयाब हुई ।

उत्तरी अभियान की पूर्व संध्या पर हुनान के श्रमिक, किसान तथा विद्यार्थी सभी पहले से ही व्यापक पैमाने पर सुसंगठित थे । प्रांत में कुल मिला कर 1,10,000 संगठित श्रमिक तथा 4,00,000 से अधिक संगठित किसान थे । 10 लाख से अधिक लोग सीधे पार्टी के प्रभाव में थे । कॉलेज तथा माध्यमिक स्कूलों के अधिकतर विद्यार्थी संगठित थे तथा उन्हें कई क्रांतिकारी संघर्षों का अनुभव भी था ।

9 मार्च, 1926 को युद्ध-सरदार सरकार द्वारा जन-नेताओं के कत्लेआम के विरोध में

सैनिक तैनात थे । ऊ की प्रतिक्रियावादी सेना को नष्ट करना उत्तरी अभियान सेना का मुख्य काम हो गया था ।

इस मोर्चे पर चौथी सेना तथा अन्य सैनिक दस्तों का गठन किया गया, जिनमें 50,000 सैनिक थे । चौथी सेना की स्वतन्त्र रेजीमेन्ट ने, जो जनरल ये थिङ के नेतृत्व में थी, हरावल दस्ते की भूमिका निभाई । यह चुने हुए सैन्य-दलों से बनी थी । इसमें अधिकतर कम्युनिस्ट तथा नौजवान कम्युनिस्ट लीग के सदस्य थे । इसने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था ।

सेना के मुख्य सैनिक दस्तों के कूच करने से पहले ही, स्वतन्त्र रेजीमेन्ट हुनान में घुस गई तथा उत्तरी अभियान सेना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया । ऊ फेइ-फू की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाते हुए तथा उसकी सेना के मनोबल को ध्वस्त करते हुए उसने तुरत-फुरत छाङशा तथा य्वेयाङ पर कब्ज़ा कर लिया । फिर क्रांतिकारी सेना बिना किसी रुकावट के उत्तर की ओर बढ़ चली ।

हुपे में तिङसच्याओ की लड़ाई युद्ध की सबसे भयंकर मुठभेड़ थी। हुपे में कैंटन-हानखओ रेलमार्ग पर स्थित तिङसच्याओ सामरिक महत्त्व का एक लगभग अभेद्य गढ़ था । उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में यह पानी से घिरा हुआ था तथा पूर्व में ऊंचे पहाड़ इसकी रक्षा करते थे । केवल दक्षिण-पश्चिम से ही इसमें पहुँचा जा सकता था, जहां रेलमार्ग एक गहरी नदी के पश्चिम में फैला हुआ था । ऊ फेइ-फू की कुछ टुकड़ियां इसकी रक्षा कर रही थीं, जबकि दूसरी टुकड़ियां प्रत्याक्रमण के लिए पूरी तेजी से कुमुक के रूप में उत्तर की तरफ से नीचे उतरीं । उनकी योजना तब तक डटे रहने की थी जब तक च्याङशी में सुन छ्वान-फाङ छाङशा पर हमला करके क्रान्तिकारी सेना की वापिसी का रास्ता काटने की तैयारी न कर ले। लेकिन उत्तरी अभियान सेना उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ी तथा अगस्त के अंत में तिङसच्याओ पर कब्जा करके ऊ फेइ-फू की युद्ध-योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया । जब ऊ फेइ-फू की सेना उत्तर से हानखओ पहुँची तथा सुन छ्वान-फाङ ने च्याङशी में अपने मुख्य सैन्य-बल को फौजी कार्यवाही करने के आदेश दिए, तब तक लड़ाई स्पष्टतया समाप्त हो चुकी थी । इससे समूचे मोर्चे पर तिङसच्याओ की लड़ाई की तुरत-फुरत विजय का बहुत बड़ा महत्त्व प्रकट होता है ।

कैंटन-हानखओ रेलमार्ग पर अगला सामरिक महत्त्व का स्थल होशङच्याओ था, तथा वहां पर भी ऊ फेइ-फू की ही सेनाएं तैनात थीं । उत्तरी अभियान सेना ने हुनान तथ हुपे में ऊ की मुख्य सैन्य-शक्ति को तहस-नहस करते हुए शत्रु के मुख्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। बाद में, इसने हानखओ पर अधिकार कर लिया तथा 10 अक्तूबर को ऊछाङ पर भी कब्जा कर लिया । ये दो शहर आने वाले समय में कुछ अर्से तक क्रान्ति का केन्द्र बनने वाले थे । 1926 के अंत तक ऊ फेइ-फू की बची-खुची सेनाओं को ऊशङक्वान दर्रे के पार खदेड़ दिया गया था । इस प्रकार हुपे प्रान्त का एकीकरण हो गया ।

दूसरा युद्ध-मोर्चा च्याङशी-आनह्वेइ-च्याङसू मोर्चा था । हुनान-हुपे मोर्चे पर निर्णायक विजय के उपरान्त, उत्तरी अभियान सेना की मुख्य सैन्य-शक्ति वहां से च्याङशी की ओर कूच कर गई । सेना में कम्युनिस्टों द्वारा किये गए राजनीतिक कार्य के कारण, दूसरी तथा छठी सेना ने सुन छ्वान-फाङ की मुख्य सैन्य-शक्ति को च्याङशी की लड़ाई में कुचल कर रख दिया। परन्तु च्याङ काई-शेक की अपनी पहली सेना का एक दस्ता, जिसकी कमान वाङ पो-लिङ

चौथा अध्याय

उत्तरी अभियान
प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध में गंभीर स्थिति
(जुलाई 1926-जुलाई 1927)

1.

- उत्तरी अभियान से पूर्व घरेलू स्थिति ।
- उत्तरी अभियान सेना का याङत्सी घाटी की ओर प्रस्थान ।
- उत्तरी अभियान के दौरान वर्ग संबंधों में नए परिवर्तन ।

1924 में पेकिङ राजविप्लव के बाद फङथ्येन गुट का युद्ध-सरदार चाङ च्वो-लिन, उत्तरी चीन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुखिया बन गया । उसके गुट ने राष्ट्रीय असेम्बली का विरोध किया, फङ य्वी-श्याङ की राष्ट्रीय सेना, जिसका क्रांति की ओर झुकाव था, का बहिष्कार किया, चीन की लम्बी दीवार के दक्षिण में अपने क्षेत्र का विस्तार किया तथा जनता के क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन किया । इस प्रकार 30 मई, 1925 की घटना के परिणाम स्वरूप उभरते देशभक्तिपूर्ण आंदोलन को फङथ्येन युद्ध-सरदारों की बर्बरतापूर्ण नीति ने पूर्णतया नष्ट कर दिया । ये विश्वासघाती फङथ्येन युद्ध-सरदार, चूँकि साम्राज्यवादियों के अत्यधिक शक्तिशाली हथियार थे, इसलिए समूची चीनी जनता ने इनका दृढ़तापूर्वक विरोध किया तथा फङथ्येन-विरोधी एक व्यापक आंदोलन देश भर में फैल गया ।

जनता की फङथ्येन विरोधी भावनाओं का लाभ उठाते हुए चली गुट के दो युद्ध-सरदारों ऊ फेइ-फू तथा सुन छ्वान-फाङ ने चाङ च्वो-लिन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा च्याङसू के शंघाई क्षेत्र पर आक्रमण के लिए कूच कर दिया । उन्होंने फङथ्येन विरोधी आंदोलन में नेतृत्वकारी स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि साम्राज्यवादियों की कृपादृष्टि पाने में फङथ्येन गुट से होड़ ली जा सके । दिसंबर 1925 में फङथ्येन विरोधी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के उभार के दौरान, फङथ्येन गुट की पांतों में "**क्वो सुङ-लिङ विद्रोह**" के नाम से एक घटना घटित हुई । क्वो ने हपे प्रान्त के ल्वानचओ नामक स्थान पर बगावत की तथा अपनी सेना को फङथ्येन के इलाके तक ले आया ।

इस प्रकार उत्तरी चीन में चाङ च्वो-लिन का प्रतिक्रियावादी शासन बुरी तरह लड़खड़ा रहा था ।

जापानी साम्राज्यवादियों ने सरेआम पूरी बेशर्मी से चाङ च्वो-लिन की फौजी साजोसामान से मदद की । उधर जब अमरीकी व बरतानवी साम्राज्यवादियों ने यह देखा कि साम्राज्यवाद के इस सबसे अधिक लाभकारी पिट्ठू के खिलाफ चल रहा जनता का राष्ट्रव्यापी फङथ्येन

विरोधी आंदोलन, अब चीन में उनके प्रभुत्व के लिए गंभीर खतरा बन गया था, तब उन्होंने "कम्युनिस्टों से लड़ने" के नारे के अन्तर्गत, चाङ च्वो-लिन तथा ऊ फेइ-फू में मेलमिलाप करा दिया तथा उन्हें चीनी जनता व राष्ट्रीय सेना जिसका झुकाव क्रान्ति की ओर था, पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

पहला साम्राज्यवादी फौजी हस्तक्षेप दिसंबर 1925 में हुआ, जब क्वो सुङ-लिङ को हराने में चाङ च्वो-लिन की मदद के लिए तथा इस प्रकार फङथ्येन सेनाओं के केन्द्रीय आधार-क्षेत्र को बचाने के लिए जापानी सेनाओं को फँङथ्येन भेजा गया । दूसरा हस्तक्षेप मार्च 1926 में हुआ जब जापान ने चली (हपे प्रान्त) पर आक्रमण करने में चाङ च्वो-लिन की सहायता की, जिसके फलस्वरूप फङ ग्वी श्याङ की राष्ट्रीय सेना को थ्येनचिन, पेकिङ तथा बाद में नानखओ व चाङच्याखओ से पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा । उसी समय ब्रिटेन ने ऊ फेइ-फू की हनान पर आक्रमण करने तथा वहां मौजूद राष्ट्रीय सना को निरस्त करने में सहायता की।

जब चाङ च्वो-लिन की फौजें चली में राष्ट्रीय सेना के खिलाफ आगे बढ़ रही थीं, तब जापानी युद्धपोतों ने ताकू बंदरगाह से राष्ट्रीय सेना पर गोले बरसाकर उसकी मदद की । इससे पेकिङ की जनता भड़क उठी तथा 18 मार्च, 1926 को चीन के आंतरिक मामलों में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया । आन्दोलन में भाग लेने वाले अनेक देशभक्त लोगों को, त्वान छी-रुइ द्वारा नृशंसतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया । बाद में यह घटना—**"18 मार्च का कांड"** के नाम से जानी गयी ।

पेकिङ में किए गए नरसंहार से, चीनी क्रांति को कुचलने के साम्राज्यवादी प्रयास को आंशिक सफलता प्राप्त हुई । फलत: "कम्युनिस्ट विरोधी" आंदोलन देश के कोने-कोने में फैलने लगा । सबसे पहले साम्राज्यवादियों ने चली तथा फङथ्येन गुटों को एकत्र किया, उत्तरी तथा मध्य चीन में उनके वर्चस्व को दृढ़ता प्रदान की । तथा पेकिङ में दोनों गुटों की साँझा सरकार की स्थापना की । दूसरे, उन्होंने राष्ट्रीय सेना को लम्बी दीवार से परे दूर उत्तर-पश्चिम की तरफ खदेड़ने में चाङ च्वो-लिन की सहायता की । तीसरे, उन्होंने हुनान, च्याङशी तथा फूच्येन से क्वाङतुङ के क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र पर घेरा डालकर आक्रमण करने में चली गुट की सहायता की ।

उस समय हनान तथा हुपे ऊ फेइ-फू के कब्जे में थे ; च्याङशी, चच्याङ, आनह्वेइ, च्याङशी तथा फूच्येन सुन छ्वान-फाङ के कब्जे में तथा उत्तर-पूर्वी प्रान्तों के साथ-साथ हपे, छाहाइ व शानतुङ चाङ च्वो-लिन के कब्जे में थे । ऊ फेइ-फू तथा सुन छ्वान-फाङ ने दक्षिण में क्रान्तिकारी सेनाओं पर हमला किया, जबकि चाङ च्वो-लिन ने उत्तर में स्थित क्रान्तिकारी सेनाओं पर हमला किया ।

"कम्युनिस्ट विरोधी" आंदोलन के दौरान, ऊ फेइ-फू तथा चाङ च्वो-लिन के बीच लगातार चल रहे झगड़ों तथा तकरारों के कारण युद्ध-सरदार शिविर में दरार चौड़ी होती जाने के बावजूद, साम्राज्यवादी साजिशों के फलस्वरूप चली तथा फङथ्येन के दोनों गुटों का एकीकरण हो गया । केन्द्रीय सरकार में सत्ता के बंटवारे को लेकर उनके अनेक विवादों से सरकार के मूलभूत प्रतिक्रियावादी चरित्र में कोई बदलाव न आया । साम्राज्यवादियों ने अपने-अपने युद्ध-सरदारों पर नियंत्रण बनाए रखा तथा चीन में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते रहे, लेकिन उन्होंने उत्तरी युद्ध-सरदारों के प्रतिक्रियावादी शासन का

एकजुट होकर समर्थन किया ।

ऊ फेइ-फू ने दक्षिण में क्रान्तिकारी शक्तियों के विरुद्ध निम्न कदम उठाए : पहला, क्रान्तिकारी झुकाव वाले सैन्य-दलों को हुनान से बाहर खदेड़ने में सभी प्रतिक्रियावादी सेनाओं की सहायता करना तथा वहां मौजूद क्रान्तिकारी सेनाओं पर हमला करना; दूसरे, हुपे के सभी सैन्य-दलों तथा हनान, हुनान और च्याङशी प्रान्तों के सैन्य-दलों के कुछ हिस्सों को इकट्ठा करके उस समय के क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों—क्वाङतुङ तथा क्वाङशी पर आक्रमण करना। यह देखते हुए कि चीनी जनता चली तथा फङथ्येन युद्ध-सरदारों के शासन को अब और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्वाङतुङ की क्रांतिकारी सरकार ने उत्तरी युद्ध-सरदारों की प्रतिक्रियावादी सरकार को एक क्रांतिकारी युद्ध के माध्यम से चकनाचूर करने तथा देशभर की दबी-कुचली जनता की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माँगों के अनुरूप चीन की स्वतंत्रता तथा एकता को साकार करने का निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त, उस समय क्रांतिकारी सरकार घेराबन्दी का निशाना बनी हुई थी तथा इस असुविधाजनक स्थिति से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता, **उत्तरी अभियान** आरंभ करना था ।

जुलाई 1926 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने मौजूदा स्थिति पर एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें देशभर के श्रमिकों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं सैनिकों से एकजुट होने, राष्ट्रीय क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे को सुदृढ़ करने तथा युद्ध-सरदारों एवं साम्राज्यवादियों के शासन का तख्ता पलटने का आह्वान किया । उत्तरी अभियान शुरू करने के लिए क्वाङतुङ की क्रान्तिकारी सरकार के लिये यह एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था । लेकिन छन तू-श्यू ने पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए पार्टी के साप्ताहिक पत्र *'दि गाइड'* में *"राष्ट्रीय सरकार के उत्तरी अभियान पर"* नाम से एक लेख छापा जिसमें उसने उत्तरी अभियान के महत्त्व का वास्तविकता से कम आकलन किया तथा कहा कि इसके लिए हालात अभी अपरिपक्व थे तथा मौजूदा कार्यभार उत्तरी अभियान की बजाय "रक्षा" करना होना चाहिये । उसका कहना था कि अभियान क्वोमिंताङ तथा राष्ट्रीय सरकार का दायित्व था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य सत्ता से बाहर वाली पार्टी के रूप में केवल सहायता देना भर था । उसके इस तरह के उदासीनतापूर्ण रवैये ने, असल में, अभियान के राजनीतिक महत्त्व को क्षीण कर दिया तथा युद्ध का फौजी नेतृत्व हथियाने में च्याङ का रास्ता साफ कर दिया ।

जुलाई 1926 में क्रान्तिकारी सेना ने उत्तर की ओर अपना अभियान आरंभ कर दिया ।

सोवियत लाल सेना की तर्ज पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रांतिकारी सेना में राजनीतिक काम की प्रणाली लागू की । अधिकतर राजनीतिक कार्य की जिम्मेदारी कम्युनिस्टों के कंधों पर थी, अभियान की निर्णायक सफलता में इस तथ्य का एक महत्त्वपूर्ण योगदान था ।

उत्तरी अभियान की रणनीतिक योजना क्रांतिकारी सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियों को हुनान-हुपे मोर्चे पर तैनात करने तथा फूच्येन व च्याङशी में शत्रु को काबू में रखने के लिए दो दस्ते क्वाङतुङ की पूर्वी तथा उत्तरी सीमाओं पर भेजने की थी । हुनान-हुपे मोर्चे पर विजय प्राप्त करने के बाद अभियान सेना ने अपनी सैन्य शक्ति को सुन छ्वान-फाङ की फौजों पर आक्रमण करने के लिए केन्द्रित करना था तथा चाङ च्वो-लिन अन्तिम निशाना रहना था ।

उत्तरी अभियान की पहली लड़ाई हुनान-हुपे मोर्चे पर हुई, जहाँ ऊ फेइ-फू के एक लाख

ऐसा कोई भी विचार कि आमूल-चूल कृषि-सुधार तथा जनवादी सरकार की स्थापना करने से पहले उत्तरी अभियान पूरा किया जाए, केवल पूँजीपति वर्ग की ही मदद करेगा, जिसने साम्राज्यवादियों के हितों की खातिर, तटवर्ती प्रान्तों में तेजी से घुसपैठ करने के लिए राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ लिया था ।

कहने का तात्पर्य यह कि, कृषि सुधार लागू करने से पहले उत्तरी अभियान पूरा करने की धारणा से च्याङ काई-शेक के लिए राष्ट्रवादी का मुखौटा पहनना तथा दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना आसान हो जाता क्योंकि वह भी "अभियान को आगे बढ़ाने तथा सारे देश को एकीकृत करने" की पैरवी कर रहा था ।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि च्याङ काई-शेक की गद्दारी से क्रांति विफल नहीं हुई थी, कि क्रांति उस समय उतार पर नहीं थी, बल्कि क्रान्तिकारी उभार आ रहा था और कि कृषि-क्रांति का समय आ पहुँचा था । उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थान करने के दृष्टिकोण को साफ तौर से कतई बेतुका करार देकर उसका खण्डन किया गया ।

कांग्रेस ने सारी पार्टी के सामने दो महत्त्वपूर्ण कार्यभार रखे : कृषि-क्रांति को कार्यान्वित करना तथा जनता की सत्ता की स्थापना करना ।

कांग्रेस ने केन्द्रीय समिति के लिये 29 सदस्यों तथा 11 वैकल्पिक सदस्यों का चुनाव किया । चूंकि छन तू-श्यू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा की थी, अत: उसे दोबारा पार्टी की केन्द्रीय समिति का महासचिव चुन लिया गया ।

लेकिन असल में, छन तू-श्यू अभी भी अपने अवसरवादी दृष्टिकोण पर पूरी हठधर्मिता से अड़ा हुआ था । कांग्रेस के बाद, राजनीतिक ब्यूरो के बहुत से सदस्य केन्द्रीय समिति में काम कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि पार्टी हर लिहाज से छन के कब्जे में थी ।

अत: पाँचवीं कांग्रेस ने वास्तव में कोई ज्यादा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं की ।

कामरेड माओ ने भी कांग्रेस में भाग लिया, परन्तु छन ने उन्हें नेतृत्व से बाहर रखा तथा गैरकानूनी ढंग से उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया । ●

5.

- **ऊहान पर प्रतिक्रान्तिकारी हमले के दौरान क्वोमिंताङ का ढुलमुलपन ।**
- **छन तू-श्यू की आत्मसमर्पणवादी कार्यदिशा द्वारा क्रान्ति को पहुँचाई गई क्षति ।**
- **वाङ चिङ-वेइ गुट की गद्दारी ।**
- **प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध की असफलता ।**

ऊहान सरकार की स्थापना के समय से ही विपत्तियों ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था । यह एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक नगर था तथा यहां से कई व्यापार-मार्ग निकलते थे, लेकिन उस समय साम्राज्यवादियों तथा युद्ध-सरदारों की सरकार ने इसकी घेराबंदी कर रखी थी। फलत: शहर में स्थित बहुत सी व्यापारिक फर्में मजबूरन बन्द हो गई थी ।

बरतानवी, अमरीकी तथा जापानी पूँजीपतियों ने ऊहान में अपने कारोबारों को बन्द कर

कहा कि पूँजीवादी समाज के दौर से गुजरे बिना चीन में समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती । उसने कहा,*"हम अव्यावहारिक समाजवादी नहीं हैं, अत: हम यह नहीं मान सकते कि पूँजीवादी समाज को नजरअंदाज करते हुए, एक ही छलांग में अर्द्ध-सामंती समाज से समाजवादी समाज में सीधा संक्रमण किया जा सकता है ।"*

इस प्रकार असल में छन तू-श्यू ने प्रतिक्रियावादियों का पिछलग्गु बन कर, उत्तरी अभियान के दौरान लगातार आगे बढ़ रहे किसान आंदोलन पर अंकुश लगा दिया ।

छन तू-श्यू क्वोमिंताङ के जमींदार तथा पूँजीवादी तत्वों को रियायतों तथा समझौतों द्वारा तुष्ट करना चाहता था ताकि वे संयुक्त मोर्चे का साथ न छोड़ जाएँ, तथा उसे लगता था कि इस प्रकार वह क्रांतिकारी ध्येय की रक्षा कर रहा था । नतीजा यह निकला कि कम्युनिस्ट पार्टी जितनी ज्यादा रियायतें देती गई, प्रतिक्रियावादी ताकतें उतनी ही बेलगाम होती चली गईं, जबकि पार्टी की मार्गदर्शक समिति में मौजूद दक्षिणपंथी अवसरवादियों की गलत धारणाओं के कारण जन-आंदोलन को बार-बार अवरोधों का सामना करना पड़ा तथा बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी।

पहले से ही चल रहे या उत्तरी अभियान के दौरान उठ खड़े हुए किसान संघर्षों के समर्थन में जांच-पड़ताल करने के लिए कामरेड माओ त्से-तुङ जनवरी 1927 में हुनान गए तथा प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के काल का पार्टी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज—**"हुनान के किसान आंदोलन की जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट,"**[12] तैयार किया । कामरेड माओ ने किसानों के बहादुराना कारनामों तथा क्रांतिकारी संरचनाओं की दिल खोलकर प्रशंसा की, तथा सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाते हुए मौजूदा किसान क्रांति के अनुभवों तथा उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत किया । प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत किसान समस्या का यह एक वैज्ञानिक सामान्यीकरण था ।

प्रथम, इस रिपोर्ट ने चीनी क्रांति में किसानों की भूमिका का सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत किया । किसान क्रांति उन सभी सामंती शक्तियों को अपना निशाना बनाए हुए थी, जिन्होंने चीन पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए सामाजिक आधार की भूमिका निभाई थी । सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष चीनी किसान समुदाय का एक ऐतिहासिक मिशन था । किसान क्रांति की तहेदिल से प्रशंसा करते हुए, कामरेड माओ ने स्पष्ट तौर से इसके असीम महत्त्व की पुष्टि की, क्योंकि चीनी इतिहास में पिछले हज़ारों सालों में हुए किसान विद्रोहों तथा डॉ० सुन यात-सेन के 40 वर्षों के क्रांतिकारी संघर्ष ने जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, उसे इसने पूरा करना था।

उस समय जमींदार वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अफवाह फैलाई गई जिसके अनुसार किसान आन्दोलन, एक तरह का **"सत्यानाश हो गया था ।"** लेकिन कामरेड माओ ने चीन के दसियों करोड़ किसानों के हितों को वाणी प्रदान करते हुए इस आंदोलन को **"दरअसल बहुत ही ठीक हुआ"** बताकर इसकी सराहना की । उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति एक भीषण तूफान की तरह उठ खड़ी होनी थी तथा कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी । उसने सभी साम्राज्यवादी तथा सामंती ताकतों को यमलोक भेज देना था । सभी राजनीतिक पार्टियों को किसानों द्वारा जांचा-परखा जाना था तथा उनके फैसले के अनुसार अपनाया या ठुकराया जाना था । पार्टियों को निम्न तीन रास्तों में से एक का तुरंत चुनाव करना था : **"उनके आगे-आगे चलें और उनका नेतृत्व करें ? या उनके पीछे-पीछे चलें और उंगली उठा-उठाकर उनकी आलोचना करते रहें ? या उनके**

सामने खड़े होकर उनका विरोध करें ?''[3] चीनी सर्वहारा तथा उसकी पार्टी की ओर से, कामरेड माओ ने पहला रास्ता चुना, तथा इस प्रकार सर्वहारा को किसानों के सच्चे नेता के रूप में प्रस्तुत किया ।

किसान समुदाय में अनेक श्रेणियाँ थीं, उनमें से गरीब किसान, जो ग्रामीण आबादी का बहुमत थे, सर्वाधिक क्रांतिकारी ताकत थे । धनी, मध्यम तथा गरीब किसान, तीनों के क्रांति के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण थे । धनी किसान शुरू से आखिर तक निष्क्रिय बने रहे, जबकि मध्यम किसानों ने ढुलमुल रवैया अपनाया, यद्यपि धनी किसानों से हटकर, उन्हें क्रांतिकारी उभार के समय क्रांति की ओर आकर्षित किया जा सकता था । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसान क्रान्ति की सबसे मुख्य ताकत थे, जिन्होंने हमेशा सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ीं। वे क्रांति की रीढ़ की हड्डी, पथ-प्रदर्शक तथा उसके श्रेष्ठ वीर थे । क्रांतिकारी होने के कारण उन्होंने किसान सभाओं का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था तथा निचले स्तर पर लगभग सभी नेतृत्वकारी पद उनके पास थे । वे उठ खड़े हुए और सत्ता अपने हाथों में ली तथा स्वयं को मध्यम किसानों के साथ मिलाकर धनी किसानों को अलग-थलग कर दिया । कामरेड माओ के शब्दों में **''गरीब किसानों के बिना कोई क्रान्ति नहीं हो सकती । उन्हें नकारना, क्रान्ति को नकारना है । उन पर हमला करना, क्रान्ति पर हमला करना है ।''**[4] तथाकथित *''अवारागर्दों का आंदोलन''* तथा *''आलसी किसानों का आंदोलन''* ऐसे अपमानजनक विशेषण थे जिन्हें, प्रतिक्रान्तिकारी जमींदारों तथा शरीफजादों ने गरीब किसानों पर अपने अत्यधिक घिनौने आक्रमण के रूप में इस्तेमाल किया था ।

दूसरे, इस रिपोर्ट ने, एक क्रांतिकारी सरकार की स्थापना के लिए तथा किसानों की सशस्त्र सेनाओं का गठन करने के लिए, जनता को हिम्मत से लामबन्द करने के क्रान्तिकारी विचार की पैरवी की ।

ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे, दुनिया को हिला कर दे रख देने वाले इन परिवर्तनों को सुधारवादियों ने *''हर चीज को अस्त-व्यस्त करने,'' ''बहुत आगे बढ़ जाने''* तथा *''सत्यानाश हो गया''* की संज्ञा दी । लेकिन कामरेड माओ ने निश्चित रूप से स्पष्ट किया कि क्रान्ति के दौरान ये परिवर्तन अपरिहार्य थे । पहले, किसानों ने जमींदारों के दमन की प्रतिक्रियास्वरूप विद्रोह किया, तथा उनके विद्रोह की उग्रता, स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा झेले गए नृशंसतापूर्ण दमन के अनुरूप थी । उनकी क्रान्तिकारी आम दिशा जरा भी गलत नहीं थी । **''कौन बुरा है और कौन नहीं, कौन सबसे ज्यादा दुष्ट है और कौन कम, और किसे सख्त सजा देनी चाहिये, और किसके साथ जरा मुलायमियत से पेश आना चाहिये, इन सबके बारे में किसान अपना हिसाब एकदम साफ रखते हैं । ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि अपराध की तुलना में सजा ज्यादा दे दी गई हो ।''**[5] दूसरे, क्रान्ति में पुराने का सफाया किये बगैर नव-निर्माण नहीं किया जा सकता था । इसलिए क्रान्तिकारी कार्यवाही के काल में देहाती इलाकों में एक जबरदस्त क्रान्तिकारी उभार का होना तथा किसानों की एकछत्र सत्ता का कायम किया जाना बेहद जरूरी था ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष एक भयंकर वर्ग-संघर्ष था, तथा यह सामंती तथा जनवादी शक्तियों के बीच आखिरी निर्णायक मुकाबला था । क्रांतिकारियों तथा सुधारवादियों में बुनियादी अंतर, क्रांति के प्रति उनके सकारात्मक या नकारात्मक रवैये में

पर ''राजनीतिक जब्ती'' का विचार रखा, यानि कि केवल प्रति-क्रान्तिकारियों की जमीन तथा जायदाद को ही जब्त किया जाए ।

छन की अवसरवादी धारणाओं में से एक थी—**''क्रान्ति के विस्तार की धारणा ।''** वह क्रान्ति के विस्तार तथा तीव्रीकरण, दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग मानता था । उसका कहना था कि या तो क्रान्ति का विस्तार किया जाए, यानि कि उत्तरी अभियान जारी रखा जाए तथा क्रान्ति के क्षेत्र में वृद्धि की जाए, या फिर क्रान्ति को और अधिक गहराई से चलाया जाए, यानि कि कृषि-क्रान्ति लाई जाए तथा जनता की सत्ता स्थापित की जाए । उसने पहला रास्ता चुना, वह भी इसलिये नहीं कि वह उत्तरी अभियान जारी रखने के पक्ष में था, जैसा कि उसने दावा किया, बल्कि इसलिये क्योंकि वह कृषि-क्रान्ति के काम को धीमा करना चाहता था तथा वर्ग-संघर्ष को कुंद करना चाहता था ।

उसकी एक अन्य अवसरवादी धारणा **''उत्तर-पश्चिम की ओर जाने''** की थी । उसका विचार था कि कैंटन, शंघाई, हानखओ, थ्येनचिन तथा अन्य औद्योगिक जिलों में, जहाँ साम्राज्यवादी तथा युद्ध-सरदार ज्यादा ताकतवर थे, क्रांति का विकास नहीं हो सकता था, लेकिन उत्तर-पश्चिमी प्रांत, जहाँ साम्राज्यवादी प्रभाव बहुत कम था, वहाँ क्रांति की जड़ें आसानी से जम सकती थीं । इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि क्रांतिकारी ताकतों को दक्षिण-पूर्वी प्रांतों से उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में लगाया जाए ।

ये धारणाएँ उसकी दक्षिणपंथी अवसरवादी कार्यदिशा का ही जारी तथा विकसित रूप थीं।

कांग्रेस ने छन की अवसरवादी कार्यदिशा की निंदा करते हुए कृषि-सुधारों को लागू करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया ।

कांग्रेस ने **''राजनीतिक स्थिति तथा पार्टी के कार्यभारों से संबंधित प्रस्ताव''** पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि छन की राजनीतिक कार्यदिशा सर्वथा गलत थी तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सिद्धांतों तथा निर्देशों का उल्लंघन करती थी, क्योंकि इसने पूँजीवादी जनवादी क्रांति में सर्वहारा के नेतृत्व का परित्याग करके क्रांति को उसकी विजय के लिए महत्त्वपूर्ण गारंटी से ही वंचित कर दिया था ।

कांग्रेस ने छन की इस गलत धारणा का भी खण्डन किया कि क्रांति का विस्तार तथा तीव्रीकरण एक-दूसरे से अलग-अलग मुद्दे थे । बल्कि कांग्रेस के विचार में ये परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर थे । यदि क्रांति को ठोस आधार प्रदान करना था तो उसका तीव्रीकरण एवं विस्तार दोनों साथ-साथ करने थे । कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि **''क्रांति के विस्तार की धारणा''** केवल पूँजीवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती थी । साथ ही कांग्रेस ने बिना तीव्रीकरण के क्रान्ति का विस्तार करने के खतरों से भी आगाह किया । उदाहरण के तौर पर, विगत में क्रांतिकारी शक्तियों के कब्जे में आए इलाकों में जो कुछ हुआ था, वह जगजाहिर था । उन इलाकों में क्रांति को गहराई से चलाने में विफल रहने के कारण, कोई भी ठोस क्रांतिकारी आधार तैयार नहीं किया जा सका था तथा प्रतिक्रियावादी सामाजिक आधार के अवशेषों को अक्षुण्ण छोड़ दिया गया था । फलतः, जब च्याङ काई-शेक गुट ने गद्दारी की, तो उन्हें अलग-थलग नहीं किया जा सका था, बल्कि उनके अनुगामियों की काफी बड़ी तादाद भी उनके साथ ही संयुक्त मोर्चे से अलग हो गई थी ।

कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि :

जमीन के पुन: बंटवारे की माँग कर रहे थे, हालाँकि प्रतिक्रियावादी शासन के अन्तर्गत किसान संगठनों का सख्तीपूर्वक दमन किया गया । लगान में कमी करने तथा टैक्स अदा न करने को लेकर च्याङशी, आनह्वेइ, चच्याङ तथा फूच्येन के दक्षिण-पूर्वी प्रान्तों में एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ । हनान में, 'लाल भाला समाज' ने युद्ध-सरदारों के विरुद्ध तथा लेवियों एवं टैक्सों की अदायगी के विरुद्ध संघर्ष किये । उत्तरी प्रांतों में भी, किसानों के दल युद्ध-सरदारों के जुल्मों के विरुद्ध उठ खड़े हुए ।

हुनान, हुपे तथा क्वाङतुंङ में किसान आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तथा गरीब किसान उसकी रीढ़ की हड्डी थे । यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा था कि आन्दोलन ने अन्तत: कृषि-क्रांति लेकर आनी थी । गरीब किसान, किसान शासन व्यवस्था का मुख्य आधार थे । क्रांति के लिए यह अत्यावश्यक था कि किसान राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करें, क्योंकि अपनी सरकार के बिना किसान लगान में कटौती तक नहीं करवा सकते थे, जमीन प्राप्त करना तो दूर की बात थी । किसान संघर्ष लगान तथा सूद में कटौती करने को लेकर शुरू हुआ और जमींदारों की सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा कृषि-क्रान्ति लाने के लिए आगे बढ़ गया ।

जबकि सारे देश में किसान आन्दोलन का विकास असमान ढंग से हो रहा था, दक्षिणी प्रांतों में, कुल मिलाकर यह जमींदारों की सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा ज़मीन के लिए संघर्ष करने की स्थिति में पहुँच चुका था । यह चीनी क्रांति के एक नए दौर की बुनियादी विशिष्टता थी ।

क्रान्ति की ऐसी नाजुक परिस्थितियों के दौर में, 27 अप्रैल 1927 को कम्युनिस्ट पार्टी ने हानखओ में अपनी पाँचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की । कांग्रेस में 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 57,900 पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

कांग्रेस में, छन तू-श्यू ने अपनी दक्षिणपंथी अवसरवादी कार्यदिशा को छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया । जलपोत चुङशान घटना के विषय में रियायत तथा समझौते की नीति अपनाकर उसने जो अवसरवादी गलती की थी, उसकी आलोचना से सही निष्कर्ष निकालना तो दूर, उसने उल्टा क्रांतिकारी शक्तियों पर आरोप लगाया कि वे इतनी ताकतवर ही नहीं थीं कि च्याङ काई-शेक को पराजित कर पातीं तथा यह कहते हुए अपनी सफाई दी कि च्याङ काई-शेक के प्रति-क्रान्तिकारी मन्सूबों का पूरी तरह पर्दाफाश नहीं हो पाया था । शंघाई के श्रमिकों के विद्रोह के विषय में छन का मानना था कि श्रमिक वर्ग को अपना संघर्ष आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित रखना चाहिए तथा राजनीतिक संघर्ष या विद्रोह करना गलत था, इस प्रकार उसने श्रमिक वर्ग के नेतृत्व को ही पूरी तरह नकार दिया तथा क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष के विशाल महत्त्व से इंकार कर दिया ।

उस समय सबसे बड़ी बुनियादी समस्या कृषि समस्या थी, जो कि समस्त क्रांति की कुंजी थी । लेकिन छन तू-श्यू ने इस समस्या को किस तरह निपटाया ? उसने पैरवी की कि छोटे जमींदारों की जमीन को हाथ न लगाया जाए । यद्यपि वह बड़े तथा मध्यम दर्जे के जमींदारों की जमीन को जब्त करने पर सहमत हो गया, लेकिन ऐसा उसने केवल सिद्धांत के तौर पर माना, तत्काल कार्यवाही के लिए आदेश देने को वह तैयार न था ।

असल में, छन तू-श्यू ने इस समस्या से पूरी तरह आँखें ही मूंद ली तथा इसके स्थान

अन्तर्निहित था । सुधारवादियों ने किसानों की क्रांतिकारी कार्यवाहियों में अवरोध खड़े करने का प्रयास किया। वे उन्हें केवल सामंती व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्यवाही करने की अनुमति दे रहे थे । वे किसानों को केवल इतनी अनुमति दे रहे थे कि वे सामंती व्यवस्था में कुछ जोड़-तोड़ तो कर सकें, लेकिन उसे नष्ट न करें । कामरेड माओ ने इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का खण्डन करते हुए कहा, **"अन्याय को मिटाने के लिए उचित सीमा से बाहर जाना जरूरी होता है और उचित सीमा से बाहर गए बिना अन्याय मिटाया नहीं जा सकता ।"**[6] कहने का तात्पर्य है कि सामंती व्यवस्था का तख्ता केवल जनता के क्रांतिकारी तरीकों से ही उल्टा जा सकता था, सुधारवादी तरीकों से नहीं ।

निस्सन्देह लोग अपने संघर्ष में कुछ गलतियाँ भी कर सकते थे । लेकिन सिर्फ इसी कारण से उनकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए ? उन्हें निरुत्साहित नहीं करना चाहिए या इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि उनके संघर्ष के महत्त्व को ही पूर्णतया नकार दिया जाए । यहाँ क्रान्तिकारी नेतृत्व का होना सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात थी । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह जरूरी था कि वह किसानों के आगे-आगे चले तथा उन्हें नेतृत्व प्रदान करे ।

क्रांति शुरू होने के बाद ही पता चलता है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, इससे पहले नहीं । यह नेताओं का कर्तव्य है कि वे जनता के सही, रचनात्मक विचारों में अपनी आस्था रखें, उनके क्रांतिकारी अनुभवों का सार प्रस्तुत करें तथा उन्हें विजय के सही रास्ते पर ले जाएं ।

यह सच है कि निचले स्तर की किसान सभाओं के कुछ नेताओं में, जिन पर शरीफजादों ने "अवारागर्द" का ठप्पा लगा दिया था, थोड़ी-बहुत गलत आदतें तथा कमियां भी थीं, क्योंकि उनका पालन-पोषण भी पुराने समाज में ही हुआ था । परन्तु जब क्रान्तिकारी तूफान के समय सत्ता उनके हाथों में आई तो उनमें से बहुत से सुधर गए । **"वे खुद जुआ खेलने पर जोरों से पाबंदी लगा रहे हैं और डकैती खत्म कर रहे हैं । जहां किसान सभा मजबूत है, वहां जुआ कतई बंद हो गया है और डकैती का नामोनिशान मिट गया है । यह अक्षरत: सही है कि कुछ स्थानों में लोग सड़कों पर गिरी हुई चीजें अपनी जेब में नहीं डाल लेते और रात को दरवाजे बंद नहीं किये जाते । हङशान के सर्वेक्षण के अनुसार गरीब किसान के नेताओं में से 85 प्रतिशत अब बिल्कुल सुधर गए हैं तथा योग्य और परिश्रमी बन गए हैं ।"**[7] यहां कामरेड माओ त्से-तुङ ने इस सच्चाई को साबित किया कि किसान क्रान्तिकारी चमत्कार करने में सक्षम हैं तथा उनकी शक्ति असीम है । पुराने समाज का कायापलट करते समय उन्होंने स्वयं को भी सुधार लिया था । यह लोगों का एक क्रान्तिकारी सृजन था तथा साथ ही उनका स्वयं का पुनर्निर्माण भी था ।

इस रिपोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में देहाती इलाकों में क्रान्तिकारी सरकार तथा एक किसान सेना की स्थापना करने की जरूरत पर बल दिया । इसने स्पष्ट किया कि क्रान्ति एक हिंसात्मक कार्यवाही थी, जिसके द्वारा शोषित वर्ग, शोषक वर्ग की सत्ता का तख्ता उलट देता है । हुनान के देहाती इलाकों में क्रान्ति एक ऐसी ही कार्यवाही थी जिसके द्वारा किसानों ने जमींदारों की सत्ता को उखाड़ फेंका था तथा एक क्रान्तिकारी सत्ता की स्थापना की थी । किसान सभा सत्ता का एकमात्र प्रतीक बन गई थी । **"सारी सत्ता किसान सभा के हाथ में हो"** का नारा हुनान

के एक करोड़ क्रान्तिकारी किसानों का नारा था । किसान सभा ने, जिसकी सत्ता सर्वोच्च है, जमींदारों की धाक खत्म कर दी तथा अपने कायदे-कानून लागू किये । पुराने समाज में जिन लोगों की कोई औकात न थी, वे अब उठ खड़े हुए थे तथा उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी ।

क्रांतिकारी सरकार का मुख्य आधारस्तंभ उसकी क्रांतिकारी सशस्त्र सेनाएँ थीं तथा उन्होंने ही किसानों को अपने हितों की रक्षा करने, तथा सभी प्रतिक्रियावादी विद्रोहों को कुचलने में सक्षम बनाया । हुनान में उस समय दो तरह की किसान सशस्त्र सेनाएं थीं : पहली, जमींदारों की पुनर्गठित सशस्त्र सेनाएं थीं तथा दूसरी स्वयं किसानों द्वारा गठित बल्लम दल थे । बल्लम दल जमींदारों की पुनर्गठित सेनाओं से ज्यादा शक्तिशाली थे । उनकी संख्या भिन्न-भिन्न काउंटियों में 30,000 से 80,000 तक थी । कामरेड माओ ने हुनान के क्रान्तिकारी अधिकारियों को स्मरण कराया कि इस प्रकार की सैन्य-शक्ति सारे प्रांत में स्थापित की जानी चाहिए तथा हर किसान को चाहे वह नौजवान हो या प्रौढ़, एक बल्लम से लैस किया जाना चाहिये, ताकि क्रांति की सम्पूर्ण विजय के लिए सशस्त्र सेनाओं को और ज्यादा मजबूत किया जा सके ।

जनता को लामबन्द करते समय यह जरूरी है कि फरमानशाही तथा दुमछल्लावाद, दोनों का विरोध किया जाए, क्योंकि दोनों ही जनता से अलगाव को प्रकट करते हैं। फरमानशाही का अर्थ है जनता की राजनीतिक चेतना से परे हटकर, यानि कि उससे आगे बढ़कर काम करना, स्वेच्छा के सिद्धांत का उल्लंघन करना तथा जनता की सही गतिविधियों में विश्वास न रखना । दुमछल्लावाद का अर्थ है जनता की राजनीतिक चेतना से बहुत पीछे रह जाना, उन्हें एक कदम आगे ले जाने के सिद्धांत का उल्लंघन करना, उनकी इच्छाओं तथा अनुभवों को एकत्र कर उन्हें विजय के मार्ग पर ले जाने में असफल रहना ।

कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषताओं में से एक, उसका जनता के साथ गहरे रूप से जुड़े होना है, और यही विशेषता उसे अन्य राजनीतिक पार्टियों से एक अलग पहचान प्रदान करती है । इस विशेषता का विस्तृत ब्यौरा **'किसान क्रान्ति के चीनी सर्वहारा नेतृत्व'** पर कामरेड माओ के विचारों में दिया गया है । उन्होंने इस बात का वैज्ञानिक ढंग से आकलन किया कि कृषि क्रांति, चीनी पूँजीवादी-जनवादी क्रांति का मुख्य अंश थी तथा किसान इसकी बुनियादी शक्ति थे । इस प्रकार उन्होंने, किसानों को निडरतापूर्वक लामबन्द करके ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना करने व उनकी सेना बनाने के बुनियादी उसूल को सूत्रबद्ध किया । किसान क्रान्ति के प्रश्न को लेकर नव-जनवादी क्रांति के विचार का यह एक साकार रूप था ।

"हुनान के किसान आंदोलन की जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट" एक बेहद महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है । अपनी बेजोड़ क्रांतिकारी तथा वैज्ञानिक सोच से कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि चीनी क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि श्रमिक वर्ग किसानों को नेतृत्व प्रदान कर सकता था या नहीं । इस प्रकार किसान समुदाय पर चीनी सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व को लेकर यह रचना एक शानदार ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुकी है । ●

को लागू करने, क्रान्ति का विस्तार करने तथा इसे और गहराई से चलाने का हर संभव प्रयास किया ।

मजदूर-किसान जन-आंदोलन का विकास जारी रहा तथा खासकर हुनान व हुपे में किसान आंदोलन अपने उभार पर था ।

पाँचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कम्युनिस्ट पार्टी के 57,900 से अधिक सदस्य थे, जबकि चौथी कांग्रेस के समय इसकी सदस्य संख्या केवल 900 से कुछ ही अधिक थी । पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार, अपनी सदस्यता से भी ज्यादा तेजी से तथा बड़े पैमाने पर किया था और अब लगभग 28 लाख मजदूर तथा 90 लाख किसान सीधे इसके नेतृत्व में थे।

श्रमिक वर्ग-आंदोलन की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार थीं : राजनीतिक क्षेत्र में सभा करने, संगठन बनाने तथा हड़ताल करने की आजादी के संघर्ष से आगे बढ़कर, अब वह सरकार में भागेदारी की माँग कर रहा था, आर्थिक क्षेत्र में रहन-सहन के हालात में सुधार तथा सामूहिक सौदाकारी के संघर्ष से आगे बढ़कर, अब वह सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन में भी हिस्सेदारी माँग रहा था, तथा संगठनात्मक क्षेत्र में बिखरे हुए शिल्प संघों को धीरे-धीरे औद्योगिक संगठनों का रूप दे कर श्रमिक संगठनों की ताकत का केन्द्रीकरण कर रहा था तथा हर इलाके में सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न जनरल ट्रेड यूनियनों की स्थापना कर रहा था ।

क्रांतिकारी सरकार के नेतृत्व में हुनान, हुपे तथा च्याङशी में किसान आंदोलन झंझावात की तरह उठ खड़े हुए ।

जून 1927 में सारे देश में किसान सभाओं के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 91 लाख 50 हजार के करीब थी । 45 लाख 10 हजार सदस्यों के रहते हुनान पहले नंबर पर था तथा 25 लाख सदस्य संख्या वाला हुपे दूसरे नंबर पर था ।

हुनान के देहात में तो एक क्रांतिकारी तूफान आ गया था । किसानों ने अनाज क नियन्त्रण तथा बंटवारा अपने हाथ में ले लिया था, जमींदारों की सत्ता को चकनाचूर कर दिय था, तथा कृषि-समस्या के हल के रूप में, पहले उन्होंने जमीन की नपाई की तथा उसके आधार पर लगान निश्चित किया, उसके बाद जमीन की निशानदेही करके जोतने के अधिकार को नए सिरे से निर्दिष्ट किया तथा अंत में जमींदारों के स्वामित्व वाली ज़मीन को ज़ब्त करके उसका पुनः बटंवारा कर दिया ।

उत्तरी अभियान सेना द्वारा ऊहान पर कब्ज़ा करने के बाद, हुपे में किसान आन्दोलन क बहुत ज्यादा विस्तार हुआ । मार्च, 1927 में पहली प्रान्तीय किसान कांग्रेस आयोजित की गई जिसके बाद किसानों ने देहात में भीषण वर्ग-संघर्ष छेड़ दिया । किसान सभा ने क्रान्तिकारी किसान शासन-व्यवस्था का रूप ले लिया, अपने आत्मरक्षा-दस्ते गठित किये तथा लगान व सूद में कटौती के पश्चात ज़मीन के पुनः बंटवारे की माँग की ।

फरवरी 1927 में च्याङशी में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के बाद किसानों ने वहाँ जमींदारों की सत्ता उलटने तथा लगान व सूद में कटौती के लिए संघर्ष किया । क्योंकि च्याङशी काफी समय से च्याङ काई-शेक के शासन के अधीन थी तथा उसकी सरकार दो बार क्वोमिंताङ के वामपक्ष तथा दक्षिणपक्ष के हाथों में रही थी, अतः वहां पर किसान आंदोलन अभी शुरू ही हो रहा था ।

किसान आंदोलन सबसे पहले क्वाङतुङ में विकसित हुआ, जहाँ किसान काफी समय से

3.

- **चीनी क्रांति में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप में बढ़ोतरी ।**
- **ऊहान तथा च्योच्याङ में ब्रिटिशों द्वारा पट्टे पर लिये गए क्षेत्रों की वापसी के लिए मज़दूरों का आंदोलन ।**
- **शंघाई के श्रमिकों की तीन बगावतें ।**
- **नानकिङ पर कब्जा तथा ब्रिटिश-अमरीकी बमबारी की घटना ।**
- **12 अप्रैल 1927 का च्याङ काई-शेक का प्रति-क्रांतिकारी राजविप्लव ।**

उत्तरी अभियान सेना के विजयी अभियान तथा श्रमिकों व किसानों के क्रांतिकारी उभार से भयभीत होकर साम्राज्यवादियों ने चीनी क्रांति में अपना हस्तक्षेप और ज्यादा तेज कर दिया।

यह हस्तक्षेप दो किस्म का था : नृशंसतापूर्वक नरसंहार करके चीनी जनता के संघर्ष को कुचलना, तथा विजयी क्रांतिकारी आन्दोलन का विरोध करने के लिए प्रति-क्रांतिकारी शक्तियों की सहायता करना ।

उत्तरी युद्ध-सरदारों—ऊ फेइ-फू, सुन छ्वान-फाङ, चाङ च्वो-लिन तथा चाङ छुङ-छाङ ने जिस तरह से एकजुट होकर क्रान्ति का विरोध किया; ब्रिटिश, जापानी तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के वित्तीय, फौजी तथा नैतिक समर्थन के अभाव में वे ऐसा करने के लिए कभी इकट्ठे न हुए होते । साम्राज्यवादियों की ओर से यह एक शर्मनाक हस्तक्षेप था । चीनी क्रांति ने, जिसका उद्देश्य इन युद्ध-सरदारों का सफाया करना था, साम्राज्यवादियों की इस हस्तक्षेप नीति पर भी चोट की ।

जब क्वाङतुङ की क्रांतिकारी सेना याङत्सी घाटी की ओर बढ़ रही थी, साम्राज्यवादियों को लगा कि क्रांति को कुचलने के लिए उन्हें उत्तरी युद्ध-सरदारों से भी ज़्यादा असरदार "औजारों" की जरूरत थी । इसलिए वे, इससे भी ज्यादा ओछे हथकंडों पर उतर आए, उन्होंने क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे में ही अपने मित्रों की तलाश शुरू कर दी । उनकी उम्मीदें क्रान्तिकारी पाँतों में छिपे बैठे प्रतिक्रियावादियों के साथ सांठगांठ करके काम करने पर टिकी थीं, ताकि संयुक्त मोर्चे को तोड़कर क्रान्ति को अन्दर ही अन्दर से ध्वस्त किया जा सके ।

3 जनवरी, 1927 को ऊहान सरकार ने राष्ट्रीय सरकार के उत्तर में स्थानान्तरण तथा उत्तरी अभियान की विजय के उपलक्ष्य में हानखओ में एक जनसभा का आयोजन किया । हानखओ में ब्रिटिशों को पट्टे पर दी गई बस्ती की सीमा पर एक प्रचारक भाषण दे रहा था कि ब्रिटिश नौसैनिकों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिये भेजा गया । सैनिकों ने श्रोताओं पर संगीनों से हमला करके बहुतों को घायल कर दिया तथा कइयों को जान से मार दिया । चीनी सरकार से ब्रिटिश सरकार को इस बारे में कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए अनुरोध करने हेतु, हानखओ की जनता ने 5 जनवरी को एक विशाल प्रदर्शन किया तथा ब्रिटिशों के पट्टे वाले इलाके पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश अधिकारियों को वह क्षेत्र चीनी सरकार को लौटा देने के लिए मज़बूर कर दिया । 6 जनवरी को जब ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ चीनी श्रमिकों को च्योच्याङ में गोली से उड़ा दिया, स्थानीय जनता ने वहाँ के ब्रिटिशों को दिये गए पट्टे वाले इलाके को भी कब्जे में ले लिया, तथा बाद में उसे भी चीनी सरकार को सौंप दिया गया ।

15 अप्रैल, 1927 को, क्वाङतुङ में क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादियों ने अनेक कम्युनिस्टों तथा प्रगतिशील श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया तथा मार डाला, ह्वाङफू फौजी अकादमी तथा कैंटन-हांगकांग हड़ताल कमेटी की निगरानी टुकड़ियों को निरस्त्र कर दिया, तथा ट्रेड यूनियनों व किसान सभाओं जैसे क्रान्तिकारी जन-संगठनों की तलाशी ली । क्वाङतुङ में प्रति-क्रान्तिकारी राज-विप्लव के दौरान, 2100 से अधिक कम्युनिस्ट तथा सक्रिय मजदूर मारे गए, 100 से भी ज्यादा की गुप्त रूप से हत्या कर दी गई तथा 2000 से अधिक रेल-मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा । 19 तथा 23 जून को श्रमिकों ने बहादुरीपूर्वक आम हड़ताल पर दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कुचल दिया गया ।

च्याङ काई-शेक के विश्वासघात के कारण, क्रान्ति को आंशिक विफलता का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर, क्रान्ति अपने रास्ते पर विकास की नई मंजिलों की ओर लगातार आगे बढ़ती रही । ●

4.

- **ऊहान की क्रान्तिकारी सरकार के काल में मजदूरों तथा किसानों का बढ़ता जन-आंदोलन ।**
- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पाँचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस ।**

12 अप्रैल, 1927 की घटना, प्रतिक्रियावादी च्याङ काई-शेक गुट द्वारा क्रांति पर एक खुल्लमखुल्ला प्रति-क्रांतिकारी हमला था । इस घटना के बाद दक्षिणी चीन में दो शिविर बन गए : **क्रांतिकारी शिविर** जिसका केन्द्र **ऊहान** था, एवं **प्रति-क्रांतिकारी शिविर,** जिसका केन्द्र **नानकिङ** था ।

साम्राज्यवादियों की हस्तक्षेप की नीति के कारण ऊहान की क्रांतिकारी सरकार को शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा था । इसके पूर्व में च्याङ काई-शेक, पश्चिम में सछ्वान युद्ध-सरदार याङ सेन, उत्तर में फङथ्येन युद्ध-सरदार चाङ च्वो-लिन तथा दक्षिण में क्वाङतुङ का युद्ध-सरदार मौजूद थे । चूंकि क्रान्तिकारी सेनाएं एक ही वक्त में चारों मोर्चों पर हमला करने की स्थिति में न थीं, इसलिए ऊहान सरकार ने एक फ़ौरी रक्षात्मक कार्यवाही के रूप में चाङ च्वो-लिन की सेनाओं के खिलाफ अपने उत्तर की ओर बढ़ने के अभियान को जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उसकी सेनाएं ऊहान पर कब्जा करने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ रही थीं । चूंकि ऊहान एक वाणिज्यिक केन्द्र था, अतः उसे आर्थिक अव्यवस्था से बचाने के लिए उसकी घेराबन्दी तोड़नी बेहद जरूरी थी और फङथ्येन गुट की सेनाओं के हमले के खतरे को कम करने या दूर करने के लिए ऊहान सरकार, लुङहाए रेलमार्ग के साथ फैली च्याङ की सेनाओं पर घूमकर आक्रमण करने से पहले, हनान में फङ ग्वी-श्याङ के सैन्य-दलों से मिलना चाहती थी ।

इसलिए स्वयं को फौजी तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, ऊहान सरकार ने सबसे पहले फङ ग्वी-श्याङ के सैन्य-दलों के साथ जुड़ना बेहतर समझा । इसी बीच, च्याङ काई-शेक पर आक्रमण करने के बारे में सोच-विचार करने से पहले, सरकार ने कृषि-क्रान्ति

हानखओ तथा च्योच्याङ में पट्टे वाले क्षेत्रों की वापिसी साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी ।

ऊहान पर कब्जा करने के बाद उत्तरी अभियान सेना सुन छ्वान-फाङ की सेना से टक्कर लेने के लिये च्याङशी, फूच्येन तथा आन्ह्वेइ की ओर बढ़ी । क्रान्तिकारी सेना के इस अभियान के साथ तालमेल स्थापित करते हुए शंघाई के श्रमिकों ने पार्टी के नेतृत्व में तीन बगावतें कीं तथा अनेक वर्षों से साम्राज्यवादी आक्रमण तथा युद्ध-सरदारों के प्रभुत्व का मजबूत गढ़ रहे इस शहर को मुक्त करा लिया ।

थोड़ा पीछे चलते हैं—सशस्त्र बगावत से पहले, 30 मई, 1926 को शंघाई की जनता ने, श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में विशाल पैमाने पर एक साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन का आयोजन किया। इसके बाद शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नेतृत्व में एक विशाल हड़ताल हुई । जून से अगस्त तक 2,00,000 श्रमिक हड़ताल पर चले गए, यहां तक कि सितम्बर में भी 30 हजार श्रमिक ऐसे थे जो अभी तक संघर्ष में डटे हुए थे । श्रमिकों ने सभा करने तथा संगठन बनाने की आजादी, न्यूनतम वेतन, छोटे कार्य-दिवस, काम-काज के हालात में सुधार वगैरा के लिए हड़ताल की । पूँजीपतियों ने अपनी फैक्ट्रियों तथा वर्कशापों में तालाबन्दी करके जवाबी कार्यवाही की तथा युद्ध-सरदार सरकार को शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कर लिया । जिन श्रमिकों ने हड़ताल में हिस्सा ही नहीं लिया था, उन्हें भी बिना किसी कारण के या तो बर्खास्त कर दिया गया, या फिर उनके वेतन बहुत ज्यादा घटा दिये गए । उन्होंने श्रमिकों को परेशान करने के लिए भाड़े के शरारती तत्वों का भी सहारा लिया। लेकिन इस सबके बावजूद भी शंघाई में हड़तालें नहीं रुकीं । अगस्त माह के उत्तरार्द्ध से हड़ताल का निशाना जापानी साम्राज्यवादियों को बनाया गया, जिन्होंने चीनी श्रमिकों का नरसंहार किया था । शंघाई सूती-कपड़ा उद्योग संघ (Shanghai Textile Union Federation) द्वारा की गई हड़ताल ने श्रमिकों की जुझारू इच्छाशक्ति को और ज्यादा दृढ़ता प्रदान की तथा उनकी संगठित शक्ति में और ज्यादा वृद्धि हुई ।

अक्तूबर 1926 में उत्तरी अभियान सेना द्वारा ऊछाङ पर कब्जा करने से ऊ फेइ-फू का आखिरी आधार भी उससे छिन गया । इसके बाद अभियान सेना की मुख्य सैन्य-शक्ति च्याङशी की ओर बढ़ी, जहाँ उसका सामना सुन छ्वान-फाङ के मुख्य सैन्य-बल से हुआ । इसी दौरान चच्याङ में सुन का एक सिपहसालार श्या-चाओ, जिसका झुकाव क्रान्ति की ओर था, हाङचओ में सुन की सरेआम खिलाफत करते हुए क्रान्ति की तरफ आ मिला तथा शंघाई के उपनगरीय क्षेत्रों पर चढ़ाई कर दी । उधर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, शंघाई के श्रमिकों ने 23 अक्तूबर, 1926 को पहला सशस्त्र विद्रोह किया । विद्रोह से पहले, उन्होंने 1130 श्रमिकों की एक लड़ाका यूनिट का गठन किया, जिसमें केवल 130 लोग हथियारबंद थे । जबकि शत्रु के पास शहर में 3000 पैदल सेना तथा पुलिस के सिपाही थे तथा एक ब्रिगेड शंघाई के समीप याङत्सी नदी के किनारे पर तैनात थी । अपर्याप्त तैयारी तथा श्या-चाओ की पराजय के कारण विद्रोह का अंत असफलता में हुआ ।

उत्तरी अभियान सेना द्वारा हाङचओ तथा च्याशिङ पर कब्ज़े के बाद, पार्टी ने अभियान की प्रगति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, दूसरा सशस्त्र विद्रोह करने का निर्णय लिया। 19 फरवरी, 1927 को शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आम हड़ताल का आह्वान किया तथा

और कुछ नहीं, बल्कि *''श्रमिकों की अन्दरूनी फूट के कारण था''* तथा दावा किया कि इसीलिए टुकड़ियों को निरस्त्र करना पड़ा । इसी दौरान, सभी हड़तालों पर पाबन्दी लगा दी गई, क्योंकि उन्हें डर था कि निरस्त्र की गई टुकड़ियों के समर्थन में कहीं श्रमिक हड़ताल पर न चले जाएं ।

शंघाई के श्रमिकों ने, च्याङ काई-शेक द्वारा टुकड़ियों को निरस्त्र करने के विरुद्ध साहसपूर्वक जवाबी कार्यवाही की । 12 अप्रैल की दोपहर को उन्होंने ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कार्यालय पर दोबारा कब्जा कर लिया । उसके तुरंत बाद ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने उसी दिन से सारे शहर में आम हड़ताल का आह्वान किया । श्वेत आतंक के बावजूद, हड़ताल में 2 लाख से भी अधिक मजदूरों ने भाग लिया ।

शंघाई के मजदूरों तथा नागरिकों ने सभी जगह प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध अपना कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए, जन-सभाएं की । नानश में एक जनसभा करने के बाद लगभग पाँच लाख लोग पाए छुङ-शी को एक आवेदन-पत्र देने के लिए लुङह्वा स्थित उत्तरी अभियान सेना के कमान मुख्यालय तक गए तथा उसे कुछ शर्तें मानने के लिए मजबूर करने में सफल हो गए ।

13 तारीख को ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने चाफेइ में एक जनसभा आयोजित की, जिसके बाद लोग उत्तरी अभियान सेना की एक डिवीजन के कमाण्डर चओ फङ-ची के दफ्तर में एक आवेदन-पत्र देने के लिए गए । रास्ते में पाओशान नामक स्थान पर, प्रतिक्रियावादी सैनिकों ने उन पर हमला करके 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी तथा असंख्य लोगों को घायल कर दिया ।

इस विशाल नरसंहार के बाद, च्याङ काई-शेक ने ट्रेड यूनियन फेडरेशन को भंग करने का आदेश जारी कर दिया, तथा मजदूर संगठनों की संघबद्ध शंघाई संस्था (बाद में जिसका पुनर्नामकरण *'यूनियन संगठनों की शंघाई संयुक्त कमेटी'* कर दिया गया) में मौजूद गुंडे-बदमाशों को शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन के दफ्तर पर कब्ज़ा करने, यूनियन के सभी संगठनों को बन्द करने तथा मजदूरों के नेताओं का कत्लेआम करने के लिए भड़काया । तब एक के बाद एक, सभी क्रांतिकारी संस्थाओं तथा संस्थानों को बन्द कर दिया गया । तब से शंघाई के श्रमिकों तथा क्रान्तिकारियों की हर प्रकार की आजादी छीन ली गई । सभाएँ करने या हड़ताल पर जाने वालों को मौत की सजा दी जाती । ऐसे हालातों में, यदि श्रमिक अपनी इस अलग-थलग स्थिति में भी आम हड़ताल जारी रखते तो वे अपनी जानें व्यर्थ में ही कुर्बान करते, इसलिए श्रमिकों की शक्ति बचाए रखने के लिए ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने 14 तारीख की शाम को, काम पर वापिस लौटने का आदेश जारी कर दिया ।

यद्यपि शंघाई में श्रमिक-वर्ग आन्दोलन को जबरदस्त धक्का लगा तथा आम हड़ताल को मजबूरी में वापिस लेना पड़ा, परन्तु शंघाई के श्रमिकों ने हार नहीं मानी । कड़े श्वेत आतंक के दौरान भी जनरल ट्रेड यूनियन ने भूमिगत गतिविधियाँ जारी रखीं, तथा शंघाई के श्रमिकों का, प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध संघर्ष में नेतृत्व किया ।

च्याङ काई-शेक के विश्वासघात ने दक्षिण-पूर्वी प्रान्तों तथा क्वाङतुङ में आतंक का राज कायम कर दिया, तथा वहां पर काफी बड़ी तादाद में कम्युनिस्टों तथा शानदार क्रान्तिकारी वीरों की च्याङ काई-शेक के गुंडे-बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई ।

कम्युनिस्ट-विरोधी संयुक्त कांफ्रेन्स का आयोजन किया तथा कम्युनिस्ट पार्टी व शंघाई के हथियारबंद श्रमिकों का दमन करने तथा ऊहान स्थित क्वोमिंताङ मुख्यालय के आदेशों का पालन करने से इंकार करने संबंधी कुछ समझौते किये गए । इसके तुरन्त बाद च्याङ काई-शेक ने शंघाई के गुंडे-बदमाशों को इकट्ठा किया तथा शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन के खिलाफ, *'इकट्ठे मिलकर चलने वाली चीनी सभा'* (China March Together Society) व *'मजदूर संगठनों की संघबद्ध शंघाई संस्था'* (Shanghai Federated Association of Labour Unions) नामक संस्थाओं का गठन किया । प्रतिक्रियावादी सैनिकों को शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन तथा श्रमिकों की निगरानी टुकड़ियों पर निगाह रखने के लिए चाफेइ भेजा गया । श्रमिकों की सभाओं, हड़तालों तथा परेडों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, पाए छुङ-शी तथा चओ फङ-ची जैसे खूंखार प्रतिक्रियावादियों के नेतृत्व में शंघाई-वूसुङ मार्शल-लॉ मुख्यालय की स्थापना की गई ।

इसके साथ-साथ च्याङ काई-शेक ने अपनी प्रतिक्रान्तिकारी दुरंगी चालें जारी रखीं । यद्यपि वह श्रमिक टुकड़ियों को निश्चित तौर पर अपने रास्ते के कांटे के रूप में देखता था, फिर भी उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया । उलटे उसने श्रमिक-टुकड़ियों को एक रेशमी झण्डा भी प्रदान किया, जिस पर *"हमारे साझे संघर्ष को"* अंकित था । इसका उद्देश्य क्रान्तिकारियों द्वारा, क्रान्ति पर हमले की संभावना के विरुद्ध, (जिसकी वह योजना बना रहा था) की जा रही चौकसी को ढीला करना था । इसके इलावा छन तू-श्यू के अवसरवादी रुझानों का लाभ उठाते हुए उसने शंघाई की जनप्रिय नगर सरकार की स्थापना पर रोक लगा दी (जिसकी स्थापना 29 मार्च, 1927 को होनी थी) तथा पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों को इस्तीफा देने के लिए भड़काया । फलतः जन-सरकार स्थापित करने की योजना को त्याग दिया गया। दूसरी ओर, सरकार के समर्थन में जनता को लामबन्द करने की बजाय, छन तू-श्यू ने सर्वहारा सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी, तथा पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों की कृपादृष्टि अर्जित करने के लिए उन की ओर झुक गया क्योंकि उसे डर था कि उनके बिना सरकार कामकाज नहीं कर पाएगी । छन तू-श्यू की कमजोरी तथा अक्षमता से उत्साहित होकर च्याङ काई-शेक ने अपने पिट्ठुओं को "शंघाई की अंतरिम राजनीतिक समिति" गठित करने का आदेश दिया तथा इस प्रकार उसने शंघाई की राजनीतिक सत्ता को हड़प लिया । 5 अप्रैल, 1927 को छन तू-श्यू तथा वाङ चिङ-वेइ द्वारा एक तथाकथित "संयुक्त वक्तव्य" जारी किया गया, जिसमें प्रति-क्रांतिकारी षड्यन्त्र की निन्दा में एक भी शब्द नहीं था । इसके विपरीत, इसने च्याङ काई-शेक की कातिलाना योजनाओं के लिए एक प्रकार के पर्दे का काम किया ।

अपने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र की तैयारियाँ पूरी करने के बाद, च्याङ काई-शेक 9 अप्रैल को शंघाई से नानकिङ के लिए रवाना हो गया । 12 अप्रैल, 1927 को भोर से पहले ही च्याङ काई-शेक ने चाफेइ, वूसुङ, फूतुङ तथा नानश में स्थित सभी श्रमिक टुकड़ियों के कत्लेआम का आदेश दे दिया । पूरी तरह लैस गुंडे, बदमाश तथा प्रति-क्रांतिकारी सैनिक, एक साथ कार्यवाही में कूद पड़े; गुंडे-बदमाश तो विदेशियों को पट्टों पर दिये गए इलाकों से दौड़ते हुए आए और श्रमिकों पर टूट पड़े और प्रति-क्रांतिकारी सैनिकों ने सहायता करने के बहाने या फिर जबरदस्ती श्रमिकों के हथियार छीन लिये । श्रमिक टुकड़ियों को निहत्था करने के बाद जल्लाद पाए छुङ-शी ने बड़ी ही निर्लज्जता से आरोप लगाया कि श्रमिकों पर गुंडे-बदमाशों का हमला

अपनी माँगों की घोषणा की । पहले दिन डेढ़ लाख श्रमिक हड़ताल पर चले गए, दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 2,70,000 हो गई, तीसरे दिन 3,50,000 तक पहुँच गई तथा चौथे दिन यह संख्या 3,60,000 हो गई । हड़ताल के पहले दिन से ही, युद्ध-सरदार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बस्ती की "शंघाई नगर परिषद" के साथ मिलीभगत करके शहर में श्वेत आतंक बरपा दिया। सशस्त्र विद्रोह, चौथे दिन (22 फरवरी को) शुरू हुआ । श्रमिकों, व्यापारियों, छात्रों तथा कम्युनिस्ट पार्टी व क्वोमिंताङ के प्रतिनिधियों को लेकर—**शंघाई के नागरिकों की क्रान्तिकारी अन्तरिम समिति** का गठन किया गया ।

परन्तु हालात सशस्त्र विद्रोह के प्रतिकूल थे । पहला, प्रतिक्रियावादी पाए छुङ-शी की कमान वाली उत्तरी अभियान सेना की यूनिटों ने शंघाई पर अपना आक्रमण रोक दिया था तथा श्रमिकों को सुन की फौजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था, यह सोचते हुए कि वे एक-दूसरे से लड़कर कट मरेंगे । दूसरे, पार्टी ने युद्ध-सरदारों की सशस्त्र सेनाओं (अनिश्चय के अधर में लटकी नौ सेना तथा ली पाओ-चाङ की सेना) तथा मध्यवर्ती वर्गों में न के बराबर काम किया था । वास्तव में शत्रु को अन्दर से ही छिन्न-भिन्न करने के लिए इन सेनाओं को अपनी तरफ मिलाया जा सकता था । पार्टी ने कार्यवाही करने के लिए जन साधारण का आह्वान नहीं किया । इसने निम्न-पूँजीपति वर्ग की अवहेलना की तथा केवल न्यू युङ-च्येन तथा च्वी श्या-चिङ जैसे बड़े पूँजीपतियों पर ही निर्भर रही । 23 फरवरी को ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने घोषणा की कि अगले दिन एक बजे दोपहर बाद हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी । दूसरे विद्रोह का अंत भी असफलता में हुआ ।

फिर बेहद साहस तथा दृढ़ता के साथ पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर **तीसरे विद्रोह** की तैयारी की । इसने श्रमिक संगठनों तथा शहर की गरीब जनता और निम्न-पूँजीपति वर्ग के बीच

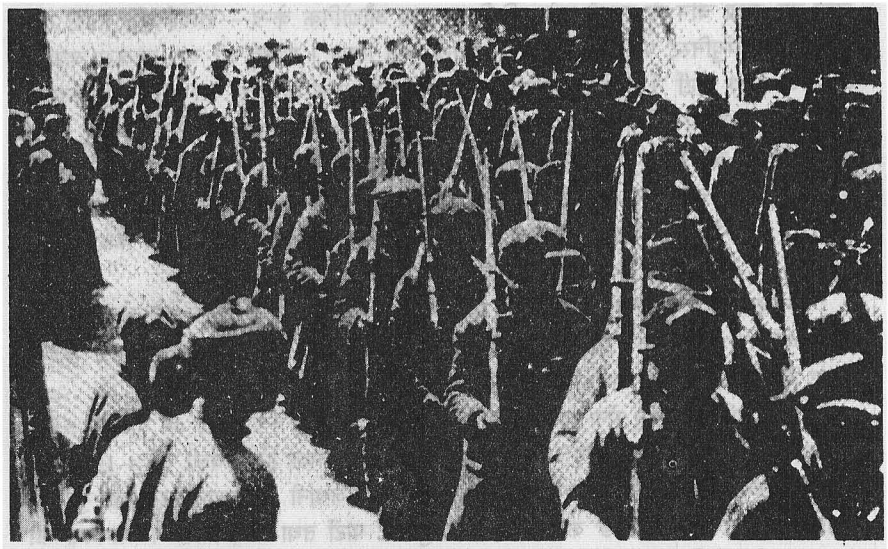

शंघाई के तीसरे सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने वाले श्रमिकों का दस्ता

बहुत ज्यादा राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्य किया । मजदूरों में **'जनवादी सरकार स्थापित करने'** के नारे का प्रचार किया गया । निम्न-पूँजीपति वर्ग को मजदूर वर्ग के साथ ठोस संश्रय कायम करने के लिये प्रोत्साहित किया गया तथा बड़े पूँजीपतियों से सम्पर्क बना कर रखते हुए पार्टी ने उन्हें जनता की इच्छा के आगे झुकने तथा समझौते की नीति त्यागने को बाध्य किया।

21 मार्च, 1927 को जब उत्तरी अभियान सेना ने शंघाई के नज़दीक लुङह्वा पर आक्रमण किया, शंघाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आम हड़ताल का एक और आह्वान किया, जिसमें 8,00,000 मजदूरों ने भाग लिया । पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह निम्नलिखित सात जिलों में शुरू हुआ : नानश, हाङक्यू, फूतुङ, वूसुङ, पूर्वी शंघाई, पश्चिमी शंघाई तथा चापेइ में विद्रोह के शुरू होते ही मज़दूरों ने रेलमार्गों, विद्युत एवं जल-आपूर्ति को काट दिया, तथा पुलिस मुख्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज एवं तारघर पर कब्जा कर लिया । सारे शंघाई में गोलियों की आवाजें तथा जनता के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे । निहत्थी जनता ने अब शत्रु से हथियार छीन लिये थे । 21 मार्च, यानि कि उसी दिन दोपहर ढलने तक चापेइ को छोड़कर बाकी सभी जिलों पर कब्ज़ा कर लिया गया । चापेइ की लड़ाई सबसे ज्यादा भयंकर थी, तथा दो दिन व एक रात तक चली । 22 तारीख को शाम के छः बजे जाकर जीत हासिल हुई । श्वेत रूसी तथा ब्रिटिश बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हपे-शानतुङ युद्ध-सरदारों की सेनाओं के साथ कन्धे से कन्धे मिलाकर लड़ाई में भाग लेती देखी गईं । विभिन्न पुलिस दफ्तरों पर कब्ज़े के बाद, मज़दूरों तथा जनता ने थ्येनथुंगार रेलवे स्टेशन तथा कमर्शियल प्रैस क्लब पर कब्ज़ा कर लिया। अन्तिम लड़ाई उत्तरी स्टेशन पर कब्ज़े को लेकर हुई । श्रमिकों की सशस्त्र सेना के बहादुराना हमले तथा युद्ध में जनता की व्यापक भागेदारी के फलस्वरूप स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया तथा प्रतिक्रियावादी सेनाओं को हार का मुँह देखना पड़ा । इस प्रकार तीसरे विद्रोह ने विजयश्री प्राप्त की, तथा चीन के सबसे बड़े वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र—शंघाई को, जनता तथा श्रमिकों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में स्वतन्त्र करा लिया । शंघाई की जन-सरकार चयनित करने के लिए पार्टी ने तत्काल शंघाई के नागरिकों की एक जनसभा का आयोजन किया ।

उत्तरी अभियान सेना की छठी सेना, दूसरी सेना तथा अन्य इकाइयों ने 24 मार्च, 1927 को नानकिङ को मुक्त करा लिया । उसी रात बरतानवी, अमरीकी, जापानी तथा फ्रांसीसी युद्धपोतों ने नानकिङ पर बमबारी की तथा 2000 से अधिक सैनिकों एवं नागरिकों को मार डाला या ज़ख्मी कर दिया । साम्राज्यवादियों का उद्देश्य था कि चीनी जनता को तोपों से भयभीत कर दिया जाए तथा क्रांति के दिल पर गहरी चोट की जाए ।

नानकिङ की घटना चीनी क्रांति में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के बढ़ जाने की चेतावनी थी। इसके कुछ ही समय बाद इन साम्राज्यवादियों के सहयोग से च्याङ काई-शेक ने 12 अप्रैल, 1927 को प्रतिक्रांतिकारी राज-विप्लव कर दिया ।

जब उत्तरी अभियान सेना याङत्सी घाटी में प्रवेश कर गई, क्वोमिंताङ के दक्षिणपक्ष की प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधियां और अधिक स्पष्ट तथा लज्जाजनक होती चली गई । 1926 की सर्दियों में च्याङ काई-शेक के नानछाङ पहुँचने पर, राजधानी के स्थानान्तरण के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया । च्याङ काई-शेक ने कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वामपक्ष की इस सलाह का विरोध किया कि राजधानी ऊहान में स्थानांतरित कर दी जाए, क्योंकि वह क्रांति के केन्द्र ऊहान के मुकाबले में नानछाङ को अपनी प्रति-क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र

बनाए हुए था । तथापि नवम्बर 1926 में क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति ने राजधानी स्थानांतरित करने का फैसला ले लिया, तथा राष्ट्रीय सरकार के साथ वह तत्काल ऊहान आ गई । 1927 के मार्च माह में हानखओ में क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति का पूर्ण अधिवेशन बुलाया गया । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के वामपक्ष के सक्रिय सहयोग से पार्टी के अधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने, जनवाद को बढ़ावा देने तथा तानाशाही शासन-व्यवस्था को खत्म करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये । च्याङ काई-शेक को केन्द्रीय कार्यकारी समिति तथा फौजी कमीशन, दोनों की अध्यक्षता से हटा दिया गया । अधिवेशन क्रान्तिकारी गुट की उसके विरोधियों पर विजय के साथ समाप्त हुआ । अधिवेशन के बाद च्याङ काई-शेक पूरे जोर से विश्वासघात करने की तैयारी में जुट गया तथा सक्रियतापूर्वक अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाने लगा । उसने फूच्येन, चच्याङ, च्याङशी तथा आनह्वेइ की लड़ाइयों में क्रान्ति की तरफ आ जाने वाली युद्ध-सरदारों की सेनाओं के सैनिकों को भारी मात्रा में अपनी सेना में भरना शुरू कर दिया । उसने साम्राज्यवादियों को मदद के लिए अपील की तथा ताए ची-थाओ के माध्यम से जापानी साम्राज्यवादियों, वाङ चङ-तिङ के माध्यम से ब्रिटिश, टी.वी.सुङ के माध्यम से अमरीकी तथा ली श-छङ व ऊ च-ह्वेइ के माध्यम से फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों से सांठगांठ की । उधर जापानी, अमरीकी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी भी शंघाई के एक बड़े दलाल-पूँजीपति च्वी श्या-चिङ के माध्यम से च्याङ काई-शेक के साथ प्रति-क्रान्ति करने के लिए बातचीत करना चाहते थे । साम्राज्यवादियों की शह पर ह्वाङ फू तथा छाङ-छुन जैसे कई नौकरशाह तथा राजनेता च्याङ के समर्थन में इकट्ठे हो गए तथा उसे उसकी प्रति-क्रान्तिकारी गतिविधियों में मदद देने लगे । उस समय 30,000 से भी अधिक ब्रिटिश, जापानी, अमरीकी तथा फ्रांसीसी सैनिक शंघाई में जमा थे तथा और सैन्य-दल भी लगातार च्याङ की मदद के लिए आ रहे थे । साम्राज्यवादियों से अपने नजदीकी संबंधों के बल पर कूदते हुए च्याङ पहले से कहीं अधिक प्रतिक्रियावादी तथा बर्बर बन गया था । मार्च 1927 में उसने च्याङशी में खानचओ की ट्रेड यूनियन फेडरेशन के प्रधान छन छान-श्येन की हत्या कर दी तथा वहां के मजदूर आंदोलन को कुचल डाला । फिर उसने बहुत से श्रमिकों की हत्या करके व अनेकों को घायल करके च्योच्याङ की ट्रेड यूनियन फेडरेशन को भंग कर दिया । आनकिङ में उसने आन्ह्वेइ प्रान्त की एक नकली ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की, जिसने एक दंगे में असली प्रान्तीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मुख्यालय तथा क्वोमिंताङ वामपक्ष के प्रान्तीय पार्टी मुख्यालय को तहस-नहस कर दिया । जब शंघाई को श्रमिकों ने मुक्त करा लिया, च्याङ वहाँ जाकर साम्राज्यवादियों, बड़े दलाल-पूँजीपतियों तथा जमींदारों से मिला तथा उनका सहयोग प्राप्त किया । साम्राज्यवादियों तथा दलाल-पूँजीपतियों की शह पर उसने राज्य-विप्लव की तैयारियाँ शुरू कर दीं ।

शंघाई के इर्द-गिर्द के महत्त्वपूर्ण शहरों से शुरू करते हुए, च्याङ काई-शेक ने नानकिङ तथा हाङचओ पर कब्ज़ा करने के लिए अपने कुछ पिट्ठुओं को भेजा तथा इस प्रकार उसने शंघाई की क्रांतिकारी ताकतों को अलग-थलग कर दिया । 2 अप्रैल, 1927 को क्वोमिंताङ की केन्द्रीय पर्यवेक्षक समिति के तथाकथित पूर्ण अधिवेशन में ऊ च-ह्वेइ ने कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा । यह भावी प्रति-क्रान्तिकारी राज-विप्लव का प्रारंभिक चरण था । इसके बाद च्याङ काई-शेक तथा वाङ चिङ-वेइ के गुटों ने एक

आह्वान किया । इसने एक क्रांतिकारी समिति की स्थापना की, जिसका कर्त्तव्य पहले तो विद्रोह के समय एक नेतृत्वकारी संगठन के कार्य करना था तथा विद्रोह की सफलता के बाद अंतरिम क्रांतिकारी सरकार के रूप में कार्य करना था । इसने श्रमिकों तथा किसानों की एक क्रान्तिकारी सेना का निर्माण करने, बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्य करने तथा सेना में पार्टी प्रतिनिधियों की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया । 7 अगस्त के सम्मेलन की ये उपलब्धियाँ ही इसकी मुख्य विशिष्टताएँ थी ।

पार्टी ने किसानों का आह्वान किया कि वे शरद-फसल की कटाई के समय क्रान्ति को बचाने के लिए बगावतें खड़ी करें ।

हुनान, हुपे, च्याङशी तथा क्वाङतुङ में, जहां क्रान्ति की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत थीं, विद्रोह आरंभ करने का फैसला किया गया । क्योंकि शरद में किसान अपनी फसल काटते थे तथा जमींदार लगान बटोरने आते थे, अतः पार्टी के नेतृत्व में विद्रोह समयानुकूल था ताकि जमींदार, निरंकुश तत्व व बुरे शरीफजादे, चावल का एक दाना भी प्राप्त न कर सकें तथा साथ में उनकी जमीन भी जब्त कर ली जानी थी । इसके बाद मध्य हुनान में श्याङथान व निङश्याङ पूर्वी हुनान में फिङच्याङ, लीलिङ व ल्यूयाङ; पूर्वी हुपे में ह्वाङआन व माछङ; दक्षिणी हुपे में फूची व श्येननिङ तथा पूर्वी क्वाङतुङ में हाएफङ व लूफङ में विद्रोहों की एक शृंखला फूट पड़ी ।

कामरेड माओ को **शरद-फसल विद्रोह** का नेतृत्व करने के लिए हुनान भेजा गया । वहां पर उन्होंने आनय्वान कोयला खान के खनिकों; ऊछाङ की क्वोमिंताङ रक्षक रेजीमेन्ट, जो कि पार्टी के प्रभाव में होने के कारण क्रान्ति की पांतों में आ मिली थी; तथा फिङश्याङ, लीलिङ व ल्यूयाङ के किसान आत्मरक्षा दलों को मिलाकर मजदूरों और किसानों की क्रान्तिकारी सेना का गठन किया । 8 सितंबर को विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन **श्या तओ-इन के बचे-खुचे सैनिकों**[4] की गद्दारी के कारण नुकसान उठाना पड़ा । तब कामरेड माओ अपने सैनिकों को च्याङशी प्रान्त की युङशिन काउंटी के सानवान नामक स्थान पर ले गए । वहां पर नए कमांडर नियुक्त करके, सेना में पार्टी-प्रतिनिधियों की व्यवस्था लागू करके, तथा सेना के सर्वोच्च नेतृत्वकारी संगठन के रूप में पार्टी की मोर्चा समिति की स्थापना करके, उन सैनिकों का **श्रमिकों तथा किसानों की लाल सेना** के रूप में पुनर्गठन किया गया । पुनर्गठन के बाद, सेना ने योजनानुसार हुनान-च्याङशी सीमा पर स्थित चिङकाङ पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर अक्तूबर 1927 में पहला क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित किया गया ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की नरसंहार की नीति का प्रतिरोध करने के लिए 11 दिसंबर 1927 को पार्टी के नेतृत्व में कैंटन के श्रमिकों तथा सैनिकों ने सुविख्यात **'कैंटन विद्रोह'** का आयोजन किया । श्रमिकों के लाल-रक्षक दस्तों के साथ मिलकर फौजी-प्रशिक्षण कोर ने ये च्येन-इङ की कमान में विद्रोह शुरू किया । शुरू में फौजी प्रशिक्षण कोर विद्रोह की मुख्य शक्ति थी, लेकिन शीघ्र ही लगभग 60,000 स्वयंसेवक, श्रमिकों के लाल-रक्षक दस्तों में आ मिले, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई । **'कैंटन कम्यून'** के नाम से श्रमिकों तथा किसानों की एक जनवादी सरकार की स्थापना की गई तथा एक क्रांतिकारी कार्यक्रम का ऐलान किया गया। चूंकि यह विद्रोह एक बड़े शहर में हुआ था, सैनिकों तथा श्रमिकों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । शहर में तैनात क्वोमिंताङ सैनिकों की संख्या क्रांतिकारी सेनाओं से

दिया । अमरीकी व्यापारियों ने तो अपना मिट्टी के तेल का भंडार भी ऊहान से बाहर भेज दिया । ईंधन तथा कच्चे माल की कमी के कारण फैक्ट्रियों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। रोजाना इस्तेमाल के सामान की कमी के कारण कीमतें बहुत बढ़ गईं, और जब अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बन्द हो गई तो शहर में कोहराम मच गया ।

तब, चीनी पूँजीपतियों ने चांदी के डालरों के विशाल भंडारों के साथ ऊहान से भागना शुरू कर दिया । अप्रैल के अंत में जब ऊहान सरकार ने चाँदी के बहिर्गमन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तथा सभी बैंकों के लिए अपने नकदी भण्डार पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया, तब बैंकों ने इस कदम का विरोध किया तथा उन्होंने सरेआम अपने सभी व्यापारिक सौदों को स्थगित कर दिया ।

वाणिज्यिक संकट से वित्तीय राजस्व पर असर पड़ा तथा यह उत्तरी अभियान के निष्पादन में निरंतर हो रहे सैनिक खर्चे को वहन करने में कतई पर्याप्त न था । ऊहान सरकार को वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बैंक नोट जारी करने का आपातकालीन कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा ।

ऊहान सरकार ने खुद को आर्थिक संकट में फँसे पाया ।

गंभीर आर्थिक संकट का फायदा उठाते हुए, पूँजीपतियों ने श्रमिकों के शोषण-चक्र को **और तेज कर** दिया । इसने तथा इसके साथ बेरोजगारी और बढ़ती हुई कीमतों ने श्रमिकों के रहन-सहन के हालात को और ज्यादा बदतर बना दिया तथा वर्ग अंतर्विरोध और तीव्र हो गए।

ऊहान सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में किसान आन्दोलन का आगे बढ़ना जारी रहा । बहुत सी काउंटियों में किसानों ने जमींदारों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया ।

आर्थिक घेराबन्दी, वाणिज्यिक दिवालिएपन, अनाज की कमी, वित्तीय संकट, उद्योगों में मंदी तथा श्रमिक-किसान क्रान्ति के मद्देनजर राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग के ऊपरी तबके ने क्रांति से मुँह मोड़ना शुरू कर दिया ।

1 जून, 1927 को उत्तरी अभियान सेना ने हनान प्रान्त में चङचओ तथा खाएफङ पर कब्जा कर लिया तथा वहां पर फङ ग्वी-श्याङ की सेना से हाथ मिलाया । इस विजय से ऊहान सरकार की स्थिति मज़बूत हो गई होती यदि अन्दरूनी झगड़े तथा फूट न होती, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह सरकार वास्तव में गिर रही थी ।

ऊहान सरकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के जमींदारों तथा पूँजीपतियों ने श्रमिक-किसान आंदोलन का सबसे पहले विरोध किया । उन्होंने शहरों में किसान सभाओं तथा श्रमिक-संगठनों को गैर-कानूनी संगठन करार देते हुए उन पर हमला बोल दिया, और उनसे मिलीभगत करके, ऊहान सरकार में मौजूद प्रतिक्रियावादियों ने विद्रोह कर दिया । जब क्रांतिकारी सेना हनान में **आगे बढ़** रही थी, उस समय सछ्वान के युद्ध-सरदार चाङ सेन की फौजें ऊहान पर हमला **कर रही** थीं, तथा उसी समय श्या तओ-इन पहला व्यक्ति था, जिसने 17 मई, 1927 को खुल्लम-खुल्ला विद्रोह कर दिया । इसके बाद एक अन्य प्रतिक्रियावादी अफसर श्वी ख-श्याङ ने **भी उसका** अनुसरण करते हुए 21 मई को छाङशा में प्रांतीय ट्रेड यूनियन संघ, प्रांतीय किसान **सभा तथा सभी** दूसरे क्रांतिकारी संगठनों के भवनों को घेरे में ले लिया । नानछाङ, च्याङशी में **चू फेइ-त ने** कम्युनिस्टों तथा क्रान्तिकारी जनता को गिरफ्तार करते तथा मौत के घाट उतारते हुए, **सेना में मौजूद** सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शहर छोड़ने के लिए

बाध्य किया तथा श्रमिक-किसान आंदोलन के अनेक नेताओं का वध कर दिया और इस प्रकार च्याङशी को ऊहान सरकार से आजाद करा लिया ।

इन विद्रोहों तथा गद्दारियों के फलस्वरूप ऊहान सरकार के कब्जे में बहुत थोड़ा इलाका रह गया ।

इन सब बातों ने ऊहान में मौजूद क्वोमिंताङ के उन नेताओं पर अपना पूरा असर डाला जो जमींदारों तथा पूँजीपतियों से घिरे हुए थे व उनसे प्रभावित थे । ऊहान के आर्थिक तथा राजनीतिक संकट ने उन्हें और ज्यादा ढुलमुल बना दिया तथा अन्ततः वे क्रांति से विश्वासघात कर गए ।

उन्होंने दावा किया कि श्रमिक तथा किसान जनता बहुत आगे बढ़ गई थी तथा सेना में इससे विरोध भड़क जाना था तथा यह कि इस विरोध में सभी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने सम्मिलित हो जाना था तथा साम्राज्यवादियों ने अपना हस्तक्षेप और ज्यादा तीव्र कर देना था । उनका कहना था कि यदि ऐसी स्थिति को ज्यादा देर चलने दिया गया तो घिरी हुई ऊहान सरकार धराशायी हो जानी थी । 12 अप्रैल की घटना के बाद, उन्होंने सोचा, चूंकि क्वाङतुङ के दस लाख किसानों को स्थानीय युद्ध-सरदारों ने आसानी से पराजित कर दिया था, तथा शंघाई के आठ लाख श्रमिकों को च्याङ काई-शेक से पराजय का मुँह देखना पड़ा था, अतः केवल सेना पर ही भरोसा किया जा सकता था, श्रमिकों तथा किसान समुदाय पर नहीं ।

ढुलमुलपन से गद्दारी तक की प्रक्रिया ने सबसे पहले कृषि-संबंधी प्रश्न पर स्वयं को प्रकट किया । 1927 की बसन्त ऋतु में ऊहान में क्वोमिंताङ ने एक केन्द्रीय कृषि समिति की स्थापना की । कृषि के सवाल को लेकर हुई बहस के दौरान क्वोमिंताङ नेताओं के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया । उन्होंने विभिन्न बहाने करते हुए भूमि-सुधारों का विरोध किया । कुछ ने कहा कि उत्तरी अभियान सेना के अफसरों के स्वामित्व वाली ज़मीन ज़ब्ती से मुक्त रखी जाए; अन्यों का विचार था कि छोटे जमींदारों की जमीन भी जब्ती से मुक्त रहनी चाहिए, तथा कुछ का विचार तो यहां तक था कि प्रति-क्रांतिकारी तत्वों की जमीन भी अक्षुण्ण रहनी चाहिए । यह दलील भी पेश की गई कि क्योंकि चीन में केवल 15 प्रतिशत जमीन पर ही खेती होती थी, अतः जमींदारों की ज़मीन ज़ब्त करना जरूरी नहीं था, बल्कि, जरूरत केवल इस बात की थी कि बेकार पड़ी ज़मीन किसानों को दे दी जाए । बाद में एक कृषि-सुधार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका असली मकसद जमीन की जब्ती के कार्यक्षेत्र को सीमित करना था । मई में पास किए गए प्रस्ताव में बड़े जमींदारों की जमीन की जब्ती को केवल सिद्धान्त के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई थी । यह सच है कि प्रस्ताव में लगान में कटौती का प्रावधान था तथा लगान की उच्चतम सीमा कुल उपज का चालीस प्रतिशत निश्चित की गई थी, लेकिन इन धाराओं को सार्वजनिक नहीं किया गया । बाद में, "अच्छे शरीफजादों" की रक्षा के लिए, दूसरे शब्दों में सामंती जमींदार वर्ग की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए एक आदेश जारी किया गया । अन्त में हुपे की दो सबसे बड़ी काउंटियों, ह्वांङकांङ तथा ह्वाङफी की किसान सभाएं भी भंग कर दी गईं।

इन सब बातों से पूर्णतः सिद्ध हो गया कि ऊहान के क्वोमिंताङ नेता किसान आंदोलन तथा कृषि-सुधारों के घोर विरोधी थे । वे मजदूर-वर्ग के संघर्ष के भी खिलाफ थे । जबरदस्ती मध्यस्थता करने, (जिसमें अंतिम निर्णय का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा), श्रमिकों

5 अगस्त को क्रांतिकारी सेनाओं ने नानछाङ को खाली कर दिया तथा क्वाङतुङ की ओर कूच किया ।

सशस्त्र विद्रोह को किसान आन्दोलन से जोड़ने की अनिवार्यता को महसूस करने में नेतृत्व की असफलता के कारण, बगावत के बाद अगले कदम के प्रश्न पर ठीक तरह से विचार नहीं किया जा सका । च्याङशी, हुनान तथा हुपे में अभी भी किसान आंदोलन पूरे जोर-शोर पर होने के कारण, क्रांतिकारी सेनाओं को एक सुनिश्चित कृषि-सुधार कार्यक्रमानुसार कृषि-क्रांति लाने के लिए, तथा एक टिकाऊ व दीर्घकालीन छापामार युद्ध चलाने की खातिर क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित करने के लिए, किसानों को हथियारबन्द करने के निमित्त ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए था । लेकिन इसकी बजाय, वे कैंटन तथा क्वाङतुङ के अन्य इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए, दक्षिण की तरफ एक अभियान पर चल पड़े । उन्होंने मार्ग चुनने में भी बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नहीं लिया । पश्चिमी च्याङशी—जहाँ किसान आन्दोलन की जड़ें मज़बूत थीं—के रास्ते कूच करने की बजाय, वे पूर्वी च्याङशी के सुनसान इलाके में से गये, जहाँ किसान आन्दोलन अभी शुरू भी नहीं हुआ था । रुइचिन तथा ह्वेइछाङ को जीतने के पश्चात, वे दक्षिण की ओर मेइश्येन काउंटी पर कब्जा करने के लिए आगे नहीं बढ़े, बल्कि शाङहाङ तथा थिङचओ के रास्ते छाओचओ तथा शानथओ पर कब्ज़ा करने के लिए पीछे मुड़े तथा इस प्रकार शत्रु को जवाबी हमले की पर्याप्त तैयारी करने के लिए समय मिल गया । अपर्याप्त राजनीतिक काम के कारण, सैनिकों तथा जनसाधारण में प्रचार-कार्य बखूबी न हो सका, तथा पार्टी शाखाएँ भी केवल रेजीमेन्टों में ही स्थापित की गईं, कम्पनियों में नहीं, जिसका नतीजा यह निकला कि अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी सेना से सामना होने पर ज्यादातर सैन्यदलों को हार का मुँह देखना पड़ा । केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचाया जा सका ।

हार के बावजूद, नानछाङ विद्रोह का एक महान ऐतिहासिक महत्त्व था ।

इससे कम्युनिस्ट पार्टी के एकछत्र नेतृत्व में प्रति-क्रांति के विरुद्ध, क्रांतिकारी सशस्त्र सेनाओं के संघर्ष का आरंभ हुआ । यह एक बहादुराना संघर्ष था जिसका उद्देश्य सशस्त्र बगावत द्वारा प्रति-क्रांतिकारी नरसंहार का विरोध करते हुए, संकटवेला में क्रांति की रक्षा करना था । इसने चीनी जनता के सामने अथक क्रांतिकारी संघर्ष का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया।

नानछाङ विद्रोह ने चीनी जन-सेना को जन्म दिया, एक ऐसी सेना जिसका नेतृत्व केवल कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था तथा जो जी-जान से जन-क्रांति को समर्पित थी । इस प्रकार चीनी जनता के क्रांतिकारी संघर्ष की एक नयी ऐतिहासिक मंजिल शुरू हुई ।

क्रांति को बचाने के लिए कदम उठाने की खातिर 7 अगस्त को च्याङशी प्रांत के च्योच्याङ नामक स्थान पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने केन्द्रीय समिति का एक आपातकालीन सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन ने क्रान्तिकारी नेतृत्व, क्रान्तिकारी सशस्त्र सेनाओं तथा कृषि-क्रान्ति के प्रश्नों पर दक्षिणपंथी अवसरवादी छन तू-श्यू की भ्रांतिपूर्ण आत्मसमर्पणकारी नीति की आलोचना की तथा उसे नेतृत्वकारी पद से हटा दिया । इसने इस बात की पुष्टि की, कि चूँकि कृषि-क्रान्ति चीनी जनवादी-क्रांति की सफलता की कुँजी थी, अतः पार्टी को किसानों का नेतृत्व करना चाहिए ताकि वे क्रांतिकारी तरीकों द्वारा भूमि-समस्या को हल कर सकें । सम्मेलन ने क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की नरसंहार नीति का सशस्त्र विरोध करने के लिए एक आम कार्यदिशा निर्धारित की तथा पार्टी एवं जनसाधारण का क्रांतिकारी संघर्ष में डटे रहने के लिए

कम्युनिस्ट पार्टी की सही क्रांतिकारी कार्यदिशा को सूत्रबद्ध किया गया—वह कार्यदिशा जिसका प्रतिनिधित्व कामरेड माओ त्से-तुङ ने किया—जिसने धीरे-धीरे चीनी क्रांति की लहर का रुख मोड़ दिया ।

2.

- **चीनी क्रांति का आगे बढ़ने के दौर से पीछे लौटने के दौर में संक्रमण ।**
- **कम्युनिस्ट पार्टी में पहली ''वामपंथी'' कार्यदिशा में संशोधन ।**

जब पहले च्याङ काई-शेक और फिर वाङ चिङ-वेइ ने क्रान्ति से गद्दारी कर दी थी, ऐसे गंभीर समय में पार्टी ने 1 अगस्त, 1927 को कामरेड चओ एन-लाई तथा चू तेह की कमान में 30,000 से अधिक सैनिकों को लेकर च्याङशी के नानछाङ में एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन कर क्रांति को हार से उबारने का बीड़ा उठाया । क्रांतिकारी समिति के नाम से एक नेतृत्वकारी संगठन की स्थापना की गई । सुबह के समय बगावत आरंभ की गई तथा केवल तीन घंटे की लड़ाई के बाद, क्वोमिंताङ की प्रतिक्रियावादी सेनाओं को निष्क्रिय कर दिया गया तथा शहर को मुक्त करा लिया गया ।

कामरेड चओ एन-लाई (1898-1976)

तथा दुकान-नौकरों की माँगों पर अंकुश लगाने, श्रमिकों को फैक्ट्रियों तथा वर्कशापों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने से रोकने तथा श्रमिक-टुकड़ियों द्वारा कानून तोड़ने वाले पूँजीपतियों पर जुर्माना न करने और उन्हें गिरफ्तार न करने संबंधी कानून बनाए गए ।

ये सभी कदम श्रमिक-किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तथा इसे शासक-वर्ग के हितों के अधीन करने की सोच के तहत उठाए गए थे ।

क्वोमिंताङ नेताओं ने विद्रोही जनरलों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की । वे केवल श्या तओ-इन की सेना के एक हिस्से को निरस्त करने के लिए तैयार थे । उन्होंने यह कह कर तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा कि छाङशा घटना के दौरान श्रमिक-टुकड़ियों ने श्वी ख-श्याङ के सैनिकों पर हमला किया था । च्याङशी में चू फेइ-त के विश्वासघात के विषय में उन्होंने पूर्णरुपेण चुप्पी धारण कर ली, मानो वे इस विषय में कुछ जानते ही न थे ।

इस प्रकार ऊहान के क्वोमिंताङ नेता युद्ध-सरदारों के राजनीतिक पिट्ठू बन गए ।

लेकिन छन तू-श्यू के गुट ने, जिसके हाथ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व था, उस समय क्या किया ?

ऐसी गंभीर स्थिति में, पार्टी को बिना किसी झिझक के श्रमिकों तथा किसानों के जन-आन्दोलन को, खास तौर से हुनान के आस-पास केन्द्रित किसान आन्दोलन को, आगे बढ़ाना चाहिए था ताकि जनता की ताकत से, साम्राज्यवादियों तथा चीनी प्रतिक्रियावादियों के साँझे हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता । उसे राष्ट्रीय सरकार तथा क्रांतिकारी सेना में से क्वोमिंताङ के दक्षिणपंथियों के निष्कासन की माँग करनी चाहिए थी तथा क्वोमिंताङ और उसकी सरकार में नए श्रमिक तथा किसान नेताओं को शामिल करने की माँग करनी चाहिए थी । उसे तेजी से श्रमिकों एवं किसानों की एक सेना का गठन करना चाहिए था तथा सरकार व सेना पर सीधा नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए था । यही एकमात्र रास्ता था जो क्रांति को विजयश्री दिला सकता था ।

लेकिन छन तू-श्यू आत्मसमर्पणकारियों ने ऐसा नहीं किया, और पाँचवीं पार्टी कांग्रेस में भी उनकी गलतियों को वास्तव में सुधारा नहीं गया ।

जहाँ तक कृषि-कार्यक्रम का संबंध है, पार्टी में दक्षिणपंथी अवसरवादी, क्वोमिंताङ नेताओं के आदेशों का पूरी तरह पालन कर रहे थे, उन्होंने क्वोमिंताङ नेताओं द्वारा किसान-आंदोलन के विरोध में रखे गए प्रस्ताव का रत्ती भर भी विरोध नहीं किया । बल्कि उन्होंने क्वोमिंताङ में, जमीदारों तथा पूँजीपतियों द्वारा किसान आंदोलन की तथाकथित ''ज्यादतियों'' के विरुद्ध मचाई गई हाय-तौबा तक को प्रतिध्वनित किया तथा कृषि-क्रांति रोकने की सलाह दी व माँग की कि समाचार-पत्रों में इसकी आलोचना की जाए, तथा कृषि मंत्रालय इसके ''भटकावों'' में सुधार का ऐलान करे । जहाँ तक किसानों की राजनीतिक सत्ता का सवाल था, अवसरवादी ऊहान में क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा किसान-आंदोलन को रोकने के लिए प्रस्तुत ''ग्रामीण स्वायत्तता'' की नीति पर सहमत हो गए । उन्होंने यह जहरीली अफवाह भी फैलाई कि ऊहान में जन-आंदोलन च्याङ काई-शेक के गुर्गों द्वारा शुरू किया गया था ।

जब छाङशा घटना घटी, शहर में श्वी ख-श्याङ की कमान में केवल एक हजार सैनिक थे, जबकि लाखों किसान इसे घेरे हुए थे । किसानों के लिए शहर पर कब्जा करना बिल्कुल आसान था, लेकिन पार्टी की नेतृत्वकारी समिति ने हमले की योजना को रद्द कर दिया । असल

में यह एक प्रकार से क्रांति से गद्दारी करना ही था । छाङशा घटना के बाद, आत्मसमर्पणकारियों, ने राजनीतिक दाँवपेचों के जरिए समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह निकला कि प्रतिक्रियावादी पहले से भी ज्यादा निरंकुश हो गए ।

पार्टी में मौजूद अवसरवादियों का विश्वासघाती रुख श्रमिक-वर्ग आंदोलन के प्रति उनके रवैये से भी उतने ही स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ । उन्होंने अनिवार्य मध्यस्थता, विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों में हड़तालों पर पाबन्दी, संगठनों की गतिविधियों पर रोक, श्रमिकों के संघर्ष पर प्रतिबन्ध जैसे क्वोमिंताङ के सभी आदेशों को स्वीकार कर लिया । उन्होंने श्या तओ-इन के विद्रोह के समय 1500 श्रमिकों को हथियार देने के परामर्श का विरोध किया, यहां तक कि हथियार लेने तक से भी इन्कार कर दिया । और भी ज़्यादा बुरी बात यह हुई कि ऊहान में प्रतिक्रियावादी अधिकारियों के असंतोष के दृष्टिगत, उन्होंने तत्काल श्रमिक टुकड़ियों को निरस्त करके भंग कर दिया, तथा इस प्रकार श्रमिकों को दुश्मन के हमले का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया ।

ऊहान काल में, क्वोमिंताङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त सभाएं हुआ करती थीं, लेकिन आत्मसमर्पणकारियों ने स्वेच्छा से नेतृत्व का परित्याग कर दिया । उन्होंने क्वोमिंताङ मुख्यालय तथा समाचार-पत्रों में कार्यरत सभी कम्युनिस्टों को आदेश दिया कि वे क्वोमिंताङ के निर्देशन में काम करें तथा अपने विचारों को त्याग दें । उनकी हिदायतों के अनुसार, जनवादी क्रांति का नेतृत्व क्वोमिंताङ के हाथ में होना चाहिए था, तथा वे कम्युनिस्ट जो क्वोमिंताङ के सदस्य भी थे तथा क्रांतिकारी सरकार में काम करते थे, उन्हें क्वोमिंताङ के सदस्यों के रूप में सरकार में शामिल होना चाहिए था, न कि एक कम्युनिस्ट के रूप में । प्रतिक्रियावादियों द्वारा शुरू किए गए हमलों द्वारा उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने में क्वोमिंताङ की मदद करने के लिए, इन कम्युनिस्टों को सलाह दी गई कि वे लम्बी छुट्टी पर चले जाएं । ऐसी व्यवस्था भी की गई कि श्रमिकों तथा किसानों के जन-संगठन क्वोमिंताङ के नेतृत्व तथा निरीक्षण के अधीन कर दिए जाएँ, तथा उनकी सशस्त्र टुकड़ियां क्वोमिंताङ के आदेशों का पालन करें ।

इन सब बातों का अर्थ, न केवल कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतंत्रता की समाप्ति था, बल्कि मोटे तौर पर क्रान्तिकारी जन आंदोलन को क्वोमिंताङ नेतृत्व के सुपुर्द करके उसका खात्मा करना भी था ।

प्रतिक्रियावादियों द्वारा ऊहान पर अन्दर तथा बाहर, दोनों तरफ से किये जा रहे हमलों ने क्वोमिंताङ नेताओं को ही नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी समिति के आत्मसमर्पणकारियों को भी भयभीत कर दिया । दोनों ग्रुप डगमगाने लगे । एक तरफ छन तू-श्यू की डगमगाहट का परिणाम था—रियायत अर्थात् नेतृत्व क्वोमिंताङ को सौंप देना, वहीं पर दूसरी ओर वाङ चिङ-वेइ के ढुलमुलपन के कारण कम्युनिस्ट पार्टी से नेतृत्व हथियाने के उद्देश्य से एक आक्रामक अभियान चला ।

श्या तओ-इन के विश्वासघात तथा छाङशा घटना के बाद, ऊहान में प्रतिक्रांतिकारी खुल्लम-खुल्ला च्याङ काई-शेक की ओर चले गए । प्रतिक्रियावादियों से प्रभावित होकर, उत्तर-पश्चिमी सेना के कमांडर फङ ख्वी-श्याङ ने, 10 जून को छङचओ में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें क्वोमिंताङ के नेताओं तथा उत्तरी अभियान सेना के अफसरों ने भाग लिया । सम्मेलन के फलस्वरूप, श्रमिकों तथा किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए ताङ

कामरेड माओ त्से-तुङ ने क्रांति की असफलता के बाद हुनान-च्याङशी सीमा पर छापामार युद्ध के दौरान हासिल हुए अपने अनुभवों के आधार पर स्पष्ट किया था :

"पिछले साल जगह-जगह लड़ने के बाद हम इस बात को अच्छी तरह महसूस करते हैं कि समूचे देश के पैमाने पर क्रान्तिकारी ज्वार उतार पर है.....जहां भी लाल सेना जाती है, वहां की आम जनता उसे उदासीन और विरक्त नजर आती है, और हमारे द्वारा प्रचार किये जाने के बाद ही वह धीरे-धीरे जागती है । शत्रु की जो भी सेना हो, उससे हमें कठोर लड़ाई लड़नी पड़ती है; तथा शत्रु सेनाओं में मुश्किल से ही कोई बलवा या विद्रोह होता है ।"[3]

घरेलू स्थिति का यह गहरा विश्लेषण अत्यधिक महत्त्व का था । जनसाधारण की उदासीनता तथा अलगाव से उनका अभिप्राय यह था कि कुचला हुआ जन-आन्दोलन अभी तक दोबारा उबर नहीं पाया था । छापामार युद्ध में सख्त लड़ाई से स्पष्ट होता था कि प्रतिक्रियावादी वर्गों का शासन अभी तक सम्पूर्ण विंध्वंस के कगार पर नहीं पहुँचा था ।

हुनान-च्याङशी सीमा का जो सत्य था, वही अन्य स्थानों पर भी लागू होता था ।

इस समय के अधिकतर विद्रोह क्वाङतुङ, हुनान, हुपे तथा च्याङशी में हुए, जहाँ उत्तरी अभियान के दौरान महान क्रांतिकारी झंझावात के प्रभाव में एक क्रांतिकारी आधार की नींव रखी गई थी तथा जहाँ देहाती इलाकों में साम्राज्यवादियों एवं सामंती युद्ध-सरदारों का शासन अपेक्षाकृत कमजोर था । लेकिन केवल पार्टी के सही मार्गदर्शन द्वारा ही किसानों की सशस्त्र सेनाएँ तथा शासन व्यवस्था सुदृढ़ एवं विकसित किए जा सकते थे । चूंकि पार्टी नेतृत्व तथा क्रांतिकारी सेनाओं की शक्ति विभिन्न जिलों में अलग-अलग थी, अतः किसान आन्दोलन का विकास भी असमान था ।

आमतौर से, 1927 के बाद क्वोमिंताङ के नए युद्ध-सरदारों का शासन, अभी भी शहरों में दलाल-पूँजीपति वर्ग का तथा देहात में जमींदार-वर्ग का शासन था । फलतः, चीन तब भी पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति की मंजिल में ही था । लेकिन, क्रांति की असफलता के बाद, श्रमिकों तथा किसानों की शक्ति को नृशंस श्वेत आतंक द्वारा कुचला तथा तितर-बितर किया गया । क्रांति की लहर उस वक्त दो उभारों के मध्यांतर में थी, एक को तो भूतकाल पहले ही लील गया था, तथा दूसरे का अभी आविर्भाव होना था ।

तथापि, नए युद्ध-सरदारों का शासन अस्थिर था । ये युद्ध-सरदार जनसाधारण से पूरी तरह कटे हुए थे तथा जनता के साथ उनके अन्तर्विरोध दिन-प्रतिदिन तीव्रतर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना शासन श्रमिकों, किसानों तथा क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का लगातार अभूतपूर्व रक्तरंजित दमन करते हुए स्थापित किया था । उनके सभी संगठन (सरकार, सशस्त्र सेनाएँ, पार्टियाँ वगैरा) कमजोर थे, क्योंकि वे एक पिछड़े सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर स्थापित किये गए थे । अन्दरूनी अनबन तथा युद्धों ने उनकी ताकत को और ज्यादा खोखला कर दिया था। इन सब बातों से यह साफ जाहिर होता था कि क्रांतिकारी ताकतों के बहुत ज्यादा कमजोर होने के बावजूद क्वोमिंताङ के नए युद्ध-सरदारों का शासन जरा भी स्थिर नहीं था । इन हालातों में क्रांतिकारी लहर में दूसरा उभार आना अवश्यम्भावी था ।

क्रांति की असफलता के बाद जो राजनीतिक स्थिति थी, उसे देखते हुए क्रांतिकारी युद्ध की रणनीति तथा कार्यनीति का निर्माण करना था । इससे दूसरे क्रातिकारी गृहयुद्ध के दौरान

अत्यधिक मुश्किल हालात में भी संघर्ष को जारी रखा ।

लेकिन चूंकि श्रमिकों की हड़तालें प्रतिक्रांतिकारी शासन के आतंक के साये तले तथा ऐसे समय में चलाई जा रही थीं जब कम्युनिस्ट श्रमिक संगठनों को भूमिगत होना पड़ा था, अत: वे अनिवार्य रूप से क्रान्ति के उतार की निम्नलिखित विशेषताएं लिये हुए थीं :

प्रथम, श्रमिक संघर्षों का स्वरूप बहुधा आर्थिक था । उदाहरण के लिए, 1928 के उत्तरार्द्ध के पूँजी तथा श्रम के बीच के 92 प्रतिशत विवाद, आर्थिक कारणों की वजह से थे, तथा उच्चतर वेतन की मांग के इर्द-गिर्द केन्द्रित थे । श्रमिकों ने संघर्ष करने की फौरी जरूरत को महसूस किया क्योंकि वे अत्यधिक क्रूर शोषण का शिकार थे ।

दूसरी, संघर्ष आमतौर से स्वत:स्फूर्त था । 49 प्रतिशत से भी अधिक हड़तालें श्रमिकों ने स्वयं चलाई, जब कि 12 प्रतिशत का नेतृत्व पीत श्रमिक संगठनों[2] तथा 37 प्रतिशत का नेतृत्व कम्युनिस्ट श्रमिक संगठनों ने किया ।

तीसरी, हड़तालियों का बहुत बड़ा हिस्सा दुकानदारों, हस्तशिल्पकारों तथा खलासियों का था । जिन 196 व्यवसायी-समुदायों ने संघर्ष में भाग लिया, उनमें से 94 समुदाय (लगभग 48 प्रतिशत) इन्हीं के थे । फैक्ट्री मजदूर अभी तक प्रति-क्रांतिकारी आतंक के तहत टूटे कहर से उबर नहीं पाए थे ।

चौथी, केवल 22 प्रतिशत हड़तालों को पूर्ण सफलता मिली, 19 प्रतिशत को आंशिक सफलता मिली जब कि 59 प्रतिशत, यानि कि बहुत बड़े हिस्से को हार का सामना करना पड़ा, या बिना किसी उपलब्धि के दम तोड़ गईं ।

प्रति-क्रांतिकारी आतंक के तहत, शहरों में श्रमिक-वर्ग आंदोलन ज्वार से उतार की ओर था, यानि आक्रमणात्मक से रक्षात्मक हो गया था ।

च्याङ काई-शेक की नई क्वोमिंताङ युद्ध-सरदार सरकार ने देहातों में जमींदारों को किसानों पर जवाबी हमले करने तथा अपना हिसाब चुकता करने का मौका दिया । फलत: उत्तरी अभियान के दौरान किसानों द्वारा स्थापित अधिकतर स्थानीय क्रांतिकारी सरकारें नष्ट कर दी गईं तथा लगान व सूद में कटौती के आदेशों को रद्द कर दिया गया । जमींदारों ने बुरी तरह से लगान एवं सूद में वृद्धि करके तथा प्रतिक्रियावादी सरकार ने अत्यधिक भूमि-कर एवं अन्य शुल्क थोंपकर, किसानों को जीवनयापन तथा उत्पादन के लिए जरूरी हालातों से भी वंचित कर दिया ।

क्वाङतुङ, हुनान, हुपे तथा च्याङशी में किसान आंदोलन ने सशस्त्र नियंत्रण का रूप धारण कर लिया । पूर्वी क्वाङतुङ के हाएफङ तथा लूफङ में, हाएनान द्वीप, हुनान-च्याङशी तथा हुनान-क्वाङतुङ की सीमाओं पर तथा हुपे के ह्वाङआन व माछङ में किसानों ने अपनी सेनाओं का गठन किया तथा अपनी सरकारें स्थापित की । च्याङ काई-शेक के शासन केन्द्रों—च्याङसू तथा चच्याङ में लगान तथा टैक्सों की अदायगी के विरोध में किसान संघर्ष भड़क उठे । कुछ आदिम किस्म के किसान संगठनों, जैसे कि हनान के "लाल भाला समाज" आदि के संघर्षों में अत्यधिक तेजी आई । हपे तथा शानतुङ के कुछ जिलों में किसान उपद्रव हुए ।

अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी किसान वर्ग अपने संघर्ष में डटा रहा । लेकिन श्वेत आतंक के कारण, किसान आंदोलन भी आंदोलन के उतार के गुण लिए हुए था, जैसा कि

शङ-च के सैनिक हनान से ऊहान वापिस आ गए । 19 जून को, श्वीचओ में फङ य्वी-श्याङ तथा च्याङ काई-शेक ने एक कांफ्रेन्स की, जिसके बाद फङ ने ऊहान स्थित क्वोमिंताङ नेताओं को खुल्लम-खुल्ला विश्वासघात के रास्ते पर बढ़ चलने के लिए तार-संदेश भेजा ।

इस गंभीर स्थिति में, पार्टी में मौजूद आत्मसमर्पणकारियों ने, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने की बजाय, ऊहान में क्वोमिंताङ नेताओं को एक **"पूर्वी अभियान"** शुरू करने के लिए मनाने का प्रयास किया । उनका सोचना था कि उत्तर-पूर्वी प्रांतों पर कब्जा करने से पहले वाङ चिङ-वेइ तथा अन्य क्वोमिंताङ नेताओं के, कम्युनिस्ट पार्टी से नाता तोड़ने की कोई संभावना न थी तथा उन्होंने उनसे च्याङ काई-शेक को हराने से पहले पांतों को न तोड़ने के लिए कहा । लेकिन क्वोमिंताङ नेता तो "पूर्वी अभियान" नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का आत्मसमर्पण चाहते थे ।

29 जून, 1927 को, ऊहान सरकार के एक प्रतिक्रियावादी अफसर हो च्येन ने अपने अधीनस्थों को कम्युनिस्ट-विरोधी हिदायतें देते हुए, कम्युनिस्टों से अलग हो जाने का आदेश दिया । 15 जुलाई, 1927 को, वाङ चिङ-वेइ के गुट ने *"कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने के लिए सम्मेलन"* का आयोजन किया तथा इस मुद्दे को लेकर एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया तथा इस प्रकार क्रांति से विश्वासघात किया । कम्युनिस्ट पार्टी ने वाङ चिङ-वेइ गुट के अपराधों की निन्दा करने तथा ऊहान सरकार से अपने सदस्यों को हटाने के बारे में एक घोषणापत्र जारी किया । 15 जुलाई से ऊहान के प्रतिक्रियावादियों ने श्रमिकों तथा किसानों के संगठनों को खत्म कर दिया तथा कम्युनिस्टों एवं अन्य क्रांतिकारियों का भारी संख्या में कत्लेआम करके क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल डाला ।

क्वोमिंताङ का जनवादी धड़ा, जिसका प्रतिनिधित्व डॉ० सुन की पत्नी सुङ चिङ-लिङ कर रही थीं, दृढ़ता से डॉ० सुन यात-सेन के तीन जन-सिद्धान्तों व तीन प्रधान नीतियों पर डटा रहा तथा उसने डॉ० सुन के क्रांतिकारी सिद्धान्तों और नीतियों का उल्लंघन करने व उनकी शिक्षाओं के प्रति विश्वासघात करने के लिए क्वोमिंताङ नेताओं की भर्त्सना की तथा ध्यान दिलाया कि उनके विश्वासघात से क्वोमिंताङ की भूमिका युद्ध-सरदारों की कठपुतली मात्र की रह जाएगी । उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि-क्रांति किसानों की फौरी तथा मुख्य माँग थी तथा कृषि समस्या का क्रांतिकारी तरीकों द्वारा समाधान करना ही डॉ० सुन का महान उद्देश्य था । उन्होंने अपने इस क्रान्तिकारी पक्ष की दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया।

12 अप्रैल, 1927 तथा 15 जुलाई के नरसंहार के बाद प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध की परिणति असफलता में हुई ।

असफलता का पहला कारण साम्राज्यवादियों, उत्तरी युद्ध-सरदारों तथा क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी गुट की प्रति-क्रातिकारी शक्तियों की क्रांतिकारी सेनाओं पर अत्यधिक प्रबलता का होना था और दूसरा कारण पार्टी नेतृत्व द्वारा दक्षिणपंथी अवसरवादी गलतियां करना था।

छन तू-श्यू अवसरवादियों की गलतियां मुख्य रूप से पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति में सर्वहारा के नेतृत्व को तिलांजलि देना, तथा किसान वर्ग, निम्न-पूँजीवादी वर्ग, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा सबसे ऊपर, सशस्त्र सेनाओं पर सर्वहारा के नेतृत्व को नकार देना थीं । जिसका नतीजा यह निकला कि शत्रु द्वारा हमला करने पर पार्टी कारगर ढंग से प्रतिरोध करने में असमर्थ रही और इसीलिए क्रांति को हार का सामना करना पड़ा ।

लेकिन क्रान्ति की ज्वाला को कभी बुझाया नहीं जा सकता । कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीनी जनता का क्रांति के लिए संघर्ष जारी रहा ।

● प्रथम क्रांतिकारी गृह-युद्ध का सारांश

1924-27 का युद्ध पहला साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद-विरोधी क्रांतिकारी युद्ध था जिसे चीनी जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ा ।

1924 में कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के बीच आपसी सहयोग से क्वाङतुङ में क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई । क्रांतिकारी श्रमिक तथा किसान जनता के सहयोग से क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र को एकीकृत तथा सुदृढ़ किया गया तथा इस प्रकार उत्तरी अभियान युद्ध की नींव तैयार की गई ।

उत्तरी अभियान युद्ध जुलाई 1926 में शुरू हुआ । आधे साल के अन्दर ही उत्तरी अभियान सेना ने चली युद्ध-सरदारों की सेना को कुचल डाला तथा याङत्सी घाटी की ओर बढ़ गई तथा इस प्रकार उत्तर में फङथ्येन युद्ध-सरदारों के मुकाबले पर आ गई । इस बात की पूरी संभावना थी कि क्रान्ति की सफलता से चीन का एकीकरण हो जाएगा तथा उसे आजादी मिल जाएगी।

लेकिन तेजी से फैल रही क्रांति का आधार बेहद कमजोर था, क्योंकि क्रान्तिकारी सेना में युद्धपतिवाद का उन्मूलन नहीं किया गया था तथा क्रांतिकारी सेनाओं के कब्जे वाले इलाकों में जमीदारों का शासन छिन्न-भिन्न नहीं किया गया था ।

इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए, क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादियों ने, साम्राज्यवादियों की शह पर तथा उनके सहयोग से क्रांति पर अचानक हमला बोल दिया । इसी दौरान, कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी समिति, जिसमें आत्मसमर्पणकारियों का वर्चस्व था जिनका नेतृत्व छन तू-श्यू के हाथ में था, तथा जिसने कामरेड माओ के सही विचारों को दबा दिया था, हमलें का प्रतिरोध करने के लिए कारगर ढंग से कदम नहीं उठा पाई । इस प्रकार क्रांति का अंत असफलता में हुआ ।

क्रांति के समूचे दौर में दो परस्पर विरोधी नीतियों में संघर्ष साफ दिखाई देता रहा । एक तरफ पूँजीपति वर्ग नेतृत्व पर कब्जा करने के प्रयास में था । साम्राज्यवादियों से साँठ-गाँठ करके, उसने क्रांति पर हमला किया, उसका प्रयास था कि पूँजीवादी प्रभुत्व स्थापित करके क्रांति को समाप्त कर दिया जाए । दूसरी ओर, सर्वहारा वर्ग ने अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करने तथा करोड़ों मेहनतकश जनता को पूरी तरह लामबन्द करके पूँजीपति वर्ग के हमले का प्रतिरोध करने का प्रयास किया । उसका उद्देश्य पहले जनवादी क्रान्ति में पूर्ण विजय प्राप्त करके, फिर धीरे-धीरे समाजवादी क्रान्ति में संक्रमण करना था ।

पार्टी के बीच इस संघर्ष ने छन तू-श्यू के प्रतिनिधित्व वाली दक्षिणपंथी अवसरवादी नीति तथा कामरेड माओ त्से-तुङ के प्रतिनिधित्व वाली मार्क्सवादी-लेनिनवादी नीति के बीच के संघर्ष का रूप धारण कर लिया । पार्टी के आरंभिक काल में, अपर्याप्त सैद्धांतिक तैयारी के कारण अनेक सदस्यों ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सार गंभीरतापूर्वक ग्रहण करने की कोशिश नहीं की, हालांकि संघर्ष के दौरान उन्होंने क्रांति के प्रति असीम निष्ठा तथा शानदार संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया था । इसी कमज़ोरी के कारण छन तू-श्यू गुट के अवसरवादियों को पार्टी के मुख्य संगठनों पर अस्थायी नियन्त्रण करने में कामयाबी मिली ।

ऊपरी तबके को, जो कि बड़े पूँजीपति वर्ग से जा मिले थे, कोई राजनीतिक अधिकार या आर्थिक लाभ प्रदान नहीं किए । यह तथ्य कि राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के एक या दो प्रतिनिधियों ने प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार में हिस्सा लिया, केवल उसकी असली फासीवादी तानाशाही प्रकृति पर लीपापोती करने से अधिक कुछ न था । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने उन श्रमिकों तथा किसानों का जो क्रांतिकारी लड़ाई में डटे रहे थे, क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया। सन् 1928 के जनवरी और अगस्त के महीनों के बीच एक लाख श्रमिकों तथा किसानों का कत्ल किया गया तथा जो बच गए उनका इतनी ज्यादा नृशंसता से दमन तथा शोषण किया गया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने पहले शहरों में श्रमिकों पर हमला किया ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों का शासन पुराने युद्ध-सरदारों के शासन की अपेक्षा कहीं ज्यादा पाशविक तथा बर्बर था । श्रमिकों ने जो आर्थिक लाभ तथा जनवादी अधिकार पहले से प्राप्त किए हुए थे, वे सभी उनसे पूरी तरह छीन लिए गए । शंघाई, कैंटन तथा ऊहान में श्रमिक संघर्षों की मुख्य विजयों में से एक--वेतन में वृद्धि थी । परन्तु प्रतिक्रांतिकारी राज्य-विप्लव के बाद, इन शहरों में श्रमिकों के वेतन में भारी कटौती की गई ।

कार्यदिवस दोबारा से 11 घंटे का या इससे भी ज्यादा का कर दिया गया । दोपहर के खाने के बाद जो आधे घंटे का विश्राम-समय मिलता था, उसे भी रद्द कर दिया गया तथा आमतौर पर ऐसा था कि या तो श्रमिकों को रविवार की छुट्टी मिलती ही नहीं थी और यदि वे छुट्टी करते थे तो उन्हें एक दिन के वेतन से हाथ धोना पड़ता था ।

काम करने के हालात में बेहद गिरावट आई तथा श्रम की मात्रा में वृद्धि हुई । उदाहरण के तौर पर, अब हर श्रमिक को तीन या चार मशीनों पर काम करना पड़ता था, जबकि पहले वह एक या दो पर काम करता था । बाल-मजदूरों का पहले की तरह ही भारी शोषण चलता रहा तथा महिला श्रमिकों को प्रसूतिकाल के दौरान मिलने वाली एक महीने की छुट्टी रद्द कर दी गयी । इसके अलावा फैक्ट्री श्रमिकों का एक या एक से अधिक गारंटीकर्ता होना जरूरी था, तथा श्रमिकों पर विशेष रूप से भाड़े पर लिए गए जासूसों, पुलिस और यहाँ तक कि सेना द्वारा नजर रखी जाती थी ।

संक्षेप में, वे सभी आर्थिक लाभ जिन्हें श्रमिक संघों ने अपने संघर्षों से जीत कर प्राप्त किया था, क्रांति की असफलता के बाद छीन लिए गए ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने लाल (यानि कि कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले) श्रमिक-संघों पर पहले से कई गुना ज्यादा बर्बरता से हमला किया तथा चारों तरफ श्वेत आतंक फैलाकर उन्हें बंद होने तथा भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया । श्रमिकों तथा उनके नेताओं की सभी गतिविधियों को दबा दिया गया । क्रान्तिकारी संघर्ष का अनुभव रखने वाले श्रमिकों में से 80% को या तो कत्ल कर दिया गया या फिर नौकरी से निकाल दिया गया ।

इस सबके बावजूद भी क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी अपने शासन में केवल अस्थाई स्थिरता ही कायम कर सके । किसी भी तरह की व्यावहारिक स्थिरता, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक, उनके बूते से बाहर की बात थी । और उधर बेहद खराब होते जा रहे राजनीतिक व आर्थिक हालातों के बावजूद, श्रमिक अपने संघर्ष में डटे रहे ।

सन् 1928 में, शंघाई में 140 हड़तालें हुईं, जिनमें 2,33,002 श्रमिकों ने भाग लिया तथा

राजनीतिक गिरोह था जिसमें दलाल-पूँजीपति, डाकू, युद्ध-सरदार तथा पार्टी-स्वामी शामिल थे। च्याङसू तथा चच्याङ के बैंकों के दलाल-पूँजीपति इस की धुरी थे । इन लोगों ने पूरे देश पर अपनी सैनिक शक्ति तथा खुफिया पुलिस का आतंककारी शासन थोंप रखा था । नए युद्ध-सरदारों के शासन ने क्वोमिंताङ को संयुक्त-मोर्चे के एक संगठन से बड़े पूँजीपतियों के फासीवादी संगठन में परिवर्तित करके रख दिया था । उन्होंने क्रांति के झंडे का इस्तेमाल अपनी प्रति-क्रांतिकारी गतिविधियों पर पर्दा डालने तथा लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए किया । इस प्रकार आतंकवाद के साथ-साथ राजनीतिक धोखेबाज़ी भी च्याङ काई-शेक के शासन की विशेषता थी ।

1927 में क्रांति की असफलता के बाद चीन में वर्ग-संबंधों में एक नया परिवर्तन आया। बड़े पूँजीपति वर्ग ने क्रांति से धोखा किया था, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने घुटने टेक दिए थे, तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग का कुछ हिस्सा क्रान्ति का साथ छोड़ गया था । केवल श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग का गरीबी का मारा तबका क्रांतिकारी संघर्ष में डटे रहे। साम्राज्यवादियों, जमींदारों, अफसरशाह दलाल-पूँजीपतियों तथा क्वोमिंताङ के दक्षिणपक्ष ने एक प्रतिक्रांतिकारी गठबंधन की स्थापना की, जिसकी ताकत क्रांति से कई गुना ज्यादा थी । इसलिए क्रांति की लहर उतार पर आ गई ।

क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी शासन ने राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग के

सामंती पाशविकता का एक लोमहर्षक दृश्य

प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध ने चीनी जनवादी क्रांति के निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों को सिद्ध किया :

1. आधुनिक चीन में जनवादी क्रांति संयुक्त मोर्चे द्वारा लाई जानी चाहिए, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथ में हो । संयुक्त मोर्चे के बिना क्रान्ति की विजय नहीं हो सकती थी, तथा यदि इसका नेतृत्व मजदूर-वर्ग के हाथ में नहीं हुआ तो संयुक्त मोर्चे ने असफल हो जाना था।

2. चीन की जनवादी क्रान्ति में श्रमिक-वर्ग के नेतृत्व में मुख्य प्रश्न किसान-समस्या का था । क्रान्ति को केवल तभी सफलता मिल सकती थी जब किसान मुख्य क्रान्तिकारी संश्रयकारी के रूप में उसके साथ आ जाते ।

3. चीन में क्रांति का मुख्य रूप सशस्त्र प्रतिक्रान्ति के विरोध में केवल सशस्त्र क्रांति ही हो सकता था; क्रांतिकारी सेना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था ।

प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध में तथा कुल मिलाकर जनवादी क्रांति में यही सब कुछ सफलता की कुंजी था ।

जनवादी क्रांति के रूप में, प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध ने बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिक तथा किसान वर्ग पर एक दूरगामी प्रभाव छोड़ा । कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र सेनाओं के एक हिस्से को नियंत्रित तथा प्रभावित किया; क्वोमिंताङ, साम्राज्यवादियों, जमींदार वर्ग तथा दलाल पूँजीपति वर्ग के प्रतिक्रियावादी चरित्र तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के दोगले चरित्र का पर्दाफाश किया एवं इस प्रकार पार्टी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई तथा दूसरे क्रांतिकारी गृहयुद्ध की आधारशिला रखी ।

प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व यह था कि इसने विश्व-पूँजीवाद की अस्थायी स्थिरता को अस्त-व्यस्त करते हुए उसे करारी चोट पहुँचाई तथा पूर्व के दबे-कुचले लोगों के मुक्ति-आंदोलन को बढ़ावा दिया, तथा इस प्रकार सोवियत-संघ को उसके समाजवादी निर्माण में सहयोग दिया ।

लेनिन ने एक बार कहा था **''1905 के 'पूर्वाभ्यास' के बिना, 1917 की अक्तूबर क्रांति की सफलता असंभव थी ।[8]''** प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध चीनी क्रांति का एक शानदार पूर्वाभ्यास था ।

●

नोट

1. "For what Are We Struggling Now ?" The Guide, No. 172, Chinese edition.
2. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1971, पृष्ठ-21 से 88 तक ।
3. —वही—पृष्ठ-23
4. —वही—पृष्ठ-40
5. —वही—पृष्ठ-31
6. —वही—पृष्ठ-32
7. —वही—पृष्ठ-41
8. Lenin, Selected Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1952, Vol-II, Part -2, P. 348.

●●●

पाँचवां अध्याय

चीनी क्रांति का उतार
क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों की स्थापना तथा विकास
(अगस्त 1927-सितंबर 1931)

1.

- **सन् 1927 में क्रांति की पराजय के बाद की राजनीतिक परिस्थिति ।**
- **क्रांति की लहर उतार पर ।**

सन् 1924 से 1927 के दरम्यान पूँजीवादी विश्व की स्थिरता की एक मूलभूत कमज़ोरी थी—स्थिरता को सुदृढ़ नहीं किया जा सका था, सच बात तो यह है कि इस स्थिरता में ही एक नए संकट का भ्रूण विद्यमान था ।

इस कालावधि के दौरान पूँजीवादी उत्पादन में हुई वृद्धि का अत्यधिक असाधारण लक्षण यह था कि इस वृद्धि में विषमता थी । संसार के पहले से ज़्यादा देश अपने बढ़े हुए उत्पादन के लिए, बाज़ारों की खोज कर रहे थे, लेकिन बाज़ारों का आकार तथा प्रभाव के क्षेत्र कमोबेश अपरिवर्तित ही रहे । फलतः, बाजारों की समस्या, विशेषकर विदेशी बाज़ारों की समस्या, गंभीर हो गई । इस कालखंड के दौरान, पूँजीवादी देशों के मध्य असंगत अंतर्विरोधों के तीव्रीकरण का यही बुनियादी कारण था ।

यूरोप तथा सुदूर पूर्व में व्यवस्था कायम करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों ने संधियां (वार्सेल्स तथा वाशिंगटन संधियाँ) सम्पन्न करके पूँजीवादी विश्व की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया तथा थोड़े समय के लिए वे इसमें सफल भी हुए । लेकिन विकट बाजार समस्या के कारण अमरीका, बरतानिया, जापान, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी शीघ्र ही प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक बाजारों के बंटवारे के ढंग पर असंतुष्ट हो गए तथा बंटवारे को रद्द समझ लिया गया ।

इसलिए विदेशी बाज़ारों को लेकर, विश्व तथा प्रभाव क्षेत्रों का पुनर्विभाजन साम्राज्यवादियों के मध्य मूलभूत अंतर्विरोध बन गया । पूर्व का बाजार, जिसका केन्द्र चीन था, साम्राज्यवादियों के मध्य कलह का मुख्य मुद्दा था । इस प्रकार अस्थायी तौर पर स्थिर स्थिति से एक नए संकट का जन्म हुआ, जिसने साम्राज्यवादी देशों के मध्य युद्ध को अवश्यम्भावी बना दिया ।

यही कारण था कि सन् 1927 की क्रांति की असफलता के बाद चीन में साम्राज्यवादियों के बीच आपसी संघर्षों में और तेजी आई । और यह क्वोमिंताङ के नए युद्ध-सरदारों के मध्य युद्धों की एक शृंखला के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ । अगस्त 1927 से 1930 की कालावधि के दरम्यान छः बड़े गृहयुद्ध लड़े गए । ये थे—(1) अक्तूबर 1927 में एक तरफ च्याङ

काई-शेक तथा ली चुङ-रन तथा दूसरी ओर, ऊहान के वाङ चिङ-वेइ और थाङ शङ-च के बीच युद्ध; (2) उसी साल दिसंबर में क्वाङतुङ पर कब्जे के लिए च्याङ काई-शेक तथा क्वाङतुङ युद्ध-सरदारों में युद्ध; (3) अप्रैल-मई 1928 में च्याङ काई-शेक, ली चुङ-रन, फङ ग्वी-श्याङ तथा येन शी-शान द्वारा फङथ्येन गुट के युद्ध-सरदार चाङ च्वो-लिन के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध; (4) मार्च व अप्रैल 1929 में मध्य चीन पर कब्ज़े के लिए च्याङ काई-शेक तथा क्वाङसी युद्ध-सरदारों के बीच युद्ध; (5) तथा (6) अगस्त 1929 में तथा अप्रैल 1930 में, च्याङ की फौज तथा फङ और येन की संयुक्त सेनाओं के मध्य दो युद्ध । इसके अतिरिक्त, युन्नान, क्वेइचओ तथा सछ्वान के युद्ध-सरदारों के बीच भी लड़ाइयां हुईं । नए क्वोमिंताङ युद्ध-सरदारों के शासनकाल के पहले तीन वर्षों में देश के बहुत बड़े भाग में युद्धों का ताण्डव जारी रहा, आधुनिक चीनी इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर युद्ध विभीषिका कभी नहीं फैली थी । ये युद्ध साम्राज्यवादी देशों के मध्य अंतर्विरोधों को दर्शाते थे । अंत में, इन युद्धों में अपनी बरतर सैन्य-शक्ति तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के सहयोग के फलस्वरूप च्याङ काई-शेक विजेता के रूप में उभरा ।

साम्राज्यवाद समर्थित नए क्वोमिंताङ युद्ध-सरदारों के शासन ने, च्याङ काई-शेक के प्रतिनिधित्व में, साम्राज्यवादियों के सम्मुख पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया तथा चीन के राष्ट्रीय हितों को सरेआम नीलाम कर दिया । इसके अतिरिक्त, चीनी जनता का दमन करने के लिए वे पूरी तरह सामंती ताकतों पर निर्भर हो गए । क्रांति के साथ गद्दारी करने के बाद, च्याङ काई-शेक ने चीन की कोई भी समस्या हल नहीं की और न ही वह कर सकता था । उलटे वह साम्राज्यवादियों, सामंतवादियों तथा दलाल-पूँजीपतियों का सांझा गुर्गा बन गया ।

कामरेड माओ त्से-तुङ ने च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रियावादी शासन का गहरा तथा स्पष्ट विश्लेषण किया है :

"क्वोमिंताङ के नए युद्ध-सरदारों का वर्तमान शासन अब भी शहरों में दलाल-पूँजीपति वर्ग का और देहाती इलाकों में स्थानीय निरंकुश तत्वों व बुरे शरीफजादों के वर्ग का शासन है। इस शासन ने वैदेशिक मामलों में साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक दिये हैं और घरेलू मामलों में पुराने युद्ध-सरदारों की जगह नए युद्ध-सरदारों को ला खड़ा किया है जिससे मजदूर वर्ग और किसान वर्ग को पहले से और ज्यादा निर्मम आर्थिक शोषण और राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। क्वाङतुङ में जो पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति शुरू हुई थी, वह अभी चल ही रही थी कि दलाल-पूँजीपति वर्ग और स्थानीय निरंकुश तत्वों व बुरे शरीफजादों के वर्ग ने उसका नेतृत्व हथिया लिया और तुरन्त उसे प्रतिक्रान्ति के रास्ते पर मोड़ दिया; पूरे देश के मजदूर, किसान, आम जनता के दूसरे तबके और यहां तक कि पूँजीपति वर्ग (इसका मतलब राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग से है - अनुवादक) अब भी प्रतिक्रान्तिकारी शासन की अधीनता में रहते हैं और उन्हें लेशमात्र भी आर्थिक या राजनीतिक मुक्ति नहीं मिली हुई है ।[1]

कहने का मतलब है कि जहां तक वर्गीय पृष्ठभूमि का सवाल था, क्वोमिंताङ के नए युद्ध-सरदारों का शासन, हू-ब-हू पुराने युद्ध-सरदारों के शासन जैसा ही था, अंतर था तो केवल इतना कि यह पुराने युद्ध-सरदारों के शासन से कहीं ज्यादा पाशविक था । यह एक

दिया । बाद में उन्होंने पार्टी, यूथ लीग तथा ट्रेड-यूनियनों के नेतृत्वकारी संगठनों को सशस्त्र विद्रोहों की तैयारी के लिए कार्यवाही समितियों में मिला दिया, तथा इस प्रकार इन संगठनों का रोज़मर्रा का काम ठप्प पड़ गया ।

लेकिन पार्टी में ली ली-सान की कार्यदिशा का शासन केवल थोड़े दिनों, जून से सितंबर 1930 तक ही चला, क्योंकि जहाँ भी इस नीति को लागू किया गया, पार्टी तथा क्रांतिकारी शक्तियों को निरपवाद रूप से हानि उठानी पड़ी, बहुत से पार्टी-सदस्यों ने इसे सुधारने की मांग की । खासतौर से कामरेड माओ त्से-तुङ ने, अत्यधिक धैर्य के साथ, प्रथम मोर्चा सेना में "वामपंथी" गलतियों को दुरुस्त किया, जिसके फलस्वरूप च्याङशी के क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की लाल सेना, इस कालावधि में न केवल कोई नुकसान उठाने से ही बची रही, बल्कि उसने अनुकूल परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी पाँतों का विस्तार भी किया तथा 1930 के अंत व 1931 के शुरू में च्याङ काई-शेक की पहली घेराबन्दी मुहिम को भी सफलतापूर्वक तहस-नहस कर दिया ।

सितंबर 1930 में पार्टी की छठी केन्द्रीय समिति ने अपना तीसरा पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया । इस अधिवेशन में तथा इसके बाद के काम के दौरान केन्द्रीय समिति ने चीन में क्रांतिकारी स्थिति की अत्यंत "वामपंथी" व्याख्या को, जो ली ली-सान की कार्यदिशा में प्रकट हुई थी, संशोधित किया, सारे देश में विद्रोह आयोजित करने तथा लाल सेना के सभी सैन्य-दलों को बड़े शहरों पर हमला करने के लिए केन्द्रित करने की योजना को रद्द किया तथा पार्टी, यूथ लीग व श्रमिक संगठनों (ट्रेड-यूनियनों) को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में सक्षम, स्वतन्त्र संगठनों के रूप में पुनः सुव्यवस्थित किया इस प्रकार ली ली-सान की कार्यदिशा की उपरोक्त गलतियों को समाप्त करके, तीसरे पूर्ण अधिवेशन ने कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये । अधिवेशन में, कामरेड ली ली-सान ने स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार किया तथा केन्द्रीय समिति में अपने नेतृत्वकारी पद को त्याग दिया । लेकिन चूंकि तीसरे पूर्ण अधिवेशन तथा केन्द्रीय समिति ने ली ली-सान की कार्यदिशा की पूरी तरह आलोचना करने का काम नहीं किया, इसलिए अधिवेशन में तथा बाद में काफी समय तक, पार्टी में कट्टरतावाद जारी रहा, तथा "वामपंथी" धारणाओं तथा नीतियों की अभिव्यक्ति भी बार-बार होती रही ।

जहां भी लाल राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में थी, तथा जहां भी लाल सेना गई, वहां-वहां पर पार्टी की रहनुमाई में जमींदारों की जमीन की जब्ती के लिए संघर्ष करने व उसे किसानों में बाँटने के लिए विशाल किसान समुदाय को गोलबन्द किया गया ।

व्यापक किसान समुदाय को क्रान्तिकारी युद्ध में तथा क्रान्ति के भावी विकास के लिए आधार-क्षेत्र स्थापित करने में भागेदारी निबाहने के लिए केवल तभी तत्पर किया जा सकता था जब ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग-संघर्ष, कृषि-समस्या का सही समाधान करने की स्थिति तक भड़क चुका हो ।

कृषि-समस्या का सही हल, कृषि-क्रान्ति की सही मार्गदर्शक कार्यदिशा पर टिका हुआ था । साथी माओ त्से-तुङ ने चीन की परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण किया तथा ऐसी कार्यदिशा निर्धारित की जिसके अनुसार, जमींदार-वर्ग का सफाया करने के लिए गरीब किसानों व खेत मजदूरों पर भरोसा करते हुए, मध्यम दर्जे के किसानों को साथ मिलाया जाए, धनी-किसानों पर अंकुश रखा जाए तथा छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों व व्यापारियों की

शरद फसल विद्रोह (1927) के नेता

दिसंबर 1927 के कैंटन विद्रोह के बाद कम्युनिस्टों का कत्लेआम

पाँच या छः गुना अधिक थी । इसके अलावा अमरीकी, ब्रिटिश और जापानी साम्राज्यवादियों की तोपों वाली नावों की ओट में, क्वोमिंताङ की अन्य सशस्त्र सेनाओं, पुलिस और मिलिशिया ने भी सभी ओर से कैंटन पर संयुक्त हमला बोल दिया । हाएफङ तथा लूफङ में उठे किसान विद्रोहों से तालमेल बैठा पाने में असफलता ने भी विद्रोह की तत्काल हार में योगदान दिया । श्वेत आतंक का दौर शुरू हो गया । क्वोमिंताङ युद्ध-सरदारों ने लगभग 8000 क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया । इससे यह सिद्ध हो गया कि जब क्रांति उतार पर हो तथा शत्रु सेनाएँ क्रांतिकारी सेना के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हों, ऐसे समय में कैंटन जैसे बड़े शहरों पर ज्यादा समय तक कब्जा जमाए रखना असंभव था ।

शरद-फसल विद्रोह ने किसान वर्ग में पार्टी के प्रभाव को बढ़ाया तथा उन्हें कृषि-क्रान्ति के विचार से गहरे तक प्रभावित किया । जिन सैनिकों, श्रमिक टुकड़ियों तथा किसान आत्म-रक्षा दलों ने बगावत में भाग लिया था, उनके एक हिस्से ने कामरेड माओ त्से-तुङ तथा दूसरे साथियों के नेतृत्व में चीनी श्रमिकों तथा किसानों की लाल सेना का निर्माण किया जो कि जन-मुक्ति सेना की पूर्वगामी थी ।

1927 में क्रांति की असफलता के बाद, पार्टी में मौजूद दक्षिणपंथी अवसरवादी, जिनका नेतृत्व छन तू-श्यू कर रहा था, क्रांति को खत्म करने पर तुल गए । यह सोचते हुए कि च्याङ काई-शेक का प्रतिक्रियावादी शासन स्थाई हो चुका था तथा क्रान्ति पूर्णतया असफल हो चुकी थी । उन्होंने लड़ाई के मोर्चे से सभी सेनाओं को तुरन्त लौटाने तथा सभी क्रांतिकारी संघर्षों को बंद करने की माँग करते हुए पीछे हटने की नीति की पैरवी की तथा "कानूनी आन्दोलन" चलाए जाने का सुझाव दिया । छन तू-श्यू ने निरंकुश ढंग से ज़ोर देकर कहा कि सशस्त्र बगावतों द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना एक बेहद अनुचित कपोल-कल्पना थी । उसने यह प्रस्ताव तक रखा कि किसानों को केवल लगान, टैक्स, लेवियों तथा कर्जों को अदा करने से इन्कार करने तक ही सीमित रहना चाहिए तथा सशस्त्र बगावतों, कृषि-क्रान्ति व कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए । सारांश यह कि, वह और उसके अनुयायी, जनवादी-क्रांति के सर्वहारा नेतृत्व का विरोध कर रहे थे तथा चीनी जनता पर साम्राज्यवादियों, सामंतवादियों और दलाल-पूँजीपतियों का शासन सुदृढ़ करने में मदद कर रहे थे । ऐसा व्यवहार सीधे तौर से पार्टी विरोधी रुख की उपज था ।

इसी समय पार्टी में "वामपंथी" रुझान तेजी से फैला । यह निम्न-पूंजीपति वर्ग के अविवेकपूर्ण व्यवहार का प्रतिबिंब था, जिसे क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की नरसंहार की नीति के प्रति घृणा ने, तथा छन तू-श्यू के आत्मसमर्पणवाद के प्रति विक्षोभ ने और अधिक बढ़ावा दिया । यह रुझान पहले-पहल पार्टी के 7 अगस्त के सम्मेलन में उभरा तथा नवंबर 1927 में हुई केन्द्रीय समिति की विस्तृत मीटिंग में इसने **"वामपंथी" मुहिमजोई**[6] का रूप धारण कर लिया । यह पहला मौका था जब "वामपंथी" कार्यदिशा ने पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्वकारी संगठन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था ।

उस समय छ्वी छ्यू-पाए तथा पार्टी के दूसरे नेताओं ने गलती से जनवादी क्रान्ति को समाजवादी क्रान्ति के साथ गड्ड-मड्ड कर दिया । उन्होंने इस बात को नकार दिया कि क्रान्ति को मंजिल-दर-मंजिल आगे बढ़ना चाहिये तथा जनवादी-क्रान्ति की अपनी कालावधि तथा

में पार्टी के नेतृत्वकारी संगठन पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया ।

"वामपंथी" दुस्साहसवाद के दूसरे भटकाव की गलती के क्या कारण थे ?

प्रथम, कामरेड ली ली-सान तथा उनके अनुयाइयों ने चीनी क्रांति के असमान विकास को नकार दिया तथा दावा किया कि शहरों तथा देहाती क्षेत्रों के संघर्षों में तथा श्रमिक वर्ग आंदोलन व किसान-आंदोलन में कोई आधारभूत अंतर न था, क्योंकि वे सभी समान रूप से संगीन हो गए थे । उनका यह भी मानना था कि केवल बड़े शहरों में किए गए विद्रोह ही राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी उभार ला सकते थे तथा एक या कई प्रांतों में विजय दिला सकते थे । इसलिए उन्होंने पहले ऊहान के इर्द-गिर्द के प्रान्तों में विद्रोहों की रूपरेखा तैयार की । उन्होंने चीनी जनवादी क्रांति में श्रमिक वर्ग के नेतृत्व के अन्तर्गत, किसानों के सामंतवाद विरोधी संघर्ष की निर्णायक भूमिका को वास्तविकता से कम करके आंका। अतः उन्होंने कामरेड माओ त्से-तुङ की धारणा—कि एक लंबी अवधि तक हमें अपना ध्यान देहातों में आधार-क्षेत्रों कायम करने पर लगाना चाहिये, जिससे कि देहातों से शहरों को घेरा जा सके और इन आधार-क्षेत्रों से देशभर में क्रान्तिकारी उभार को तेज किया जा सके—को "पूर्णतया गलत" करार दे दिया।

दूसरे, उन्होंने संगठनात्मक शक्ति इकट्ठी करने तथा क्रांति के लिए पूरी तैयारी करने की आवश्यकता को नकार दिया । उन्होंने सोचा कि क्योंकि क्रांति की शक्तियों ने प्रगति करनी शुरू कर दी थी तथा युद्ध-सरदार परस्पर युद्धों में उलझे हुए थे, अतः सारे देश में तत्काल सशस्त्र विद्रोह शुरू करने के हालात पहले ही पूर्णतया विकसित थे । उनका सोचना था कि पार्टी द्वारा विद्रोह का आह्वान करने पर जनता तुरंत उठ खड़ी होगी । उनका मत था कि जनता को केवल विद्रोह करने चाहिएं, आर्थिक हड़तालें नहीं; तथा केवल बड़ी-बड़ी कार्यवाहियां ही करनी चाहिएं, छोटी नहीं । फलतः उन्होंने भ्रांतिपूर्ण ढंग से इस बात की पैरवी की कि श्रमिकों की राजनीतिक हड़तालों तथा राजनीतिक संघर्षों को तीव्र किया जाए, ताकि हर आर्थिक संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष में बदल जाए, श्रमिकों की सशस्त्र सैन्य-शक्तियों का विस्तार किया जाए तथा राष्ट्रव्यापी विद्रोह के लिए सैनिक प्रशिक्षण को और ज्यादा तेज किया जाए ।

तीसरे, उन्होंने विश्व-क्रांति के असमान विकास को नकार दिया । उनका विचार था कि चीनी क्रांति के सामान्य विस्फोट से विश्व-क्रान्ति का सामान्य विस्फोट होकर रहेगा और विश्व-क्रांति के सामान्य विस्फोट के बिना चीनी क्रान्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती ।

चौथे, उन्होंने चीन की पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति के दीर्घकालीन स्वरूप को अनदेखा किया तथा जनवादी क्रान्ति व समाजवादी क्रान्ति के बीच की सीमा-रेखा को धुंधला कर दिया। उनकी धारणा थी कि जैसे ही एक या कुछ प्रान्तों में विजय प्राप्त होगी, समाजवादी क्रान्ति की ओर संक्रमण शुरू हो जाएगा । फलतः उन्होंने मध्यवर्ती वर्गों के प्रति "वामपंथी" दुस्साहसवादी नीतियां अख्तियार कीं । उनका विचार था कि चीनी पूँजीपति वर्ग की सभी फैक्ट्रियां, कारोबार तथा बैंक "प्रति-क्रान्तिकारी हथियारों" के तौर पर जब्त कर लिये जाएं ।

जून 1930 में, "वामपंथियों" ने देशभर के बड़े-बड़े शहरों में सशस्त्र बगावतें करने तथा इन शहरों पर हमला करने के लिए लाल सेना की सभी यूनिटों को केन्द्रित करने की दुस्साहसवादी योजना की रूपरेखा तैयार की । उन्होंने लाल सेना को नानछाङ, च्योच्याङ छाङशा, ऊहान, क्वेइलिन, ल्यूचओ, तथा कैंटन पर हमला करने व कब्जा करने का आदेश

के कुङआन में दूसरी तथा छठी फौजी कोरों को मिला दिया गया तथा दूसरे सेना ग्रुप का गठन किया गया, जिसके कमांडर हो लुङ थे तथा राजनीतिक कमिसार क्वान श्याङ-इङ थे ।

5. फूच्येन-चच्याङ-च्याङशी आधार-क्षेत्र :- 1927 में क्रान्ति की असफलता के बाद फाङ च-मिन ने पूर्वी च्याङशी के ख्याङ तथा हङफङ में क्रान्तिकारी गतिविधियां जारी रखीं तथा साल के अन्त में एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया । अगले दो वर्षों में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र का विस्तार च्याङशी के उत्तर-पूर्वी हिस्से तक कर दिया गया । 1920 में उत्तरी फूच्येन के किसानों ने, उत्तर पूर्वी च्याङशी के किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर विद्रोह किया । 1929 की सर्दियों में शिनच्याङ में आयोजित 'मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के प्रथम प्रतिनिधि सम्मेलन' के बाद फूच्येन, चच्याङ, आन्ह्वेइ तथा च्याङशी प्रान्तों के नेतृत्वकारी संगठन की स्थापना की गई । मई 1930 में च्याङ काई-शेक का फङ ग्वी-श्याङ तथा येन शी-शान के साथ युद्ध छिड़ने के बाद लाल सेना छिङतेहछन, लोफिङ, चह्वा, फूल्याङ तथा ऊय्वान के तिकोने इलाके में पहुँची तथा वहां जाकर छापामार लड़ाई जारी रखी । 1930 में उत्तरी पूर्वी च्याङशी में मजदूरों तथा किसानों की जन-सरकार तथा दसवीं फौजी कोर का गठन किया गया।

6. क्वाङशी (ग्वीच्याङ नदी-च्वोच्याङ नदी) आधार-क्षेत्र :- अक्तूबर 1929 में च्याङ काई-शेक तथा क्वाङसी के युद्ध-सरदारों के बीच लड़ाई छिड़ जाने के बाद, पार्टी ने ग्वीच्याङ नदी के क्षेत्र में किसान सैन्य-दलों तथा क्वोमिंताङ के सैनिकों की बगावत का नेतृत्व किया तथा दिसंबर में श्रमिकों तथा किसानों की ग्वीच्याङ जन-सरकार व सातवीं फौजी कोर का गठन किया गया । फरवरी 1930 में पार्टी ने च्वोच्याङ नदी के इलाके में स्थित लुङचओ में क्वोमिंताङ सैनिकों के एक हिस्से के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा उन्हें आठवीं फौज कोर के रूप में संगठित किया । इसके बाद इस इलाके में मजदूरों तथा किसानों की जन-सरकार की स्थापना की गई । यद्यपि च्वोच्याङ की क्रांतिकारी सरकार शीघ्र ही धराशायी हो गई, परन्तु ग्वीच्याङ नदी के इलाके में सातवीं फौजी कोर तथा किसान सैन्य-दल अपने संघर्ष में डटे रहे। 1930 में ग्वीच्याङ नदी-क्षेत्र की लाल सेना की मुख्य शक्ति उत्तर की ओर आगे बढ़ी तथा हुनान में लड़ाई लड़ने के बाद केन्द्रीय लाल-सेना से जाकर मिल गई ।

1927 में शरद-फसल विद्रोह से लेकर 1930 के शुरू तक सशस्त्र विद्रोहों के इलाके तथा ग्रामीण क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र च्याङशी, फूच्येन, हुनान, हुपे, आन्ह्वेइ, हनान, क्वाङतुङ, क्वाङशी तथा चच्याङ प्रान्तों के अनेक हिस्सों में फैल गए थे । लाल सेना की संख्या 60,000 तक पहुँच गई थी, जो कि कुछ ही समय बाद एक लाख हो गई थी ।

छठी कांग्रेस के बाद, कुछ समय तक पार्टी का काम संतोषजनक रहा । कामरेड माओ के मार्गदर्शन तथा प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लाल सत्ता कदम-ब-कदम विकसित होती गई । क्वोमिंताङ के नियंत्रण वाले इलाकों में पार्टी संगठन दोबारा खड़े किये गए तथा उनका काम दोबारा कुछ हद तक शुरू किया गया । परन्तु उस समय दुस्साहसवाद के "वामपंथी" विचार अभी भी पार्टी में मौजूद थे । मई 1930 में जब एक ओर च्याङ काई-शेक तथा दूसरी ओर फङ ग्वी श्याङ व येन शी-शान के मध्य युद्ध छिड़ जाने पर घरेलू परिस्थिति क्रान्ति के अनुकूल हो गई, ऐसे में **कामरेड ली** ली-सान के नेतृत्व में "वामपंथी" विचार फिर से मजबूती पकड़ने लगे, जिसकी परिणति दूसरी "वामपंथी" कार्यदिशा के रूप में हुई, जिसने जून 1930

कार्यभार थे । उन्होंने सोचा कि जो कार्यभार एक दूसरी मंजिल में पूरे किये जाने थे, उन्हें जनवादी क्रान्ति में ही पूरा किया जा सकता था ।

उन्होंने चीनी क्रान्ति के "लगातार उभार" पर होने का भ्रान्तिपूर्ण मूल्यांकन किया तथा दावा किया कि 1927 की असफलता के बाद भी क्रांति की लहर उभार पर थी, न कि उतार पर । उनका विचार था कि अनेक प्रान्तों तथा यहां तक कि कुछ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्रों में भी किसान वर्ग के लिए राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनुकूल समय था । इसलिए उन्होंने क्वोमिंताङ के केन्द्रों—हुनान व हुपे; च्याङसू व चच्याङ में विद्रोह करने की योजनाएं तैयार की; यहां तक कि हपे से शुरू करते हुए उत्तरी प्रान्तों तथा उत्तरपूर्व में भी विद्रोह करने की योजनाएं बनाईं । शहरों तथा ग्रामीण इलाकों के संघर्षों में अन्तर को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने भ्रान्तिपूर्वक दावा किया कि शहरों में विद्रोह करने का समय आ गया था । फलतः उन्होंने शंघाई के श्रमिकों को आदेश दिया कि वे पड़ौस की काउंटियों के किसान विद्रोहों के साथ तालमेल बैठाते हुए उठ खड़े हों, तथा नानकिङ के श्रमिकों को आदेश दिया कि वे ईशिङ व ऊशी में किसान विद्रोहों के उठने के बाद कार्यवाही करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयारियां करें । किसान क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों के निर्णायक महत्त्व की अनदेखी करते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदें मुख्यतः बड़े-बड़े शहरों में होने वाले विद्रोहों पर टिकाए रखीं।

वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध असफल हो गया था और कि क्रान्ति उस समय उतार पर थी । इसलिए उन्होंने पीछे हटने के कार्य का पुरजोर विरोध किया तथा लगातार हमला करते रहने की माँग की । उन्होंने जोर दिया कि शहरी श्रमिकों के आर्थिक संघर्षों तथा किसानों के लेवियों व टैक्सों के विरुद्ध संघर्षों को, राजनीतिक संघर्षों तथा सशस्त्र विद्रोहों में बदल दिया जाए; साथ ही उनका कहना था कि इसके लिए किसी तैयारी की कोई जरूरत नहीं थी तथा एक बार विद्रोह शुरू होने के बाद पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था । क्रांति की असफलता के बाद शत्रु की ताकत तथा जनसाधारण की कलान्ति की परवाह न करते हुए, उन्होंने थोड़े से पार्टी सदस्यों तथा क्रांतिकारियों को फौजी जोखिम उठाने का आदेश दिया, जिसमें सफलता की जरा भी उम्मीद नहीं थी । जहाँ कहीं भी पार्टी संगठन तथा पार्टी सदस्य थे, सशस्त्र विद्रोहों के लिए सक्रियता से तैयारी करने के आदेश दिए गए ।

इस भ्रान्तिपूर्ण "वामपंथी" कार्यदिशा की कामरेड माओ त्से-तुङ तथा क्वोमिंताङ के कब्जे वाले इलाकों में काम करने वाले बहुत से दूसरे साथियों द्वारा, शुरू से ही कड़ी आलोचना की गई । फिर भी 1928 के शुरू में इस नीति को तिलांजलि देने से पहले कई स्थानों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा । अतः अप्रैल 1928 में, सारे देश में क्रियात्मक रूप से इस नीति का परित्याग कर दिया गया । ●

3.

● चिङकाङशान पहाड़ों में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना ।

शरद-फसल विद्रोह में भाग लेने वालों ने कामरेड माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में, अक्तूबर 1927 में, हुनान-च्याङशी सीमान्त-क्षेत्र में स्थित चिङकाङशान पहाड़ों की ओर ऐतिहासिक

प्रस्थान किया तथा वहां पर प्रथम क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना की ।

अप्रैल 1928 में कामरेड चू तेह नानछाङ विद्रोह में भाग लेने वाले सैन्य-दल को दक्षिणी हुनान से चिङकाङशान पहाड़ों की ओर ले गए, जहां वह कामरेड माओ के सैन्य-दल से जा मिला, और इस प्रकार चीन में एक नई प्रकार की सेना—**चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल फौज की चौथी सेना**—का निर्माण हुआ ।

अप्रैल से जुलाई 1928 तक, जब दक्षिण में प्रतिक्रियावादी शासन की स्थिरता का दौर था, च्याङ काई-शेक ने च्याङशी और हुनान में अपने सैन्य-दलों को सीमान्त क्षेत्र में तीन घेराबन्दी मुहिमों के लिए केन्द्रित होने का आदेश दिया । हर बार प्रतिक्रियावादी सेनाओं की कम से कम आठ या नौ रेजीमेन्टें, यहां तक कि कभी-कभी अठारह-अठारह रेजीमेन्टें तक तैनात की गईं। तो भी चार रेजीमेन्टों से भी कम सैन्य-शक्ति के बल पर, लाल सेना ने शत्रु से लोहा लिया, उसके "संयुक्त अभियानों" को चकनाचूर किया तथा चिङकाङशान पहाड़ों के आधार-क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान की ।

कामरेड माओ की मार्क्सवादी-लेनिनवादी नीति पर कायम रहने के कारण चिङकाङशान पहाड़ों के क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र का सृजन तथा विकास हुआ ।

इस नीति के दो बुनियादी उसूल थे :

पहला, फौजी कार्यवाहियों में शत्रु का मुकाबला करने के लिए सैन्य-शक्ति को केन्द्रित रखने का उसूल था । अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित रखकर ही लाल सेना अपने से ज्यादा शक्ति वाले दुश्मन का सफाया कर सकती थी, तथा नतीजतन कई काउंटियों तक फैले एक अविभाजित इलाके में क्रान्तिकारी शासन-व्यवस्था कायम करने के लिए जनता को गोलबन्द कर सकती थी । हुनान-च्याङशी सीमान्त-क्षेत्र में लाल सत्ता का अस्तित्व तथा विकास सैन्य-शक्ति को केन्द्रित रखने का ही नतीजा था, जबकि सैन्य-शक्ति के बिखराव या फैलाव वाली कार्यवाहियों में लगभग हमेशा हार का सामना करना पड़ा था । यह सच है कि इस कालावधि में कम या ज्यादा दूरियों के बीच सफल बिखराव या फैलाव के उदाहरण भी सामने आए थे, लेकिन वे कार्यवाहियाँ मोटे तौर पर जनता का दिल जीतने व आधार-क्षेत्र का विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, केवल अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों में ही की गईं थीं । परन्तु यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी था कि प्रतिक्रियावादी सरकार के हालात कैसे थे : उसे राजनीतिक विघटन का खतरा था, या फिर वह अस्थाई स्थिरता के दौर में थी। पहली स्थिति में, अपेक्षाकृत जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ने की रणनीति अपनाना तथा सशस्त्र सैन्य-शक्ति द्वारा काफी विशाल भूभाग में स्वाधीन शासन-व्यवस्था का विस्तार करना संभव था, निस्सन्देह, अपनी स्थिति को हमेशा सुदृढ़ रखना बेहद जरूरी था । परन्तु दूसरी स्थिति में, धीरे-धीरे आगे बढ़ने की रणनीति अपनाना तथा लहरों की तरह सिलसिलेवार आगे बढ़ते हुए आधार-क्षेत्र का विस्तार करने की नीति अपनाना जरूरी था ।

दूसरे, स्थानीय कार्य करते हुए, केन्द्रीय आधार-क्षेत्र को ठोस आधार प्रदान करने के प्रयासों को केन्द्रीकृत करना जरूरी था, कहने का तात्पर्य यह कि सभी प्रयास, श्रमिकों तथा किसानों की जनवादी सरकार स्थापित करने, कृषि-क्रान्ति सम्पन्न करने, जनता की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने तथा कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार करने के चारों तरफ केन्द्रित होने चाहिएं थे । एक लाल स्वाधीन शासन-व्यवस्था करने के लिए ये बुनियादी उसूल थे ।

नेतृत्व का अनुकरण करते हुए कामरेड माओ त्से-तुङ की—ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ने तथा आधार-क्षेत्र स्थापित करने—की नीति के अनुरूप नीति अपनाई । तीन वर्षों के संघर्ष के बाद, सन् 1930 के आरंभ तक, कई इलाकों में, क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों तथा जनता की सशस्त्र सैन्य-शक्तियों, अर्थात् चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना की स्थापना हो गई थी ।

1. केन्द्रीय आधार क्षेत्र :- अक्तूबर 1927 में चिङकाङशान पहाड़ों में पहुँचने पर हुनान-च्याङशी आधार-क्षेत्र की आधारशिला रखी गई । 1 नवम्बर, 1928 में पाँचवीं फौजी कोर के कुछ हिस्से के चिङकाङशान पहाड़ों में माओ त्से-तुङ तथा चू तेह के नेतृत्व वाली चौथी फौजी कोर के साथ आकर मिल जाने से लाल सेना की शक्ति में वृद्धि हुई । शत्रु की नाकेबन्दी तथा घेराबन्दी को तोड़ने के लिए चौथी फौजी कोर दक्षिणी च्याङशी में घुस गई तथा जनवरी 1929 में वहां एक आधार-क्षेत्र की स्थापना कर दी । इसी साल फरवरी तथा दिसंबर के बीच चौथी फौजी कोर तीन बार फूच्येन में घुसी तथा स्थानीय पार्टी संगठनों के साथ मिलकर पश्चिमी फूच्येन आधार-क्षेत्र की स्थापना की । मार्च 1930 में पश्चिमी फूच्येन तथा दक्षिणी च्याङशी में मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों की सरकारों की स्थापना की गई तथा जून में चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना की पहली फौजी कोर का गठन किया गया। अगस्त में पहली तथा तीसरी फौजी कोर को मिलाकर पहली मोर्चा सेना गठित की गई जिसका प्रधान सेनापति, चू तेह को तथा प्रधान राजनीतिक कमिसार माओ त्से-तुङ को बनाया गया ।

2. हुनान-हुपे-च्याङशी आधार-क्षेत्र :- जुलाई 1928 में फिङच्याङ विद्रोह के बाद, पाँचवीं फौजी कोर का गठन किया गया । इस कोर ने हुनान तथा च्याङशी में छापामार लड़ाई जारी रखते हुए हुनान-हुपे-च्याङशी आधार-क्षेत्र की स्थापना की । फरवरी 1930 के बाद लाल सेना दक्षिणी-पूर्वी हुपे में चली गई, जहां उसने छापामार युद्ध जारी रखते हुए तायेह तथा कई दूसरी काउंटियों पर कब्जा कर लिया तथा तीसरी फौजी कोर के रूप में अपना विस्तार किया ।

3. हुपे-हनान-आनह्वेइ आधार-क्षेत्र :- ह्वाङआन तथा माछङ में दो विद्रोह हुए थे; पहला अक्तूबर 1927 में व दूसरा 1928 के शुरू में । ताप्ये पहाड़ इनके लिए केन्द्रीय आधार-क्षेत्र थे । मार्च 1929 में शाङछङ में एक बगावत हुई, जिसके फलस्वरूप दक्षिण-पूर्वी हनान में एक केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की स्थापना हुई । फिर ल्यूआन की बगावत हुई, जिसने उत्तर-पश्चिमी आनह्वेइ में एक केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की स्थापना की । ये तीनों आधार-क्षेत्र हुपे-हनान-आनह्वेइ इलाके के ठीक मध्य में स्थित थे, जिनमें दर्जन से ज्यादा काउंटियां शामिल थीं । फरवरी 1930 में हुपे-हनान-आनह्वेइ विशेष क्षेत्र का गठन किया गया । 1931 में वहां लाल सेना का चौथी मोर्चा सेना के रूप में गठन किया गया तथा श्वी श्याङ-च्येन को उसका कमांडर बनाया गया ।

4. हुङहू-हुनान-पश्चिमी हुपे आधार-क्षेत्र :- लाल सेना ने 1927 के अंत से 1930 के शुरू तक दक्षिणी हुपे में याङत्सी नदी के उत्तर में स्थित, हुङहू झील के इलाके में छापामार लड़ाई जारी रखी, हुङहू आधार-क्षेत्र की स्थापना की तथा छठी फौजी कोर का गठन किया। शरद-फसल विद्रोह के बाद, उत्तरी-पश्चिमी हुनान के शाङच व थायुङ तथा दक्षिणी-पश्चिमी हुपे के एनश तथा होफङ में छापामार युद्ध चलाया गया, जिसके फलस्वरूप हुनान-पश्चिमी हुपे आधार-क्षेत्र की स्थापना हुई तथा दूसरी फौजी कोर का गठन हुआ । 1930 में दक्षिणी हुपे

को राजनीतिक मोर्चे पर दो भटकावों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए । एक ओर तो, क्रांति की शक्तियों को वास्तविकता से कम करके आंकने व इसके भविष्य को देखने या समझने में विफल होने से उपजे निराशावाद का विरोध करना चाहिए; दूसरी ओर इसे मुहिमजोई का विरोध करना था, जो उन साथियों के क्रान्तिकारी उतावलेपन का प्रतिबिंब थी, जो कोई भी छोटा या बारीक काम करने से कतराते थे । संगठनात्मक स्तर पर इसे जनवादी केन्द्रीयता पर जोर देना था व पार्टी की केन्द्रीयता पर बिना जरूरत की पाबंदी का विरोध करना था तथा साथ ही पार्टी के भीतरी जनवाद पर अनुचित पाबन्दी का भी विरोध करना था । निर्देशन के अधीन पार्टी में जनवाद पर सख्ती से अमल किया जाए । फलतः, अतिजनवाद, निरपेक्ष समानतावाद, गैर-संगठनात्मक दृष्टिकोणों तथा व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति के विभिन्न रूपों का हर स्तर पर दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिये । क्योंकि केवल इसी प्रकार एक सच्चे अर्थों में मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया जा सकता था ।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व तथा लाल सेना की उपस्थिति से प्रति-क्रांति के विभिन्न धड़ों में संघर्षों का पूरा लाभ उठाना संभव हो सकता था, जिससे क्रान्तिकारी शक्तियां जिन्दा रह सकती थीं तथा ग्रामीण इलाकों में, जहां दुश्मन की शक्तियां अपेक्षाकृत कमजोर थीं, क्रान्ति विजय प्राप्त कर सकती थी एवम् क्रान्तिकारी शक्तियां वहां लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रख सकती थीं ।

इस प्रकार क्रांति की मनोगत तथा वस्तुगत परिस्थितियों का सही विश्लेषण करके कामरेड माओ एक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचे ।

साम्राज्यवाद के दौर में पूँजीवादी देशों के असमान आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के जिस नियम की व्याख्या कामरेड लेनिन तथा स्तालिन ने की थी, कामरेड माओ त्से-तुङ ने उसे अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती चीन पर बड़े शानदार ढंग से लागू किया तथा ध्यान दिलाया कि श्वेत राजनीतिक सत्ता के घेरे में लाल राजनीतिक सत्ता के मातहत एक या अनेक छोटे-छोटे लाल इलाकों का पैदा हो जाना तथा बढ़ते जाना संभव था, एवम् क्रान्ति पहले तो ग्रामीण इलाकों में, जहां शत्रु की शक्तियां कमजोर थीं, जीत हासिल कर सकती थी तथा बाद में सारे देश में विजयी हो सकती थी, और इस प्रकार उन्होंने चीन के असमान आर्थिक और राजनीतिक विकास के नियम को स्पष्ट किया । यह नया निष्कर्ष, पूँजीवादी देशों के असमान आर्थिक और राजनीतिक विकास के नियम के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त का तथा समाजवाद की पहले एक देश में विजय प्राप्त करने की संभावना के सिद्धान्त का और अधिक विकसित रूप था । यही वह नया निष्कर्ष था जिसने चीनी क्रान्ति को विजयश्री दिलाई । ●

5.

- **केन्द्रीय तथा दूसरे आधार-क्षेत्रों की स्थापना ।**
- **कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दूसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा में सुधार ।**
- **कृषि-क्रान्ति के लिए निर्देशक कार्यदिशा तथा लाल इलाकों में कृषि-नीति।**

शरद-फसल विद्रोह के बाद विकसित हुए सभी क्रांतिकारी सशस्त्र सैन्य-दलों ने सही

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर कामरेड माओ त्से-तुङ ने आधार-क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए सिलसिलेवार कदम उठाए ।

1. चिङकाङशान पहाड़ों में संघर्ष की कालावधि के दौरान, सभी स्तरों पर प्रतिनिधि सम्मेलनों तथा मजदूरों, किसानों व सैनिकों की सरकारों के रूप में एक जनवादी शासन-व्यवस्था की स्थापना की गई । चीन में लागू की जाने वाली यह पहली, सच्चे अर्थों में जनवादी शासन-व्यवस्था थी । एक जनसभा में मजदूरों तथा किसानों की सरकार चुनी जाती थी । कुछ स्थानों में कार्यकारिणी समिति का चुनाव करने के लिए कांग्रेसों का आयोजन भी किया गया। इन कार्यकारी समितियों में स्थानीय सरकार की सत्ता की शक्तियां निहित थीं ।

2. कृषि-क्रान्ति के झण्डे तले, पहले सारी की सारी जमीन जब्त करके उसका मुकम्मिल तौर पर दोबारा बंटवारा किया जाता था । बाद में इस नीति को केवल जमींदारों की जमीन जब्त करके, उसे कस्बाई आधार पर किसानों के बीच बांटने की नीति से बदल दिया गया । कामरेड माओ त्से-तुङ ने **मध्यवर्ती वर्ग**[6] को अपने साथ मिलाने की और पूरा ध्यान दियां । उनका कहना था कि कृषि-क्रान्ति के दौरान इस वर्ग पर किसी भी हालत में जरूरत से ज्यादा प्रहार न किया जाए । क्योंकि एक शत्रुतापूर्ण मध्यवर्ती वर्ग, अपनी सामाजिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमीन के बंटवारे में अड़चन डाल सकता था, अपनी जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल की जानकारी छुपा सकता था, तथा यहां तक कि श्वेत आतंक से सामना होने पर गद्दारी भी कर सकता था ।

3. श्रमिकों तथा किसानों की एक क्रांतिकारी सशस्त्र सेना का निर्माण किया गया । चूंकि लाल सेना श्रमिकों, किसानों, खानाबदोश सर्वहारा तथा सबसे ऊपर शत्रु सेना के बन्दी बनाए गए सैनिकों को मिलाकर बनाई गई थी, अतः सैनिकों को राजनीतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था । पार्टी प्रतिनिधियों की व्यवस्था को लागू किया गया तथा सेना में पार्टी के नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी स्तर पर पार्टी-शाखाएं संगठित की गईं । सेना में जनवादी व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत सैनिकों को गाली देना या उनकी मारपीट करना एकदम निषिद्ध था, तथा अफसरों व सैनिकों के साथ एक जैसा बरताव किया जाता था । लाल सेना ने स्थानीय सैन्य-दलों (लाल रक्षक दल तथा मजदूरों किसानों के विद्रोही दस्ते) को हथियारबन्द करने में सहायता की, ताकि वे प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन कर सकें, कस्बाई सरकारों की रक्षा कर सकें तथा शत्रु से मुठभेड़ के समय लाल सेना को सहयोग दे सकें । बन्दी सैनिकों के विषय में एक सही नीति अपनाई गई, जिसके तहत बन्दी सैनिकों को छोड़ देना तथा घायलों की दवा-दारू करना शामिल था ।

4. पार्टी-संगठनों की स्थापना तथा विस्तार किया गया । कामरेड माओ त्से-तुङ ने पार्टी के सैद्धांतिक कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया तथा सर्वहारा के सैद्धांतिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने व निम्न-पूँजीपति वर्ग के दृष्टिकोण को बदलने के अत्यधिक महत्त्व को स्पष्ट किया, क्योंकि सैद्धांतिक कार्य ही कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की कुंजी था ।

उपरोक्त तथ्य ही वह सही नीति थे जिसके द्वारा आधार-क्षेत्रों की स्थापना तथा विस्तार किया जा सका तथा उन्हें राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी उभार लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सका। कामरेड माओ ने इस नीति को ''चू तेह-माओ त्से-तुङ नीति या **फाङ च मिन**[7] नीति'' का नाम दिया ।

चीनी क्रांति के विकास को संचालित करने वाले नियमों में से एक नियम, जिसकी खोज कामरेड माओ त्से-तुङ ने की थी, यूँ था—**सशस्त्र संघर्ष द्वारा, आधार-क्षेत्र स्थापित करके तथा उनकी संख्या व क्षेत्रफल में वृद्धि करके, क्रांति को पहले ग्रामीण इलाकों में शुरू किया जाए और फिर सशस्त्र, क्रांतिकारी ग्रामीण ज़िलों के माध्यम से घेराबन्दी करके प्रति-क्रांतिकारी सेनाओं के नियंत्रण वाले शहरों पर कब्ज़ा किया जाए ।** ऐसे समय में, जब पार्टी की ताकत शहरों में एक शक्तिशाली शत्रु द्वारा कुचली जा चुकी हो तथा मौजूदा समय में उसके पुनरुत्थान की संभावना भी नहीं हो, यही क्रांति के विकास का नियम है । चिङकाङशान पहाड़ों का आधार-क्षेत्र ऐसे क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों में पहला था ।

चिङकाङशान पहाड़ों को प्रथम आधार-क्षेत्र की स्थापना के लिए चुनने का फैसला निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर लिया गया :

- चिङकाङ पहाड़, लोश्याओ पर्वत-श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित है, जो उत्तर में हुपे, दक्षिण में क्वाङतुङ, पूर्व में च्याङशी तथा पश्चिम में हुनान की सीमाओं तक फैली है । इसलिए चिङकाङशान पहाड़ों में क्रान्तिकारी परिस्थितियों के विकास ने हुनान, हुपे तथा च्याङशी की मजदूर व किसान जनता को निश्चित रूप से प्रभावित करना था ।
- इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत मज़बूत पार्टी संगठन था जिसका जन साधारण तथा स्थानीय सशस्त्र सैन्य-शक्तियों, (जिन्हें संघर्षों का अनुभव था) में जबरदस्त प्रभाव था ।
- आसपास के इलाके की जमीन उपजाऊ व संसाधनों से भरपूर होने के कारण लाल सेना को चन्दा इकट्ठा करने व जरूरत की सामग्री प्राप्त करने में आसानी थी ।
- 250 किलोमीटर के घेरे तथा 40 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में फैले, खड़ी चट्टानों व घने जंगलों द्वारा आरक्षित, ये चिङकाङशान पहाड़, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क केवल पांच तंग रास्तों के जरिये था, लगभग अभेद्य थे ।

चिङकाङशान पहाड़ों पर क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना अत्यधिक ऐतिहासिक महत्त्व की बात थी, क्योंकि इसने क्रान्तिकारी हमले को क्रान्तिकारी ढंग से पीछे हटने के साथ जोड़ दिया था । पीछे हटने की कालावधि में ग्रामीण इलाकों को केन्द्रीय स्थल के रूप में चुना गया, क्योंकि वहां क्रान्तिकारी ताकत को इकट्ठा करना ज्यादा आसान था । कुल मिलाकर यह पार्टी के लिए अत्यधिक सुनियोजित, व्यवस्थित तथा सबसे कम नुकसानदायक पीछे हटना था, क्योंकि पीछे हटने में हिस्सा लेने वाली क्रांतिकारी सैन्य-शक्तियों को बचाए रखने के अलावा, सारे देश में क्रांति के पीछे हटने के लिए भी यह एक सुरक्षा-कवच का काम करता था । यह एक हमला भी था । ऐसी स्थिति में जब क्रांति को अस्थाई हार का सामना करना पड़ा था, क्रांतिकारी हमले को ग्रामीण इलाके में स्थानांतरित करना बिल्कुल ठीक था, जहां प्रतिक्रांति की ताकतें अपेक्षाकृत कमज़ोर थीं, वर्ग अन्तर्विरोध ज्यादा तथा तीव्र थे, तथा क्रांति की जड़ें अपेक्षाकृत अच्छी तरह जमी हुई थीं । शत्रु के सबसे कमजोर ठिकाने पर यह एक अत्यन्त शक्तिशाली आक्रमण था । 1926 में क्रान्ति की हार के बाद चिङकाङशान पहाड़ों की ओर प्रस्थान ने, क्रान्ति की प्रगति के लिए एकमात्र सही मार्ग का द्वार खोल दिया, उस एकमात्र रास्ते का द्वार खोल दिया जिसमें **''एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती थी ।''** ●

हुआ था । **ये अंतर्विरोध साम्राज्यवाद तथा चीनी राष्ट्र के बीच, चीन की नोंच-खसोट के लिए साम्राज्यवादियों के बीच, चीन के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के बीच, जमींदार वर्ग तथा किसान वर्ग के बीच, पूँजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के बीच तथा युद्ध-सरदारों तथा उनकी सेनाओं की पाँतों के बीच के अन्तर्विरोध थे ।** एक-दूसरे से अलग होते हुए भी ये अन्तर्विरोध एक दूसरे से जुड़े हुए थे । पूँजीवाद के आम संकट के आधार से शुरू करते हुए, कामरेड माओ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चीन को लेकर साम्राज्यवादियों का भीषण संघर्ष साम्राज्यवाद तथा चीनी राष्ट्र के बीच के अन्तर्विरोधों को अवश्यम्भावी रूप से तेज करेगा तथा साथ ही स्वयं साम्राज्यवादियों के बीच के अन्तर्विरोधों को भी तेज करेगा, इस प्रकार युद्ध-सरदारों के बीच असंख्य युद्ध भड़केंगे जो कि बदले में अन्तर्विरोधों को और तीव्र करेंगे । इस प्रकार चीनी युद्ध-सरदारों के बीच लगातार लंबे युद्धों तथा फूट के कारण, श्वेत राजनीतिक सत्ता के पूर्ण घेरे में एक या अनेक छोटे-छोटे क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों का आर्विभाव तथा विकास संभव था ।

चौथे, लाल राजनीतिक सत्ता की स्थापना तथा विकास के लिए एक काफी मजबूत नियमित लाल सेना का होना एक अनिवार्य शर्त थी । एक नियमित लाल सेना होने से, शत्रु के आक्रमणों का दो टूक जवाब देने के लिए सशस्त्र सैन्य-शक्तियों को केन्द्रित करना, छापामार युद्ध जारी रखना तथा क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों का विस्तार करना संभव था । लाल सेना जन साधारण को लामबंद भी कर सकती थी तथा क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करने व पार्टी संगठन बनाने में उनकी मदद कर सकती थी ।

पाँचवें, लाल राजनीतिक सत्ता के अस्तित्व व विकास के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का होना एक अनिवार्य शर्त थी । कामरेड माओ ने चिङकाङ पहाड़ों में संघर्ष के दौरान सर्वहारा के सैद्धांतिक नेतृत्व की ज़रूरत के प्रश्न पर जोर दिया, अर्थात् सर्वहारा की विचारधारा को किसान वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग का नेतृत्व करना चाहिए । लाल सेना में सैद्धांतिक संघर्ष चलाने के पार्टी के अनुभवों ने चौथी फौजी कोर की नौंवी पार्टी कांग्रेस में पारित प्रस्ताव का आधार तैयार किया । इस प्रस्ताव में लाल सेना के पार्टी संगठनों में गैर-सर्वहारा विचारों की अभिव्यक्ति तथा स्रोतों का विश्लेषण किया गया तथा इन गलत विचारों को सुधारने के तरीके निर्धारित किये गए । इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण को संचालित करने वाले बुनियादी विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सांगठनिक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया । **पार्टी का निर्माण पक्के तौर पर सैद्धान्तिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पार्टी में गलत विचार पार्टी की गलत राजनीतिक कार्यदिशा का स्रोत थे । एक राजनीतिक परिस्थिति के मनोगतवादी विश्लेषण तथा काम के मनोगतवादी निर्देशन का लाजमी नतीजा या तो दक्षिणपंथी अवसरवाद हो सकता था या फिर ''वामपंथी'' मुहिमजोई । पार्टी में गलत विचारों को सुधारने का सही तरीका यह था कि राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करते समय तथा विभिन्न समस्याओं का निपटारा करते समय मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण तथा विधि अपनाई जाए एवम् सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन व छानबीन के लिए ठोस व्यावहारिक तरीकों का ज्ञान प्राप्त किया जाए । सैद्धांतिक मोर्चे पर व्यक्तिवाद को पराजित करते समय पार्टी**

इस तथ्य ने कि लाल शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी तथा विकसित हो रही थी, साबित कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनता की क्रांतिकारी शक्तियाँ अजेय थीं । इससे चीनी जनता में बड़ी उम्मीदें जागीं, तथा उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति तथा क्रांतिकारी उभार के आगमन को तेज करने की हिम्मत पैदा हुई ।

क्या इस प्रकार देहाती इलाकों में आधार-क्षेत्र स्थापित करके चीनी क्रांति का पुनरुत्थान करने की इस कार्यदिशा के अनुसार कार्यवाही करना तथा क्रांति को राष्ट्रव्यापी विजय दिलाना संभव था ? इस प्रश्न का जवाब, कामरेड माओ ने देहाती इलाकों में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों (लाल सत्ता) के आर्विभाव तथा अस्तित्व के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, हां में दिया ।

प्रथम, अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती चीन में कमज़ोर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा पिछड़ी सामंती अर्थव्यवस्था का सह-अस्तित्व था तथा विशाल मध्यकालीन व पिछड़े देहाती क्षेत्र के साथ थोड़े से आधुनिक औद्योगिक शहर स्थित थे । चीन की अर्थव्यवस्था का विकास पिछड़ेपन तथा विषमता का जीता जागता प्रमाण था, तथा विभाजन की साम्राज्यवादी नीति ने इसे और अधिक गंभीर बना दिया था । चीन की जनवादी क्रान्ति के विकास में इस कारण बहुत ज़्यादा विषमता आई । जैसा कि चीन की अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी तथा एकीकृत नहीं थी, इसलिए चीन के ग्रामीण इलाके जो कुछ हद तक शहरों के मोहताज नहीं थे, आत्मनिर्भर रह सकते थे तथा लम्बे समय तक क्रांति को आश्रय दे सकते थे ! जैसा कि चीन का आर्थिक विकास असमान था, इसलिए साम्राज्यवादी आर्थिक शक्तियों का अनेक दूर-दराज के इलाकों पर सीधा नियंत्रण नहीं था, बल्कि केवल अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, या फिर बिल्कुल ही नहीं था। फलत: चीनी क्रांति के लिए पहले उन इलाकों में विजय पाना संभव था, जहाँ शत्रु की शक्तियाँ अपेक्षाकृत कमजोर थीं ।

दूसरे, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में लाल शासन-व्यवस्था अन्धाधुन्ध तरीके से स्थापित नहीं की जानी थी । पहले यह उन इलाकों में स्थापित की जानी चाहिये थी जो क्रान्ति के प्रभाव में रह चुके थे । जैसे कि हुनान, हुपे, क्वाङतुङ व च्याङशी, जहाँ मजदूर व किसान जनता क्रांतिकारी युद्धों तथा जमींदार वर्ग के विरुद्ध भीषण संघर्षों में फौलाद बन चुकी थी तथा जहाँ श्रमिक संगठन एवं किसान सभाएं स्थापित की जा चुकी थीं । दूसरे शब्दों में, लाल सत्ता के पास इन इलाकों में अपनी स्थापना तथा विकास के लिए बेहतर जनाधार होना था । कामरेड माओ ने इन प्रांतों में से च्याङशी के हालातों का विशेष तौर से विश्लेषण किया—(1) च्याङशी की अर्थव्यवस्था मुख्यत: सामंती थी तथा जमीदारों की सशस्त्र सेनाएँ दूसरे दक्षिणी प्रान्तों की तुलना में सबसे ज़्यादा कमज़ोर थीं । (2) च्याङशी में हमेशा अन्य प्रान्तों के सैनिक रक्षक के रूप में तैनात रहते थे, उन्हें स्थानीय हालातों की जानकारी नहीं होती थी और नतीजतन वे इसकी समस्याओं में खास दिलचस्पी नहीं लेते थे । (3) च्याङशी साम्राज्यवादी प्रभावों से अपेक्षाकृत काफी दूर था अत: यहां देहाती क्षेत्र में बगावतें अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक विस्तृत पैमानों पर हुई थीं ।

तीसरे, लाल राजनीतिक सत्ता लंबे समय तक स्थिर रह सकती थी या नहीं, यह क्रांतिकारी स्थिति के आगे विकास पर निर्भर करता था । क्वोमिंताङ की गद्दारी के बाद, क्रांति की लहर उतार पर थी । लेकिन जिन अंतर्विरोधों ने क्रांति को जन्म दिया था, उनमें से एक भी हल नहीं

4.

- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस ।**
- **चीन में लाल सत्ता का अस्तित्व कायम रखने तथा उसके विकास के बारे में कामरेड माओ का सिद्धान्त ।**

जुलाई 1928 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी छठी राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जिसका मुख्य कार्यभार प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के अनुभवों को सारबद्ध करना तथा संघर्ष के लिए पार्टी की नीतियों, कार्यभारों व कार्यनीतियों को तय करने के लिए मौजूदा समय में क्रान्ति की प्रकृति तथा स्थिति का विश्लेषण करना था ।

कांग्रेस ने पुष्टि की कि चीनी क्रान्ति एक पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति रही थी, जिसका मुख्य कार्यभार साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी, मजदूरों तथा किसानों का जनवादी अधिनायकत्व स्थापित करना था । क्योंकि पहली बात तो यह कि चीन को अभी साम्राज्यवादी दमन से मुक्ति नहीं मिली थी, तथा उसका सच्चा एकीकरण नहीं हो पाया था । दूसरे, सामंती भू-प्रणाली का उन्मूलन नहीं किया जा सका था तथा सामंती ताकतों का सफाया नहीं हुआ था। तीसरे, राजसत्ता अभी भी साम्राज्यवाद-समर्पित ज़मींदार वर्ग तथा दलाल-पूँजीपति वर्ग के हाथ में थी । कांग्रेस ने श्रमिकों तथा किसानों की लोकशाही की स्थापना के लिए एक, **दस-सूत्री कार्यक्रम**[6] सुनिश्चित किया ।

कांग्रेस ने ध्यान दिलाया कि 1927 के बाद क्रांतिकारी लहर उतार पर थी; यह क्रांतिकारी गतिविधियों के दो उभारों के बीच की कालावधि थी । श्रमिकों तथा किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तथा उनके क्रान्तिकारी संगठन छिन्न-भिन्न हो गए थे । क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों में किसानों की छापामार कार्यवाहियां यहां-वहां छिटपुट घटनाओं तक ही सीमित थीं। कांग्रेस ने जोर देकर यह भी कहा कि एक नए उभार का आना अवश्यम्भावी था, क्योंकि जिन अंतर्विरोधों ने चीनी क्रान्ति को जन्म दिया था, उनमें से एक का भी समाधान नहीं हो पाया था, तथा यह कि अंतर्विरोधों के तीव्रीकरण व अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन से ही इसके आगमन को नजदीक लाया जा सकता था ।

इस आधार पर कांग्रेस ने तय किया कि मौजूदा समय में पार्टी की कार्यनीति शहरों में हमलों तथा विद्रोहों का आयोजन करने की न होकर, आने वाले नए क्रान्तिकारी उभार की तैयारी के लिए जनता का दिल जीतने की होनी चाहिये थी ।

कांग्रेस ने दो मोर्चों पर संघर्ष चलाया ।

इसने छन तू-श्यू के दक्षिणपंथी आत्मसमर्पणवाद का पूरी तरह सफाया करते हुए इस बात की पुष्टि की कि छन तू-श्यू ने स्वेच्छा से क्रांतिकारी नेतृत्व का समर्पण किया था । लेकिन छन ने पार्टी की सही नीति को स्वीकारने तथा अपनी गलत नीति को त्यागने से ही मना नहीं किया, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी व कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को क्रान्ति की हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, पार्टी की क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की नीति का भी मिथ्या वर्णन किया। त्रोतस्कीवादियों से गठजोड़ करके उसने एक पार्टी-विरोधी गुट खड़ा किया । अत: नवम्बर 1929 में पार्टी ने छन तू-श्यू को निष्कासित कर दिया ।

कांग्रेस ने "वामपंथी" मुहिमजोई की गलती की भी भर्त्सना की । कांग्रेस का मत था कि बड़े शहरों में, जहां शत्रु सेनाएं प्रबल स्थिति में थीं, "वामपंथियों" द्वारा फरमानशाही के तरीके अपनाकर अन्धाधुंध सशस्त्र विद्रोह करना केवल एक प्रकार का सैनिक दुस्साहसवाद ही था । क्योंकि फरमानशाही के तरीकों से, यानि कि दादागिरी से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता था, जोकि मौजूदा समय में पार्टी के लिए एक बेहद महत्त्वपूर्ण कार्यभार था । अतः "वामपंथी" मुहिमजोई से पार्टी को सबसे गंभीर खतरा था ।

मुहिमजोई, सैनिक दुस्साहसवाद तथा फरमानशाही, ये सभी निम्न-पूँजीवादी "वामपंथी" विचारों का प्रतिबिंब थे, जो कि पार्टी को आम जनता से दूर, अलगाव में ले जाते थे ।

यह सब छठी कांग्रेस का सही व मुख्य पहलू था । परन्तु कांग्रेस की कुछ कमियां तथा गलतियां भी रहीं ।

प्रथम, कांग्रेस ग्रामीण इलाकों के आधार-क्षेत्रों, जनवादी क्रान्ति के दीर्घकालीन स्वरूप, पार्टी के लिए कार्यनीतिक रूप से पीछे हटने की जरूरत तथा खासकर पार्टी की गतिविधियों का केन्द्र शहरों से ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित करने के मुख्य प्रश्न के महत्त्व को ठीक ढंग से समझने में नाकामयाब रही । फलतः पार्टी का केन्द्रीय संगठन शहर में ही रहा तथा पार्टी की गतिविधियाँ भी मुख्यतया शहरों में ही केन्द्रित रहीं ।

दूसरे, यह मध्यवर्ती वर्गों के दोहरे चरित्र तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दरम्यान अन्दरूनी अन्तर्विरोधों का सही आकलन करने में विफल रही, क्योंकि इसकी नज़र में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग उन *"सर्वाधिक खतरनाक शत्रुओं में से एक था जो क्रांति की विजय में बाधक थे ।"* च्याङ काई-शेक के शासन के अन्तर्गत राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की स्थिति तथा दोहरे चरित्र की अनदेखी करके, यह इस वर्ग के राजनीतिक रुझान में परिवर्तन की संभावना का अनुमान लगाने में विफल रही । कांग्रेस ने यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा भी किया कि *"क्वोमिंताङ के सभी धड़े प्रतिक्रियावादी हैं"* तथा उनमें फर्क करने में विफल रही अथवा उनके बीच के अंतर्विरोधों का लाभ उठाने में विफल रही, जिससे कि सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी शत्रु को अलग-थलग करके, उसे अलग से कुचला जा सकता ।

तीसरे, कांग्रेस द्वारा पहली "वामपंथी" कार्यदिशा की आलोचना, मुहिमजोई की गलती तथा कुछ दूसरी छोटी-मोटी गलतियों की ओर ध्यान दिलाने तक ही सीमित रही । यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर गलत कार्यदिशा की आलोचना करने में विफल रही, अर्थात् ऐसी गलत कार्यदिशा के सैद्धान्तिक बुनियादी कारण की गहरी खोजबीन करने के लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख, दृष्टिकोण तथा तरीका अपनाने में असफल रही ।

इन कमियों के कारण तथा असल में कांग्रेस के बाद नेतृत्व "वामपंथियों" के हाथ में रहने के कारण, "वामपंथी" गलतियों को पूरी तरह सुधारा नहीं गया, बल्कि बाद में "वामपंथी" अवसरवादियों ने इन्हें बढ़ावा देते हुए एक पूर्ण गलत कार्यदिशा में विकसित कर डाला ।

कामरेड माओ त्से-तुङ ने पार्टी की छठी कांग्रेस में हिस्सा नहीं लिया, तथापि उन्हें केन्द्रीय समिति का सदस्य चुन लिया गया ।

कांग्रेस के बाद, कामरेड माओ ने व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक, दोनों स्तरों पर चीनी क्रान्ति की उन महत्त्वपूर्ण समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर लिया, जिन्हें कांग्रेस ने बिना हल किये

छोड़ दिया था या फिर जिनका गलत समाधान निकाला था ।

शहरों में ताकतवर शत्रु से हार खाने के बाद, क्रांतिकारी शक्तियों के लिए एकमात्र सही रास्ता यही था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाएँ, जहाँ वे क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित कर सकती थीं तथा शहरों को घेरने व अन्ततः उन पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी ताकत को एकत्र तथा विकसित कर सकती थीं । शरद-फसल विद्रोह के बाद कामरेड माओ त्से-तुङ अपने सैन्य-दल को चिङकाङशान पहाड़ों में ले गए तथा वहां पर क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित करके उन्होंने व्यावहारिक स्तर पर क्रान्ति की एक महत्त्वपूर्ण समस्या को हल कर दिया। लेकिन, क्या क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र अथवा चीन की लाल सत्ता का अस्तित्व कायम रह सकता था तथा उसका विकास हो सकता था ? समूची पार्टी के सामने यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवाल था, जिसका अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया था ।

मौजूदा स्थिति को लेकर पार्टी में कुछ साथियों के बीच दो गलत धारणाएँ मौजूद थीं । पहली, क्रान्ति की शक्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर आँकना तथा प्रति-क्रान्ति की शक्तियों को कम करके आँकना और इस प्रकार क्रान्ति को मुहिमजोई के रास्ते पर ले जाना । दूसरी, क्रान्ति की शक्तियों को कम करके आँकना तथा प्रति-क्रान्ति की शक्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर आँकना और इस प्रकार निराशावाद में डूब जाना । कुछ साथी क्रान्तिकारी उभार को बहुत दूर समझते थे, अतः वे चलती-फिरती छापामार कार्यवाहियों तक ही सीमित रहे तथा आधार-क्षेत्रों की स्थापना करने की परवाह ही नहीं की । इसी तरह कुछ साथी ऐसे भी थे, जो जब भी किसी हार का सामना करते थे या शत्रु द्वारा घेर लिये जाते थे तो हर बार एक ही संदेह प्रकट करते थे, "हम लाल झण्डे को कब तक फहराता रख सकते हैं ?"

फलतः, इस समस्या का वैज्ञानिक मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्लेषण करके, इसकी सैद्धान्तिक व्याख्या करना मौजूदा समय का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य बन गया था । कामरेड माओ ने इस महत्त्वपूर्ण कार्यभार को बड़े शानदार ढंग से पूरा किया ।

मजदूर वर्ग के नेतृत्व में लाल राजनीतिक सत्ता तथा लाल सेना की स्थापना व विकास, अर्ध-औपनिवेशिक चीन में किसान क्रान्ति का सर्वोच्च रूप थे । क्रान्ति को बड़े-बड़े शहरों में जल्दी सफलता नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वे एक लंबे समय से साम्राज्यवादियों तथा सामंती युद्ध-सरदारों के कब्जे में थे । अतः शत्रु के साथ, समय से पहले, निर्णायक मुठभेड़ को टालने के लिए मजदूर वर्ग को अपना हरावल दस्ता निश्चय ही ग्रामीण इलाकों में भेज देना चाहिये था, ताकि दुश्मन के हमलों का प्रतिरोध करने तथा क्रान्तिकारी शक्तियों का विकास करने के लिए किसानों के साथ एक पक्का क्रान्तिकारी संश्रय स्थापित किया जा सके तथा क्रान्तिकारी रणनीति के अनुसार राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधार-क्षेत्र स्थापित किये जा सकें ।

क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों तथा लाल सेना की स्थापना व विकास राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी उभार के आगमन में तेजी लाने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक थे । देहात में क्रांति का विकास, पिछड़े ग्रामीण इलाकों को क्रांतिकारी इलाकों में बदल सकता था । देहात में स्थित अपने मजबूत आधार-क्षेत्रों से लाल सेना बड़े तथा मध्यम आकार के शहरों में सभी दिशाओं से शत्रु की घेराबन्दी कर सकती थी तथा बार-बार हमले करके प्रति-क्रांतिकारियों को परेशान कर सकती थी, तथा इस प्रकार शत्रु के मार्ग में विपत्तियों के पहाड़ खड़े कर सकती थी ।

शंघाई, हानखओ तथा कैंटन से छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल नानकिङ में प्रदर्शन करने गए तथा क्वोमिंताङ के पार्टी मुख्यालय तथा राष्ट्रीय सरकार व विदेश मन्त्रालय के दफ्तरों को ध्वस्त कर दिया । शंघाई में छात्रों ने क्वोमिंताङ के नगर निगम मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा मेयर व पुलिस ब्यूरो के प्रधान पर मुकद्दमा चलाने के लिए लोक-अदालत गठित की । देश भर में बहुत से दूसरे स्थानों पर भी स्थानीय क्वोमिंताङ मुख्यालयों तथा स्थानीय सरकारों के दफ्तरों पर छात्रों द्वारा हमले किए गए ।

18 सितम्बर की घटना के बाद, देश की जनता ने, जिसमें शहरी उद्योगपति तथा व्यापारी भी शामिल थे, जापानी सामान का बहिष्कार करने तथा जापान के साथ आर्थिक सम्बन्ध तोड़ने की मुहिम छेड़ दी । 1932 में शंघाई की लड़ाई के दौरान, **'शंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स,' 'बैंकर्स एसोसिएशन,'** तथा **'राष्ट्रीय बैंकर्स गिल्ड'** ने अपने कारोबार स्थगित कर दिये । राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समाचार-पत्रों, जैसे कि शन-पाओ (Shen Pao), ने लेख लिखे, जिनमें मांग की गई कि क्वोमिंताङ सरकार अपना राजनीतिक रवैया बदले, सोवियत-संघ के साथ राजनयिक संबंध पुनः बहाल करे, गृहयुद्ध को समाप्त करे, एक पार्टी की तानाशाही को समाप्त करे तथा अन्य पार्टियों की गतिविधियों से प्रतिबंध हटाये, ताकि जापानी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध सारा राष्ट्र एकजुट हो सके ।

जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा चीन को एकमात्र जापानी प्रभुत्व के अधीन उपनिवेश में बदल देने के प्रयास ने चीन के शासक-वर्गों में गहरी फूट डाल दी ।

अक्तूबर 1931 के आरंभ में, जब जापानी फौज ने ल्याओनिङ तथा चीलिन पर कब्जा करने के बाद हेलुङच्याङ पर हमला किया तो मा चान-शान के नेतृत्व वाली चीनी फौज प्रतिरोध करने के लिए उठ खड़ी हुई ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा जापानी साम्राज्यवादियों का प्रतिरोध करने के आह्वान के जवाब में, 26वीं राह सेना, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिक थे तथा जिसे च्याङ काई-शेक ने च्याङशी में लाल सेना पर हमला करने के लिए भेजा था, ने दिसम्बर 1931 में साथी चाओ पो-शाङ तथा तुङ चन-थाङ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा लाल सेना के पक्ष में चली गई ।

28 जनवरी, 1932 को 19वीं राह सेना ने शंघाई पर जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करना आरंभ कर दिया । शंघाई के मजदूरों, छात्रों तथा अन्य नागरिकों के सहयोग तथा सारे देश की जनता के समर्थन से, उन्होंने दृढ़ता से डटे रह कर जापानी हमलावर सेनाओं को मार भगाया तथा शंघाई पर कुछ ही घंटों में कब्जा करने के जापानी सैन्यवादियों मंसूबों को विफल कर दिया ।

च्याङ काई-शेक, वाङ चिङ-वेइ तथा हू हान-मिन के क्वोमिंताङ गुटों के बीच के अंतर्विरोधों तथा झगड़ों के कारण, सितम्बर 1931 में नानकिङ-कैंटन युद्ध भड़क उठा, जिसकी परिणति उसी वर्ष दिसम्बर माह में च्याङ काई-शेक द्वारा मजबूर होकर गद्दी छोड़ने में हुई ।

30 जनवरी, 1932 को जापानी हमले की आशंका के मद्देनजर, नानकिङ सरकार लोयाङ स्थानांतरित हो गई ।

च्याङ के प्रभुत्व वाली विश्वासघाती नानकिङ सरकार का शासन लड़खड़ा रहा था ।

अगस्त 1931 में, च्याङशी में लाल आधार-क्षेत्रों में केन्द्रीय लाल सेना ने च्याङ

रक्षा की जाए । पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति की मंजिल में, कृषि-क्रान्ति संबंधी पार्टी की यह एकमात्र सही कार्यदिशा थी ।

खेत-मजदूर के पास निरपवाद रूप से कोई जमीन या खेती के औजार नहीं होते थे । वह अपनी श्रम-शक्ति बेचकर गुजारा करता था । अतः खेत-मजदूर देहात के सर्वहारा तथा कृषि-क्रांति का हरावल दस्ता थे । गरीब किसान के पास बहुत कम ज़मीन होती थी तथा उसके पास खेती के उपकरण भी अधूरे होते थे । अतः होता यूँ था कि उसे लगान पर जमीन लेनी पड़ती थी, अपनी श्रम-शक्ति का एक हिस्सा बेचना पड़ता था तथा इस प्रकार शोषण का शिकार होना पड़ता था । इसलिए गरीब किसान वर्ग कृषि-क्रांति का दृढ़ तथा विश्वस्त समर्थक तथा देहात में पार्टी व सर्वहारा वर्ग का सबसे शक्तिशाली समर्थक था । अतः कृषि-क्रान्ति के लिए संघर्ष चलाने में गरीब किसानों व खेत-मजदूरों पर निर्भर करना पार्टी की केन्द्रीय नीति थी ।

मध्यम किसान के पास आमतौर से अपनी जमीन होती थी तथा किसी हद तक खेती के औजार भी होते थे । उसकी आय का जरिया मुख्यतः उसका अपना श्रम ही होता था । आमतौर पर वह दूसरों का शोषण नहीं करता था, बल्कि इसकी बजाय वह खुद साम्राज्यवादियों, जमींदारों तथा पूँजीपतियों के शोषण तथा दमन का शिकार होता था । सामान्यत उसे भी जमीन की जरूरत थी । अतः मध्यम किसान न केवल जनवादी क्रांति में भाग ले सकता था, बल्कि समाजवाद को भी स्वीकार कर सकता था । मध्यम किसान वर्ग सर्वहारा का भरोसेमन्द संश्रयकारी था । मध्यम किसान वर्ग को अपने साथ मिलाना कृषि-क्रांति की एक महत्त्वपूर्ण नीति थी, क्योंकि ऐसा करके ही ज़मीदारों के विरोध पर कारगर ढंग से काबू पाया जा सकता था । इसके अतिरिक्त, कृषि-क्रांति के बाद, देहात की जनता का बड़ा हिस्सा मध्यम किसान वर्ग होता । अतः सभी नीतियों का उन द्वारा समर्थन किया जाना जरूरी था । उनकी बात पर उचित ध्यान दिया जाना जरूरी था । मध्यम किसानों के हितों पर कुठाराघात करने वाले किसी भी प्रयास या कार्यवाही का सख़्ती से विरोध करना जरूरी था ।

धनी किसान के पास अपनी ज़मीन होती थी तथा सामान्यतः उत्पादन के साधन भी काफी मात्रा में उसके पास होते थे । यद्यपि वह खुद भी श्रम करता था, लेकिन उसकी आमदनी का अधिकांश भाग भाड़े के मजदूरों के शोषण, सूदखोरी तथा जमीन के लगान से प्राप्त होता था। धनी किसान एक अर्ध-सामंती शोषक था, लेकिन काफी लंबी कालावधि तक उसके उत्पादन का तरीका लाभदायक हो सकता था । धनी किसान साम्राज्यवाद-विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी संघर्षों में भाग ले सकता था अथवा तटस्थ रवैया भी अपना सकता था । इसलिए धनी किसानों पर अंकुश रखते हुए परन्तु धनी किसान अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के किसी भी रुझान का विरोध करते हुए उसे बनाये रखने की नीति अपनाई गई ।

जमींदार के पास ज़मीन होती थी, लेकिन वह स्वयं श्रम नहीं करता था तथा किसानों के शोषण पर निर्भर करता था । जमींदार सामंती शोषक तथा दमनकारी थे तथा चीन पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व का प्रमुख सामाजिक आधार थे । एक वर्ग के रूप में, ज़मींदार चीनी समाज की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति में बाधक थे तथा क्रांति के कट्टर विरोधी थे । इसलिए एक वर्ग के रूप में उनका सफाया करने तथा एक व्यक्ति के रूप में उन्हें अपनी जिंदगी बसर करने का अवसर देने की नीति अपनाई गई ।

मध्यम तथा छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों के प्रति अपनाई गई एहतियाती नीति जनवादी क्रान्ति की कालावधि में बुनियादी नीति थी, जो कि साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध करने एवं क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी थी ।

कृषि-क्रांति की यह कार्यदिशा पूर्णतया सही थी । तथ्यों से सिद्ध हुआ कि जिन क्षेत्रों में यह कार्यदिशा अपनाई गई, वहाँ विशाल जन-समुदाय को लामबन्द किया गया, सामंती ताकतों का तख्ता पलटा गया तथा कृषि-संघर्ष को सफलतापूर्वक चलाया गया ।

सन् 1928 से 1931 तक, चिङकाङशान पहाड़ों के काल तथा केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की स्थापना के दौर में, कामरेड माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में जनता की क्रांतिकारी कार्यवाहियों तथा रचनात्मक अनुभवों के निचोड़ से पार्टी की कृषि-संबंधी नीति तैयार की गई ।

प्रथम, लाल इलाकों में कृषि-सुधारों के तहत जमीन का बंटवारा जन-सरकार द्वारा बुनियादी स्तर पर ज़मीन के सर्वेक्षण से शुरू हुआ, जिसमें जमीन के कुल क्षेत्रफल, आबादी तथा प्रतिव्यक्ति जमीन के आबंटन का निर्धारण किया गया । इसके बाद एक जन सभा में इस पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसे स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्याङ[9] को बुनियादी इकाई मानते हुए आबादी के अनुसार जमीन का बंटवारा किया गया, बंटवारा इस आधार पर किया गया कि मौजूदा खेतिहार किसान को जमीन आबंटित कर दी गई तथा ज़मीन के क्षेत्रफल तथा किस्म के आधार पर जरूरी पुनर्समायोजन किया गया । लाल इलाकों में कृषि-नीति का यह बुनियादी आधार था ।

दूसरे, जमीन जब्त करने की हद तथा जमीन के स्वामित्व के अधिकार की समस्याएं थीं। मजदूरों तथा किसानों की जन-सरकार ने दो कृषि-कानून लागू किये : **'चिङकाङशान पहाड़ों का कृषि-कानून'** दिसंबर 1928 में लागू किया गया तथा **'शिङक्वो काउंटी का कृषि-कानून'** अप्रैल 1929 में लागू किया गया । पहले कानून में केवल सार्वजनिक जमीन तथा जमींदारों की जमीन ही नहीं, बल्कि सारी जमीन की जब्ती का प्रावधान था । लेकिन लाल सेना के चिङकाङशान पहाड़ों से दक्षिणी च्याङशी की शिङक्वो काउंटी में पहुँचने के बाद नए कृषि-कानून में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया : ''सारी की सारी जमीन जब्त करो'' वाली धारा को ''सार्वजनिक जमीन तथा जमींदार वर्ग की जमीन जब्त करो'' की धारा से बदल दिया गया ।

जहां तक जमीन की मिलकीयत का सवाल था, दोनों कानूनों में व्यवस्था थी कि जमीन सरकार की मिलकीयत थी, किसानों की नहीं । दूसरे शब्दों में, जमीन पर जमींदार वर्ग की मिलकीयत के बदले राज्य की मिलकीयत हो गई थी । इसी समस्या के साथ ज़मीन की खरीदो-फरोख़्त पर पाबन्दी का सवाल भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ था । संक्षेप में, जमीन किसानों की मिलकीयत नहीं थी, पर वे अपनी सुविधानुसार उसका इस्तेमाल कर सकते थे । लेकिन, 1930 में इन धाराओं में परिवर्तन किया गया तथा ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार किसानों के हाथ में दे दिया गया, तथा उन्हें ज़मीन को बेचने की पूरी आजादी दे दी गई।

तीसरे, कृषि-क्रांति के दौर में, मध्यम या छोटे औद्योगिक या वाणिज्यिक कारोबारों में लगे लोगों को अपने साथ मिलाना आवश्यक था। जनवरी 1929 में लाल सेना के मुख्यालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार, ''शहरों में जिन व्यापारियों ने मेहनत से धीरे-धीरे थोड़ी सी सम्पत्ति अर्जित कर ली थी, उन्हें तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा, जब तक वे सरकार की

बाद अंग्रेजी-अमरीकी सहायता से प्रतिक्रियावादी गृहयुद्ध जारी रखे हुए थी, जापानी साम्राज्यवादियों ने मौके का फायदा उठाते हुए चीन पर हमला कर दिया, जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर थी तथा जिसके पास विशाल बाजार था । उन्होंने उत्तर पूर्वी चीन पर कब्ज़े से शुरुआत की तथा इसे आधार बनाते हुए वे सारे चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे ।

18 सितम्बर 1931 को पूर्वोत्तर में तैनात जापानी सेना ने अचानक शनयाङ (मुकदन) पर हमला कर दिया। च्याङ ने चीनी सेना को किसी तरह का भी प्रतिरोध न करने का आदेश दिया। च्याङ के आदेशों का पालन करते हुए, शनयाङ तथा पूर्वोत्तर के अन्य इलाकों में स्थित चीनी सेना, चीन की विशाल दीवार के दक्षिण में पीछे हट गई, तथा इस प्रकार जापानी साम्राज्यवादियों के लिए तीन महीने से भी कम समय में उत्तर पूर्व पर कब्ज़ा करना संभव कर दिया।

20 जनवरी, 1932 की रात को, जापानी सेना ने शंघाई पर हमला किया । उनका प्रयास था कि शहर पर कब्ज़ा करके, उसे चीन को उपनिवेश बनाने के लिए, दूसरे आधार-क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाए । सेना तथा शंघाई की जनता बहादुराना लड़ाई के लिए उठ खड़ी हुई, तथा बारम्बार आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया । लेकिन च्याङ काई-शेक ने प्रतिरोध की जड़ें खोदने में कोई कसर न छोड़ी । उस समय आक्रमणकारियों से लोहा ले रही 19वीं राह सेना को शंघाई से हटने पर मजबूर करके, उसने जापान के साथ शंघाई युद्ध-विराम समझौता किया, जिसकी शर्त थी कि चीन शंघाई में अपनी सेनाएं तैनात नहीं करेगा तथा सारे देश में जापान-विरोधी आंदोलन पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा ।

जापानी साम्राज्यवादियों की दहाड़ती तोपों-बंदूकों ने चीन के विशाल जन-समुदाय को जगा दिया तथा उसकी देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को आन्दोलित किया । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर जनता जापानी साम्राज्यवादियों तथा च्याङ काई-शेक के विरुद्ध एक सशक्त मुहिम में कूद पड़ी ।

उत्तर पूर्व की जनता तथा देशभक्त सैनिकों के एक हिस्से ने, जिनका नेतृत्व तथा सहायता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, जापान-विरोधी स्वयंसेवकों की एक फौज का गठन किया तथा बहादुराना संघर्ष जारी रखा । स्वयंसेवकों द्वारा शुरू की गई छापामार लड़ाई कदम-ब-कदम विशाल पैमाने पर विकसित हो गयी । अनेक कठिनाइयों तथा गतिरोधों के बावजूद छापामार, शत्रु द्वारा उन्हें नेस्तनाबूद करने की कोशिशों को नाकामयाब करने में सफल रहे । इसके अतिरिक्त वे तब तक लड़ते रहे, जब तक कि उत्तर-पूर्व में जापानी-सैन्यवादियों के औपनिवेशिक शासन का अन्त नहीं हो गया ।

अक्तूबर 1931 के आरंभ में, शंघाई के आठ लाख श्रमिकों ने **''जापान का प्रतिरोध करो तथा चीन को बचाओ''** (Resist-Japan-and-Save-China Association) नामक संस्था की स्थापना की तथा यह माँग करते हुए अपने प्रतिनिधि नानकिङ भेजे कि सरकार तत्काल अपनी सेना जापान से लड़ने के लिए भेजे, तथा उनके द्वारा गठित स्वयंसेवक कोर को हथियारों की आपूर्ति करे । पेकिङ में भी श्रमिकों ने **''जापान का प्रतिरोध करो, चीन बचाओ'** संस्था का तथा डाक विभाग के श्रमिकों में स्वयंसेवक टुकड़ियों व प्रचार-दस्तों का गठन किया । दूसरे शहरों में भी मजदूरों द्वारा जापान-विरोधी गतिविधियाँ चलाई गईं ।

28 सितम्बर, 1931 को नानकिङ में छात्रों ने क्वोमिंताङ सरकार के विदेश मन्त्रालय के परिसर को ध्वस्त कर दिया तथा मन्त्री पर हमला किया । 1931 के अन्त में पेकिङ, थ्येनचिन

विशाल पैमाने पर समाजवादी कृषि-व्यवस्था को संगठित करना ।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की पन्द्रहवीं कांग्रेस से, खासतौर से 1928 के आरंभ से, जब अनाज की समस्या गंभीर हो गई, पार्टी ने व्यावहारिक स्तर पर इस नीति का सुसंगत ढंग से अनुपालन किया था ।

यह महान कार्यभार सफल हुआ । देश के कुल किसान परिवारों में सामूहिक किसान परिवारों का अंश 1929 के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 1930 में 23.6 प्रतिशत तथा 1931 में 52.7 प्रतिशत हो गया । 1930 से 1931 के समय के दौरान सोवियत-संघ के ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त परिवर्तन आया तथा कृषि सहकारिता की विजय हुई ।

इस दौर में दुनिया के सभी देशों—पूंजीवादी देशों तथा साथ ही सोवियत-संघ—के आर्थिक हालात में परिवर्तन आया । लेकिन सोवियत संघ में यह परिवर्तन और अधिक आर्थिक विकास के रूप में दृष्टिगोचर हुआ । जबकि पूँजीवादी देशों में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया ।

विश्व आर्थिक संकट ने, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच, विजेता तथा पराजित देशों के बीच, साम्राज्यवादी देशों तथा उपनिवेशों एवं अर्ध-उपनिवेशों के बीच, मज़दूरों तथा पूँजीपतियों के बीच तथा किसानों एवं जमींदारों के बीच के अंतर्विरोधों को और ज्यादा तीव्र कर दिया ।

स्तालिन ने स्पष्ट किया कि पूँजीपति वर्ग आर्थिक संकट का समाधान दो दिशाओं में ढूँढ़ेगा—अपने ही देश में सर्वहारा वर्ग तथा अन्य मेहनतकश जनता को कुचलने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियावादी फासिस्ट तानाशाही की स्थापना द्वारा, तथा जैसे-तैसे रक्षित देशों की कीमत पर उपनिवेशों तथा प्रभाव-क्षेत्रों के पुनर्बंटवारे के लिए युद्ध को भड़का कर ।

जापान को, जिसका अपना घरेलू बाजार बहुत छोटा था, आर्थिक संकट से गंभीर आघात पहुँचा । जापान के शासक वर्ग ने आक्रमणकारी युद्ध को ही अपनी समस्या का अकेला समाधान समझा । जापानी सैन्यवादियों ने यूरोपीय तथा अमरीकी शक्तियों को चीन से खदेड़ने तथा चीन को केवल अपने उपनिवेश में परिवर्तित करने के उद्देश्य से नौ-शक्ति संधि की धज्जियाँ उड़ाते हुए चीन के विरुद्ध युद्ध का डंका बजा दिया ।

स्तालिन ने आगे स्पष्ट किया कि सर्वहारा को केवल क्रांति में समाधान खोजना चाहिए : **"सर्वहारा वर्ग, पूँजीवादी शोषण तथा युद्ध के खतरे से लड़ते हुए, क्रांति के रास्ते से समाधान ढूँढ़ेगा ।"**[1]

जब चीनी सर्वहारा तथा उसकी राजनीतिक पार्टी ने जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा थोंपे गए आक्रमणकारी युद्ध का विरोध करने के लिए समूची जनता का नेतृत्व किया, तब वे राष्ट्रीय क्रांति के युद्ध द्वारा अपने लिए समाधान खोज रहे थे । ●

2.

- **उत्तर पूर्वी चीन पर जापानी साम्राज्यवादियों का कब्जा ।**
- **देश भर में राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन का उत्थान ।**

जब यूरोपीय देश तथा अमरीका अपने आर्थिक संकट की अन्दरूनी कठिनाइयों में उलझे हुए थे, तथा च्याङ काई-शेक सरकार साम्राज्यवादियों के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करने के

आज्ञाओं का पालन करते हैं, तथा अत्यधिक लेवियां व टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे ।" इन लोगों के प्रति पार्टी की यह एहतियाती नीति थी ।

कृषि-सुधारों से, गरीब किसानों व खेत-मजदूरों को आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ हुआ। इन लोगों को, जो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा थे, खेती के लिए ज़मीन दी गई, जिससे उन्होंने अपनी बुनियादी आर्थिक जरूरतें पूरी कीं । क्रांति से पहले के सभी कर्ज़ों को रद्द कर दिया गया । लेकिन इन आर्थिक लाभों की तुलना में राजनीतिक लाभ कहीं अधिक था, क्योंकि अब उन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी ।

ज़मीन के एक समान पुनर्बंटवारे से मध्यम किसानों को भी लाभ हुआ । जिनके पास पर्याप्त ज़मीन न थी उनमें से अधिकांश को पुनर्बंटवारे के बाद पहले से ज़्यादा ज़मीन मिली। उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला, क्योंकि गरीब किसानों तथा खेत-मज़दूरों के साथ वे भी सरकार में भागेदारी कर सकते थे । जिला तथा कस्बाई स्तर की स्थानीय सरकारों में काम करने वालों में लगभग 40 प्रतिशत लोग मध्यम किसान थे ।

कस्बाई सरकार में, जो क्रांति के बाद स्थापित श्रमिकों तथा किसानों की जन-सरकार की निम्नतम इकाई थी, गरीब किसान तथा खेत-मजदूर मुख्य तत्व थे । यह मेहनतकश जनता की सरकार थी तथा सर्वाधिक क्रांतिकारी गरीब किसान तथा खेत-मजदूर इसकी धुरी थे ।

क्योंकि क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र लगातार शत्रु की घेराबन्दी की हालत में रहते थे, अत: हर कस्बे की व्यवस्था फौजी-पद्धति के अनुसार की गई थी । हर कस्बे में, 8 से 50 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार 'बच्चों की कोर', 'यंग पायोनियर्स' (नौजवान पथ प्रदर्शक) या 'लाल रक्षक दल' का सदस्य था । उनका कार्यभार अपने घरों की रक्षा करने के लिए रक्षकों तथा संतरियों की भूमिका निभाना था, जिसके लिए उन्हें आवश्यक सैनिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता था ।

जनता के ये फौजी संगठन लाल सेना के मुख्य शक्ति स्रोत भी थे । इन संगठनों से लाल सेना को कुमुक तथा विस्तार के लिए आधार मिला । ●

6.

- **लाल सेना के निर्माण तथा उसकी रणनीति व कार्यनीति के बुनियादी सिद्धान्त ।**
- **लाल इलाके में च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रियावादी गुट द्वारा की गई तीन घेराबंदी मुहिमों का सफाया ।**
- **चीनी क्रान्ति का नया उभार ।**

सशस्त्र संघर्ष के परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों की स्थापना हुई । सशस्त्र संघर्ष में विजय के बिना, क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार करना अथवा कृषि-क्रांति को आगे बढ़ाना असंभव था । सशस्त्र संघर्ष में सफलता के लिए जनता की एक ऐसी क्रान्तिकारी सेना का होना जरूरी था, जो पुरानी किस्म की सभी सेनाओं से अलग हटकर हो तथा जो सही रणनीति व कार्यनीति के दिशा-निर्देशन में युद्ध करे । लाल सेना के निर्माण

तथा उसकी रणनीति व कार्यनीति के बुनियादी उसूल, इस कालावधि के दौरान कामरड माओ त्से-तुङ द्वारा बड़े ही व्यवस्थित ढंग से व विस्तारपूर्वक सूत्रबद्ध किये गए । ये बुनियादी उसूल, दूसरे फौजी उसूलों के साथ मिलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की फौजी कार्यदिशा बने, जिसका प्रतिनिधित्व साथी माओ ने किया ।

लाल सेना के निर्माण के बुनियादी सिद्धांत क्या थे ?

लाल सेना सर्वहारा विचारधारा द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, जनता के संघर्षों में काम आए तथा आधार-क्षेत्रों के निर्माण में सहायता करे । लाल सेना के निर्माण को संचालित करने वाला यह आधारभूत सिद्धान्त था ।

इस बुनियादी सिद्धांत के आधार पर संगठनात्मक, राजनीतिक तथा विचारधारात्मक स्तर पर, लाल सेना पर पार्टी का नेतृत्व पक्के तौर पर सुनिश्चित किया जाना जरूरी था । लाल सेना में विभिन्न स्तरों पर पार्टी संगठन स्थापित करके तथा राजनीतिक का मिसारों की व्यवस्था को लांगू करके, पार्टी, लाल सेना पर दृढ़ नेतृत्व कायम कर सकती थी तथा उसे पार्टी के कार्यक्रमों व नीतियों को दृढ़ता से लागू करने में सक्षम बना सकती थी । इसके साथ ही, राजनीतिक कार्य के एक ढाँचे को लाल सेना में स्थापित करना तथा मज़बूत करना जरूरी था, जिसका काम लाल सेना को पार्टी के कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में शिक्षित करना, उसमें (लाल सेना में) विद्यमान गैर-सर्वहारा विचारों के खिलाफ संघर्ष करना तथा सेना की मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारात्मक चेतना व लड़ने की क्षमता के स्तर को ऊँचा उठाना था ।

इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, क्रांतिकारी युद्ध चलाने में किसान वर्ग पर भरोसा करना जरूरी था । एक ऐसी सेना की स्थापना करना जरूरी था, जिसकी रीढ़ की हड्डी किसान हों, तथा विशाल पैमाने पर छापामार लड़ाई लड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित किए जाने जरूरी थे । इसलिए लाल सेना का कार्यभार मात्र लड़ाई करना ही नहीं था । जनसाधारण को आंदोलित करना, उन्हें संगठित करना, हथियारबन्द करना, क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करने में उनकी मदद करना तथा पार्टी का निर्माण करना जैसे कामों को भी उसे अपने कन्धों पर लेना था । इन सबके ऊपर, लाल सेना का काम चंदा एकत्र करना था । लड़ाई करना, जनता में काम करना तथा चन्दा/धन इकट्ठा करना—लाल सेना के ये तीन कार्यभार एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हुए थे ।

इसके अतिरिक्त, लाल सेना को यह सुनिश्चित करना था कि फौज तथा राजनीतिक संगठनों के बीच, सेना तथा जनता के बीच तथा अफसरों व सैनिकों के बीच सही संबंध स्थापित हों । शत्रु को छिन्न-भिन्न करने तथा युद्ध-बन्दियों का दिल जीतने के लिए इसके पास एक सही नीति का होना जरूरी था ।

लाल सेना के निर्माण के लिए कामरेड माओ त्से-तुङ के मौलिक सिद्धान्त तथा इस सिद्धान्त से विकसित नियम प्रणाली ने लाल सेना को एक ऐसी अजेय शक्ति तथा क्रान्तिकारी सेना बना दिया, जो कि दूसरी सभी सेनाओं से अलग हटकर थी ।

अगली बात, लाल सेना की रणनीति तथा कार्यनीति के बुनियादी सिद्धांत क्या थे ?

कामरेड माओ त्से-तुङ ने चीन के क्रांतिकारी-युद्ध की निम्नलिखित चार विशेषताओं की व्याख्या की : (1) चीन एक ऐसा विशाल अर्ध-औपनिवेशिक देश है, जिसका राजनीतिक तथा आर्थिक विकास असमान रूप से हुआ था, तथा जो हाल ही में एक महान क्रांति के दौर

के लिए संघर्ष को और तीव्र कर दिया । तीसरी विशेषता इस तथ्य में निहित थी कि इन पूँजीवादी देशों की उद्योग, परिवहन तथा कृषि व्यवस्थाएं उनकी क्षमता से नीचे काम कर रही थीं तथा वहाँ बेरोजगारों की विशाल फौज खड़ी हो गई थी । पूँजीवाद के आम संकट से पहले, पूँजीवादी देशों के लिए औद्योगिक तेजी के वर्षों के दौरान अपने उत्पादक कारोबारों को उनकी पूरी क्षमता पर चलाना तथा बेरोज़गारों की संख्या घटाना संभव होता आया था, लेकिन आम संकट के दौरान, अपेक्षाकृत तेज़ आर्थिक गतिविधियों के वर्षों में भी, विभिन्न कारोबारों की उत्पादक शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था, तथा बेरोज़गारों की फौज लगातार बढ़ती ही चली गई ।

इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी थे जिनसे यह आर्थिक संकट और अधिक गहराया तथा देर तक जारी रहा । पहला, इस संकट ने सभी पूँजीवादी देशों को प्रभावित किया, तथा अमरीका को खासतौर से भारी नुकसान पहुँचाया, जहाँ पर दुनिया का आधे से अधिक उत्पादन तथा खपत होती थी । फलतः कुछ देशों के लिए दूसरों की कीमत पर अपना काम चलाना कठिन हो गया था । दूसरे, सभी कृषि प्रधान देशों में यह संकट कृषि संकट से जुड़ गया था तथा उसने इसे और ज़्यादा जटिल तथा गंभीर बना दिया । तीसरे, एकाधिकारवादी उत्पादक-संघों, जिनका उद्योग पर प्रभुत्व था, ने वस्तुओं की एकाधिकार वाली कीमतें बनाए रखने की भरपूर कोशिश की । इससे उत्पादक-संघों के बाहर के उत्पादकों में व्यापक दिवालियापन आ गया, तथा उपभोक्ताओं के विशाल समुदाय पर जबरदस्त संकट टूट पड़ा एवं जिन्सों के स्टॉक के विपणन में रुकावट आई ।

पूँजीवादी समाज के उत्पादन के संबंधों का, उत्पादन की शक्तियों के सामाजिक चरित्र के साथ इतना अधिक अंतर्विरोध पहले कभी नहीं रहा था ।

इस कालावधि के दौरान, सोवियत-संघ समाजवादी निर्माण में लगा हुआ था, तथा उसका उद्योग व कृषि आगे बढ़ रहे थे ।

सोवियत-संघ में उद्योग, समाजवादी औद्योगीकरण तथा अपने भारी उद्योग के सुदृढ़ीकरण तथा विकास के रास्ते पर सुसंगत तरीके से आगे बढ़ा । 1931 तक, जिस साल जापान ने चीन के विरुद्ध आक्रमणकारी युद्ध आरंभ किया, सोवियत संघ में औद्योगिक उत्पादन सन् 1913 के युद्ध-पूर्व स्तर से 214.7 प्रतिशत बढ़ गया था । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उद्योगों का योगदान 1913 के 42.1 प्रतिशत से बढ़कर 1931 में 66.7 प्रतिशत हो गया । अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग ने प्रमुख भूमिका निभाई । भारी उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन का 55.4 प्रतिशत उत्पादन करते थे । इसलिए कुल मिलाकर उद्योग में इसका प्रमुख स्थान था। समाजवादी औद्योगीकरण की खास बात है पूँजीवादी क्षेत्र तथा छोटे जिन्स के क्षेत्र पर समाजवादी क्षेत्र की विजय । इस दिशा में, सोवियत-संघ ने भी पूर्ण विजय प्राप्त की । 1930 में भारी पैमाने के उद्योगों के कुल उत्पादन का 99.7 प्रतिशत उत्पादन समाजवादी क्षेत्र में होता था । उद्योग में पूँजीवाद के अवशेषों को समाप्त कर दिया गया था ।

सोवियत-संघ की कृषि-व्यवस्था में भी विशेष परिवर्तन आया । सामूहिक कृषि-प्रणाली को भारी सफलता मिली । सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का एक ही रास्ता था, और वह था—राजकीय फार्मों की स्थापना, छोटे किसानों को सामूहिक फार्म बनाने के लिए प्रेरित करने तथा आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल द्वारा,

छठा अध्याय

जापान-विरोधी जनवादी आन्दोलन का उदय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा "वामपंथी" भटकावों का सुधार पार्टी का बोल्शेवीकरण के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होना

(सितम्बर 1931 से दिसंबर 1935)

1.

● 1929 से 1932 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा एक नए युद्ध की आशंका ।

1929 के अंत में पूँजीवादी देशों में अभूतपूर्व पैमाने पर एक अत्यंत विध्वंसकारी विश्व आर्थिक संकट फूट पड़ा । यह संकट लगातार तीन सालों तक और ज्यादा गहराता चला गया। औद्योगिक संकट, कृषि संकट के साथ गुंथा हुआ था, तथा उत्पादन में संकट वाणिज्य तथा वित्त के संकटों से जुड़ा हुआ था, जिस कारण पूँजीवादी देशों में आर्थिक हालात अत्यधिक गंभीर हो गए ।

1932 के अंत तक, अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस का औद्योगिक उत्पादन 1929 के आँकड़ों की तुलना में क्रमश: 53.8, 83.8, 59.8 तथा 69.1 प्रतिशत रह गया था । इस संकट की अवधि तथा गंभीरता ने इसे पहले के सभी संकटों से अलग कर दिया था । पहले के संकट एक या दो साल तक रहे थे, लेकिन यह 1932 के अंत तक भी दूर नहीं हुआ था इसने पूँजीवाद द्वारा एक लंबे समय तक विश्व की जनता का शोषण करके बटोरी गई धन-दौलत को शून्य कर दिया था । इस तरह का गंभीरतम संकट पहले कभी नहीं आया था।

इस आर्थिक संकट में अभूतपूर्व स्थायित्व शक्ति थी क्योंकि यह पूँजीवाद के आम संकट के हालातों में फैला था । आम संकट की पहली निर्णायक विशेषता यह थी कि अक्तूबर समाजवादी क्रांति की सफलता के कारण, अब पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ही एकमात्र, सर्वव्यापक विश्व प्रणाली नहीं रह गई थी, तथा एक नई समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो इसकी विरोधी थी, दिन प्रतिदिन मज़बूत होती जा रही थी । दूसरी विशेषता थी—साम्राज्यवादी औपनिवेशिक व्यवस्था में संकट । औपनिवेशिक तथा अर्ध-औपनिवेशिक देशों में एक जबरदस्त राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन उठ खड़ा हुआ था । बहुत से औपनिवेशिक देशों में इस आंदोलन का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग तथा उसकी राजनीतिक पार्टी के हाथों में जाना शुरू हो गया था । इसके साथ ही इन औपनिवेशिक तथा अर्ध-औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय पूँजीवाद का आविर्भाव तथा विकास हुआ तथा पूँजीवादी देशों के साथ उसकी प्रतिस्पर्द्धा ने औपनिवेशिक बाजार पर कब्जे

से गुज़रा था; (2) शत्रु की ताकत में श्रेष्ठता, (3) लाल सेना की कमज़ोरी तथा छोटा आकार; (4) कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व तथा कृषि-क्रांति ।

इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि जहां एक ओर लाल सेना के विकसित होने तथा अपने शत्रु को हराने की संभावना थी, वहीं दूसरी ओर लाल सेना का तेजी से विकास होना तथा उसके द्वारा अपने शत्रु को तत्काल हरा देना भी असंभव था । वास्तव में, इन विशेषताओं ने क्रान्तिकारी-युद्ध की विभिन्न परिस्थितियों से गलत तरीके से निपटने पर, असफलता की संभावना को भी स्पष्ट किया । इन विशेषताओं से उत्पन्न बुनियादी रणनीतिक तथा कार्यनीतिक सिद्धांत इस प्रकार थे : लोकयुद्ध चलाने के लिए जनता पर भरोसा करना, छापामार युद्ध-प्रणाली तथा छापामार किस्म की चलायमान युद्ध-प्रणाली को लड़ाई के मुख्य तरीकों के रूप में अपनाना, लाल सेना के लिए रणनीतिक रूप से दीर्घकालीन युद्ध तथा अलग-अलग मुहिमों में तत्काल फैसले की लड़ाइयां लड़ने की आवश्यकता, रणनीतिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को कम शक्ति द्वारा, परन्तु अलग-अलग मुहिमों में कमजोर शत्रु को ज्यादा शक्ति द्वारा पराजित करना ।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, शत्रु सेना ताकतवर तथा विशाल थी लेकिन जनता से कटी हुई थी । जबकि लाल सेना कमजोर तथा छोटी थी लेकिन जनसाधारण से पूर्णतया जुड़ी हुई थी । इन हालातों के अन्तर्गत लाल सेना के अस्तित्व, विजय तथा आगे कहे विकास का तब तक प्रश्न ही नहीं पैदा होता था जब तक वह शत्रु की कमजोरियों तथा अपनी अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ नहीं उठाती । इसलिए अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को पराजित करने हेतु, लाल सेना के लिए लोकयुद्ध चलाना निश्चित रूप से जरूरी था, जिसमें मुख्य सैन्य-शक्ति का स्थानीय सैन्य-दलों, नियमित सेना का छापामार तथा मिलिशिया दस्तों व सशस्त्र जनता का निहत्थी जनता से तालमेल हो ।

लाल सेना के लिए छापामार युद्ध-प्रणाली तथा छापामार किस्म के चलायमान युद्ध को लड़ाई के मुख्य तरीकों के रूप में अपनाना ज़रूरी था । रणनीतिक स्तर पर छापामार युद्ध-प्रणाली की विवेचना, निश्चय ही कामरेड माओ द्वारा सैन्य-विज्ञान में किए गए महान योगदानों में से एक है । उनका कहना था :

छापामार-युद्ध क्या है ? यह एक पिछड़े देश, एक बड़े अर्ध-औपनिवेशिक देश में एक लम्बे समय के लिए, अपरिहार्य तथा इसीलिए सशस्त्र शत्रु को पराजित करने तथा अपने मज़बूत गढ़ खड़े करने के लिए जनता की सशस्त्र शक्तियों के लिए संघर्ष की सर्वोत्तम किस्म है ।[10]

छापामार-युद्ध का उसकी उच्चतम सीमा तक विस्तार करना और फिर विशेष हालातों के अन्तर्गत तथा ताकत में वृद्धि होने पर उसे नियमित युद्ध में बदल देना ही एक सही नीति थी। दूसरा क्रांतिकारी गृहयुद्ध, छापामार लड़ाई का नियमित लड़ाई की ओर कदम-ब-कदम विकास पहले ही देख चुका था । लेकिन, कुल मिलाकर, उस समय तक भी लाल सेना छापामार किस्म की चलायमान लड़ाई ही लड़ रही थी ।

क्योंकि ताकत के मामले में, लाल सेना शत्रु से कमजोर थी, अत: तत्काल विजय के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था । इसलिए दीर्घकालीन युद्ध की रणनीति अपनाना तथा कदम-ब-कदम शक्ति के प्रतिकूल संतुलन में परिवर्तन लाना जरूरी था । कार्यवाहिक तथा

कार्यनीतिक निर्देशन का सिद्धांत, तथापि इसके बिल्कुल विपरीत था, और वह था—बचाव न करके, तत्काल फैसला करना । इसके अनेक कारण थे । पहला, लाल सेना के पास हथियारों की, खासकर गोला-बारूद की आपूर्ति के कोई साधन नहीं थे, दूसरे, शत्रु के पास अनेक अलग-अलग दस्ते थे । अगर उनमें से एक के विरुद्ध लड़ते हुए, लाल सेना जल्दी ही विजय प्राप्त करने में असफल रहती, तो दूसरे दस्ते इकट्ठे होकर उस दस्ते को बचाने आ जाते। तीसरे, एक 'घेराबन्दी मुहिम' को तहस-नहस करने के बाद लाल सेना को लगातार जारी हमलों की एक दूसरी शृंखला के लिए खुद को जल्दी से तैयार करना पड़ता था । ये तथा अन्य कारण, किसी भी मुहिम में तत्काल फैसले की जरूरत का निर्धारण करते थे । लम्बे समय तक खिंचने वाली लड़ाइयाँ लाल सेना के हित में न थीं । लाल सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुतों को थोड़ों से हराने तथा कार्यनीतिक रूप से थोड़ों को बहुतों से हराने के लिए यह जरूरी था कि वह अपनी सैन्य-शक्ति को इस प्रकार केन्द्रित करे कि हर लड़ाई में जीतने, अपनी ताकत बचाए रखने, शत्रु का सफाया करने, तथा अन्ततः एक निर्णायक जीत हासिल करने के लिए, उसे संख्या बल की दृष्टि से शत्रु पर पूर्ण श्रेष्ठता हासिल हो ।

यह कामरेड माओ त्से-तुङ ही थे जिन्होंने चीन के क्रांतिकारी युद्ध की इन विशिष्टताओं की खोज की तथा उनसे क्रांतिकारी युद्ध के रणनीतिक तथा कार्यनीतिक उसूल तय किये ।

ये सही रणनीतिक तथा कार्यनीतिक सिद्धांत, संघर्ष के दौरान धीरे-धीरे विकसित हुए थे। चिङकाङशान पहाड़ों में संघर्ष के दौरान कामरेड माओ त्से-तुङ ने छापामार युद्ध की रणनीति तथा कार्यनीति को निर्देशित करने वाले बहुत से सुविख्यात सिद्धांतों को पहले ही निर्धारित कर दिया था, जैसे कि, **''जनता को जागृत करने के लिए उसके बीच अपनी सैन्य-शक्ति को बिखेर दो तथा शत्रु से निपटने के लिए अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित कर लो ।''** तथा **''जब शत्रु आगे बढ़ता है, तो हम पीछे हट जाते हैं; जब शत्रु पड़ाव डालता है तो हम उसे हैरान-परेशान करते हैं ; जब शत्रु थक जाता है, तो हम उस पर हमला कर देते हैं, जब शत्रु पीछे हटता है, तो हम उसका पीछा करते हैं ।''** पहला सिद्धांत छोटे आधार-क्षेत्रों से छापामार युद्ध लड़ने वाली छोटी यूनिटों के लिए था तथा इसका जोर **''सारी की सारी सैन्य शक्ति को टुकड़ों में विभक्त कर देने''** तथा **''टुकड़ों को मिलाकर केन्द्रित करने''** के ढंग पर था । बाद वाले सिद्धांत में रणनीतिक रक्षा तथा रणनीतिक आक्रमण, इन दोनों दौरों की व्याख्या की गई थी तथा रक्षा करने के दौरान रणनीति की दृष्टि से पीछे हटने व रणनीतिक प्रत्याक्रमण करने के दौर भी मौजूद थे । उस समय के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये सीधे-सादे, बुनियादी सिद्धांत थे, जिन्हें लाल सेना के छापामार युद्ध के लिए निर्धारित किया गया था । लाल सेना के छोटी छापामार यूनिटों से विशाल छापामार दस्तों में विकसित हो जाने से तथा च्याङशी के केन्द्रीय आधार-क्षेत्र द्वारा ''घेरा डालने और विनाश करने'' की मुहिमों के खिलाफ चलाई गई जवाबी मुहिमों के दौरान आधार-क्षेत्रों के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण से अन्य बुनियादी सिद्धान्त विकसित हुए, जैसे : ''दुश्मन को भुलावा देकर अपने प्रदेश में दूर तक प्रवेश करने देना,'' सैन्य-शक्तियों का केन्द्रीकरण, चलायमान लड़ाई, तुरंत निर्णय की लड़ाई तथा नेस्तनाबूद करने की लड़ाई ।

पहला, शत्रु को भुलावा देकर अपने प्रदेश में दूर तक प्रवेश करने देना या रणनीति की दृष्टि से पीछे हटना । यह एक योजनाबद्ध रणनीतिक कदम था जिसे एक कमतर सैन्य-दल

साथियों ने चीनी क्रान्ति को ''स्थाई क्रान्ति'' और चीन की क्रान्तिकारी परिस्थिति को ''स्थाई उभार'' मान लिया और इस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित ढंग से पीछे हटने के कार्य का संगठन करने से इन्कार कर दिया, तथा फरमानशाही के तरीके अपनाकर थोड़े से पार्टी सदस्यों और जन-समुदाय के एक छोटे हिस्से के भरोसे समूचे देश में ऐसे बहुत से स्थानीय विद्रोह कराने का गलत प्रयत्न किया, जिनकी सफलता की कोई सम्भावना नहीं थी । 1927 के अन्त में, मुहिमजोई की इस प्रकार की कार्यवाही बड़े पैमाने पर फैली हुई थी । 1928 के आरम्भ में वह धीरे-धीरे ठण्प हो गई, यद्यपि कुछ पार्टी सदस्यों के अन्दर मुहिमजोई का पक्षपोषण करने की भावना फिर भी बनी रही । मुहिमजोई, दुस्साहसवाद ही है ।

6. छोटे जमींदार तथा धनी-किसान ।

7. **फाङ च-मिन :-** कामरेड फाङ च-मिन च्याङशी प्रान्त के ईयाङ नामक स्थान के निवासी तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे, तथा उत्तर-पूर्वी च्याङशी में लाल इलाके के और लाल सेना की दसवीं फौजी कोर के संस्थापक थे । 1934 में उत्तर की ओर अभियान करने में उन्होंने लाल सेना के जापान-विरोधी हिरावल दस्ते का नेतृत्व किया । जनवरी 1935 में क्वोमिंताङ की प्रतिक्रान्तिकारी सेना के विरुद्ध लड़ते समय वे पकड़ लिये गए और जुलाई 1935 में च्याङशी प्रान्त के नानछाङ में वीरतापूर्वक शहीद हो गए ।

8. **दस सूत्री कार्यक्रम :-** जुलाई 1928 में आयोजित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित दस सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया : (1) साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ फेंकना ; (2) विदेशी पूँजी वाले उद्योग-धन्धों तथा बैंकों को जब्त करना; (3) चीन का एकीकरण करना और विभिन्न जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देना; (4) क्वोमिन्ताङ युद्ध-सरदारों की सरकार को उखाड़ फेंकना; (5) मजदूरों, किसानों व सैनिकों की प्रतिनिधि-परिषदों वाली सरकार की स्थापना करना; (6) आठ घण्टे का श्रम-दिन निश्चित करना, तनख्वाह बढ़ाना, बेरोजगारों को सहायता देना, सामाजिक बीमा-व्यवस्था कायम करना, इत्यादि; (7) जमींदार वर्ग की तमाम जमीन को जब्त करना और जमीन का किसानों में बंटवारा कर देना; (8) सिपाहियों के रहन-सहन की स्थिति को सुधारना, सिपाहियों को जमीन और रोजगार देना; (9) तमाम बेजा टैक्सों और तरह-तरह की लेवियों का खात्मा करना और एक समेकीकृत वर्धमान कर-व्यवस्था को लागू करना; और (10) विश्व-सर्वहारा से एकता कायम करना, सोवियत-संघ से एकता कायम करना । (माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, पेकिङ, पहले संस्करण का दूसरा मुद्रण-1971, पृष्ठ-303)

9. **श्याङ :-** यह उस काल में चीन की बुनियादी प्रशासनिक इकाई थी जिसमें कई गांव शामिल होते थे ।

10. माओ त्से-तुङ, संकलित रचनाएं Vol-III, पृष्ठ 60-61, (अंग्रेजी) ।

11. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, दूसरा मुद्रण-1971, पृष्ठ-194

●●●

अपने से श्रेष्ठ शत्रु सेना से सामना होने पर, अपनी ताकत बनाए रखने व जवाबी हमले द्वारा शत्रु को पराजित करने के उपयुक्त मौके की प्रतीक्षा के दृष्टिगत उठाता था । जवाबी हमले की कार्यवाही करने से पहले कुछ ऐसे हालात पैदा किये जाने बेहद जरूरी थे जो क्रान्तिकारी शक्तियों के अनुकूल तथा दुश्मन के प्रतिकूल हों और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में, जवाबी हमला तब तक शुरू नहीं करना चाहिये, जब तक कि निम्नलिखित हालात पैदा न हो जाएं :

- ❑ एक ऐसा क्षेत्र, जहां जनता बेहद या अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रियता से समर्थन करती हो।
- ❑ धरातल फौजी कार्यवाही के अनुकूल हो ।
- ❑ शत्रु के कमजोर स्थलों को पहचान लिया गया हो ।

दूसरे, सैन्य-शक्तियों का केन्द्रीकरण । यह शत्रु-सेनाओं तथा जनता की सैन्य-शक्तियों के बीच आगे बढ़ने तथा पीछे हटने की, तथा आक्रमण व रक्षा की परिस्थिति को उल्ट देने के लिए जरूरी था ताकि रणनीतिक तौर पर श्रेष्ठ शत्रु को, जिसके हाथ में पहलकदमी थी, कार्यनीतिक स्तर पर (मुहिमों तथा लड़ाइयों के स्तर पर) कमजोर तथा निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया जाए । निस्सन्देह सारी की सारी सैन्य-शक्ति का केन्द्रीकरण करना जरूरी नहीं था, क्योंकि सैन्य-शक्तियों के केन्द्रीकरण का एकमात्र उद्देश्य रणभूमि में फौजी-कार्यवाही के लिए पूर्ण अथवा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ सैन्य-शक्ति को सुनिश्चित करना था, इसलिए जनता की सैन्य-शक्ति के एक हिस्से को शत्रु को रोकने या अपेक्षाकृत गौण अथवा पूरक मुहिमों में लगाया जाना भी जरूरी था ।

तीसरे, लाल सेना की फौजी कार्यवाहियों की विशिष्टता चलायमान लड़ाई थी, न कि मोर्चेबद्ध लड़ाई । ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल इलाके का विस्तार छोटा था, लाल सेना संख्या तथा तकनीकी साजोसामान, दोनों की दृष्टि से शत्रु के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थी तथा प्रत्येक आधार-क्षेत्र में लाल सेना के केवल एक ही दस्ते को सारी लड़ाई लड़नी होती थी । इसलिए मोर्चेबद्ध लड़ाई लाल सेना के लिए बुनियादी तौर पर व्यर्थ थी । तथापि, इसे बिल्कुल ही नकारा भी नहीं जा सकता था । रणनीतिक रक्षा के दौरान जब कुछ मुख्य स्थलों की हर हालत में शत्रु को रोके रखकर रक्षा करनी हो, तथा रणनीतिक आक्रमण के दौरान जब हमारा सामना अकेले पड़े हुए शत्रु से हो, तब मोर्चेबद्ध लड़ाई, निस्सन्देह जरूरी तथा संभव थी ।

चौथे, तत्काल फैसले की नीति—इसका अनुसरण अकेली लड़ाइयों या मुहिमों के दौरान किया जाना था । हर लड़ाई कुछ ही घंटों या एक-दो दिनों में अवश्य खत्म कर देनी चाहिये। "शत्रु की कुमुक पर हमला करने के लिए शत्रु के दुर्ग पर घेरा डालने" के उसूल के तहत घेरा डालने की फौजी कार्यवाहियों में कुछ हद तक दीर्घकालीनता के लिए तैयार रहना भी जरूरी था । परन्तु इस दांव का उद्देश्य घिरे हुए शत्रु को हराना नहीं, बल्कि उसकी कुमुक पर प्रहार करना था । और कुमुक के साथ निपटने में भी तुरन्त निर्णय करना जरूरी था ।

पाँचवे, चूंकि व्यावहारिक तौर पर लाल सेना अपनी सारी की सारी सामग्री शत्रु से प्राप्त करती थी, अत: शत्रु का सफाया करना जरूरी था । केवल शत्रु को नेस्तनाबूद करके ही लाल सेना अपनी क्षतिपूर्ति कर सकती थी ।

इन सब बातों से लाल सेना के फौजी उसूलों के एक नए रूप का उदय हुआ, जो विषय-वस्तु में काफी समृद्ध तथा रूप में परिवर्तित थे, लेकिन बुनियादी उसूल वही थे जिन्हें चिङकाङशान पहाड़ों के संघर्ष के दौरान प्रतिपादित किया गया था ।

कामरेड माओ ने उस धारणा का खंडन किया जो इस विश्वास पर आधारित थी कि राष्ट्रव्यापी क्रान्ति के लिए समय आ गया था तथा जिसके अनुसार क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करने से पहले ही जनता को कायल करने की, उसका दिल जीतने की पैरवी की गई थी । दूसरे शब्दों में, जनता को राष्ट्रव्यापी सशस्त्र संघर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए गोलबंद करने की पैरवी की गई थी । यह भ्रांतिपूर्ण धारणा मुख्य रूप से यह समझने में भूल होने के कारण पैदा हुई कि चीन उस समय एक अर्द्ध-उपनिवेश था, जिसके लिए अनेक साम्राज्यवादी शक्तियाँ संघर्षरत थीं ।

कामरेड माओ त्से-तुङ ने लाल शासन-व्यवस्था को, एक अर्ध-उपनिवेश में सर्वहारा के नेतृत्व के अंतर्गत, किसान संघर्ष का सर्वोच्च रूप तथा समस्त देश में क्रांतिकारी लहर के उभार को तेज करने वाला अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कारक माना । उनके लेख—**"एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है"** में इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट किया गया है ।

"सिर्फ इसी तरह हम समूचे देश की क्रान्तिकारी जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोवियत-संघ ने समूची दुनिया में प्राप्त किया है । सिर्फ इसी तरह हम प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के लिए घोर कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं, उनकी बुनियाद को हिला सकते हैं और उनके आन्तरिक विघटन में शीघ्रता ला सकते हैं । और सिर्फ इसी तरह हम सही मायनों में एक ऐसी लाल सेना का निर्माण कर सकते हैं जो आने वाली महान क्रान्ति में हमारा मुख्य हथियार बन सके । संक्षेप में यह कि सिर्फ इसी तरह क्रान्तिकारी उभार को तेज करना संभव है ।"[1]

इस प्रकार लाल शासन व्यवस्था अक्तूबर 1927 से 1931 तक की कालावधि में समय की कसौटी पर खरी उतरी । इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसका विस्तार भी हुआ तथा उसने स्वयं को सुदृढ़ भी किया, तथा क्रान्ति को आगे बढ़ाने में महान योगदान दिया । "एक चिंगारी" से यह पूरे "दावानल" में बदल गई थी ।

घेराबंदी मुहिमों के खिलाफ जवाबी मुहिमों में प्राप्त सफलताओं ने चीनी क्रान्ति को नई बुलंदियों पर पहुँचा दिया । ●

नोट

1. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, दूसरा मुद्रण-1971, पृष्ठ-91-92

2. **पीत श्रमिक-संघ** :- प्रतिक्रियावादी श्रमिक संगठन ।

3. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, दूसरा मुद्रण-1971, पृष्ठ-154-155

4. **श्या तओ-इन** :- श्या तओ-इन ने ऊहान सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, परन्तु उसे कुचल दिया गया था । उसका बचा-खुचा सैन्य-दल दक्षिणी हुनान में इधर-उधर भटकता फिर रहा था, जिसे मजदूरों तथा किसानों की सेना में शामिल कर लिया गया था ।

5. **"वामपंथी" मुहिमजोई** :- 1927 में क्रान्ति की पराजय होने के बाद, थोड़े समय के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक "वामपंथी" मुहिमजोई का रुझान पैदा हो गया । मुहिमजोई के शिकार

घेराबन्दी के खिलाफ, चार जवाबी मुहिमों में लाल सेना द्वारा अर्जित जीत ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया कि कामरेड माओ त्से-तुङ द्वारा प्रतिपादित रणनीति तथा कार्यनीति के ये मार्गदर्शक सिद्धांत ही केवल ऐसे सिद्धान्त थे, जिन्हें, जिन यथार्थ परिस्थितियों में लाल सेना लड़ रही थी, उनके पूर्णतया अनुकूल बनाया गया था ।

पहली घेराबंदी मुहिम, 1930 की सर्दियों में, एक तरफ च्याङ काई-शेक तथा दूसरी ओर येन शी-शान व फङ य्वी-श्याङ के बीच की लड़ाई की समाप्ति के बाद शुरू हुई । तब तक लाल सेना विभिन्न आकार के बहुत से क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित कर चुकी थी । जनता की सैन्य-शक्तियों तथा जनता की सत्ता के इस विकास से भयभीत हो कर, च्याङ काई-शेक ने लाल सेना के केन्द्रीय आधार-क्षेत्र पर हमले करने के लिए एक लाख सैनिकों की फौज भेजी।

शत्रु की फौज च्याङशी में चीआन तथा फूच्येन में च्येननिङ के बीच की लाइन से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर आधार-क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ी । लू ती-फिङ इस मुहिम का प्रधान-सेनापति था । लाल सेना में उस वक्त लगभग 40,000 सैनिक थे, जो कि च्याङशी प्रान्त की निङतू काउंटी में केन्द्रित थे ।

सामान्य परिस्थिति बहुत गंभीर नहीं थी, क्योंकि शत्रु की कोई भी डिवीजन च्याङ की निजी सेना में से नहीं थीं । चाङ ह्वेइ-चान (जो फील्ड कमांडर भी था) तथा थान ताओ-य्वान की कमान में दो डिवीजनें शत्रु की "घेराबंदी-फौज" की मुख्य सैन्य-शक्ति थीं तथा क्रमश: लुङकाङ तथा य्वानथओ में तैनात थीं । लुङकाङ-य्वानथओ क्षेत्र उस स्थान के नजदीक था जहां लाल सेना केन्द्रित थी । लाल सेना की अधिकांश सैन्य-शक्ति को लुङकाङ में एकत्र किया गया क्योंकि वहां की जनता क्रान्ति का समर्थन करती थी तथा धरातल फौजी-कार्यवाहियों के अनुकूल था ।

27 दिसंबर, 1930 को जवाबी हमला शुरू हुआ । एक अप्रत्याशित हमले में, जिसमें लाल सेना ने अपनी सारी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित कर दिया था, चाङ की फौज को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया । थान की फौज का पीछा किया गया । 1 जनवरी, 1931 को जवाबी हमले की कार्यवाही का समापन हुआ । शत्रु की डेढ़ डिवीजन को निष्क्रिय कर दिया गया, तथा चाङ ह्वेइ-चान को बन्दी बना लिया गया । इस प्रकार पहली घेराबन्दी मुहिम समाप्त हुई।

अप्रैल 1931 में च्याङ काई-शेक ने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र के विरुद्ध दो लाख सैनिकों की एक और फौज भेजी । शत्रु ने "हर कदम पर मोर्चेबन्दी करने" की नीति अपनाई तथा चीआन से च्येननिङ के बीच फैले 400 किलोमीटर लंबे लड़ाई के मोर्चे का निर्माण किया । हो इङ-छिन फौज का प्रधान-सेनापति था ।

पहली मुहिम की तरह ही इसमें भी च्याङ की निजी सेना का कोई सैन्य-दल नहीं था। लाल सेना ने (जिसमें लगभग 30,000 सैनिक थे) घेरा डाल रही फौज के कमजोर स्थल, वाङ चिन-य्वी के सैन्य-दल पर हमला करने का फैसला किया । योजना इस प्रकार थी कि वाङ के फूथ्येन का मजबूत गढ़ छोड़ देने तक प्रतीक्षा की जाए तथा जब उसकी फौज प्रस्थान कर रही हो, उसका सफाया कर दिया जाए ।

16 मई, 1931 को मुहिम शुरू हुई । जब वाङ चिन-य्वी फूथ्येन से तुङकू की ओर बढ़ रहा था, लाल सेना ने उस पर ज़बरदस्त हमला किया । लड़ाई जीतने के बाद, लाल सेना ने

फूथ्येन से चलकर शत्रु के दूसरे सैन्य-दलों पर सफलतापूर्वक हमला किया तथा उन्हें धकेलते हुए च्याङशी-फूच्येन सीमा पर च्येननिङ-थाएनिङ क्षेत्र तक ले गई । 16 मई से 30 मई, 1931 तक, 15 दिन की मुहिम में लाल सेना ने 350 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया, पाँच लड़ाइयाँ लड़ीं, 400 किलोमीटर लम्बे लड़ाई के मोर्चे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया तथा 30,000 से अधिक शत्रु सैनिकों का सफाया कर दिया। इस प्रकार दूसरी घेराबन्दी मुहिम को चकनाचूर कर दिया गया ।

जुलाई 1931 में, च्याङ काई-शेक ने लाल सेना को घेरने का तीसरा प्रयास किया । मुहिम में 3,00,000 शत्रु सैनिक उतारे गए तथा च्याङ काई-शेक ने सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से स्वयं मैदान संभाला । क्रमश: हो इङ-छिन, छन मिङ-शू तथा चू शाओ-ल्याङ की कमान में तीन कालमों में आगे बढ़ती हुई शत्रु सेना केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में घुस गई । मुख्य सैन्य-शक्ति, जिसकी संख्या लगभग एक लाख थी, च्याङ की अपनी निजी सेना थी । इसके बाद छन मिङ-शू के सैन्य-दल का नंबर आता था । शेष सभी सैन्य-दल अपेक्षाकृत कमजोर थे ।

दुश्मन ने तूफानी वेग से आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई । इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि लाल सेना को पीछे धकेलकर कानच्याङ नदी तक ले जाए और वहां उसका सफाया कर दे । बेहद सख्त लड़ाई के बाद, एक क्षण भी आराम करने या क्षतिपूर्ति करने की प्रतीक्षा किये बिना, तथा अभी भी शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्ति से बचने तथा उसके कमजोर स्थलों पर हमला करने की नीति अपनाते हुए, लाल सेना च्येननिङ से घूमकर शिङक्वो में दोबारा एकत्र हुई ।

लाल सेना ने शत्रु को हैरान-परेशान करने के लिए आधार-क्षेत्रों की अनुकूल परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया । अगस्त के शुरू में लाल सेना शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्ति से दूर रहते हुए, घूमकर ल्येनथाङ की ओर मुड़ी तथा तीन विजयी लड़ाइयां लड़ीं । दुश्मन के लगभग 30,000 सैनिक मारे गए ।

उस समय शत्रु के जो मुख्य सैन्य-दल पश्चिम तथा दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, सभी घूमकर पूर्व की ओर मुड़ गए तथा एक विशाल तथा सुदृढ़ घेरा डालने के लिए तेजी से दौड़े। लेकिन लाल सेना ने उन्हें एक बार फिर चकमा दिया तथा विश्राम के लिए शिङक्वो काउंटी की सीमाओं में एक बार फिर एकत्र हो गई । उस समय तक शत्रु की सेना पूर्ण रूप से भूख से बेहाल, थककर चूर तथा बुरी तरह निरुत्साहित हो चुकी थीं । उसके पास पीछे लौटने के सिवा और कोई चारा न था । शत्रु की फौज जब पीछे लौट रही थीं, तो लाल सेना ने बड़ी मुस्तैदी से उसका पीछा करके उस पर हमला किया । सितंबर में, पहले वाली मुहिमों की भाँति, तीसरी घेराबन्दी मुहिम भी पूर्णतया असफल हो गई ।

शत्रु की तीन घेराबन्दी मुहिमों का मुकाबला करते हुए लाल सत्ता ने च्याङ काई-शेक के बार-बार के हमलों का, जिनमें लाखों की तादाद में आधुनिकृत सैन्य-शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, मुंहतोड़ जवाब दिया । लाल सेना ने अडिग रहकर, अपना विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण करते हुए अपनी योग्यता तथा शक्ति का परिचय दिया ।

लाल शासन व्यवस्था स्थापित करने के पीछे साथी माओ की बुनियादी धारणा सर्वहारा के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों की स्थापना करके दीर्घकालीन संघर्ष में जूझने की थी । जब पर्याप्त शक्ति संचित कर ली जाती, तब लाल सेना समूचे देश में क्रान्ति की अन्तिम विजय प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आगे बढ़कर शहरों को घेर लेती ।

से शत्रु के साथ एक जुझारू संघर्ष छेड़ दिया । वे सांस्कृतिक मोर्चे पर क्रांति का झंडा उठाए थे। क्वोमिंताङ की सांस्कृतिक "घेराबन्दी मुहिम" विफल हो गई । इस सबसे क्वोमिंताङ की एक अत्यंत घटिया तथा बर्बर शासकीय गुट के रूप में पोल खुल गई तथा यह सिद्ध हो गया कि चीनी सर्वहारा क्रांतिकारी संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता था । नरसंहार की नीति क्वोमिंताङ संस्कृति के खोखलेपन का ही पर्दाफाश करती थी । क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन का नष्ट होना तो दूर की बात थी, बल्कि वह मौजूदा समय का एकमात्र सांस्कृतिक आंदोलन बन गया ।

अक्तूबर 1933 में जब सारी तैयारी हो गई, च्याङ काई-शेक ने पाँचवीं घेराबन्दी मुहिम के लिए दस लाख फौज इकट्ठी की । आधी सैन्य-शक्ति केन्द्रीय लाल इलाके पर सीधे आक्रमण में झोंक दी गई । पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम से पहले, केन्द्रीय लाल इलाके में लाल सेना के विस्तार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जो इतना सफल हुआ कि 1,00,000 श्रमिक तथा किसान मोर्चे पर चले गए । आर्थिक स्थिति की दोबारा बहाली तथा विकास से लाल सेना को रसद की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई थी तथा लोगों के जीवन-स्तर में भी कुछ सुधार हुआ था। कामरेड माओ त्से-तुङ की रणनीति तथा कार्यनीति को लागू करने के परिणामस्वरूप जवाबी घेराबंदी मुहिमों में अनेक जीतें पहले से ही प्राप्त की जा चुकी थीं। क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में चल रहे क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन द्वारा भी लाल सेना को सशक्त सहयोग दिया गया। इसके अतिरिक्त क्वोमिंताङ क्षेत्रों में जापान तथा च्याङ काई-शेक के विरुद्ध जन-आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था तथा उसी समय फूच्येन घटना घटी, जिसके कारण च्याङ काई-शेक को एक से ज्यादा मोर्चों पर लड़ने को विवश होना पड़ा । पार्टी के नेतृत्व में **'सशस्त्र आत्मरक्षा के लिए चीनी जनता की समिति'** (Chines People's Committee for Armed Self Defence) का गठन करने के लिए शंघाई तथा अन्य बड़े शहरों में, प्रारंभिक समितियों की स्थापना की गई, सभी सामाजिक तबकों के गण्य-मान्य लोग इस समिति में शामिल थे तथा सुङ छिङ-लिङ (डॉ० सुन यात-सेन की पत्नी) व मा श्याङ-पो इसका नेतृत्व कर रहे थे । उन्होंने चीनी जनता के जापान-विरोधी युद्ध के लिए एक बुनियादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया । ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में लाल सेना को पाँचवीं घेराबन्दी मुहिम को ध्वस्त कर देना चाहिये था । परन्तु "वामपंथी" अवसरवादी नेता इन हालातों से फायदा उठाने में नाकामयाब रहे तथा खासतौर से पूर्णतया गलत फौजी कार्यदिशा के कारण लाल सेना को गंभीर क्षति उठानी पड़ी।

वे अभी भी अपने उसी दृष्टिकोण से चिपके हुए थे कि सभी साम्राज्यवादी शक्तियाँ संयुक्त रूप से सोवियत-संघ पर हमला करेंगी तथा क्वोमिंताङ के विभिन्न गुट, संयुक्त रूप से चीनी क्रान्ति पर हमला करेंगे । "वामपंथी" कार्यदिशा के नेताओं ने जापानी हमले के कारण पैदा हुई चीन के राष्ट्रीय संकट की अनदेखी की तथा क्वोमिंताङ शासन के संकट के परिमाण व चीनी क्रांतिकारी शक्तियों के विकास को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते रहे'। बिना किसी तथ्यात्मक आधार के उनका मानना था कि पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम क्वोमिंताङ तथा लाल सत्ता के बीच की निर्णायक लड़ाई होगी तथा इस लड़ाई में विजय, एक या अनेक प्रांतों में अथवा समूचे देश में विजय की कुंजी होगी । इससे भी ज्यादा बे-सिर-पैर की बात उनका यह सोचना था कि जैसे ही, कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में श्रमिकों व किसानों का जनवादी

काई-शेक की तीसरी घेराबन्दी मुहिम को चकनाचूर कर दिया, तथा हुपे-हनान-आनह्वेइ आधार-क्षेत्र में भी लाल सेना ने एक जवाबी-घेराबन्दी मुहिम में क्वोमिंताङ की फौज को पराजित कर दिया तथा इस तरह क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों का विस्तार किया । हुपे में हुङहू आधार-क्षेत्र को दोबारा प्राप्त कर लिया गया । शेनशी तथा कानसू की सीमाओं पर लाल छापामार दस्ते हमला करने लगे ।

7 नवम्बर, 1931 को, च्याङशी के रुइचिन नामक स्थान में श्रमिकों, किसानों तथा सैनिकों की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें मजदूरों व किसानों की केन्द्रीय जन-सरकार की स्थापना की घोषणा की गई । कामरेड माओ त्से-तुङ तथा चू तेह को क्रमशः सरकार का अध्यक्ष तथा लाल सेना का प्रधान सेनापति चुना गया ।

कांग्रेस ने मजदूरों व किसानों की जन-सरकार का बुनियादी कानून पारित किया, तथा श्रम कानून, कृषि कानून तथा आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित आज्ञप्तियाँ पारित कीं ।

15 अप्रैल, 1932 को मजदूरों तथा किसानों की केन्द्रीय जन-सरकार ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा जापानी साम्राज्यवादियों को चीन से बाहर खदेड़ने के लिए मजदूरों व किसानों की लाल सेना, तथा तमाम दबी-कुचली विशाल जनता का राष्ट्रीय क्रान्तिकारी युद्ध लड़ने के लिए आह्वान किया ।

क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में जापान-विरोधी तथा च्याङ काई-शेक विरोधी आंदोलन के उभार, क्वोमिंताङ की अन्दरूनी फूट, राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग के जापान-विरोधी रुझान, तीसरी जवाबी घेराबन्दी मुहिम में मजदूरों तथा किसानों की जन-सरकार की स्थापना तथा जापान के विरुद्ध उस की युद्ध-घोषणा; इन सब कारणों के फलस्वरूप, 1931 में जापान द्वारा उत्तर-पूर्व में घुसपैठ करने के बाद, चीन की घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

जापानी साम्राज्यवादी हमले से क्रान्तिकारी शिविर तथा प्रति-क्रांतिकारी शिविर की तुलनात्मक स्थितियों में परिवर्तन आया । चूंकि चीनी जनता का जापान-विरोधी आंदोलन कठिन रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, अतः सारे देश की स्थिति क्रान्ति के अनुकूल थी । यद्यपि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियां अभी भी क्रान्तिकारी शक्तियों से अत्यन्त बढ़-चढ़कर थीं, परन्तु लोग पहले की तरह शासित होने को तैयार नहीं थे; तथा न ही च्याङ काई-शेक गुट पुराने ढंग से शासन जारी रख सकता था । बहुत से विरोधी दल तथा च्याङ विरोधी गुट या तो उसका तख्ता पलटने को सहमत हो गए थे या उन्होंने अपनी तटस्थता की घोषणा कर दी थी । इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति क्रान्ति के अनुकूल तथा प्रतिक्रान्ति के प्रतिकूल थी ।

एक नई क्रांतिकारी परिस्थिति तेजी से पैदा हुई । जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का नारा दिया गया, जिसमें जापानी हमलावरों का मुकाबला करने, च्याङ काई-शेक का विरोध करने एवं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार तथा जापान-विरोधी मित्र सेना की स्थापना करने की मांग की गई। यदि पार्टी ने जनता को ठीक ढंग से लामबन्द करने तथा उसके संघर्ष का नेतृत्व करने, सभी जापान-विरोधी एवं च्याङ विरोधी ग्रुपों को एकबद्ध करने, 19वीं राह सेना को प्रोत्साहित करने तथा श्रमिकों व किसानों की लाल सेना का संयुक्त कार्यवाही करने के लिए नेतृत्व करने की सही कार्यनीति अपनाई होती, तो च्याङ काई-शेक को दोबारा सत्ता में आने से रोका जा सकता था, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार व जापान-विरोधी मित्र सेना की स्थापना की जा सकती थी तथा राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी शक्तियों का जापान के विरुद्ध लड़ाई में नेतृत्व किया जा सकता था । ●

3.

- **तीसरी "वामपंथी" कार्यदिशा का उद्‌भव ।**
- **"वामपंथी" कार्यदिशा के निर्देशन में क्रान्ति के लिए एक लाभकारी परिस्थिति की क्षति ।**

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छठी केन्द्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन के बाद ली ली-सान की कार्यदिशा के कार्यान्वन पर रोक लगा दी गई, लेकिन अव्यावहारिक लोगों का एक ग्रुप, जिसका नेतृत्व साथी वाङ मिङ तथा छिन पाङ-श्येन कर रहे थे, केन्द्रीय समिति के विरोध में उठ खड़ा हुआ । उनका मत था कि ली ली-सान कार्यदिशा *"वामपंथी थोथी बातों के लबादे में एक प्रकार का दक्षिणपंथी अवसरवाद"* था, तथा उन्होंने तीसरे पूर्ण अधिवेशन पर आरोप लगाया कि उसने *"ली ली-सान कार्यदिशा की लगातार चली आ रही दक्षिणपंथी अवसरवादी धारणाओं का पर्दाफाश करने या उनके कार्यान्वन को रोकने अथवा उनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं किया ।"* इसके साथ ही उन्होंने *"मौजूदा समय में पार्टी में दक्षिणपंथी भटकाव के मुख्य ख़तरे को"* समझने में असफल रहने पर केन्द्रीय समिति की निंदा की । उन्होंने पूँजीपतियों तथा धनी किसानों से लड़ने के महत्त्व एवं पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति में "समाजवादी क्रान्ति के" तथाकथित "तत्वों" के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, मध्यम वर्गों के अस्तित्व को नकार दिया, तथा दावा किया कि सारे देश में क्रान्ति की लहर अभी भी उभार पर थी तथा पार्टी के लिए आक्रामक राष्ट्रीय कार्यदिशा अपनाने की जरूरत पर जोर दिया ।

क्रान्तिकारी कार्यभारों को लेकर इस कार्यदिशा के पैरोकारों ने चीन में पूँजीवाद के विकास को वास्तविकता से अधिक आँकने से आरंभ करते हुए, पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष तथा सामंती ताकतों के विरुद्ध संघर्ष के बराबर रख दिया । उनका मत था कि पूँजीपति वर्ग का केवल दृढ़तापूर्वक विरोध करके ही जनवादी क्रान्ति में पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती थी । उन्होंने धनी किसानों की ज़मीन के पुनर्बंटवारे की पैरवी की, जिसमें स्वयं धनी किसानों को निम्न गुणवत्ता की कुछ जमीन आबंटित की जानी थी । उनका यह भी मत था कि मजदूरों-किसानों की सत्ता के अन्तर्गत धनी किसानों तथा पूँजीपतियों को उनके राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाना चाहिए ।

उन्होंने मध्यम वर्गों के अस्तित्व को नकारते हुए जोर देकर कहा कि मध्यम पूँजीपति वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग का ऊपरी तबका, प्रतिक्रांति की पाँतों का ही हिस्सा थे । इसलिए उनके मतानुसार यह असंभव था कि "एक तीसरे ग्रुप" या "एक मध्यवर्ती शिविर" जैसी किसी चीज का भी अस्तित्व हो सकता था । उनके मतानुसार उस समय हो रही जनवादी क्रान्ति में, पूँजीपति वर्ग की भूमिका किसी भी तरह प्रगतिशील नहीं थी, तथा केवल श्रमिक वर्ग, खेत-मजदूर, गरीब किसान, मध्यम किसान तथा शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग का निचला तबका ही चीनी क्रान्ति की शक्तियाँ थे ।

उन्होंने यह दावा करते हुए कि राष्ट्रव्यापी क्रान्तिकारी उभार जारी था, पार्टी के लिए देश भर में आक्रामक रुख अख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया । उनका विश्वास था कि **राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी उभार के अंतर्गत, क्रांति के लिए पहले एक या कई प्रांतों में विजय**

के लिए क्वोमिंताङ ने क्रांतिकारी लेखकों तथा कलाकारों की निन्दा, उत्पीड़न, कैद तथा कत्लेआम करने की घिनौनी नीति अपनाई तथा उनके विरुद्ध गुण्डे, जासूस, ठग तथा हत्यारे भेजे ।

क्वोमिंताङ ने सभी प्रगतिशील पत्रिकाओं तथा पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । कोई भी पुस्तक, यदि उसमें क्रांतिकारी भावना का जरा सा भी पुट होता था, या उसका आवरण-पृष्ठ लाल अक्षरों में होता था, या उसे वामपक्ष के किसी लेखक द्वारा ही लिखा गया होता था, या फिर किसी रूसी लेखक द्वारा लिखा गया था, तो उसे प्रतिबन्धित किया जा सकता था । प्रगतिशील किताबों या पत्रिकाओं को छापने अथवा बेचने वाली अनेकों पुस्तकों की दुकानों को बन्द कर दिया गया था । इसके साथ ही क्वोमिंताङ ने अपनी भरपूर ताकत से लोगों को गुमराह करने तथा उनकी जुझारू-भावना को खत्म करने का प्रयास किया । उसने कन्फ्यूशियस की पूजा तथा प्राचीन "शास्त्रीय ग्रंथों" के पठन को प्रोत्साहित किया तथा फासीवाद का प्रचार किया । क्रांतिकारी लेखकों तथा नौजवान प्रगतिवादियों के ऐसे दमन तथा नरसंहार की मिसाल इतिहास में दूसरी नहीं मिलती । **क्वोमिंताङ द्वारा 1927 में क्रान्ति से गद्दारी करने के बाद से लेकर 1935 तक की कालावधि के दौरान तीन लाख से भी अधिक लोगों की हत्या की गई। लापता या जेलों में डाले गए लोग इस संख्या में शामिल नहीं थे ।**

जब क्वोमिंताङ ने क्रांतिकारी संस्कृति का गला घोंटने व कम्युनिस्ट तथा जनवादी विचारों को "नेस्तनाबूद" करने के लिए बेहद क्रूरतापूर्वक श्वेत आतंक का शिकंजा कस दिया तो क्रांतिकारी सांस्कृतिक मोर्चे के महानतम तथा अडिग योद्धा **लू-शुन** ने, चीनी जनता की ओर

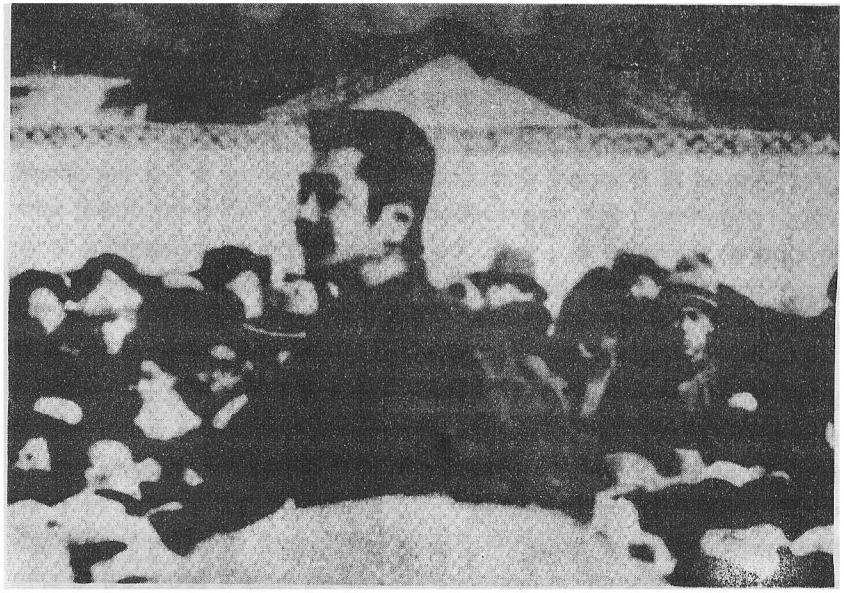

लू शुन (1881-1936) चीन जन-क्रान्ति के सांस्कृतिक योद्धा, जो मानते थे कि कला एवं साहित्य को जनता के क्रान्तिकारी ध्येय की सेवा करनी चाहिये

युद्ध के लिए जनता को गोलबंद करने में भी छाङकाङ तथा छाएशी कस्बों ने अत्यधिक सफलता हासिल की । नौजवानों तथा अधेड़ उम्र के लोगों में से 80 प्रतिशत ने छाङकाङ में, 80 प्रतिशत ने ऊपरी छाएशी में तथा 70 प्रतिशत ने निचली छाएशी में लाल सेना में भर्ती होने या दूसरी प्रकार के क्रान्तिकारी कामों में भाग लेने के लिए अपने घर छोड़ दिये ।

इस उपलब्धि को लोगों के रहन-सहन के स्तर में बेहतरी से अलग करके नहीं देखा जा सकता था । अपने व्यक्तिगत अनुभवों से लोगों को महसूस हुआ कि क्रांतिकारी युद्ध का उनके लिए क्या महत्त्व था । अत: उन सभी ने पार्टी के राजनीतिक आह्वान का जवाब दिया, क्योंकि वे क्रांति को अपना जीवन ही समझते थे ।

5.

- **तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा के निर्देशन में पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम की असफलता ।**
- **चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना का लम्बा रणनीतिक स्थानांतरण।**

चौथी घेराबन्दी मुहिम की विफलता के बाद च्याङ काई-शेक ने साम्राज्यवादियों के समर्थन से पाँचवीं मुहिम के लिए तैयारी शुरू कर दी । यह मालूम होने के बाद कि लाल इलाकों पर हमला करते समय अपनी सेना के कालमों को एक केन्द्र बिन्दु पर चारों तरफ से इकट्ठे होकर हमला करने की कार्यनीति असफल सिद्ध हुई, उसने क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों के खिलाफ व्यापक स्तर पर—मसलन, सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैद्धान्तिक स्तर पर—हमला शुरू कर दिया । च्याङशी के लूशान में उसने अफसर प्रशिक्षण कोर की स्थापना की, जहां अफसरों को फासीवादी राजनीतिक तथा फौजी प्रशिक्षण दिया जाता था, तथा किलेबन्दियों की मदद से लड़ने के व पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई के तरीके भी सिखाए जाते थे। उसने स्थानीय रक्षा दलों का गठन किया, प्रतिक्रियावादी फासीवादी शासन को सुदृढ़ किया, विदेशी कर्जों के लिए अनुबन्ध किये, तथा लाल इलाकों की सख्त आर्थिक नाकेबन्दी कर दी।

रणनीतिक स्तर पर दीर्घकालीन तथा कार्यनीतिक स्तर पर किलेबन्दियों पर आधारित युद्ध शुरू करके च्याङ काई-शेक ने अंतिम सफाया मुहिम के लिए लाल सेना की मुख्य शक्तियों से मुठभेड़ करने से पहले, लाल सेना की मानव-शक्ति के स्त्रोतों तथा उसके साजोसामान व रसद-पानी के संसाधनों को खत्म करने तथा क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की कांट-छांट करने का प्रयास किया ।

लाल-इलाकों के विरुद्ध अपनी फौजी मुहिम के साथ-साथ च्याङ ने सांस्कृतिक घेराबन्दी की मुहिम भी चलाई । इस मुहिम ने क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन के अभूतपूर्व दमन का रूप धारण कर लिया ।

क्रांतिकारी संस्कृति के विरुद्ध ''घेरा डालने तथा विनाश करने'' की मुहिम में सांस्कृतिक हथियारों की जरूरत थी । लेकिन क्वोमिंताङ द्वारा पैरवीकृत विशेष ब्रांड की ''संस्कृति'' के अत्यधिक मुखर प्रवक्ता, उसके अति-प्रतिक्रियावादी सरकारी अधिकारी तथा खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी थे । क्वोमिंताङ के पास ऐसे कोई भी लेखक या कलाकार नहीं थे जो किसी दर्ज करने योग्य सामग्री की रचना या सृजन कर सकें । क्रान्तिकारी संस्कृति का मुकाबला करने

हासिल करना संभव हो सकता था, तथा यह विजय एक या कई राजनीतिक अथवा आर्थिक केन्द्रों पर कब्जे से शुरू होनी थी । इसलिए, उनके विचार में, देश के विभिन्न भागों या बड़े शहरों में आम हड़तालें तथा प्रदर्शन आदि आयोजित करने के लिए तैयारियां करना आवश्यक था । उन्होंने यह जोर देते हुए, कि यह लड़ाई दो शासन-व्यवस्थाओं के बीच की निर्णायक लड़ाई होनी थी, इस बात की पैरवी की कि पार्टी की रणनीति आक्रामक होनी चाहिए ।

''वामपंथी'' कठमुल्लावादियों के दबाव के अन्तर्गत, पार्टी की छठी केन्द्रीय समिति का चौथा पूर्ण अधिवेशन जनवरी 1931 में बुलाया गया । इस अधिवेशन में कठमुल्लावादियों ने पार्टी की केन्द्रीय समिति में नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त कर ली तथा ''वामपंथी'' कार्यदिशा को स्वीकृति प्रदान कर दी गई । इस प्रकार तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा के प्रभुत्व का दौर आरंभ हो गया।

इसी दौरान, चीन में कई बड़ी-बड़ी घटनाओं का सिलसिला चला । च्याङशी के केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की लाल सेना ने लगातार, शत्रु की दूसरी तथा तीसरी घेराबन्दी मुहिमों को तहस-नहस करके जबरदस्त सफलताएँ प्राप्त कीं । इसी दौरान, जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा उत्तर-पूर्व पर कब्जे से, जनवाद तथा राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलनों ने देश भर में नई बुलंदियों को छू लिया ।

लेकिन पार्टी के नेतृत्वकारी संगठन ने स्वयं को तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा की भयंकर गलतियों में उलझा लिया । ''वामपंथियों'' ने कट्टरता की नीति अपनाते हुए संयुक्त मोर्चे की नीति का विरोध किया । इस प्रकार उन्होंने पार्टी के लिए, जापान तथा च्याङ काई-शेक के विरुद्ध एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ने के लिए जनता को विशाल पैमाने पर संगठित करने तथा सभी संभावित संश्रयकारियों को एकजुट करने के कार्य को असंभव बना दिया । क्रान्ति को अनुकूल परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ाया जा सका, इसके विपरीत भ्रांतिपूर्ण नेतृत्व के कारण और ज्यादा नए गतिरोधों को झेलना पड़ा ।

(1) जापानी साम्राज्यवादी हमले से अन्दरूनी वर्ग सम्बन्धों में परिवर्तन आए । वर्ग अन्तर्विरोधों पर राष्ट्रीय अन्तर्विरोधों के प्रभुत्व ने जापान तथा च्याङ काई-शेक के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे के निर्माण को संभव बनाया । लेकिन ''वामपंथियों'' ने इस बात पर बल दिया कि साम्राज्यवादी शक्तियां सोवियत-संघ पर संयुक्त हमला करेंगी तथा क्वोमिंताङ के विभिन्न गुट संयुक्त रूप से चीनी क्रान्ति पर हमला करेंगे । उनका मत था कि उत्तर-पूर्व में जापान की फौजी कार्यवाहियां सोवियत-संघ के विरुद्ध खुली जंग की प्रस्तावना थीं । तथा मौजूदा परिस्थितियों में क्वोमिंताङ के विभिन्न गुटों के बीच झगड़ों तथा फूट का बढ़ना तो दूर की बात थी, बल्कि क्रान्ति का विरोध करने के लिए उन लोगों ने एकजुट हो जाना था ।

यह था मौजूदा परिस्थिति को लेकर ''वामपंथियों'' का भ्रांतिपूर्ण मत ।

सोवियत-संघ पर हमले में साम्राज्यवादी शक्तियों के एकजुट हो जाने को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने का नतीजा यह निकला कि ''वामपंथियों'' ने जापान के, पहले उत्तर-पूर्व तथा फिर बाकी चीन को उपनिवेश बनाने के प्रयासों के खतरे तथा चीन की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को बचाने के महत्त्व की अनदेखी की । यह एक ऐसा गलत अनुमान था, जिसके कारण पार्टी उस समय फैल रहे व्यापक जापान-विरोधी आन्दोलन से कट गई । दूसरी ओर, उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तेज होते संघर्षों तथा अंतर्विरोधों की एवं साम्राज्यवादी

युद्ध के आसन्न खतरे की अनदेखी की । इस प्रकार जापान तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच के अंतर्विरोधों एवं मतभेदों का जापान-विरोधी संघर्ष के हक में फायदा नहीं उठाया जा सका ।

चीनी क्रान्ति पर हमले को लेकर घरेलू शासक वर्गों के इकट्ठे होने तथा प्रतिक्रान्तिकारी गुटों की एकता पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की वजह से, वे सभी सत्तासीन ग्रुपों को समान रूप से प्रतिक्रान्तिकारी मान बैठे । उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की कि सत्तासीन ग्रुप राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे थे । उन्होंने शासक वर्गों के बीच के सभी अन्तर्विरोधों की उपेक्षा की । उन्होंने पूँजीपति वर्ग, जो सत्ता से बाहर था तथा दलाल-पूँजीपति वर्ग व जमींदार वर्ग, जो कि सत्ता में थे, के बीच के तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग व जापानी साम्राज्यवादियों के बीच के सभी अन्तर्विरोधों की उपेक्षा की । इस प्रकार पार्टी के लिए एक लचीली नीति अपनाना असंभव हो गया—ऐसी नीति जो सबसे ज्यादा भयंकर व सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु को अलग-थलग करने तथा उस पर हमला करने के लिए इन अन्तर्विरोधों से फायदा उठाते हुए क्रान्ति की शक्तियों को मजबूत करती ।

(2) "वामपंथी" कार्यदिशा के नेताओं ने क्वोमिंताङ की सत्ता के संकट तथा क्रान्तिकारी शक्तियों के विकास का वास्तविकता से ज्यादा आकलन किया । फलतः उन्होंने दो शासन व्यवस्थाओं के बीच के प्रतिद्वन्द्व तथा वर्गों के बीच की फैसलाकुन लड़ाई पर एक तरफा जोर दिया । उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन में केवल दो शासन व्यवस्थाएं थीं—क्वोमिंताङ शासन व्यवस्था तथा लाल शासन व्यवस्था, तथा एक तीसरी शासन व्यवस्था जो नानकिङ की विरोधी थी, के अस्तित्व की संभावना को ही नकार दिया ।

यही कारण था कि "वामपंथी" कार्यदिशा के नेताओं ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार के नारे को अस्वीकार कर दिया । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार न तो विश्वासघाती नानकिङ सरकार होनी थी और न ही लाल सरकार । यह तो सभी वर्गों, सभी राजनीतिक दलों तथा ग्रुपों के गठबन्धन से बनी एक जापान-विरोधी जन-सरकार होती । यद्यपि उस समय व्यापक जनता विश्वासघाती नानकिङ सरकार का विरोध कर रही थी, लेकिन वह अभी मजदूरों-किसानों की जन-सरकार की स्थापना के लिए तैयार न थी । "वामपंथी" इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि जनता अभी दो परस्पर विरोधी सरकारों के बीच में कहीं ठहरी हुई थी तथा वह जापान-विरोधी सरकार की मांग कर रही थी । फलतः "वामपंथियों" ने विश्वासघाती नानकिङ सरकार की जगह जापान-विरोधी जन-सरकार की स्थापना के नारे को पेश नहीं किया । इस गलती के बाद स्वभावतः दूसरी गलती हुई, और वह थी—हुनान, हुपे तथा च्याङशी के तीन प्रान्तों में से एक या अधिक में क्रान्ति को विजयश्री दिलाने के लिए एक या दो बड़े केन्द्रों पर कब्जा करने का प्रयास । तीसरी जवाबी घेराबन्दी मुहिम के बाद "वामपंथियों" ने लाल सेना को कुछ समय के लिए आराम करने तथा अपनी क्षतिपूर्ति करने की इजाजत देने की बजाय शत्रु का पीछा करते रहने का आदेश जारी कर दिया ताकि "एक या दो बड़े अथवा गौण शहरों पर कब्जा किया जा सके।" परिस्थितियों का गलत विश्लेषण करने के परिणामवश, उन्होंने पहले एक या कई प्रांतों में क्रान्तिकारी विजय हासिल करने की संभावना पर बल दिया तथा इसे पार्टी के प्रमुख कार्यभार के रूप में पूरा करने का प्रयास किया ।

इस प्रकार लाल सेना को रसद की आपूर्ति सुनिश्चित की गई ।

उद्योग (कागज, तम्बाकू, टंगस्टन, कपूर, कृषि-उपकरण, रासायनिक खाद, कपड़ा, दवाइयाँ, चीनी, शोरा व नमक) को अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित तीन विभिन्न अंगों के तहत विकसित किया गया ; राजकीय कारोबार, सहकारी कारोबार तथा निजी कारोबार । इस सबका उद्देश्य यह था कि पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए तथा फिर बाहरी इलाकों के साथ व्यापार के लिए जिन्सों का उत्पादन किया जाए । क्रांतिकारी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही बातें जरूरी थीं ।

आर्थिक कार्य में क्वोमिंताङ नियंत्रित इलाकों के साथ व्यापार एक महत्त्वपूर्ण विषय था। हर साल 15 लाख क्विंटल धान, (औसतन प्रति व्यक्ति आधा क्विंटल) दैनिक जरूरत की वस्तुओं के बदले केन्द्रीय आधार-क्षेत्र से बाहर भेजा जाता था । टंगस्टन भी बाहर भेजा जाता था । केन्द्रीय आधार-क्षेत्र के तीस लाख लोगों को हर साल 90 लाख च्वान (24 ग्राम चांदी का सिक्का) का नमक तथा लगभग 60 लाख च्वान का सूती कपड़ा चाहिए होता था । श्रमिकों तथा किसानों की केन्द्रीय जन-सरकार ने उचित दामों पर वस्तुओं की बिक्री करने तथा बाहर के क्षेत्रों से नमक तथा कपड़ा मुहैया करवाने के लिए व्यापार नियंत्रण किया । सरकार ने बांड भी जारी किए ।

कामरेड माओ त्से-तुङ ने ध्यान दिलाया कि इस समय लाल क्षेत्रों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीन अंग थे—राजकीय कारोबार, सहकारी कारोबार तथा निजी कारोबार । उनका मत था कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था के राजकीय कारोबार को सभी संभव उपायों से विकसित किया जाए तथा सहकारी कारोबार का भी व्यापक स्तर पर विकास किया जाए । जहां तक निजी सेक्टर का सवाल था, उसे कानूनी सीमाओं में रहते हुए प्रोत्साहित किया जाए व आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजकीय सेक्टर का निजी सेक्टर पर नेतृत्व, भविष्य में समाजवाद की ओर संक्रमण की एक शर्त होगी ।

दूसरे, आर्थिक निर्माण का उद्देश्य जनता के जीवन के हालातों को बेहतर बनाना तथा क्रांतिकारी युद्ध के बारे में उसकी समझ को विकसित करना था ।

लोगों के जीवन के संगठनकर्त्ता के रूप में श्रमिकों तथा किसानों की जन-सरकार ने उनकी दिक्कतें दूर करने तथा उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की हर संभव कोशिश की ।

लाल इलाकों के उन हिस्सों में जहां काम ठीक ढंग से किया गया, लोगों के रहन-सहन के स्तर में काफी सुधार हुआ । उदाहरण के तौर पर, छाङकाङ तथा छाएशी के कस्बों को लिया जाए जिन्हें **"आदर्श कस्बे"** का सम्मान दिया गया । क्रांति से पहले, छाएशी में गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों के पास साल में केवल तीन महीने खाने को चावल होता था । बाकी समय में उन्हें मक्के तथा बाजरे जैसे अन्य अनाजों पर निर्भर रहना पड़ता था, तथा इनकी मात्रा भी अपर्याप्त होती थी । लेकिन 1934 में हालात बदल गए थे । वे आधा साल चावल खा सकते थे, तथा बाकी आधे साल के लिए उनके पास मक्के तथा बाजरे की पर्याप्त मात्रा होती थी । छाङकाङ में माँस खाने वाले गरीब किसानों की तादाद दुगुनी तथा श्रमिकों की तिगुनी हो गई थी । किसान पहले की अपेक्षा दुगुना कपड़ा खरीदते थे । खाद्य-तेल सभी के लिए काफी था तथा बच भी जाता था ।

घेराबन्दी मुहिम को पूर्णतया कुचल कर रख दिया ।

इस विजय के बाद लाल सेना के विस्तार के लिए केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया । स्थानीय सैन्य-दलों को मिलाकर पहली मोर्चा सेना की संख्या उस समय 1,00,000 के लगभग थी । आधार-क्षेत्र हुनान, च्याङशी, फूच्येन तथा क्वाङतुङ के इलाकों में फैले हुए थे तथा उनकी आबादी 30 लाख के आस-पास थी ।

22 जनवरी, 1934 को रुइचिन में श्रमिकों, किसानों व सैनिकों की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई । इस कांग्रेस में कामरेड माओ त्से-तुङ ने पूरे कर लिये गए कार्यों का सारांश देते हुए रिपोर्ट पेश की ।

1933 की गर्मियों में च्याङ काई-शेक ने अपनी पाँचवीं घेराबन्दी मुहिम के लिए सक्रिय तैयारियां शुरू कर दीं । उसने रुइचिन को अपने हमले का मुख्य केन्द्र बनाकर, लाल इलाके के चारों ओर किलेबन्दियां बनाने की नई रणनीति अपनाई । इसके साथ ही, उसने बर्बर आर्थिक नाकेबन्दी भी लागू कर दी । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कामरेड माओ-से-तुङ ने श्रमिकों, किसानों व सैनिकों की दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आर्थिक निर्माण का प्रश्न रखा ।

कामरेड माओ त्से-तुङ ने क्रांतिकारी युद्ध में आर्थिक निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका का सही ढंग से विश्लेषण किया । उन्होंने ध्यान दिलाया कि लाल सेना के लिए युद्ध-सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए तथा जनता के रहन-सहन के हालात में सुधार लाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष करना जरूरी था ।

इस सिद्धांत के मार्गदर्शन के अन्तर्गत, महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गईं ।

पहला, आर्थिक निर्माण ने लाल सेना को सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करके क्रांतिकारी युद्ध को सहारा दिया ।

लाल क्षेत्र के आर्थिक निर्माण में मुख्य कार्यभार खेती-बाड़ी का विकास करना था । श्रम शक्ति तथा भारवाहक पशुओं का तर्कसंगत इस्तेमाल मुख्य प्रश्न बन गया था ।

क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अनेक नौजवान तथा अधेड़ लोग मोर्चे पर चले गए थे । इसलिए श्रम शक्ति को संगठित करना, विशेषकर महिलाओं में से, एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था। परस्पर लाभ के स्वैच्छिक सिद्धान्तानुसार तथा व्यक्तिगत अर्थ-प्रणाली के आधार पर केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में आपसी-सहयोग समितियां गठित की गईं । हर समिति में एक गाँव या कस्बे में रहने वाले सभी किसान होते थे । इस प्रकार बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं उत्पादक कार्यों में हिस्सा लेने में सक्षम हुईं ।

आपसी-सहयोग की व्यवस्था करने के अतिरिक्त ये समितियां लाल सेना के सैनिकों के परिवारों, यतीमों व उन वृद्ध लोगों की, जिन्हें सहारा देने के लिए उनकी कोई औलाद न थी, सहायता करती थीं ।

उन किसानों की समस्याएँ हल करने के लिए जिनके पास भारवाहक पशु कम या बिल्कुल ही नहीं थे, केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में सहकारी समितियां स्थापित की गईं । इन सहकारी समितियों के सदस्य अपना-अपना चंदा इकट्ठा करके सांझे इस्तेमाल के लिए पशु खरीदते थे।

लाल इलाकों में इन आपसी-सहयोग समितियों की स्थापना से कुछ स्थानों में कृषि-उत्पादन न केवल क्रांति पूर्व के स्तर तक जा पहुँचा, बल्कि कुछ स्थानों पर तो उसे भी पार कर गया।

4.

● क्रान्ति के अस्थाई उतार के दौरान जापान व च्याङ काई-शेक के विरुद्ध संघर्ष ।

च्याङ काई-शेक ज्यादा समय तक सत्ताच्युत न रहा । जापानी साम्राज्यवादियों की मदद तथा वाङ चिङ-वेइ के गुट से गठजोड़ करके वह पुनः सत्तासीन हो गया । जनवरी 1932 में राजनीतिक परिदृश्य में पुनः आविर्भाव के तत्काल बाद, च्याङ काई-शेक तथा वाङ चिङ-वेइ, दोनों राष्ट्रव्यापी जापान-विरोधी आन्दोलन को कुचलने तथा शंघाई में जापानी हमलावरों के विरुद्ध चल रही लड़ाई को ध्वस्त करने में जुट गए । शंघाई युद्ध-विराम समझौता करते ही च्याङ ने हुपे-हनान-आन्हेइ क्षेत्र में लाल सेना के खिलाफ अपनी घेराबन्दी मुहिमें तत्काल दोबारा शुरू कर दीं । उसने **सी.सी.गुट**[2] के अलावा **'राष्ट्रीय पुनर्जागरण समिति'** (Society of National Revival) या **'नीली कमीज सोसाइटी'** (The Blue Shirt Society) की भी स्थापना की । ये दोनों संस्थाएँ कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें खोदने, देशभक्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलनों को कुचलने तथा क्वोमिंताङ के अन्दर मौजूद च्याङ विरोधी ग्रुपों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक कुत्सित व नृशंस तरीकों का इस्तेमाल करती थीं । कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध का नारा देते हुए, च्याङ ने तथाकथित "राष्ट्रीय आपातकालीन सम्मेलन" बुलाया तथा अपने प्रतिक्रियावादी शासन को सहारा देने के लिए प्रतिक्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की स्थापना की । इस दौर में, क्रान्ति अस्थाई रूप से उतार पर थी ।

लेकिन इस कालावधि में भी, जब क्रान्तिकारी लहर उतार पर थी, चीनी जनता ने च्याङ काई-शेक तथा जापानी हमलावरों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा ।

शंघाई युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी जापानी साम्राज्यवादियों ने आगे बढ़ना जारी रखा । जनवरी 1933 में जापानी सेना ने शानहाएक्वान दर्रे को पार करते हुए जेहोल पर हमला किया । चूंकि क्वोमिंताङ सेना हमला किये बिना ही भाग खड़ी हुई थी, अतः शीघ्र ही समूचा जेहोल प्रान्त तथा उत्तरी छाहाड़ प्रान्त जापान के हाथों में चले गए । मार्च के मध्य में जापानियों ने लम्बी दीवार के दर्रों पर एक बहुत बड़ा हमला किया । उस समय पेकिङ-थ्येनचिन क्षेत्र में तैनात क्वोमिंताङ फौज, शत्रु सेना से दस गुणा अधिक थी, लेकिन च्याङ काई-शेक ने चीनी सेना को लड़ने से रोक दिया । फलतः जापानी सेना लम्बी दीवार के सभी दर्रों को हथियाने के बाद आगे बढ़ी तथा पेकिङ व थ्येनचिन को घेर लिया । 31 मई को क्वोमिंताङ सरकार ने जापान के साथ थाङकू के समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा व्यावहारिक स्तर पर तीन उत्तरी प्रांतों व जेहोल पर जापानी कब्जे को मान्यता दे दी तथा पूर्वी हपे को विसैन्यीकृत जोन (जहाँ चीन की कोई फौज नहीं होगी) घोषित कर दिया, तथा इस प्रकार जापान के लिए सारे उत्तरी चीन पर कब्जा करना संभव बना दिया ।

अपनी देशद्रोही गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए च्याङ काई-शेक सरकार ने लाल सेना पर पृष्ठभाग में गड़बड़ करने का मिथ्यापूर्ण आरोप लगाया तथा, *"विदेशी शत्रु से लड़ने से पहले घरेलू विद्रोह को कुचला जाना जरूरी है"* के प्रतिक्रान्तिकारी नारे का प्रचार किया। च्याङ काई-शेक सरकार के अनर्गल प्रचार को ध्वस्त करने तथा जापान का प्रतिरोध करने की लाल सेना की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए मजदूरों-किसानों की केन्द्रीय जन-सरकार

तथा क्रान्तिकारी फौजी परिषद ने 17 जनवरी, 1933 को एक घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि जापान का मुकाबला करने के लिए वे किसी भी सेना से इस शर्त पर समझौता करने को तैयार थे कि लाल इलाकों पर हमले बन्द किए जाएँ, लोगों के जनवादी अधिकारों की गारंटी की जाए तथा व्यापक जनता को हथियारबन्द किया जाए ।

इस प्रकार क्वोमिंताङ के बेशर्मी भरे झूठों को पूर्णतया नंगा कर दिया गया । क्वोमिंताङ सदस्यों के बीच क्वोमिंताङ सरकार की कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध की नीति को लेकर असंतोष बढ़ रहा था । इसके अतिरिक्त, इस घोषणा ने, उस वक्त लाल सेना की घेराबंदी कर रही क्वोमिंताङ फौजों का मनोबल गिरा दिया । च्याङ काई-शेक अब अत्यधिक कठिन परिस्थिति में फंस गया था ।

जापान की चीन को एकमात्र अपने प्रभुत्व वाले उपनिवेश में बदलने की कोशिश तथा प्रतिक्रियावादी च्याङ काई-शेक गुट की देशद्रोही गतिविधियों ने चीन के शासक वर्ग के शिविर में आई दरार को और अधिक चौड़ा कर दिया । 1933 में फङ ग्वी-श्याङ तथा छाए थिङ-खाए ने जापान के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से तालमेल करने के लिए कदम उठाए ।

लम्बी दीवार के सभी दर्रों व ल्वान नदी के पूर्व की ओर के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद, जापानियों ने कठपुतली सेना को छाहाङ पर हमला करने तथा तोलुन व उस प्रदेश के पूर्वी हिस्से की अन्य कांउटियों को हथियाने के लिए उकसाया । मई 1933 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आकर तथा उसकी मदद से, फङ ग्वी-श्याङ तथा कुछ दूसरे लोगों ने छाहाङ के चाङच्याखओ में जापान-विरोधी मित्र सेना का गठन किया तथा जापान के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया । बहुत सख्त लड़ाई के बाद, उन्होंने छाहाङ का उत्तरी हिस्सा वापिस ले लिया । इसके बाद च्याङ काई-शेक ने जापान-विरोधी मित्र सेना पर हमला करने के लिए जापानी सेना से गठजोड़ कर लिया । फङ ग्वी-श्याङ को छाहाङ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तथा जापान-विरोधी सेना पर, जो उस समय ची हुङ-चाङ के नेतृत्व में पूर्वी हपे की ओर बढ़ रही थी, जापानियों तथा च्याङ की फौजों ने पीछे से हमला किया तथा अक्तूबर में उसे खदेड़ दिया ।

19वीं राह सेना के छाए थिङ-खाए तथा अन्य अफसर, जिन्हें "कम्युनिस्टों का सफाया" करने के लिए फूच्येन भेजा गया था, कदम-ब-कदम लाल सेना से लड़ने की निरर्थकता को महसूस करने लगे थे । नवंबर 1933 में ली ची-शन के नेतृत्व वाली क्वोमिंताङ की सैन्य-शक्तियों से सहयोग करके उन्होंने सार्वजनिक रूप से च्याङ काई-शेक से संबंध तोड़ने की घोषणा की, फूच्येन में **"चीनी लोकतन्त्र की क्रान्तिकारी जन-सरकार"** की स्थापना कर दी और जापान का प्रतिरोध करने तथा च्याङ काई-शेक का विरोध करने के लिए लाल सेना से समझौता कर लिया ।

फूच्येन की घटना तथा लाल इलाके में जवाबी घेराबन्दी मुहिम, दोनों एक साथ हुई थीं। फूच्येन में जन-सरकार की उपस्थिति का लाल सेना द्वारा दुश्मन की घेराबन्दी ध्वस्त करने के संघर्ष में तथा क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र का विस्तार करने में फायदा उठाया जा सकता था । इसलिए पार्टी द्वारा 19वीं राह सेना के साथ युद्ध-विराम समझौता संपन्न करना और उसे जापान का प्रतिरोध करने तथा च्याङ काई-शेक का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना एक

अपनी शक्तियों को केन्द्रित कर लिया । जनवरी 1932 में जब उसने हुपे-हनान-आन्ह्वेइ क्षेत्र पर हमला किया, चौथी मोर्चा सेना ह्वाङछ्वान के स्थान पर उसकी पांतों को तोड़कर उसके पृष्ठभाग में घुस गई तथा उसकी कुमुक को तहस-नहस कर दिया और आधार-क्षेत्र हनान में शाङछङ, कूश तथा शिनचि तक और आन्ह्वेइ में छिनच्याच्या तथा ग्वेशि तक फैल गया । हुपे-हनान-आन्ह्वेइ आधार-क्षेत्र अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखता था, क्योंकि याङत्सी नदी पर इसका नियंत्रण था, यह हानखओ तथा ऊछाङ पर नजदीक से दबाव डाल सकता था (यानि कि हमला कर सकता था) तथा इसकी सैन्य-शक्तियां पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के लिए खतरा बन सकती थीं । जुलाई में च्याङ काई-शेक ने हुपे-हनान-आन्ह्वेइ आधार-क्षेत्र के खिलाफ अपनी चौथी घेराबन्दी मुहिम शुरू की । चिलीफिङ की लड़ाई में उसकी मुख्य सैन्य-शक्ति को पराजित कर दिया गया । लेकिन चौथी मोर्चा सेना के नेताओं ने यह सोचते हुए, कि क्वोमिंताङ फौजें बहुत ज्यादा कमजोर कर दी गईं थीं तथा उन्हें अब गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी, विजय-प्राप्ति के बाद जवाबी घेराबन्दी मुहिम के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए जब शत्रु ने एक और हमला किया तो उन्हें एक असुविधाजनक स्थिति में दृढ़ प्रतिरोध करने को बाध्य होना पड़ा, तथा इतनी गंभीर क्षति उठानी पड़ी कि उन्हें अक्तूबर 1932 में हुपे-हनान-आन्ह्वेइ आधार-क्षेत्र से ही हटना पड़ा तथा हनान व शेनसी के रास्ते उत्तरी सछ्वान में शरण लेनी पड़ी ।

1932 के शरद में लाल सेना की दूसरी फौजी कोर ने हो लुङ की कमान में हुङहू क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया । इसके हरावल दस्ते के हानयाङ के नजदीक पहुँचते ही इसने चौथी मोर्चा सेना के साथ ऊहान पर दबाव डालने के लिए एक मुहिम में तालमेल बैठाया । जब चौथी मोर्चा सेना पश्चिम की ओर मुड़ी, दूसरी फौजी कोर हुङहू क्षेत्र से बाहर आ गई। बाद में, इसने हुनान-हुपे-सछ्वान-कवेइचओ की सीमाओं में प्रवेश करके, वहाँ एक नये आधार-क्षेत्र की स्थापना की ।

1932 की गर्मियों में च्याङ काई-शेक ने पांच लाख फौज इकट्ठी की तथा केन्द्रीय आधार-क्षेत्र के विरुद्ध चौथी घेराबन्दी मुहिम शुरू कर दी ।

यह मुहिम जून 1932 से फरवरी 1933 तक, आठ महीने चली । शत्रु ने उत्तर से दक्षिण की ओर कई मार्गों द्वारा चिनशी की ओर बढ़ने की कार्यनीति अपनाई । दूसरी ओर, लाल सेना ने, शत्रु पर घात लगाकर हमला करने तथा शत्रु की घेराबन्दी के लिए अपनी ज्यादा रेजीमेन्टें लगाईं । हुवान (चिनशी के पश्चिम में) की लड़ाई में, शत्रु की एक पूरी डिवीजन को निष्क्रिय कर दिया गया । इसके बाद शत्रु ने अपनी सैन्य-शक्तियों को पुनः व्यवस्थित किया तथा तीन कालमों में बंटकर नानफङ तथा क्वाङछाङ की ओर बढ़ा । शत्रु का मुख्य सैन्य-दल पूर्वी कालम था तथा उसकी पश्चिमी भुजा वाली दो डिवीजनें लाल सेना के हमले की जद में थीं। अपनी स्थिति बदलने तथा गुप्त रूप से सैन्य-शक्ति केन्द्रित करने के बाद, लाल सेना ने ईह्वाङ काउंटी के दक्षिण में ह्वाङफी के स्थान पर शत्रु की दो डिवीजनों पर हमला किया तथा उनका सफाया कर दिया । जब शत्रु ने अपने पश्चिमी कालम को सहारा देने के लिए पूर्वी कालम से विशाल कुमुक भेजी, तो लाल सेना ने ईह्वाङ के दक्षिण में स्थित थुङफी तथा छाओथाएकाङ के नजदीक पिलीशान तथा लेइखुङशङ में अपने सैन्य-दल तैनात करके शत्रु की एक और डिवीजन का सफाया कर दिया । इन दो मुठभेड़ों के साथ ही लाल सेना ने चौथी

किसान केवल ऐसे उपकरण तथा भारवाहक पशु ही अपने पास रख सकते थे जिनकी उन्हें हाल में आबंटित जमीन को जोतने के लिए जरूरत थी; इसके इलावा सभी फालतू उपकरण तथा पशु ज़ब्त किए जाने थे। ''संविधान की रूपरेखा'' में यह अनुबन्ध था कि धनी किसानों को कोई भी जनवादी अधिकार नहीं दिए जाने थे। लाल सत्ता के अन्तर्गत उन सभी सामाजिक स्तरों के प्रति, जिनका चरित्र पूँजीवादी था, उन्होंने श्रम, अर्थ-व्यवस्था तथा राजनीतिक सत्ता को लेकर अति ''वामपंथी'' नीतियां अपनाईं ; कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों तथा शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग के निचले तबके को छोड़ कर, बाकी सभी सामाजिक तत्वों के विरुद्ध एक अविवेकपूर्ण संघर्ष छेड़ दिया गया। केन्द्रीय आधार-क्षेत्र तथा सीमांत क्षेत्रों के बीच विकास की विषमता को नकारते हुए उन्होंने इस विचार को अस्वीकृत कर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी की नीति किंचित बदलाव के साथ लागू की जानी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि मज़दूरों तथा किसानों की जन-सरकार की बुनियादी सांस्कृतिक तथा शैक्षिक नीति कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिक्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए तथा अनेक दूसरे मामलों में अति ''वामपंथी'' नीति अपनाई। इस प्रकार उनकी यह गलत कार्यदिशा आगे चलकर केन्द्रीय आधार-क्षेत्र तथा उससे लगते अन्य इलाकों में भी लागू की गई।

फूच्येन घटना के बारे में भी ''वामपंथियों'' ने पूर्णतया गलत नीति अपनाई।

उन्होंने क्वोमिंताङ तथा उसकी सरकार के अंदर मौजूद सभी गुटों तथा धड़ों पर अंधाधुंध तरीके से प्रतिक्रान्तिकारी का ठप्पा लगा दिया। फूच्येन में जन-सरकार की स्थापना को भी उन्होंने एक नई चाल माना जबकि वास्तव में यह क्वोमिंताङ में आई दरार का द्योतक थी। उन्होंने च्याङ काई-शेक सरकार तथा फूच्येन सरकार के बीच किसी भी प्रकार का फर्क करने से इंकार कर दिया तथा एक तीसरी प्रकार की सरकार के अस्तित्व को ही नकार दिया। फूच्येन की जन-सरकार को सक्रिय सहयोग देने की बजाय उन्होंने उसकी लाल स्वाधीन शासन व्यवस्था से भिन्न राजनीतिक कार्यक्रम अपनाने के लिए निन्दा की। उन्होंने फूच्येन के व्यापक जनसमुदाय का आह्वान तक किया कि वह उठे, और *''तीसरे मार्ग के अन्वेषकों के पतन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए''* स्वतंत्र कार्यवाही करे।

अत: फूच्येन जन-सरकार का सन् 1934 में निम्नलिखित तीन कारणों से पतन हो गया: च्याङ काई-शेक की श्रेष्ठ सैन्य-शक्तियों द्वारा हमला, उसकी अपनी पांतों में फूट तथा तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा की गलत नीति।

''वामपंथियों'' ने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में पार्टी तथा फौज के सही नेतृत्व को किनारे कर दिया था, लेकिन फिर भी कामरेड माओ त्से-तुङ के सही रणनीतिक सिद्धांतों के प्रभाव के कारण, लाल सेना गलत ''वामपंथी'' कार्यदिशा का प्रभाव फैलने से पहले, 1933 की बसन्त ऋतु में चौथी जवाबी-घेराबन्दी मुहिम में भी विजय प्राप्त करने में सफल रही।

तीसरी जवाबी घेराबन्दी मुहिम की विजय के बाद, क्रांतिकारी आधार-क्षेत्रों में प्रति-क्रांतिकारी गढ़ों का सफाया कर दिया गया था तथा क्रांतिकारी सैन्य-शक्तियों के पृष्ठभाग को सुदृढ़ कर दिया गया था।

च्याङ काई-शेक ने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में तो लाल सेना के विरुद्ध रक्षात्मक रुख अपना लिया, लेकिन हुपे-हनान-आन्ह्वेइ आधार-क्षेत्र व हुङहू आधार-क्षेत्र पर हमला करने के लिए

बिल्कुल सही कदम था।

लेकिन रणनीतिक स्तर पर ''वामपंथी'' कार्यदिशा के पैरोकारों ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई। 19वीं राह सेना की कार्यवाहियों से तालमेल बैठाते हुए वे पूर्वी मोर्चे पर अचानक हमला बोल सकते थे और यह एक ऐसी कार्यवाही होती जिससे केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की च्याङ द्वारा की गई पाँचवी घेराबन्दी ध्वस्त हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

1 सितंबर, 1931 को कामरेड छिन पाङ-श्येन की अध्यक्षता में स्थापित अंतरिम केन्द्रीय समिति से लेकर, जनवरी 1935 में हुए चुनई सम्मेलन के बीच की कालावधि में, तीसरी ''वामपंथी'' कार्यदिशा लगातार विकसित हुई।

1933 के आरंभ में, पार्टी का मुख्यालय शंघाई से दक्षिणी च्याङशी के क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले, ''वामपंथी'' कार्यदिशा के नेताओं ने 18 सितंबर की घटना के बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में जापान-विरोधी आंदोलन को उन्होंने जो नुकसान पहुँचाया था, उसकी परवाह न करते हुए अंधाधुंध अनुमान लगाया था कि हर गुजरते दिन के साथ क्रांतिकारी उभार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने चीनी क्रांति के असमान विकास के नियम को नकार दिया; तथा इस दृष्टिकोण को कि श्रमिक-वर्ग आंदोलन, किसान आंदोलन से पीछे रह गया था तथा उत्तर में क्रांतिकारी आंदोलन दक्षिण के आंदोलन से पीछे था, ''दक्षिणपंथी अवसरवादी'' रुझान करार दिया। उन्होंने घोषणा की कि देश के सभी बड़े शहरों में हड़तालों की लहर जोर पकड़ रही थी तथा सारे उत्तरी चीन में लाल सत्ता की स्थापना संभव थी। उन्होंने बिना किसी आधार के ज़ोर देकर कहा कि उस वक्त क्रांतिकारी संघर्ष दो रास्तों के बीच का संघर्ष था—लाल स्वाधीन शासन व्यवस्था का रास्ता तथा चीन को उपनिवेश में बदलने का रास्ता। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इसे *''वर्गों के बीच की निर्णायक लड़ाई''* का नाम दिया। उनका विचार था कि उस वक्त भी अत्यधिक जरूरी कार्यभार *''सक्रिय आक्रमण करने''* तथा बड़े शहरों पर कब्जा करने की नीति अपनाना था। वे संघर्ष के कानूनी तरीकों के इस्तेमाल के विरुद्ध थे तथा खुले में काम को भूमिगत काम के साथ गडमड कर देते थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शत्रु की शक्ति तथा क्रांति की शक्तियों के बीच की विराट असमानता की परवाह न करते हुए अक्सर श्रमिकों तथा विद्यार्थियों की हड़तालें, प्रदर्शन तथा यहां तक कि सशस्त्र विद्रोह भी आयोजित किए। इस दुस्साहसवादी नीति के कारण पार्टी को क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में गंभीर क्षति उठानी पड़ी।

दूसरी ओर, उन्होंने दावा किया कि पार्टी के अंदर मुख्य खतरा तथाकथित ''दक्षिणपंथी भटकाव'' से था, तथा उन्होंने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में अपनाई गई सही कार्यदिशा की निन्दा करते हुए, उसे *''धनी किसानों की कार्यदिशा''* करार दिया। च्याङशी के क्रांतिकारी आधार-क्षेत्र में आने के बाद, उन्होंने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र में कार्यरत पार्टी तथा फौज के सही नेतृत्व को बदल दिया। उन्होंने कामरेड माओ त्से-तुङ की सही कृषि-नीति को नकार दिया, तथा लाल आधार-क्षेत्रों में जमींदारों को कोई जमीन आबंटित न करने तथा धनी किसानों को केवल घटिया दर्जे की जमीन आबंटित करने की अति ''वामपंथी'' नीति लागू कर दी। उन्होंने कृषि-कानून में यह प्रावधान जोड़ा कि जमीन की ज़ब्ती के बाद, जमींदार को उसकी ज़मीन में से कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना था तथा धनी किसानों को अपेक्षाकृत घटिया गुणवत्ता की, केवल कृषि-योग्य जमीन ही आबंटित की जानी थी। धनी

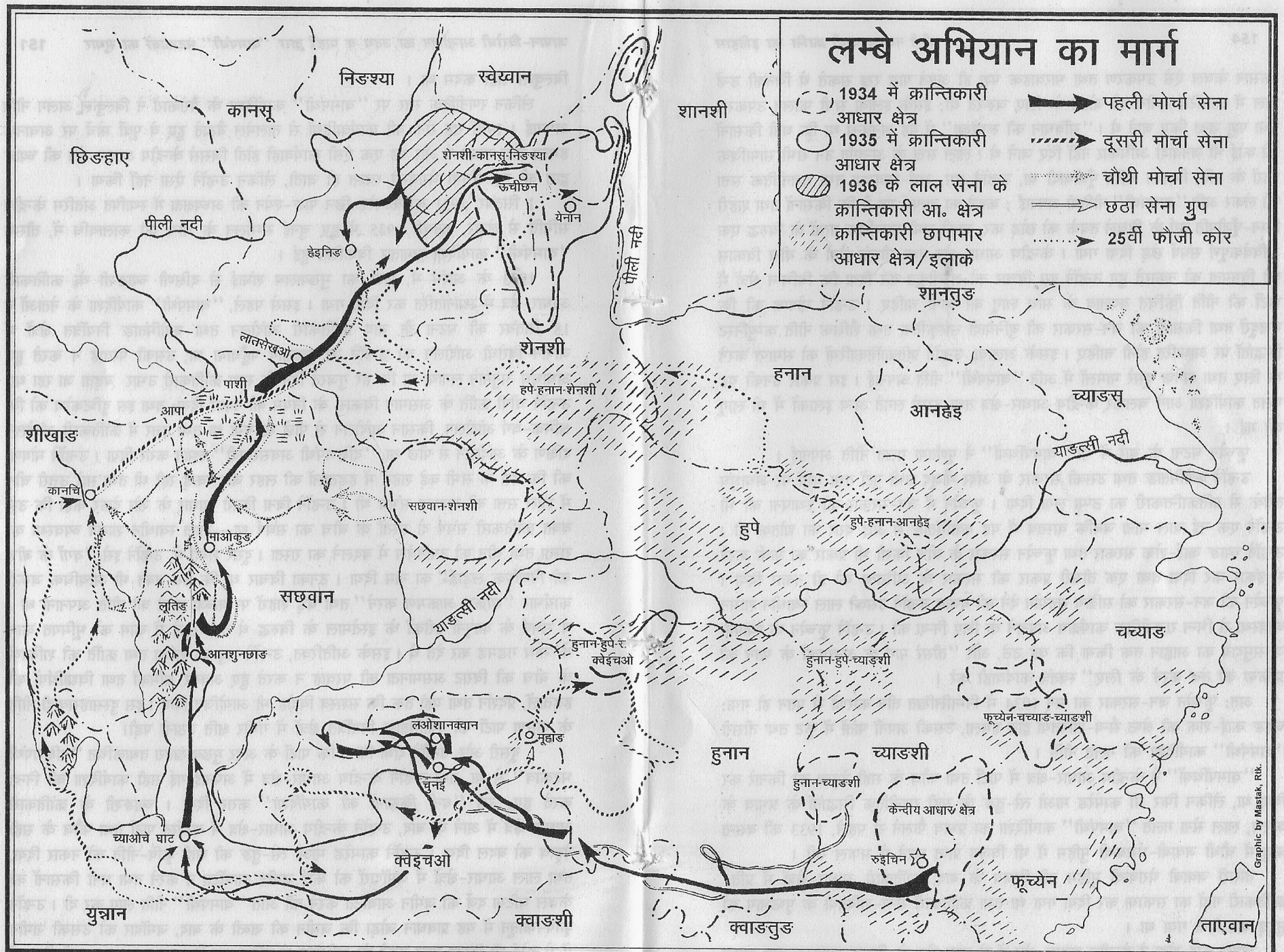

नोट : (अक्तूबर 1934 में शुरू हुए इस अभियान में लाल सेना की विभिन्न इकाईयों ने एक महान रणनीतिक स्थानांतरण प्रारम्भ किया। 11 प्रान्तों फूच्येन, च्याङशी, क्वाङतुङ, हुनान, क्वाङशी, क्वेइचओ, सछ्वान, युन्नान, शीखाङ, कानसू और शेनशी को पार करते हुए, बारह महीने हिमाच्छिादित रहने वाले पर्वतों तथा मार्गहीन घास के दलदले मैदानों को लांघकर तथा अकथनीय मुसीबतों को झेलकर, बार-बार शत्रु की घेराबन्दियों, पीछा करने, अडचनें डालने और रास्ता रोकने की कार्यवाहियों को विफल करके लाल सेना ने 12,500 कि.मी. लम्बा रास्ता तय किया तथा अक्तूबर 1935 में विजयपूर्वक उत्तरी शेनशी के क्रान्तिकारी आधार क्षेत्र में पहुँच गई।)

का 90.7 प्रतिशत साम्राज्यवादियों का था । 1936 में याङत्सी नदी में चल रहे जहाजों की वहन क्षमता के कुल भार का 81.9 प्रतिशत टन भार, विदेशी जहाजों के कारण था, तथा सारे देश में 55 प्रतिशत विद्युत उत्पादन, (किलोवाट प्रति घंटे के रूप में) विदेशी संयन्त्रों ने किया । बैंकों की सभी सम्पत्तियों में 20.8 प्रतिशत अंश विदेशी पूँजी का था । तथापि, विदेशी बैंकों की आर्थिक शक्ति का सही आकलन चीन में केवल उनकी पूँजी की मात्रा से नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्हें बैंक नोट जारी करने तथा कस्टम ड्यूटी व नमक कर को नियंत्रित करने के विशेषाधिकार भी प्राप्त थे । विनिमय-दर भी उनके नियंत्रण में थी । 1936 में चीन के कताई तकलों का 46.2 प्रतिशत, सूत लपेटने वाले तकलों का 67.4 प्रतिशत तथा उसके करघों का 56.4 प्रतिशत विदेशी पूँजी के स्वामित्व में था । 1935 में सिगरेट के कुल उत्पादन का 58 प्रतिशत विदेशी उद्यमों द्वारा किया गया ।

संक्षेप में, जापान-विरोधी युद्ध से पहले क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में कोयला तथा लौह-उद्योग, रेलवे, जल-परिवहन तथा अन्य उद्यमों पर साम्राज्यवादियों का एकाधिकार था । चीन की वित्त-व्यवस्था पर भी उनका नियत्रंण था । उद्योग के कुछ विभागों, खासतौर से सूती कपड़ा उद्योग तथा सिगरेट उद्योग में तो विदेशी पूँजी का ही बोलबाला था ।

साम्राज्यवादी निवेश अधिकतर चीन से ही निचोड़ा जाता था, न कि विदेश से आयात किया जाता था । साम्राज्यवादियों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना ऐंठ कर, बलात् भूमि पर कब्जा करके, धोखे से उद्यमों के स्वामित्व को हथिया कर, तथा चीनी पूँजी को निगल कर, चीन को लूटा । बहुत छोटी मात्रा में पूँजी के आयात के बदले, पूँजीवादी देशों ने अत्यधिक मुनाफा ऐंठा । इस साम्राज्यवादी आर्थिक हमले के परिणामस्वरूप, चीन को अपने विदेशी भुगतान में प्रतिकूल संतुलन झेलना पड़ा । 1894 से 1937 तक के 43 वर्षों में पूँजी के चीन में आने तथा बाहर जाने का प्रवाह क्रमशः इस प्रकार था: प्राप्तियां—173.6 करोड़ अमरीकी डॉलर, व्यय—343.7 करोड़ अमरीकी डॉलर । इस अंतर का कुछ अंश चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिकूल संतुलन के कारण तथा कुछ अंश साम्राज्यवादी पूँजी द्वारा लूट के परिणामवश था ।

चीन में साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पूँजी का विस्तार एक कटु संघर्ष द्वारा किया गया।

पहला, 1936 में साम्राज्यवादी निवेश की कुल पूँजी, जो 428.5 करोड़ अमरीकी डॉलर थी, में से ब्रिटेन का हिस्सा 104.5 करोड़ अमरीकी डॉलर था । इसकी 1930 के 104.7 करोड़ डॉलर के आंकड़े से तुलना करने पर ब्रिटिश पूँजी निवेश वास्तव में वहीं का वहीं खड़ा था। अमरीकी पूँजी निवेश 34 करोड़ डॉलर था, जिसमें 1930 के 28.5 करोड़ डॉलर की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । तथापि, अमरीकी पूँजी निवेश की कुल मात्रा अभी भी कम थी । जापान का पूँजी निवेश 209.6 करोड़ डॉलर था, जो 1930 के 141.1 करोड़ डॉलर की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक था । अतः इस कालावधि के दौरान, जापानी पूँजी निवेश तेजी से बढ़ा तथा पहले स्थान पर आ गया । चीन में विदेशी पूँजी निवेश की कुल मात्रा का आधा भाग जापान का था ।

दूसरे, 1936 में उत्तर-पूर्वी चीन में जापानी पूँजी निवेश 145.5 करोड़ डॉलर था, जो चीन में उसके कुल पूँजी निवेश के दो-तिहाई से भी ज्यादा था । लेकिन इस कालावधि के दौरान, शेष चीन में जापानी निवेश कम था, तथा इसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि भी नहीं हुई । यह

अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, उसी समय समाजवादी क्रांति की तैयारी शुरू हो जाएगी ।

फौजी नीति के सम्बन्ध में उन्होंने छापामार लड़ाई तथा छापामार चरित्र की चलायमान लड़ाई का विरोध किया, तथा ऐसे नारे प्रस्तुत किए, *"लाल सेना को जवाबी घेराबंदी मुहिम में अपने ठिकानों पर मजबूती से डटे रहना चाहिए तथा लाल इलाके की एक इंच ज़मीन भी शत्रु के हवाले नहीं करनी चाहिए ।"*

केन्द्रीय लाल इलाके तथा फूच्येन-चच्याङ-च्याङशी आधार-क्षेत्र के बीच सम्पर्क काटने के लिए शत्रु ने पहले लीछ्वान पर हमला किया । इसके बाद श्युनखओ के स्थान पर लाल सेना ने शत्रु का सामना किया तथा उसकी एक पूरी की पूरी डिवीजन का सफाया कर दिया। लाल सेना हमेशा पहली लड़ाई जीतने के लिए पूरा जोर लगाती थी, तथा उसे हर हाल में जीतना होता था, क्योंकि इसमें हार-जीत समूची परिस्थिति, यहां तक की अंतिम मुठभेड़ पर भी बेहद असर डालती थी । यद्यपि श्युनखओ की लड़ाई जीत ली गई थी, परन्तु मुहिम के निर्देशकों ने, जो पूर्णतया रक्षात्मक फौजी कार्यदिशा के पक्षधर थे, इस लड़ाई को जवाबी घेराबंदी मुहिम की पहली लड़ाई के तौर पर स्वीकार नहीं किया, न ही उन्होंने युद्ध को विजय मार्ग की ओर ले जाने के लिए इस लड़ाई से होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाया । इसके बजाय, वे केवल एक कस्बे के हाथ से चले जाने पर ही घबरा उठे, तथा उन्होंने उसे (लीछ्वान) वापिस लेने व शत्रु को आधार-क्षेत्र की सीमा से बाहर रोकने का प्रयास किया । पहले लाल सेना ने लीछ्वान के उत्तर में, श्वेत क्षेत्र में स्थित श्याओशि पर आक्रमण किया । इस हमले में हार जाने के बाद उसने श्योओशि के दक्षिणपूर्व में चिशीछ्याओ पर हमला किया, लेकिन दोबारा भी उसे कोई सफलता नहीं मिली । इसके बाद तो लाल सेना शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्ति और उसकी किलेबन्दियों के बीच आगे-पीछे भटकती रही तथा उसकी अवस्था बिल्कुल निष्क्रियता की हो गई ।

दिसंबर में शत्रु ने लीछ्वान के दक्षिण में श्वानछुन पर हमला किया । क्योंकि इस लड़ाई में लाल सेना की शक्ति बँटी हुई थी, इसलिए शत्रु को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सका । जब शत्रु के सैन्य-दल पुनः इकट्ठे होकर आधार-क्षेत्र को कुतरते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़े, तब लाल सेना च्येननिङ-थाएनिङ मार्ग की रक्षा करते हुए, फूच्येन-च्याङशी की सीमा पर तशङक्वान तथा ताशानलिङ में पीछे हट गई ।

फूच्येन घटना के समय, शत्रु ने अपने कुछ सैन्य-दल 19वीं राह सेना पर हमला करने के लिए हटा लिए थे तथा केन्द्रीय आधार-क्षेत्र के मोर्चे पर रक्षात्मक कार्यवाही पर उतर आया था व समूचे युद्ध-मोर्चे पर रक्षात्मक मोर्चेबन्दियों का निर्माण कर रहा था । लाल सेना के लिए दुश्मन का सफाया करने का यह सुनहरी मौका था । लेकिन "वामपंथी" कार्यदिशा के निर्देशन के तहत, शत्रु पर जवाबी हमला करने की बजाय, लाल सेना ऊच्याङ (चीश्वेइ के दक्षिणपूर्व में), शनखाङ तथा थाङखओ की तरफ आगे बढ़ी । और शत्रु सेना की श्रेष्ठता तथा 19वीं राह सेना की अन्दरूनी फूट के कारण फूच्येन की जन-सरकार धराशायी हो गई ।

इसके बाद शत्रु ने लाल सेना पर हमले के लिए अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित किया। नौ महीनों तक काङतू (च्येननिङ के उत्तर-पश्चिम में), च्येननिङ तथा थाएनिङ के इलाके में डटे रहने के पश्चात, आखिरकार लाल सेना को विवश होकर पीछे हटना पड़ा ।

इसके बाद शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्ति कानच्वी से क्वाङछाङ की ओर आगे बढ़ी, जो

कि केन्द्रीय लाल इलाके का उत्तरी प्रवेश द्वार था । शत्रु के उत्तरी कालम द्वारा क्वाङ्छाङ पर कब्जा करने का उद्देश्य अपने सभी दूसरे कालमों के साथ तालमेल बिठाते हुए केन्द्रीय लाल इलाके पर एक संयुक्त आक्रमण को निश्चित करना था । "वामपंथी" नेताओं ने मोर्चेबद्ध लड़ाई की रणनीति अपनाई; उन्होंने शत्रु की तरह ही अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित करने तथा किलेबन्दियों का निर्माण करने की कार्यनीति अपनाई । अस्त्रों-शस्त्रों की बेहद कमी होते हुए भी, लाल सेना ने शत्रु को भारी क्षति पहुँचाई, परन्तु वह अपने खूंटे से बंधी हुई थी, नतीजतन उसमें लचीलेपन का अभाव था । इस कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा वह शत्रु को रोकने में विफल रही ।

क्वाङ्छाङ की लड़ाई के बाद, शत्रु का पहला कालम थाएहो से शिङक्वो की ओर बढ़ा, दूसरा कालम थङथ्येन से खुलुङकाङ की तरफ तथा तीसरा कालम निङतू व शछङ की ओर बढ़ा । इन मार्गों पर महत्त्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा के लिए लाल सेना ने अपनी सैन्य-शक्ति को बिखेर दिया तथा शत्रु को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया । क्वाङ्छाङ के दक्षिण भाग में काओहुनआओ तथा वानन्येनथिङ की लड़ाइयों में लाल सेना ने एक के बाद दूसरे मोर्चे पर हमलावर शत्रु का मुकाबला करते हुए पूर्णतया मोर्चेबद्ध लड़ाई की कार्यनीति अपनाई । और इस पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम के दौरान मोर्चेबद्ध लड़ाई की कार्यनीति अपनी चरमसीमा पर पहुँच गई । यद्यपि शत्रु को भारी क्षति पहुँची थी, लेकिन लाल सेना भी गंभीर क्षति के कारण बेहद कमजोर हो गई थी । इसके बाद ईच्येन (शछङ के उत्तर में) की लड़ाई हुई । लाल सेना लगातार पीछे हटती गई तथा आधार-क्षेत्र कदम-ब-कदम सिकुड़ता चला गया ।

ईच्येन की लड़ाई के बाद, शिङक्वो-काओशिङच्वी-लाओइङपान मार्ग पर भी लाल सेना उसी प्रकार शिङक्वो के दक्षिण में पीछे हट गई ।

सारांश यह कि पाँचवीं जवाबी घेराबंदी मुहिम के दौरान "वामपंथी" अवसरवादी कार्यदिशा के नेताओं ने एक के बाद दूसरी गंभीर गलतियां कीं । वे श्युनखओ की प्रारंभिक विजय से लाभ उठाने में विफल रहे, फूच्येन जन-सरकार की मदद करने से इंकार किया, तथा शत्रु पर "दोनों मुक्कों से दोनों दिशाओं में प्रहार करने" पर अड़े रहे, यानि की केन्द्रित शत्रु सेना का मुकाबला क्रान्तिकारी सैन्य-शक्तियों को केन्द्रित करके करने तथा सभी मोर्चों की रक्षा के लिए लाल सेना को विभक्त कर देने की जिद पर अड़े रहे । संक्षेप में, ये गलतियां तथा ऐसी ही दूसरी गलतियां, वे नकारात्मक कदम या निष्क्रिय कार्यनीतियां थीं, जिसके कारण लाल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा वह शत्रु को रोकने में नाकामयाब रही । फलतः एक साल से ज्यादा समय तक लड़ने के बाद भी, लाल सेना घेराबन्दी को ध्वस्त न कर सकी तथा अन्त में उसे च्याङशी के आधार-क्षेत्र से हटना पड़ा ।

च्याङ काई-शेक की घेराबंदी को तोड़ने तथा नई सफलताएं अर्जित करने के लिए चीनी मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना ने, अक्तूबर 1934 में दुनिया को हिला देने वाला विशाल रणनीतिक स्थानांतरण शुरू किया, जो **लंबे अभियान** के नाम से प्रसिद्ध है ।

जुलाई 1934 में पार्टी ने उत्तरी चीन में जापानी हमलावरों के विरुद्ध सातवें सेना-ग्रुप को अपने हरावल दस्ते के रूप में भेजा था । यह दस्ता फूच्येन से चलकर चच्याङ और आनह्वेइ के रास्ते च्याङशी में दाखिल हुआ, जहां उसने कामरेड फाङ च-मिन के नेतृत्व वाली दसवीं फौजी कोर से मिलकर दसवें सेना-ग्रुप की स्थापना की । अनेक लड़ाइयां लड़ने के बाद, यह

इनके हाथ में आ गया था तथा सारे देश के बैंक नोटों का 78 प्रतिशत ये जारी करते थे । वास्तव में, ये सभी दूसरे बैंकों के लिए बैंक का कार्य करते थे तथा चीन के वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि पर इनका एकाधिकारवादी नियंत्रण था ।

नवम्बर 1935 में, च्याङ सरकार ने "कानूनी टेण्डर" (जैसा कि उसे नाम दिया गया) की नीति पर चलते हुए, लोगों की संपत्ति हड़पने व उसे "चार बड़े घरानों" की निजी संपत्ति में बदलने के लिए, अविनिमेय मुद्रा जारी की । यह लूट की सर्वाधिक नृशंस किस्म थी । जुलाई 1937 में जापान-विरोधी युद्ध भड़कने तक 140 करोड़ चीनी डॉलर की राशि के "कानूनी टेण्डर" जारी किए जा चुके थे ।

चार बड़े बैंकों को अपनी गतिविधियों के केन्द्र के रूप में रखते हुए "चार बड़े घरानों" ने वाणिज्य के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना व लूट मचाना शुरू कर दिया । सुङ घराने ने कपास, चावल तथा अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं का एक वाणिज्यिक ट्रस्ट स्थापित किया तथा देश के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया ।

1935 तथा 1936 के वर्ष राष्ट्रीय उद्योग तथा वाणिज्य के लिए संकट के वर्ष थे । वित्त पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद "चार बड़े घरानों" ने उद्योग पर अपना प्रभुत्व जमाने व एकाधिकार स्थापित करने की राह ली । सरकारी प्रबन्ध की आड़ में, "चार बड़े घरानों" ने मौजूदा अफसरशाहों के उद्योगों को अपने कब्जे में लेने के साथ-साथ, राष्ट्रीय उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, अपनी मुख्य संस्था के रूप में, 'राष्ट्रीय संसाधन कमीशन' की स्थापना की । उनकी वुलफ्रैम खानें, इस्पात व इन्जिनियरिंग उद्योग साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चलाए जाते थे । निजी पूँजीपतियों के छद्म वेश में तथा अतिरिक्त पूँजीनिवेश, पुनर्गठन व बहुत ज्यादा ब्याज पर ऋण देने जैसे हथकण्डों द्वारा, "चार बड़े घरानों" ने निजी स्वामित्व वाले उद्योगों को (जब ये उद्योग आर्थिक संकट में थे) अपने कब्जे में ले लिया तथा उनके मालिक बन बैठे । सूती वस्त्र उद्योग में यह खास तौर से सुस्पष्ट था। सन् 1937 के पूर्वार्द्ध में "चार बड़े घरानों" द्वारा कब्जे में लिये गए या उनके प्रबन्धन में चल रहे सूती मिलों के तकलों का अंश, चीन के कुल तकलों का 13 प्रतिशत था ।

कृषि क्षेत्र में, "चार बड़े घराने" देश के सबसे बड़े जमींदार थे तथा किसान वर्ग के क्रूरतम शोषक थे । प्रतिक्रियावादी शासन के समर्थन से उन्होंने सारे देश में किसानों पर भारी टैक्सों का बोझ लाद दिया, उन्हें बेगार करने पर मजबूर किया, उनकी सेना में जबरन भर्ती की तथा उनकी जमीनों का बिना मुआवजे के अधिग्रहण किया ।

वित्त, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि पर अपने एकाधिकारवादी नियंत्रण द्वारा, "चार बड़े घरानों" ने जनता को लूटा तथा देश के सबसे बड़े नरपिशाचों के रूप में कुख्यात हो गए ।

विदेशी सहायता के बदले में चीन की संप्रभुता को बेचकर च्याङ काई-शेक गुट ने अपना प्रतिक्रियावादी प्रभुत्व कायम रखा । इस गुट के प्रतिक्रियावादी शासनकाल में ही साम्राज्यवादियों ने चीन को एक औपनिवेशिक बाजार में बदलने की प्रक्रिया को पूरा किया ।

साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पूँजीनिवेश चीन की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं में घुसपैठ कर गया तथा उसने उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 1936 में चीन के कोयला उत्पादन का 55.7 प्रतिशत विदेशी पूँजी के कारण था जब कि चीन की लौह-खानें लगभग पूरी तरह जापानी पूँजी के कब्जे में थीं । 1937 में चीनी रेलवे के कुल पूँजी-निवेश

आया । पूँजीवाद के खात्मे से समाजवादी प्रणाली ही सोवियत-संघ के उद्योग में एकमात्र प्रणाली बन गई ।

कृषि क्षेत्र में, 1933 में, अनाज की फसलें जितने क्षेत्र में बोई गईं, उसके 84.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व, अर्थव्यवस्था की समाजवादी प्रणाली ने किया, जबकि निजी किसान अर्थव्यवस्था का अंश केवल 15.5 प्रतिशत था । सामूहिक फार्मों ने स्थायी जीत अर्जित कर ली थी तथा सोवियत-संघ के किसानों ने सदा-सदा के लिए समाजवाद को अपना लिया था।

अपनी विदेश नीति में सोवियत-संघ ने लगातार युद्ध का विरोध किया तथा शांति की रक्षा की । इसलिए उसके हितों की माँग थी कि वह उन देशों के साथ नज़दीकी सम्बन्ध बनाए जो शांति भंग करने के इच्छुक नहीं थे ।

1934 के अंत में, जब जर्मनी, इटली व जापान राष्ट्र-संघ से बहिर्गमन कर चुके थे, सोवियत-संघ इसमें सम्मिलित हुआ । अपनी कमजोरियों के बावजूद राष्ट्र-संघ हमलावरों को नंगा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता था । इसलिए सोवियत-संघ ने हमले के विरुद्ध अपने संघर्ष में राष्ट्र-संघ का इस्तेमाल किया । उसने दूसरे देशों के साथ आपसी-सहयोग संधियों पर हस्ताक्षर किये, मई 1935 में फ्रांस व चेकोस्लोवाकिया के साथ तथा मार्च 1936 में मंगोलियाई जनवादी गणतंत्र के साथ सहयोग संधि की । ●

2.

- **चीनी अफसरशाह-पूँजीवाद की उत्पत्ति ।**
- **क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों का औपनिवेशीकरण ।**
- **चीन में अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान के बीच संघर्ष ।**

नानकिङ में फासीवादी सैनिक तानाशाही स्थापित करने के बाद, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने अफसरशाह-पूँजीपतियों का आर्थिक एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया, इसका प्रतिनिधित्व—च्याङ काई-शेक, टी०वी० सुङ, एच०एच०खुङ तथा छन बन्धुओं (छन क्वो-फू तथा छन ली-फू) के "चार बड़े घराने" कर रहे थे ।

इन "चार बड़े घरानों" की एकाधिकारवादी गतिविधियाँ निम्नलिखित चार बैंकों के इर्द-गिर्द केन्द्रित थीं : 'सैन्ट्रल बैंक ऑफ चाइना', 'बैंक ऑफ चाइना', 'बैंक ऑफ कम्युनिकेशन्ज' तथा 'फार्मरज बैंक ऑफ चाइना' । सैंट्रल बैंक ऑफ चाइना की स्थापना 1928 में की गई थी । तथाकथित "राजकीय बैंक (स्टेट बैंक)" होने के नाते इसे बैंक नोट जारी करने, राष्ट्रीय मुद्रा के सिक्के ढलवाने व प्रसारित करने तथा सरकारी बाँड जारी करने का अधिकार प्राप्त था । सरकारी खजाने का कार्यभार भी इसके पास था । 1928 से 1935 के बीच, च्याङ सरकार ने 'बैंक ऑफ चाइना' तथा 'बैंक ऑफ कम्युनिकेशन्ज' में सरकारी पूँजी की हिस्सेदारी बढ़ाकर उन पर अधिकार कर लिया, जो कि पहले उत्तरी युद्ध-सरदार सरकार के आर्थिक आधार स्तम्भ थे । 1935 में 'फार्मरज़ बैंक ऑफ चाइना' की स्थापना की गई ।

इन चार बड़े बैंकों की, सभी चीनी बैंकों के बीच एकाधिकार की स्थिति थी । 1936 तक चीन के बैंकों की सभी परिसम्पत्तियों का 59 प्रतिशत तथा जमा खातों का 59 प्रतिशत

नया सेना-ग्रुप 1934 के अंत में ह्वाएय्वी पहाड़ों में आ गया । वहां क्वोमिंताङ की सैन्य-शक्तियों के साथ एक मुठभेड़ में यह पराजित हो गया । कामरेड फाङ च-मिन को जनवरी 1935 में बन्दी बना लिया गया तथा जुलाई 1935 में वे नानछाङ में वीरतापूर्वक शहीद हो गए । बाकी बचे सैन्य-दल ने कामरेड सू य्वी की कमान में, फूच्येन-चच्याङ-च्याङशी सीमा पर छापामार लड़ाई जारी रखी ।

पार्टी की केन्द्रीय समिति के आदेशों का पालन करते हुए, छठे सेना-ग्रुप ने कामरेड रन पी-श के नेतृत्व में, अगस्त 1934 में हुनान-च्याङशी आधार-क्षेत्र खाली कर दिया । इसने लाल सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियों के हरावल दस्ते के रूप में आगे बढ़कर रास्ता खोलने तथा शत्रु की टोह लेने के लिए उसकी घेराबन्दी को तोड दिया । दिसंबर 1934 में पूर्वी क्वेइचओ में छठे सेना-ग्रुप तथा कामरेड हो लुङ के नेतृत्व वाले दूसरे सेना-ग्रुप को मिलाकर, दूसरी मोर्चा-सेना कायम की गई तथा हुनान-हुपे-सछ्वान-क्वेइचओ क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना की गई ।

सितंबर में लाल सेना की 25वीं फौजी कोर ने, जो हुपे-हनान-आन्ह्वेइ के इलाके में कार्यवाही कर रही थी, हनान में लोशान नामक स्थान पर शत्रु की घेराबन्दी को तोड़ दिया, तथा शेनशी के दक्षिणी भाग में घुसकर, हनान-हुपे-शेनशी आधार-क्षेत्र की स्थापना की ।

जापान-विरोधी हरावल दस्ते के उत्तर की ओर प्रस्थान ने, छठे सेना-ग्रुप के पश्चिम की ओर बढ़ने ने तथा 25वीं फौजी कोर के उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थान ने केन्द्रीय आधार-क्षेत्र की पहली मोर्चा-सेना तथा देशभर में लाल सेना की दूसरी यूनिटों के विशाल रणनीतिक स्थानांतरण को मजबूत सहारा प्रदान किया ।

अक्तूबर 1934 में लाल सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियों ने, पृष्ठभागीय संस्थाओं के स्टाफ को साथ लेकर, लगभग एक लाख की तादाद में फूच्येन के छाङथिङ और निङह्वा से और

लंबे अभियान के दौरान आगे बढ़ता एक लाल सैन्य-दल

च्याङशी के रुइचिन व य्वीतू नामक स्थानों से कूच कर दिया और एक विशाल रणनीतिक स्थानांतरण प्रारंभ किया । च्याङशी में आनय्वान तथा शिनफङ के बीच शत्रु की पहली घेराबंदी को तोड़ते हुए वे क्वाङतुङ के उत्तरी हिस्से में पहुँच गये । फिर हुनान में क्वेइतुङ तथा रूछङ के बीच उन्होंने शत्रु का दूसरा घेरा तोड़ा तथा ईचाङ पर कब्जा कर लिया । इसके बाद उन्होंने कैंटन-हानखओ रेलमार्ग पर तीसरा घेरा तोड़ा तथा लिनऊ व दूसरी काउंटियों पर कब्जा कर लिया । इसके बाद लाल सेना अलग-अलग रास्तों से पश्चिम की ओर बढ़ी, श्याओ नदी पार की तथा तेजी से क्वाङशी की सीमा की ओर बढ़ गई ।

नवंबर के अंत में, लाल सेना श्याङ नदी के पूर्वी किनारे पर पहुँच गई, जबरदस्ती नदी पार की, तथा शत्रु के चौथे घेरे को तोड़कर निकल गई । क्वाङशी में शीयेन पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ते हुए, वह क्वेइचओ प्रान्त के पूर्वी हिस्से में दाखिल हुई तथा लीफिङ, चिनफिङ, शफिङ, य्वीछिङ व दूसरी काउंटियों पर कब्जा कर लिया ।

फिर वह चुनई की ओर बढ़ चली । रास्ते में उसने वाङ च्या-ल्ये के नेतृत्व वाले क्वोमिंताङ सैन्य-दल को पराजित किया । ऊच्याङ नदी को पार करके, उसने 6 जनवरी, 1935 को चुनई पर अधिकार कर लिया। यहां पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की एक विस्तृत मीटिंग बुलाई गई । यह प्रसिद्ध **चुनई कान्फ्रेंस थी ।** ●

6.

- **चुनई कान्फ्रेंस का संघर्ष**
- **लाल सेना के जापान-विरोधी उत्तर की ओर अभियान में चाङ क्वो-थाओ की गलत कार्यदिशा का विरोध ।**
- **लम्बे अभियान में लाल सेना की विजय ।**

जनवरी 1935 में लाल सेना द्वारा चुनई पर कब्जा करने के बाद केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की विस्तृत मीटिंग बुलाई गई, ताकि संकटग्रस्त लाल सेना तथा चीन के क्रान्तिकारी ध्येय की रक्षा की जा सके । उस समय तक "वामपंथी" अवसरवाद की गलतियों ने कार्यकर्ताओं तथा लाल सेना की पांतों में गंभीर असन्तोष उत्पन्न कर दिया था तथा बहुत से कामरेड जो एक बार "वामपंथी" गलतियां कर चुके थे, संभलने तथा उनके खिलाफ होने लगे थे । इस प्रकार, कामरेड माओ तथा अनेक दूसरे साथियों के दृढ़ संघर्ष, तथा बहुमत साथियों के समर्थन के फलस्वरूप, चुनई कान्फ्रेंस ने गलत "वामपंथी" फौजी कार्यदिशा का खण्डन किया तथा कामरेड माओ की सही कार्यदिशा को मान्यता दी । "वामपंथी" अवसरवादियों को उनके नेतृत्वकारी पदों से अलग कर दिया गया तथा कामरेड माओ की रहनुमाई में एक नये पार्टी नेतृत्व की स्थापना की गई ।

चुनई सम्मेलन ने पार्टी की केन्द्रीय समिति में "वामपंथी" कार्यदिशा के प्रभुत्व का तथा खासकर, "वामपंथी" अवसरवाद की फौजी गलतियों का खात्मा कर दिया और कामरेड माओ को समूची पार्टी के नेता के रूप में स्थापित कर दिया । इस प्रकार, लम्बे अभियान की अत्यधिक विषम व खतरनाक परिस्थितियों के दौरान पार्टी, लाल सेना की रीढ़ को (केन्द्र को) बचाए रखने व उसे फौलाद बनाने में सफल रही और इस प्रकार स्वयं को और क्रान्ति को

साम्राज्यवादी देशों ने अपनी विदेश नीति को अंधराष्ट्रवाद तथा युद्ध की तैयारी पर आधारित करते हुए तथा भावी युद्ध में अपने पृष्ठभाग को मजबूत करने के लिए, अपने अंदरूनी शासन प्रबन्ध में प्रतिक्रान्तिकारी आतंक तथा मजदूर व किसान वर्ग के दमन को जरूरी उपायों के रूप में लागू किया । वे अन्दरूनी तथा बाहरी अन्तर्विरोधों के एक ऐसे अगाध गर्त में डूबते जा रहे थे, जिस पर पार नहीं पाया जा सकता था ।

मौजूदा परिस्थिति से निपटने के एक रास्ते के रूप में एक नया साम्राज्यवादी युद्ध अत्यधिक नजदीक आता जा रहा था ।

तीन युद्धवादी साम्राज्यवादी देशों,—जर्मनी, इटली व जापान में, पूँजीवादी-जनवादी प्रणाली पूर्णतया नष्ट कर दी गई थी तथा फासीवादी तानाशाही स्थापित करने के लिए सरेआम आतंकवादी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे ।

अपनी विदेश नीति में, ये तीनों देश 'नौ-शक्ति संधि' व 'वार्सेल्स की संधि' से असंतुष्ट थे । वे इन संधियों को अपनी हमलावर गतिविधियों के रास्ते का रोड़ा समझते थे । इस प्रकार ये तीन हमलावर देश एक नए युद्ध का स्त्रोत बने । इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार ब्रिटेन तथा इटली के बीच के अन्तर्विरोध और ज्यादा तीव्र हो गए । जर्मनी पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा-रेखा को 'ठीक' करना चाहता था, इसलिए उसने आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया व पोलैण्ड पर कब्जा करने के लिए कमर कस ली । उत्तर-पूर्वी चीन पर कब्जा करने के बाद, जापान ने उत्तरी चीन तथा शेष चीन पर एक नया हमला शुरू कर दिया। जर्मनी और इटली ने वार्सेल्स की संधि तथा जापान ने नौ-शक्ति संधि की धज्जियाँ उड़ा दीं तथा ये तीनों देश राष्ट्र संघ (League of Nations) से बहिर्गमन कर गए ।

युद्ध द्वारा दुनिया का एक नया पुनर्बंटवारा सन्निकट आ गया था ।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नया युद्ध, जर्मनी, इटली और जापान के शासकों द्वारा शुरू किया गया । यह युद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विरुद्ध था तथा ब्रिटिश, फ्रांसीसी व अमरीकी साम्राज्यवाद के हितों के भी खिलाफ था, तथा इसका उद्देश्य तमाम दुनिया में अपने प्रदेशों (Territories) तथा प्रभाव-क्षेत्रों (Spheres of Influence) का पुनर्बंटवारा करना था ।

इस प्रकार तीन हमलावर देशों के गठजोड़ ने रूप लेना शुरू किया ।

इस कालावधि के दौरान सोवियत-संघ में औद्योगिक उत्पादन लगभग तीन गुना हो गया था, सन् 1935 में यह 1929 के स्तर से 293.4 प्रतिशत बढ़ गया था । ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात वह बुनियादी परिवर्तन था जो उद्योगों में विकास के फलस्वरूप सोवियत-संघ के आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचे में आया । इस कालावधि के दौरान सोवियत-संघ एक कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिक देश में बदल गया ; एक निजी कृषि-व्यवस्था वाले देश से, एक यंत्रीकृत व सहकारी कृषि-व्यवस्था वाले देश में बदल गया ।

सोवियत-संघ में औद्योगीकरण के तीव्र विकास से, उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मात्रा में औद्योगिक उत्पादन का पहला स्थान था। 1933 में यह उद्योग तथा कृषि के कुल उत्पादन का 70.4 प्रतिशत था। अत: सोवियत-संघ एक औद्योगिक देश बन गया।

सोवियत-संघ के एक कृषि-प्रधान देश से औद्योगिक देश में बदलने से पूँजीवाद का खात्मा भी व्यक्त हुआ । समाजवादी प्रणाली ने उद्योगों में अत्यधिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली । 1935 में सोवियत-संघ में सभी औद्योगिक उत्पादों का 99.96 प्रतिशत समाजवादी उद्योग से

सातवां अध्याय

जापान-विरोधी जन-आंदोलन का नया उभार आन्तरिक शांति की स्थापना

(दिसंबर 1935 से जुलाई 1937)

1.

- 1933 से 1935 तक की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ।
- एक नए साम्राज्यवादी युद्ध की शुरुआत ।

1929 के उत्तरार्द्ध में पूँजीवादी देशों में जो आर्थिक संकट गहराया था वह 1932 के अंत तक चला । इसके बाद उद्योग में गिरावट रुक गई तथा संकट ने मंदी का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात् उद्योगों की हालत में भी कुछ सुधार हुआ । 1933 में पूँजीवादी देशों में उद्योगों की हालत कुछ हद तक सुधरने व संभलने लगी । 1933 के बाद के कुछ वर्षों तक यह सुधार जारी रहा । पूँजीवादी देशों में 1929 के औद्योगिक उत्पादन को 100 लेते हुए, 1935 में, जिस वर्ष जापान ने उत्तरी चीन पर हमला किया, अमरीका में यह 75.6 प्रतिशत था; बरतानिया में 105.8 प्रतिशत; फ्रांस में 67.4 प्रतिशत ; इटली में 93.8 प्रतिशत ; जर्मनी में 94 प्रतिशत ; तथा जापान में 141.8 प्रतिशत था । जापान और ब्रिटेन ने संकट पूर्व के स्तर को पार कर लिया था, जबकि जर्मनी व इटली उस स्तर के बिल्कुल करीब थे, लेकिन अमरीका तथा फ्रांस अभी भी उस स्तर से औसतन 25 प्रतिशत नीचे थे ।

पूँजीवादी संकट के इस मामूली तौर पर ढीला पड़ने या हल होने का कारण क्या था ? पहला, पूँजीवाद की अंदरूनी आर्थिक शक्तियों ने कुछ असर डाला था ; पूँजीवादी देशों में एकाधिकारवादियों ने श्रमिकों का शोषण तीव्र कर दिया था तथा अपने देशों व औपनिवेशिक एवं अर्ध-औपनिवेशिक देशों में कृषि-उत्पादों की कीमतें घटा दी थीं । दूसरे, यह ढीलापन साम्राज्यवादी लड़ाई के लिए तैयारी तथा पूँजीवादी देशों द्वारा मुद्रास्फीति की नीति पर चलने जैसे कृत्रिम कारकों के कारण था ।

इस कालावधि के दौरान जापान ने अपने हमले को उत्तर-पूर्व से उत्तरी चीन तक बढ़ा दिया । चीन से अत्यधिक मुनाफा बटोरने के बाद, जापान ने अपने अस्त्रों-शस्त्रों के भंडार का विस्तार किया तथा अपने हमलावर युद्ध को आगे बढ़ाया । इस प्रकार संकट के दौरान हुई हानि को उसने किसी हद तक पूरा कर लिया तथा उसके उद्यमों का भी कुछ हद तक पुनरुद्धार हुआ और उनकी हालत में कुछ हद तक सुधार आने की प्रवृत्ति प्रकट हुई ।

आर्थिक संकट ने पूँजीवादी देशों के अन्दरूनी तथा उनके बीच के अंतर्विरोधों को और अधिक तीव्र कर दिया।

भीषण खतरे से निकाल ले गईं । कामरेड माओ त्से-तुङ की रहनुमाई में केन्द्रीय समिति के नए नेतृत्व की शुरुआत, पार्टी में बेहद ऐतिहासिक महत्त्व का परिवर्तन था । इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा चीनी क्रान्ति इस महान, श्रेष्ठ तथा पूर्णतया विश्वसनीय नेता के मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेतृत्व के अन्तर्गत विजय पर विजय प्राप्त करती चली गईं ।

चुनई सम्मेलन के बाद, पार्टी ने चलायमान लड़ाई की फौजी कार्यदिशा अपनाई, तथा सेना का पुनर्गठन करके व साजोसामान में कमी करके, तीव्र व अचानक कार्यवाहियों से शत्रु को हैरान-परेशान करने व चकमा देने लगी ।

चुनई सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि लाल सेना को अपना उत्तर की ओर अभियान जारी रखना चाहिये । अत: क्वोमिंताङ ने लाल सेना को सछ्वान में याङत्सी नदी पार करने से रोकने के लिए तथा सछ्वान-शेनशी आधार-क्षेत्र की चौथी मोर्चा-सेना के साथ मिलने से रोकने के लिए, जल्दी से अपनी फौजों को दोबारा तैनात किया । लाल सेना पहले, सछ्वान से पश्चिम की तरफ युन्नान में वेइशिन की ओर बढ़ी, फिर क्वेइचओ की ओर पीछे मुड़कर तथा चुनई के पास अपनी मुख्य सैन्य-शक्ति को केन्द्रित करके, अपना तेजी से पीछा कर रहे क्वोमिंताङ के कई दस्तों को खदेड़ दिया । इस लड़ाई के बाद जब लाल सेना उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ी, तो च्याङ काई-शेक की फौजों ने उसका रास्ता रोक लिया तथा उसे दूसरी मोर्चा सेना से अलग कर दिया । तब लाल सेना क्वेइयाङ की ओर मुड़ गई तथा वहां से युन्नान की तरफ कूच कर गई । उसने क्रमश: सुङमिङ तथा श्युनथ्येन पर अधिकार कर लिया तथा खुनमिङ को घेर लिया । उस समय तक, लाल सेना क्वोमिंताङ फौजों को काफी पीछे छोड़ चुकी थी । पार्टी ने लाल सेना को चिनशा नदी पार करने का आदेश दिया । रणनीतिक स्थानांतरण के दौरान यह एक बेहद महत्त्वपूर्ण कार्यवाही थी । चिनशा नदी पार करने के बाद, लाल सेना ने उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा तथा उसका हरावल दस्ता 15 मई 1935 को **तातू नदी** (TATU RIVER) के दक्षिण में आनशुनछाङ नामक जगह पर पहुँच गया । गोलियों की बौछारों में नदी को जबरदस्ती पार किया गया तथा लाल सेना नदी के दोनों किनारों के साथ-साथ सीधे **लूतिङ के पुल** (LUTING BRIDGE) की तरफ बढ़ चली ।

याङत्सी नदी की सहायक नदी, तातू नदी, खड़े पहाड़ों में से होती हुई तेज गति से बहती है । यह 300 मीटर से भी अधिक चौड़ी थी तथा इसकी गहराई 7 से 12 मीटर के बीच थी। शत्रु द्वारा लगातार रास्ता रोकने व पीछा करने के बावजूद, लाल सेना ने 29 मई को आनशुनछाङ के उत्तर में नदी पर बने रणनीतिक महत्त्व के लूतिङ पुल पर कब्जा कर लिया। फिर चिनछ्वान व लूशान से गुजरकर, लाल सेना ने च्याचिनशान पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी, जो सछ्वान-शीखाङ सीमा पर स्थित विशाल बर्फीले पहाड़ों के धुर दक्षिणी छोर की एक ऊंची चोटी है । 16 जून, 1935 को पश्चिमी सछ्वान के माओकुङ में केन्द्रीय लाल सेना व चौथी मोर्चा-सेना आपस में मिल गईं तथा उन्होंने उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखते हुए विशाल बर्फीले पहाड़ों की एक और ऊंची चोटी मङफीशान को पार किया । 10 जुलाई को लाल सेना सुङफान काउंटी के दक्षिण-पश्चिम में माओअड़काए नामक स्थान पर पहुँच गई ।

तब ऐसा हुआ कि चौथी मोर्चा-सेना में काम करने वाले चाङ क्वो-थाओ ने, शत्रु के हमले का सामना होने पर पलायनवाद तथा युद्धपतिवाद के प्रति गंभीर रुझान प्रकट किया । उसे क्रान्ति के भविष्य में कोई भरोसा न रहा क्योंकि उसने जापान-विरोधी जनवादी आंदोलन

के राष्ट्रव्यापी उत्थान को नकार दिया, तथा शत्रु की ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर आंका तथा क्रान्तिकारी शक्तियों को बेहद कमजोर समझा । इस प्रकार पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा उसके बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया । केन्द्रीय समिति का मानना था कि लाल सेना को उत्तर की ओर आगे बढ़ना चाहिये तथा दिन-प्रतिदिन तेज होते जापान-विरोधी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए शेनशी-कानसू-निङश्या सीमांत क्षेत्र में एक आधार-क्षेत्र का निर्माण करना चाहिये । परन्तु चाङ क्वो-थाओ ने इस नीति का विरोध किया तथा इसके बजाय उसने शीखाङ तथा तिब्बत के अल्पसंख्यक-जातीय क्षेत्रों में पीछे हटने की पराजयवादी कार्यदिशा की पैरवी की ।

चाङ क्वो-थाओ की लाल सेना को अल्पसंख्यक-जातीय क्षेत्रों में पीछे हटाने की इस गलत कार्यदिशा से न केवल लाल सेना तथा राष्ट्रव्यापी जापान-विरोधी आंदोलन गंभीर रूप से कमजोर पड़ जाते, बल्कि क्रान्तिकारी उद्देश्य भी पूरी तरह लड़खड़ा जाता ।

लाल सेना ने विशाल बर्फीले पहाड़ों में एक माह आराम किया । इस अन्तराल के दौरान पार्टी की केन्द्रीय समिति ने माओकुङ तथा माओअड़काए में दो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन किये, दोनों ही सफल रहे, तथा चाङ क्वो-थाओ की पलायनवादी कार्यदिशा को अस्वीकृत कर दिया गया।

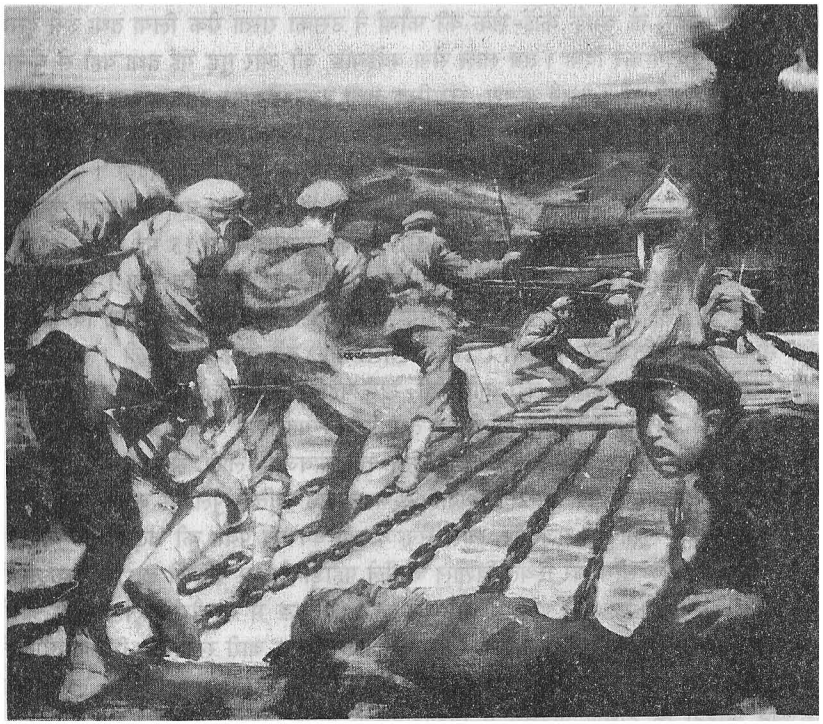

लूतिङ पुल :- लंबे अभियान के दौरान तातू नदी पर बने इस पुल पर कब्जा करना चीनी लाल सेना के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था । बहुत संभव था कि यदि लाल सेना इस नदी को पार न कर पाती तो उसे वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया जाता

अक्तूबर 1934 से अक्तूबर 1935 तक के बारह महीनों के दौरान, केन्द्रीय लाल सेना ग्यारह प्रान्तों (फूच्येन, च्याङशी, क्वाङतुङ, हुनान, क्वाङशी, क्वेइचओ, सछ्वान, युन्नान, शीखाङ, कानसू तथा शेनशी) में से गुजरी, ऊँचे हिमाच्छादित पहाड़ों तथा मार्गहीन व निर्जन घास के दलदले मैदानों को पार किया, तथा बार-बार शत्रु द्वारा की गई घेराबन्दियों तथा पीछा करने, रास्ते में रुकावट डालने व रास्ता छेंकने की कार्यवाहियों को विफल किया । उसने 12,500 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया, असंख्य फौजी तथा राजनीतिक समस्याओं तथा साथ ही प्राकृतिक रुकावटों पर विजय पाई तथा अन्त में विजय पताका फहराते हुए उत्तरी शेनशी के क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र में पहुँचकर, उत्तरी लाल सेना से जा मिली । पाँचवीं जवाबी घेराबन्दी मुहिम से पहले लाल सेना की शक्ति बढ़कर तीन लाख सैनिक हो गई थी । लेकिन "वामपंथियों" के गलत नेतृत्व तथा चाङ क्वो-थाओ की विघटनवादी गतिविधियों व तोड़-फोड़ के फलस्वरूप, उसे बेहद क्षति उठानी पड़ी । जब वह उत्तरी शेनशी पहुँची तो उसकी संख्या घटकर 30,000 से भी कम रह गई थी । तो भी ये लाल सेना तथा पार्टी का सारभाग थे तथा चीनी जनता का अनमोल खजाना थे ।

यह एक अत्यधिक ऐतिहासिक महत्त्व की बात थी कि लाल सेना के तीन मुख्य सैन्य-दलों ने अपनी स्थितियों में इतना विराट स्थानांतरण किया तथा वे सफलतापूर्वक एक-दूसरे से मिल गए । कामरेड माओ त्से-तुङ के शब्दों में, **"लम्बा अभियान अपने ढंग की पहली घटना है जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती ; वह एक घोषणा-पत्र है, एक प्रचार-दल है, बीज डालने वाली मशीन है ।"**[13] एक नया ऐतिहासिक रिकार्ड इसलिए, क्योंकि लंबा अभियान विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी ; एक घोषणा-पत्र इसलिये, क्योंकि उसने लाल सेना की अपराजेयता की पुष्टि की तथा साम्राज्यवादियों व च्याङ काई-शेक के गठजोड़ की घेराबन्दी मुहिमों की विफलता को प्रमाणित किया ; एक प्रचार-दल इसलिए, क्योंकि उसने चीन के विशाल भूभाग में घोषणा की कि लाल सेना का रास्ता ही जनता की मुक्ति का रास्ता था ; तथा अन्त में बीज डालने वाली मशीन इसलिए, क्योंकि उसने ग्यारह प्रान्तों में क्रान्ति के बीज बोए ।

इस प्रकार लम्बे अभियान की समाप्ति लाल सेना की विजय तथा शत्रु की पराजय में हुई।

नोट

1. J.Stalin, Works, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1955, Vol. 12, - 262 (जोसेफ स्तालिन की रचनाएं, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, मास्को, 1955, भाग-12, पृष्ठ-262, अंग्रेजी में देखें ।)

2. सी०सी०गुट :- फासीवादी जासूसों की एक संस्था, जिसके मुखिया छन क्वो-फू तथा छन ली-फू नामक दो भाई थे । यह 1929 में स्थापित की गई थी ।

3. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, पेकिङ, पहला संस्करण, 1971, पृष्ठ-270

●●●

इसके बाद लाल सेना दो कालमों में बंट गई । एक कालम ने पूर्वी रास्ते से तथा दूसरे ने पश्चिमी रास्ते से उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा । पूर्वी रास्ते से बढ़ने वाला कालम सुङफान के पश्चिम में निर्जन व दलदले घास के मैदानों को पार करते हुए 28 अगस्त को पाशी पहुँचा। परन्तु, दूसरा कालम जब आपा पहुँचा, तो चाङ क्वो-थाओ ने निरंकुशतापूर्वक उसे दक्षिण की ओर मुड़ने तथा चिनछ्वान व लूशान की ओर बढ़ने का आदेश दिया । इसके अलावा उसने पूर्वी कालम में आगे बढ़ रहे चौथी मोर्चा-सेना के सैनिकों को घास के मैदानों को दोबारा पार करने व उसके साथ दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया । वह अपने सैन्य-दल को शीखाङ के कानचि क्षेत्र में ले गया तथा पार्टी व लाल सेना की एकता को तहस-नहस करते हुए एक नकली "केन्द्रीय समिति" की स्थापना की । इसके अलावा उसने पार्टी की केन्द्रीय समिति को खतरे में डालने का षड्यन्त्र भी रचा ।

लाल सेना का कामरेड माओ त्से-तुङ के नेतृत्व वाला हिस्सा, कानसू तथा शेनशी की दिशा में, दृढ़तापूर्वक उत्तर की ओर आगे बढ़ता रहा । 5 सितंबर को माओलुङ से चलकर, वे कानसू के दक्षिणी भाग में मिनश्येन में दाखिल हुए तथा थुङवेइ पर अधिकार कर लिया । ल्यूपानशान में शत्रु के घेरे को तोड़ते हुए, वे खुय्वान काउंटी के रास्ते, ह्वानश्येन काउंटी में पहुँचे । 19 अक्तूबर, 1935 को वे उत्तरी शेनशी में पाओआन काउंटी के ऊचीछन कस्बे में पहुँचे। वहां उत्तरी शेनशी की लाल सेना ने उनका स्वागत किया, जिसका नेतृत्व कामरेड ल्यू च-थान कर रहे थे ।

नवंबर 1935 में, मजदूरों तथा किसानों की लाल सेना की दूसरी मोर्चा-सेना ने हुनान-हुपे-सछ्वान-क्वेइचओ सीमान्त क्षेत्र में शत्रु की घेराबन्दी को तोड़ा, तथा जून 1936 में शीखाङ के कानचि में चौथी मोर्चा-सेना से मिल गई । चू तेह, रन पी-श, हो लुङ, क्वान श्याङ-इङ तथा दूसरे साथियों की दृढ़ एवम् निरंतर कोशियों के फलस्वरूप, चाङ क्वो-थाओ के विरोध के बावजूद, चौथी मोर्चा-सेना, दूसरी मोर्चा-सेना के साथ-साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ी । परन्तु जब दोनों मोर्चा सेनाएं, अक्तूबर 1936 में कानसू के ह्वेइनिङ तथा छिङनिङ पहुँची, तथा पहली मोर्चा-सेना से जाकर मिलीं, तब एक बार फिर चाङ क्वो-थाओ ने चौथी मोर्चा-सेना को पश्चिम में सिनच्याङ की तरफ बढ़ने का आदेश दिया । नतीजतन, एक छोटी सी टुकड़ी के अतिरिक्त, समूची चौथी मोर्चा-सेना चाङ क्वो-थाओ की गलत कार्यदिशा की भेंट चढ़ गई तथा सिनच्याङ के रास्ते में नेस्तनाबूद कर दी गई । लाल सेना के लिए यह एक गंभीर क्षति थी ।

माओकुङ, माओअड़काए तथा बाद में येनान में हुए पार्टी सम्मेलनों के कारण, जिनमें चाङ क्वो-थाओ की पार्टी-विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया गया, तथा पार्टी के अन्दरूनी संघर्ष को लेकर, पार्टी तथा कामरेड माओ त्से-तुङ द्वारा अपनाई गई सही नीति के कारण, चौथी मोर्चा-सेना ने शीघ्र ही केन्द्रीय समिति के सही नेतृत्व को स्वीकार कर लिया । चाङ क्वो-थाओ की गलतियों से निपटने के लिए, केन्द्रीय समिति ने लगातार शिक्षा व समझाने के तरीके अपनाए। उदारता की भावना के तहत उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका दिया गया था, इसके बावजूद भी उसने नकली केन्द्रीय समिति की स्थापना की। परन्तु ये तरीके उदारतापूर्ण व अत्यधिक न्यायोचित होते हुए भी इस अवसरवादी का पतन रोकने में विफल रहे, तथा अन्त में उसने क्रान्ति से गद्दारी करते हुए स्वयं को क्वोमिंताङ के हाथों बेच दिया ।

लंबे अभियान के दौरान दुर्गम, बर्फीले पहाड़—च्याचिन को पार करती लाल सेना (1934-35)

लंबे अभियान के दौरान निर्जन, दुर्गम्य एवम् दलदले घास के मैदानों को पार करती लाल सेना

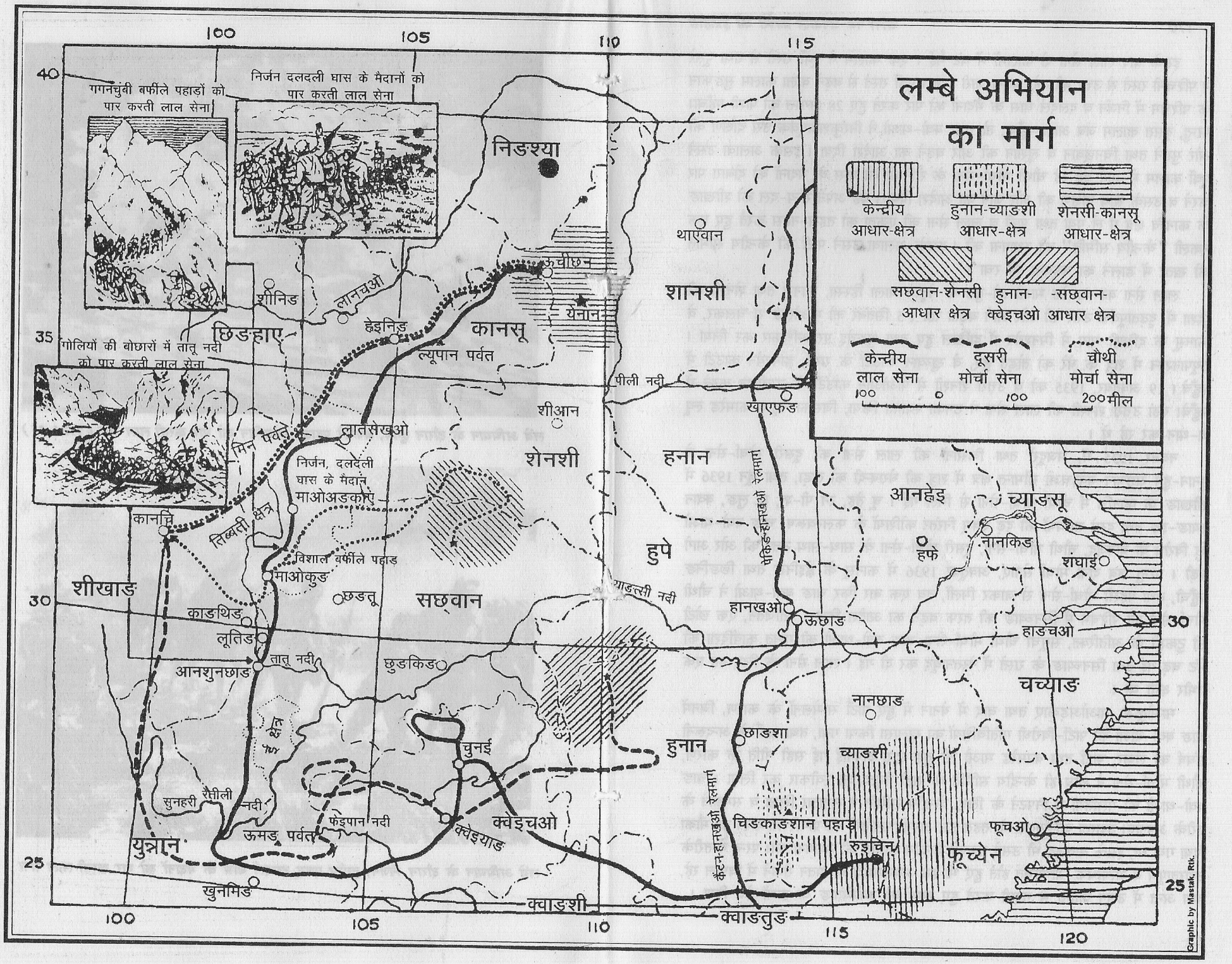

Graphic by Mastak, Rtk.

संघर्ष करना तथा अन्दरूनी सशस्त्र संघर्षों को रोकना रहा था । उस कालखण्ड के दौरान जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे को व्यावहारिक रूप से स्थापित करने के लिए, आंतरिक शांति के लिए संघर्ष करना एक अनिवार्य शर्त थी। क्वोमिंताङ के तीसरे पूर्ण अधिवेशन के बाद, चीनी क्रांति जापानी-आक्रमण-विरोधी काल में दाखिल हो रही थी । उस समय पार्टी का मुख्य कार्य देश में जनवाद तथा आजादी के लिए संघर्ष करना था । जापान के विरुद्ध युद्ध के लिए घरेलू शांति तथा जनता का लामबन्द होना जरूरी था, लेकिन जनवाद के बिना शांति, चाहे हासिल कर भी ली जाती, पर सुदृढ़ नहीं की जा सकती थी तथा लामबन्दी को कार्यान्वित करने का कोई रास्ता न था । अतः सशस्त्र प्रतिरोध की सफलता सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक जनवाद तथा आज़ादी के लिए संघर्ष करना एक केन्द्रीय कड़ी थी ।

राजनीतिक प्रणाली में तात्कालिक जनवादी सुधारों को लागू करना ज़रूरी था । पहला, सभी पार्टियों तथा वर्गों के आपसी सहयोग पर आधारित एक जनवादी स्वरूप की सरकार की स्थापना की जानी चाहिए थी । राष्ट्रीय असेम्बली के चुनावों के लिए अपनाया जा रहा अलोकतान्त्रिक तरीका बदला जाना चाहिये था तथा असेम्बली के लिए जनवादी तरीके से चुनाव करवाए जाने जरूरी थे, उसके बाद एक जनवादी संविधान बनाया जाना चाहिये था, फिर एक जनवादी संसद को बुलाकर जनवादी सरकार का चुनाव होना चाहिए था । दूसरे, लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार की, खासतौर से उनके विचार प्रकट करने, सभा करने तथा संगठन बनाने की आज़ादी के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए थी ।

संयुक्त मोर्चा बनाने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए, तथा जनवादी गणराज्य की स्थापना को साकार करने हेतु, जनता का दिल जीतने के अत्यधिक प्रयास करने निहायत जरूरी थे, यानि कि मजदूरों, किसानों तथा शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग को लामबंद करना तथा पूँजीपति वर्ग के जापान-विरोधी हिस्से को अपनी तरफ करना बेहद जरूरी था । अतः पार्टी का मुख्य कार्यभार कोटि-कोटि जनता को जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के पक्ष में करने के प्रयास करना, जापानी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना तथा राष्ट्रीय मुक्ति व सामाजिक मुक्ति को साकार करने के लिए प्रयास करना था ।

रिपोर्ट में जापान-विरोधी युद्ध में चीनी श्रमिक वर्ग के नेतृत्व के सवाल पर विशेष बल दिया गया था ।

सर्वहारा वर्ग पूँजीपति वर्ग का अनुसरण करे या पूँजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का ? चीनी क्रांति में नेतृत्व की जिम्मेदारी का यह प्रश्न ही वह धुरी है जिस पर क्रांति की सफलता या असफलता निर्भर करती है ।[7]

कामरेड माओ द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष का औचित्य, चीनी क्रांति के ऐतिहासिक अनुभव ने सिद्ध कर दिया । पूँजीपति वर्ग के अन्तर्निहित ढुलमुलपन तथा स्पष्टता की कमी पर, सर्वहारा वर्ग की धैर्यशीलता तथा पूर्णता का पर्याप्त रूप से विकास करके ही क्रान्ति में विजय पाई सकती थी । क्वोमिंताङ ने जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे के प्रति आमतौर से उदासीनतापूर्ण रवैया ही अपनाया । इस तथ्य के मद्देनजर, सर्वहारा वर्ग तथा उसकी पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई । सर्वहारा वर्ग के लिए अपनी पार्टी के द्वारा इस राजनीतिक नेतृत्व के लागू करने के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी थीं : पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टी का अनुकरणीय उदाहरण पेश करना, अपने

केवल अमरीका था जिसने शेष चीन में अपने पूँजी निवेश में किसी प्रकार की वृद्धि की, उसकी वृद्धि की दर 40 प्रतिशत तक पहुँच गई । क्वोमिंताङ सरकार अपने दो-तिहाई वित्तीय-ऋण अमरीका से प्राप्त करती थी ।

तीसरे, 1936 में, चीनी उद्यमों में (उत्तर-पूर्व को छोड़कर) साम्राज्यवादी निवेश 136.9 करोड़ डॉलर था । इसमें ब्रिटेन का हिस्सा सबसे बड़ा था—65.1 करोड़ डॉलर से ज्यादा । जापान 30.5 करोड़ डॉलर के हिस्से के साथ दूसरे नंबर पर था । तथा 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा पूँजी के साथ अमरीका सबसे छोटा हिस्सेदार था । चीन में माल तैयार करने वाले कारखानों में (उत्तर-पूर्व को छोड़कर), 28.1 करोड़ डॉलर के कुल साम्राज्यवादी पूँजी निवेश में जापान का हिस्सा सबसे बड़ा था, जो 14.0 करोड़ डॉलर से ज्यादा था । ब्रिटेन 10.7 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर था तथा अमरीका 2 करोड़ डॉलर वाला तीसरा व सबसे छोटा हिस्सेदार था ।

चीन में साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पूँजी का विकास अत्यंत विषम था ।

इस कालावधि के दौरान जापान ने चीन की लम्बी दीवार के दक्षिण में अपना हमला जारी रखा तथा सूती वस्त्र उद्योग, विद्युत-शक्ति, बैंकिंग, खनन उद्योग, रेलवे तथा उत्तरी चीन की बन्दरगाहों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया तथा अपनी जिन्सों का चीन में ढेर लगा दिया । यहां तक कि उनकी तस्करी भी की । शंघाई में, जापानी सूती वस्त्र मिलों का और अधिक विस्तार किया गया तथा चीनी मिलों के लिए कोई जगह न बची तथा उनके मुनाफे पर भी डाका डाला गया।

जापानी साम्राज्यवादियों की चीन को जीतने की नीति ने उत्तरी तथा मध्य चीन में ब्रिटिश व अमरीकी साम्राज्यवादियों के हितों को गंभीर संकट में डाल दिया व "चार बड़े घरानों" के आर्थिक आधार को चकनाचूर कर दिया ।

इस प्रकार एक ओर, ब्रिटिश व अमरीकी साम्राज्यवादियों और चीन में उनके पालतू कुत्तों— "चार बड़े घरानों", तथा दूसरी ओर, जापानी साम्राज्यवादियों के बीच अंतर्विरोधों की खाई दिन-प्रतिदिन और ज्यादा चौड़ी व गहरी होती चली गई ।

1935 की गर्मियों में, अमरीकी आर्थिक कमीशन चीन आया ; इसके बाद ब्रिटिश सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार, सर फ्रेडरिक लीथ-रोस, उसी साल की सर्दियों में चीन आया। ब्रिटेन तथा अमरीका के उकसावे पर च्याङ काई-शेक ने तथाकथित "मुद्रा सुधार" लागू किए तथा सैन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ चाइना तथा बैंक ऑफ कम्युनिकेशन्ज द्वारा जारी नोटों को ही एकमात्र "कानूनी टेन्डर" बना दिया तथा चाँदी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी । विदेशी मुद्रा को आधार मानते हुए, "कानूनी टेन्डर" को पाउंड-स्टर्लिंग से जोड़ दिया गया । विनिमय-दर से ऋण निर्धारित किया गया, जो कि एक ख्वान के लिए एक शिलिंग, अढ़ाई पेन्स था । यह दर कायम रखने के प्रयास में, चीनी चाँदी की बहुत बड़ी मात्रा अमरीका चली गई, तथा अमरीका के मुनाफे में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई । "कानूनी टेन्डर" नीति के परिणाम स्वरूप, च्याङ काई-शेक सरकार की मुद्रा पूर्णतया अमरीकी डॉलर तथा अंग्रेजी पाउंड के नियंत्रण में आ गई ।

साम्राज्यवादियों के दरम्यान संघर्ष ने क्वोमिंताङ में दरार डाल दी तथा नानकिङ सरकार जापान के प्रति अपनी नीति में डगमगाने लगी । क्वोमिंताङ के ब्रिटिश-परस्त व अमरीका-परस्त

गुट के नेताओं तथा जापान-परस्त गुट के नेताओं के दरम्यान, दरार लगातार बढ़ती जा रही थी। नानकिङ सरकार में मौजूद पहले गुट के लोगों ने, जनता में बढ़ रही जापान-विरोधी भावनाओं के मद्देनजर तथा अमरीकी व बरतानवी सरकारों के प्रभावों में आकर, जापान के प्रति अपनी नीति को बदलना शुरू कर दिया ।

1935 के अन्त में, जापान-परस्त गुट के सरगना—वाङ चिङ-वेइ तथा गुट के एक सदस्य थाङ ग्वी-रन की हत्या करने की कोशिश की गई । फिर इसके बाद क्वोमिंताङ सरकार में फेर-बदल हुआ, जिसके फलस्वरूप जापान-परस्त गुट का स्थान, च्याङ काई-शेक के अमरीका व बरतानिया-परस्त गुट ने ले लिया तथा वाङ व च्याङ में फूट पड़ गई । सितंबर से दिसंबर 1936 के बीच, जापानी राजदूत कावागोई तथा च्याङ सरकार के विदेश मंत्री—छाङ छुन के बीच अनेक वार्ताएं हुईं । लेकिन च्याङ ने जानबूझकर वार्ताओं को लंबा खींचा तथा उन्हें निष्फल कर दिया ।

1935 में उत्तरी चीन पर जापानी हमले से, चीन तथा जापान के बीच का अंतर्विरोध, मुख्य अंतर्विरोध बन गया । इससे विदेशी संबंधों में, तथा चीन के अंदरूनी वर्ग-संबंधों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के मद्देनजर, मई 1936 के बाद, पार्टी ने च्याङ काई-शेक को जापान का मुकाबला करने के लिए बाध्य करने की नीति अपनाई तथा चीन के जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे को विश्व के फासीवाद-विरोधी शान्ति-मोर्चे से जोड़ने का उद्देश्य सामने रखा ।

3.

- **उत्तरी चीन पर जापानी साम्राज्यवादी हमला ।**
- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जापान का प्रतिरोध करने तथा राष्ट्र को बचाने की घोषणा ।**
- **जापान का प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में नया उभार ।**

1935 में जापानी हमलावरों ने उत्तरी चीन पर एक नया हमला किया ।

इससे पहले, जापान सरकार का दावा था कि जापान एशिया का स्वामी तथा चीन का रक्षक था तथा किसी दूसरे देश को चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, तथा न ही चीन, जापान के अलावा किसी अन्य देश से संबंध स्थापित कर सकता था । यह घोषणा करते हुए कि चीन एकमात्र उसके नियंत्रण में एक उपनिवेश था, जापान ने सरेआम अन्य साम्राज्यवादियों को निकाल बाहर किया । 17 अप्रैल, 1934 को जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा चीन के बारे में दिए गए वक्तव्य का यह मुख्य उद्देश्य था ।

उस समय, च्याङ काई-शेक अभी भी इसी भ्रम में था कि पीली नदी के दक्षिण में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं मिलेगी । तथापि 29 मई, 1935 को जापानी युद्ध-सरदारों ने, इस आड़ में कि चीन उत्तर-पूर्व में स्वयंसेवकों को मदद दे रहा था, अत्यधिक बेहूदा मांगें पेश कीं । जापानी फौजों ने उत्तरी चीन में घुसना आरंभ कर दिया, जिससे पेकिङ व थ्येनचिन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया, तथा जापानी युद्ध-सरदारों ने उनकी शर्तें न माने जाने की हालत में "स्वतन्त्र कार्यवाही" करने की धमकी दी ।

घटना के शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी की । फलतः च्याङ काई-शेक द्वारा कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाने तथा जापान का प्रतिरोध करने की शर्तों को मानने के बाद, चाङ तथा याङ ने उसे रिहा कर दिया ।

फरवरी 1937 में आयोजित क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में, क्वोमिंताङ के जनवादी धड़े की ओर से सुङ छिङ-लिङ ने क्वोमिंताङ से डॉ० सुन यात-सेन की तीन महान नीतियों का अनुसरण करने, जनता को लामबन्द करने तथा उसके रहन-सहन के हालातों में सुधार करने, गृहयुद्ध को समाप्त करने तथा कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य सभी जनवादी ताकतों से सहयोग करने, तथा आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में, सोवियत-संघ के नेतृत्व वाले सभी देशों, जो कि चीनी जनता के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे, के साथ एकजुट होने का आग्रह किया । जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की स्थापना को सफल बनाने के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ के तीसरे पूर्ण अधिवेशन के नाम एक तार भेजा, जिसमें उसने निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करने का वचन दिया :

1. कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में काम करने वाली शेनशी-कानसू-निङश्या क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की सरकार को विशेष प्रदेश की सरकार का नया नाम देना ।
2. लाल सेना का पुनर्नामकरण (यानि कि लाल सेना, राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना का हिस्सा कहलाएगी—अनुवादक)
3. सशस्त्र विद्रोह की नीति का परित्याग ।
4. जमींदारों की जमीनों की जब्ती बन्द करना ।

इसके साथ ही पार्टी ने क्वोमिंताङ से निम्न पाँच शर्तें मानने को कहा :

1. गृहयुद्ध की समाप्ति ।
2. भाषण देने, सभा करने व संगठन बनाने की आजादी को सुनिश्चित करना ।
3. जापान-विरोधी जन-कांग्रेस का आयोजन करना ।
4. जापान का प्रतिरोध करने के लिए तैयारियों को पूरा करना ।
5. जनता की जीवन-स्थिति को सुधारना

चीन के आन्तरिक तथा बाह्य अन्तर्विरोधों में हुए परिवर्तनों के अनुसार, दो राजनीतिक सत्ताओं की आपसी शत्रुता की स्थिति को बदलने के लिए ये वादे आवश्यक थे । ये सकारात्मक, सशर्त तथा सैद्धांतिक रियायतें थीं, जो राष्ट्रीय प्रतिरोध युद्ध के लिए हालात पैदा करने के उद्देश्य से दी गई थीं, तथा विशेष प्रदेश व लाल सेना में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को बनाए रखने तथा क्वोमिंताङ के साथ अपने संबंध रखने के दौरान पार्टी की स्वतन्त्रता तथा आलोचना करने की उसकी आजादी को बनाए रखने की शर्तों पर दी गई थीं ।

मई 1937 में, येनान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 1935 से लागू पार्टी की राजनीतिक कार्यदिशा पर विचार विमर्श किया गया तथा उसे स्वीकृति प्रदान की गई ।

इस सम्मेलन में कामरेड माओ त्से-तुङ ने "**जापानी-आक्रमण-विरोधी काल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य**" शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की । उन्होंने ध्यान दिलाया कि 9 दिसम्बर, 1935 से फरवरी 1937 तक, जब क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अपना तीसरा पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया था, पार्टी का कार्य, आंतरिक शांति के लिए

पार्टी के नेतृत्व को मज़बूत करना तथा जनता को लामबन्द करना ज़रूरी था । प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया था कि जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद उसे जापानी प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय पुनरुद्धार के पार्टी के कार्यक्रम पर अमल करना था । हालांकि ''लोक गणराज्य'' तथा ''जनवादी गणराज्य'' के दोनों नारों की शब्दावली में अंतर था, लेकिन इनका सारतत्व एक ही था ।

जापान से लड़ने तथा देश को बचाने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को देश भर की जनता का उत्साहवर्धक समर्थन मिला । कामरेड ल्यू शाओ-ची के नेतृत्व में क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में पार्टी का काम तथा जनता का जापान-विरोधी आंदोलन पुनर्जीवित हो उठा तथा और ज्यादा फैल गया । अगस्त 1936 में जब जापानियों और कठपुतली चीनी फौजों ने स्वेय्वान पर आक्रमण किया तो वहां की चीनी रक्षक सेना ने उसका मुकाबला किया तथा सारे देश की जनता ने प्रतिरोध के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया । नवम्बर तथा दिसंबर में, शंघाई तथा छिङ्ताओ के सूती-वस्त्र श्रमिकों ने जापान-विरोधी हड़तालें कीं । यहां तक की जून 1936 में सरकार में शामिल क्वाङशी तथा क्वाङतुङ के युद्ध-सरदार भी ''जापान का प्रतिरोध करने तथा देश बचाने'' के नाम पर च्याङ काई-शेक के विरोध में इकट्ठे हो गए ।

देशभर में जापान-विरोधी आंदोलन के निरन्तर विकास की परवाह न करते हुए, च्याङ काई-शेक अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनता का विरोध करने की नीति से ही चिपका रहा तथा उसने लाल सेना पर हमले करना जारी रखा । चाङ श्वे-ल्याङ के नेतृत्व वाली उत्तरपूर्वी सेना तथा याङ हू-छङ के नेतृत्व वाली उत्तर-पश्चिमी सेना, लाल सेना तथा जनता के जापान-विरोधी आंदोलन के प्रभाव में आ गई थीं और उन्होंने लाल सेना से लड़ना बन्द कर दिया था । कम्युनिस्ट पार्टी की जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की नीति को स्वीकार करते हुए चाङ तथा याङ ने च्याङ काई-शेक से, जापान के विरुद्ध कम्युनिस्टों से हाथ मिला लेने का आग्रह किया । च्याङ काई-शेक ने उनकी माँग को अस्वीकार कर दिया तथा कम्युनिस्टों को ''नेस्तनाबूद'' करने के लिए अपनी फौजी तैयारियां और तेज कर दीं । वह चाङ तथा याङ को उनके पदों से भी बर्खास्त करना चाहता था । जापान के प्रतिरोध व राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए विभिन्न संगठनों की उत्तर-पश्चिमी सभा, राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए उत्तरपूर्वी चीन सभा, छात्र संघ तथा अन्य जापान-विरोधी संगठनों ने शीआन के पार्टी संगठन के प्रभाव में आकर, क्वोमिंताङ की फौजों, पुलिस बलों, सशस्त्र पुलिस बलों, तथा जासूसों की परवाह न करते हुए विशाल जन-प्रदर्शन किए । जनता के जापान-विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर चाङ तथा याङ ने च्याङ काई-शेक को 12 दिसंबर, 1936 को शीआन में हिरासत में ले लिया तथा उसे कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध रोकने को विवश किया, जिसकी परिणति केवल देश का विनाश करके ही होती । च्याङ काई-शेक की नजरबन्दी के परिणामवश, जापान-परस्त तत्त्वों, वाङ चिङ-वेइ तथा हो इङ-छिन ने, नानकिङ सरकार पर नियंत्रण कर लिया । शीआन पर हमला करने के लिए बड़ी तादाद में सैन्य-शक्ति इकट्ठी की गयी तथा च्याङ काई-शेक से राजनीतिक सत्ता छीनने के लिए योजनाएं बनाई गईं । जापानी साम्राज्यवादी भी परिस्थिति से लाभ उठाने तथा चीन के गृहयुद्ध को व्यापक बनाने को उत्सुक थे । इन हालातों के मद्देनजर, कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने जापानी साम्राज्यवादियों तथा वाङ चिङ-वेइ व हो इङ-छिन के षड्यन्त्र को विफल करने का निर्णय किया तथा सारे राष्ट्र के हित में शीआन

इस नए सैनिक हमले से नानकिङ सरकार पूर्णतया भयभीत हो गई । नतीजे के तौर पर **''हो-उमेजू'' समझौते**[1] पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत चीन को अपनी संप्रभुता से हाथ धोना पड़ा तथा सारे राष्ट्र को अपमानित होना पड़ा । इस समझौते के अनुसार, हपे प्रान्त, पेकिङ तथा थ्येनचिन में क्वोमिंताङ के मुख्यालयों को बन्द कर दिया गया; सशस्त्र पुलिसबल, केन्द्रीय सेना तथा उत्तर-पूर्वी सेना को हपे से हटा लिया गया; हपे प्रान्त के पुराने गवर्नर के स्थान पर नए तथा पेकिङ व थ्येनचिन के पुराने मेयरों के स्थान पर नए मेयर नियुक्त किए गए; फौजी परिषद की पेकिङ शाखा का राजनीतिक विभाग भंग कर दिया गया तथा जापान-विरोधी आंदोलन को कुचल दिया गया । नानकिङ सरकार द्वारा जापानियों की सभी इच्छाओं का पालन करने से, जापानी साम्राज्यवादियों ने चीन पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने की नीति को लागू करने की राह ली ।

5 जून, 1935 को जापान ने छाहाङ प्रान्त के गवर्नर—सुङ छ-च्वान को हटाने की मांग की, बहाना यह बनाया कि चीनी फौज ने छाङफी में कुछ जापानी खुफिया एजेन्टों को बन्दी बना लिया था ।

अक्तूबर में पूर्वी हपे की श्याङहो, छाङफिङ, ऊद्दिङ, सानहो तथा अन्य काउंटियों के कुछ शरारती तत्वों ने, जापानियों के उकसावे में आकर विद्रोह कर दिया तथा श्याङहो कस्बे में ''शान्ति रक्षक समिति'' का गठन किया । इसी प्रकार गद्दार इन रु-कङ ने, नवंबर 1935 में **''पूर्वी हपे कम्युनिस्ट-विरोधी स्वायत-शासन''** के नाम से एक कठपुतली सत्ता की स्थापना की, तथा कठपुतली अफसरों—ली शओ-शिन तथा डेमचिगडॉनरॉब ने, **''भीतरी मंगोलियाई स्वायत्त-सरकार''** नाम से एक नकली सरकार की स्थापना की ।

''उत्तरी चीन में विशेष सरकार'' की स्थापना, की जापानी माँग को पूरा करने के लिए नानकिङ सरकार ने सुङ छ-च्वान, वाङ इ-थाङ तथा वाङ ख-मिन को ''हपे-छाहाङ राजनीतिक परिषद'' स्थापित करने के लिए नियुक्त किया । इस प्रकार उसने इन प्रांतों को अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर कर दिया तथा उनका रुतबा घटकर एक कठपुतली राज्य के दर्जे का रह गया ।

ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय संकट और ज्यादा गहराता चला गया, त्यों-त्यों चीनी जनता का जापान-विरोधी आंदोलन और अधिक नई ऊँचाइयों को छूने लगा ।

1 अगस्त, 1935 को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने **''साथी देशवासियों के नाम जापान का प्रतिरोध करने तथा राष्ट्रीय-मुक्ति के लिए एक अपील''** जारी की, जिसमें उनका, एक ऐसे समय में जब चीन के आसन्न-विनाश का खतरा सिर पर मंडरा रहा था, अपने राजनीतिक मतों व हितों में जो भी मौजूदा या पिछले मतभेद रहे हों, उन्हें भुलाते हुए, एक सांझे दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया था ।

इस घोषणा द्वारा, मजदूरों व किसानों की जन-सरकार, लाल सेना, दूसरे जापान-विरोधी सैन्य-दल तथा वे सभी लोग, जो जापान का प्रतिरोध करने व चीन को बचाने के इच्छुक थे, **इन सभी को मिलाकर, एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार तथा** जापान-विरोधी संश्रयकारी सेना के गठन का आग्रह किया गया था ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा लाल सेना की मुख्य सैन्य-शक्ति के उत्तर-पश्चिम में पहुंचने तथा शेनशी व कानसू आधार-क्षेत्र की लाल सेना के साथ मिल जाने

के बाद, 13 नवम्बर, 1935 को एक घोषणा जारी की गई । इसमें चीन को जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा उपनिवेश बनाने के खतरे व च्याङ काई-शेक द्वारा राष्ट्रीय हितों से गद्दारी करने के बारे में बताया गया । अत: राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई में चीनी जनता के लिए, जापान का प्रतिरोध करना तथा च्याङ का विरोध करना ही एकमात्र रास्ता था । इसमें जोर देकर कहा गया था कि यह संघर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था । इसमें देश को सर्वनाश से बचाने व उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जनता से उठ खड़े होने, संगठित होने व इस एकमात्र सही दृष्टिकोण का समर्थन करने की अपील की गई थी ।

नवंबर 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, पेकिङ छात्र संघ की स्थापना की गई । इस संगठन ने उत्तरी चीन में कठपुतली "स्वायत्त-शासन" के विरुद्ध व्यापक स्तर पर **आवेदन-आंदोलन** आरंभ किया । 9 दिसम्बर, 1935 को पेकिङ में लगभग 6,000 छात्रों ने एक विशाल देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन किया तथा जापान का प्रतिरोध करने व देश को बचाने के लिए बुनियादी शर्तें सामने रखीं तथा माँग की कि च्याङ काई-शेक सरकार गृहयुद्ध समाप्त करे तथा हमले का प्रतिरोध करे । परन्तु क्वोमिंताङ सरकार ने इस देशभक्तिपूर्ण आंदोलन को नरसंहार तथा गिरफ्तारियों जैसे नृशंस हथकण्डों से कुचलने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे यह आंदोलन और ज्यादा फैल गया । आगे के संघर्षों के लिए सक्रिय तैयारियां, निरन्तर व्यापक स्तर पर चलती रहीं । 10 दिसंबर को पेकिङ के सभी स्कूलों में शिक्षण-कार्य स्थगित कर दिया गया। फिर प्रचार व संगठनात्मक कार्य करने के लिए इन स्कूलों में छात्र-संगठन बनाए गए ।

16 दिसंबर, 1935 को जब "हपे-छाहाड़ राजनीतिक परिषद" का विधिवत उद्घाटन होना था, पेकिङ के 30,000 विद्यार्थियों व नागरिकों ने पार्टी के नेतृत्व में एक विशाल देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन किया । क्वोमिंताङ के सशस्त्र पुलिस बल तथा पुलिस कर्मियों का घेरा तोड़ते हुए तथा उनके प्रहारों को विफल करते हुए, उन्होंने शहर के दक्षिणी हिस्से में थ्येनच्याओ नामक स्थान पर एक जनसभा की तथा इसके बाद एक विशाल परेड की । जनता के दबाव में आकर कठपुतलियों को उस "परिषद" की स्थापना के स्थगन की घोषणा करने को बाध्य होना पड़ा।

9 तथा 16 दिसंबर के देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनों ने क्वोमिंताङ सरकार तथा जापानी साम्राज्यवादियों के सांझे आतंककारी शासन को चुनौती दी, और चीन के अन्य भागों के विद्यार्थियों में तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई तथा आंदोलन देशभर में फैल गया ।

इन प्रदर्शनों के बाद, अनेक विद्यार्थी जापान का प्रतिरोध करने व चीन को बचाने के आंदोलन की बुनियाद के विस्तार हेतु श्रमिकों तथा किसानों के बीच गए । इससे उन्हें मजदूर वर्ग के साथ निकट संबंध स्थापित करने के लिए स्वयं को शिक्षित करने व फौलादी बनाने का सुअवसर मिला ।

पेकिङ तथा थ्येनचिन के छात्रों ने किसानों में व्यापक स्तर पर प्रचार व सांगठनिक कार्य करने के लिए प्रचार-ब्रिगेडों का गठन किया तथा श्रमिकों व किसानों के लिए रात्रि-स्कूल स्थापित किए । जनता के साथ निकट संबंधों के आधार पर चीन के सभी भागों में शीघ्र ही पार्टी के नेतृत्व में **चीन की राष्ट्रीय-मुक्ति के हरावल दस्ते**[2] की स्थापना हो गई । लगभग दो साल बाद, जब जापानी-आक्रमण-विरोधी-युद्ध शुरू हुआ, बहुत से छात्रों ने छापामार लड़ाई

काई-शेक गुट, जिसका ब्रिटिश-अमरीकी हितों से गहरा सम्बन्ध था, दोनों देशों की सरकारों के आदेश पर, जापान के प्रति अपना रवैया बदल सकता था, अत: संदेश में पार्टी की केन्द्रीय समिति ने, च्याङ काई-शेक को, जापान का प्रतिरोध करने के लिए, बाध्य करने की नीति अपनाई ।

पार्टी की नीतियाँ इस प्रकार थीं : (1) च्याङ काई-शेक गुट को संयुक्त मोर्चे में शामिल करना तथा इसके साथ ही चीन की प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय अस्मिता की कीमत पर जापान के साथ समझौता करने के क्वोमिंताङ सरकार के प्रयासों का पर्दाफाश करना । (2) क्वोमिंताङ के विभिन्न गुटों के साथ तथा साथ ही उनकी सेनाओं के साथ एकबद्ध होना, चूँकि जापान का प्रतिरोध करने के लिए च्याङ काई-शेक को बाध्य करने के प्रयास किए जा रहे थे, अत: जितनी ज्यादा जापान-विरोधी जनवादी शक्तियां संयुक्त मोर्चे के पक्ष में होतीं, च्याङ काई-शेक को अपना मन बदलने के लिए बाध्य करना उतना ही अधिक संभव हो सकता था ; तथा (3) देश की समस्त जनता के सामने संयुक्त मोर्चे के नेता तथा संगठनकर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए, देश की आंतरिक शांति तथा एकता को बढ़ावा देने के प्रयास करना ।

यह जानते हुए कि **"लोक गणराज्य का नारा"** च्याङ काई-शेक को अस्वीकार्य होगा, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने नानकिङ सरकार तथा उसकी सेना को जापान के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने की भावना से, अपने 25 अगस्त, 1936 के क्वोमिंताङ को लिखे गए पत्र में, इस नारे की जगह **"जनवादी गणराज्य"** का नारा दिया । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जापानी प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए अखिल चीनी कांग्रेस के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन क्वोमिंताङ ने प्रयास किया कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद, (जो कि थोड़े से उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा गठित, क्वोमिंताङ सरकार की मात्र एक परामर्शदात्री संस्था थी) इसका स्थान ले ले, तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पैरवीकृत चीनी जनवादी गणराज्य तथा उसकी संसद का स्थान, क्वोमिंताङ अधिकारियों द्वारा छल-प्रपंच से बनाई गई, राष्ट्रीय असेम्बली ले ले; कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने क्वोमिंताङ के उपरोक्त प्रयासों की सख्त आलोचना की । केन्द्रीय समिति ने स्पष्ट किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्वोमिंताङ में मौजूद असंख्य देशभक्त लोगों के साथ हाथ मिलाने व संयुक्त मोर्चा गठित करने के लिए सदैव तत्पर थी तथा आशा प्रकट की कि क्वोमिंताङ में देशभक्त सदस्यों का बोलबाला होगा। केन्द्रीय समिति ने जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के गठन तथा क्वोमिंताङ के साथ दोबारा सहयोग कायम करने की पार्टी की नीति की पुन: पुष्टि की ।

"जापान का प्रतिरोध करने तथा देश को विनाश से बचाने के आंदोलन में नई परिस्थिति संबंधी तथा जनवादी गणराज्य संबंधी प्रस्ताव" में जिसे पार्टी की केन्द्रीय समिति ने सितम्बर 1936 में पारित किया था, "जनवादी गणराज्य" के नारे की ठोस रूप से व्याख्या की गई थी, तथा यह स्पष्ट किया गया था, कि इसका अर्थ एक ऐसा लोकतंत्र था, जो भौगोलिक दृष्टि से श्रमिकों तथा किसानों के जनवादी अधिनायकत्व के अन्तर्गत चलने वाले जनतंत्र से ज्यादा विस्तृत था, तथा एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली थी जो क्वोमिंताङ की एक-दलीय तानाशाही से कहीं ज्यादा प्रगतिशील थी । इससे लोग राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने में समर्थ हो जाते तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवाद के भावी निर्माण हेतु काम करने की आजादी प्राप्त हो जाती । प्रस्ताव में ज़ोर देकर कहा गया था कि इस नारे को साकार करने के लिए,

सेना के साथ युद्ध-विराम सन्धि तथा जापान-विरोधी समझौता संपन्न किया जाए ; इन सेनाओं को प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार ने कम्युनिस्टों से युद्ध करने के लिए शेनशी भेजा था । 25 जनवरी, 1936 को लाल सेना ने उत्तरपूर्वी सेना के सिपाहियों तथा अफसरों के नाम एक पत्र भेजा । पत्र में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि च्याङ काई-शेक ने, उत्तरपूर्वी सेना को, जो जापान से लड़ने को तैयार थी, लाल सेना के विरुद्ध भेजा था, जो कि स्वयं उसी उद्देश्य (जापान से लड़ने) के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ थी, और यह सब उसने (च्याङ काई-शेक ने) दोनों सेनाओं को कमज़ोर करने या नष्ट करने की नीयत से किया था ; कि च्याङ काई-शेक का उत्तरपूर्वी सेना के प्रति सौतेला व्यवहार इस बात से भली-भाँति प्रकट हो जाता था कि उसने इस सेना को शेनशी तथा कानसू के गरीबी की चक्की में पिस रहे प्रान्तों में भेजा था, तथा अपेक्षाकृत समृद्ध दक्षिणी शेनशी तथा दक्षिण कानसू के इलाकों से निकाल बाहर किया था ; कि च्याङ काई-शेक ने उत्तरपूर्वी सेना में जासूसी तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ चलाने के लिए अपने पिट्ठुओं को भर्ती किया हुआ था, तथा यह कि उनके लिए एकमात्र रास्ता जापान के खिलाफ लड़ने तथा च्याङ काई-शेक का विरोध करने का था । मज़दूरों तथा किसानों की जन-सरकार व लाल सेना उनके साथ मिलकर जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए, एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सरकार के निर्माण तथा जापान-विरोधी संश्रयकारी सेना के गठन के लिए तैयार थी।

जापान का प्रतिरोध करने व राष्ट्र को बचाने के जनता के जोरदार आग्रह के जवाब में, लाल सेना के जापान-विरोधी दस्ते का गठन किया गया तथा उसे दस मार्च को पीली नदी पार करने का आदेश दिया गया । लेकिन ज्योंही उसने ताथुङ-फूचओ रेलमार्ग पर अधिकार किया तथा हपे व छाहाङ में मोर्चे पर जाने की तैयारी की, च्याङ काई-शेक ने उसका रास्ता रोकने के लिए एक विशाल फौज भेज दी । उसने उत्तरपूर्वी सेना तथा उत्तरपश्चिमी सेना को भी, लाल सेना के पृष्ठभाग को हैरान-परेशान करने के लिए, उत्तर की ओर व कूच करने का आदेश दिया ।

इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में, एक निर्णायक लड़ाई में, जिसमें विजयश्री किसी भी पक्ष को क्यों न मिलती, केवल राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए चीन की ताकत में ही कमी आनी थी तथा जापानी साम्राज्यवादियों को खुशी मिलनी थी, यह सोचकर लाल सेना के क्रांतिकारी फौजी कमीशन ने जापान-विरोधी दस्ते को पीली नदी के पश्चिम में पीछे हटा लिया । 5 मई, 1936 को कमीशन ने एक खुले तार के जरिये नानकिङ सरकार को राष्ट्रव्यापी गृहयुद्ध समाप्त करने, सबसे पहले शेनशी, कानसू तथा शानशी में युद्ध बन्द करने की सलाह दी, ताकि दोनों पक्ष जापान का प्रतिरोध करने तथा राष्ट्र को बचाने के विशेष उपायों पर विचार-विमर्श के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज सकें । संदेश में देश की समस्त जनता का भी आह्वान किया गया कि वह गृहयुद्ध को जल्दी बन्द करवाने के लिए एक कमेटी का गठन करे तथा उस कमेटी के प्रतिनिधि मोर्चे पर जाकर दोनों ओर से गोलाबारी बन्द करवाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि वह प्रस्ताव पूरी तरह लागू हो ।

इससे पहले, चूँकि च्याङ काई-शेक उत्तरपूर्व तथा उत्तरी चीन को बेचना जारी रखे हुए था, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने उसे जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं किया था । लेकिन चूँकि उत्तरी चीन पर जापानी हमले ने, जापानी साम्राज्यवादियों तथा ब्रिटिश-अमरीकी साम्राज्यवादियों के हितों में गंभीर टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी थी ; तथा च्याङ

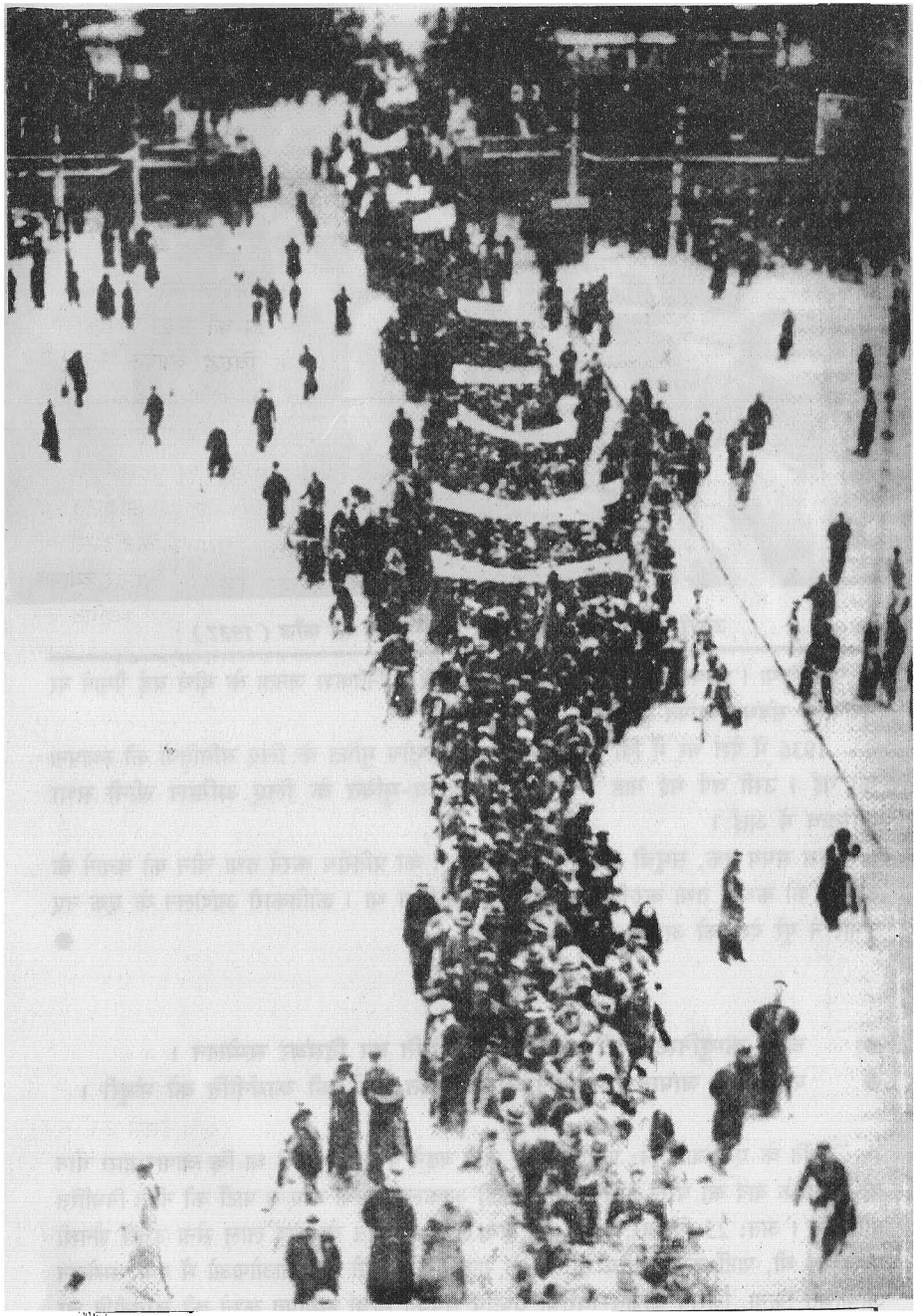

मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे पेकिङ के छात्रों के जुलूस का एक दृश्य (16 दिसंबर, 1935)

उत्तरी चीन में युवा कम्युनिस्ट स्वयंसेवकों की फौज (1937)

में भाग लिया । इसके फलस्वरूप बुद्धिजीवियों तथा मेहनतकश जनता के बीच बड़े पैमाने पर नज़दीकी संबंध स्थापित हुए ।

1936 में देश भर में विभिन्न समुदायों द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति के लिए समितियों की स्थापना की गई । उसी वर्ष मई माह में शंघाई में **राष्ट्रीय-मुक्ति के लिए अखिल चीनी सभा** अस्तित्व में आई ।

इस समय तक, समूची चीनी जनता ने जापान का प्रतिरोध करने तथा चीन को बचाने के आह्वान को कथनी तथा करनी, दोनों में लागू कर दिया था । क्रांतिकारी आंदोलन के एक नए उभार ने पूरे देश को अपनी लपेट में ले लिया । ●

4.

- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का दिसंबर सम्मेलन ।**
- **पार्टी द्वारा जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति को मंजूरी ।**

क्रांति के एक बार पुन: प्रगतिपथ पर आगे बढ़ने पर यह ज़रूरी था कि जापान द्वारा चीन पर हमले के बाद की घरेलू परिस्थिति का सही आकलन किया जाए व पार्टी की नीति निर्धारित की जाए । अत: 25 दिसंबर, 1935 को जब लंबे अभियान के बाद लाल सेना उत्तरी शेनशी पहुँच गई थी, पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो ने वायाओपाओ में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसने जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा स्थापित करने की कार्यनीति का निर्धारण किया तथा **''मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति व पार्टी के कार्यभार''** संबंधी प्रस्ताव

जापान विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे तथा उसके दृढ़संकल्प नेताओं के लिए, एक सुदृढ़ आधार-स्तंभ बन जाना था ।

इस संयुक्त मोर्चे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का होना एक निर्णायक भूमिका रखता था । इतिहास ने यह साबित कर दिया था कि चीन की साम्राज्यवाद-विरोधी व सामंतवाद विरोधी क्रान्ति का नेतृत्व पूँजीपति वर्ग को नहीं, बल्कि श्रमिक-वर्ग को करना था । संयुक्त मोर्चे में पार्टी का नेतृत्व क्रान्ति की विजय को सुनिश्चित करता था ।

संक्षेप में, इस कारण से यह जरूरी था कि पार्टी अपनी पांतों का विस्तार करे, तथा संयुक्त मोर्चे में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित करे; अपने पार्टी संगठनों का, अपने नेतृत्व वाली सेना का तथा क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों का विस्तार करें । एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी, लाल सेना तथा क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र, ये तीनों संयुक्त मोर्चे के आधार-स्तंभ थे ।

4. कामरेड माओ त्से-तुङ ने निर्भीक जुझारूपन के साथ, चीनी जनता की जापानी-साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की दृढ़ इच्छा तथा अन्तिम विजय में उनके विश्वास को आवाज प्रदान करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पर बल दिया । चीन का जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चा अकेला नहीं पड़ सकता था ; इसे पूरे विश्व की जनता से सोवियत-संघ के नेतृत्व में मदद मिलनी निश्चित थी । जैसा कि कामरेड माओ ने रिपोर्ट में कहा :

''हमारे जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध को विश्व की जनता और सबसे पहले सोवियत-संघ की जनता के समर्थन की आवश्यकता है, और वह हमारा समर्थन अवश्य करेगी, क्योंकि हम और वह समान उद्देश्य के सूत्र में बंधे हुए हैं ।''[6]

जापान-विरोधी युद्ध तथा क्रांति में विजयश्री प्राप्त करने के लिए सोवियत जनता का समर्थन, चीन के लिए एक अनिवार्य शर्त थी । दूसरी ओर, इस नए आक्रमणकारी युद्ध का विरोध करने के लिए चीन को, यूरोप तथा अमरीका के उन सभी पूँजीवादी देशों, जिनके जापान के साथ अन्तर्विरोध थे, के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की संभावनाओं को खोजना चाहिए था । संक्षेप में, चीन के लिए अपने जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे को विश्व के शांति-मोर्चे के साथ एकताबद्ध कर देना, तथा जापानी साम्राज्यवादियों को पूरी तरह से अलग-थलग कर देना बेहद जरूरी था । ●

5.

- **च्याङ काई-शेक को जापान का प्रतिरोध करने के लिए बाध्य करने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति ।**
- **शीआन घटना—परिस्थिति का मोड़-बिन्दु ।**
- **जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का प्रारंभिक चरण ।**
- **उत्तरपूर्वी जापान-विरोधी संश्रयकारी सेना का संघर्ष ।**

केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ त्से-तुङ के सही नेतृत्व में सारी पार्टी ने जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई तथा कदम-ब-कदम इसके प्रारंभिक रूप को साकार किया ।

पहले कदम के रूप में, पार्टी ने यह ज़रूरी समझा कि उत्तरपूर्वी सेना तथा सत्रहवीं राह

जिनका प्रबन्ध वे वेतनभोगी मजदूरों द्वारा करते थे, उन्हें ज़ब्ती से छूट मिलनी थी तथा उत्पादन को बढ़ाने तथा औद्योगिक व व्यापारिक कारोबारों को चलाने की उनकी आजादी की जन-सरकार ने रक्षा करनी थी । जुलाई 1936 में, इस सम्मेलन के लगभग आधा वर्ष बाद, केन्द्रीय समिति ने लाल सत्ता को जापान-विरोधी तथा राष्ट्रीय-मुक्ति के आंदोलन की धुरी बनाने के विचार से, एक बार फिर, कृषि-नीति संबंधी निर्देश दिये कि केवल गद्दारों की जमीन-जायदाद, तथा जमींदार वर्ग की जमीन, खाद्य-साम्रगी, मकान व अन्य संपत्तियां ही जब्त की जानी थीं; तथा सभी छोटे मालिकों की जमीन (जैसे कि पेशेवर मजदूरों, छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, छोटे ज़मीदारों—जो तंगी में जीवन-यापन कर रहे थे तथा वे दूसरे लोग, जो जमीन का थोड़ा हिस्सा लगान पर देते थे) जब्ती से मुक्त रखी जानी थी ।

3. जापान विरोधी संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति मार्क्सवादी-लेनिनवादी कार्यनीति थी तथा कट्टरतावाद के पूरी तरह विरुद्ध थी । कट्टरतावादी इस बात को नहीं मानते थे कि चीन को उपनिवेश बनाने का जापानी प्रयास चीन में क्रांतिकारी तथा प्रति-क्रांतिकारी शक्तियों की पांत-बंदी में कोई परिवर्तन ला सकता था । उनका दावा था कि जमींदार वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग का पूरे का पूरा खेमा एकजुट तथा मजबूत था, तथा उन्होंने मनमाने ढंग से, उस समय अपने आपको सक्रियता से प्रेरित कर रहे मध्यवर्ती ग्रुपों को क्रान्ति का सबसे खतरनाक दुश्मन मान लिया । कट्टरतावादियों के अनुसार, क्रान्ति की शक्तियां निश्चित रूप से शुद्ध तथा पूर्णतया शुद्ध होनी चाहिएं थीं तथा क्रान्ति की राह एकदम सीधी तथा पूर्णतया सीधी होनी चाहिए थी। लेकिन, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी । **दुनिया की सभी गतिविधियों की भांति, क्रान्ति की राह भी हमेशा ही टेढ़ी-मेढ़ी थी, कभी भी सीधी नहीं थी** तथा क्रान्तिकारी व प्रति-क्रान्तिकारी व्यक्तियों की पांत-बंदी में परिवर्तन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था । क्रान्तिकारी शक्तियों के लिए यह जरूरी था कि वे कोटि-कोटि जनता को संगठित करें तथा एक विशाल क्रान्तिकारी सेना का संचालन करें । केवल ऐसी शक्ति ही जापानी साम्राज्यवादियों तथा गद्दारों के गुट को नेस्तनाबूद कर सकती थी । संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति दुश्मन को घेरने तथा उसका विनाश करने के लिए विशाल शक्ति को लामबन्द करने के लिए थी । यह एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी कार्यनीति थी । इसके विपरीत, कट्टरतावादियों की कार्यनीति, ''एक विकट शत्रु के साथ दु:साहसपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए एक अकेले घुड़सवार पर निर्भर रहने'' की थी । उन्होंने उन सभी लोगों को शत्रु के पक्ष में धकेल देना था जो क्रान्ति के मित्र बन सकते थे । इस तरह उन्होंने दरअसल शत्रु की ही सहायता करनी थी और क्रान्ति को गतिरोध, अलगाव, क्षीणता व ह्रास की स्थिति में डाल देना था, यहां तक कि उसे पराजय के मार्ग पर भी धकेल देना था ।

जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे में तथा प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध काल के क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे में बेहद फर्क था । पार्टी के उस समय के अवसरवादी नेतृत्व ने अपनी पांतों का विस्तार करने की कोशिश करने की बजाय केवल अपने अस्थाई संश्रयकारी क्वोमिंताङ पर भरोसा किया । अत: क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, एक मजबूत आधार-स्तंभ की कमी के कारण धराशायी हो गया । परन्तु 1935 में घरेलू परिस्थिति पूर्णतया भिन्न थी । अब एक खूब तपी हुई कम्युनिस्ट पार्टी तथा खूब तपी हुई लाल सेना मौजूद थी । लाल सेना ने विजयपूर्वक अपना महान लंबा अभियान पूरा कर लिया था । पार्टी तथा लाल सेना ने भविष्य में अनिवार्यत:

को स्वीकृत किया । प्रस्ताव में राजनीतिक परिस्थिति का सम्पूर्ण विश्लेषण तथा अन्दरूनी वर्ग-सम्बन्धों में परिवर्तनों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था तथा पार्टी की कार्यनीति को परिभाषित किया गया था । प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा हालातों का असाधारण लक्षण, जापान का चीन को अपना उपनिवेश बनाने की जिद पर अड़े होना था । अन्दरूनी राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में कहा गया, कि विभिन्न वर्गों, पार्टियों तथा उनकी सशस्त्र सेनाओं के बीच के सम्बन्धों में परिवर्तन हो रहा था । न केवल श्रमिक, किसान तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग ही जापान से लड़ने को कृतसंकल्प थे, बल्कि शासक वर्गों के एक हिस्से ने भी हमले का प्रतिरोध करने की माँग पेश की । शासक वर्ग के शिविर में फूट तथा दरारें दृष्टिगोचर होने लगी थीं । इसलिए पार्टी का कार्यभार था कि व्यापकतम संभव राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, हमलावरों के विरुद्ध लड़ाई के लिए सभी जापान-विरोधी शक्तियों को लामबन्द करे । प्रस्ताव में ''वामपंथी'' कट्टरतावाद का खंडन किया गया जो कि उस समय पार्टी के लिए मुख्य खतरा था तथा ''दक्षिणपंथी'' अवसरवाद का भी खण्डन किया गया । उस प्रस्ताव के आधार पर 27 दिसम्बर, 1935 को, पार्टी कार्यकर्त्ताओं की एक सभा में कामरेड माओ त्से-तुङ ने ''**जापानी साम्राज्यवाद विरोधी कार्यनीति के बारे में**'' नामक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पार्टी द्वारा प्रस्तावित जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया गया ।

1. कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थिति की बुनियादी विशेषता यह थी कि जापानी साम्राज्यवाद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था । खासतौर से 1935 में जापान द्वारा उत्तरी चीन में घुसपैठ करने के बाद, जापानी हमले से समूची चीनी जनता के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया था । फलत:, चीन व जापान के बीच का राष्ट्रीय अंतर्विरोध, मुख्य अंतर्विरोध बन गया था जबकि चीन का अन्दरूनी वर्ग-अंतर्विरोध दूसरे स्थान पर आ गया था । जापानी हमले के दृष्टिगत मज़दूर, किसान व निम्न-पूँजीपति वर्ग, सभी प्रतिरोध की माँग कर रहे थे, मज़दूर तथा किसान इस माँग को लेकर सबसे ज़्यादा कृतसंकल्प थे । जहाँ तक राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का सवाल था, यह सच था कि 1927 के बाद वह च्याङ काई-शेक के पक्ष में चला गया था, लेकिन असलियत यह थी कि उसे अपने संश्रयकारी—मजदूर वर्ग का साथ छोड़ने तथा जमींदार वर्ग व दलाल-पूँजीपति वर्ग के साथ दोस्ती गांठने से कुछ हासिल नहीं हुआ था ।

18 सितंबर, 1931 की घटना के बाद राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग को गंभीर आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी । मिसाल के तौर पर, 1926 से 1930 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तपूर्वी चीन में सूती धागे व कपड़े का वार्षिक आयात क्रमश: 1,28,88,977 तथा 5,31,99,255 हाएक्वान ताइल (Haikwan taels) तक पहुंच गया था । इसमें से सूती धागे का 99,06,183 हाएक्वान ताइल, यानि कि कुल आयात का 77 प्रतिशत, तथा सूती कपड़े का 1,38,57,174 हाएक्वान ताइल, यानि कि कुल आयात का 26 प्रतिशत, लम्बी दीवार के दक्षिण में पड़ने वाले चीनी भाग में तैयार किया जाता था । उत्तरपूर्व पर जापान के कब्ज़े तथा दूसरे विभिन्न कारणों से लंबी दीवार के दक्षिण में स्थित प्रांतों की सूती-वस्त्र मिलों के दस लाख से ऊपर तकले, 1931 के बाद से लगातार बेकार पड़े थे । दूसरे, घटना से पहले उत्तरपूर्व, अपने लगभग एक करोड़ टन कोयले के उत्पादन के साथ, चीन के मुख्य कोयला-उत्पादक क्षेत्रों में से एक था । लगभग

आधे कोयले का निर्यात कर दिया जाता था ; लंबी दीवार के दक्षिण में स्थित प्रांतों की अनेक फैक्ट्रियां अपनी कोयला आपूर्ति के लिए उत्तरपूर्व पर निर्भर थीं । लेकिन, 1931 से जापान ने उत्तरपूर्व की कोयला खानों को पूरी तरह अपने नियन्त्रण में ले लिया तथा इस प्रकार चीन के उद्योगों की ईंधन-आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा । अंत में, उत्तरपूर्व की सोयाबीन की पैदावार विदेश-व्यापार की महत्त्वपूर्ण जिन्सों में से एक थी ; चालीस से पचास लाख टन की सलाना पैदावार का लगभग आधा हिस्सा निर्यात किया जाता था । लेकिन उत्तर पूर्व पर कब्जे के बाद जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कृषि-उपज के स्वामित्व पर कब्जा कर लिया गया। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों व उसकी विदेशी मुद्रा-विनिमय दर पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्तियों का अंश, जो सारे का सारा निर्यात से आता था, 1930 के 61 प्रतिशत से गिरकर, 1933 में केवल 42 प्रतिशत रह गया । चीन के उद्योगपतियों व व्यापारियों ने विदेशी व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में गंभीर क्षति उठाई ।

1931 से 1936 तक की अवधि में जापानियों ने लंबी दीवार के दक्षिण में अपने कारखानों, विशेषकर सूती-कपड़ा मिलों का तेज गति से विस्तार किया और कई चीनी मिलों को निगल गए । छिङताओ तथा थ्येनचिन, उत्तरी चीन के दो बड़े सूती-वस्त्र केन्द्र हैं । छिङताओ में तो जापानी कपड़ा मिलों को काफी अर्से से प्रमुख स्थान प्राप्त था । थ्येनचिन में, 1931 तक, एकमात्र जापानी पूँजीपतियों के स्वामित्व वाली एक भी कपड़ा मिल नहीं थी, लेकिन सन् 1936 तक कुल तकलों का 55.2 प्रतिशत तथा कुल करघों का 32.9 प्रतिशत जापानी मिलों के पास था । चीन के वस्त्र-उद्योग के सबसे बड़े केन्द्र शंघाई में, जापानी स्वामित्व के तकलों का अनुपात कुल तकलों के 1931 के 51 प्रतिशत से घटकर, 1936 में 49.9 प्रतिशत रह गया, लेकिन उसके करघों का अंश 1931 के 52.8 प्रतिशत से बढ़कर 1936 में 57.7 प्रतिशत हो गया ; चीनी तकलों का अंश तो कुल मिलाकर स्थिर रहा (41.9 प्रतिशत से 41.8 प्रतिशत), लेकिन चीनी करघों का अंश 34 प्रतिशत से गिरकर 29.1 प्रतिशत रह गया। संक्षेप में, चीन के तीन सबसे बड़े सूती-वस्त्र उद्योग केन्द्रों में जापान का प्रभुत्व था ।

चीन के औपनिवेशीकरण के संकट तथा उसके राष्ट्रीय उद्योग तथा वाणिज्य के दिवालिएपन या अर्ध-दिवालिएपन के खतरे ने राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग के राजनीतिक रुख में परिवर्तन को संभव बना दिया—एक ऐसा परिवर्तन जो या तो उसे जापान-विरोधी संघर्ष में खींच सकता था, या फिर तटस्थ बना सकता था ।

जैसा कि कामरेड माओ त्से-तुङ ने रिपोर्ट में कहा था, **''जमींदार वर्ग और दलाल-पूंजीपति वर्ग के खेमे में भी पूर्ण एकता नहीं है ।''**[3] चीन अनेक साम्राज्यवादी देशों के संयुक्त नियंत्रण में एक अर्ध-उपनिवेश था । चीन को हड़पने के जापानी प्रयासों ने स्वाभाविक तौर पर साम्राज्यवादियों के बीच की दरार को चौड़ा करना था । कामरेड माओ त्से-तुङ को दोबारा उद्धत करते हुए :

''जब हमारा संघर्ष जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहा हो, तो अमरीका या ब्रिटेन के पालतू कुत्ते अपने मालिकों की उंगलियों पर नाचते हुए जापानी साम्राज्यवादियों और उनके पालतू कुत्तों के खिलाफ परोक्ष रूप से या खुला संघर्ष चला सकते हैं ।''[4]

चीन के वर्ग सम्बन्धों में ये परिवर्तन तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच सम्बन्धों में

परिवर्तन जो कि जापान की हमलावर कार्यवाहियों का नतीजा थे, इस बात के पर्याप्त सूचक थे कि चीन में क्रांतिकारी मोर्चा तथा प्रति-क्रांतिकारी मोर्चा, दोनों ही परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे थे । राष्ट्रीय क्रान्ति के खेमे की शक्ति बढ़ गई थी, जबकि प्रति-क्रान्तिकारी खेमा कमजोर हुआ था । इस प्रकार जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की स्थापना संभव हो गई ।

लाल सेना के लंबे अभियान की महान विजय से तथा चीनी जनता के जापान-विरोधी आंदोलन व समस्त विश्व के क्रांतिकारी आंदोलनों के निरंतर विकास से, उस समय क्रांतिकारी स्थिति स्थानीय से राष्ट्रव्यापी हो रही थी तथा कदम-ब-कदम असमानता की स्थिति से सापेक्ष समानता की स्थिति में बदल रही थी । तथापि, कुल मिलाकर चीनी क्रांति का विकास असमान था तथा क्रांतिकारी शक्तियाँ अभी भी प्रति-क्रांतिकारी शक्तियों से कमजोर थीं । इसी तथ्य में कम्युनिस्ट पार्टी की यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण जरूरत निहित थी कि एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए देश की सभी जापान-विरोधी ताक़तों को एकजुट किया जाए । इसलिए पार्टी के लिए यह ज़रूरी भी था और संभव भी था कि कोटि-कोटि जनता को जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे में खींचा जाए । जैसा कि कामरेड माओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा,

''पार्टी का कार्य है कि वह लाल सेना की कार्यवाहियों को सारे देश के मज़दूरों, किसानों, विद्यार्थियों, निम्न-पूँजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की सभी कार्यवाहियों के साथ मिलाकर एक राष्ट्रीय क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा कायम करे ।''[5]

2. रिपोर्ट में कामरेड माओ त्से-तुङ ने **''लोक-गणराज''** का नारा पेश किया तथा ऐसे गणराज्य के स्वरूप तथा नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की । लोक-गणराज्य का एक सुस्पष्ट लोकप्रिय स्वरूप व गंभीर राष्ट्रीय चरित्र होना था । लोक-गणराज्य की सरकार मुख्यतः श्रमिकों तथा किसानों पर ही आधारित होनी थी, लेकिन साथ ही उसमें उन सभी दूसरे वर्गों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना था जो साम्राज्यवादी तथा सामन्ती शक्तियों का विरोध करते थे । श्रमिकों तथा किसानों के हितों को सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करते हुए, इसने राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबारों के विकास को प्रोत्साहित करना था । इसी प्रकार धनी किसानों की जमीन के उन हिस्सों को छोड़कर जिनसे सामंती शोषण होता था, उनकी जमीन व अन्य सम्पत्तियों के विषय में भी एक एहतियाती नीति बरती जानी थी ।

वायाओपाओ सम्मेलन से ठीक पहले, 6 दिसंबर, 1935 को, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने धनी किसानों के प्रति अपनी कार्यनीति में परिवर्तन करने संबंधी एक प्रस्ताव लागू किया था। इसमें ध्यान दिलाया गया था कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, धनी किसान साम्राज्यवाद तथा गद्दार क्वोमिंताङ सरकार के विरुद्ध संघर्षों में हिस्सा लेना शुरू कर रहे थे, या फिर सहानुभूतिपूर्ण तटस्थ रवैया अपना रहे थे । आगे स्पष्ट किया गया था कि भूतकाल में लाल सत्ता की स्थापना के लिए आंदोलन के दौरान धनी किसानों के विरुद्ध संघर्ष के तीव्रीकरण ने इस रुझान को उभारा कि उन्हें एक वर्ग के रूप में नेस्तनाबूद कर दिया जाए । इससे मध्यम किसान बुरी तरह प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने कृषि-उत्पादन में और वृद्धि करने में ज्यादा दिलचस्पी न दिखाई । इसलिए केन्द्रीय समिति ने धनी किसानों के बारे में अपनी कार्यनीति को बदलने का निर्णय लिया । प्रस्ताव में व्यवस्था की गई थी कि धनी किसानों के केवल सामंती शोषण को समाप्त किया जाना था, तथा जमीन, व्यापारिक करोबार व अन्य सम्पत्तियाँ,

जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनेक निर्देश जारी किए ।

सबसे पहले, छापामार युद्ध स्वतन्त्र रूप से तथा अपनी ही पहलकदमी पर शुरू करने के लिए सेना को अलग-अलग टुकड़ियों में बाँट दिया जाना चाहिए तथा लोगों को लामबन्द करने व जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित करने के लिए शत्रु के पृष्ठभाग में गहराई तक घुसपैठ कर देनी चाहिए ।

दूसरे, उत्तरी चीन में पार्टी का मुख्य उद्देश्य छापामार युद्ध को जारी रखना होना चाहिए तथा बाकी सभी कार्यवाहियाँ उसके इर्द-गिर्द केन्द्रित की जानी चाहिएं । स्थानीय पार्टी-शाखाओं को जनता को लामबन्द करना चाहिए, इधर-उधर बिखरे हुए हथियारों को इकट्ठा करना चाहिए, बिखरे हुए सैनिकों को भर्ती करना चाहिए तथा योजनानुसार सभी क्षेत्रों में छापामार दस्तों का गठन करना चाहिए ।

तीसरे, पहले से ही स्थापित जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों (उदाहरण के लिए—शानशी-छाहाड़-हपे आधार-क्षेत्र) को सुदृढ़ करने के सबसे अधिक प्रभावी उपाय थे—फौजों के पुनर्गठन व प्रशिक्षण तथा पार्टी के काम में तेजी लाना ; आधार-क्षेत्रों से डाकुओं का सफाया करना ; अनियमित सैनिकों को प्रशिक्षित करने के भरसक प्रयास करना, क्योंकि उन्हें भी हमलावरों से लोहा लेना था तथा स्थानीय देशद्रोहियों का सफाया कर देना । इन उपायों की सफलता के साथ ही शानशी-छाहाड़-हपे आधार-क्षेत्र का पश्चिमी तथा मध्य हपे से पूर्वी हपे तक विस्तार करने के प्रयास भी किये जाने चाहिएं थे ।

चौथे, यदि समूचा राष्ट्र प्रतिरोध युद्ध में डटा रहा तथा जनता को जागृत करने का काम बखूबी किया गया तो शानतुङ तथा हपे के मैदानी इलाकों में जापान-विरोधी छापामार-युद्ध शुरू करना व उसे व्यापक पैमाने पर चलाते रहना बिल्कुल संभव हो सकता था । इन मैदानी क्षेत्रों में छापामार इलाकों को तुरन्त चिन्हित करना तथा कमान मुख्यालय स्थापित करके कदम-ब-कदम छापामार कार्यवाहियों को आगे बढ़ाना जरूरी था । शत्रु से मुक्त कराए गए क्षेत्रों में जापान-विरोधी जन-सरकारों का गठन करना चाहिये था, बिखरे हथियारों को इकट्ठा करना चाहिये था तथा जनता को छापामार दस्तों या नियमित सेना में शामिल होने के लिए लामबन्द किया जाना चाहिये था ।

पार्टी की केन्द्रीय समिति ने मध्य चीन में स्थित नई चौथी सेना को निर्देश दिया कि वह जनता को लामबन्द करे तथा क्वाङते, सूचओ, छनच्याङ, नानकिङ तथा ऊहू के बीच के विशाल भूभाग में जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित करे । माओशान आधार-क्षेत्र की स्थापना के बाद सूचओ, छनच्याङ तथा ऊहू के बीच के तिकोने भूभाग में सैन्य-दल भेजने की तैयारी करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त याङत्सी नदी के उत्तर के इलाकों में भी एक टुकड़ी भेजी जानी चाहिये । नई चौथी सेना को उस समय मौके का फायदा उठाते हुए शत्रु की पांतों के पीछे घुसपैठ कर देनी चाहिये तथा नदी के किसी एक ओर छापामार आधार-क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिये । नई चौथी सेना के नेताओं को निर्देश किया गया कि वे जापान-विरोधी युद्ध तथा गृहयुद्ध के दौरान संघर्ष के विकास में तथा काम करने के तरीकों में जो बुनियादी फर्क था, उसे पार्टी सदस्यों की अच्छी तरह समझाएं ; उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि केवल पार्टी तथा क्रान्तिकारी सेना के विस्तार से ही संयुक्त मोर्चे को व्यापक तथा सुदृढ़ बनाया जा सकता था तथा क्वोमिंताङ के कट्टरपंथियों (Die-Hards) द्वारा क्रान्तिकारी सैन्य-शक्तियों का

संश्रयकारियों के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित करना, तथा पार्टी की पांतों का विस्तार करना ।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जनवाद की समस्या, बाद में, पार्टी की पूर्ण प्रतिरोध की नीति तथा क्वोमिंताङ की आंशिक प्रतिरोध की नीति के मध्य संघर्ष का, केन्द्र-बिन्दु बननी थी । जापान-विरोधी लड़ाई की आरंभिक मंजिलों के दौरान पार्टी की सही कार्यदिशा तथा आत्मसमर्पणकारी कार्यदिशा के बीच नेतृत्व हासिल करने की समस्या भी, एक मुख्य मुद्दा बननी थी।

जापान द्वारा उत्तरपूर्वी चीन पर कब्जा करने तथा उसे अपना उपनिवेश बनाने से, चीन एक अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती समाज से बदलकर एक औपनिवेशिक, अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती समाज बन गया ।

18 सितंबर, 1931 की घटना से पहले जापान ने उत्तरपूर्वी चीन में एक पुख्ता राजनीतिक तथा आर्थिक आधार बना लिया था, उसके क्वानतुङ सेना मुख्यालय तथा उसकी क्वानतुङ सरकार का वहां के सैनिक तथा राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण था तथा उसकी दक्षिण मन्चूरिया रेलवे कम्पनी का उद्योग तथा संचार माध्यमों पर आधिपत्य था । 9 मार्च, 1932 को जापान अधिकृत उत्तरपूर्वी चीन में कठपुतली "**मंचूक्वो**"[8] की स्थापना कर दी गई।

जापानी साम्राज्यवादियों के उत्तरपूर्वी चीन में शासन के दौरान जापानी पूँजीनिवेश 1932 के 55 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 1936 में 145.5 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया । (उस समय चीन में जापान का कुल पूँजीनिवेश 200 करोड़ अमरीकी डॉलर था) 1937 में उत्तर पूर्व में कच्चे लोहे का उत्पादन 8,11,000 टन था तथा इस्पात उत्पाद 2,46,000 टन से ऊपर था । सारे देश के 19,028 किलोमीटर लंबे रेलमार्गों की तुलना में अकेले उत्तरपूर्व में ही जापानी स्वामित्व के रेलमार्गों की लंबाई कुल मिलाकर 8,296 किलोमीटर थी ।

सशस्त्र घुसपैठ द्वारा, ज़मीन की ज़ब्ती द्वारा, जापानी बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज पर ऋण देकर तथा खाने-पीने की चीज़ों पर नियंत्रण करके, जापानी आक्रमणकारी उत्तरपूर्वी चीन के सर्वोच्च सामंती जमींदार बन गए ।

जापान ने उत्तरपूर्व के बाज़ार तथा वहां की जमीन के साथ-साथ, फैक्ट्रियों, खानों, कच्चे औद्योगिक माल, संचार-माध्यमों तथा परिवहन पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार उसने उत्तरपूर्वी चीन को अपने एकछत्र नियंत्रण के तहत एक उपनिवेश बना दिया ।

उत्तरपूर्व की जनता तथा सशस्त्र सेनाओं के एक देशभक्त हिस्से ने जापानी आक्रमण तथा कब्जे के विरुद्ध एक बहादुराना छापामार लड़ाई शुरू की । और एक समय तो ऐसा भी आया, जब यह लड़ाई काफी व्यापक स्तर पर फैल गई । पर जापान द्वारा "सफाया मुहिमें" चलाने, क्वोमिंताङ की फूट डालने तथा तोड़-फोड़ करने की गतिविधियों के कारण तथा सबसे ऊपर, इन छापामार दस्तों द्वारा लचीली रणनीति तथा कार्यनीति अपनाने में असफल रहने के कारण, ये दस्ते 1933 के बसन्त तक एक-एक करके हरा दिये गए ।

1933 के अन्त में, उत्तरपूर्व में जापान-विरोधी युद्ध एक नई मंजिल में दाखिल हो गया, जिसकी खास विशेषता यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली फौजें प्रतिरोध-युद्ध की रीढ़ की हड्डी बन गईं थीं । अनेक स्थानों में पार्टी के नेतृत्व वाले छापामार दस्ते बेहद सुसंगठित तथा अनुशासित थे । छापामार लड़ाई के लिए जनता पर निर्भर करते हुए, उन्होंने महत्त्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं तथा पार्टी का सम्मान बढ़ाया । जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे की नीति के कार्यान्वन के कारण जनता के बिखरे हुए तथा पराजित सैन्य-दलों तथा पुराने

किस्म की फौजों का एक हिस्सा पार्टी के इर्द-गिर्द गोलबन्द हो गया । इन्होंने पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया, तथा फिर उन्हें पुनःसंगठित किया गया ।

जब विभिन्न जिलों में जापान-विरोधी दस्तों की कार्यवाहियों में तालमेल बैठाने में प्रारंभिक सफलताएँ मिल गई, फिर उसके बाद सारे उत्तरपूर्वी चीन में उनके एकीकृत नेतृत्व की समस्या सामने आई । अतः पार्टी के मार्गदर्शन में, **उत्तर-पूर्वी जापान-विरोधी संश्रयबद्ध सेना** का गठन किया गया तथा फरवरी 1935 में सेना का एक राजनीतिक कार्यक्रम पारित किया गया।

जापान के प्रतिरोध की परिस्थिति के विकास के अनुरूप तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की हिदायतों पर अमल करते हुए, 1937 में जापान-विरोधी संश्रयबद्ध सेना को तीन सैन्य-दलों में विभक्त कर दिया गया : 1. पहली राह सेना, जिसकी कार्यवाही के क्षेत्र पूर्वी ल्याओनिङ प्रान्त के पहाड़ी जिले थे ; 2. दूसरी राह सेना, उसे पूर्वी चीलिन के पर्वतीय जिलों में कार्यवाही करनी थी ; तथा 3. तीसरी राह सेना, जिसका कार्यक्षेत्र हेलुङच्याङ प्रान्त के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र थे । जापानी हमलावरों द्वारा शेष चीन पर चौतरफे हमले की स्थिति में व्यापक स्तर पर छापामार युद्ध की तैयारियां की गई थीं । इसने शत्रु के लिए एक शक्तिशाली तथा खतरनाक अवरोधक का काम करना था तथा राष्ट्रीय प्रतिरोध की संपूर्ण योजना के बिल्कुल अनुरूप होना था ।

उत्तरपूर्व में रहने वाले कोरियाई राष्ट्रीयता के लोगों ने भी अपने छापामार दस्ते गठित कर लिये थे तथा जापानी हमलावरों से बहादुरीपूर्वक लोहा ले रहे थे । छाङपाए पहाड़ों तथा सुंगाड़ी नदी की घाटी में जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र बनाए गए । 1934 में **कोरियाई क्रान्तिकारी जनसेना** का तथा 1935 में **मातृभूमि के उद्धार के लिए सोसाइटी** का गठन किया गया । चीनी तथा कोरियाई जनता कन्धे से कन्धा मिलाकर अपने सांझे शत्रु के खिलाफ लड़ी ।

इस प्रकार समस्त राष्ट्र द्वारा जापान के विरुद्ध सम्पूर्ण युद्ध में कूदने से पहले ही, उत्तरपूर्वी चीन की जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जापानी हमलावरों का बहादुराना प्रतिरोध किया तथा उनके शासन को कमजोर किया और इस प्रकार चीन के दूसरे हिस्सों पर जापानी हमले को विलम्बित किया । ●

● द्वितीय क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के काल का सारांश

1927-37 के अत्यधिक संकटपूर्ण प्रतिक्रियावादी दौर में पार्टी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रही । इस कालखण्ड के दौरान, एक ओर तो शत्रु ने पार्टी तथा क्रांतिकारी सेनाओं का पूरी तरह विनाश करने के लिए असंख्य सैनिक हमले किए । दूसरी ओर, पार्टी को छन तू-श्यू के दक्षिणपंथी अवसरवाद पर विजय प्राप्त करने के बाद, बार-बार "वामपंथी" अवसरवाद के हमलों का सामना करना पड़ा तथा चाङ क्वो-थाओ की पराजयवादी कार्यदिशा से तथा उसकी विघटनकारी व तोड़फोड़ की गतिविधियों से क्षति उठानी पड़ी । इस प्रकार पार्टी को गंभीर खतरे में डाल दिया गया था । ऐसे नाजुक दौर में पार्टी ने साथी माओ त्से-तुङ को अपने एक महान, बुद्धिमान तथा पूर्णतया भरोसेमंद नेता के रूप में स्वीकार किया । अतः उनकी रहनुमाई में एक नये पार्टी नेतृत्व की स्थापना की गई ।

नीति समझौते तथा आत्मसमर्पण की नीति थी, तथा उस द्वारा इस्तेमाल किए गए उपायों का उद्देश्य जनता का दमन करना था । फलतः इसके बाद पराजय की संभावना थी । इस अन्तर के कारण जापान-विरोधी युद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ की नीतियों में संघर्ष उठ खड़ा हुआ ।

25 अगस्त को उत्तरी शेनशी के लोछ्वान नामक स्थान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की विस्तृत मीटिंग हुई । मीटिंग में यह स्पष्ट किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के बीच जापान का प्रतिरोध करने के प्रश्न पर जो मतभेद तथा विवाद थे, वे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त की जाए, केवल इसी बात को लेकर ही थे । इसलिए नेतृत्व किसका हो, यह प्रश्न विशेष महत्त्व का हो गया था । सम्मेलन ने **राष्ट्रीय मुक्ति के दस-सूत्री कार्यक्रम**[1] को स्वीकृति प्रदान की । इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जापान-विरोधी युद्ध जीतने के लिए तथा क्वोमिंताङ की जन-विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी समस्त देश की जनता को नेतृत्व प्रदान करे। पार्टी का यह दृढ़ मत था कि केवल इस कार्यक्रम को दृढ़तापूर्वक लागू करके ही मातृभूमि की रक्षा करने तथा शत्रु को पराजित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था ।

अपनी नीति को दृढ़ता से लागू करने तथा किसी भी प्रकार के आत्मसमर्पणकारी रुझानों को, जिनके प्रकट होने की संभावना थी या जो प्रकट हो चुके थे, विफल करने या दुरुस्त करने के लिए 25 सितम्बर को केन्द्रीय समिति ने सरकार में भागेदारी करने संबंधी प्रश्न को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया । इसमें स्पष्ट किया गया कि उस समय जो सरकार अस्तित्व में थी वह जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की नहीं थी, बल्कि अभी भी क्वोमिंताङ की एक दलीय तानाशाही के अधीन थी । इसलिए किसी भी कम्युनिस्ट को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इससे पार्टी का अपना विशेष रुख ही धुँधला पड़ जाए तथा क्वोमिंताङ का प्रतिक्रियावादी शासन और लम्बा खिंच जाए ।

सैनिक मामलों में आजादी तथा पहलकदमी का अर्थ था—पर्वतीय क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से छापामार लड़ाई चलाना, तथा मुख्य मोर्चे पर छापामार-युद्ध की नीति पर डटे रहना, परन्तु अनुकूल परिस्थितियों में चलायमान लड़ाई के अवसरों को हाथ से जाने न देना । कहने का भाव यह कि शत्रु की पाँतों के पीछे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित करना तथा शत्रु के पार्श्वों में बड़े पैमाने पर छापामार-युद्ध छेड़ना ।

जापानी-आक्रमण-विरोधी-युद्ध के आंरभिक काल में पार्टी के अन्दर तथा बाहर बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इस युद्ध में छापामार युद्ध की रणनीतिक भूमिका को कम करके आँकते थे तथा क्वोमिंताङ द्वारा चलाए जा रहे नियमित युद्ध तथा क्वामिंताङ फौजों की कार्यवाहियों पर ही अपनी विजय की आशाएं केन्द्रित किए हुए थे । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा कामरेड माओ त्से-तुङ ने इस दृष्टिकोण का खण्डन किया तथा स्पष्ट किया कि शत्रु की पाँतों के पीछे जनता की शक्तियों को संगठित करके तथा स्वतन्त्र छापामार युद्ध के आंरभिक रणनीतिक काल से नियमित युद्ध के दूसरे रणनीतिक काल तक सशस्त्र प्रतिरोध को व्यापक बनाने के लिए लड़ते हुए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से युद्ध में विजय पताका फहराएगी ।

राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध युद्ध छिड़ने के तत्काल बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ त्से-तुङ ने स्वतन्त्र छापामार युद्ध चलाने व शत्रु के पृष्ठभाग में

6. उत्तरी चीन में कोई सेना तैनात न करना । यद्यापि इन शर्तों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से चीन को अपना गुलाम बनाना था, तो भी क्वोमिंताङ सरकार ने बातचीत के आधार के रूप में इन शर्तों को स्वीकार करने की तत्परता दिखाई लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी तथा समूची चीनी जनता द्वारा जापानी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के दृढ़ संकल्प ने जापान तथा क्वोमिंताङ के इन षड्यन्त्रों को ध्वस्त कर दिया ।

चूंकि जापान के प्रति क्वोमिंताङ की नीति समझौतापरस्ती तथा आत्मसमर्पण की थी, अतः क्वोमिंताङ स्वभावतः जनता की सम्पूर्ण लड़ाई के खिलाफ थी । उसका विश्वास केवल सरकार द्वारा चलाई गई आंशिक लड़ाई में ही था । राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के अपने काबू से बाहर हो जाने के डर से, क्वोमिंताङ ने आंदोलन में तोड़-फोड़ करने तथा उसे अपने हाथों में लेने के जोरदार प्रयास किये । यद्यपि क्वोमिंताङ सरकार ने प्रतिरोध युद्ध के समर्थन में अपनी खुद की समितियों की स्थापना की, लेकिन उनका असली मकसद आन्दोलन को प्रोत्साहित करने की बजाय उसे अवरुद्ध करना था । यहां तक कि एकीकृत नेतृत्व की आड़ में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए काम कर रहे अनेक जनसंगठनों पर पाबंदी लगा दी गई तथा जापान-विरोधी आन्दोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को कानूनी छल-प्रपन्चों के जरिए उत्पीड़ित किया गया।

इस जन-विरोधी नीति के फलस्वरूप क्वोमिंताङ सेनाओं को सभी मोर्चों पर हार का मुँह देखना पड़ा ।

लूकओछ्याओ घटना के एक महीने के अन्दर-अन्दर क्वोमिंताङ सरकार ने पेकिङ तथा थ्येनचिन को शत्रु के हवाले कर दिया तथा इसके तुरन्त बाद छाहाड़ तथा स्वेय्वान के प्रान्तों को भी शत्रु के हवाले कर दिया । नवम्बर 1937 में शंघाई का तथा दिसम्बर में नानकिङ का पतन हो गया । युद्ध छिड़ने के केवल छः महीने से थोड़ा अधिक समय बाद ही, मार्च 1938 तक शत्रु शानशी में फङलिङत्, हनान में क्वेइते तथा शानतुङ में चाओच्वाङ तक पहुँच गया। जून 1938 में क्वोमिंताङ सरकार ने याङत्सी नदी पर स्थित मातङ दुर्ग शत्रु को सौंप दिया तथा इस प्रकार ऊहान को, उत्तर तथा पूर्व, दोनों ओर से शत्रु के हमलों का निशाना बना दिया। जापानी सेनाओं के लगातार हमलों से क्वोमिंताङ सेनाओं को एक के बाद दूसरी पराजय का मुँह देखना पड़ा । अक्तूबर 1938 में कैंटन तथा ऊहान का पतन हो गया । इस प्रकार च्याङसू, आनह्वेइ, हनान, च्याङशी, क्वाङतुङ तथा हुपे, लगभग सभी प्रान्त एक-एक करके हाथ से निकल गए । संक्षेप में, जापानी हमले के आंशिक प्रतिरोध की नीति पर चलते हुए तथा चीनी जनता का प्रतिरोध करते हुए क्वोमिंताङ सेनाएं 15 माह की अल्पावधि में ही पेकिङ, थ्येनचिन, शंघाई, कैंटन तथा ऊहान से ठीक सछ्वान तक पीछे हट गईं ।

दूसरी ओर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लूकओछ्याओ घटना वाले दिन ही सम्पूर्ण प्रतिरोध का आह्वान करते हुए राष्ट्र के नाम एक तार जारी किया ।

23 जुलाई, 1937 को कामरेड माओ त्से-तुङ ने **"जापानी हमले का प्रतिरोध करने के लिए नीतियां, उपाय तथा संभावनाएं"** शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जापान-विरोधी युद्ध के प्रति दो प्रकार की नीतियाँ, दो प्रकार के उपाय तथा दो प्रकार की संभावनाएं थीं । कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति, सम्पूर्ण प्रतिरोध की नीति थी तथा इस नीति को सफल बनाने के उपाय जनता पर विश्वास करने में निहित थे । फलतः इनको लागू करने के बाद राष्ट्रीय मुक्ति की संभावना होती । दूसरी ओर, क्वोमिंताङ द्वारा अपनाई गई

साथी माओ के नेतृत्व में, क्रान्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होकर, दृढ़तापूर्वक सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ी तथा उसने अपने आप को आधार-क्षेत्रों में स्थापित किया, जिनकी संख्या व आकार धीरे-धीरे बढ़ता चला गया । इस प्रकार ग्रामीण जिलों की सशस्त्र क्रान्तिकारी फौजों द्वारा, प्रतिक्रांतिकारियों द्वारा हथियाए गए शहरों की घेराबन्दी की जा सकती थी तथा अन्ततः उन पर कब्जा किया जा सकता था । जब शहरों में क्रांति को शक्तिशाली शत्रु के हाथों पराजित होना पड़ा था तथा विजय प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं बचा था, ऐसे समय में चीनी क्रान्ति के विकास के लिए यही एकमात्र सही रास्ता था । इस प्रकार पार्टी ने लाल सेना तथा क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों का सृजन किया तथा क्रान्तिकारी युद्ध व कृषि-क्रांति का नेतृत्व करना तथा राजनीतिक सत्ता स्थापित करना सीखा।

18 सितम्बर, 1931 की घटना के बाद तथा विशेषकर, 1935 में उत्तरी चीन में घुसपैठ के बाद, जापानी साम्राज्यवादियों ने समूचे चीन पर कब्जा करने की नीति का अनुसरण किया। इससे चीन तथा जापान के बीच का अंतर्विरोध मुख्य अंतर्विरोध बन गया, तथा चीन के अन्दरूनी अंतर्विरोध दूसरे स्थान पर आ गए । चीन के अन्दरूनी वर्ग-सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों मे परिवर्तनों का एक लंबा सिलसिला घटित हुआ । पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा साथी माओ ने तदनुसार, जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा स्थापित करने व इस संयुक्त मोर्चे को विश्व के शांति मोर्चे से सम्बद्ध करने के कार्यभार प्रस्तुत किये । लाल शासन स्थापित करने के संघर्ष के दौरान, पार्टी ने साथी माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में, गलत "वामपंथी" कार्यदिशा तथा चाङ क्वो-थाओ की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की तथा जापानी सैनिकवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान "वामपंथी" कट्टरतावाद की कार्यनीतियों में सुधार किया ।

इस प्रकार दस वर्ष की प्रतिक्रियावादी अवधि के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सही, सृजनात्मक व मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेतृत्व के अन्तर्गत, घरेलू तथा विदेशी शत्रुओं के हमलों को विफल किया, अवसरवाद के हमलों पर विजय पाई तथा लाल सेना की मुख्य-शक्ति, क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों के कुछ हिस्सों व बड़ी संख्या में श्रेष्ठ कार्यकर्त्ताओं को बचाए रखा, और इसके साथ-साथ शानदार क्रान्तिकारी अनुभव प्राप्त किया । 1935 के अंत में, जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के लिए पार्टी की कार्यनीति की पक्के तौर से स्थापना के बाद, गृहयुद्ध समाप्त हो गया तथा उसका जापान-विरोधी युद्ध में संक्रमण शुरू हो गया ।

दूसरे क्रांतिकारी गृहयुद्ध का काल एक ऐसा काल था जिसमें पार्टी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सैद्धांतिक तथा राजनीतिक परिपक्वता हासिल की । इस प्रकार दूसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तैयारियों को पूरा किया तथा चीनी क्रान्ति के विकास के लिए जरूरी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया । ●

नोट

1. **"हो उमेजू" समझौता :-** इस समझौते पर जून 1935 में, उत्तरी चीन में क्वोमिंताङ सरकार के प्रतिनिधि हो इङ-छिन तथा उत्तरी चीन में जापानी सशस्त्र सेनाओं के सेनापति योशीजीरो उमेजू के

बीच हस्ताक्षर हुए थे । इसमें क्वोमिंताङ सरकार ने जापान द्वारा प्रस्तुत मांगें स्वीकार कर लीं तथा इसके अनुसार हपे तथा छाहाड़ प्रान्तों में चीनी प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को जापान के हवाले कर दिया गया।

2. चीन की राष्ट्रीय मुक्ति का हरावल दस्ता :- यह एक क्रांतिकारी युवा संगठन था, जिसका गठन सितंबर 1936 में, 9 दिसंबर, 1935 के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रगतिशील युवाओं द्वारा कम्युनिस्ट नेतृत्व के अंतर्गत किया गया था । जापानी हमले के विरुद्ध प्रतिरोध की लड़ाई शुरू हो जाने के बाद, इस संगठन के बहुत से सदस्य मोर्चे पर चले गए तथा उन्होंने शत्रु के पृष्ठभाग में आधार-क्षेत्र स्थापित करने में हिस्सा लिया ।

3. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं ; ग्रन्थ-1, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ ; दूसरा मुद्रण, 1971 ; पृष्ठ-267

4. —वही—पृष्ठ-267

5. —वही—पृष्ठ-274

6. —वही—पृष्ठ-291

7. —वही—पृष्ठ-488

8. मंचूक्वो :- जापान द्वारा उत्तर-पूर्वी चीन में स्थापित कठपुतली राज्य ।

●●●

3.

- **जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे के अन्दर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतन्त्रता तथा पहलकदमी की नीति ।**
- **पार्टी द्वारा छापामार लड़ाई आरंभ करना तथा शत्रु की पाँतों के पीछे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना करना ।**

जापान-विरोधी युद्ध की शुरुआत से ही दो विरोधी नीतियाँ सामने आईं : एक थी—जिसका अनुसरण बड़े जमींदार तथा बड़े पूँजीपति कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व क्वोमिंताङ कर रही थी; दूसरी नीति थी—जिसका अनुसरण श्रमिक वर्ग तथा व्यापक जनसमुदाय ने किया, जिनका प्रतिनिधित्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी ।

क्वोमिंताङ को जनता के दबाव तथा इस तथ्य के कारण प्रतिरोध करने को बाध्य होना पड़ा कि जापानी हमले ने ब्रिटिश तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के हितों को तथा बड़े जमींदारों व बड़े पूँजीपतियों, जिनका प्रतिनिधित्व "चार बड़े घराने" करते थे, के हितों को गंभीर क्षति पहुंचाई थी ।

आखिरकार 17 जुलाई, 1937 को च्याङ काई-शेक ने लूशान में एक वक्तव्य जारी किया तथा बड़े ही अनमने ढंग से जापान का प्रतिरोध करने की घोषणा की । तथापि, युद्ध के बारे में उसका रवैया ढुलमुलपन का ही रहा ।

लूकओछ्याओ घटना के तुरंत बाद, आत्मसमर्पण के लिये तैयार बैठी क्वोमिंताङ ने जापान के साथ वार्ता का प्रस्ताव रखा तथा पेशकश की कि चीनी तथा जापानी, दोनों सेनाएं, लूकओछ्याओ के समीप चीनी धरती के एक निश्चित क्षेत्र से एक साथ पीछे हट जाएं । लेकिन जापान सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया । फिर क्वोमिंताङ सरकार ने तथाकथित "शांतिपूर्ण समझौते के लिए योजना" को स्वीकार कर लिया, जिसे जापानी प्रतिनिधियों तथा उत्तरी चीन में स्थानीय अधिकारियों ने तैयार किया था । (इसमें दो मुख्य बातें थीं : पेकिङ, थ्येनचिन, लूकओछ्याओ तथा युङथिङ नदी के पूर्व में स्थित इलाकों से चीनी फौजों की वापसी, तथा चीन व जापान के बीच कम्युनिस्ट विरोधी गठजोड़) इन वार्ताओं ने जापान को, विशाल पैमाने पर चीन पर हमला करने के लिए अपनी और ज्यादा सैन्य-शक्ति को लाने के लिए समय प्रदान किया, जिसकी उसे जरूरत थी ।

जब 13 अगस्त को जापानी सेना द्वारा शंघाई पर हमला किया गया तथा दक्षिण-पूर्वी चीन में "चार बड़े घरानों" का शासन लड़खड़ाने लगा, तथा क्वोमिंताङ के पास और कोई चारा न बचा, केवल तभी उसने प्रतिरोध युद्ध शुरू किया ।

नानकिङ के पतन से पहले, क्वोमिंताङ सरकार जापान के साथ बार-बार की जा रही वार्ताओं में आत्मसमर्पण करने को तैयार थी । इन वार्ताओं में से एक में, जैसा कि सर्वविदित था, चीन में नियुक्त फासीवादी जर्मन राजदूत ने बिचौलिये की भूमिका निभाई । उसके माध्यम से जापान ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं : 1. चीन द्वारा मंचूक्वो (उत्तरी चीन में जापान द्वारा स्थापित कठपुतली राज्य) को मान्यता देना, 2. भीतरी मंगोलिया की स्वतंत्रता को मान्यता देना, 3. चीन-जापान के बीच "आर्थिक सहयोग" की स्थापना, 4. कम्युनिज्म के खिलाफ संयुक्त चीनी-जापानी रक्षात्मक कार्यवाही, 5. चीन में जापान-विरोधी आन्दोलनों पर पाबंदी लगाना तथा

युद्ध के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए तथा किसी तीसरी शक्ति द्वारा चीन पर हमले की स्थिति में, सोवियत-संघ हमलावर देश को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता देने से इन्कार कर देगा ।

इस संधि से चीनी जनता को नैतिक समर्थन मिला तथा हमलावरों के मुँह पर भारी तमाचा पड़ा ।

सोवियत-संघ ने साजोसामान की मदद भी दी। उत्तर-पश्चिम के जरिए शस्त्रास्त्रों, पेट्रोल तथा वाहनों की विशाल खेप भेजी गई। सोवियत वायु सैनिकों ने चीन की रक्षा में हिस्सा लिया ।

चीनी जनता के संकट की घड़ी में महान दोस्ती का यह बढ़ा हुआ हाथ, चीन के राष्ट्रीय-मुक्ति आन्दोलन में एक अमूल्य योगदान था ।

युद्ध के आरंभ में, किसी भी पश्चिमी पूँजीवादी देश ने चीन को किसी प्रकार की वास्तविक मदद नहीं दी । लूकओछ्याओ घटना से पहले पश्चिम के अखबारों ने बड़े जोर-शोर से दावा किया कि चीन का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ढाँचा हमले का प्रतिरोध करने के लिए असमर्थ था तथा कुछ ही महीनों में जापान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लेना था । पश्चिमी पूँजीपति वर्ग के शासकीय तबकों ने *"प्रतीक्षा करो और देखो"* का रवैया अपनाया । जब जापान ने हमला किया तो ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका, मध्य चीन में उनके प्रभुत्व के केन्द्र, शंघाई से पीछे हट गए ; ब्रिटेन कैंटन से भी पीछे हट गया, जो कि दक्षिणी चीन में उसके एकछत्र प्रभुत्व वाला अड्डा था, तथा फ्रांस हाएनान द्वीप से पीछे हट गया ।

आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादियों को विश्वास था कि चीन-जापान युद्ध में चीन के राष्ट्रीय-मुक्ति-संग्राम की ज्वाला बुझ जाएगी तथा जापानी साम्राज्यवादी कमजोर हो जाएंगे । अतः उन्होंने *"शेरों को सुरक्षित दूरी से लड़ते देखने"* की नीति अपनाई । ब्रिटेन तथा खासतौर से अमरीका, जापान-विरोधी युद्ध छिड़ जाने के बाद भी विशाल मात्रा में जापान को युद्ध-सामग्री की आपूर्ति करते रहे । **जापान द्वारा चीन के विरुद्ध इस्तेमाल किये गये पेट्रोल, वायुयानों, लोहे, इस्पात तथा अन्य युद्ध-सामग्री का बहुत बड़ा हिस्सा अमरीका द्वारा सप्लाई किया गया था । अमरीका के सरकारी आँकड़ों के अनुसार, जापान को 1937 में किये गए कुल निर्यात का 58 प्रतिशत, 1938 के निर्यात का 66 प्रतिशत तथा 1939 में किये गये निर्यात का 81 प्रतिशत हिस्सा केवल युद्ध-सामग्री थी ।**

चूंकि चीन के विरुद्ध जापानी हमलावर युद्ध से, पूर्व में ब्रिटेन तथा अमरीका के हितों को धक्का पहुँचता था, अतः जापान तथा उनके दरम्यान दरार पड़ना स्वाभाविक था । लेकिन चीनी जनता की शक्ति के विकास को अवरुद्ध करने, युद्ध को सोवियत-संघ की ओर मोड़ने तथा हिटलर द्वारा यूरोप में पैदा की गई तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादी जापान के साथ अपने संघर्ष को कम करने को आतुर थे, और इसके लिए वे जापानी हमले को प्रोत्साहित करने की सीमा तक चले गए । 1941 में प्रशान्त युद्ध छिड़ने से पहले, उन्होंने या तो जापान के साथ समझौते के भरसक प्रयास किए, या फिर इस उम्मीद में पीछे बैठे रहे कि युद्ध में चीन तथा जापान, दोनों ही शिथिल हो जाएंगे ।

यह ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा अपनाई गई *"हस्तक्षेप न करने की नीति"* का असली नंगा रूप था ।

आठवां अध्याय

जापानी हमले के विरुद्ध प्रतिरोध-युद्ध का आरंभिक काल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चे के अन्दर सर्वहारा वर्ग की स्वतन्त्रता व पहलकदमी तथा जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देना

(जुलाई 1937 से दिसंबर 1940)

1.

- **1937 से 1939 तक की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ।**
- **दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत ।**

जापानी हमले के विरुद्ध प्रतिरोध-युद्ध आरंभ हुआ तथा जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी जारी रहा ।

1929 से 1932 तक चला विश्व आर्थिक संकट, अपनी कालावधि, गंभीरता तथा मारक क्षमता के लिहाज से अभूतपूर्व था । 1933 में यह संकट आर्थिक मंदी के दौर में तब्दील हो गया । पूँजीवाद के सामान्य संकट के हालातों के अन्तर्गत, यह मन्दी, जो पहले की मन्दियों से भिन्न थी, औद्योगिक तेज़ी लाने में विफल रही । यदि विभिन्न पूँजीवादी देशों के 1929 के औद्योगिक उत्पादन को 100 माना जाए तो सन् 1937 में तीन तथाकथित जनवादी देशों, अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के आँकड़े क्रमशः 92.2, 82.8 तथा 123.7 थे । अमरीका तथा फ्रांस, संकट पूर्व के स्तर से नीचे थे जबकि ब्रिटेन ने वृद्धि दर्ज की थी । जबकि तीन आक्रमणकारी देशों जर्मनी, जापान तथा इटली के औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े क्रमशः 117.2, 170.8 तथा 99.6 थे । जर्मनी तथा जापान तो 1929 के स्तर से आगे बढ़ गए थे जबकि इटली ने उस स्तर को लगभग छू लिया था ।

1937 के उत्तरार्द्ध में एक और आर्थिक संकट फैल गया । 1938 में अमरीका का औद्योगिक उत्पादन, 1929 के स्तर की तुलना में 72 प्रतिशत, ब्रिटेन का 112 प्रतिशत, फ्रांस का 71 प्रतिशत, इटली का 96 प्रतिशत, जापान का 165 प्रतिशत तथा जर्मनी का 125 प्रतिशत था । अकेले जर्मनी को छोड़कर, जहां पर औद्योगिक उत्पादन में बढ़ौतरी हुई, बाकी देशों के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई । लेकिन, जर्मनी ने चूंकि अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध-स्तर पर ला खड़ा किया था, अतः उसका भी आर्थिक संकट में फँस जाना अवश्यभ्भावी था ।

सोवियत-संघ ही एकमात्र ऐसा देश था, जहाँ इस दौर में आर्थिक संकट नाममात्र को भी नहीं थे । औद्योगिक उत्पादन के लिए उसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना नियत समय से पहले

ही पूरी हो गई थी । 1937 के अंत तक, सोवियत-संघ का औद्योगिक उत्पादन 1929 के स्तर की तुलना में 428 प्रतिशत हो गया था । इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात उद्योगों के विकास में समाजवादी प्रणाली को महान सफलता मिलना थी । 1937 में समाजवादी उद्यमों का उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का 99.97 प्रतिशत था, जिससे पता चलता था कि सोवियत-संघ में समाजवादी प्रणाली ही उद्योग की एकमात्र प्रणाली थी । कृषि सहकारिता को भी खूब सफलता मिली । 1937 तक, 1,25,00,000 किसान परिवार या कुल किसानों का 93 प्रतिशत, सहकारी फार्मों में शामिल हो चुके थे । इससे कृषि सहकारिता के सम्पन्न होने की मुहर लग गई ।

पूँजीवादी देशों में नए आर्थिक संकट के फैल जाने ने, इन देशों द्वारा सैनिक हस्तक्षेप से विश्व बाजार, कच्चे माल के स्त्रोतों, अपने अधिकार-क्षेत्रों तथा प्रभाव-क्षेत्रों का पुनर्विभाजन करने के क्षण को और नजदीक ला दिया ।

1937 में जापान ने उत्तरी तथा मध्य चीन पर हमला कर दिया । जर्मनी ने 1938 के आरंभ में आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, तथा उसी वर्ष के पतझड़ में चेकोस्लोवाकिया के सूडेतन क्षेत्र को हथिया लिया व 1939 में सारे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार जमा लिया । 1939 के बसन्त में, इटली ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया, तथा जर्मनी के साथ मिलकर स्पेन में फासीवादी शासन स्थापित करने में फ्रान्को की मदद की । इसके बाद जर्मनी ने पोलैण्ड पर हमला कर दिया, तदनन्तर ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई तथा इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया ।

यह युद्ध राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन तथा सोवियत-संघ के विरुद्ध था, एवं साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका के साम्राज्यवादी हितों के खिलाफ भी था । द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले जर्मनी, इटली तथा जापान ने अनेक अवसरों पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका के हितों का अतिक्रमण किया था, लेकिन ये देश हस्तक्षेप न करने की नीति पर चलते हुए तथा हमलावरों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा तथा सामूहिक प्रतिरोध की नीति को अस्वीकारते हुए, समान रूप से पीछे हटते रहे थे । यहां तक कि उन्होंने हमलावरों की कई तरह से मदद तक भी की ।

यह अमरीकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों का समर्थन ही था जिसकी वजह से जर्मन इजारेदार पूँजीपति, जर्मन सैनिकवाद को पुनर्जीवित करने में सफल हुए । खासतौर से अमरीकी सरकार के नेताओं ने, जर्मनी के भारी उद्योगों तथा सामरिक उद्योगों की पुनर्स्थापना तथा पुनरुद्धार में मदद की । 1924 से 1929 के दौरान अमरीकी इजारेदार पूँजीपतियों ने जर्मनी के सामरिक उद्योगों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ मार्क (जर्मन मुद्रा) के बराबर की पूँजी जर्मनी भेजी । और इसी अमरीकी वित्तीय सहायता ने जर्मन सैनिकवाद के पुनरुद्धार को आधार प्रदान किया । हिटलर के सत्ता में आने के बाद, ब्रिटेन तथा फ्रांस की सरकारों ने उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई । 1933 में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली ने रोम में **चार शक्ति समझौते (Four Power Pact)** पर हस्ताक्षर किए । 1934 में ब्रिटेन तथा फ्रांस की मध्यस्थता से नाजी जर्मनी ने पोलैण्ड के साथ द्विपक्षीय अनाक्रमण संधि (Mutual Non-Aggression Treaty) संपन्न की । ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जर्मनी के पुनर्स्त्रीकरण, इथोपिया पर इटली के कब्जे तथा स्पेन पर जर्मनी तथा इटली के संयुक्त हमले को भी मौन स्वीकृति प्रदान की । 1937 में, ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, तथा दान्जिग पर कब्जे को सहमति प्रदान की, और यहां तक कि हिटलर से ब्रिटेन तथा फ्रांस को "बर्लिन-रोम-धुरी" में शामिल कर लेने

जुलाई 1937 में जारी वक्तव्य को सरकारी तौर पर प्रकाशित किया तथा च्याङ काई-शेक को मजबूरन एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी को वैधानिक रूप से मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार पार्टी की पहलकदमी पर शुरू हुआ जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा स्थापित हो गया । यह एक ऐसा संयुक्त मोर्चा था जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक था तथा ढाँचा बेहद जटिल था । इसमें श्रमिक, किसान, शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा यहां तक कि ब्रिटेन व अमरीका-परस्त बड़े-बड़े पूँजीपति भी शामिल थे ।

समूचे प्रतिरोध युद्ध के दौरान चीन को सोवियत-संघ से भरपूर सहायता मिली ।

विशाल सोवियत-संघ सर्वाधिक विश्वसनीय तथा शक्तिशाली देश था जो युद्ध में चीन की सहायता कर सकता था । वह सदैव चीनी जनता के दुख-दर्द में पूरी गंभीरता से उसका साथ देता रहा था तथा सभी दबे-कुचले राष्ट्रों एवं सभी क्रान्तिकारी युद्धों का समर्थन करना अपना कर्त्तव्य समझता था । 21 अगस्त, 1937 को सोवियत-संघ ने चीन के साथ अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए तथा घोषणा की कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक उद्देश्यों के लिए

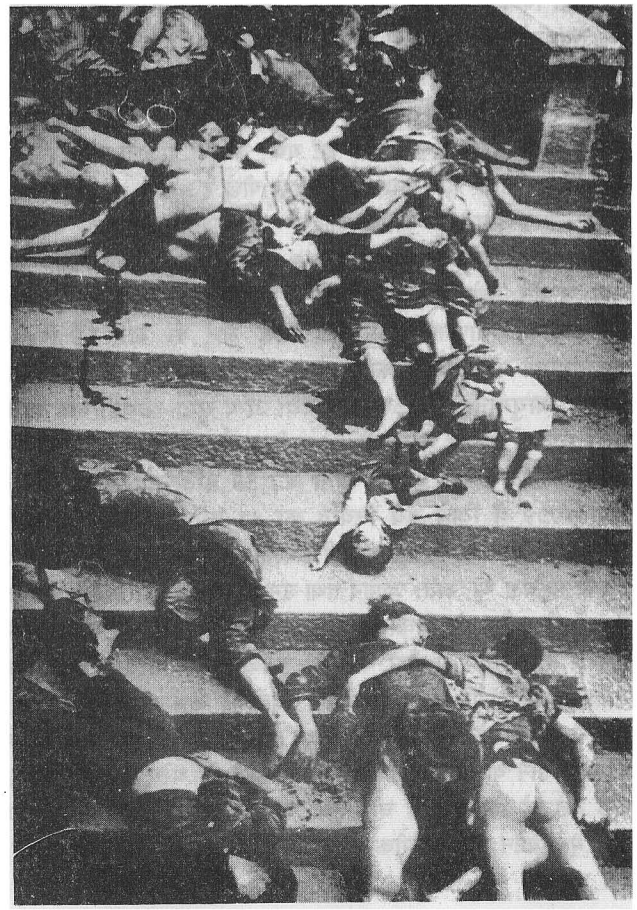

जापानी बमवर्षकों द्वारा छुङकिङ पर की गई बमबारी के दौरान मारी गई निर्दोष महिलाएं एवम् मासूम बच्चे

दृढ़ प्रतिरोध करने, सभी राजनीतिक संगठनों में आमूल-चूल परिवर्तन करने तथा लोकतन्त्र को लागू करने के लिए उठ खड़ी हुई । उसने किसी भी प्रकार के ढुलमुलपन तथा समझौतों का जबरदस्त विरोध किया । क्वोमिंताङ सेना के बहुत से अफसरों तथा उसकी अनेक स्थानीय इकाइयों ने भी प्रतिरोध का आह्वान किया । इस प्रकार जापान के प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय पुनरुद्धार आंदोलन में अभूतपूर्व गति आ गई ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 15 जुलाई, 1937 को कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ में सहयोग का आह्वान करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया : ''डॉ०सुन के 'तीन जन-सिद्धान्तों' की जनता को आज सख्त जरूरत है, और हमारी पार्टी उनके पूर्णतया साकार होने तक लड़ते रहने की प्रतिज्ञा करती है ।'' वक्तव्य में क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन को भेजे गए तार में पार्टी द्वारा दिए गए चार वचनों को पूरा करने की पार्टी की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई । ऐसा करके, पार्टी ने राष्ट्रीय ध्येय के प्रति अपनी निस्वार्थ निष्ठा को प्रकट किया ।

कम्युनिस्ट पार्टी के अथक प्रयास तथा जनता की पुरजोर मांग अंततः सफल हुई । 22 अगस्त, 1937 को क्वोमिंताङ सरकार ने उत्तर-पश्चिम में लाल सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियों को राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना की आठवीं राह सेना के रूप में पुनर्गठित करने की घोषणा की। (बाद में, लाल सेना द्वारा दक्षिणी प्रान्तों में पीछे छोड़े गए छापामार दस्तों को नई चौथी सेना के रूप में पुनर्गठित किया गया) 22 तथा 23 सितंबर को क्वोमिंताङ ने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा

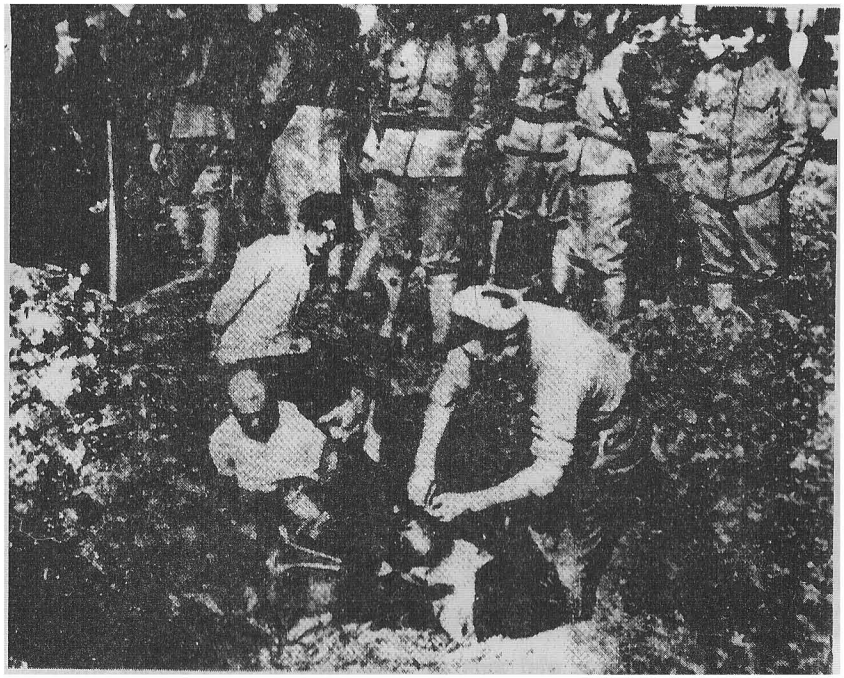

बर्बर जापानी सिपाही निर्दोष चीनी लोगों को जिन्दा दफन करते हुए

के लिये भी कहा । ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी शासक, सामने खड़े खतरे से आँखें मूंदे हुए थे, तथा फासीवादी हमले को पूर्व की ओर, सोवियत-संघ के विरुद्ध मोड़ने का प्रयास कर रहे थे ।

यद्यपि ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका, चीन में जापान द्वारा उनके हितों के अतिक्रमण से खिन्न थे, लेकिन वे सोवियत-संघ में समाजवादी निर्माण की सफलता, यूरोप में श्रमिक-वर्ग आंदोलन के उभार तथा एशिया में राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों के उत्थान से भी भयभीत थे । उनके अनुसार, विश्व-क्रांति के विरुद्ध फासीवाद एक शक्तिशाली हथियार था । अतः उन्होंने इस उम्मीद में एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखने की नीति अपनाई कि जब युद्धरत देश एक-दूसरे से लड़ते हुए थककर चूर हो जाएंगे, तब वे आगे बढ़कर दोनों पक्षों पर अपनी मनचाही शर्तें थोंप देंगे ।

हमलावरों द्वारा थोंपा गया कोई भी युद्ध, सभी शांति-प्रिय देशों के लिए स्पष्टतः एक खतरा था । यह भली प्रकार विदित था कि एक ऐसा युद्ध, जिसने कोटि-कोटि लोगों को अपनी लपेट ले लेना था, विशेषकर, सोवियत-संघ के लिए एक गंभीर खतरा था ।

सोवियत-संघ घटनाओं को इस तरह खतरनाक मोड़ लेते देखकर नजरअन्दाज नहीं कर सकता था । अतः सोवियत-संघ ने शांति बनाए रखने, सभी देशों के साथ व्यापार-संबंधों को सुदृढ़ करने, पड़ौसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा आक्रमण के विरुद्ध आजादी के लिए संघर्ष कर रहे देशों को समर्थन देते रहने की अपनी नीतियों का पालन करते हुए, अपनी लाल सेना तथा जल सेना की युद्ध-क्षमता को बढ़ाने का भी भरपूर प्रयास किया, ताकि यदि कोई युद्धोन्मादी उस पर हमला करने का दुस्साहस करता तो दुगुनी शक्ति से उस पर जवाबी वार किया जा सकता ।

आर्थिक संकट से प्रभावित होकर, जर्मन, इतालवी तथा जापानी साम्राज्यवादियों ने दूसरा विश्वयुद्ध शुरू कर दिया और उधर फासीवाद-विरोधी मित्र-राष्ट्रों में, युद्ध के उद्देश्यों तथा युद्धोपरान्त विश्व में शांति बनाए रखने के कार्यभार को लेकर तीव्र मतभेद थे ।

धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध का जो उद्देश्य सोवियत-संघ तथा विश्व के सभी आजादी चाहने वाले लोगों ने ग्रहण किया, वह था—जनवाद को दोबारा कायम करना तथा सुदृढ़ करना, फासीवाद को नेस्तनाबूद करना, धुरी-राष्ट्रों द्वारा दोबारा हमले की किसी भी संभावना को समाप्त करना तथा सभी राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग स्थापित करना । लेकिन बरतानवी, फ्रांसीसी तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों का जो उद्देश्य था, वह इसके बिल्कुल उल्ट था । वे जर्मनी तथा जापान को विश्व बाजार से खदेड़कर उस पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे । उन्हें सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध, फासीवाद को कुचल कर रख देगा तथा फासीवादी शक्तियों द्वारा गुलाम बनाए गए देशों को मुक्ति दिलवाएगा और इस प्रकार इन देशों में जनवादी सुधारों के लिए हालात पैदा करेगा । ●

2.

- **राष्ट्रीय प्रतिरोध-युद्ध छिड़ने पर जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का गठन ।**
- **प्रतिरोध-युद्ध में सोवियत-संघ द्वारा चीन को समर्थन ।**

7 जुलाई, 1937 को जापानी फासीवादी सैनिकों ने पेकिङ से लगभग 10 किलोमीटर

दक्षिण-पश्चिम में स्थित लूकओछ्याओ (मारकोपोलो पुल) पर हमला कर दिया। बढ़ते जा रहे जापान-विरोधी आंदोलन के प्रभाव के अन्तर्गत, स्थानीय चीनी सेना ने क्वोमिंताङ की इच्छाओं की परवाह न करते हुए दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया । 13 अगस्त, 1937 को मध्य चीन पर चढ़ाई के आरंभिक कदम के रूप में, जापानी सेनाओं ने शंघाई पर हमला किया । वहां मौजूद चीनी सैनिक टुकड़ियों ने दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया । इस प्रकार जापानी हमले के विरुद्ध चीन का प्रतिरोध युद्ध शुरू हुआ ।

अपने आन्तरिक तथा बाह्य अन्तर्विरोधों में तीव्रता आ जाने के कारण, जापानी साम्राज्यवादियों ने बड़े व्यापक पैमाने पर भयंकर तथा दुस्साहसपूर्ण युद्ध—एक अत्यधिक बर्बरतापूर्ण साम्राज्यवादी युद्ध—शुरू कर दिया । जापानी फासीवादी सैनिकों द्वारा किये गए नरसंहारों, बलात्कारों, लूटमार, आगजनी, विध्वंसों तथा अन्य अमानवीय अत्याचारों ने मानवता के इतिहास पर एक अमिट कालिख पोत दी ।

शत्रु ने चीनी जनता का अन्धाधुन्ध कत्लेआम किया । नानकिङ के पतन के बाद हुए कत्लेआम में, जो एक महीने से भी ज्यादा समय तक चला, तीन लाख से भी अधिक निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया । बहुत बड़ी तादाद में उन सैनिकों को, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, टोलियों में मशीनगनों से भून दिया गया या फिर जिन्दा जला दिया गया।

बलात्कार की घटनाएँ तो और भी ज्यादा रौंगटे खड़े कर देने वाली थीं । न तो छोटी उम्र की मासूम बच्चियों की और न ही वृद्धाओं को बक्शा गया । बहुत से मामलों में बलात्कार करने के बाद अंग-भंग कर दिए गए, हत्या कर दी गई तथा अवर्णनीय पाशविकता का व्यवहार किया गया ।

इन अत्याचारों द्वारा शत्रु स्पष्टतः चीनी जनता को गुलाम बनाना तथा हमले का प्रतिरोध करने के उसके मनोबल को तोड़ना चाहता था ।

जापानी हमलावरों द्वारा लूटमार व विनाश की कोई सीमा न रही । जहाँ भी वे गए, वहाँ उन्होंने वाहनों, पशुधन, अनाज, वस्त्र, पैसा तथा अन्य जो कुछ भी उनके हाथ लगा, उसे लूट लिया । फर्नीचर, दरवाजे तथा खिड़कियों के चौखटे आग जलाने के काम में लाए गए । असंख्य घरों को जलाकर राख कर दिया गया ।

शत्रु ने हर संभव तरीके से चीन के उद्योग तथा व्यापार को नष्ट करने का प्रयास किया। चीनी राष्ट्रीय उद्योग तथा व्यापार के केन्द्रों—च्याङसू तथा चच्याङ को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा । 13 अगस्त से नवंबर 1937 तक शंघाई में कुल घाटा, युद्ध-पूर्व की राष्ट्रीय मुद्रा के अनुसार 300 करोड़ डॉलर था । बहुत से दूसरे शहरों में भी लगभग इसी तरह से घाटा हुआ।

चीनी जनता की धन-दौलत को, चाहे वह आधुनिक फैक्ट्रियों के रूप में थी, या किसानों की झोंपड़ियों के रूप में थी, बेहद बर्बरतापूर्वक नष्ट किया तथा लूटा गया ।

इस बर्बरतापूर्ण नीति ने चीनी जनता के सभी तबकों को एक शक्तिशाली जापान-विरोधी संघर्ष छेड़ने के लिए मजबूर कर दिया । उत्तरी चीन में जापानी हमले के तत्काल बाद, जापान के प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए, दोबारा इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था । प्रतिरोध युद्ध में चीनी जनता ने हर संभव योगदान दिया। समूचे चीन में राष्ट्र को बचाने के लिए अनेक संगठन स्थापित हो गए । समूची चीनी जनता

28 अगस्त, 1937 को जापानी बमवर्षकों द्वारा शंघाई पर की गई नृशंस बमबारी के दौरान घायल एक बच्चा

बर्बर जापानी सिपाही एक चीनी जवान को जिन्दा निशाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए

विकास के फलस्वरूप, निस्सन्देह एक समाजवादी समाज में विकसित हो जाना था । नव-जनवादी क्रान्ति का यह काल, अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती समाज तथा समाजवादी समाज के बीच का संक्रमण काल (Transition Period) होना था ।

सबसे पहले, कामरेड माओ ने क्वोमिंताङ के कट्टरपंथियों के पूँजीवादी तानाशाही संबंधी बेहूदा दावों का खण्डन किया । उन्होंने स्पष्ट किया कि बीसवीं सदी के पाँचवें दशक में जब पूँजीवाद का पतन तथा समाजवाद का उत्थान हो रहा था, चीन में पूँजीवादी तानाशाही के तहत किसी पूँजीवादी समाज की स्थापना का विचार पूर्णरुपेण अव्यावहारिक तथा भ्रामक था । न तो घरेलू और न ही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति चीन को यह रास्ता चुनने की अनुमति दे सकती थी । कामरेड माओ ने कमाल (Kemal) की भूमिका निभाने के च्याङ काई-शेक के प्रयास को हास्यास्पद बताते हुए स्पष्ट किया कि क्रान्ति से गद्दारी करने के पश्चात च्याङ ने जो कुछ किया वह एक स्वाधीन पूँजीवादी समाज का निर्माण करना नहीं था बल्कि अर्ध-औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक समाज को बचाए रखना था; किसी तरह की पूँजीवादी-तानाशाही लाना नहीं था बल्कि एक दयनीय अर्ध-औपनिवेशिक एवं अर्ध-सामंती तानाशाही स्थापित करना था । इस प्रकार च्याङ ने स्वयं को एक दलाल-पूँजीपति तथा साम्राज्यवादियों का पालतू कुत्ता सिद्ध कर दिया था ।

चीनी क्रांति की पहली मंजिल काफी लम्बे समय तक चलनी थी । जब तक साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरोध का कार्यभार संपन्न नहीं हो जाता (अर्थात् इन दोनों का चीन से खात्मा नहीं कर दिया जाता), तब तक समाजवादी क्रांति आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था । चूंकि जनवादी तथा समाजवादी क्रांति, प्रत्येक के अपने-अपने तयशुदा कार्यभार तथा अपने-अपने तयशुदा समय थे, इसलिए समाजवादी कार्यभारों—जिन्हें केवल किसी दूसरे वक्त ही कार्यान्वित किया जा सकता था—को जनवादी कार्यभारों के साथ मिलाना तथा दोनों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करना गलत था । दो क्रांतिकारी मंजिलों में से, पहली मंजिल ने दूसरी मंजिल के लिए परिस्थितियाँ तैयार करनी थीं । विकास तथा संक्रमण का यही वह रास्ता था, जिस पर चीन के क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ना चाहिये थे ।

"एक ही क्रान्ति का सिद्धान्त" का मतलब *"किसी इमारत के शहतीर (Beam) तथा खंभों (Pillars) की जगह गली-सड़ी लकड़ी लगा देना"* था; असलियत में यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र था, जिसका उद्देश्य क्रान्ति को ही समूल नष्ट करना था ।

कामरेड माओ ने केवल चीनी क्रान्ति के सिद्धान्तों की विस्तार से व्याख्या तथा विभिन्न प्रतिक्रियावादी धारणाओं का खण्डन ही नहीं किया, बल्कि ठोस नव-जनवादी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये तथा इस प्रकार एक नए चीन के निर्माण की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत की ।

1. राजनीतिक कार्यक्रम के तहत एक नव-जनवादी गणराज्य की स्थापना की जानी थी। इस गणराज्य ने एक ओर तो पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व वाले पुराने यूरोपीय-अमरीकी ढंग के पूँजीवादी गणराज्य से भिन्न होना था तथा दूसरी ओर सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत सोवियत-संघ के ढंग के समाजवादी गणराज्यों से भी भिन्न होना था । मजदूर-किसान मैत्री पर आधारित, सर्वहारा के नेतृत्व में, तथा सभी साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद विरोधी क्रान्तिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकत्व के अधीन एक जनवादी गणराज्य होना था । इस प्रकार राजनीतिक

दमन करने की नीति को चकनाचूर किया जा सकता था ।

जापान-विरोधी युद्ध में रणनीतिक रक्षा की मंजिल के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, क्वोमिंताङ की नीति के विपरीत, संपूर्ण जनप्रतिरोध की नीति पर चली तथा एक स्वतन्त्र छापामार-युद्ध चलाया व शत्रु के पृष्ठभाग में अनेक जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना की।

अगस्त 1937 में आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना ने, जिनकी कुल तादाद 40,000 से अधिक थी, मोर्चे की ओर कूच किया । आठवीं राह सेना ने उत्तरी चीन की ओर तथा नई चौथी सेना ने याङत्सी नदी के उत्तर तथा दक्षिण के इलाकों की ओर प्रस्थान किया । आठवीं राह सेना के प्रधान सेनापति कामरेड चू तेह थे तथा उसमें तीन डिवीजनें थीं (115वीं, 120वीं तथा 129वीं), जिनकी कुल तादाद 30,000 से अधिक थी । नई चौथी सेना के कमाण्डर ये थिङ तथा डिप्टी कमाण्डर श्याङ इङ थे तथा उसमें 12,000 सैनिक थे । यद्यपि दोनों सेनाएँ संख्या की दृष्टि से क्वोमिंताङ की सेनाओं से कहीं छोटी थीं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से वे उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं, क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ का स्तर बहुत ऊँचा था, जनता के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे तथा वे समस्त राष्ट्र के हितों के लिए लड़ रही थीं । इनमें से किसी भी बात में क्वोमिंताङ की सेनाएँ उनकी बराबरी नहीं कर सकती थीं । फलतः, ज्योंही आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना लड़ाई के मैदान में उतरीं, क्वोमिंताङ सेनाओं के विपरीत, उन्होंने सफलताओं की झड़ी लगा दी तथा क्वोमिंताङ द्वारा हारे गए विशाल क्षेत्रों को शत्रु से मुक्त करा लिया ।

मोर्चे पर पहुँचने के तत्काल बाद, आठवीं राह सेना की मुख्य शक्ति—115वीं डिवीजन, जापानी सेना को थाएय्वान के दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए फिङशिङक्वान दर्रे की ओर बढ़ी । 25 सितम्बर को, उसने शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए कामरेड लिन प्याओ की कमान में पहली लड़ाई शुरू की तथा शत्रु के 3,000 बर्बर सैनिकों को खदेड़ दिया । इस विजय ने सेना की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि की तथा जनता को अन्तिम विजय में विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया ।

क्वोमिंताङ की सेनाओं ने बदहवासी की हालत में पीछे की तरफ भागना जारी रखा, जबकि आठवीं राह सेना ने शिनखओ तथा थाएय्वान में लगातार दो लड़ाइयों में चङतिङ-थाएय्वान तथा ताथुङ-फूचओ रेलमार्गों के साथ आगे बढ़ रहे जापानियों को रोकने में सफलता प्राप्त की।

8 नवम्बर, 1937 को थाएय्वान जापानियों के कब्जे में चला गया तथा क्वोमिंताङ सेनाएँ शानशी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से की ओर पीछे हट गईं । लेकिन उत्तरपूर्वी शानशी के ऊथाएशान क्षेत्र में तथा चङतिङ-थाएय्वान रेलमार्ग के साथ-साथ शत्रु की पांतों के पीछे कार्यवाहियां कर रही आठवीं राह सेना की विभिन्न यूनिटों ने हमलावर जापानियों को परेशान करना जारी रखा तथा उन्हें पीली नदी पार करने तथा पश्चिम की ओर आगे बढ़ने से रोके रखा, तथा इस प्रकार रणनीतिक आवरण के शानदार कौशल द्वारा, पीछे हट रही कई लाख क्वोमिंताङ फौजों को धराशायी होने से बचाया ।

इसके बाद आठवीं राह सेना शत्रु की पाँतों के पीछे गहरे तक घुसपैठ करके अनेकों जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित करने में जुट गई । उनमें मुख्य इस प्रकार थे :-

1. शानशी-छाहाड़-हपे जापान-विरोधी आधार क्षेत्र :-

फिङशिङक्वान की लड़ाई के बाद 115वीं डिवीजन का एक हिस्सा ऊथाएशान क्षेत्र में

कार्यरत रहा । उस समय शानशी-छाहाड़-हपे की सीमाओं के मिलन-क्षेत्र में घोर अव्यवस्था फैली हुई थी । कभी-कभी तो, केवल मुट्ठी भर जापानी लुटेरे, जापानी झंडा उठाए, किसी एक काउंटी कस्बे पर कब्जा कर लेते थे । और क्वोमिंताङ सेनाएँ शत्रु के दिखाई देने से पहले ही दक्षिण दिशा की ओर भाग पड़ती थीं । इस स्थिति को, जो स्थानीय क्वोमिंताङ शासन-व्यवस्था के धराशायी हो जाने के फलस्वरूप पैदा हुई थी, आठवीं राह सेना ने 1937 के पतझड़ में समाप्त कर दिया तथा ऊथाएशान को केन्द्र बनाकर शानशी-छाहाड़-हपे फौजी जोन की स्थापना की । उत्तरपूर्वी सेना की एक रेजीमेंट ने आनक्वो, होच्येन, श्येनश्येन, काओयाङ तथा अन्य काउंटियों में कठपुतली शासन-व्यवस्था को कुचल दिया तथा मध्य हपे के मैदानी भूभाग में जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र की स्थापना की । 15 जनवरी, 1938 को सीमान्त-क्षेत्र के सैनिकों, कर्मचारियों तथा नागरिकों का एक सम्मेलन हपे के फूपिङ नामक स्थान पर आयोजित किया गया तथा शानशी-छाहाड़-हपे सीमान्त-क्षेत्र की प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया । आठवीं राह सेना ने, जून 1938 में, पूर्वी हपे में एक जापान-विरोधी विद्रोह का नेतृत्व कर, वहां भी एक आधार-क्षेत्र की स्थापना कर दी ।

2. शानशी-हपे-शानतुङ-हनान जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र :-

थाएय्वान के पतन के बाद जब क्वोमिंताङ सेनाएं दक्षिण की ओर पीछे हट रही थीं तब आठवीं राह सेना की 129वीं डिवीजन ने कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय संगठनों तथा नवगठित स्थानीय जापान-विरोधी सैन्य दलों के साथ तालमेल बैठाते हुए, थाएहाङ पहाड़ी इलाके को अपना केन्द्र बनाकर, थाएहाङ आधार-क्षेत्र स्थापित किया । सन् 1937 के अन्त में तथा 1938 में, 129वीं डिवीजन पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग को पार करके हपे-शानतुङ-हनान के मैदानी भू-भाग में आ गई तथा लोगों को छापामार लड़ाई के लिए संगठित करने लगी । 1939 में हपे-शानतुङ-हनान फौजी जोन की स्थापना करके, एक विशाल मैदानी भूभाग में हपे-शानतुङ-हनान आधार-क्षेत्र कायम किया गया ।

3. शानशी-स्वेय्वान जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र :-

1937 की सर्दियों में आठवीं राह सेना की 120वीं डिवीजन शानशी के उत्तर-पश्चिमी इलाके में आगे बढ़ी । फरवरी 1938 में इस डिवीजन ने ताथुङ-फूचओ रेलमार्ग के उत्तरी हिस्से का संपर्क शेष रेलमार्ग से काटने का बीड़ा उठाया ताकि थाएय्वान पर किये जा रहे उस जवाबी हमले के साथ तालमेल बैठाया जा सके, जिसे करने का क्वोमिंताङ दावा कर रही थी। जब बहुत बड़ी संख्या में शत्रु की फौजें दक्षिण में लिनफन की ओर बढ़ रही थीं, तब ताथुङ में तैनात शत्रु सैनिकों ने शानशी के उत्तर-पश्चिमी इलाके पर हमला कर दिया । ऐसी परिस्थिति में, 120वीं डिवीजन पीछे मुड़ी तथा मुकाबला किया और सात काउंटियों को शत्रु से मुक्त करा लिया । मार्च में उत्तर-पश्चिमी शानशी में जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र की स्थापना कर दी । अगस्त में डिवीजन की एक टुकड़ी उत्तरी स्वेय्वान में ताचिङ पर्वतों की ओर आगे बढ़ी तथा सितंबर में ताओलिन व अक्तूबर में ऊलानह्वा को मुक्त करा लिया ।

4. शानतुङ जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र :-

1937 के अन्त में जब शानतुङ का तत्कालीन शासक हान फू-च्वी, एक भी गोली चलाए बिना, लगातार पीछे हटता चला गया, तब कम्युनिस्ट पार्टी की शानतुङ प्रान्तीय कमेटी तथा थाएआन काउंटी कमेटी ने स्थानीय किसानों एवं पेकिङ तथा थ्येनचिन से राष्ट्रीय मुक्ति

"केवल एक ही क्रान्ति" के बेहूदा सिद्धान्त की रट लगाते हुए, दो अलग-अलग क्रान्तिकारी मंजिलों—जनवादी क्रान्ति व समाजवादी क्रान्ति—को जान-बूझकर उलझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीन जन-सिद्धान्त सभी क्रान्तियों पर लागू होते थे । यहां तक कि उन्होंने साम्यवाद के अस्तित्व तक को ही नकार दिया । यह सब कुछ प्रतिरोध युद्ध में डटी हुई जनता तथा कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने तथा लोगों के दिमागों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने हेतु किया गया, जैसा कि कट्टरपंथी चाहते थे ।

क्वोमिंताङ की जापान के साथ समझौता करने के लिए चिल्ल-पों, तथा फौजी, राजनीतिक व सैद्धान्तिक मोर्चों पर उसकी कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधियां, उस आत्मविश्वास व हर्षोल्लास की आम भावना का ही गला घोंट रही थीं जो क्वोमिंताङ-कम्युनिस्ट सहयोग के कारण युद्ध शुरू होने पर पैदा हुआ था, तथा ये सब देश को एक बार फिर से निराशा तथा दुःखों के गर्त में धकेल सकती थीं । इसके अलावा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह भी जरूरी था कि वह जनता को—युद्ध किस तरह चलाया जाना था तथा विजय-प्राप्ति के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की जानी थी—इस तरह की महत्त्वपूर्ण समस्याओं के बारे में विस्तार से समझाए । ऐसे नाजुक समय में, कामरेड माओ ने जनवरी 1940 में, **"नव-जनवाद के बारे में"** नामक एक बेहद महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक रचना लिखी । औपनिवेशिक तथा अर्ध-औपनिवेशिक क्रान्ति के लेनिनवादी सिद्धान्त की रोशनी में तथा चीन की ऐतिहासिक विशेषताओं व क्रान्तिकारी अनुभवों के आधार पर, उन्होंने चीनी क्रान्ति के बुनियादी सिद्धान्तों का विस्तृत विश्लेषण किया, तथा एक नव-जनवादी शासन-व्यवस्था के तहत राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम पेश किया।

अर्ध-सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेशिक चीन में क्रान्ति का कार्यभार साम्राज्यवादी तथा सामन्ती शासन को उखाड़ फेंकना था, न कि सामान्यतः पूँजीवाद को खत्म करना । इस कारण चीनी क्रान्ति में दो कदम उठाने जरूरी थे । पहला कदम था—एक अर्ध-सामंती तथा अर्ध-औपनिवेशिक समाज को एक स्वतन्त्र जनवादी समाज में बदलना । दूसरा कदम था—क्रान्ति का विकास करना तथा एक समाजवादी समाज की स्थापना करना ।

यद्यपि अपने सामाजिक चरित्र में चीनी क्रान्ति की प्रथम मंजिल अभी भी बुनियादी तौर पर पूँजीवादी-जनवादी थी, पर यह पुरानी तरह की क्रान्ति की श्रेणी में नहीं आती थी जिसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग ने पूँजीवादी तानाशाही के तहत पूँजीवादी समाज तथा शासन-व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया था । बल्कि यह एक नए किस्म की क्रान्ति थी जिसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथ में था तथा जिसका उद्देश्य सभी क्रान्तिकारी वर्गों के सांझे अधिनायकत्व में, सबसे पहले एक नव-जनवादी समाज तथा शासन-व्यवस्था की स्थापना करना था ।

यद्यपि क्रान्ति की वस्तुगत मांग पूँजीवाद के विकास के लिए रास्ता साफ करना था, पर इसने समाजवाद की विजय के लिए हालात पैदा करने का काम किया । जहां तक क्रान्तिकारी मोर्चे की बात थी, यह क्रान्ति पुरानी पूँजीवादी-जनवादी विश्व-क्रान्ति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि नई सर्वहारा-जनवादी विश्व-क्रान्ति का हिस्सा थी ।

फलतः जनवादी क्रान्ति संपन्न होने पर चीन को, समाजवादी तत्वों—देश के राजनीतिक पटल पर सर्वहारा तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में राजकीय स्वामित्व वाले तथा सहकारी क्षेत्रों का विस्तार तथा अनुकूल विश्व परिस्थिति—के निरंतर

च्याङ के गुप्त आदेशों का पालन करते हुए, प्रतिक्रियावादियों ने सभी जगह गड़बड़ पैदा कर दी । अप्रैल 1939 में क्वोमिंताङ फौजों ने पोशान में आठवीं राह सेना के शानतुङ कालम पर हमला कर दिया । अप्रैल तथा मई में क्वोमिंताङ फौजों ने हपे प्रान्त की शनश्येन काउंटी में पृष्ठभागीय संस्थानों पर भी हमले किये जबकि अन्यों (27वीं ग्रुप सेना) ने हुनान प्रान्त के फिङच्याङ में स्थित नई चौथी सेना के सम्पर्क कार्यालय पर धावा बोल दिया । सितंबर में, क्वोमिंताङ सैनिकों ने, हुपे में नई चौथी सेना के पृष्ठभागीय संस्थानों को घेर लिया तथा नवम्बर में क्वोमिंताङ के गुप्त एजेन्टों ने हनान प्रान्त की छ्वेशान काउंटी के चूकओचन स्थान में नई चौथी सेना के पृष्ठभागीय सेवा कार्यालय पर हमला किया ।

दिसंबर 1939 से मार्च 1940 तक की कालावधि में, क्वोमिंताङ के कट्टरपंथियों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध शुरू किया गया राजनीतिक दमन तथा फौजी हमला, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था । इसे **पहली कम्युनिस्ट विरोधी मुहिम** के रूप में जाना गया।

इस कम्युनिस्ट विरोधी मुहिम के मुख्य निशाने शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र तथा शानशी के पश्चिमी व दक्षिण-पूर्वी हिस्से थे । दिसंबर 1939 में च्याङ काई-शेक ने शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र की घेराबन्दी किए पड़ी, क्वोमिंताङ सेनाओं को हमला करने का आदेश दिया । उन्होंने पाँच काउंटियों पर कब्जा कर लिया । पश्चिमी शानशी में क्वोमिंताङ युद्ध-सरदार येन शी-शान ने छः फौजी कोरों को केन्द्रित करके **''मौत से न डरने वाली जापान-विरोधी पलटन ''**[10] तथा **''शानशी प्रान्त की राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए आत्म-बलिदानी लीग''**[11] पर हमला कर दिया । 1940 के बसन्त में च्याङ काई-शेक ने अपनी सेना को, थाएहाङ पर्वतीय इलाके में स्थित आठवीं राह सेना के जनरल मुख्यालय पर हमला करने का आदेश दिया ।

जुलाई 1939 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने नारा दिया : *''प्रतिरोध में डटे रहो तथा आत्मसमर्पण का विरोध करो!, एकता पर डटे रहो तथा फूट का विरोध करो!, प्रगति पर डटे रहो तथा प्रतिगामिता का विरोध करो !''* पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्र ने क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी तथा समझौतेपरस्त रुझान के विरुद्ध डट कर लोहा लिया । *''जब तक हम पर हमला नहीं किया जाता, हम कभी हमला नहीं करेंगे ; यदि हम पर हमला किया गया, तो हम निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देंगे ।''* इस कथन में अन्तर्निहित आत्मरक्षा के दृढ़ सिद्धान्त का पालन करते हुए, पार्टी ने प्रतिक्रियावादियों के हमलों के जवाब में उनकी जमकर धुनाई की । शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र पर हमला करने वाली क्वोमिंताङ की कम्युनिस्ट विरोधी सैन्य-शक्तियों को तितर-बितर कर दिया गया । येन शी-शान की फौज को भारी क्षति पहुँचाने के बाद जन-सेना, शानशी के उत्तर-पश्चिम में स्थानान्तरण कर गई । थाएहाङ पर्वतीय क्षेत्र में क्वोमिंताङ की तीन डिवीजनों को निष्क्रिय कर दिया गया । इस प्रकार सभी मोर्चों पर जुझारू जवाबी हमलों के सामने कम्युनिस्ट विरोधी सेनाएं धराशायी हो गईं ।

पहले कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह के दौरान क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों का हमला केवल राजनीतिक तथा फौजी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे सैद्धान्तिक मोर्चे पर भी शुरू कर दिया था । उन्होंने **कमालवाद (Kemalism)**[12] (पूँजीवादी तानाशाही) का ढिंढोरा पीटा तथा इस तरह क्वोमिंताङ शासन व्यवस्था के असली चेहरे पर पर्दा डालने की कोशिश की, जो कि केवल बड़े पूँजीपतियों की तानाशाही के सिवाय और कुछ नहीं थी । उन्होंने

आन्दोलन में शामिल हुए छात्रों को संगठित किया तथा छुलाए पर्वतों में जापान-विरोधी विद्रोह का डंका बजा दिया । 1938 की पतझड़ तक शानतुङ कालम में बढ़कर नौ दस्ते हो गये तथा उसने शानतुङ प्रायद्वीप के ह्वाश्येन, फङलाए तथा येश्येन क्षेत्रों में एक छापामार इलाके की स्थापना कर डाली। ल्याओछङ के स्थानीय पार्टी संगठन ने एक स्थानीय जन नेता फान च्ची-श्येन को शानतुङ प्रान्त के उत्तर-पश्चिमी इलाके में जापान-विरोधी कार्यवाहियां आरंभ करने में मदद दी ।

5. मध्यचीन जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र :-

दक्षिण की लाल छापामार यूनिटों को पुनर्गठित कर बनाई गई नई चौथी सेना ने जनवरी 1938 में नानछाङ में अपना मुख्यालय स्थापित किया । बाद में यह सेना दो रास्तों से मध्य चीन में शत्रु की पांतों के पीछे घुस गई : एक टुकड़ी याङत्सी नदी के दक्षिण की ओर से तथा दूसरी उत्तर की ओर से । दक्षिणी टुकड़ी जून 1938 में नानकिङ-शंघाई रेलमार्ग तक पहुंच गयी तथा दक्षिणी च्याङसू मुक्त क्षेत्र स्थापित किया जिसका केन्द्र माओशान का पहाड़ी इलाका था। उत्तरी टुकड़ी मई 1938 में आनह्वेइ प्रान्त के छाओ हू, ऊवेइ तथा थिङच्वान क्षेत्र में दाखिल हो गई तथा ऊथाङ को केन्द्र बनाकर, एक मुक्त क्षेत्र स्थापित कर दिया । ●

4.

- **राष्ट्रीय आत्मसमर्पणकारियों तथा तुरत-फुरत विजय के पैरोकारों का शोर शराबा ।**
- **चीनी-जापानी युद्ध के विकास को लेकर कामरेड माओ त्से-तुङ की दूरदर्शिता।**

मई 1938 तक, जापान-विरोधी युद्ध को चलते दस महीने हो गए थे, चीनी जनता युद्ध की मुसीबतों को झेल रही थी तथा अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने हेतु युद्धरत थी और विजय के दिन का इन्तजार कर रही थी । परन्तु लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी ? क्या चीनी जनता इसे जीत सकती थी ? उसे विजय प्राप्ति के लिए किस तरह संघर्ष करना चाहिये ? ये कुछ ऐसे प्रश्न थे, जिनके जवाब अनेक लोगों के लिए नदारद थे । युद्ध आरंभ होने से पहले तथा बाद में, क्वोमिंताङ के अनेक लोगों ने गला फाड़-फाड़कर चीन के अवश्यम्भावी आत्मसमर्पण की घोषणा की थी । वास्तव में, इस नीति की आड़ में ही लूकओछ्याओ काण्ड से पहले तक, क्वोमिंताङ जापान का प्रतिरोध करने से इंकार करती रही थी । परन्तु जब इस काण्ड ने च्याङ काई-शेक गुट को युद्ध करने पर विवश कर दिया तो वाङ चिङ-वेइ का गुट, जो इस नीति का भोंपू था, आत्मसमर्पण की तैयारी करने लगा । इसके अतिरिक्त युद्ध के आरंभिक चरणों में क्वोमिंताङ सेनाओं की बार-बार की पराजयों ने जनता के एक हिस्से में निराशा व हताशा को जन्म दिया ।

दूसरी ओर, युद्ध छिड़ने के बाद, तुरत-फुरत विजय की एक पूर्णतया आधारहीन व बेहद आशावादी हवाई धारणा का प्रचार किया गया । कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों ने शत्रु की शक्ति को कम करके आँका तथा क्वोमिंताङ की शक्ति और युद्ध में उसकी भूमिका को वास्तविकता से कहीं ज्यादा करके आँका । उन्होंने क्वोमिंताङ के केवल एक ही पहलू की

ओर ध्यान दिया कि वह प्रतिरोध कर रही थी । लेकिन उसके भ्रष्ट तथा प्रतिक्रियावादी होने के दूसरे पहलू को नजरअन्दाज कर दिया । उनका मानना था कि चीन पूर्णतया क्वोमिंताङ पर निर्भर रहकर तुरन्त विजय प्राप्त कर सकता था । और जहां तक च्याङ काई-शेक गुट का सवाल था उसने अपनी सारी आशाएं विदेशी मदद पर टिकाए रखीं, तथा यह सोचकर कि ब्रिटेन व अमरीका उसके लिए जापान से युद्ध करेंगे, और वह चीन में अपना प्रतिक्रियावादी शासन चलाता रहेगा, लगातार युद्ध से पीछे हटता रहा । जैसा कि क्वोमिंताङ के **राजनीति विज्ञान गुप**[2] के मुखपत्र *ता कुङ पाओ* में प्रस्तुत किया गया था, क्वोमिंताङ में बहुत से लोगों का यह अवसरवादी मत था कि मार्च 1938 में लड़ी गई थाएअड़च्वाङ तथा सूचओ की लड़ाइयां जापान के विरुद्ध चीनी प्रत्याक्रमण की शुरुआत थीं ।

इन पूर्णतया गलत धारणाओं का खण्डन करने के लिए तथा समूचे राष्ट्र को युद्ध के वास्तविक हालात के बारे में बताने के लिए कामरेड माओ त्से-तुङ ने मई 1938 में **'दीर्घकालीन युद्ध के बारे में'** नामक पुस्तिका लिखी । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद की रोशनी में, चीन तथा जापान की तुलनात्मक ताकत का विस्तार से वस्तुगत विश्लेषण करते हुए, उन्होंने जापान-विरोधी युद्ध के स्थिति-निर्धारण तथा संभावना (Orientation and Prospect) के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किये :

प्रथम, असल में न तो चीन की राष्ट्रीय गुलामी के सिद्धान्त का कोई आधार था, और न ही चीन की शीघ्र विजय के सिद्धान्त का । घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों का विश्लेषण करते हुए कामरेड माओ ने निष्कर्ष निकाला कि जापान-विरोधी युद्ध एक दीर्घकालीन युद्ध होगा (तुरन्त विजय के सिद्धान्त के विपरीत), लेकिन अन्तिम विजय चीनी जनता की ही होगी (राष्ट्रीय गुलामी के सिद्धान्त के विपरीत) । इस तरह के मत का आधार क्या था ? उन्होंने कहा :

चीन-जापान युद्ध अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती चीन तथा साम्राज्यवादी जापान के बीच बीसवीं सदी के चौथे दशक में चल रहे जीवन-मरण के युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है । इसी में पूरी समस्या का आधार निहित है ।[3]

इस आधार से युद्धरत पार्टियों के बीच चार विरोधी तथ्य उठ खड़े हुए : जापान शक्तिशाली देश था, लेकिन छोटा था, पतनोन्मुख था तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं था ; दूसरी तरफ, चीन एक कमजोर देश था लेकिन वह विशाल व प्रगतिशील था तथा उसे प्रचुर मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त था । इन चार तथ्यों में से, केवल एक जापान के पक्ष में था कि वह शक्तिशाली था और चीन कमजोर था । इसका मतलब था कि युद्ध अवश्यम्भावी था तथा प्रतिरोध युद्ध में चीन को घोर कठिनाई के दौर से गुजरना था तथा इस युद्ध ने एक शीघ्र निर्णय वाला युद्ध न होकर, एक दीर्घकालीन युद्ध होना था । इस तथ्य को भूलना या दरकिनार करना तथा केवल दूसरे तीनों तथ्यों के बारे में विचार करना या उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना गलत होता, जैसा कि "शीघ्र विजय" के सिद्धान्त के अनुयायियों ने किया था ।

जहाँ तक दूसरे तीन विरोधी तथ्यों का सवाल था, संभावनाएँ स्पष्टत: चीनी प्रतिरोध के अनुकूल तथा जापानी हमले के प्रतिकूल थीं । सबसे पहले तो यही बात जापान के प्रतिकूल था कि उसने एक छोटा सा देश होते हुए, चीन जैसे बड़े देश पर हमला किया था । लेकिन केवल इतना होने भर से ही चीन गुलामी से नहीं बच सकता था, क्योंकि इतिहास गवाह है

काई-शेक ने अंतिम सांस तक मुकाबला करने के अपने इरादे की घोषणा की । लेकिन "अंतिम" से उसका मतलब लूकओछ्याओ घटना से पहले की स्थिति फिर से बहाल करने से अधिक और कुछ न था । च्याङ काई-शेक गुट आत्मसमर्पण करने के लिए तथा गद्दार बनने के लिए तैयार था, बशर्ते जापान "चार बड़े घरानों" तथा अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के हितों तथा प्रभुत्व को मध्य तथा दक्षिणी चीन में अक्षुण्ण बनाए रखे । सितम्बर 1939 में क्वोमिंताङ सरकार के विदेश मन्त्री, वाङ छुङ-ह्वेइ ने घोषणा की : *"युद्ध छिड़ने के समय से ही चीन ने शांतिपूर्ण समझौते की किसी भी संभावना को अस्वीकार नहीं किया है"*—दूसरे शब्दों में, क्वोमिंताङ सरकार ने समझौते तथा आत्मसमर्पण की अपनी गतिविधियों को कभी भी बन्द नहीं किया था ।

आत्मसमर्पण का रास्ता साफ करने के लिए च्याङ काई-शेक गुट ने अपनी शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनता का विरोध करने पर केन्द्रित कर दी, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके नेतृत्व में जनता की जापान-विरोधी सेनाएं अत्यधिक दृढ़ता से समझौते तथा आत्मसमर्पण का विरोध कर रही थीं । कट्टरपंथियों ने कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध भड़काने का प्रयास किया क्योंकि इससे प्रतिरोध युद्ध का अवश्यम्भावी रूप से अंत हो जाना था । तथा जापान के साथ आत्मसमर्पणकारी संधि करने के उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जानी थी ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए च्याङ गुट ने अपनी कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधियां तेज कर दीं । सबसे पहले क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी के कई सम्मेलनों में लगातार बहुत से कम्युनिस्ट-विरोधी तथा जन-विरोधी प्रस्ताव पास किए गए, जैसे कि : *"कम्युनिस्ट समस्या से निपटने के लिए उपाय"*, *"शत्रु के अधिकार वाले क्षेत्रों में कम्युनिस्टों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए ड्राफ्ट योजना,"* *"दुश्मन-पार्टियों (Alien-Party) की समस्या से निपटने के उपाय,"* तथा *"दुश्मन-पार्टियों की समस्या से निपटने के लिए निर्देश"* आदि-आदि। इसके साथ ही आधार-क्षेत्रों पर फौजी हमला करने का भी फैसला किया गया।

क्वोमिंताङ कट्टरपथिंयों ने शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र तथा उत्तरी चीन के आधार-क्षेत्रों के सभी जापान-विरोधी फौजी व नागरिक संगठनों को भंग करने का प्रयास किया। इन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट-विरोधी अड्डे स्थापित करने व **पाओ-च्या**[4] प्रणाली लागू करने की भी कोशिश की । उनका उद्देश्य राजनीतिक, फौजी तथा आर्थिक मामलों में, तथा साथ ही जन-आंदोलनों व प्रचार-प्रसार में पार्टी की अगुवाई में काम करने वाली जनता की जापान विरोधी ताकतों पर रोक लगाना, तोड़फोड़ करना एवं उन्हें नेस्तनाबूद करना था । ऐसा वे समूचे देश में करना चाहते थे, पर सबसे पहला निशाना उत्तरी शेनशी व उत्तरी चीन थे ।

यह प्रतिक्रियावादी योजना जल्दी ही अमल में आ गई । शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र की घेराबन्दी कर दी गई । आठवीं राह सेना को छाङश्येन-शच्याच्वाङ व चङतिङ-थाएय्वान रेलमार्गों के उत्तर की ओर वाले क्षेत्र में पीछे हटने का आदेश दिया गया । इसके साथ ही शानशी के आधार-क्षेत्रों में से एक पर उत्तर की तरफ हमला करने के लिए क्वोमिंताङ की विशाल सैन्य-शक्ति को केन्द्रित किया गया । इस फौजी चालबाजी का उद्देश्य जापानी सेना द्वारा चाङच्याखओ-पेकिङ रेलमार्ग पर जनता की सशस्त्र सेनाओं का 'सफाया' करने के लिए चलाए जा रहे दक्षिणाभिमुख सैनिक अभियान के साथ तालमेल स्थापित करना था । 1938 के पतझड़ में, च्याङ काई-शेक ने दक्षिण हपे प्रशासनिक कार्यालय को बंद करने का आदेश दिया।

तथा बेल्जियम (ये सभी देश ऐसे थे, जिन्हें बचाने में ब्रिटेन तथा फ्रांस दिलचस्पी रखते थे) की रक्षा करने का बीड़ा उठाए, लेकिन खुद उन्होंने सोवियत-संघ के पड़ोसी देशों जैसे लातविया, एस्तोनिया तथा फिनलैण्ड के लिए ऐसा ही करने से इन्कार कर दिया । वे केवल अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहते थे, परन्तु सोवियत-संघ की उन्हें कोई परवाह न थी । अतः, जैसा कि स्वाभाविक था बातचीत विफल हो गई ।

सोवियत-संघ के साथ वार्ता करते हुए, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सरकारों ने नाजी जर्मनी के साथ राजनयिक वार्ताएं करना भी जारी रखा । वे जर्मनी के साथ समस्त विश्व के प्रभाव क्षेत्रों के पुनर्बंटवारे के लिए किसी समझौते पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे । ऐसे किसी समझौते के सफल होने की दशा में, ब्रिटेन ने पोलैण्ड की सुरक्षा की गारंटी से इन्कार कर देना था, तथा इस प्रकार जर्मन हमला पूर्व की ओर मुड़ जाना था । ऐसी परिस्थितियों में सोवियत-संघ को अपने खिलाफ षड्यन्त्रपूर्ण ढंग से रचे गये युद्ध में फंसने के खतरे से स्वयं की रक्षा करनी थी । इसलिए एक जर्मन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसने 23 अगस्त, 1939 को जर्मनी के साथ एक द्विपक्षीय अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तथा इस प्रकार 21 जून, 1941 तक अपने लिए लगभग दो साल का शान्तिपूर्ण समय प्राप्त कर लिया ।

1 सितम्बर, 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद फ्रांस व ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया।

यूरोप में गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों ने **"सुदूर पूर्व का म्यूनिख"** रच डालने का कुचक्र चलाया । जून 1939 में उन्होंने **"प्रशान्त महासागर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन"** आयोजित करने का प्रस्ताव रखा । जैसा कि म्यूनिख में फ्रांस तथा ब्रिटेन ने चेकोस्लोवाकिया तथा सोवियत-संघ की जनता की कीमत पर जर्मनी द्वारा सूदेतन पर किए गए कब्जे को मान्यता देकर जर्मनी तथा इटली से समझौता किया था, ठीक उसी प्रकार प्रशान्त महासागर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस चीनी जनता की कीमत पर जापान से समझौता करना चाहते थे तथा जापानी साम्राज्यवाद के भाले की नोंक सोवियत-संघ की ओर मोड़ना चाहते थे । (और इस षड्यन्त्र को लोगों ने सुदूर-पूर्व के म्यूनिख षड्यन्त्र का नाम दिया था—अनुवादक ।)

जब एक ओर ब्रिटेन व फ्रांस तथा दूसरी ओर जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया, तब अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस जापान के साथ समझौता करने को व्यग्र थे, ताकि वे अपनी सेनाओं को जर्मनी के विरुद्ध केन्द्रित कर सकें। फलतः उन्होंने चीन सरकार पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला।

इन हालातों में क्वोमिंताङ का जापान-परस्त वाङ चिङ-वेइ गुट सबसे पहले खुल्लम-खुल्ला शत्रु के पक्ष में चला गया । 18 दिसंबर, 1938 को वाङ चिङ-वेइ छुङकिङ से भाग गया तथा हनोई में कोनोई के विचारों का समर्थन करते हुए एक वक्तव्य जारी किया । इसके थोड़े समय बाद उसने नानकिङ में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की । इस प्रकार वाङ चिङ-वेइ गुट, जो चीन के बड़े-पूँजीपतियों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था, खुल्लम-खुल्ला गद्दारी पर उतर आया तथा चीनी जनता का शत्रु बन गया ।

इसी दौरान क्वोमिंताङ का च्याङ काई-शेक गुट भी, जो अमरीका-परस्त बड़े पूँजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता था, आत्मसमर्पण के लिए तैयार खड़ा था ।

जनवरी 1939 में, क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग में, च्याङ

कि कभी-कभी एक छोटा किन्तु शक्तिशाली देश भी एक बड़े लेकिन बेहद कमजोर देश को जीत सकता है जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को जीता था । पर इस युग की विशिष्टताओं (जब साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ आजादी के लिए जनता के संघर्ष अपने चरम पर थे) के कारण चीन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, तथा जब तक वह आखिरी क्षण तक सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के अपने संकल्प पर डटा रहता, तब तक अंतिम विजय उसी की होनी निश्चित थी । इन विशिष्टताओं की झलक जापान के प्रतिगामी स्वरूप व उसे समर्थन के अभाव में, एवम् चीन की प्रगति व उसे समर्थन के बाहुल्य में दिखाई देती थी । चीन के विरुद्ध जापान का युद्ध, एक प्रतिक्रियावादी, बर्बरतापूर्ण तथा आक्रमणकारी युद्ध था, जबकि चीनी प्रतिरोध युद्ध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रांति के लिए लड़ा जा रहा, एक न्यायसंगत तथा प्रगतिशील युद्ध था । चीन के विरुद्ध जापान द्वारा छेड़े गए युद्ध की अन्यायपूर्ण तथा लुटेरी प्रकृति ने जापान के विभिन्न वर्गों के बीच, जापानी तथा चीनी जनता के बीच, तथा जापान एवम् विश्व के अधिकांश देशों के बीच अत्यधिक प्रचण्ड विरोध पैदा करना था तथा इस सब की परिणति जापान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव में होनी थी । दूसरी ओर, प्रतिरोध युद्ध की न्यायसंगत तथा प्रगतिशील प्रकृति के कारण, चीन समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँध सकता था तथा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर सकता था, खासतौर से सोवियत संघ से । जापान की ताकत को तथा चीन की कमजोरी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, जैसा कि राष्ट्रीय गुलामी के पैरोकारों ने किया था, बिल्कुल गलत था ।

जहाँ तक दीर्घकालीन युद्ध की प्रगति सवाल था, कामरेड माओ त्से-तुङ का मानना था कि चीनी प्रतिरोध-युद्ध ने तीन मंजिलों से गुजरना था : रणनीतिक रक्षा, रणनीतिक ठहराव तथा रणनीतिक प्रत्याक्रमण ।

पहली मंजिल, शत्रु के रणनीतिक आक्रमण तथा चीन की रणनीतिक रक्षा की मंजिल होनी थी । इस मंजिल में, चीन में युद्ध का मुख्य रूप चलायमान लड़ाई ही होना चाहिए था, तथा इसे छापेमार तथा मोर्चेबद्ध लड़ाई द्वारा सहायता दी जानी थी । शत्रु की पाँतों के पीछे छापामार लड़ाई को वरीयता मिलनी थी, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में चलायमान लड़ाई को नकार कर नहीं ।

दूसरी मंजिल, रणनीतिक ठहराव की मंजिल होनी थी । शत्रु ने रणनीतिक आक्रमण को बन्द करके अपने अधिकृत प्रदेशों की रक्षा करनी थी तथा इसके लिए एकीकृत कठपुतली शासन की व्यवस्था करनी थी । लेकिन साथ में उसे व्यापक पैमाने पर फैले जोरदार छापामार युद्ध का सामना भी करना था । इस मंजिल में चीन की लड़ाई का मुख्य रूप छापामार लड़ाई होना था तथा इसे चलायमान व मोर्चेबद्ध युद्ध द्वारा सहायता दी जानी थी । मुख्य कार्यभार जवाबी आक्रमण के लिए भरपूर तैयारियां करना था । चीन के लिए यह मंजिल अत्यन्त कष्टदायी दौर की होनी थी, लेकिन यही मंजिल परिवर्तन की धुरी भी होनी थी ।

तीसरी मंजिल, चीन के रणनीतिक प्रत्याक्रमण की मंजिल होनी थी । चीन को मुख्यतः अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना था, उस शक्ति पर, जिसका पिछली मंजिल में पोषण हुआ था तथा इस मंजिल में बढ़ना जारी था । चीन को अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने तथा शत्रु देश में परिवर्तनों से लाभ उठाने का प्रयास करना था । लड़ाई का मुख्य रूप चलायमान युद्ध होना था, लेकिन मोर्चेबद्ध युद्ध की भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी थी । तीसरी मंजिल

दीर्घकालीन युद्ध की अन्तिम मंजिल होनी थी, तथा अंत तक लड़ने का अर्थ था इन सभी मंजिलों से गुजरना ।

दूसरे, पहली समस्या से संबंधित दो अन्य समस्याएँ भी थीं, जो कि और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण थीं । ये समस्याएँ थीं : युद्ध में नेतृत्व की भूमिका तथा घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों में संभाव्य परिवर्तन ।

फौजी ताकत में बरतरी या कमतरी, पहलकदमी या निष्क्रियता का वस्तुगत आधार होती है, लेकिन यह अपने आप में समस्या का हल नहीं कर सकती । पहलकदमी या निष्क्रियता के एक वास्तविकता बनने से पहले दोनों पक्षों में एक संघर्ष होना चाहिए तथा युद्ध-संचालन की क्षमता का मुकाबला होना चाहिए । सही युद्ध-संचालन कमतरी को बरतरी तथा निष्क्रियता को पहलकदमी में बदल सकता है तथा गलत युद्ध-संचालन इसके एकदम उलट साबित हो सकता है ।

ताकत व कमजोरी के बीच का अन्तर, तथा बरतरी व कमतरी के बीच का अन्तर सापेक्ष (तुलनात्मक) था, निरपेक्ष नहीं । यह भी सच है कि यह अन्तर जो चार बुनियादी विरोधी तथ्यों में से एक था, एक यथार्थ तथ्य था तथा इसी के बलबूते पर शत्रु चीन की धरती पर हमला करने व घुसने में सक्षम हुआ था । शत्रु हमला करने की स्थिति में था जबकि चीन रक्षात्मक स्थिति में था। जहाँ तक अन्य तीन विरोधी तथ्यों का सवाल था (यानि कि विशालता बनाम लघुता, प्रगतिशीलता बनाम प्रतिगामिता तथा समर्थन का बाहुल्य बनाम समर्थन का अभाव) ये तथ्य या तो प्रारंभिक अवस्था में थे या फिर अभी प्रकट नहीं हुए थे । धारा का रुख मोड़ने के लिए, शत्रु की बढ़ती को रोकने के लिए तथा अंतिम जवाबी-आक्रमण की तैयारी के लिए ; शत्रु को मुँहतोड़ जवाब देना, तथा चीन के अनुकूल परिस्थितियों को प्रारंभिक अवस्था से प्रधानता की अवस्था में, तथा संभाव्यता से वास्तविकता की अवस्था में बदलना जरूरी था। और यह सब नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करना था जैसा कि कामरेड माओ त्से-तुङ ने स्पष्ट किया :

जो लोग युद्ध का संचालन करते हैं, वे विजय प्राप्त करने की कोशिश में वस्तुगत परिस्थितियों द्वारा निर्धारित सीमाओं को लांघ नहीं सकते, लेकिन इन सीमाओं के भीतर रहते हुए वे अपनी जागरूक क्रियाशीलता द्वारा विजय के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए ।[4]

शत्रु के शक्तिशाली होने तथा चीन के कमजोर होने के कारण, शत्रु की रणनीति हमला करने, तुरन्त निर्णय तथा बाहरी सैन्य-पंक्ति वाली फौजी कार्यवाहियां करने की थी जबकि चीन की रणनीति रक्षात्मक, दीर्घकालीन युद्ध तथा भीतरी सैन्य-पंक्ति वाली फौजी कार्यवाहियों की थी । लेकिन जापान चूंकि एक छोटा देश था, उसके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक भी नहीं थे और उसने चीन जैसे विशाल देश पर, जिस की सेनाएँ उससे बड़ी थीं, आक्रमण करने का दुस्साहस किया था । अतः वह चीन का केवल एक हिस्सा ही अपने कब्जे में रख सकता था तथा अधिकृत प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी वह अपनी रक्षक सेना तैनात नहीं कर सकता था और इस प्रकार चीन के पास चलायमान व छापामार-युद्ध की कार्यवाहियां करने के लिए एक विशाल क्षेत्र सुलभ हो जाता था तथा इस प्रकार मुहिमों तथा लड़ाइयों में तुरन्त निर्णय की बाहरी सैन्य-पंक्ति वाली कार्यवाहियां करने की पहलकदमी चीन के हाथ आ सकती थी, जबकि शत्रु

प्रमुख सैन्य-शक्तियों का रुख अपने पृष्ठभाग के युद्ध मोर्चों की ओर मोड़ दिया, और क्वोमिंताङ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपना रणनीतिक हमला रोक दिया । क्वोमिंताङ के प्रति शत्रु की नीति अब मुख्य रूप से राजनीतिक उपायों द्वारा उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करने की हो गई थी तथा सैनिक हमले गौण हो गए थे ।

दिसम्बर 1938 में जापानी प्रधानमन्त्री कोनोई ने चीन के प्रति जापान की मूल नीति से संबंधित एक वक्तव्य जारी किया । इस नीति का उद्देश्य चीन को अपना गुलाम बनाना था । जिस "चीन-जापान आर्थिक सहयोग" का हवाला उसने अपने वक्तव्य में दिया था, आगे चलकर उसने इसकी व्याख्या इस प्रकार की : मध्य तथा दक्षिणी चीन में कुल पूँजी-निवेश का 51 प्रतिशत चीनी पूँजीपतियों द्वारा किया जाना था तथा 49 प्रतिशत जापानियों द्वारा; जबकि उत्तरी चीन में इस अनुपात को उलटा कर देना था । कुछ आर्थिक रियायतों का चारा डालकर, चीन के जापान-विरोधी खेमे को विभाजित करने का यह जापानी षड्यन्त्र था तथा इसके द्वारा वह चीन को गुलाम बनाने के अपने मन्सूबे को पूरा करना चाहता था ।

कोनोई मन्त्रीमण्डल के गिरने के बाद नए प्रधानमन्त्री, कीचिरो हिरानुमा ने मार्च 1939 में घोषणा की कि जापान चीन के साथ शत्रुता समाप्त करने के लिए बातचीत करने को तैयार था, बशर्ते की क्वोमिंताङ सरकार जापान के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करे तथा उसके साथ सहयोग करे । इस सार्वजनिक वक्तव्य में जापानी सरकार ने स्पष्ट किया कि अब उसकी नीति च्याङ काई-शेक के त्याग-पत्र पर जोर देने की बजाय उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने की थी ।

3. क्वोमिंताङ सरकार को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने के ब्रिटेन तथा अमरीका के षड्यन्त्र :-

अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा यूरोप में अपनाई गई "हस्तक्षेप न करने" की नीति का सारांश था—अपने लाभ के लिए आक्रमणकारी युद्ध को अनदेखी करने की नीति । लेकिन फासीवादी देशों के लालच की कोई सीमा न थी । स्पेन पहला देश था, जो इस नीति की बलि चढ़ा; उसके बाद आस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया की बारी आई । वास्तव में अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के लिए इस नीति पर चलने का परिणाम *"अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने"* के समान था, इससे उन्हें खुद भी नुकसान होता था तथा साथ ही दूसरों को भी क्षति होती थी।

मार्च 1938 में आस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के सूदेतन क्षेत्र पर अपना दावा ठोंका । फ्रांस तथा चेकोस्लोवाकिया ने आक्रमण का सामूहिक मुकाबला करने के सोवियत-संघ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया । 30 सितम्बर, 1938 को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा चेकोस्लोवाकिया को, सूदेतन जर्मनी को सौंपने के लिए विवश होना पड़ा।

15 मार्च, 1939 को जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया तथा पूर्व में और आगे बढ़कर पोलैण्ड में दाखिल होने के नजदीक पहुंच गया । इस नाजुक दौर में सोवियत-संघ ने, फासीवादी शक्तियों द्वारा धमकाए गए देशों की संयुक्त सुरक्षा के लिए, फ्रांस तथा ब्रिटेन के सामने एक त्रिपक्षीय संधि का प्रस्ताव रखा ।

इन तीनों शक्तियों के बीच मार्च से अगस्त 1939 तक बातचीत चलती रही । बरतानवी तथा फ्रांसीसी सरकारों ने सोवियत-संघ के साथ समानता के आधार पर संधि करने में अपनी अनिच्छा जतलाई । उन्होंने माँग की कि सोवियत-संघ पोलैण्ड, रूमानिया, तुर्की, यूनान (ग्रीस)

सशस्त्र शक्तियाँ ही थीं, जिन्होंने जापानी साम्राज्यवादियों पर अंकुश लगाए रखा । दूसरे शब्दों में, आधार-क्षेत्र प्रतिरोध का केन्द्र थे तथा जन-सेना इसकी मुख्य शक्ति थी ।

जन-सेना ने शत्रु के अनेक ''सफाया'' अभियानों तथा घेराबन्दी मुहिमों को बहादुरी के साथ चकनाचूर कर दिया । इन विजयों से आधार-क्षेत्रों का निरन्तर विकास हुआ ।

सितम्बर से नवम्बर 1939 तक, जन-सेना ने, शानशी-छाहाड़-हपे सीमान्त क्षेत्र की शत्रु के 50,000 सैनिकों द्वारा की गई घेराबन्दी को ध्वस्त किया ।

सबसे बड़ी कार्यवाही सौ रेजिमेन्टों की फौजी मुहिम थी, जो अगस्त से दिसम्बर 1940 तक साढ़े तीन महीने चली । जन-सेना की 115 रेजिमेन्टों ने, जिन की सैनिक संख्या 4,00,000 थी, इसमें भाग लिया ।

इस मुहिम के पहले चरण में, जन-सेना का उद्देश्य, शत्रु की परिवहन-पंक्तियों को नष्ट करना था । उत्तरी चीन में सभी रेलमार्गों को हमले का निशाना बनाया गया तथा चङतिङ-थाएय्वान रेलमार्ग को मुख्य निशाना बनाया गया । दूसरे चरण का उद्देश्य, शत्रु के मजबूत ठिकानों पर हमला करना था, तथा मुख्य निशाना रेलमार्गों के साथ-साथ आधार-क्षेत्रों में उसके ठिकाने थे। तीसरे चरण में जन-सेना ने शत्रु की ''सफाया'' मुहिम पर जवाबी हमला किया तथा थाएहाङ पहाड़, उत्तर-पश्चिमी शेनशी, शेनशी-छाहाड़-हपे, मध्य हपे तथा ताचिङ पहाड़ों के इन पाँच आधार-क्षेत्रों में शत्रु की सेनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया ।

इस सैनिक कार्यवाही के तीन मुख्य परिणाम निकले । आधार-क्षेत्रों को विभाजित करने व घेरने की शत्रु की नीति को विफल कर दिया गया, बहुत बड़ी संख्या में शत्रु के सैन्य-बल को जकड़ लिया गया तथा मुख्य मोर्चे पर हमला करने से रोक दिया गया, तथा कट्टरपंथियों के समझौता करने तथा आत्मसमर्पण करने के षड्यन्त्रों को तहस-नहस कर दिया गया । जन-सेना द्वारा प्रदर्शित प्रचंड शक्ति से शत्रु अत्यधिक भयभीत हो गया । तब जापान ने अपनी हमले की योजनाओं में व्यापक फेर-बदल किया तथा अपनी सारी शक्तियों को उत्तरी चीन में आधार-क्षेत्रों के खिलाफ केन्द्रित कर दिया तथा उनके विरुद्ध सैनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मोर्चों पर सम्पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया ।

युद्ध के आरंभ से ही क्वोमिंताङ की आँखें, जापान की मदद से, कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनता की सैन्य-शक्तियों को कमजोर व नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई थीं । लेकिन उसकी आशा के विपरीत, जनता की सैन्य-शक्तियों का निरन्तर विकास होता चला गया । मुक्त-क्षेत्रों में प्राप्त विजयों के ठीक विपरीत क्वोमिंताङ सेनाओं को पराजय का मुँह देखना पड़ा, जिससे च्याङ काई-शेक को अचंभा हुआ व उसकी बेइज्जती हुई । युद्ध में लगातार पराजयों तथा अपनी बढ़ती हुई कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं के वशीभूत हो क्वोमिंताङ ने पहले से भी ज्यादा नृशंस व घिनौनी कम्युनिस्ट विरोधी व जन-विरोधी कार्यवाहियाँ करनी शुरू कर दीं ।

2. जापान द्वारा क्वोमिंताङ को आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने की कोशिश :-

युद्ध के आरंभिक दौर में, जापानी साम्राज्यवादियों ने केवल क्वोमिंताङ शासकों की ताकत को ही आँका था तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जरा भी परवाह नहीं की थी; इसलिए क्वोमिंताङ के प्रति उनकी सैनिक नीति आक्रामकता तथा इसके साथ-साथ राजनीतिक उपायों के जरिए उसे आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने की थी । लेकिन प्रतिरोध-युद्ध की ठहराव की मंजिल में शत्रु ने क्वोमिंताङ की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी पर ज्यादा ध्यान दिया तथा अपनी

को भीतरी सैन्य-पंक्ति वाली दीर्घकालीन रक्षात्मक कार्यवाहियां करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। तुरन्त फैसले के बाहरी सैन्य-पंक्ति वाले हमले में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू ''हमला'' था;

''बाहरी सैन्य-पंक्ति'' का मतलब आक्रमण का दायरा तथा ''तुरन्त फैसले'' का अर्थ इस की अवधि था । इस प्रकार अलग-अलग लड़ाइयों में, शत्रु की पहलकदमी को निष्क्रियता में, मजबूती को कमजोरी में तथा बरतरी को कमतरी में बदला जा सकता था; जबकि चीन के संदर्भ में इन परिस्थितियों ने इसके बिल्कुल उलट हो जाना था । इस तरह की अलग-अलग लड़ाइयों में लगातार विजयें प्राप्त करने के बाद शक्ति-संतुलन बदल जाना था । चीन ने ताकतवार तथा शत्रु ने कमजोर हो जाना था ।

इस प्रकार अनेक विजयों के सम्मिलित प्रभाव तथा चीन के अनुकूल अन्य परिस्थितियों, जैसे कि—शत्रु के शिविर के अन्दर होने वाले परिवर्तनों, तथा अन्तर्राष्ट्रीय हालात में आए परिवर्तनों ने एक साथ मिलकर संपूर्ण परिस्थिति को बदल देना था । पहले चीन ने शत्रु की बराबरी पर आना था तथा बाद में उसकी स्थिति शत्रु से श्रेष्ठ हो जानी थी । जैसा कि कामरेड माओ ने कहा था : **''यहां निर्णायक तत्व मनोगत प्रयत्न—अधिक से अधिक विजयें प्राप्त करना तथा कम से कम गलतियां करना—होते हैं ।''**[15]

कामरेड माओ ने जापान-विरोधी युद्ध में छापामार युद्ध के रणनीतिक महत्त्व पर जोर दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि जापान-विरोधी युद्ध में लड़ाई का मुख्य रूप चलायमान लड़ाई होना था तथा छापामार लड़ाई को सहायक भूमिका अदा करनी थी, तो भी छापामार लड़ाई की युद्ध के दौरान महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका थी । इसे नियमित लड़ाई की सहायता करनी थी तथा अपने को नियमित लड़ाई में बदल देना था ।

तीसरे, युद्ध के लिए जनसमुदाय को गोलबन्द करना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय था । **युद्ध एक निश्चित राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन है । दूसरे शब्दों में, यह राजनीति का ही जारी रूप है ।** जापान-विरोधी युद्ध का राजनीतिक उद्देश्य साम्राज्यवादियों को बाहर खदेड़ देना तथा स्वतन्त्रता व समानता वाले एक नए चीन का निर्माण करना था । अपनी पुस्तक *''दीर्घकालीन युद्ध के बारे में''* में कामरेड माओ ने स्पष्ट किया : **''फौज तथा जनता विजय के आधार हैं ।''**[16] **''युद्ध करने की शक्ति का अथाह स्रोत जन-समुदाय में है ।''**[17] **''हम सारे देश की जनता को जत्थेबंद करके उसे एक ऐसे विशाल सागर में बदल देंगे जिसमें हमारा दुश्मन डूब मरने की स्थिति में पड़ जाएगा, तथा हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर लेंगे जिसकी मदद से हथियारों और दूसरी बातों में अपनी कमी को दूर कर सकें और ऐसी पूर्व शर्तें तैयार कर लेंगे जिनकी मदद से युद्ध में हर कठिनाई पर काबू पा सकें।''**[18] युद्ध जीतने के लिए समस्त देश की जनता को लामबन्द करना तथा जापान-विरोधी राष्ट्रीय मोर्चे का विस्तार करना व उसे सुदृढ़ करना अनिवार्य था । युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यह बुनियादी शर्त थी ।

''दीर्घकालीन युद्ध के बारे में'' पुस्तक उस समय लिखी गई थी, जब जापान ऊहान पर एक बड़ा हमला कर रहा था तथा राष्ट्रीय गुलामी व तुरन्त विजय की वाहियात धारणाएं पूरे जोर से फैल रही थीं । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों को लागू करते हुए, कामरेड माओ ने इन धारणाओं का पूर्ण रूप से खण्डन किया, दीर्घकालीन युद्ध की

रणनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत की तथा वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करते हुए युद्ध की प्रगति के बारे में अपनी विचारधारा रखी। इस प्रकार उन्होंने अंतिम विजय में लोगों के विश्वास को आशातीत रूप से बढ़ाया तथा मजबूत किया एवं युद्ध को वैज्ञानिक सिद्धान्तों के मार्गदर्शन के तहत ले आए। जापान-विरोधी युद्ध की समस्त प्रगति ने उनके इस दृष्टिकोण की सत्यता की पुष्टि की । ●

5.

- रणनीतिक ठहराव के आरंभिक काल के दौरान प्रतिरोध-युद्ध ।
- पहली कम्युनिस्ट विरोधी बगावत तथा उसकी पराजय ।
- चीनी क्रान्ति के मूलभूत सिद्धान्त तथा एक नये चीन के निर्माण के लिए कार्यक्रम।

युद्ध की पहली मंजिल में आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना शत्रु की पाँतों के पीछे चली गईं, व्यापक छापामार युद्ध चलाया तथा उत्तरी एवं मध्य चीन में अनेक जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना की गई ।

चीन के दृढ़ प्रतिरोध तथा जापानी सशस्त्र सेनाओं की कमी के कारण, जापानी हमलावरों को कैंटन व ऊहान पर कब्जा करने के बाद अपना हमला रोकने को बाध्य होना पड़ा। क्योंकि उनकी पृष्ठभागीय पंक्तियों को चीन के शक्तिशाली छापामार दस्तों के हमले का निरन्तर सामना करना पड़ता था, अतः उन्हें अपने कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को बचाने के लिए वापिस मुड़ना पड़ा। इस प्रकार जापान-विरोधी युद्ध रणनीतिक ठहराव की मंजिल में दाखिल हो गया ।

इस मंजिल के आरंभिक दौर में, 1938 की सर्दियों से लेकर 1940 के अन्त तक, शत्रु की पाँतों के पीछे आधार-क्षेत्र तथा जनता की सशस्त्र शक्तियाँ विकसित होती रहीं । इसलिए शत्रु ने धीरे-धीरे अपनी मुख्य सैन्य-शक्तियों को कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध झोंकना शुरू कर दिया, जबकि क्वोमिंताङ को आत्मसमर्पण करने हेतु तैयार करने के लिए मुख्यतया राजनीतिक उपाय प्रयोग करने शुरू कर दिए । इसी दौरान यूरोप में गंभीर तनाव से सामना होने पर, अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी क्वोमिंताङ सरकार पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे चीन के हितों की कीमत पर जापान को सोवियत-संघ के विरुद्ध हमला करने के लिए प्रेरित कर सकते थे ।

जनता की जापान-विरोधी शक्तियों के विकास, क्वोमिंताङ सरकार को आत्मसमर्पण हेतु तैयार करने के लिए किए गए जापानी प्रयास तथा इसी उद्देश्य के लिए ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा की गई कोशिशों का परिणाम यह निकला कि क्वोमिंताङ सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति सक्रिय विरोध तथा जापान के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपना ली ।

1. जनता की जापान-विरोधी शक्तियों का विकास :-

ऊहान के पतन से पहले, उत्तरी चीन में शत्रु की पाँतों के पीछे चार आधार-क्षेत्र स्थापित कर लिए गए थे; शानशी-छाहाङ् हपे, शानशी-हपे-शानतुङ-हनान, शानशी-स्वेय्वान तथा शानतुङ आधार-क्षेत्र । इस शहर के पतन के बाद के दो वर्षों के दौरान, ये आधार-क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होते चले गए ।

शत्रु की पाँतों के पीछे स्थापित किया जाने वाला पहला आधार-क्षेत्र—शानशी-छाहाङ्-हपे

आधार-क्षेत्र था । यह एक ऐसे इलाके में स्थित था, जहाँ से पाँच मुख्य रेलमार्ग—पेकिङ-हानखओ, पेकिङ-पाओतओ, ताथुङ-फूचओ, चङतिङ-थाएय्वान तथा पेकिङ-शनयाङ गुजरते थे । इस प्रकार यह इलाका एक ऐसा शानदार तथा अनुकूल धरातल प्रदान करता था, जहाँ से कार्यवाही करके पेकिङ, थ्येनचिन, शच्याच्वाङ, पाओतिङ, ताथुङ, चाङच्याखओ तथा चङते जैसे रणनीतिक महत्त्व के स्थलों तथा प्रमुख परिवहन-पंक्तियों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जा सकता था ।

अगस्त 1940 में शानशी, हपे, शानतुङ तथा हनान के आधार-क्षेत्रों को एकीकृत कर दिया गया तथा छापामार लड़ाई अपने पहले के आधार-क्षेत्र—थाएहाङ पहाड़ों से आगे बढ़कर एक विशाल इलाके में फैल गई, जो पश्चिम में ताथुङ-फूचओ रेलमार्ग तथा फन नदी से लेकर, पूर्व में पोहाए की खाड़ी के तट तक, तथा उत्तर में चङतिङ-थाएय्वान व छाङश्येन-शच्याच्वाङ रेलमार्गों से लेकर, दक्षिण में पीली नदी तक फैला हुआ था ।

शानशी तथा स्वेय्वान में विभिन्न आधार-क्षेत्रों को शानशी-स्वेय्वान आधार-क्षेत्र में एकीकृत कर दिया गया तथा फरवरी 1940 में वहाँ एक जापान-विरोधी जन-सरकार का गठन किया गया । उत्तरी चीन में प्रतिरोध-युद्ध के समर्थन के लिए तथा उत्तर-पश्चिमी चीन को शत्रु से सुरक्षित रखने के लिए, यह क्षेत्र एक रणनीतिक कवच बन गया ।

115वीं डिवीजन की मुख्य सेनाएँ शानशी से शानतुङ की ओर बढ़ीं तथा स्थानीय छापामार यूनिटों के साथ मिल गईं । 1940 के अन्त में, अनेक काउंटियों में जापान-विरोधी सरकारों की स्थापना की गई तथा मध्य एवं दक्षिणी शानतुङ, पो-हाए क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में अनेक आधार-क्षेत्र स्थापित किए गए ।

मध्य चीन में, नई चौथी सेना ने दक्षिणी च्याङसू, उत्तरी च्याङसू, मध्य आनह्वेइ, ह्वाए नदी के उत्तर में तथा हुपे, हनान व आनह्वेइ की सीमाओं पर आधार-क्षेत्र स्थापित किए तथा दो मुख्यालय स्थापित किए और इस प्रकार याङत्सी नदी के दोनों किनारों पर छापामार लड़ाई को अलग-अलग एकीकृत कमान के अन्तर्गत कर दिया । मध्य चीन के आधार-क्षेत्र के अन्तर्गत एक विशाल इलाका था, यह पूर्व में समुद्र को छूता हुआ, पश्चिम में ऊथाङ पर्वतों से रक्षित था, तथा उत्तर में लुङहाए रेलमार्ग से लेकर दक्षिण में चच्याङ-च्याङशी रेलमार्ग तक फैला हुआ था । चूंकि इसमें च्याङसू, चच्याङ, आनह्वेइ, हनान तथा हुपे प्रांतों के अनेक हिस्से शामिल थे, अतः यह एक ऐसा अनुकूल धरातल प्रदान करता था, जहाँ से नानकिङ, शंघाई, सूचओ, ऊहान तथा हाङचओ जैसे रणनीतिक महत्त्व के शत्रु के ठिकानों को वापिस लिया जा सकता था तथा जापानी सेना की मध्य चीन पर कब्जा करने तथा पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की योजना को गहरा धक्का पहुँचाया जा सकता था ।

कैंटन के पतन के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय संगठनों के नेतृत्व में दक्षिणी चीन नामक जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र की स्थापना की गई ।

लड़ाई के आरंभ से 1940 के अन्त तक, जन-सेना ने 150 काउंटियों को पुनः प्राप्त कर लिया तथा जापानी व कठपुतली सेनाओं के 4,00,000 सैनिकों का सफाया कर दिया । जन-सेना ने चीन में मौजूद जापानी सेनाओं के आधे हिस्से से लोहा लिया । मुक्त तथा छापामार क्षेत्रों की जनसंख्या 10 करोड़ तथा कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 8 लाख तक पहुँच गई। प्रतिरोध युद्ध की ठहराव की मंजिल में, वास्तव में यह शत्रु की पाँतों के पीछे की जनता की

अध्ययन करने के ढंग की समस्या मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति रवैये से जुड़ी थी । अध्ययन के ढंग में सुधार करने का अर्थ था—सारी पार्टी को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति सही रवैया अपनाने के लिए शिक्षित करना ।

पार्टी में दो प्रकार का मनोगतवाद था—कठमुल्लावाद तथा अनुभववाद । मुख्यतया कठमुल्लावाद के खिलाफ संघर्ष करने पर जोर दिया गया क्योंकि इसी से पार्टी तथा क्रान्ति को ज्यादा खतरा था ।

'दोष निवारण मुहिम' से पहले उन पार्टी सदस्यों में सच्चे मार्क्सवादी की परिभाषा को लेकर भ्रांतिपूर्ण विचार प्रचलित थे; जिन्हें पार्टी के ऐतिहासिक अनुभवों की जानकारी नहीं थी। काफी समय तक, साथी वाङ मिङ जैसे कठमुल्लावादियों ने स्वयं को "पूर्ण मार्क्सवादी" के ठप्पे से अभिनन्दित किया । मार्क्सवाद का उनका अध्ययन अव्यावहारिक तथा बिना किसी उद्देश्य के था । वे इसे क्रान्तिकारी व्यवहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ते थे। इस प्रकार वे चीनी क्रांति की समस्याओं के ठोस विश्लेषण तथा हल के लिए मार्क्सवादी रुख, दृष्टिकोण तथा तरीका अपनाने में अक्षम थे, वे तो मार्क्सवादी साहित्य में से मुहावरेदार शब्दों का केवल उल्लेख भर कर सकते थे । मार्क्सवाद के प्रति ऐसा रवैया अत्यन्त हानिकारक था। पार्टी सदस्यों के एक हिस्से में यह गलतफहमी भी घर करने लगी थी कि मार्क्सवाद किताबों में से इधर-उधर से चुनकर इकट्ठे किए गए कुछ बेतरतीब उद्धरणों के जोड़-तोड़ के सिवा और कुछ न था । अतः कठमुल्लावाद का विरोध करते हुए, कुछ धारणाओं की सही व्याख्या करना अत्यंत जरूरी था ।

सिद्धान्त क्या है ?

सिद्धान्तकार कैसे बना जा सकता है ?

मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सारतत्व क्या है ?

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन का सही तरीका क्या है ? आदि-आदि ।

सिद्धान्त क्या है ?

वास्तविक समस्याओं के सामान्यीकरण को सिद्धांत कहते हैं । **"दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म का सच्चा सिद्धान्त होता है—वह सिद्धान्त जो वस्तुगत यथार्थ से निकाला गया हो और वस्तुगत यथार्थ की कसौटी पर परखा जा चुका हो ।"**[2] सिद्धान्त तथा व्यवहार में एकता मार्क्सवाद व लेनिनवाद के बुनियादी उसूलों में से एक है । वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करके, तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके तथा फिर उनसे एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहिये । इसके बाद दूसरा कदम है—इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक स्तर पर प्रमाणित करना । इसीलिए पार्टी की केन्द्रीय समिति ने अपने सभी सदस्यों से, वास्तविक संघर्षों में हिस्सा लेने तथा वास्तविक समस्याओं को समझने का आह्वान किया।

पार्टी के सिद्धान्तकार कौन हैं ?

सिद्धान्तकार वे हैं—**"जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख, दृष्टिकोण और तरीके के अनुसार इतिहास और क्रान्ति के दौरान पैदा होने वाली व्यावहारिक समस्याओं की सही ढंग से व्याख्या करते हैं तथा चीन की आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक तथा अन्य समस्याओं की वैज्ञानिक व्याख्या तथा सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं ।"**[3] सिद्धान्त ऐसे होने चाहियें जो क्रान्ति के उद्देश्य को पूरा कर सकें । एक पार्टी सदस्य को

क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग का संपूर्ण नेतृत्व सुनिश्चित किया जाना था ।

2. नव-जनवादी आर्थिक कार्यक्रम के तहत बड़े-बड़े बैंकों, बड़े औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कारोबारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना था । लेकिन गणराज्य ने न तो पूँजीवादी निजी संपत्ति की दूसरी किस्मों का अधिग्रहण करना था और न ही ऐसे पूँजीवादी उत्पादन के विकास पर पाबन्दी लगानी थी जिसने जनता के जीवन-यापन को नियंत्रित नहीं करना था । ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की जमीन जब्त करके भूमिहीन अथवा बहुत ही थोड़ी जमीन वाले किसानों में बांट दी जानी थी । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सामंती सम्बन्धों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाना था तथा जमीन को किसानों की निजी मिलकियत घोषित कर दिया जाना था । धनी-किसानों की अर्थ-प्रणाली के अस्तित्व की इजाजत दी जानी थी । सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व वाले नव-जनवादी गणराज्य में राजकीय-स्वामित्व वाले उद्यमों का स्वरूप समाजवादी होना था तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका होनी थी, जबकि सभी प्रकार के सहकारी उद्यमों में भी कुछ समाजवादी तत्व होने थे । इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में समाजवादी तत्वों की संपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित किया जाना था ।

3. सांस्कृतिक कार्यक्रम में नव-जनवादी संस्कृति को राष्ट्रीय, वैज्ञानिक तथा जन-संस्कृति के रूप में परिभाषित किया गया था । इस संस्कृति ने साम्राज्यवादी दमन का विरोध करना था तथा चीनी राष्ट्र की गरिमा व स्वतन्त्रता को कायम रखना था तथा इसने राष्ट्रीय विशेषताओं को समेटे हुए होना था । इसके साथ ही चीन को अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए विदेशों की प्रगतिशील संस्कृतियों का व्यापक स्तर पर अपनी संस्कृति में समावेश कराना था। तथापि अविवेचनीय समावेश की भर्त्सना की जानी थी, इसकी इजाजत नहीं दी जानी थी । विदेशी बातों को राष्ट्रीय विशेषताओं के अनुरूप ढाला जाना था, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रयोग में लाने से पहले सुस्पष्ट राष्ट्रीय रूप दिया जाना था ।

नव-जनवादी संस्कृति को एक वैज्ञानिक संस्कृति होना था । इसे सभी सामंती तथा अन्धविश्वासपूर्ण विचारों का विरोध करना था तथा सत्य को तथ्यों से ढूंढने का व सिद्धान्त को व्यवहार के साथ मिलाने का पक्ष-पोषण करना था । सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक सही दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी थी । प्राचीन सभ्यता को न तो निरंकुश तरीके से अस्वीकृत किया जाना था, और न ही अविवेचनीय तरीके से स्वीकार किया जाना था । इसके जनवादी सारतत्व को तो शामिल किया जाना था, जबकि इसके सामंती कूड़े-कबाड़ को फेंक दिया जाना था । केवल इस तरह ही एक नई संस्कृति का सृजन किया जा सकता था।

नव-जनवादी संस्कृति आम जनता की संस्कृति होनी चाहिये थी । इसका सर्वप्रथम कर्त्तव्य मेहनतकश किसान तथा मजदूर वर्ग की सेवा करना था, जो राष्ट्र की आबादी का 90% से भी अधिक था । तथा इसे कदम-ब-कदम इसी सही दिशा में आगे बढ़ते जाना चाहिये था ।

नव-जनवादी क्रान्ति के दौरान, कम्युनिस्ट विचारधारा की नेतृत्वकारी भूमिका तथा राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्वों की उपस्थिति के मद्देनजर, साम्यवाद के प्रचार-प्रसार को व्यापक बनाने तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन कार्य को तेज करने के प्रयास किये जाने चाहिएं थे । लेकिन यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाना जरूरी था कि राष्ट्रीय संस्कृति को नव-जनवादी रास्ते पर चलना था । साम्यवाद के प्रचार-प्रसार का यह अर्थ नही था कि उसे साकार करने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही-योजना अमल में लाई जाए ।

मार्क्सवाद के प्रचार-प्रसार का उद्देश्य मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा उपायों को, विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करने, अनुसंधान-कार्य करने, कार्यों का प्रबन्ध करने तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल करना था। राष्ट्रीय संस्कृति के लिए कार्यदिशा का निर्धारण करना इसका उद्देश्य नहीं था।

कामरेड माओ की सशक्त रचना *''नव-जनवाद के बारे में''* ने क्वोमिंतांङ के प्रतिक्रियावादियों तथा उनके पिछलग्गुओं को सैद्धान्तिक स्तर पर पूर्णतया निरस्त कर दिया था तथा चीनी श्रमिक वर्ग व चीनी जनता को बौद्धिक स्तर पर पूरी तरह लैस कर दिया था। इसने पार्टी तथा समूचे राष्ट्र की विचारधारात्मक एकता तथा सभी मुक्त क्षेत्रों की नीतियों के एकीकरण में अत्यधिक योगदान दिया तथा इस प्रकार चीनी क्रान्ति को आगे बढ़ाने में सहायता पहुँचाई। ●

6.

- **जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे की कार्यनीतिक कार्यदिशा का दृढ़ता से पालन करना।**
- **दूसरी कम्युनिस्ट-विरोधी बगावत एवं उसकी पराजय।**

उस समय क्वोमिंतांङ के कट्टरपंथियों द्वारा आत्मसमर्पण कर देने का खतरा बेहद गंभीर था। ब्रिटेन तथा अमरीका-परस्त बड़े-पूँजीपतियों की आत्मसमर्पणकारी कार्यदिशा तथा जनता की सशस्त्र प्रतिरोध की कार्यदिशा के बीच संघर्ष दिन-प्रतिदिन गंभीर होता चला गया। इन दोनों अलग-अलग कार्यदिशाओं के दो अलग-अलग नतीजे हो सकते थे। यदि क्वोमिंतांङ की कम्युनिस्ट-विरोधी नीति को बेरोकटोक फलने-फूलने की इजाजत दी जाती, तो आत्मसमर्पणकारी तथा कम्युनिस्ट-विरोधी गतिविधियां सारे देश में फैल जातीं तथा अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त मोर्चे के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यभार सशस्त्र प्रतिरोध की कार्यदिशा पर डटे रहना तथा आत्मसमर्पण के खतरे को खत्म करना था। पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ ने युद्ध की स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण किया तथा पार्टी के कार्यभारों को सही तौर से परिभाषित किया। घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर ऐसी अनेक अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं, जिन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय एकता कायम रखने व प्रगति के लिए संघर्ष हेतु स्थिति सुधारने तथा प्रतिरोध में डटे रहने में मदद दी। ये परिस्थितियां इस प्रकार थीं :

- चूंकि जापान को गंभीर क्षतियां उठानी पड़ी थीं, इसलिए युद्ध रणनीतिक ठहराव की मंजिल में प्रवेश कर गया था, लेकिन जापान अभी भी चीन को गुलाम बनाने की अपनी मूल नीति पर अड़ा हुआ था।
- यद्यपि एक ओर अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस तथा दूसरी ओर जापान के बीच अन्तर्विरोध धीरे-2 कम होने शुरू हो गए थे, फिर भी अभी किसी ठोस समझौते के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके अतिरिक्त, यूरोप में युद्ध की वजह से पूर्व में ब्रिटेन व फ्रांस की हालत कमजोर हो गई थी, इसलिए किसी ''पूर्व के म्यूनिख'' का आयोजन करना असंभव था।
- सोवियत-संघ को अपनी विदेश नीति में और ज्यादा सफलताएं प्राप्त हुई थीं; और वह

नेतृत्वकारी पदों के केवल एक तिहाई हिस्से पर ही कम्युनिस्ट होंगे।

जापानी हमलावरों के विरुद्ध भीषण संघर्ष के दौर में, केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में, समूची पार्टी में **'दोष-निवारण मुहिम'** के नाम से एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी शैक्षणिक आन्दोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य, गैर-सर्वहारा विचारों से छुटकारा पाना था, जो एक समय पार्टी में गंभीरता की हद तक फैल गए थे तथा अभी भी पार्टी की सही कार्यदिशा तथा नीतियों को लागू करने में रोड़ा अटका रहे थे।

यह मुहिम चलाने से पहले ही पार्टी एक एकीकृत तथा सुदृढ़ पार्टी बन चुकी थी तथा व्यापक जन-समुदाय इसका आधार था। कम्युनिस्ट पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तथा इसकी सदस्य संख्या दसियों हजार से बढ़ती-बढ़ती आठ लाख तक पहुँच गई थी। सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक दृष्टि से यह अब एक एकीकृत तथा मजबूत पार्टी बन चुकी थी। सैद्धान्तिक रूप से, इसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की रोशनी में चीनी क्रांति की समस्याओं को हल करना सीख लिया था; राजनीतिक स्तर पर इसने एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा का प्रतिपादन कर लिया था; तथा संगठनात्मक स्तर पर इसके पास एक बोल्शेविक मार्गदर्शक केन्द्रीय नेतृत्व था।

'दोष-निवारण मुहिम' से पहले ऐसी थी पार्टी की सामान्य हालत। लेकिन इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना था कि पार्टी अभी भी अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी हुई थी। चूंकि पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही थी, अतः वह अपने इर्द-गिर्द व्यापक रूप से फैले निम्न-पूँजीपति वर्ग के विचारों से लगातार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती थी। पूँजीपति वर्ग भी पार्टी को प्रभावित करने के लिए सभी साधन इस्तेमाल करता था। जापान-विरोधी युद्ध छिड़ने के बाद, बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण व शहरी निम्न-पूँजीवादी मूल के प्रगतिशील लोग पार्टी में शामिल हो गए थे। चूंकि पार्टी श्रमिक वर्ग के हितों के साथ-साथ समस्त राष्ट्र के हितों का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी, तथा लोगों में इसका बहुत ज्यादा सम्मान था, अतः यह अवश्यम्भावी एवं स्वाभाविक ही था कि निम्न-पूँजीवादी मूल के प्रगतिशील लोग बड़ी तादाद में चीनी श्रमिक वर्ग की पार्टी में शामिल हों तथा इसकी सदस्य संख्या में उनका बहुमत हो जाए।

यह भी अपरिहार्य था कि निम्न-पूँजीवादी मूल के वे सदस्य जो अभी सैद्धांतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया परिपक्व नहीं हुए थे, अपनी विचारधारा तथा कार्यप्रणाली द्वारा पार्टी को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने तथा यहां तक कि कुछ मामलों में, अपनी निम्न-पूँजीवादी विचारधारा तथा सोचने के ढंग के अनुसार पार्टी को ''सुधारने'' की कोशिश भी करें। इससे पार्टी के अंदर सर्वहारा तथा गैर-सर्वहारा विचारधाराओं में अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया, विशेषतः सर्वहारा वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग की विचारधाराओं के बीच में। अपनी स्वयं की पाँतों में उत्पन्न इस गंभीर समस्या से सामना होने पर पार्टी ने अपने सदस्यों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद में शिक्षित करने का फौरी कार्य शुरू करने का फैसला किया।

'दोष निवारण मुहिम' मुख्यतया अध्ययन के ढंग में मनोगतवादी रुझान के खिलाफ, पार्टी की कार्यशैली में कट्टरवादी रुझान के खिलाफ तथा अभिव्यक्ति के ढंग में घिसे-पिटे पार्टी लेखन के खिलाफ चलाई गई।

1. अपने अध्ययन के तरीके में सुधार करो—मनोगतवाद का विरोध करो।

व प्रतिक्रियावादियों का दमन करना ।''[1]

जापान-विरोधी जनवादी सरकार की कृषि-नीति के अनुसार जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले लगान तथा सूद में कमी की गई तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसान लगान तथा सूद अदा करें । यह व्यवस्था की गई कि आमतौर से जमीन के लगान में 25 प्रतिशत की कटौती हो तथा यह कि सूद की दर इतनी कम भी न हो कि समाज में कोई उधार देने के लिए ही तैयार न हो, तथा इन कटौतियों के बाद लगान तथा सूद बकायदा अदा किए जाएं। इस प्रकार जमींदारों के मालिकाना हक तथा किसानों के काश्तकारी अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई ।

जापान-विरोधी जनवादी सरकार की श्रम-नीति के तहत श्रमिकों के रहन-सहन के हालात में उचित सुधार तथा काम के घण्टों को तय करने का प्रावधान किया गया । लेकिन श्रम तथा पूँजी के बीच एक बार अनुबन्ध हो जाने के बाद श्रमिकों को श्रम-अनुशासन का पालन करना था ताकि पूँजीपतियों को मुनाफे का कुछ हिस्सा मिल सके ।

आर्थिक नीति का उद्देश्य था—उद्योग तथा कृषि का त्वरित विकास करना व व्यापार को प्रोत्साहन देना ताकि आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके । राजकीय तथा सहकारी उद्यमों को विकसित करने के साथ-साथ सरकार ने आधार-क्षेत्रों में बाहर से आए पूँजीपतियों द्वारा लगाए गए निजी कारोबारों तथा पूँजीनिवेशों को भी प्रोत्साहन दिया ।

कर नीति आय पर आधारित थी । अत्यन्त गरीब लोगों को छोड़ कर, आमदनी वाले सभी लोगों के लिए सरकार को कर देना जरूरी था । करों का समूझा बोझ केवल जमींदारों तथा पूँजीपतियों पर ही नहीं डाला गया, बल्कि 80 प्रतिशत से अधिक जनता ने इसमें हिस्सा बंटाया।

जापान-विरोधी जनवादी सरकार ने सभी जमींदारों व पूँजीपतियों को, जो जापान का प्रतिरोध करते थे, व्यक्तिगत अधिकार प्रदान किए, जैसे कि राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार तथा सम्पत्ति रखने का अधिकार । लेकिन साथ ही उनकी किसी संभावित प्रति-क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी गई ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की सीधी देख-रेख में शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र एक आदर्श जापान-विरोधी जनवादी आधार-क्षेत्र बन गया । इस क्षेत्र में 1937 में आम चुनाव हुआ तथा सभी प्रशासनिक स्तरों पर जनता की जनवादी सरकारें स्थापित कर दी गईं । 1941 में ''तीन-तिहाई व्यवस्था'' के तहत एक और चुनाव कराया गया ।

उत्तरी चीन में शत्रु के पृष्ठभाग में आधार-क्षेत्रों की स्थापना के तुरन्त बाद, गांव तथा काउंटी के स्तर पर असेम्बलियों का गठन कर दिया गया । शानशी-छाहाङ-हपे सीमान्त-क्षेत्र में 1940 में हुए आम चुनाव में 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया । 1941 तथा 1942 के बीच सभी आधार-क्षेत्रों में असेम्बलियों के चुनाव करा दिये गए । शानशी-हपे-शानतुङ-हनान सीमान्त क्षेत्र की अन्तरिम असेम्बली के चुनाव 1941 में हुए तथा शानशी-छाहाङ-हपे सीमान्त-क्षेत्र की असेम्बली के चुनाव जनवरी 1943 में सम्पन्न हुए । इन असेम्बलियों ने प्रशासनिक कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा उन्हें लागू किया व बुनियादी कानूनों को पारित किया । लोगों द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था होने के नाते असेम्बली को सरकार चुनने व कानून बनाने के अधिकार प्राप्त थे । कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रक्रिया का पूरी सख्ती के साथ पालन किया कि सभी सरकारी संस्थाओं तथा जन-प्रतिनिधित्व वाले संस्थानों में

चीन के प्रतिरोध-युद्ध को सक्रिय समर्थन देने की अपनी नीति पर कायम था ।

- कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रगतिशील शक्तियों का बड़े व्यापक रूप से विस्तार हो चुका था तथा वे प्रतिरोध-युद्ध की रीढ़ की हड्डी बन गई थीं ।
- यद्यपि बड़े-पूँजीपति वर्ग का जापान-परस्त धड़ा ग़द्दार हो गया था तथा शत्रु से जा मिला था, परन्तु उसका ब्रिटेन व अमरीका-परस्त धड़ा प्रतिरोध शिविर में ही था । इस धड़े ने प्रगतिशील शक्तियों को दबाना जारी रखा, पर इसने वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं किया था। और जो भी हो, ये पूँजीवादी कट्टरपंथी क्वोमिंताङ में बहुत ही अल्पमत में थे ।
- मध्यवर्ती शक्तियां आत्मसमर्पण के विरुद्ध थीं ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू परिस्थितियों का सवाल था, जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे को बनाए रखने तथा स्थिति को बेहतर बनाने की या फिर कम से कम उसे और ज्यादा खराब होने से रोकने की संभावनाएं मौजूद थीं । कट्टरपंथियों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध 1939 से की गई सभी फौजी कार्यवाहियां स्थानीय पैमाने की ही थीं । वे रणनीतिक टोह जैसी मात्र प्रारंभिक किस्म की कार्यवाहियां ही थीं तथा उनसे तत्काल बड़े पैमाने पर किसी कम्युनिस्ट-विरोधी युद्ध का आभास नहीं मिलता था । उनका उद्देश्य आत्मसमर्पण के लिए रास्ता तैयार करना था, लेकिन उनका निशाना तत्काल आत्मसमर्पण का नहीं था ।

मार्च 1940 में कामरेड माओ द्वारा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्त्ताओं की बैठक में **''मौजूदा जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में कार्यनीति संबंधी समस्याओं''** पर प्रस्तुत रिपोर्ट ने तथा इसी विषय पर उनके द्वारा लिखे गए अन्तः पार्टी निर्देशों ने जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे से संबंधित सामान्य नीति तथा क्वोमिंताङ कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष में अपनाए जाने वाले कार्यनीतिक सिद्धान्तों की और अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की ।

पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे को लेकर तैयार की गई नीति थी—प्रगतिशील शक्तियों का विकास करना, मध्यवर्ती शक्तियों को अपने पक्ष में करना तथा कट्टरपंथियों को अलग-थलग कर देना ।

प्रगतिशील शक्तियों के विकास का अर्थ था—सर्वहारा, किसान समुदाय तथा शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग की शक्तियों का विकास करना ; आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना का साहस के साथ विस्तार करना ; जापान-विरोधी जनवादी आधार-क्षेत्रों की स्थापना करना; तथा इन आधार-क्षेत्रों में जनता को लामबन्द करने, कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन स्थापित करने तथा जनता की जापान-विरोधी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की खुली छूट देना । क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में, क्वोमिंताङ से सभी जापान-विरोधी पार्टियों, ग्रुपों तथा संगठनों को कानूनी मान्यता प्रदान करने की मांग करते हुए जन-आंदोलन खड़े करने के सभी संभव उपाय किये जाने चाहिएं थे । प्रगतिशील शक्तियां संयुक्त मोर्चे की रीढ़ की हड्डी थीं; उन्हें कदम-ब-कदम विकसित करके ही पार्टी मध्यवर्ती शक्तियों को असरदार ढंग से अपनी ओर कर सकती थी, कट्टरपंथी शक्तियों को अलग-थलग कर सकती थी, उनके (कट्टरपंथियों के) आत्मसमर्पण तथा फूट को रोक सकती थी तथा जापान-विरोधी युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने के लिए एक फौलादी नींव डाल सकती थी ।

मध्यवर्ती शक्तियों को अपनी ओर करने का अर्थ था—मध्यम पूँजीपति वर्ग (राष्ट्रीय

पूँजीपति-वर्ग), जागृत शरीफजादों तथा प्रभुत्वशाली स्थानीय ग्रुपों को अपने पक्ष में कर लेना। प्रगतिशील शक्तियों के विपरीत, मध्यवर्ती साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में केवल सहयोगी ही थे । मध्यम पूँजीपति वर्ग एवं जागृत शरीफजादे जापान के विरुद्ध सांझी लड़ाई में तथा जापान-विरोधी जनवादी सरकार की स्थापना में तो भाग ले सकते थे, परन्तु उन्हें कृषि-सुधारों से डर लगता था । उनमें से कुछ लोग कट्टरपंथियों के खिलाफ संघर्ष में भी हिस्सा ले सकते थे, या फिर तटस्थ रह सकते थे । स्थानीय प्रभावशाली ग्रुप बड़े-जमींदार वर्ग तथा बड़े-पूँजीपति वर्ग से संबंध रखते थे । वे जापान-विरोधी युद्ध में तो शामिल हो सकते थे, लेकिन जापान-विरोधी जनवादी सरकार के गठन में उनके हिस्सा लेने की संभावना नहीं थी। कट्टरपंथियों के खिलाफ किये जाने वाले संघर्ष में भी वे केवल अस्थाई तौर पर तटस्थ रह सकते थे । मध्यवर्ती शक्तियों का रवैया निश्चित रूप से ढुलमुलपन का था तथा कट्टरपंथी भी पूरे जोर-शोर से उन्हें अपनी ओर मिलाने के प्रयास कर रहे थे । चीन में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण, कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष में वे अक्सर निर्णायक तत्व साबित हो सकते थे । इसलिए इन शक्तियों के साथ बरताव करते समय बड़ी संजीदगी तथा असरदार उपायों से काम लेने की जरूरत थी ।

कट्टरतावादी शक्तियों को अलग-थलग करने का अर्थ था—बड़े जमींदार वर्ग तथा बड़े-पूँजीपति वर्ग (दलाल-पूँजीपति वर्ग) की शक्तियों को अलग-थलग करना, जिनका नेतृत्व च्याङ काई-शेक के हाथ में था तथा जो दोगली प्रति-क्रान्तिकारी नीति पर चल रहा था । एक ओर तो वे जापान का प्रतिरोध कर रहे थे तथा दूसरी ओर प्रगतिशील शक्तियों को नष्ट करने की अत्यन्त प्रतिक्रियावादी नीति पर चल रहे थे ताकि भविष्य में आत्मसमर्पण के लिए रास्ता तैयार किया जा सके । वे जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, परन्तु सक्रियतापूर्वक नहीं, वे कम्युनिस्ट पार्टी का भी विरोध कर रहे थे, परन्तु अभी तक संयुक्त मोर्चे को खुल्लम-खुल्ला दो फाड़ करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी । कट्टरतावादियों की इस दोगली प्रतिक्रान्तिकारी नीति का सामना करने के लिए एक दुधारी क्रान्तिकारी नीति अपनाना जरूरी था । जब तक वे जापान का विरोध कर रहे थे तथा संयुक्त मोर्चे को पूर्णतया दो फाड़ करने की जुर्रत नहीं करते, तब तक उनके साथ एकता बनाए रखने तथा उन्हें जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनाए रखने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये थी । लेकिन यदि वे जापान का निष्क्रिय प्रतिरोध करते तथा कम्युनिस्ट पार्टी व जनता का सक्रिय विरोध करते, तो उनके विरुद्ध राजनीतिक, फौजी व सैद्धान्तिक मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक संघर्ष चलाया जाना था । केवल इसी तरह की क्रान्तिकारी दुधारी नीति पर चलकर ही पार्टी उनकी प्रतिक्रियावादी नीति के दायरे को सीमित करने, प्रगतिशील शक्तियों को विकसित करने, मध्यवर्ती शक्तियों को अपने पक्ष में करने तथा कट्टरपंथियों को अलग-थलग करने में सफल हो सकी और ऐसा करके ही पार्टी उन्हें संयुक्त मोर्चे में रखने तथा विशाल पैमाने पर गृहयुद्ध रोकने में कामयाब हुई ।

संयुक्त मोर्चे से संबंधित सामान्य कार्यनीतिक कार्यदिशा तैयार करने के अतिरिक्त, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने क्वोमिंताङ के कट्टरतावादियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए **तीन मार्गदर्शक सिद्धान्त**[13]—**''न्यायोचित आधार पर''**, **''अपना फायदा देखते हुए''** और **''संयत रूप से''**—तय किये ।

व महत्त्वपूर्ण परिवहन-पंक्तियों पर कब्जा करके, विजय के फल उसकी झोली में डाल सकते थे। कम्युनिस्टों तथा जनता के विरुद्ध इस देशद्रोही षड्यन्त्र को च्याङ काई-शेक ने निर्लज्जतापूर्वक *''अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा देश को बचाने''* की संज्ञा दी । इस बहाने की आड़ में, पाँच लाख से भी अधिक क्वोमिंताङ फौजी शत्रु से जा मिले, तथा 8 लाख की कठपुतली फौज का 62 प्रतिशत हिस्सा, यही सैनिक थे । क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के 20 सदस्यों तथा 58 शीर्षस्थ जनरलों ने आत्मसमर्पण कर दिया । इन क्वोमिंताङ फौजों ने कठपुतली सेना में शामिल होते ही, जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों के विरुद्ध अत्यधिक भयंकर नृशंसताएँ करने में जापानियों को जबरदस्त सहयोग दिया । फलतः, इन आधार-क्षेत्रों को न केवल जापानी साम्राज्यवादी हमलावरों से ही लोहा लेना पड़ा, बल्कि उनके चीनी पालतू कुत्तों तथा च्याङ काई-शेक के कम्युनिस्ट विरोधी गद्दारों से भी दो-दो हाथ करने पड़े ।

इस संयुक्त तथा दो तरफे हमले के कारण, आठवीं राह सेना की संख्या 1940 के 4,00,000 सैनिकों से घटकर 1941 में 3,03,000 सैनिक रह गई तथा आधार-क्षेत्र भी सीमित हो गए, जिसके परिणामवश आधार-क्षेत्रों की आबादी भी 10 करोड़ की बजाय 5 करोड़ रह गई । 1941-42 के दो सालों के दौरान, जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों को विकट कठिनाइयों से गुजरना पड़ा तथा फौज व जनता दोनों को बड़ी भयंकर मुसीबतें झेलनी पड़ीं । ●

2.

- **जापान-विरोधी जनवादी राजनीतिक-सत्ता की बुनियादी नीति ।**
- **कम्युनिस्ट पार्टी का दोष-निवारण आंदोलन ।**
- **मुक्त-क्षेत्रों में व्यापक उत्पादन मुहिम ।**

जापान-विरोधी युद्ध के इस अत्यधिक नाजुक दौर में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शत्रु की पाँतों के पीछे जन-संघर्ष का नेतृत्व किया । युद्ध जीतने के लिए जनता की, खासकर किसान वर्ग की पहलकदमी तथा ताकत को, क्रांतिकारी संघर्ष में पूरी तरह इस्तेमाल किया जाना बेहद जरूरी था ।

पार्टी ने आधार-क्षेत्रों में जापान-विरोधी जनवादी राजनीतिक सत्ता की स्थापना की । यह जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे का शासन था, जापान का प्रतिरोध करने व जनवाद के लिए कृतसंकल्प लोगों का शासन था तथा यह देशद्रोहियों व प्रतिक्रियावादियों के ऊपर अनेक क्रांतिकारी वर्गों का संयुक्त अधिनायकत्व था । जनवादी राजनीतिक सत्ता के अन्तर्गत *''तीन तिहाई व्यवस्था''* लागू की गई । जिसके अनुसार कम्युनिस्टों (जो मजदूर वर्ग तथा गरीब किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे), प्रगतिशीलों (जो निम्न-पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि थे) तथा मध्यवर्तियों (जो राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा जागृत शरीफजादों का प्रतिनिधित्व करते थे), प्रत्येक को, सभी सरकारी संगठनों तथा जन-प्रतिनिधि निकायों में एक तिहाई पद मिले । जापान-विरोधी जनवादी राजनीतिक सत्ता के प्रशासनिक कार्यक्रम का बुनियादी प्रस्थान बिन्दू था : **''जापानी साम्राज्यवाद का विरोध करना, जापान का प्रतिरोध करने वाली जनता की रक्षा करना, सभी जापान-विरोधी सामाजिक तबकों के हितों का यथोचित रूप से समायोजन करना, श्रमिकों तथा किसानों के रहन-सहन के हालात में सुधार करना तथा देशद्रोहियों**

तथा जनता की लूट-खसोट व दमन को तेज करने की नीतियों पर निर्भर करता था । जापामार इलाकों में, शत्रु ने मुख्य रूप से खाइयां खोदकर, अवरोधक दीवारें खड़ी करके, किलेबन्दियां बनाकर, गांवों को नष्ट करके तथा बर्बरतापूर्वक विशाल इलाकों में खड़ी फसलें नष्ट कर उन्हें बंजर भूमि में तब्दील करके आधार-क्षेत्रों को "कुतरने" की नीति अपनाई । जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों से निपटते समय, शत्रु खासतौर से "सफाया अभियानों" तथा *"सब कुछ जला डालो, सभी को खत्म कर दो और सब कुछ लूट लो"* की **"तीन तरह का सफाया करने"** की अत्यधिक नृशंस नीति को लागू करने, तथा बारम्बार "तलाशी" की कार्रवाइयां करने पर निर्भर रहा । इसके पीछे उसका अन्तिम उद्देश्य केवल एक ही था कि जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की जनता तथा सशस्त्र सेनाएं अपने जीवन-यापन के साधनों से वंचित हो जाएं।

1941-42 में, उत्तरी चीन में जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों के विरुद्ध "सफाया" अभियानों की एक लंबी शृंखला चलाई गई । 174 लड़ाइयों में 8 लाख 33 हजार से भी अधिक जापानी फौजों को झोंका गया तथा हर लड़ाई में 1000 या उससे अधिक सिपाही रहते थे । पिछले दो सालों की तुलना में मुहिमों की संख्या 66 प्रतिशत बढ़ गई थी तथा सिपाहियों की तादाद दुगुनी हो गई थी । धरती के चप्पे-चप्पे पर किलेबन्दियों व पाँच-पाँच मीटर ऊँची आड़ी-तिरछी पत्थर की दीवारों तथा पाँच-पाँच मीटर चौड़ी खाइयों का जाल बिछा दिया गया था । 1944 तक, 8 लाख 30 हजार वर्ग किलोमीटर के उत्तरी चीन मुक्त क्षेत्रों में, जिनकी आबादी 8 करोड़ 30 लाख से अधिक थी, जापानी हमलावरों ने, रेलमार्गों व राजमार्गों के अतिरिक्त, 10,000 से अधिक फौजी दुर्गों, 30,000 किलेबन्दियों, 600 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों तथा 10,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी खाइयों का निर्माण किया ।

क्वोमिंताङ कट्टरवादियों से निपटने के लिए जापानियों ने अपना राजनीतिक दबाव बनाए रखा तथा उसके साथ-साथ फौजी हमले भी जारी रखे । पर व्यापक स्तर पर फौजी हमले करने की बजाय उन्होंने क्वोमिंताङ सरकार को आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने के काम पर ज्यादा ध्यान दिया । उन्होंने फुसलाहट के साथ-साथ धमकी से भी काम किया तथा फौजी दबाव केवल तभी डाला जब शान्तिपूर्ण वार्ताएं असफल हो गईं ।

कम्युनिस्टों तथा जनता के विरुद्ध अपनी कार्यवाहियों के कारण, शत्रु की पाँतों के पीछे मौजूद क्वोमिंताङ फौजें जापानी "सफाया" मुहिमों का मुकाबला नहीं कर पाईं । 1941 में शानशी प्रांत के चुङथ्याओ पर्वतों में उन्हें भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा । 1942 में चच्याङ-च्याङशी सीमा पर तथा 1943 में शानतुङ में भी ऐसा ही हुआ ।

1941 के बाद से, शत्रु की पाँतों के पीछे मौजूद क्वोमिंताङ फौजों ने, भारी संख्या में जापानियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना आरंभ कर दिया । जापान ने उन्हें अपनी कठपुतली सेना में सम्मिलित कर लिया तथा फिर मुक्त-क्षेत्रों पर हमले करने के लिए झोंक दिया ।

शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की व्यापक घेराबन्दी करते हुए, च्याङ काई-शेक ने गद्दाराना ढंग से तथा जान-बूझकर अपनी बहुत सी फौजी टुकड़ियों को जापान के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया । इसके पीछे, उसका उद्देश्य खुल्लम-खुल्ला कम्युनिस्ट-विरोधी पताका फहराना था, ताकि वह जापानी हमलावरों के सहयोग से चीनी मुक्त-क्षेत्रों पर हमले कर सके । उसने हिसाब लगाया कि जब जापान हार जाता तो ये गद्दार फिर से क्वोमिंताङ का झंडा उठा सकते थे तथा जापान द्वारा अधिकृत शहरों

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रकार की शक्तियां थीं : जापान, अमरीका व ब्रिटेन, एवं सोवियत संघ। पार्टी ने इन शक्तियों का बड़े ही स्पष्ट रूप से अलग-अलग आकलन किया। इसने सोवियत-संघ तथा दूसरी ओर अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी पूँजीवादी ताकतों के बीच के अन्तर को; जापानी साम्राज्यवाद, जो चीन पर हमला कर रहा था तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच, जो चीन पर हमला नहीं कर रही थीं; जर्मनी व इटली, जिन्होंने जापान के साथ गठजोड़ किया था तथा दूसरी ओर ब्रिटेन व अमरीका के बीच, जो जापान के विरोधी थे ; सुदूर पूर्व के म्यूनिख का षड्यन्त्र रचने वाले भूतकाल के ब्रिटेन व अमरीका तथा आज के ब्रिटेन व अमरीका के बीच, जिन्होंने उस नीति का परित्याग कर दिया था ; तथा ब्रिटेन व अमरीका की जनता व इन देशों के शासक वर्गों के बीच के अन्तरों को पूर्णतया स्पष्ट किया। इन्हीं अन्तरों के आधार पर पार्टी ने अपनी विदेश नीति तय की, ताकि प्रतिरोध युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जापान-विरोधी शक्तियों का समर्थन हासिल किया जा सके ।

केन्द्रीय समिति ने समूची पार्टी को क्वोमिंताङ के कट्टरतावादी गुट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी काण्ड करने की संभावना के प्रति सचेत किया तथा ऐसे किसी हमले का मुकाबला करने के लिए सभी संभव तैयारियां करने की जरूरत को स्पष्ट किया, ताकि पार्टी व क्रान्ति को अप्रत्याशित नुकसान न उठाने पड़ें ।

बाद में इस तरह का एक कांड हुआ भी । यह जनवरी 1941 का **दक्षिणी आनह्वेइ कांड** था । उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति नाजुक हो चुकी थी । यूरोप में जर्मन फासीवादी कहर ढा रहे थे । नाजी फौजों ने अप्रैल 1940 में डेनमार्क तथा नार्वे पर अधिकार कर लिया था, मई में इंग्लिश चैनल पर हमला कर दिया तथा अगस्त में हालैण्ड, बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग में घुस गईं थी । जून 1940 में पेरिस की पराजय के बाद, फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान की इच्छा, तत्काल चीनी-जापानी युद्ध को समाप्त करने की थी, ताकि वह जर्मनी एवं इटली के साथ तालमेल बैठाते हुए अपनी फौजों को उत्तर की ओर सोवियत-संघ के विरुद्ध झोंक सके तथा दक्षिण में दक्षिणी प्रशान्त महासागर में आगे बढ़ सके । इसी योजना के तहत उसने च्याङ काई-शेक गुट को आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने के प्रयास तेज कर दिये । उसने चीन में फूट तथा अनबन के बीज बोए तथा आपसी संघर्षों द्वारा चीन का जापान-विरोधी आंदोलन कमजोर करने की उम्मीद से क्वोमिंताङ तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरम्यान गृहयुद्ध भड़काने का प्रयास किया । जर्मनी, इटली तथा जापान में त्रिपक्षीय संधि संपन्न होने के उपरान्त, ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत-संघ, सभी ने चीन को दी जाने वाली वित्तीय तथा फौजी सहायता में वृद्धि कर दी । इसलिए च्याङ काई-शेक के नेतृत्व में क्वोमिंताङ ने सोचा, चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उनके हक में थी, अतः उनकी कम्युनिस्ट-विरोधी गतिविधियों का न केवल ब्रिटेन तथा अमरीका विरोध नहीं करेंगे बल्कि जापान का समर्थन भी उसे मिल जाएगा। घरेलू मामलों में, कम्युनिस्ट पार्टी की छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाते हुए एकजुटता को तरजीह देकर देश को बचाने की उत्कट अभिलाषा को, उन्होंने पार्टी की कमजोरी समझा । उनका सोचना था कि कम्युनिस्ट उनके साथ खुल्लम-खुल्ला दो फाड़ होने की स्थिति का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे । इसलिए क्वोमिंताङ ने उन्हें परेशान करके मनचाही रियायतें हासिल करने (बातें मनवाने) या फिर उनकी सशस्त्र सेनाओं को एक-एक करके धराशायी

करने की कोशिश की । च्याङ काई-शेक के विचार में, वह समय व्यापक स्तर पर कम्युनिस्ट-विरोध मुहिम के लिए बेहद अनुकूल समय था । इसलिए उसने विशाल पैमाने पर गृहयुद्ध की तैयारी कर ली, क्योंकि उसे आशा थी कि ऐसा करके वह अन्ततः जापान के साथ समझौता कर लेगा ।

अक्तूबर 1940 में क्वोमिंताङ कट्टरतावादियों ने क्वोमिंताङ की फौजी परिषद के नाम से आठवीं राह सेना के प्रधान सेनापति कामरेड चू तेह तथा नई चौथी सेना के सेनापति कामरेड ये थिङ के नाम एक संदेश भेजा, जिसमें दोनों सेनाओं की पीली नदी के दक्षिण में कार्यवाही कर रही सभी यूनिटों को एक महीने के अन्दर-अन्दर पीली नदी के उत्तर में चले जाने का आदेश दिया गया । इसके पीछे उनका मकसद, मध्य चीन से जनता की जापान-विरोधी सशस्त्र सेनाओं को हटाकर जापान के रास्ते का कांटा दूर करना था । इसके साथ ही, वे कूच कर रही जन-सेनाओं पर अप्रत्याशित हमला करने की योजना भी बना रहे थे । इसके जवाब में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने तथा जापान के सामने आत्मसमर्पण करने के गद्दाराना षड्यन्त्र का भण्डाफोड़ किया तथा समूचे देश की जनता को सचेत किया । 9 नवंबर, 1940 को चू तेह, ये थिङ तथा दूसरे साथियों ने क्वोमिंताङ तथा समूचे राष्ट्र के नाम अपने खुले संदेश में स्पष्ट किया : **"देश में कुछ लोग आत्मसमर्पण के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश में एक नए कम्युनिस्ट-विरोधी हमले की साजिश रच रहे हैं।"**[14] लेकिन संयुक्त मोर्चे को टूटने से बचाए रखने के लिए तथा प्रतिरोध-युद्ध में डटे रहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी, नई चौथी सेना की कुछ यूनिटों को याङत्सी नदी के उत्तर में हटाने को सहमत हो गई । पर ज्योंही 4 जनवरी, 1941 को नई चौथी सेना का मुख्यालय 10,000 सैनिकों के साथ उत्तर की ओर बढ़ा, क्वोमिंताङ के 80,000 सैनिकों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया । वे सात दिन और सात रातों तक वीरतापूर्वक लड़ते रहे, परन्तु शत्रु-फौज की संख्या बहुत ज्यादा होने तथा बिना तैयारी की अवस्था में घेर लिये जाने के कारण वे सभी के सभी शहीद हो गए, सिवाय उन एक हजार सैनिकों के, जो शत्रु की घेराबन्दी तोड़ने में कामयाब रहे थे । साथी ये थिङ को बन्दी बना लिया गया तथा साथी श्याङ इङ शहीद हो गए । अपने इस गद्दाराना षड्यन्त्र को कार्यरूप देने के तत्काल बाद, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने नई चौथी सेना को भंग करने की घोषणा करते हुए, उसकी शेष यूनिटों पर हमला करने के सार्वजनिक रूप से आदेश जारी कर दिये ।

ऐसी नाजुक स्थिति में पार्टी ने अपनी केन्द्रीय समिति के नेतृत्व में दृढ़ संघर्ष करने की नीति अपनाई तथा न्यायसंगतता, व्यावहारिकता व संयम के कार्यनीतिक सिद्धान्तों को दक्षतापूर्वक लागू करते हुए जवाबी कार्यवाही करके च्याङ काई-शेक तथा क्वोमिंताङ को मुंहतोड़ जवाब दिया।

पार्टी की केन्द्रीय समिति के क्रान्तिकारी फौजी कमीशन के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें बताया गया कि दक्षिणी आनह्वेइ काण्ड, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के कम्युनिस्ट-विरोधी तथा जापान के सामने आत्मसमर्पण करने के गद्दाराना षड्यन्त्र का मात्र पहला कदम था । उनके अगले कदम इस प्रकार होने थे :

1. याङत्सी नदी के उत्तर में स्थित नई चौथी सेना की यूनिटों पर हमला करना ।
2. आठवीं राह सेना के सरकारी नाम को खत्म कर देना ।
3. शेनशी-कानसू-निङश्या क्षेत्र पर आक्रमण करना तथा येनान पर कब्जा कर लेना ।

जर्मनी तथा इटली के साथ अपने अन्तर्विरोधों के कारण तथा अपनी जनता के दबाव के कारण, ब्रिटेन तथा अमरीका को सोवियत-संघ के साथ मैत्री सन्धि करने को विवश होना पड़ा। जुलाई 1941 में ब्रिटेन तथा सोवियत-संघ के बीच जर्मनी के विरुद्ध इकट्ठे मिलकर कार्यवाहियां करने का समझौता सम्पन्न हुआ । जून 1942 में, अमरीका तथा सोवियत-संघ के बीच, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में, परस्पर सहयोग संबंधी समझौता सम्पन्न हुआ ।

सोवियत सेना ने डट कर मुकाबला किया, शत्रु सेना को थका दिया, उसे गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई तथा उसके साजोसामान पर भी कब्जा कर लिया । पृष्ठभाग में शक्तिशाली रिजर्व सेनाएँ फासिस्ट हमलावरों पर जवाबी आक्रमण करने के लिए तैयार बैठी थीं । अनेक सोवियत शहरों के इर्द-गिर्द खंदकों में जम कर लड़ाई हुई, तथा सर्वाधिक बहादुराना लड़ाइयाँ लेनिनग्राद व मास्को की रक्षा के लिए लड़ी गईं । लाल सेना ने सफलतापूर्वक दोनों शहरों की रक्षा की तथा हिटलर के 'तूफानी हमले' की धज्जियाँ उड़ा दीं ।

8 दिसम्बर, 1941 को जापान ने पर्लहार्बर स्थित अमरीकी नौ-सैनिक अड्डे पर अकस्मात् हमला कर दिया, तथा अनेकों अमरीकी युद्धपोत नष्ट कर दिए । इसके साथ ही, प्रशान्त महासागर क्षेत्र में अमरीकी तथा ब्रिटिश उपनिवेशों पर भी हमला किया गया । प्रशान्त युद्ध आरंभ हो गया ।

प्रशान्त युद्ध के छिड़ने पर अप्रैल 1942 तक, जापान ने क्रमशः अमरीकी कब्जे वाले फिलीपीन, ग्वाम (Guam) व वेक द्वीप समूह पर; ब्रिटिश आधिपत्य वाले हांगकांग, मलाया, सिंगापुर व बर्मा पर; डच ईस्ट इंडीज पर तथा फ्रांसीसी हिन्द-चीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने हमले का रुख भारत तथा आस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया । कुछ ही महीनों में, जापान ने 15 लाख वर्ग किलोमीटर का उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र हथिया लिया था । यह क्षेत्र खूब उपजाऊ तथा कच्चे माल से भरपूर था । इसकी आबादी लगभग 12 करोड़ थी । उसका प्रभाव क्षेत्र पूर्व में मिडवे द्वीप से लेकर पश्चिम में भारत के पूर्वी तट तक, एवं उत्तर में साइबेरियाई सीमा से लेकर, दक्षिण में आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक के विशाल इलाके में फैल गया था । जो उपनिवेश एक सदी से भी अधिक समय से ब्रिटिश, अमरीकी, फ्रांसीसी तथा डच साम्राज्यवादियों के कब्जें में थे, वे सभी अब जापान के नियंत्रण में आ गए थे ।

इस प्रकार प्रशान्त युद्ध के आरंभिक दौर में अमरीका तथा ब्रिटेन को जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा ।

चूँकि फासीवादी ब्लाक को सोवियत-जर्मन युद्ध तथा प्रशान्त-युद्ध में तात्कालिक फौजी बरतरी प्राप्त हो गई थी, अतः जापान चीन में अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहता था ताकि वह विश्व के अन्य भागों में अपनी गतिविधियों को दुस्साहसपूर्वक आगे बढ़ा सके। प्रशान्त युद्ध में चीन को अपना पृष्ठभागीय आधार बनाने के लिए उसने तथाकथित 'सार्वजनिक सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने के लिए मुहिम' को तेज कर दिया ।

इसलिए उसने उत्तरी तथा मध्य चीन के इलाकों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया : *"सुरक्षित इलाके"* (यानि कि अधिकृत इलाके), *"अर्द्ध-सुरक्षित इलाके"* (यानि कि छापामार इलाके) तथा *"असुरक्षित इलाके"* (यानि कि जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र) । अधिकृत इलाकों में, शत्रु खासतौर से *"गाँव-तलाशी"* नीति पर, फासीवादी पाओ-च्या व्यवस्था को मजबूत करने पर, जापान-विरोधी योद्धाओं को समाप्त करने के लिए अनेक गांवों को मिलाकर एक करने पर

नौवां अध्याय

प्रतिरोध-युद्ध की सर्वाधिक नाजुक मंजिल संघर्ष के दौरान शत्रु की पाँतों के पीछे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(जनवरी 1941 से दिसंबर 1942)

1.

- **द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभिक काल में फासिस्ट ब्लॉक की अल्पकालिक फौजी श्रेष्ठता ।**
- **जनता के प्रतिरोध-युद्ध का अत्यधिक नाजुक दौर ।**

सोवियत-संघ सदैव शांति की नीति का पालन करता रहा । द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले उसने विश्व शांति को बनाये रखने के लिए जोरदार प्रयास किए थे तथा ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका तथा अन्य पूँजीवादी देशों का एक नए युद्ध को रोकने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था । लेकिन इन देशों ने सोवियत-संघ के प्रस्ताव को मानने की बजाय, फासीवादी शक्तियों को सोवियत-संघ पर हमला करने के लिए उकसाया । उस वक्त, एकमात्र समाजवादी देश होने के कारण, सोवियत-संघ, अन्य देशों की शांतिप्रिय जनता के समर्थन के बावजूद भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक साम्राज्यवादी युद्ध को रोक सकता ।

सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गया । 1940 से 1941 तक के समय में नाजी जर्मनी ने क्रमशः डेनमार्क, नार्वे, हालैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनान, तथा युगोस्लाविया पर कब्जा कर लिया । अधिकांश यूरोपीय देशों पर निरंकुश आधिपत्य जमाने के बाद, हिटलर ने सोवियत-संघ के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू कर दी ।

गद्दाराना हमला 22 जून, 1941 को शुरू किया गया ।

शुरू में परिस्थितियाँ सोवियत-संघ के प्रतिकूल थीं, अतः लड़ाई के आंरभिक चरण में उसकी धरती का काफी बड़ा हिस्सा जर्मन सेनाओं के कब्जे में चला गया । उक्रेन का काफी ज्यादा हिस्सा छीनने के बाद तथा बेलोरूस, मोलदेविया, लिथुआनिया, लातविया, तथा एस्तोनिया पर कब्जा करने के बाद शत्रु ने दोनबास पर हमला कर दिया, लेनिनग्राद की घेराबन्दी कर दी तथा मास्को पर टूट पड़ा ।

आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए युद्ध के आरंभिक दौर में ही, सोवियत सरकार ने शत्रु के खतरे वाले क्षेत्रों में से अनेक बड़े-बड़े उद्यमों को अपने पृष्ठभाग में स्थानांतरित कर दिया था, तथा पूर्वी क्षेत्रों में शक्तिशाली औद्योगिक आधार-क्षेत्र स्थापित कर दिए थे । फासिस्ट

4. देश भर में जापान का प्रतिरोध करने वाले लोगों को भारी तादाद में गिरफ्तार करना तथा जापान-विरोधी आन्दोलन को कुचल देना ।

5. और अन्ततः समूचे देश में सभी कम्युनिस्ट संगठनों को तहस-नहस कर देना ।

क्वोमिंताङ का सोचना था कि इन प्रतिक्रियावादी कार्यवाहियों के बदले जापान ने मध्य तथा दक्षिणी चीन से पीछे हटने का आश्वासन देना था तथा इन क्षेत्रों को क्वोमिंताङ सेना के हवाले कर देना था; इसके साथ ही जापान ने अपनी सेना को उत्तर में आठवीं राह सेना के विरुद्ध केन्द्रित कर लेना था । यह सब कुछ हो जाने के बाद, क्वोमिताङ ने धुरी शक्तियों के कम्युनिस्ट-विरोधी गठजोड़ में शामिल होने के फैसले की घोषणा कर देनी थी । पार्टी की केन्द्रीय समिति ने कट्टरतावादियों के इस खतरनाक षड्यन्त्र का भण्डाफोड़ किया तथा समूचे देश का इसे रोकने हेतु आह्वान किया ।

20 जनवरी, 1941 को पार्टी की केन्द्रीय समिति के क्रान्तिकारी फौजी कमीशन के आदेश द्वारा कामरेड छन ई को नई चौथी सेना का कार्यवाहक कमांडर, साथी चाङ युन-ई को डिप्टी कमांडर तथा साथी तङ ची ह्वेइ को राजनीतिक विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया। नई चौथी सेना के मुख्यालय को दोबारा स्थापित किया तथा उसकी कमान में अब 90,000 सिपाही थे, जिन्हें सात डिवीजनों में पुनर्गठित किया गया था । उन्हें मध्य तथा पूर्वी चीन में जापानी हमलावरों से लोहा लेना था ।

इन क्रान्तिकारी कदमों ने क्वोमिंताङ कट्टरपंथियों की हमले की योजना को खटाई में डाल दिया । नई चौथी सेना की मुख्य सैन्य-शक्ति दक्षिणी आनह्वेइ कांड से पहले की अपेक्षा और अधिक सुदृढ़ तथा और ज्यादा विकसित हो गई ।

कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा च्याङ काई-शेक तथा क्वोमिंताङ की प्रति-क्रान्तिकारी नीति के प्रति अपनाए दृढ़ रवैये ने क्वोमिंताङ के कट्टरपंथियों को उस खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो राष्ट्र के पूरी तरह दो-फाड़ हो जाने की दशा में उनके ऊपर आने वाला था ।

दक्षिणी आनह्वेइ काण्ड के बाद, क्वोमिंताङ के जनवादी हिस्से ने च्याङ को उसकी प्रतिक्रियावादी गतिविधियों के लिए आड़े हाथों लिया । यही वह समय था, जब जनवादी राजनीतिक ग्रुपों की लीग का गठन हुआ । कुछ क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली गुट भी च्याङ काई-शेक की सभी "दुश्मन" तत्वों को नष्ट करने की नीति से असंतुष्ट हो गए । यहां तक कि कट्टरवादियों की अपनी पाँतों में भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे । देशभर में मध्यवर्तियों का विशाल बहुमत तथा प्रगतिशील लोग, च्याङ काई-शेक की प्रतिक्रियावादी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट हो गए थे ।

अमरीका तथा ब्रिटेन की जनता ने भी इस काण्ड के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन दोनों देशों की सरकारें भी नहीं चाहती थीं कि क्वोमिंताङ गृहयुद्ध शुरू कर दे तथा जापान के खिलाफ प्रतिरोध-युद्ध को शिथिल कर दे । फिर सोवियत-संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली सहायता तथा उसका रवैया एक और महत्त्वपूर्ण तत्व था जिसने कट्टरवादियों को सावधानीपूर्वक सोचने पर मजबूर कर दिया ।

दक्षिणी आनह्वेइ घटना के बाद, जापान ने क्वोमिंताङ को आत्मसमर्पण के लिए विवश करने का प्रयास किया, परन्तु उसे तत्काल कोई सफलता नहीं मिली । इस प्रकार जापान तथा

क्वोमिंतांङ के बीच का अन्तर्विरोध अनसुलझा ही रहा । क्वोमिंतांङ द्वारा कम्युनिस्टों के दमन के लिए मध्य चीन में भेजी गई फौजों को, जापानी सेना ने अपनी "सफाया" मुहिम का निशाना बना डाला ।

घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने कट्टरवादियों को कुछ समय के लिए अपनी कम्युनिस्ट-विरोधी मुहिम में ढील देने को मजबूर कर दिया । दक्षिणी आनह्वेइ की घटना के बाद च्याङ काई-शेक अपनी खुद की स्थिति के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने एक बार फिर से दोगली चाल चली । उसने "राष्ट्रीय सुरक्षा" तथा "विदेशी शत्रु से निपटने" की रट लगाई तथा दलगत एवं पक्षपाती राजनीति को बीते समय की बात होने का प्रचार किया । उसका इरादा एक राजनीतिक षड्यन्त्र करने का था और इसके लिए उसने किसी पार्टी या ग्रुप की तरफदारी न करने वाले राष्ट्रीय नेता का स्वांग भरा ।

इस कम्युनिस्ट विरोधी बगावत की पराजय, चीन की घरेलू राजनीतिक परिस्थिति में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । इससे जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में शामिल विभिन्न वर्गों की ताकत में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ—एक ऐसा परिवर्तन हुआ जो जनता के प्रतिरोध आन्दोलन के लिए लाभदायक था । ●

नोट

1. **दस-सूत्री कार्यक्रम** :- यह इस प्रकार था :
   - ❑ जापानी साम्राज्यवाद का तख्ता पलट दो !
   - ❑ समूचे देश की फौजी शक्ति को गोलबंद करो !
   - ❑ समूचे देश की जनता को गोलबंद करो !
   - ❑ सरकारी ढाँचे में सुधार करो !
   - ❑ जापान-विरोधी विदेश नीति अपनाओ !
   - ❑ युद्धकालीन वित्तीय व आर्थिक नीतियां लागू करो !
   - ❑ जनता के रहन-सहन में सुधार करो !
   - ❑ जापान-विरोधी शिक्षा नीति को अपनाओ !
   - ❑ पृष्ठभागों को सुदृढ़ करो व देशद्रोहियों और जापानपरस्त तत्वों का सफाया कर दो!
   - ❑ जापान के खिलाफ राष्ट्रीय एकता कायम करो !

(विस्तृत जानकारी के लिए देखें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, पेकिङ, पहला संस्करण-1973, पृष्ठ-25 से 30 तक)

2. **राजनीति-विज्ञान ग्रुप** :- यह एक अत्यधिक दक्षिणपंथी राजनीतिक गुट था जिसे 1916 में उन अफसरशाहों तथा राजनेताओं द्वारा स्थापित किया गया था, जो सरकार में ऊँचे ओहदे पाने के लिए उत्तरी गुट तथा दक्षिणी गुट के युद्ध-सरदारों के बीच राजनीतिक सट्टेबाजी करते रहते थे । सन् 1926 से 1927 के उत्तरी अभियान के दौरान इस ग्रुप का एक हिस्सा च्याङ काई-शेक की तरफ चला गया था तथा उसने अपने प्रतिक्रियावादी राजनीतिक अनुभव के आधार पर च्याङ काई-शेक के प्रतिक्रान्तिकारी शासन को सुदृढ़ करने में मदद की ।

3. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1973, पृष्ठ संख्या-200

4. —वही—पृष्ठ संख्या-260-61

5. —वही—पृष्ठ संख्या-279
6. —वही—पृष्ठ संख्या-326
7. —वही—पृष्ठ संख्या-331
8. —वही—पृष्ठ संख्या-290-91

9. **पाओ-च्या प्रणाली** :- यह एक ऐसी प्रणाली थी जो सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित थी, प्रशासनिक इकाइयों की शृंखला में यह निम्नतम कड़ी के रूप में थी तथा इसके द्वारा क्वोमिंतांङ गुट अपना फासीवादी शासन कायम रखे हुए था । 1 अगस्त, 1932 को च्याङ काई-शेक ने हनान, हपे तथा आनह्वेइ प्रान्तों के लिए *"पाओ तथा च्या को संगठित करने, तथा काउंटियों में जनगणना करने के लिए अधिनियम"* जारी किया जिसके अनुसार, "पाओ तथा च्या का गठन घरों के आधार पर होना था; तीनों में से प्रत्येक—यानि कि घर, च्या (दस घरों को मिलाकर एक च्या बनता था) तथा पाओ (दस च्या से एक पाओ बनता था)—का अपना-अपना एक मुखिया होना था ।" अधिनियम के अनुसार पड़ोसियों को एक-दूसरे पर नजर रखनी थी तथा एक-दूसरे की गतिविधियों की रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुँचानी थी । किसी एक के दोषी पाये जाने पर सभी को सजा मिलती थी। इसके अतिरिक्त, इन कानूनों की आड़ में लोगों से जबरदस्ती बेगार भी करवाई जाती थी । 7 नवंबर, 1934 को क्वोमिंतांङ सरकार ने सरकारी तौर पर घोषणा की कि इस फासीवादी व्यवस्था को उसके शासन के तहत आने वाले सभी प्रान्तों तथा नगरपालिकाओं में लागू किया जाना था ।

10. **मौत से न डरने वाली जापान-विरोधी पलटन** :- ये शानशी की जनता की सशस्त्र सेनाएं थीं, जो जापान-विरोधी युद्ध के शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव तथा मार्गदर्शन में विकसित हुई थीं ।

11. **आत्म-बलिदानी लीग** :- यह एक स्थानीय संगठन था जिसने पार्टी के साथ निकट सहयोग कायम करते हुए शानशी में जापानी हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में विशेष भूमिका निभाई।

12. **कमालवाद** :- कमाल (1881-1938) तुर्की के सौदागर पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था । 1922 में, तुर्की की जनता ने सोवियत-संघ की मदद से यूनानी हमलावरों को पराजित कर दिया था, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उकसाया था तथा 1923 में कमाल को तुर्की का राष्ट्रपति चुना गया। कामरेड स्तालिन ने सुन यात-सेन विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करते हुए कहा था, **"कमालवादी क्रान्ति, विदेशी साम्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान उठ खड़ी हुई उच्च श्रेणियों की क्रान्ति है, राष्ट्रीय सौदागर पूँजीपति वर्ग की क्रान्ति है, जिसका आगे का विकास निश्चित रूप से किसानों व मजदूरों के विरुद्ध, तथा कृषि-क्रान्ति की हर संभावना के विरुद्ध होने वाला है ।"** (देखिए—जोसेफ स्तालिन, चीनी क्रान्ति के बारे में)

13. **तीन मार्गदर्शक सिद्धान्त** :- "न्यायोचित आधार पर" के सिद्धान्त का अर्थ था—किसी उद्देश्य या न्यायोचित आधार के बिना कभी न लड़ना । दूसरे शब्दों में, केवल आत्मरक्षा के लिए लड़ना तथा हमला करने में कभी पहल न करना, परन्तु जब दूसरे हमला करें तो जवाबी हमला करने में कभी न चूकना । विजय सुनिश्चित करने के लिए "व्यावहारिकता" का होना जरूरी था। इसका अर्थ था जवाबी हमलों की योजना इतने सटीक ढंग से बनाना तथा सैन्य-शक्तियों को इतने सही ढंग से व्यवस्थित करना कि हर मुठभेड़ के नतीजे तथा विजय के बारे में पूरी गारंटी हो जाए । "संयम" का सिद्धान्त, युद्ध-विराम का सिद्धान्त था । क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादियों को पीछे धकेलने के बाद तथा उनके दोबारा हमला शुरू करने से पहले, अत्यधिक अनुकूल समय देखते हुए लड़ाई बंद कर देनी थी।

14. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1973, पृष्ठ-818

●●●

संस्करण-1975, पृष्ठ-56

3. —वही—पृष्ठ-50,51

4. **पहाड़ी दुर्ग प्रवृति** :- चूंकि शुरू में अधिकांश आधार-क्षेत्र अलग-थलग पहाड़ी इलाकों मे स्थापित किए गए थे, अतः पार्टी सदस्य अपने आपको, स्वाभाविक तौर पर एक अलग गुट में बांध लेते थे और गुटीय रुझान की इस गलत प्रवृत्ति का नाम "पहाड़ी दुर्ग प्रवृत्ति" पड़ गया ।

5. **अष्टपदी निबन्ध** :- यह 15वीं सदी से 19वीं सदी तक चीन के सामन्ती राजवंशों के शासन-काल में होने वाली राजकीय परीक्षाओं के लिए निर्धारित निबन्ध का एक विशेष रूप था । रचना की दृष्टि से, इस प्रकार के निबन्ध के आठ भाग होते थे : प्रस्तावना, परिवर्धन, प्रारम्भिक व्याख्या, प्रारम्भिक तर्क, प्रारम्भिक पैरा, मध्यवर्ती पैरा, उत्तरवर्ती पैरा और अन्तिम पैरा । "प्रस्तावना" में दो वाक्यों से शीर्षक का मुख्य अर्थ बताया जाता था । "परिवर्धन" में तीन या चार वाक्यों से प्रस्तावना में बताए गए मुख्य अर्थ की व्याख्या की जाती थी । "प्रारम्भिक व्याख्या" में पूरे निबन्ध की संक्षिप्त व्याख्या की जाती थी और यह व्याख्या की शुरूआत थी । "प्रारम्भिक तर्क" में प्रारम्भिक व्याख्या के बाद प्रारम्भिक तर्क पेश किया जाता था। प्रारम्भिक पैरा, मध्यवर्ती पैरा, उत्तरवर्ती पैरा और अन्तिम पैरा इन चार भागों में विषय की सांगोपांग व्याख्या की जाती थी । इनमें मध्यवर्ती पैरा पूरे निबन्ध का केन्द्र होता था । पाँचवें से आठवें भाग तक प्रत्येक के दो हिस्से अर्थात विपरीत भाव वाले दो हिस्से अवश्य होते थे । इसलिए इसका नाम "अष्टपदी निबन्ध" पड़ गया ।

6. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-3, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1975, पृष्ठ-197 से 208 तक ।

7. —वही—पृष्ठ-235 से 244 तक ।

8. —वही—पृष्ठ-275 से 292 तक ।

9. —वही—पृष्ठ-337 से 350 तक ।

10. **"तीन तरह का सफाया करने" की नीति** :- यह नीति जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा चीन के मुक्त क्षेत्रों में चलाई गई "सब कुछ जला डालने, सबको मार डालने और सब कुछ लूट लेने" की नृशंस नीति थी ।

●●●

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तकार नहीं माना जा सकता बल्कि उसे कठमुल्लावादी ही कहा जाएगा, यदि वह मार्क्सवादी साहित्य में से कुछ निष्कर्षों तथा सिद्धान्तों को दोहराता भर है तथा आँखों के ठीक सामने खड़ी चीन की असली समस्याओं को नजरअन्दाज कर देता है ।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन का उद्देश्य उसमें दक्षता प्राप्त करना तथा उसे व्यवहार में इस्तेमाल करना है । इस काम के लिए यह जरूरी है कि चीनी क्रांति के कार्यान्वन से उभरी समस्याओं को सही तौर से हल करना तथा चीनी इतिहास में समस्याओं का अध्ययन, मार्क्सवादी रुख, दृष्टिकोण तथा तरीके के अनुसार करना सीखा जाए । मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन के मामले में पार्टी द्वारा जो रवैया अपनाया जाना चाहिये, उसे साथी माओ ने प्रतीकात्मक रूप से "निशाना साधकर तीर चलाने" की संज्ञा दी ।

मनोगतवाद पर काबू पाने के लिए किताबी ज्ञान रखने वालों को व्यवहार से सीखने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे स्वयं को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें या कठमुल्लावाद की गलती में न फंसें; जबकि व्यावहारिक अनुभव रखने वालों को सैद्धांतिक अध्ययन करने को प्रेरित किया गया, ताकि वे अपने अनुभव को सैद्धान्तिक स्तर तक ऊँचा उठा सकें तथा अनुभववाद की गलतियों से बचे रहें ।

2. पार्टी की कार्यशैली में सुधार करो—संकीर्णतावाद का विरोध करो ।

निम्न-पूँजीपति वर्ग की संकीर्ण मनोवृत्ति न केवल विचारधारा में मनोगतवाद के रूप में प्रकट हुई, बल्कि राजनीतिक जीवन तथा संगठनात्मक मामलों में भी संकीर्णतावाद के रूप में प्रकट हुई । एक सच्चे अर्थों में एकताबद्ध तथा सुदृढ़ पार्टी के निर्माण के लिए, सबसे पहले विचारधारा में मनोगतवाद का विरोध करना जरूरी था ताकि पार्टी में मार्क्सवाद के नेतृत्व को स्थापित तथा मजबूत किया जा सके । इसके साथ ही, संगठनात्मक मामलों में संकीर्णतावाद के विरुद्ध संघर्ष करना भी जरूरी था । यद्यपि दोष-निवारण मुहिम के वक्त पार्टी में संकीर्णतावाद की प्रभुत्वकारी भूमिका न थी, तथापि इसके अवशेष अब भी मौजूद थे, जैसे उदाहरण के लिए "कार्यवाही की आजादी" पर जोर देना तथा सबसे बढ़कर—**"पर्वतीय दुर्ग प्रवृत्ति"**[4] जो कि विभिन्न आधार-क्षेत्रों के लंबे समय तक एक-दूसरे से अलग-थलग रहने के कारण तथा पार्टी में निम्न-पूँजीपति वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण थी।

पार्टी के नेतृत्वकारी संगठनों को समूची पार्टी की इच्छा को केन्द्रीकृत करने वाले समझने की बजाय, कुछ सदस्यों ने पार्टी के अन्दर अपने सम्बन्धों में संकीर्णतावाद का प्रदर्शन किया, जिससे पार्टी की एकता तथा भाईचारे को ठेस पहुँची तथा पार्टी के नेतृत्वकारी संगठनों का पार्टी सदस्यों से अलग-थलग पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया । पार्टी में एकता तथा भाईचारे का आधार क्या होना चाहिये था ? सैद्धान्तिक स्तर पर इसे सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का नेतृत्व होना चाहिए था; पार्टी की कार्यदिशा तथा कार्यनीति मार्क्सवाद पर आधारित होनी चाहिए थी, क्योंकि केवल सर्वहारा विचारधारा ही समूची पार्टी तथा समूचे राष्ट्र के संकल्प को साकार रूप दे सकती थी । संगठनात्मक स्तर पर, पार्टी के, जनवादी केन्द्रीयतावाद के सिद्धान्त का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी था । इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य को किसी भी प्रकार के फैसले होने से पहले, पार्टी के कार्यक्रमों तथा नीतियों पर आजादी से तथा खुलकर चर्चा करने का अधिकार था । फिर पार्टी सभी प्रकार के सुझावों तथा रायों को केन्द्रित करती थी तथा फैसले लेती थी । जनवादी आधार पर लिए गए ये निर्णय भारी बहुमत की राय का प्रतिनिधित्व करते

थे । एक बार एक निर्णय हो जाने पर अल्पमत को बहुमत के अधीन, निम्न-स्तर को उच्च-स्तर के अधीन, अंश को संपूर्ण के अधीन तथा समूची पार्टी को केन्द्रीय समिति के अधीन रखने के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रत्येक को उस निर्णय का पालन करना होता था । यद्यपि प्रत्येक सदस्य को अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार था, पर उसे लिये गए निर्णयों को दृढ़तापूर्वक लागू करना होता था ।

इसके अतिरिक्त, कार्यकर्ताओं के दरम्यान सही आपसी संबंध कायम करने जरूरी थे । चूंकि पार्टी सदस्य विभिन्न समय पर, विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग तरह के क्रान्तिकारी कार्यभार हाथ में लेते थे, अत: पुराने तथा नए कार्यकर्ताओं के बीच, किसी इलाके के स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा उस इलाके में बाहर से आए कार्यकर्ताओं के बीच, सेना के कार्यकर्ताओं तथा असैनिक कार्यकर्ताओं के बीच तथा विभिन्न विभागों तथा इलाकों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर समस्याएं उठ खड़ी हुईं । इन सभी कार्यकर्त्ताओं के दरम्यान सही आपसी संबंध स्थापित करना बेहद जरूरी हो गया था । उन्हें अपनी खुद की कमजोरियों को दूर करने के लिए एक-दूसरे से तथा एक-दूसरे की खूबियों से सीखना था, ताकि समूची पार्टी तथा क्रान्तिकारी पाँतों के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके, संकीर्णतावाद के अवशेषों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके तथा संगठन में एकता को सुनिश्चित किया जा सके ।

गैर पार्टी लोगों के साथ पार्टी के संबंधों में संकीर्णतावाद के अवशेष इस तथ्य से प्रकट हुए कि पार्टी सदस्यों का एक तबका गैर पार्टी लोगों के सामने शेखी बघारने का आदी था तथा जो लोग पार्टी के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, उन्हें हिकारत की नजर से देखता था, अथवा उन्हें दूर ही रखता था तथा उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करने से इन्कार करता था । जहाँ तक उन लोगों का संबंध था जो पार्टी के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, या जिन द्वारा सहयोग करने की पूरी संभावना थी, उनके प्रति पार्टी सदस्यों का यह कर्त्तव्य बनता था कि वे उनके साथ पूरा सहयोग करें तथा ऐसे लोगों को दूर रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अन्यथा वे जनता के हितों तथा उसकी इच्छा को केन्द्रीकृत करने वाले प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के कार्यभार की अवहेलना कर रहे होते । यह अवहेलना उन्हें जनता से अलग-थलग कर देती तथा पार्टी की कार्यदिशा को लागू करने में बाधक बन जाती ।

3. साहित्यिक लेखन के ढंग में सुधार—"अष्टपदी निबन्ध"[5] या घिसे पिटे पार्टी-लेखन का विरोध करो ।

पार्टी में "अष्टपदी लेखन" कैसे शुरू हुआ ?

सामंती चीन में "अष्टपदी लेखन" एक प्रकार की साहित्यिक कलाबाजी थी जो विषय की अन्तर्वस्तु की कीमत पर उसकी शैली को अधिमान देती थी । यह कठमुल्लावादी तथा बेहद आडंबरपूर्ण थी । 4 मई आन्दोलन ने कठमुल्लावाद व "अष्टपदी लेखन" का विरोध करते हुए, स्वयं के प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी होने का परिचय दिया । चीनी मार्क्सवादियों ने आन्दोलन की आलोचनात्मक प्रवृत्ति को विरासत में ग्रहण किया, मार्क्सवाद के आधार पर इसका रूपान्तर किया तथा एक सजीव तरोताजा एवं सशक्त मार्क्सवादी साहित्यिक शैली को जन्म दिया । लेकिन पूँजीपति तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग के बुद्धिजीवियों ने दूसरा रास्ता पकड़ा तथा पुराने "अष्टपदी लेखन" का विरोध करते हुए उन्होंने समस्याओं के प्रति एक आडंबरपूर्ण तथा प्राचीन रवैया अपनाया एवं इस प्रकार अपनी तरफ से एक नये विदेशी "अष्टपदी लेखन"

पकड़ने व कठपुतली संस्थाओं को नष्ट करने के लिए घुस जाते थे । इसके अतिरिक्त, शत्रु-नियंत्रित क्षेत्रों में भूमिगत मिलिशिया सेनाएँ भी थीं । ये या तो अत्यधिक गुप्त संगठनों के रूप में कार्य करती थीं या फिर शत्रु या कठपुतली संस्थाओं की आड़ में कार्य करती थीं, जिनमें उन्होंने पहले से ही घुसपैठ की होती थी । उनका काम शत्रु एजेन्टों तथा देशद्रोहियों में से अत्यधिक कुख्यात को प्राणदण्ड देकर उन्हें चेतावनी देना, शत्रु के बारे में सूचना एकत्र करना, जनसभाएँ आयोजित करना, वगैरा-वगैरा था । वे शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिए भेजे गए सशस्त्र कार्यवाही-दलों के साथ मिलकर जापान-विरोधी गतिविधियाँ करती थीं। शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिए ठिकाने स्थापित करने, जनता का साहस बनाए रखने तथा शत्रु एवं कठपुतलियों को हैरान-परेशान करने में भूमिगत मिलिशिया की प्रधान भूमिका थी । यह भूमिगत मिलिशिया तथा सशस्त्र कार्यवाही-दलों की बदौलत ही था कि शत्रु पंक्तियों के पीछे पूर्ण छद्मावरण से सुसज्जित जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित किए जा सके ।

4. उत्पादन-अभियान में मिलिशिया की भूमिका ।

शत्रु की "तीन तरह का सफाया करने" की नीति को विफल करने के लिए, जनता की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के अलावा जनता का बोझ कम करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना भी जरूरी था । शत्रु के पृष्ठभाग में संघर्ष के दौरान मिलिशिया के जवानों ने उत्पादन की ओर भी उतना ही ध्यान दिया, जितना कि लड़ाई की ओर । उन्होंने स्थानीय मेहनतकश जनता के साथ मिलकर परस्पर सहयोग-दल बनाए । उनके लड़ाई के दौरान के समय को कार्यदिवसों के रूप में गिना जाता था । जब लड़ाई नहीं हो रही होती थी, तब वे दलों के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करते थे ।

शत्रु-पंक्तियों के पीछे युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के लिए मिलिशिया जवानों ने और भी कई कदम उठाए : 1. उन्होंने **"हर नागरिक एक सैनिक है"** के नारे के तहत परस्पर सहयोग दलों के हर सदस्य को बारूदी सुरंगें बिछाना सिखाया । 2. युद्ध तथा उत्पादन के लिए सांझे कमान मुख्यालय स्थापित किए गए, तथा इस प्रकार दोनों को एक ही संगठनात्मक नेतृत्व के अधीन करके एकताबद्ध कर दिया गया । 3. भौगोलिक तथा रणनीतिक जरूरतों के अनुसार अनेक गाँवों की संयुक्त सुरक्षा पंक्तियाँ निर्मित की गईं । इन गाँवों के मिलिशिया जवानों ने आपस में एक समझौता सम्पन्न किया, जिसके तहत किसी एक गाँव पर शत्रु का हमला होने की, स्थिति में, अन्य गाँव एकजुट हमला करने के लिए अपनी कुमुक भेजते थे ।

जापान-विरोधी युद्ध में शुरू से लेकर अन्त तक नियमित तथा छापामार सेनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ते हुए, मिलिशिया तथा जनता के आत्मरक्षा दलों ने जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करने तथा जापानी हमलावरों को पराजित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । ●

नोट

1. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, पेकिङ, पहला संस्करण-1973, पृष्ठ-752

2. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-3, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, पेकिङ, पहला

मिलता था ।

मिलिशिया ने बारूदी सुरंगें बिछाने के काम में महारत हासिल की । शत्रु की "सफाया" मुहिमों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में, उन्होंने शत्रु के आगे बढ़ने के रास्ते पर सब जगह बारूदी सुरंगें बिछा दीं । सीमाओं पर या आधार-क्षेत्रों के केन्द्रीय भागों में, सड़कों पर या गाँवों के प्रवेश-द्वारों पर, पहाड़ों की चोटियों पर या फिर खाइयों में, जहां कहीं भी शत्रु ने कदम रखा, उसे अपने सिर पर मौत मंडराती दिखाई दी ।

2. "कुतरने" की मुहिमों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों में मिलिशिया की भूमिका ।

शत्रु की "कुतरने" की नीति का मतलब, परिवहन पंक्तियों, किलेबन्दियों, खाइयों तथा दीवारों का जाल बिछाकर, जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों को अलग-अलग टुकड़ों में काट देना तथा फिर इस प्रकार अलग-थलग किए गए क्षेत्रों में "तलाशी" तथा "सफाया" कार्यवाहियां करना था । अतः इसका मुकाबला करने के लिए, शत्रु के सभी परिवहन, संचार तथा अलग करने के साधनों को नष्ट करना अत्यधिक जरूरी था ।

मिलिशिया के सहयोग से नियमित सेना द्वारा व्यापक पैमाने पर लड़ाइयाँ लड़ी गईं । नियमित सेना शत्रु के ठिकानों पर हमला करके उसे रोके रखती थी, जबकि मिलिशिया शत्रु की परिवहन व संचार-पंक्तियों को नष्ट कर रही जनता को सुरक्षा कवच प्रदान करती थी ।

मैदानी इलाकों में, मिलिशिया ने सड़कों को खोदकर उन्हें खाइयों में बदल देने में लोगों का नेतृत्व किया तथा इस प्रकार सारे इलाके का भूगोल ही बदल कर रख दिया । खाइयां द्रुत गति से आगे बढ़ रही शत्रु फौजों को रोक देती थीं तथा आधार-क्षेत्रों की फौजों तथा जनता को इधर-उधर आने-जाने में सुरक्षा प्रदान करती थीं । इस प्रकार शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में शत्रु की परिवहन व संचार-पंक्तियों को नष्ट करने के लिए खाइयां खोदना मिलिशिया का मुख्य कार्यभार बन गया ।

सुरंगों की लड़ाई खाइयों की लड़ाई से ज्यादा सख्त थी । मैदानी क्षेत्रों में सुरंगें, गाँवों, जिलों तथा काउंटियों को जोड़ती थीं तथा इस प्रकार जमीन के नीचे परिवहन पंक्तियों का एक जाल सा बिछ गया था जिसके जरिये, जनता व सेना, शत्रु की नजरों में आए बगैर, इधर उधर आवाजाही करती थीं । पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ियों के बीच सुरंगें खोदी गईं । यह जनता की शक्ति और कौशल का ही कमाल था, जिसने इतनी लम्बी सुरंगों के निर्माण को संभव बनाया।

शत्रु ने बहुत बड़ी संख्या में फौजी दुर्ग बनाकर आधार-क्षेत्रों को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह सब उसके किसी काम न आया । इन फौजी दुर्गों की जापान-विरोधी सशस्त्र सेनाओं द्वारा घेराबंदी कर ली गई । शत्रु द्वारा आधार-क्षेत्रों में घुसने की हर कोशिश को तत्काल नाकाम कर दिया गया । शत्रु की घेराबंदी के दौरान मिलिशिया बाहरी सैन्य-पंक्ति से भीतरी सैन्य-पंक्ति पर आ जाती थी तथा जब तक शत्रु को खदेड़ बाहर न कर दिया जाता, उसे हैरान-परेशान करती रहती थी।

3. "गाँव तलाशी" का मुकाबला करने के अभियान में मिलिशिया की भूमिका।

"गाँव तलाशी" मुहिम का मुकाबला करने के अभियान में मुख्य रणनीति शत्रु-पंक्तियों के पीछे गहराई तक घुसपैठ करने की थी । मिलिशिया की लड़ाका-शक्ति में लगातार वृद्धि होने के कारण, मिलिशिया के जवान, शत्रु-नियंत्रित क्षेत्रों में शत्रु एजेन्टों तथा देशद्रोहियों को

को विकसित कर दिया । बहुत से मार्क्सवादियों ने भी जो मजबूती से मार्क्सवाद पर डटे रहने में विफल रहे, इस आडंबरवाद को अपनाने की गलती की तथा अष्टपदी पार्टी लेखन को विकसित किया । क्रांतिकारी सांस्कृतिक संगठनों में इन साहित्यिक शैलियों की लगातार उपस्थिति ने समूची पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया ।

घिसा-पिटा पार्टी लेखन मनोगतवाद तथा संकीर्णतावाद की अभिव्यक्ति था । जिन लोगों को इस शैली की लत पड़ गई थी वे अपने लेखों में आसानी से हजम न होने वाली क्रान्तिकारी शब्दावली तथा मुहावरों का ढेर लगा देते थे, तथा इन लेखों में न तो समस्या उठाई जाती थी, और न ही उसका कोई विश्लेषण किया जाता था या हल ढूंढ़ा जाता था । इसलिए घिसा-पिटा पार्टी लेखन क्रान्तिकारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उचित माध्यम होने की बजाय, उनका गला घोंट रहा था ।

लिखने और बोलने में मार्क्सवादी तरीके का इस्तेमाल करना सीखना जरूरी था । प्रक्रिया यह होनी थी--पहले विषयों के अंतर्विरोधों में समस्याओं की खोज करना, फिर इन समस्याओं को एक सावधानीपूर्ण एवं बकायदा विश्लेषण तथा संश्लेषण की कसौटी पर कसना, उनकी प्रकृति को परिभाषित करना तथा उन्हें हल करने के तरीके सुझाना । खोखली बातों से बेहिसाब पृष्ठ रंग देने का, मुद्दों का सतही विश्लेषण करने का, शुष्क तथा नीरस शैली के प्रयोग का, "अन्धाधुन्ध तीर चलाने का," तथा लोगों को आडम्बरपूर्ण भाषा द्वारा बेवकूफ बनाने का विरोध करना जरूरी था । केवल एक मार्क्सवादी साहित्यिक विधा ही मार्क्सवाद का प्रचार-प्रसार कर सकती थी, लोगों को प्रेरित कर सकती थी तथा इस प्रकार जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ा सकती थी ।

दोष-निवारण मुहिम के दौरान अध्ययन का जो तरीका अपनाया गया, वह था--पहले कुछ मुख्य मार्क्सवादी-लेनिनवादी रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया जाए, उनके सारतत्व को आत्मसात करके तथा उन्हें एक मापदण्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी विचारधारा तथा कार्य की गंभीर तथा व्यावहारिक आलोचना व आत्मालोचना की जाए । अगला कदम था--इस बात का विश्लेषण करना कि सही क्या था, गलत क्या था; अपनी गलतियों के कारणों, परिस्थिति-जनित हालातों तथा सामाजिक जड़ों को ढूँढ़ना, तथा उन गलतियों को सुधारने के कारगर उपाय करना ।

पार्टी की चिरकाल से चली आ रही समस्याओं के अध्ययन के लिए भी इसी प्रकार का तरीका अपनाया गया । पहले तो बहुत सी मुख्य मार्क्सवादी-लेनिनवादी रचनाओं का अध्ययन किया गया; फिर इन रचनाओं के सारतत्व को मार्गदर्शक सिद्धान्त मानते हुए पार्टी के उन ऐतिहासिक दस्तावेजों की आपस में तुलना की गई जिनमें सही नीतियां प्रस्तुत की गई थीं, तथा जिनमें गलत नीतियाँ प्रस्तुत की गई थीं ।

चूंकि दोष-निवारण मुहिम एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी शैक्षिक मुहिम थी, अतः पार्टी की नीति थी कि जिन लोगों ने अपने कार्यभार में अज्ञानतावश गलतियाँ की थीं, उनकी सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए । अनुशासनिक कदम कभी-कभार ही उठाए जाते थे । दूसरे शब्दों में, पार्टी ने *"विचारों को स्पष्ट करने तथा सौहार्दपूर्ण भाईचारा बनाए रखने"* और *"भविष्य में गलतियों से बचने के लिए भूतकाल के अनुभव से सीखने एवं बीमार को बचाने के लिए बीमारी को खत्म करने"* की नीतियाँ अपनाईं । "भविष्य में गलतियों से बचने के लिए

भूतकाल के अनुभव से सीखने'' की नीति का अभिप्राय यह था कि सभी भ्रान्तिपूर्ण विचारों का पर्दाफाश किया जाए, तथा फिर ''तथ्यों द्वारा सच्चाई का पता लगाने'' के वैज्ञानिक ढंग से उनका विश्लेषण तथा आलोचना की जाए ताकि कूड़ा-कर्कट हटने के बाद, सम्बंधित व्यक्ति अपने सैद्धान्तिक स्तर को ऊँचा उठा सके, अधिक सावधान रहे तथा भविष्य में अपना काम बेहतर ढंग से कर सके । ''बीमार को बचाने के लिए बीमारी का इलाज करने'' से अभिप्राय था—पार्टी सदस्यों में भाईचारा बनाए रखने के लिए ईमानदार प्रयास करना । गैर सर्वहारा मूल के उन सभी साथियों के सैद्धान्तिक स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता की जानी चाहिए थी जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पहले के रुख का परित्याग कर दिया था, सर्वहारा-वर्ग के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था व पार्टी में शामिल हो गए थे । जिन्होंने गलतियां की थीं, उनके ऊपर भी व्यक्तिगत आक्षेप करने का रवैया नहीं अपनाना था । इसके बजाय, जब तक वे जानबूझकर गलती पर गलती करने पर आमादा न होते, उनकी गलतियों को ठीक करने में मदद करनी थी । सैद्धान्तिक समस्याओं से निपटने के लिए तथा गलतियाँ करने वाले लोगों को सुधारने के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति ही एकमात्र सही नीति थी तथा यह एक अत्यधिक मूल्यवान अनुभव भी था ।

1942 में शुरू की गई पार्टी की पहली दोष निवारण मुहिम ने, पार्टी में सन 1931 से मौजूद कठमुल्लावाद के प्रभावों का सफाया कर दिया, निम्न-पूँजीपति वर्ग से आए बहुत से नए पार्टी-सदस्यों की, अपने पहले के रुख को त्यागने में मदद की, पार्टी के सैद्धांतिक स्तर को बहुत ऊँचा उठा दिया तथा समूची पार्टी को केन्द्रीय समिति व कामरेड माओ के इर्द-गिर्द अभूतपूर्व रूप से एकजुट कर दिया । इससे, सभी मोर्चों पर केन्द्रीय समिति की राजनीतिक कार्यदिशा का लागू होना सुनिश्चित हो गया, पार्टी जापान-विरोधी युद्ध के दौरान अत्यधिक कठिनाइयों पर विजय पाने में समर्थ हुई, तथा उसकी सातवीं काँग्रेस के सम्मेलन के लिए सैद्धान्तिक आधार तैयार हुआ ।

इस कालावधि के दौरान, जापानी फौज, कठपुतली सेनाओं व क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के हमलों तथा नाकाबन्दी के कारण उत्पन्न गंभीर आर्थिक तथा वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए, केन्द्रीय समिति ने मुक्त-क्षेत्रों की जनता तथा सेनाओं का, *'बेहतर फौज तथा सरलीकृत प्रशासन'* की नीति का पालन करने तथा विशाल पैमाने पर उत्पादन की मुहिम शुरू करने के लिए आह्वान किया ।

इस नीति के परिणामस्वरूप, किसी उत्पादन में न लगे हुए लोगों की संख्या कम हो गई, लोगों का बोझ हल्का हो गया तथा रसद की कमी पर काबू पा लिया गया । इसके अतिरिक्त, फौजी संगठनों के सरलीकरण से, शत्रु के विरुद्ध लड़ाई में ज्यादा गतिशीलता तथा तेजी अर्जित की गई । इस प्रकार भारी-भरकम युद्ध-तन्त्र तथा वास्तविक युद्ध स्थिति में अन्तर्विरोध दूर किया गया; फौजी संगठन मौजूदा स्थिति के अनुसार और अधिक कारगर तरीके से ढल गए तथा इस प्रकार और ज्यादा दक्ष हो गए ।

कामरेड माओ द्वारा आर्थिक समस्याओं के बारे में लिखे गए लेख—''**जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध में आर्थिक और वित्तीय समस्याएं,**''[6] ''**आधार-क्षेत्रों में लगान कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा सरकार का समर्थन करने व जनता के साथ आत्मीयता बढ़ाने के आन्दोलन फैलाओ,**''[7] ''**संगठित हो जाओ,**''[8] तथा ''**हमें आर्थिक काम**

को नेस्तनाबूद करने के मौके की तलाश में बड़ी ही दक्षता एवं फुर्ती से कूच करना होता था। इसलिए युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर ''जनता के आत्म-रक्षा दलों'' का एक हिस्सा वास्तविक लड़ाई के लिए मिलिशिया में सम्मिलित हो गया ।

जापान-विरोधी युद्ध के दौरान, मुक्त-क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 25 लाख मिलिशिया सिपाही थे । घनी आबादी वाले इलाकों में, जहां राजनीतिक कार्य अच्छी तरह चलाया गया था, कभी-कभी मिलिशिया सैनिकों की संख्या कुल आबादी के आठ प्रतिशत तक पहुँच जाती थी; अपने खुद के नेतृत्वकारी संगठनों—विभिन्न स्तरों पर जनता की सशस्त्र सेनाओं के कमीशनों, के मार्गदर्शन में मिलिशिया एक सुसंगठित लड़ाका इकाई बन गई थी तथा छापामार दस्तों व नियमित सेना का एक मजबूत सहायक-दल बन गई थी । मिलिशिया की भागेदारी से शत्रु पाँतों के पीछे का छापामार युद्ध एक वास्तविक जन-संघर्ष बन गया ।

1. शत्रु की ''सफाया'' मुहिम का मुकाबला करने के लिए चलाए गए अभियानों में मिलिशिया की भूमिका ।

मिलिशिया के रोजमर्रा के कार्य गश्त लगाना तथा टोह लेना थे । शत्रु के गढ़ों के आसपास गश्ती दल भेजे जाते थे तथा गुप्तचर अक्सर शत्रु के ठिकानों में घुसपैठ कर जाते थे। इसके अलावा मिलिशिया को किसी खास इलाके में गद्दारों तथा जासूसों को ढूंढ़ निकालने के लिए फौजी कानून (मार्शल-ला) लागू करने के अधिकार भी दिये गये । उनके क्रियाकलापों ने जापान-विरोधी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में शानदार भूमिका निभाई ।

कभी-कभी जब शत्रु की फौज गांव के नजदीक पहुँच चुकी होती थी, मिलिशिया सारे के सारे अनाज, ईंधन की लकड़ी तथा पशु-चारे को जमीन में दबाने या छुपाने में लोगों का मार्गदर्शन करती थी, तथा दुश्मन को खाली घरों व खाली खेतों के अलावा और कुछ नहीं

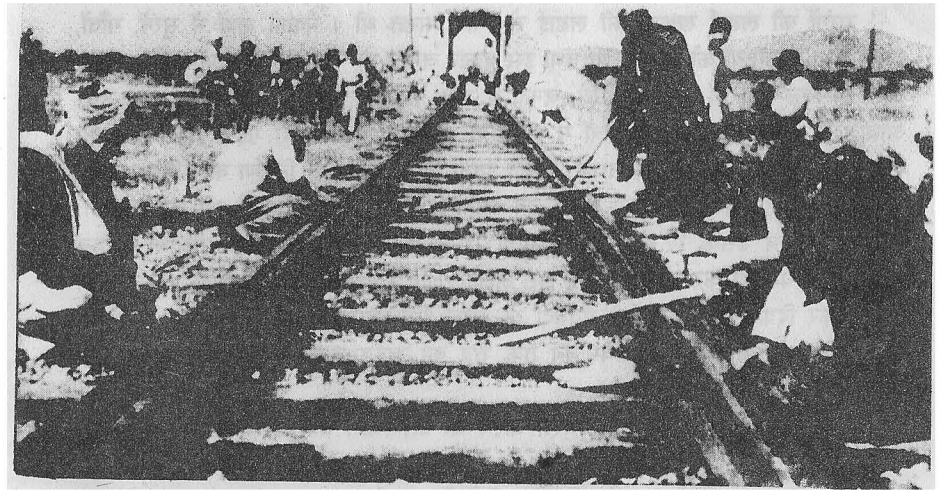

सामान्य प्रत्याक्रमण से तालमेल बिठाकर रेल पटरियों को उखाड़ती हुई चीनी जनता व लाल सेना

चौथी सेना के अफसरों तथा जवानों को पकड़ने के लिए गांव-गांव तथा घर-घर की तलाशी ली जाती थी ।

इन हालातों के मद्देनजर नई चौथी सेना ने निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाईं :

1. जब शत्रु एक क्षेत्र में तलाशी लेने के लिए अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित कर रहा होता था, दूसरे क्षेत्रों की सेना की टुकड़ियाँ, शत्रु की पृष्ठभागीय पंक्तियों को हैरान-परेशान करने के लिए एक साथ धावा बोल देती थीं ।

2. "गाँव तलाशी" वाले क्षेत्र का मुख्य सैन्य-बल या तो शत्रु की पंक्तियों के पीछे चला जाता था, या उसके पार्श्वों पर हमला करता था, या फिर बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लामबन्द करके रात में बाड़ को जला देता था अथवा उखाड़ फेंकता था ।

"कुतरने" की कार्यवाही करते हुए शत्रु जब धीरे-धीरे अपने ठिकानों से आगे बढ़ता हुआ आधार-क्षेत्रों में घुसने लगा तब उसका मुकाबला करने के लिए नई चौथी सेना ने सीमा रेखा पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सुरंगें खोदीं तथा सारे गाँव खाली कर दिए । शत्रु पर लगातार हमले करके तथा उसके रास्ते में बारूदी-सुरंगें बिछा कर उसे भारी क्षति पहुँचाई गई और इसने शत्रु के आगे बढ़ने की गति को काफी हद तक धीमा कर दिया ।

"सफाया", "कुतरने" तथा "गांव तलाशी" की कार्रवाहियों के विरुद्ध की गई जवाबी-कार्यवाहियों के फलस्वरूप, जापानी तथा कठपुतली फौजों द्वारा किए गए अनेकों बर्बरतापूर्ण हमलों को पीछे धकेल दिया गया, तथा मुक्त-क्षेत्रों का जबरदस्त सुदृढ़ीकरण हुआ। इस गंभीर स्थिति से निपटने के बाद तथा अत्यधिक कठिनाइयों पर विजय पाने के बाद, मुक्त-क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास होना शुरू हुआ, जो कि जापान-विरोधी युद्ध में विजय प्राप्ति तक तथा उसके बाद तक भी जारी रहा । ●

4.

● शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में मिलिशिया (नागरिक सेना) की भूमिका ।

जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों में युद्ध एक लोक-युद्ध था, जिसमें नियमित सेना, छापामार दस्तों तथा मिलिशिया ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी । नियमित सेना ने आधार-क्षेत्रों की समग्र रूप से रक्षा की, छापामार दस्तों ने काउंटियों तथा जिलों की रक्षा की व मिलिशिया ने गांवों तथा कस्बों की रक्षा की ।

युद्ध के शुरू में ही, पार्टी-संगठन शत्रु की पाँतों के पीछे घुसपैठ कर गए थे, उन्होंने जनता को कार्यवाही के लिए जागृत किया तथा जनता की सशस्त्र सेनाएं, जनता के आत्मरक्षा दल तैयार किये । युद्ध की आरंभिक मंजिलों में इन दलों ने शत्रु की जासूसी की गतिविधियों पर निगरानी रखी तथा नियमित सेना के लिए अन्य युद्धकालीन कार्य किए ।

1941 से 1943 तक जापानी हमलावरों ने पृष्ठभाग में बेरहमी से "सफाया" मुहिमें चलाईं। उत्तरी चीन में कई महीनों तक चलने वाली कई सैनिक कार्यवाहियाँ खासतौर से विनाशकारी थीं । आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना को शत्रु के साथ विशाल भूभागों तथा छोटे इलाकों, दोनों के लिए युद्ध करना पड़ा । फौजी कार्यवाहियों के तरीकों में मोर्चेबद्ध लड़ाई से लेकर हाथापाई की लड़ाई तक शामिल थी । ऐसी परिस्थितियों में, नियमित सेना को शत्रु

करना सीखना चाहिये,"[9]—मुक्त क्षेत्रों में उत्पादन मुहिम के लिए पार्टी की केन्द्रीय समिति के बुनियादी कार्यक्रम बने । मुक्त क्षेत्रों की आर्थिक नीति विकास की नीति थी, अर्थात् आर्थिक विकास द्वारा रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करना । वित्तीय संसाधनों को संचित करने के लिए, सार्वजनिक तथा निजी उद्यमों का विकास करना, सर्वोत्तम तरीका था । इसलिए पार्टी की केन्द्रीय समिति ने आर्थिक मोर्चे पर दो तरफा संघर्ष चलाया : पहला उस दकियानूसी मत के विरुद्ध जो आर्थिक विकास की अवहेलना करता था तथा वित्तीय कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए अपरिहार्य खर्चों में कटौती करने पर जोर देता था; तथा दूसरे उस दु:साहसी मत के विरुद्ध जो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर अव्यावहारिक व आडम्बरपूर्ण बड़ी-बड़ी योजनाओं की पैरवी करता था ।

इसी बुनियादी नीति के मद्देनजर, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने पार्टी व सरकार के सभी संगठनों के कर्मचारियों, सैनिकों तथा असैनिक जन-समुदाय का एक विशाल उत्पादन आन्दोलन चलाने के लिए आह्वान किया, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों की कृषि, उद्योग, दस्तकारी, परिवहन, पशुपालन व वाणिज्य शामिल हों और कृषि पर विशेष जोर दिया गया हो । उत्पादन में हाथ बंटाना प्रत्येक के लिए जरूरी था ताकि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लगातार जंग छिड़ी हुई थी तथा शत्रु अक्सर कहर बरपा देता था, सैनिक तथा सरकारी विभाग उत्पादन-कार्य में जुट गये, ताकि खाद्य-सामग्री तथा निर्मित वस्तुओं में धीरे-धीरे पूर्ण या आंशिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके ।

लोगों के रहन-सहन के हालातों में सुधार करने के लिए तथा क्रांतिकारी युद्ध को समर्थन

आधार-क्षेत्रों में महान उत्पादन अभियान के दौरान बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलते आठवीं राह सेना के जवान

देने लिए, जनता की अर्थ-व्यवस्था (People's Economy) के विकास हेतु कदम उठाए गए। पार्टी, सरकार तथा सेना ने उत्पादन बढ़ाने में लोगों की सहायता करने के भरपूर प्रयास किए। सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के दैनिक जीवन में उसकी सहायता की कृषि-उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए, सभी मुक्त-क्षेत्रों में लगान तथा सूद में कटौती करने के लिए एक व्यापक तथा संपूर्ण अभियान छेड़ा गया । अगला कदम था, किसानों को आपसी-सहयोग दलों या सहकारी समितियों में संगठित करना ताकि कृषि संबंधी उत्पादन-शक्ति को बढ़ाया जा सके तथा धीरे-धीरे सामूहिकीकरण में संक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो सके। कार्यकर्ताओं को अपनी शक्ति का 90 प्रतिशत हिस्सा, उत्पादन बढ़ाने में लोगों की मदद करने में, तथा केवल दस प्रतिशत उनसे सार्वजनिक अनाज इकट्ठा करने में लगाना था । इसे कम्युनिस्ट-कार्यशैली के रूप में प्रस्तुत किया गया, जोकि क्वोमिंताङ की कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें (क्वोमिंताङ कार्यशैली में) जनता के आर्थिक कल्याण की ओर रत्ती भर ध्यान दिए बगैर उससे बेरहमी से अनाज व पैसा छीनने पर ही जोर दिया जाता था।

सहकारी समितियों पर लेनिनवादी सिद्धान्त को लागू करते हुए तथा परस्पर-सहयोग कार्यवाहियों में चीनी किसानों के अनुभव के निष्कर्ष से साथी माओ ने मुक्त-क्षेत्रों के किसानों का, स्वैच्छिक भागेदारी तथा परस्पर हित के आधार पर, उत्पादन में परस्पर-सहयोग तथा सहकार के विभिन्न तरीकों के बारे में मार्गदर्शन किया । चूंकि ये सहकारी संस्थाएँ सामूहिक परस्पर सहयोग के लिए मेहनतकश जनता की श्रमिक संस्थाएँ थीं, अत: इनमें काफी हद तक समाजवादी तत्व निहित थे, हालाँकि ये अभी भी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित थीं । कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को धीरे-धीरे सामूहिकीकरण के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, जापान-विरोधी युद्ध के दौरान तथा बाद में, कम्युनिस्ट पार्टी की यह बुनियादी नीति रही।

जापान-विरोधी युद्ध के दौरान, शेनशी-कानसू-निङश्या क्षेत्र में सेना तथा सरकारी संगठनों द्वारा दो उत्पादन आन्दोलन चलाए गए । पहला 1938 में शुरू हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के हालात में सुधार करना था । दूसरा आन्दोलन जो 1941 में शुरू किया गया, मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित था । शत्रु की पाँतों के पीछे के आधार-क्षेत्रों में उत्पादन आन्दोलन 1941 में शुरू किया गया । 1943 तक यह एक व्यापक आन्दोलन बन गया था ।

मुक्त क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर चलाए गये इस उत्पादन आन्दोलन ने जबरदस्त सफलताएं प्राप्त कीं ।

शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र में काश्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 1938 के 89,94,483 मू (एक मू = 0.0667 हेक्टेयर या 0.1647 एकड़) से बढ़कर 1942 में 1,24,86,937 मू हो गया । अनाज का उत्पादन 1938 के 13 लाख तान (65 हजार टन) से बढ़कर, 1942 में 16 लाख 80 हजार तान (84 हजार टन) हो गया । 1942 में, व्यक्तिगत स्तर पर तथा सरकारी कारखानों द्वारा तैयार की गई खादी की वार्षिक पैदावार एक लाख गांठें थीं । जापान के आत्मसमर्पण से पहले, सीमान्त-क्षेत्र में लगे हुए भारी तथा रासायनिक उद्योगों में तेल-शोधन, लोहा पिघलाने, मशीन निर्माण तथा मरम्मत, युद्ध-सामग्री निर्माण तथा शोरे का तेजाब, नमक का तेजाब, गंधक का तेजाब, काँच तथा चीनी के बर्तन बनाने के उद्योग शामिल थें । सूती वस्त्र-उद्योग में वार्षिक उत्पादन 1,90,000 गांठें था । इन कारोबारों में कर्मचारियों तथा श्रमिकों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी ।

1941 में शत्रु ने शानशी-हपे-शानतुङ-हनान सीमान्त क्षेत्र में दक्षिणी-पूर्वी शानशी में ह्वाङयेनतुङ स्थित एक हथियार मरम्मत कार्यशाला को घेर लिया । कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ने के बाद, रक्षकों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, लेकिन बाहरी सैन्य-पंक्ति के सैन्य-दलों की कार्यवाहियों से शत्रु पर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि उसे भी जल्दी से पीछे हटना पड़ा । रास्ते में शत्रु पर घात लगाकर हमला किया गया तथा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।

ह्वाङयेनतुङ मुहिम एक ठेठ रक्षात्मक लड़ाई थी, जिसमें थोड़ों ने बहुतों के हमले को विफल किया ।

जून 1942 में 30,000 शत्रु सैनिकों ने दक्षिण पूर्वी शानशी में "सफाया" अभियान शुरू किया । जन-सेना ने दृढ़ता से मुकाबला किया तथा 5,000 से ज्यादा शत्रु सैनिकों को मार गिराया।

थाएय्वे क्षेत्र के विरुद्ध 1 अक्तूबर से 19 नवम्बर, 1943 तक चली, सख्त "सफाया" कार्यवाही में 20,000 शत्रु सैनिक तैनात किए गए । शत्रु ने अपनी सैन्य-शक्तियों को उत्तर से दक्षिण को जाती एक पंक्ति पर केन्द्रित किया तथा आगे-पीछे कूच करते हुए, उस क्षेत्र में बार-बार "सफाया" कार्यवाही की । शत्रु जहाँ कहीं भी गया, उसने लोगों को मारा तथा जो कुछ भी हाथ लगा उसे या तो नष्ट कर दिया या फिर लूट लिया । शत्रु का उद्देश्य केवल थाएय्वे आधार-क्षेत्र को नेस्तनाबूद करना ही नहीं था, बल्कि अन्य क्षेत्रों में ऐसी ही फौजी कार्यवाहियाँ करने के लिए अनुभव प्राप्त करना भी था । शत्रु कमाण्डर ओकामूरा नीजी द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात शत्रु अफसरों तथा स्टाफ प्रमुखों को, मौके पर कार्यवाही देखने के लिए बुलाया गया। लेकिन यह "पर्यवेक्षण ग्रुप", 23 अक्तूबर को लिंटन राजमार्ग पर हानल्वे गांव के पास एक घात में फँस गया तथा इसके सभी सदस्य मारे गए । इसके बाद शत्रु को इस क्षेत्र में सभी मोर्चों पर व्यापक पराजय का मुँह देखना पड़ा ।

मध्य चीन में नई चौथी सेना के खिलाफ भी, शत्रु ने "सफाया", "कुतरने" तथा "गाँव तलाशी" की वही नीतियाँ अपनाई, जो उसने उत्तरी चीन में अपनाई थीं । शत्रु का आक्रमण उत्तरी च्याङसू में शुरू हुआ । जुलाई 1941 में, 25,000 जापानी तथा कठपुतली सैनिकों ने येनछङ तथा फूनिङ पर संयुक्त हमला किया । हमले का उद्देश्य नई चौथी सेना के मुख्यालय तथा इस क्षेत्र में उसके मुख्य सैन्य-बल को नष्ट करना था । सेना ठीक वक्त पर घेराबन्दी को तोड़कर निकल गई तथा शत्रु पर हमला करने के लिए बाहरी सैन्य-पंक्ति पर चली गई । मध्य च्याङसू में, सैन्य-बलों द्वारा तालमेल स्थापित करके लड़ने के कारण शत्रु को अविलम्ब दक्षिण की ओर पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा ।

प्रशान्त महासागर युद्ध छिड़ जाने के बाद, शत्रु ने मध्य चीन क्षेत्र के प्रति "गाँव तलाशी" की अत्यन्त निर्मम नीति अपनाई । उसने वे सभी हथकण्डे भी अपनाए, जो क्वोमिंताङ ने लाल सेना के विरुद्ध अपनी पाँचवीं घेराबन्दी मुहिम के दौरान अपनाए थे । "गाँव तलाशी" के लिए खास-खास क्षेत्रों को निशाना बनाया गया । जघन्य अत्याचारों का यह सिलसिला दक्षिणी च्याङसू में शुरू किया गया तथा धीरे-धीरे मध्य च्याङसू, मध्य आनह्वेइ तथा ऊहान के बाहरी इलाकों तक फैला दिया गया । बेहतर सैन्य-शक्ति के बल पर एक क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद, उसे दूसरे क्षेत्रों से अलग करने के लिए, शत्रु बाँस या लकड़ी की बाड़ लगाता था, जो अक्सर सैंकड़ों ली (एक ली = 0.5 किलोमीटर) तक फैली होती थी तथा इसके बाद नई

के केन्द्र की ओर तथा रेलमार्ग के साथ लगते इलाके में स्थानांतरण कर गई तथा उस पर अप्रत्याशित हमले शुरू कर दिए जिससे शत्रु को विवश होकर, अपने पृष्ठभाग के सैन्य-दलों को बचाने के लिए, पीछे लौटना पड़ा । मुहिम के उत्तरार्द्ध में, जब शत्रु ने विशाल पैमाने पर "सफाया" कार्यवाही शुरू की, जन-सेना की मुख्य-शक्तियां विशाल पैमाने पर स्थान बदल कर बाहरी सैन्य-पंक्ति पर चली गईं तथा छिट-पुट यूनिटों को स्थानीय छापामार दस्तों तथा मिलिशिया के साथ तालमेल बिठाते हुए शत्रु से लड़ने के लिए पीछे छोड़ दिया । इस मुहिम में शत्रु ने **"तीन तरह का सफाया करने"**[10] की बर्बर नीति लागू की तथा 50,000 नागरिकों को या तो गिरफ्तार कर लिया अथवा सीधे मौत के घाट उतार दिया । इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्षेत्र की सेना तथा जनता दो महीने के बहादुराना संघर्ष के बाद, शत्रु के हमले को पीछे धकेलने में सफल रही ।

शानशी-छाहाड़-हपे सीमान्त-क्षेत्र में पेइय्वे में, शत्रु ने तथाकथित "विध्वंसक सफाया" मुहिम में 40,000 से भी अधिक फौज झोंक दी और यह मुहिम 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 1943 तक चली ।

इस मुहिम के प्रत्येक चरण में जन-सेना ने शत्रु को भारी क्षति पहुँचाई । पहले चरण में जब शत्रु ने केन्द्रीय क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद पुनः "सफाया" करने की मुहिमें छेड़ने के लिए अपनी सेनाओं को विभाजित कर दिया, जन-सेना ने अलग-थलग पड़ी शत्रु टुकड़ियों के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सैन्य-दलों को केन्द्रित किया तथा उन्हें अपने बचाव के लिए फिर इकट्ठे हो जाने को बाध्य कर दिया । दूसरे चरण में, जब शत्रु ने हुतो नदी पर मोर्चाबन्दी कर ली तथा अनाज लूटने में लगा हुआ था; जन-सेना, मिलिशिया के साथ तालमेल बिठाते हुए नदी के दोनों ओर से शत्रु पर झपटी तथा लूटा हुआ अनाज वापिस छीन लिया । तीसरे चरण में, शत्रु ने पृष्ठभाग में सरकारी दफ्तरों पर हमला किया, लेकिन उसके प्रयास विफल सिद्ध हुए। इन दफ्तरों में काम करने वाले लोग असावधान न थे । वे या तो दक्षता से शत्रु के विरुद्ध लड़े या फिर बच निकले । यद्यपि "बेहतर-फौज तथा सरल प्रशासन" की नीति अपनाने के बाद सेना की टुकड़ियां छोटी हो गई थीं, लेकिन उनकी कार्यवाहियों में और ज्यादा गतिशीलता आ गई थी ।

इस पूरी मुहिम के दौरान, जन-सेना द्वारा निम्न रणनीति अपनाई गई—मुख्य सैन्य-शक्तियों की कार्यवाहियों का मिलिशिया की कार्यवाहियों के साथ समन्वय स्थापित करना, बाहरी सैन्य-पंक्ति की कार्यवाहियों का भीतरी सैन्य-पंक्ति की कार्यवाहियों के साथ समन्वय स्थापित करना, तथा शत्रु की "सफाया" मुहिम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का राजनीतिक हमले के साथ समन्वय स्थापित करना । मुख्य सैन्य-शक्तियां हमेशा मिलिशिया के साथ जबरदस्त तालमेल बनाकर लड़ीं । जब इस क्षेत्र में लड़ाई ने गंभीर रूप धारण कर लिया, बाहरी सैन्य-पंक्ति पर तैनात जन-सेनाएं शत्रु की पंक्तियों के पीछे घुसपैठ कर गईं तथा वहां हमला कर दिया, जबकि सशस्त्र कार्य-दलों ने शत्रु-नियंत्रित क्षेत्रों के केन्द्रीय स्थलों में कठपुतली फौजों तथा कठपुतली संस्थाओं को हतोत्साहित करने के लिए राजनीतिक हमला शुरू कर दिया ।

इन उपायों के फलस्वरूप विशाल पैमाने पर छेड़ी गई इस "सफाया" मुहिम का भी मुँहतोड़ जवाब दिया गया ।

1942 में सैनिकों, सरकारी संस्थाओं तथा स्कूलों को अपनी सारी की सारी खाद्य-सामग्री लोगों से ही लेनी पड़ती थी, लेकिन 1943 तक उन्होंने आंशिक रूप से आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली थी । जहां तक खाने-पीने की आम चीजों तथा प्रशासनिक व फौजी साजोसामान के खर्चों का सवाल था, इस मामले में वे ज्यादातर अपने ही उत्पादन पर निर्भर करते थे ।

शत्रु के पृष्ठभाग वाले उत्तरी चीन के आधार-क्षेत्रों में, 'बेहतर फौज तथा सरल प्रशासन' की नीति तथा उत्पादन मुहिम के फलस्वरूप सार्वजनिक अनाज पर लेवी में बहुत ज्यादा कमी कर दी गई थी । उदाहरण के लिए थाएहाङ क्षेत्र में, सन् 1944 में सार्वजनिक अनाज की उगाही 1941 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत गिर गई ।

शानशी-हपे-शानतुङ-हनान आधार-क्षेत्र में सेना तथा जनता के मिले जुले प्रयासों ने 1939 में एक भयंकर बाढ़ पर, 1942 तथा 1943 के सूखे पर तथा 1944 के टिड्डी दल संकट पर विजय प्राप्त की ।

कम या अधिक स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए फौज तथा जनता ने उत्पादन के लिए अथक प्रयास किए । 1943 में हर सैनिक से तीन मू जमीन जोतने तथा अपने लिए एक मौसम के गुजारे लायक अनाज पैदा करने का अनुरोध किया गया । उद्योग के क्षेत्र में, कोयला-खनन, लोहा-पिघलाई, गोला-बारूद का उत्पादन, लेखन-सामग्री तथा दूसरी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का निर्माण करने के कार्य शामिल थे तथा अंतिम दो का उत्पादन, स्थानीय माँग की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था । शत्रु से आर्थिक मोर्चे पर लोहा लेने के लिए, शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों से व्यापार करने पर नियंत्रण लगाया गया । अनाज, कपास, लोहा तथा चमड़े के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी गई, जबकि नमक, माचिस, कपड़े, बिजली उपकरण, सैनिक साजोसामान तथा अन्य जरूरत की चीजों के आयात को बढ़ावा दिया गया।

आर्थिक मोर्चे पर अर्जित विजय ने जापानियों, कठपुतली सेनाओं तथा क्वोमिंताङ फौजों द्वारा मचाई गई तबाही, लूटमार तथा नाकेबन्दी का शानदार तरीके से मुँहतोड़ जवाब दिया । इससे आधार-क्षेत्रों के संसाधनों की रक्षा करने तथा उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिली ।

मुख्य-क्षेत्रों द्वारा राजनीतिक, सैद्धांतिक तथा आर्थिक मोर्चों पर अर्जित इन महान विजयों ने, खासतौर से दोष-निवारण मुहिम तथा विशाल उत्पादन अभियान ने, पार्टी को सैद्धान्तिक तथा भौतिक स्तर पर अभेद्य बना दिया । और यही वह मुख्य कारण था जिससे, जापान-विरोधी युद्ध के दौरान आई असीम मुसीबतों पर विजय पाई जा सकी । ●

3.

- **जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों में शत्रु से लड़ने के लिए रणनीति ।**
- **शत्रु की "सफाया करो," "कुतरने की," तथा "गांव तलाशी" की मुहिमों के खिलाफ संघर्ष ।**

जनता के राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारों, दोष-निवारण मुहिम तथा विशाल पैमाने पर उत्पादन अभियान ने मुक्त-क्षेत्रों के लिए शत्रु के विरुद्ध और ज्यादा असरदार ढंग से संघर्ष करना संभव बनाया ।

आधार-क्षेत्रों में, शत्रु की "सफाया" मुहिमों के खिलाफ एक सफल नीति अपनाई गई।

फौज तथा जनता को एकजुट किया गया; नियमित सेना, छापामार दस्तों तथा मिलिशिया ने लड़ते वक्त जबरदस्त तालमेल बनाए रखा। जब भी शत्रु आधार-क्षेत्रों पर हमला करता था, पार्टी अपनी सैन्य-शक्तियों को विभाजित करने तथा शत्रु को कुचलने हेतु अवसर की प्रतीक्षा करने के दौरान अथवा अचानक हमला करने हेतु शत्रु के पृष्ठभाग की ओर कूच करने के दौरान *"संपूर्ण को हिस्सों में विभाजित करने"* की नीति लागू करती। और फिर इससे पहले कि शत्रु को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का मौका मिलता, पार्टी, *"हिस्सों को सम्पूर्ण में एकजुट"* कर लेती, तथा किसी अलग-थलग पड़ी शत्रु यूनिट को कुचलने के लिए बरत्त सैन्यबल केन्द्रित कर लेती। लड़ाई के दौरान जनता ने सुरंग युद्ध-प्रणाली, बारूदी-सुरंगें बिछाने की लड़ाई, तथा लड़ाई के और भी बहुत से नये तरीके विकसित किये तथा उन्हें लागू किया। इस प्रकार जनता ने दृढ़तापूर्वक तथा निर्भीकतापूर्वक शत्रु की फौजों को लगातार क्षति पहुँचाई तथा उन्हें आतंकित किये रखा।

छापामार इलाकों में शत्रु की "कुतरने" की नीति का डटकर मुकाबला किया गया तथा उसे विफल कर दिया गया।

रणनीति यह थी—इससे पहले कि शत्रु पाँव जमा ले और छापामार इलाकों को "कुतरना" शुरू कर दे, उसे भारी क्षति पहुँचाई जाए। यदि वह पहले से ही आधार-क्षेत्रों में घुसपैठ कर चुका होता था तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर चुका होता था तो जब तक उसे खदेड़ न दिया जाता, उसकी घेराबन्दी की जाती थी तथा उसे हैरान-परेशान किया जाता था। कभी-कभी मुक्त-क्षेत्रों की सेना तथा जनता, शत्रु-पंक्तियों के पीछे घुसपैठ के लिए, **सशस्त्र कार्य-दलों** (Armed Work Teams) को भेजती थी। इस प्रकार शत्रु को सामने तथा पीछे, दोनों ओर से संकट में डाल दिया जाता था, तथा उसके लिए स्थिति से निपटना मुश्किल कर दिया जाता था।

शत्रु के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, दुश्मन की "गाँव तलाशी" मुहिम का जवाबी कार्यवाहियों द्वारा मुकाबला किया गया।

इस बारे में जो रणनीति अपनाई गई, वह इस प्रकार थी—शत्रु जब आगे बढ़ता था तो उसकी पाँतों के पीछे गहराई तक घुसपैठ कर जाना। सशस्त्र कार्य-दल शत्रु फौजों के घेरे को तोड़कर घुसपैठ कर जाते थे तथा शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्रों में कार्यवाहियां करते थे। ये दल *"एक में तीन"* के सिद्धान्त पर संगठित किये गए थे—उन्हें सैनिकों की तरह लड़ना होता था, सरकार की ओर से राजनीतिक कार्य करना होता था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आम आदमी की तरह व्यवहार करना होता था। इस प्रकार, फौजी तथा राजनीतिक संघर्ष साथ-साथ चले। दलों की कार्यवाहियों को ऐसे सुनियोजित किया गया था कि वे शत्रु को अचानक धर दबोचते थे। शत्रु सैनिक अपने दुर्गों में दलों से एक अप्रत्याशित टेलीफोन संदेश प्राप्त करते; दलों के सदस्य शत्रु-नियंत्रित गाँवों की छतों पर बिगुल बजाते प्रकट होते, तथा अप्रत्याशित अतिथि के रूप में कठपुतली सेना के सैनिकों के घरों में उपस्थित हो जाते। सशस्त्र कार्य-दल, शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजनीतिक तथा सैनिक संघर्षों द्वारा, अक्सर शत्रु के सरकारी संगठनों को नष्ट करने में, तथा स्वस्थ मनुष्यों की जबरी भर्ती, खाद्य-सामग्री की लूट, उस क्षेत्र के संसाधनों के शोषण व लोगों को गुलाम बनाने के शत्रु प्रयासों को विफल करने में सफल रहते। इसके अतिरिक्त, अनेक शत्रु तथा कठपुतली संगठनों के विरुद्ध

राजनीतिक हमले किए गए, जिससे उनमें दरारें पड़ीं, वे छिन्न-भिन्न हो गए या फिर निष्पक्ष हो गए तथा इस प्रकार शत्रु को अलगाव में डाल दिया गया।

सशस्त्र कार्य-दल अनायास ही शत्रु-अधिकृत इलाकों के हृदय-स्थलों में प्रकट या गायब हो जाते थे। जनता को उनका पता-ठिकाना हमेशा मालूम रहता था, लेकिन शत्रु उन्हें कभी भी ढूंढ़ नहीं सकता था। इस प्रकार शत्रु की पाँतों के पीछे विशाल जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों के अतिरिक्त, बहुत से बिखरे हुए छोटे-छोटे जापान-विरोधी ठिकाने भी थे। शत्रु ने आधार-क्षेत्रों को टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास किया था, परन्तु यह उसके अपने ही "सुरक्षित इलाके" थे जिनमें दरारें और ज्यादा चौड़ी हो गई थीं तथा एक क्षण के लिए भी वे सुरक्षित इलाके नहीं रह सके थे।

शत्रु की *"सफाया करने"*, *"कुतरने"* तथा *"गाँव तलाशी"* की नीतियों का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए उपाय परस्पर सम्बद्ध थे। इन उपायों ने आधार-क्षेत्रों की सेना तथा जनता के पाँव मजबूती से जमा दिये तथा वे सर्वाधिक कठिन दौर को पार कर गए।

इन उपायों के अन्तर्गत, शत्रु-पंक्तियों के पीछे सभी आधार-क्षेत्रों में बहादुराना अभियान चलाए गए।

शानशी-छाहाङ-हपे सीमान्त-क्षेत्र में, शत्रु ने 15 अगस्त, 1941 को 1,30,000 सैनिक हमले में झोंक दिए। उसकी योजना लंबी दीवार के दोनों ओर स्थित जन-सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियों को घेरकर उन्हें नष्ट करने की थी। लेकिन मुख्य सैन्य-बल तुरंत शत्रु-पंक्तियों के पीछे की ओर कूच कर गया, जबकि अनेक छापामार दस्ते व मिलिशिया (नागरिक सेना) यूनिटें शत्रु को हैरान-परेशान करती रहीं व उसका रास्ता रोके रहीं। जब शत्रु ने अपनी सेना को विभिन्न दिशाओं में "सफाये" के लिए बिखरा दिया तथा वह थक कर चूर हो गया, तब बाहरी सैन्य-पंक्ति पर कार्यवाही कर रही, हमारी सेनाएं घूमकर वापिस मुड़ी तथा भीतरी सैन्य-पंक्ति पर कार्यवाही कर रही सैन्य-टुकड़ियों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए शत्रु पर हमला कर दिया। इस क्षेत्र में शत्रु की "सफाया" मुहिम के विरुद्ध की जा रही जवाबी कार्यवाही के समर्थन में उत्तरी चीन के सभी दूसरे जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों में भी संयुक्त कार्यवाही की गई। फलतः शत्रु के मुख्य सैन्य-बल को सितंबर के मध्य में पीछे हटने को विवश होना पड़ा, सिर्फ थोड़ी सी टुकड़ियां, सीमान्त-क्षेत्र में रह गईं। इसके बाद, जन-सेना की कुछ टुकड़ियां तो बची-खुची शत्रु सेना से लड़ने के लिए भीतरी सैन्य-पंक्ति पर ही डटी रहीं, जबकि उसका मुख्य सैन्य-बल, शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ा, ताकि शत्रु के ठिकानों पर हमला किया जा सके व उसकी वापसी का रास्ता काटा जा सके। नेस्तनाबूद होने के आसन्न संकट के मद्देनजर, शत्रु की भीतरी सैन्य-पंक्ति पर तैनात फौजी टुकड़ियों को अक्तूबर के मध्य में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रास्ते में उन पर बार-बार घात लगाकर हमले किए गये तथा उन्हें काफी ज्यादा क्षति झेलनी पड़ी।

इस प्रकार शत्रु के "सफाया" अभियान की परिणति पूर्ण पराजय में हुई।

1942 में, उत्तरी चीन में शत्रु द्वारा छेड़ी गई सभी "सफाया" मुहिमों में से सबसे ज्यादा भयंकर 1 मई, 1942 को मध्य हपे के मैदानी इलाके में शुरू की गई मुहिम थी। शत्रु ने उस इलाके में 1500 दुर्ग बनाये तथा 700 गाड़ियां गश्त करने पर लगाईं। तथापि जब शत्रु फौजें हमला करने के लिए एकत्रित हुईं, जन-सेना ऐन सही वक्त पर शत्रु के कब्जे वाले इलाके

हो गए तथा जनता की सेनाएँ मजबूत हो गईं ।

अप्रैल 1945 तक, जन-सेना की संख्या बढ़कर 9,10,000, मिलिशिया की 22,00,000 तथा आत्म-रक्षा कोर की संख्या एक करोड़ तक जा पहुंची थी । 19 मुक्त क्षेत्र स्थापित किए जा चुके थे, जिनका क्षेत्रफल 9,50,000 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 9,55,00,000 थी ।

ये 19 मुक्त क्षेत्र थे :

1. शेनशी-कानसू-निङश्या क्षेत्र ।
2. शानशी-छाहाङ-हपे क्षेत्र ।
3. शानशी-हपे-हनान क्षेत्र ।
4. हपे-शानतुङ-हनान क्षेत्र ।
5. शानशी-स्वेय्वान क्षेत्र ।
6. हपे-जेहोल-ल्याओनिङ क्षेत्र ।
7. शानतुङ क्षेत्र ।
8. उत्तरी च्याङसू क्षेत्र ।
9. मध्य च्याङसू क्षेत्र ।
10. च्याङसू-चच्याङ-आनह्वेइ क्षेत्र ।
11. पूर्वी चच्याङ क्षेत्र ।
12. ह्वाएफेइ क्षेत्र (ह्वाए नदी के उत्तर में)।
13. ह्वाएनान क्षेत्र (ह्वाए नदी के दक्षिण में)।
14. मध्य आनह्वेइ क्षेत्र ।
15. हनान क्षेत्र ।
16. हुपे-हनान-आनह्वेइ क्षेत्र ।
17. हुनान-हुपे क्षेत्र ।
18. तुङ च्याङ नदी क्षेत्र ।
19. हाएनान द्वीप क्षेत्र ।

मुक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत बड़े ही महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थल आते थे । जापान-अधिकृत बड़े शहरों, परिवहन-पंक्तियों तथा तटीय पंक्तियों में से अधिकांश, जनसेना के घेरे में थीं ।

पूरे प्रतिरोध-युद्ध के दौरान शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय क्रान्तिकारी फौजी कमीशन का मुख्यालय रहा । अत: यह क्षेत्र, तथा इसकी राजधानी येनान, चीनी जनता की जापान-विरोधी सेनाओं का सामान्य पृष्ठभाग तथा शत्रु-पंक्तियों के पीछे स्थित सभी आधार-क्षेत्रों का तथा देशभर में जनता के क्रान्तिकारी संघर्षों का राजनीतिक केन्द्र बन गया । येनान में ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, फौजी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं से संबंधित निर्देश तैयार करते थे, जो चीनी जनता का जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध में मार्गदर्शन करते थे ।

उत्तरी चीन के मुक्त क्षेत्रों में—शानशी-छाहाङ-हपे, शानशी-हपे-हनान, हपे-शानतुङ-हनान, शानशी-स्वेय्वान, हपे-जेहोल-ल्याओनिङ तथा शानतुङ के रणनीतिक महत्त्व के इलाके शामिल थे। वे पूर्व में पो हाए की खाड़ी तथा पीले सागर तक पश्चिम में पीली नदी, दक्षिण में लुङहाए रेलमार्ग व उत्तर में पाओतओ, तोलुन तथा छिनचओ नामक शहरों तक फैले हुए थे। वे पेकिङ-स्वेय्वान, पेकिङ-हानखओ, ताथुङ-फूचओ, चङतिङ-थाएय्वान व पेकिङ-ल्याओनिङ रेलमार्गों को नियंत्रित करने में सक्षम थे तथा पेकिङ, थ्येनचिन, शच्याच्वाङ, पाओतिङ, ताथुङ, थाएय्वान, चाङच्याखओ तथा छङते के शत्रु के गढ़ों के लिए खतरा पैदा करते थे ।

मध्यचीन के मुक्त क्षेत्रों में—उत्तरी च्याङसू, मध्य च्याङसू, च्याङसू-चच्याङ-आनह्वेइ, पूर्वी चच्याङ, ह्वाएफेइ, ह्वाएनान, मध्य आनह्वेइ, हनान, हुपे-हनान-आनह्वेइ तथा हुनान-हुपे के दस रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे । याङत्सी, ह्वाए, हान तथा पीली नदियां इन इलाकों में से होकर गुजरती थीं, इनके पूर्व में सागर था, पश्चिम में ऊथाङ पर्वतों को छूते हुए ये दक्षिण में चच्याङ तथा च्याङशी प्रान्तों तक फैले हुए थे तथा उत्तर में इनका विस्तार लुङहाए रेलमार्ग तक था।

दसवां अध्याय

मुक्त क्षेत्रों द्वारा आंशिक प्रत्याक्रमण की शुरुआत प्रतिरोध युद्ध में अन्तिम विजय

(जनवरी 1943 से सितंबर 1945)

1.

- **फासीवाद-विरोधी युद्ध का रक्षात्मक कार्यवाही से आक्रमणात्मक कार्यवाही में बदलना ।**
- **शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में जनता के जापान-विरोधी संघर्ष ।**
- **मुक्त क्षेत्रों की पुनर्स्थापना तथा विकास ।**

स्तालिनग्राद की लड़ाई सोवियत संघ के फासीवाद-विरोधी युद्ध का एक निर्णायक मोड़ थी, जहां से उसकी रणनीतिक रक्षात्मक कार्यवाही, रणनीतिक आक्रमण में बदल गई ।

चूँकि अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों ने यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने में देरी करने का हर संभव प्रयास किया, अत: जर्मनी के लिए अपनी सारी की सारी रिजर्व सेनाएँ तथा अपने मित्र राष्ट्रों-की सेनाएँ दक्षिण-पूर्वी मोर्चे पर सोवियत-संघ के विरुद्ध झोंकना संभव हो गया। जर्मन फौजें पूर्व की तरफ से मास्को पर झपटने की नीयत से स्तालिनग्राद तथा काकेशिया की ओर बढ़ चलीं ।

सोवियत सेना ने पहले तो हमलावरों पर हमले करके उन्हें कमजोर किया, तथा फिर स्तालिनग्राद पर हमला कर रही सभी जर्मन फौजों को घेर लिया। इस शहर के लिए नवम्बर 1942 से फरवरी 1943 तक चली लड़ाई में सोवियत-संघ ने पूर्ण विजय प्राप्त की तथा 3,30,000 जर्मन सैनिकों का सफाया कर दिया ।

नवम्बर 1942 से नवम्बर 1943 तक के बारह महीनों में सोवियत-संघ ने शत्रु द्वारा कब्जाए गए लगभग दो तिहाई इलाके को वापिस ले लिया । 1943 का वर्ष, फासीवाद विरोधी युद्ध में बुनियादी तब्दीली का वर्ष था ।

1944 में सोवियत-संघ ने एक-एक नाजी हमलावर को अपनी जमीन से बाहर खदेड़ दिया।

इस साल के दौरान, सोवियत-संघ ने उत्तर से दक्षिण तक सारे के सारे युद्ध-मोर्चे पर जर्मन फौजों को करारी शिकस्त दी, तथा काला सागर एवं बैरैण्टस सागर के बीच गंवाए गए अपने सभी इलाकों को वापिस लेते हुए, युद्ध को शत्रु की भूमि पर ले गया ।

इसके बाद अनेक यूरोपीय देश मुक्त हुए । नाजी जर्मनी की हार से फासीवादी गुट धराशायी हो गया । पहले, मुसोलिनी के तानाशाही शासन का तख्ता पलटा गया तथा इटली

लड़ाई से पीछे हट गया । फिर क्रमशः रूमानिया, बल्गारिया, फिनलैण्ड, हंगरी, पोलैण्ड, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, तथा नार्वे को सोवियत फौजों द्वारा 1944 में मुक्त कराया गया। सोवियत-संघ के फासीवाद विरोधी युद्ध तथा यूरोप की जनता के स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष का एक समान उद्देश्य था ।

सोवियत-संघ की विजय ने ब्रिटेन तथा अमरीका को जून 1944 में अपनी फौजें फ्रांस के उत्तरी तट पर उतार कर दूसरा मोर्चा खोलने को विवश कर दिया । इसके बावजूद, जर्मन सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियां अभी भी सोवियत-जर्मन मोर्चे पर ही तैनात थीं ।

सोवियत-संघ के फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय ने पूर्व के देशों को उत्साहित किया तथा जापान को फौजी तथा राजनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर अलग-थलग कर दिया । इस विजय ने चीनी जनता के प्रत्याक्रमण के लिए एक अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति उत्पन्न की, तथा यह चीनी प्रतिरोध युद्ध में शीघ्र विजय-प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुई ।

युद्ध छिड़ने के बाद, उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी चीन के शत्रु-अधिकृत इलाकों में कठपुतली सरकारें स्थापित कर दी गई थीं । ये इलाके जापान के उपनिवेश बन चुके थे । *"स्वायत्तशासी मंगोलियाई सरकार"* की स्थापना के अलावा जापान ने उत्तरी चीन में *"चीनी गणराज्य की अंतरिम सरकार"* तथा नानकिङ में *"सुधारी हुई सरकार"* (Reformed Government) की स्थापना की थी । चीनी संयुक्त मोर्चे में फूट डालने व अधिकृत-क्षेत्रों की लूट-खसोट के लिए जापान ने इन कठपुतली संस्थाओं का एक "संयुक्त सरकार", यानि कि "राष्ट्रीय सरकार" में विलय कर दिया जो कि वाङ चिङ-वेइ गुट द्वारा मार्च 1940 में नानकिङ में गठित की गई थी । पिछले साल के अंत में वाङ चिङ-वेइ गुट ने जापानी हमलावरों के साथ एक गद्दाराना गुप्त संधि,—*"चीन तथा जापान के नए-संबंधों को व्यवस्थित करने के कार्यक्रम की रूपरेखा"*—पर हस्ताक्षर किये । इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार थीं : उत्तर-पूर्वी चीन को जापान के हवाले कर दिया जाए; जबकि मंगोलिया, उत्तरी चीन, याङत्सी नदी की निचली घाटी तथा दक्षिणी चीन के द्वीप समूहों में जापानी फौजें स्थाई रूप से अड्डे बनाकर रहें । इसके अतिरिक्त, कठपुतली सरकार ने जापान की देख-रेख में काम करना था, उसकी वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों पर जापान का नियंत्रण होना था, उसने (जापान ने) चीन के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना था, कठपुतली फौज तथा पुलिस को प्रशिक्षण देना था तथा उन्हें शस्त्रास्त्र भी मुहैया कराने थे । इसके साथ-साथ हर किस्म की जापान-विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना था ।

नानकिङ कठपुतली सरकार की स्थापना के साथ-साथ वाङ चिङ-वेइ ने एक और क्वोमिंताङ का गठन किया तथा दावा किया कि इसका कार्यभार "तीन जन-सिद्धान्तों" को लागू करना था । उसका "राष्ट्रवाद का सिद्धान्त" असल में, जापानी विस्तारवाद या फिर जापान की छत्रछाया में एशियाई विस्तारवाद का पर्यायवाची था । वाङ नैतिक रूप से इतना अधिक नीचे गिर चुका था कि वह यह स्वीकार करने में कोई शर्म महसूस नहीं करता था कि उसके विचार से जापान एशिया का महाप्रभू था तथा चीन उसके अधीन एक राज्य था । इस प्रकार जिसे वह "राष्ट्रवाद" कहता था वह राष्ट्रीय आत्मसमर्पणवाद के सिवाय और कुछ न था। उसके "जनवाद के सिद्धान्त" का अर्थ शत्रु-अधिकृत इलाकों में जनता को शत्रु तथा कठपुतली सरकार के फासीवादी शासन को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए बाध्य करना था।

लाल सेना को संबोधित करते कामरेड चू तेह

इस कांग्रेस में कामरेड चू तेह ने **"मुक्त क्षेत्रों का युद्ध मोर्चा"** शीर्षक से एक सैनिक रिपोर्ट पेश की। इसमें जन-सेना, लोक-युद्ध तथा चीनी जनता के जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध की विजयी फौजी कार्यदिशा का विस्तृत तथा सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट कामरेड माओ के फौजी उसूलों तथा पार्टी द्वारा पिछले 17 वर्षों के दौरान क्रान्तिकारी युद्धों का नेतृत्व करने के दौरान हासिल किये गये अनुभवों पर आधारित थी। रिपोर्ट ने इस कार्यदिशा को लागू करने के लिए जरूरी कार्य के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि—सेना के निर्माण के सिद्धान्त; फौजी भर्ती; सेना का रखरखाव, नेतृत्व तथा प्रशिक्षण; युद्ध का निष्पादन; सेना में राजनीतिक कार्य; सेना की कमान तथा साजोसामान; मुख्य सैन्य-शक्तियों का स्थानीय सैन्य-शक्तियों अथवा मिलिशिया से तालमेल; तथा कठपुतली फौजों को तोड़ने पर विस्तारपूर्वक रोशनी डाली। जापान-विरोधी युद्ध में मुक्त क्षेत्रों के मोर्चों पर हासिल की गयी विजयों का निचोड़ भी प्रस्तुत किया गया। लोकयुद्ध की फौजी कार्यदिशा लागू करने के फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी ने विशाल मुक्त क्षेत्रों में युद्ध मोर्चा खोल दिया था, जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों की स्थापना की थी, जापान के रणनीतिक आक्रमणों को रोक दिया था, शत्रु की मुख्य शक्तियों तथा कठपुतली सेना के आक्रमण का सामना किया था तथा मुक्त क्षेत्रों को प्रतिरोध युद्ध का गुरुत्व केन्द्र बना दिया था ।

इस कांग्रेस में, कामरेड ल्यू शाओ-ची ने पार्टी के संविधान में संशोधन करने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । फलतः एक नया संविधान स्वीकृत किया गया ।

पार्टी के नए संविधान में इस बात पर खास जोर दिया गया कि **जन समुदाय की कार्यदिशा ही पार्टी की बुनियादी राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्यदिशा होगी ।** साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि पार्टी के संगठनों तथा कार्यों का व्यापकतम जन-समुदाय से अत्यन्त घनिष्ठ संबंध होना चाहिये । जन-समुदाय की कार्यदिशा को व्यवहार में लाने के लिए, नए संविधान में कई बुनियादी सिद्धान्तों पर जोर दिया गया, मसलन हर कार्य जनता की ओर से किया जाए, जनता को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जन-समुदाय की स्वःमुक्ति के प्रयत्नों पर विश्वास किया जाए तथा हर कार्यकर्ता को उनसे सीखना चाहिये । यही वे बुनियादी उसूल हैं, जिन्हें श्रमिक वर्ग का हरावल दस्ता, जन-समुदाय के प्रति अपनाता है । ये उसूल इस बात की गारंटी हैं कि इन पर चलते हुए पार्टी सदैव कठमुल्लावाद तथा अनुभववाद के गलत रुझानों से, जो कि उसे जन-समुदाय से दूर करते हैं, छुटकारा पाती रहेगी ।

अन्त में, कांग्रेस ने एक नई केन्द्रीय समिति का चुनाव किया, जिसका प्रधान कामरेड माओ त्से-तुङ को चुना गया ।

कांग्रेस के बाद, जन-मुक्ति सेना ने अपना प्रत्याक्रमण और ज्यादा तेज कर दिया तथा जापानी हमलावरों को उनके द्वारा कब्जाए गए शहरों तथा उनकी तंग परिवहन पंक्तियों तक ही सीमित करके रख दिया । ●

4.

- **जनता के मुक्त क्षेत्र प्रत्याक्रमण की मुख्य-शक्ति के रूप में ।**
- **मैत्री तथा संश्रय की चीनी-सोवियत सहयोग संधि पर हस्ताक्षर ।**

आंशिक प्रत्याक्रमण के दौरान, मुक्त क्षेत्रों का विस्तार किया गया, शत्रु-अधिकृत क्षेत्र छोटे

उसके "जन-कल्याण के सिद्धान्त" का उद्देश्य कठपुतली सरकार के वित्तीय रिजर्वों को "क्रमिक संचय" द्वारा "विकसित" करने में मदद देने के लिए जनता को मजबूर करना था। 1941 की सर्दियों में जब प्रशान्त महासागर युद्ध छिड़ गया, नानकिङ की कठपुतली सरकार ने "नया राष्ट्रीय आन्दोलन" आरंभ किया, तथा अपने शासन के अन्तर्गत जनता का "*दुनिया को बचाने के लिए कुर्बानियां देने*" तथा "*शारीरिक व मानसिक स्तर पर अपना पूरा जोर लगाने*" के लिए आह्वान किया । वास्तव में, इस सब का उद्देश्य जनता के खून की आखिरी बूंदें तक निचोड़ लेना था ।

शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों को जापानी हमलावरों द्वारा बड़ी बेरहमी से लूटा गया ।

युद्ध के आरंभिक दौर में, शत्रु ने अपने शोषण द्वारा उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी चीन में, सभी आर्थिक उद्यमों को नष्ट कर दिया । उसने यह नीचतापूर्ण काम या तो सीधे फौजी नियंत्रण द्वारा खुद किया या फिर इसे करने के लिए दूसरों को अधिकृत किया । उसका इरादा "*युद्ध के जरिये युद्ध का पोषण करने*" का था । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने तथाकथित "चीनी-जापानी सहयोग" की नीति अपनाई तथा "उत्तरी चीन विकास कंपनी" एवं "मध्य चीन विकास कंपनी" के माध्यम से इन कंपनियों के चीनी सहयोगियों के पूँजीनिवेश को निगलते हुए, और ज्यादा लूट मचाई ।

अधिकृत-क्षेत्रों में जापान द्वारा मचाई जा रही लूट-खसोट में, कठपुतली शासन-व्यवस्था के तहत बेतहाशा वृद्धि हुई । उदाहरण के लिए, उसके द्वारा खनिज लोहे की लूट 1939 के 45,02,222 टन से बढ़कर 1943 में 1,06,54,325 टन तक पहुँच गई; कच्चे लोहे की लूट 1938 के 8,68,485 टन से बढ़कर 1943 में 18,18,517 टन हो गई तथा कोयले की लूट 1938 के 2,74,51,968 टन से बढ़कर 1943 में 5,00,75,741 टन तक पहुँच गई ।

1936 से 1938 के बीच जापान ने उत्तरी तथा मध्य चीन में सूती कपड़ा मिलों से 13 लाख 30 हजार तकले छीने । उत्तर-पूर्वी तथा उत्तरी चीन के अधिकृत क्षेत्रों में सूती धागे, कपड़े, आटे तथा सिगरेटों के उत्पादन में लगातार गिरावट आई ।

लंबी दीवार के दक्षिण में स्थित देहाती इलाकों में, जापानी हमलावरों ने बड़े निर्मम तरीकों से जमीनें छीनीं । जब वे जापान-विरोधी छापामार युद्ध से निपटने के लिए खाइयाँ खोदते व पत्थर की दीवारें खड़ी करते थे, तब वे जमीनों पर बलपूर्वक कब्जा कर लेते थे, और जब वे ज्यादा कपास व अनाज उगाने के लिए अपनी कृषि कंपनियां तथा कृषि-फार्म स्थापित करते थे, तब वे बहुत ही कम कीमत पर जमीन खरीदते थे या फिर जब्त ही कर लेते थे । जब भी इस प्रकार जमीनें छीनी जाती थीं तो सभी निवासियों—जमींदारों तथा किसानों को बेदखल कर दिया जाता था । जिन किसानों को रहने की अनुमति प्रदान की जाती थी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था ।

प्रशान्त महासागर युद्ध छिड़ने के बाद, शत्रु-अधिकृत शहरों तथा गाँवों में जापान-विरोधी आन्दोलन और ज्यादा व्यापक तथा तेज हो गया । च्याङसू, जिसे शत्रु तथा उसके सहयोगी "गाँव तलाशी" मुहिम का केन्द्र मानते थे, में भी व्यापक स्तर पर किसानों के सशस्त्र विद्रोह भड़क उठे । अपनी चावल मंडी के लिए प्रसिद्ध ऊहू शहर में भूख से पीड़ित लगभग एक लाख लोगों ने हंगामा किया । छिङथाओ, थाएय्वान, थ्येनचिन, पेकिङ तथा अन्य नगरों में भुखमरी के शिकार लोगों ने चावलों के गोदाम लूट लिए । उत्तरी चीन में, जापान-विरोधी

आधार-क्षेत्रों के पास वाले शत्रु-अधिकृत इलाकों के लोगों ने लगान तथा सूद में कटौती के लिए संघर्ष करने के अलावा, टोह लेने, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने व फौजी कार्यवाहियों में शामिल होने के लिए भूमिगत संगठनों का गठन किया । शंघाई में, जो मध्यचीन में शत्रु की शासन-व्यवस्था का केन्द्रीय स्थल था, लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार थे जो अपने परिवारों को मिलाकर शहर की आबादी का आधे से ज्यादा थे । वहाँ के रिक्शाचालक लगातार हड़तालें कर रहे थे, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने कक्षाएं लगाना बन्द कर दिया था, औद्योगिक श्रमिकों ने या तो काम की रफ्तार धीमी कर दी थी या फिर हड़ताल पर चले गये थे । जहाँ तक, शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों के रेलवे कर्मचारियों का सवाल था, काम की रफ्तार धीमी रखना, तोड़-फोड़ करना व सामान को गुप्त रूप से गायब कर देना उनका रोजमर्रा का कार्य था ।

संक्षेप में 1943 से 1944 के बीच, नाजी जर्मनी पर सोवियत-संघ की विजय ने चीनी जनता के लिए प्रतिरोध-युद्ध में, अंतिम विजय के लिए प्रयास करने हेतु, एक अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दी । प्रशान्त महासागर युद्ध छिड़ जाने के बाद सभी जापान अधिकृत क्षेत्रों में जापान-विरोधी आन्दोलन और ज्यादा तीव्र हो गया तथा जापान व कठपुतली सरकार का शासन लड़खड़ाना शुरू हो गया ।

इन हालातों के मद्देनजर, उत्तरी चीन में—शानतुङ, शानशी-छाहाड़-हपे तथा शानशी-हपे-शानतुङ-हनान के मुक्त क्षेत्रों में, मध्यचीन में—उत्तरी च्याङसू, दक्षिणी च्याङसू, ह्वाएफेइ तथा हुपे-हनान-आनह्वेइ के इलाकों में; तथा दक्षिणी चीन में—तुङ च्याङ नदी तथा हाएनान द्वीप के इलाकों में आंशिक प्रत्याक्रमणों की एक शृंखला शुरू की गई ।

1944 में अकेले शानतुङ इलाके में ही 36,000 शत्रु तथा कठपुतली सैनिकों को ध राशायी कर दिया गया, 10,000 से ऊपर कठपुतली सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया गया, आठ काउंटी कस्बे तथा 1,18,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापिस ले लिया गया तथा 74 लाख से भी अधिक लोगों को मुक्त करा लिया गया ।

उसी साल, शानशी-हपे-शानतुङ-हनान क्षेत्र में, शत्रु के 1,000 से ऊपर दुर्गों पर कब्जा कर लिया गया, आठ काउंटी कस्बे तथा दो लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर का इलाका, जिसमें 50 लाख से अधिक आबादी थी, वापिस ले लिया गया ।

शानसी-छाहाड़-हपे क्षेत्र में शत्रु के 1500 से भी अधिक दुर्गों पर कब्जा कर लिया गया, 24 काउंटी कस्बे अस्थाई तौर पर वापिस ले लिये गये तथा शच्याच्वाङ तथा पाओतिङ जैसे महत्त्वपूर्ण शहरों को थोड़े-थोड़े समय के लिए दो बार मुक्त कराया गया । मध्य हपे के मैदानी इलाकों में विशाल भूभाग वापिस लिया गया । पेइप्वे क्षेत्र में, शत्रु की किलेबन्दियों की पहली पंक्ति को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया ।

शानशी-स्वेय्वान क्षेत्र में 97,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का इलाका वापिस ले लिया गया तथा 3,70,000 लोगों को मुक्त करा लिया गया । इस प्रकार पीली नदी की सुरक्षा पंक्ति को मजबूत किया गया ।

आंशिक प्रत्याक्रमण के फलस्वरूप, मध्य चीन में मुक्त क्षेत्र के आकार में विस्तार हुआ। उत्तरी तथा मध्य च्याङसू के इलाकों में याङत्सी नदी पर स्थित शिनशङ, छाङह्वाङ तथा शखाङ की बन्दरगाहों तथा पीले सागर पर स्थित छनच्या बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार शत्रु के जल परिवहन को खतरा पैदा हो गया । फूनिङ पर कब्जे के बाद, उत्तरी

सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग कर देती थी । एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के होने, उसकी पाँतों में एकता होने, देशभर की जनता के साथ एकजुटता होने, तथा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति होने के कारण, जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध तथा जनवादी क्रान्ति में विजय हासिल करना निःसन्देह संभव था । कामरेड माओ ने अपनी राजनीतिक रिपोर्ट में कहा :

"हर साथी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि जब तक हम जनता पर भरोसा करते हैं, जन-समुदाय की असीमित सृजन-शक्ति पर पक्का विश्वास रखते हैं तथा इसके फलस्वरूप जन-समुदाय पर विश्वास रखते हैं और उसके साथ एकजुट हो जाते हैं, तो कोई भी शत्रु हमें कुचल नहीं सकता और हम हर दुश्मन को कुचल देंगे, तथा हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं ।"[6]

रिपोर्ट में, जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध तथा जनवादी क्रान्ति में विजय प्राप्ति हेतु देश की समूची जनता को एकताबद्ध करने के लिए पार्टी के आम तथा ठोस कार्यक्रमों की विस्तार से व्याख्या की गई । आम कार्यक्रम के तहत, जापानी हमलावरों की हार के बाद एक नव-जनवादी समाज की स्थापना की जानी थी । इस समाज में, सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक नेतृत्व तथा उसके साथ-साथ सर्वहारा की अगुवाई में राजकीय कारोबार व सहकारी संस्थाएं समाजवादी तत्व होने थे । आगे घटनाक्रम ने अनिवार्य रूप से ऐसा मोड़ लेना था कि चीन में समाजवाद के सपने ने साकार हो जाना था।

ठोस कार्यक्रम का सम्बन्ध युद्धकालीन तथा युद्ध समाप्ति के बाद की समस्याओं से था। ये समस्याएँ थीं : जापानी हमलावरों की पूर्ण पराजय; एक जनवादी मिलीजुली सरकार की स्थापना; जनता को नागरिक अधिकारों की गारंटी करना; राष्ट्रीय एकता कायम करना; जन-सेना की स्थापना; कृषि-सुधार लागू करना; आधुनिक उद्योगों का विकास करना; जनता की संस्कृति को आगे बढ़ाना; चीन की सभी राष्ट्रीयताओं की समानता की गारन्टी करना; तथा एक स्वतन्त्र शांतिपूर्ण विदेश नीति लागू करना ।

लेकिन क्वोमिंताङ की एकदलीय तानाशाही को समाप्त किए बिना तथा जनवादी मिलीजुली सरकार की स्थापना के बिना इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता था ।

क्वोमिंताङ की एकदलीय तानाशाही में बड़े जमींदारों तथा बड़े-पूँजीपति वर्ग की तानाशाही थी । इस तानाशाही ने चीन की राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया था, यह जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध में क्वोमिंताङ वाले मोर्चे पर हार का कारण बनी थी तथा गृहयुद्ध की जड़ भी यही तानाशाही ही थी । इसलिए इसको समाप्त करना चीनी जनता की एक सर्वसम्मत माँग थी । फिर भी क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी गुट ने जनता की इस मांग को धत्ता बताने व इसका प्रतिकार करने का प्रयास किया । उसने *"राजसत्ता जनता को वापिस लौटाने"* के बहाने से "संविधान" पारित करवाने के लिए तथाकथित "राष्ट्रीय असेम्बली" का अधिवेशन बुलाया, जबकि वास्तव में राजसत्ता क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी गुट को ही लौटाई जानी थी ताकि वह अपना प्रतिक्रियावादी शासन कायम रख सके । यह कार्यदिशा—विभाजन की, गृहयुद्ध की कार्यदिशा थी, यह एक ऐसा फंदा था जो अंत में प्रतिक्रियावादियों के अपने ही गले में फंस जाना था । जैसा कि कामरेड माओ का कहना था : **"वे लोग खुद अपने ही गले में फंदा डाल रहे हैं तथा उसे कस रहे हैं, और यह फंदा 'राष्ट्रीय असेम्बली' है ।"[7]**

सार-संक्षेप प्रस्तुत किया ।

इस परिस्थिति के मद्देनजर, कांग्रेस ने पार्टी के आम राजनीतिक कार्यभार को निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया : "**.....हमारी पार्टी के मार्गदर्शन में जापानी हमलावरों को परास्त करने, समूची जनता को मुक्त कराने तथा एक नव-जनवादी चीन का निर्माण करने के उद्देश्य से साहसपूर्वक, जनसमुदाय को कार्यवाही करने के लिए आंदोलित करना तथा जन-शक्तियों को मजबूत करना ।**"[5] चीन, चीनी जनता का था, प्रतिक्रियावादियों का नहीं । चीनी जनता ही चीन के भाग्य को तय करेगी । कांग्रेस में अपने समापन भाषण के दौरान साथी माओ ने बड़ी ही निर्भीकता तथा जुझारूपन के साथ स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद, दो बड़े पहाड़ थे जो चीनी जनता पर एक बड़े भारी बोझ के रूप में लदे हुए थे तथा चीनी समाज के विकास में बाधा बने हुए थे, लेकिन उन्हें निःसन्देह हटाया जा सकता था यदि समस्त चीन का व्यापक जन-समुदाय कम्युनिस्टों के साथ इस संघर्ष में सम्मिलित हो जाता ।

सबसे पहले, हरावल दस्ते में एकता होनी जरूरी थी । मार्क्सवाद-लेनिनवाद से सुसज्जित, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जनता के सामने काम करने का एक नया ढंग पेश किया, इसकी विशेषता थी कि इसमें सिद्धान्त तथा व्यवहार का एकीकरण किया गया था, जनता से निकट सम्पर्क रखने तथा आत्मालोचना करने का तरीका अपनाया गया था । काम करने के इस ढंग के आधार पर ही पार्टी का विकास हुआ था, वह आगे बढ़ी थी तथा महान राजनीतिक संघर्ष में एकता अर्जित की थी । यही ढंग वह असाधारण विशिष्टता थी जो कम्युनिस्ट पार्टी को अन्य

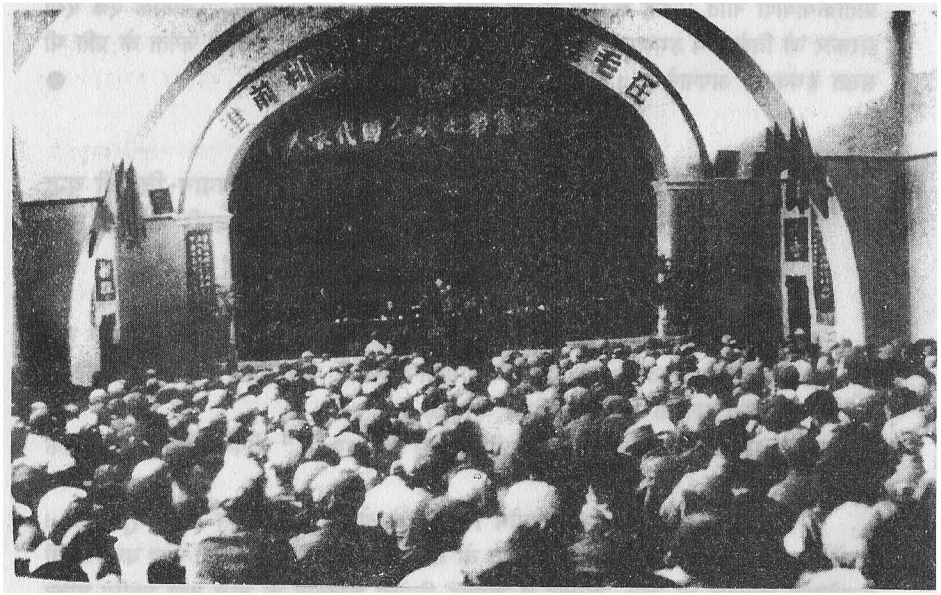

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दृश्य इस कांग्रेस ने जापान-विरोधी युद्ध की अंतिम विजय तथा क्रान्ति की देशव्यापी विजय में एक निर्णायक भूमिका अदा की

तथा मध्य च्याङसू के इलाकों का विलय कर दिया गया । दक्षिणी च्याङसू के इलाके में, एक के बाद एक करके चाङशिङ, लीयाङ तथा लीश्वेइ पर कब्जा कर लिया गया तथा छापामार दस्तों के बिखरे हुए आधार क्षेत्रों को मिला कर एक विशाल आधार-क्षेत्र बना दिया गया । मध्य आनह्वेइ क्षेत्र का विस्तार पूर्व में च्याङसू की सीमा तक तथा पश्चिम में हुपे की सीमा तक हो गया । हुपे-हनान-हुनान-च्याङशी सीमान्त-क्षेत्र तीन लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था तथा इसकी आबादी 90 लाख से अधिक थी ।

दक्षिणी चीन के मुक्त क्षेत्र का भी विस्तार किया गया । तुङ च्याङ नदी के इलाके का पूर्व में ह्वेइयाङ, पश्चिम में सानश्वेइ तथा शिनह्वेइ, उत्तर में चङछङ तथा दक्षिण में समुद्र-तट तक विस्तार किया गया । इससे कैंटन तथा हांगकांग में शत्रु के लिए स्पष्ट तौर से खतरा पैदा हो गया । हाएनान द्वीप में फौज की एक टुकड़ी डट कर छापामार युद्ध चला रही थी तथा द्वीप का विशाल देहाती क्षेत्र उसके नियंत्रण में था ।

1944 में, आठवीं राह सेना, नई चौथी सेना तथा दक्षिणी चीन के जापान-विरोधी कालम ने शत्रु तथा कठपुतली फौजों से 20,000 से अधिक लड़ाइयां लड़ीं, शत्रु के 2 लाख 60 हजार से अधिक सैनिक हताहत हुए, 60,000 से अधिक को युद्धबन्दी बनाया गया, 30,000 से अधिक कठपुतली सैनिकों का दिल जीतकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया गया, 16 काउंटी कस्बों को मुक्त कराया गया, दुश्मन के 5,000 दुर्गों पर कब्जा किया गया, 80 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक का इलाका वापिस ले लिया गया तथा 1 करोड़ 20 लाख से अधिक आबादी को मुक्त कराया गया । ●

2.

- **चीनी अफसरशाह-पूँजीवाद का भ्रष्ट प्रतिक्रियावादी शासन ।**
- **तीसरी कम्युनिस्ट-विरोधी बगावत की रोकथाम ।**
- **देशभर में जनवादी आंदोलन का उत्थान ।**
- **चीन के घरेलू मामलों में अमरीका का हस्तक्षेप ।**

जब मुक्त क्षेत्रों में पुनर्वास व विकास का कार्य चल रहा था, क्वोमिंताङ क्षेत्रों में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया ।

अर्ध-सामंती चीन की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी । दक्षिणपूर्वी प्रान्तों की अपेक्षा दक्षिणपश्चिमी तथा उत्तरपश्चिमी प्रान्त और ज्यादा पिछड़े हुए थे । प्रतिरोध युद्ध छिड़ने पर, तटीय प्रान्तों के औद्योगिक उद्यमों को एक-एक करके क्षेत्र के भीतरी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया । ऐसा 1940 तक चलता रहा । दक्षिणपश्चिमी तथा उत्तरपश्चिमी प्रान्तों में, युद्धरत क्षेत्रों से स्थानांतरित उद्योगों के अलावा, काफी तादाद में नए कारखाने भी स्थापित किये गये । दूसरे स्थानों से स्थानांतरित या नवनिर्मित फैक्ट्रियों में से ज्यादातर सछ्वान प्रान्त में थीं तथा शेष हुनान, शेनशी, क्वाङसी, युन्नान तथा अन्य प्रान्तों में थीं । दक्षिणपश्चिमी तथा उत्तरपश्चिमी चीन के विशाल इलाकों में विराट जन-शक्ति तथा भरपूर प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे । क्वोमिंताङ कट्टरवादियों ने इन सबका जापानी हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपनी ताकत में वृद्धि करने हेतु उपयोग करने की बजाय उन्हें पूरी बेरहमी से जी भरकर लूटा।

"चार बड़े घरानों" ने अपनी खुद की धन-दौलत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी का अनुचित लाभ उठाया ।

प्रतिरोध-युद्ध के दौरान चीनी अफसरशाह-पूँजीवाद का "चार बड़े घरानों" के नेतृत्व में बेहद तेज गति से विस्तार हुआ । जापान का प्रतिरोध करने की आड़ में, अफसरशाह पूँजीपतियों ने असाधारण-आर्थिक शोषण के अत्यधिक बर्बर हथकण्डों द्वारा अपने लिए अपार धन-दौलत इकट्ठी की तथा देश की सभी आर्थिक गतिविधियों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया।

चार सरकारी बैंकों का संयुक्त बोर्ड क्वोमिंताङ सरकार के वित्तीय एकाधिकार का घटक बन गया । उसने तथाकथित "राष्ट्रीय मुद्रा" को लूट-खसोट तथा एकाधिकार के हथकण्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रतिरोध-युद्ध के दौरान क्वोमिंताङ सरकार द्वारा जारी "राष्ट्रीय मुद्रा" की मात्रा 10,318 अरब चीनी डालर तक जा पहुँची । लोगों को उनकी सम्पत्ति तथा माल-असबाब के एवज में मूल्यहीन, रद्दी कागज के टुकड़े स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। "राष्ट्रीय मुद्रा" वह मुख्य हथकण्डा था जिसके माध्यम से "चार बड़े घरानों" ने चीनी जनता को लूटा तथा चीनी वित्त-व्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित कर लिया ।

युद्ध के दौरान, "चार बड़े घरानों" ने वित्तीय एकाधिकार को वाणिज्यिक एकाधिकार में बदल दिया । युद्धकाल में चार बड़े बैंकों का मुख्य काम वाणिज्यिक सट्टेबाजी करना था । जो ऋण दिए जाते थे, उनमें वाणिज्यिक ऋणों का प्रतिशत बहुत बड़ा होता था, जबकि औद्योगिक तथा खनन कार्यों के लिए दिए गए ऋण नगण्य थे । 1937 से 1942 तक के समय में कुल ऋणों का केवल 19.7 प्रतिशत फैक्ट्रियों तथा खानों को दिया गया; बाकी सारे का सारा, 80.3 प्रतिशत हिस्सा, वाणिज्यिक उद्यमों को दिया गया । "चार बड़े घरानों" ने एक व्यापार कमेटी बनाई जो वाणिज्यिक एकाधिकार का सरकारी घटक थी । इसके अतिरिक्त, वे अनेक निजी वाणिज्यिक उद्यमों के मालिक थे । उन्होंने कच्चे रेशम, चाय, तुङ तेल (Tung Oil), रेशे, वुलफ्रैम (Wolfram), तथा सुरमे जैसे निर्यात के माल के क्रय-विक्रय पर तथा इसके साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे—कपास, सूती धागा, कपड़ा, नमक, चीनी, सिगरेट तथा माचिस आदि की बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर लिया । कम दाम पर खरीद कर ज्यादा दाम पर बेचने के अपने बेशर्मीपूर्ण तरीके से उन्होंने किसानों, दस्तकारों तथा उद्योगपतियों को उनके न्यायसंगत मुनाफे से वंचित किया तथा देश भर के उपभोक्ताओं का शोषण किया।

"चार बड़े घरानों" द्वारा संचालित, औद्योगिक एकाधिकार का एक घटक—'उद्योग तथा खनन नियंत्रण कमीशन' था । इसने जो तरीका अपनाया, वह यूँ था—अफसरों द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों को अनुदान देना तथा आम नागरिकों के स्वामित्व वाले कारखानों पर कब्जा कर लेना । राष्ट्रीय संसाधन कमीशन तथा युद्ध-सामग्री के प्रशासनिक दफ्तर के अधिकार-क्षेत्र में नाममात्र के लिए भी आने वाले उद्योग, वास्तव में "चार बड़े घरानों" की सम्पत्ति बन गए थे। इसके अतिरिक्त "चार बड़े घराने", निजी रूप से भी उद्योगों को चलाते थे । 1945 में, राष्ट्रीय संसाधन कमीशन के अन्तर्गत उद्यमों के भारी उद्योगों का उत्पादन, क्वोमिंताङ क्षेत्रों के कुल उत्पादन की तुलना में यूँ था—कोयला-11.9 प्रतिशत; बिजली-35.9 प्रतिशत; कच्चा लोहा-46.5 प्रतिशत; इस्पात-56 प्रतिशत; तथा पैट्रोल, मिट्टी का तेल, खनिज लोहा, सुरमा तथा कलई; सभी 100 प्रतिशत । पूँजीनिवेश, विद्युत-शक्ति, तथा उत्पादन के मामलों में, अफसरशाही के उद्योगों की तूती बोलती थी । अनुमान के अनुसार अफसरशाह पूँजी, कुल पूँजी का लगभग

की कार्यकारिणी च्यान के सदस्यों के रूप में नियुक्त कर देता ।

इस छलपूर्ण षड्यन्त्र के माध्यम से अमरीका तथा च्याङ काई-शेक, कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार बनाने की माँग को ठुकराना, आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना से छुटकारा पाना तथा मुक्त क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे । जब कम्युनिस्ट पार्टी ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया तो हरले ने धमकी दी कि अमरीका केवल च्याङ काई-शेक के साथ ही सहयोग करेगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं; इसके साथ-साथ अमरीका चीन को ताकत के बल पर एकीकृत करने में च्याङ की मदद भी करेगा । चीन में अमरीकी फौजों के कमाण्डर, अलबर्ट सी.वेडेमेयर ने अपने मातहत सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किया कि वे ऐसे व्यक्तियों या ग्रुपों की मदद न करें जिनका सम्बन्ध क्वोमिंताङ सरकार से न हो । अमरीकी सरकार ने क्वोमिंताङ को बड़े पैमाने पर सामरिक साजोसामान की आपूर्ति करना तथा उसकी फौजों को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करना जारी रखा तथा इस प्रकार सक्रियता से चीनी जनता से उसके प्रतिरोध-युद्ध की विजय के फलों को छीनने की तैयारी में जुट गयी ।

कामरेड माओ ने अमरीकी नीति के पीछे छुपे हुए उसके कुत्सित इरादों का अच्छी तरह पर्दाफाश किया । उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति **"वर्तमान काल में जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के लिए तथा भविष्य में विश्वशान्ति के लिए बाधक बन जाएगी ।"**[1] उन्होंने चेताया कि इस प्रकार की नीति को लागू करने से अमरीकी सरकार पर कमरतोड़ बोझ लद जाएगा, क्योंकि **"इससे वह दसियों करोड़ जागृत अथवा जागृत हो रही चीनी जनता से दुश्मनी मोल ले लेगी।"**[2] उन्होंने अमरीकी जनता को भी सावधान किया कि उनकी सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति **"उन्हें बेअन्त दुःखों तथा मुसीबतों में डुबो देगी,"**[3] क्योंकि एक ऐसी सरकार जो विदेशों में हमलावर नीति अपना रही थी, निस्सन्देह उसने अपनी जनता के प्रति भी सख्त हथकण्डे अपनाने थे ।

3.

● चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जापान-विरोधी युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए निर्धारित बुनियादी नीतियां तथा युद्धोपरान्त बुनियादी कार्यभार ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस 23 अप्रैल, 1945 को येनान में शुरू हुई। इसमें 544 प्रतिनिधियों तथा 208 वैकल्पिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कुल मिलाकर 12,10,000 पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

कांग्रेस में साथी माओ ने **"मिलीजुली सरकार के बारे में"**[4] शीर्षक से एक राजनीतिक रिपोर्ट पेश की ।

कामरेड माओ ने मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ठोस विश्लेषण से रिपोर्ट शुरू की । उन्होंने अनुमान लगाया कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फासीवाद विरोधी जनता तथा बची-खुची फासीवादी शक्तियों के बीच, जनवाद व जनवाद-विरोधी शक्तियों के बीच तथा राष्ट्रीय मुक्ति व राष्ट्रीय दमन के बीच अभी और संघर्ष होना था । उन्होंने बड़े ही स्पष्ट ढंग से जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध में दो कार्यदिशाओं तथा दो भविष्यों के बीच जारी संघर्ष का

उन्होंने स्वयं को **"तीन जन-सिद्धातों के समर्थकों की एसोसिएशन"** के रूप में संगठित कर लिया ।

क्वोमिंताङ तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में वार्तालाप शुरू होने के बाद, छङतू, खुनमिङ, छुङकिङ तथा अन्य स्थानों के देशभक्त जनवादियों ने जनवाद तथा राजनीतिक सुधारों को लागू करने तथा फासीवाद का अन्त करने की मांग की । सितम्बर 1944 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जनवादी मिलीजुली सरकार की स्थापना का आह्वान किया तो क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों के विभिन्न जनवादी दलों तथा ग्रुपों, राष्ट्रीय उद्योगपतियों तथा व्यापारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा पत्रकारों, सभी ने इसका जोरदार समर्थन किया, तथा सर्वसम्मति से क्वोमिंताङ की एकदलीय तानाशाही को समाप्त करने की मांग की । शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र तथा शत्रु की पाँतों के पीछे स्थित आधार-क्षेत्रों की जनता के सभी समुदायों ने एक आवाज से क्वोमिंताङ सरकार तथा सेना की कमान के पुनर्गठन की मांग की । छुङकिङ, छङतू तथा खुनमिङ के जनवादियों ने **'जनवाद के उत्थान के लिए सोसाइटी'** (Society for the Promotion of Democracy) का गठन किया, सभाएं कीं तथा प्रदर्शन किए । जनवादी मिलीजुली सरकार के लिए आह्वान ने क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में जनवाद के लिए एक आन्दोलन खड़ा कर दिया ।

लेकिन एक आक्रामक विदेशी शक्ति ने चीनी जनता के इस आन्दोलन में हस्तक्षेप किया। अमरीका ने, जिसे अब प्रशान्त महासागर युद्ध में जापान पर बढ़त हासिल हो गई थी, अपना आक्रामक प्रभाव चीन तक फैलाने का प्रयास किया ताकि चीनी बाजार पर जो जापानी एकाधिकार था, वह अब उसके हाथों में स्थानांतरित हो जाए तथा चीन को अमरीकी उपनिवेश में बदल दिया जाए । इस उद्देश्य के लिए, अमरीका ने *'ऋण-पट्टा-कानून'* (Lend-Lease Act) तथा जापान से लड़ने की आड़ में, क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी शासन को विपुल मदद की । बहुत बड़ी संख्या में अमरीकी "विशेषज्ञ" क्वोमिंताङ सरकार में घुसपैठ कर गए; अमरीकी अफसरों ने क्वोमिंताङ सैनिकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया; विशाल मात्रा में युद्ध-सामग्री की आपूर्ति की गई तथा अमरीका ने फौजी परिवहन पंक्तियां आरंभ कर दीं ।

जब चीनी जनता जनवादी मिलीजुली सरकार के गठन के लिए संघर्ष कर रही थी, अमरीका ने निष्पक्ष रहने का ढोंग रचते हुए, क्वोमिंताङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की । "तीसरे पक्ष" के रूप में अमरीकी प्रतिनिधि—पैट्रिक जे. हरले, येनान पहुँचा तथा कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता-वार्ता की । जनवादी मिलीजुली सरकार तथा सांझा सर्वोच्च कमान की स्थापना करने के संबंध में एक समझौता हो गया ।

लेकिन जल्दी ही अमरीकी सरकार ने यह जाहिर कर दिया कि वह च्याङ काई-शेक की तरफदार थी । जब हरले छुङकिङ वापिस लौटा, तो उसने येनान में सम्पन्न हुए समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तथा च्याङ काई-शेक को सक्रिय रूप से मदद देने में जुट गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कहा गया कि वह अपनी फौजों को या तो च्याङ काई-शेक के नियन्त्रण वाली क्वोमिंताङ फौजी परिषद के अधीन कर दे या तीन सदस्यीय कमेटी के अधीन कर दें । इस तीन सदस्यीय कमेटी में क्वोमिंताङ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अमरीका के प्रतिनिधि होने थे, जिसमें अमरीकी प्रतिनिधि का प्रमुख स्थान था । बदले में, च्याङ काई-शेक कम्युनिस्ट पार्टी को कानूनी मान्यता प्रदान करता तथा कुछ कम्युनिस्टों को क्वोमिंताङ सरकार

70 प्रतिशत थी । "चार बड़े घरानों" के औद्योगिक एकाधिकार ने राष्ट्रीय उद्योगों तथा वाणिज्य का गला घोंट दिया था ।

कृषि-क्षेत्र में, "चार बड़े घराने" सबसे बड़े जमींदार तथा सूदखोर थे । भूमि-कर की उगाही करने में शोषण का क्रूरतम तरीका इस्तेमाल किया जाता था । उदाहरण के लिए सछ्वान में पूरी कृषि-उपज का आधे से ज्यादा भूमि-कर के रूप में देना पड़ता था । और यह सारे का सारा बोझ पूरी तरह किसानों के कन्धों पर ही पड़ता था । चीन के किसान बैंक ने, जिसका नियन्त्रण "चार बड़े घरानों" के हाथों में था, पुराने जमाने के सूदखोरों का स्थान ने लिया था। उसके कृषि ऋणों का स्वरूप सूदखोरी जैसा था, क्योंकि ऋणावधि एक साल की होती थी तथा किसानों को कमी के मौसम में, जब अनाज की कीमतें आसमान छूने लगती थीं, ऋण लेने पर विवश होना पड़ता था, तथा फसल कटाई के मौसम में, जब कृषि उपज की कीमतें अत्यधिक गिर जाती थीं, ऋण वापिस करना पड़ता था । इस प्रकार उनका दोनों मौकों पर बेरहमी से शोषण किया जाता था । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सूदखोरों के माध्यम से प्रदान किए जाते थे, अतः किसानों का शोषण और ज्यादा बढ़ जाता था । इस प्रकार किसान बैंक एक ही वक्त में दो अपराध करता था : सामन्ती ताकतों का पोषण करना, तथा किसानों का खून चूसना ।

युद्ध के दौरान अफसरशाह-पूँजीपतियों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार जमाने तथा अपने हाथों में अकूत धन-दौलत इकट्ठी करने के लिए किए गए गहन प्रयासों के फलस्वरूप, चीन के उत्पादनकारी उद्यम पूरी तरफ नष्ट हो गए । क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी शासन का आर्थिक आधार जड़ तक सड़-गल गया । यही मुख्य कारण था कि क्वोमिंताङ कट्टरवादियों ने अपना तानाशाही शासन कायम रखने के लिए जनवाद का गला घोंटने की व जापानी हमले का निष्क्रिय प्रतिरोध करने की नीतियाँ अपनाईं ।

अपनी प्रतिक्रियावादी घरेलू नीति को लागू करने के लिए क्वोमिंताङ ने अपने फासीवादी शासन का दमनचक्र तेज कर दिया । जनवाद का गला घोंटने के लिए 'सी०सी०गुट' तथा 'राष्ट्रीय पुनरुद्धार सभा' इसके सबसे अधिक सुविधाजनक औजार थे, तथा इसके फासीवादी तानाशाही शासन के शक्तिशाली स्तम्भ थे । उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी तथा इसके नेतृत्व में चलने वाली जापान-विरोधी फौजों, देशभक्त जनवादियों, तथा खुद क्वोमिंताङ के भीतर मौजूद च्याङ काई-शेक के विरोधी ग्रुपों के खिलाफ दमनकारी हथकण्डे अपनाने में महारत हासिल थी । प्रथम, वे गुप्त रूप से कम्युनिस्टों तथा प्रगतिशीलों की हत्या करते थे तथा क्वोमिंताङ क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत संगठनों को नष्ट करते थे । दूसरे, वे बहुत बड़ी तादाद में खुफिया एजेन्टों को प्रशिक्षित करते थे, जो शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र तथा शत्रु-पंक्तियों के पीछे के आधार-क्षेत्रों में जासूसी व तोड़-फोड़ करने के लिए चोरी-छिपे घुसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे । तीसरे, उन्होंने शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत संगठनों तथा अन्य जापान-विरोधी ग्रुपों को नष्ट करने के लिए जापानियों व कठपुतली संस्थाओं से गठजोड़ किया । संक्षेप में, च्याङ काई-शेक की प्रतिक्रियावादी नीति के अनुरूप इन संस्थाओं ने युद्ध की हर मंजिल में सभी तरह के गन्दे काम किए ।

1943 में, जब फासीवाद विरोधी विश्वयुद्ध, विजय की तरफ एक निर्णायक मोड़ काटने ही वाला था, क्वोमिंताङ कट्टरतावादियों ने जन-सेनाओं को कुचलने व जापानी हमलावरों की

हार के बाद युद्ध की विजय के फल हड़पने के लिए, तीसरे कम्युनिस्ट-विरोधी हमले का षड्यन्त्र रचा ।

च्याङ काई-शेक ने हमला शुरू करने से पहले, जन-समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से विचारधारात्मक स्तर पर तैयारियां शुरू कीं ।

मार्च 1943 में, च्याङ काई-शेक ने अपनी कुख्यात पुस्तक *''चीन का भाग्य''* प्रकाशित की, जिसमें उसने घरेलू समस्याओं का समाधान करने, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा सभी क्रांतिकारी ताकतों को दो साल के अन्दर-अन्दर नष्ट कर देने का इरादा जाहिर किया । इसके अतिरिक्त, तीसरी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भंग होने के मौके का फायदा उठाते हुए, उसने क्वोमिंताङ क्षेत्रों में अपने खुफिया एजेंटों को आदेश दिया कि वे ''लोकप्रिय संगठनों'' के धूमावरण में कम्युनिस्ट पार्टी को भंग करने की मांग करें ।

जून 1943 में, जब उसकी सोच के अनुसार सभी इन्तजाम कर लिये गये तब उसने पीली नदी पर तैनात क्वोमिंताङ रक्षक फौजों को शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया । 7 जुलाई, 1943 को उन्होंने सीमान्त-क्षेत्र पर गोलाबारी शुरू कर दी तथा जबरदस्त क्षति पहुँचाने व येनान पर कब्जा करने के लिए नौ अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ने की योजना बनाई । कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने समय रहते, च्याङ काई-शेक द्वारा पीली नदी से अपनी सेनाएं हटाने व कम्युनिस्ट पार्टी को भंग करने की मांग करने के उसके प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रों का भण्डाफोड़ किया तथा एक खुले तार के जरिये शान्ति की रक्षा करने व गृहयुद्ध का विरोध करने के लिए समस्त राष्ट्र का आह्वान किया । इसी दौरान सीमान्त-क्षेत्र तथा मुक्त क्षेत्रों के सैनिकों एवं जनता ने सभाएँ कीं, विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए तथा प्रत्याक्रमण के लिए तैयारियाँ कीं । चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ कट्टरवादियों के षड्यन्त्रों का भण्डाफोड़ व भर्त्सना करके, उनकी कार्यवाहियों को पहले से ही रोकने का प्रबन्ध कर लिया था तथा उनकी प्रति-क्रांतिकारी नीति के विरुद्ध डट कर संघर्ष किया था और चूँकि देशभर की जनता ने इसके खिलाफ अपना जबरदस्त विरोध प्रकट किया था, अतः क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को अपना तीसरा कम्युनिस्ट-विरोधी हमला रोकने को विवश होना पड़ा । फासीवाद-विरोधी युद्ध के निर्णायक मोड़ लेते ही जापान एक अंधी गली में फंस गया। यूरोप के मोर्चे पर सोवियत-संघ की महान विजय के फलस्वरूप, ब्रिटेन तथा अमरीका के लिए अपनी सेनाओं का एक हिस्सा प्रशान्त मोर्चे पर भेजना व हमला शुरू करना संभव हो गया । चीन के मुक्त क्षेत्रों की जनता द्वारा शुरू किए गये सफल प्रत्याक्रमण के फलस्वरूप हमलावरों की कठिनाइयाँ और ज्यादा बढ़ गईं । इसलिए जापानियों ने पेकिङ से कैंटन तथा नाननिङ तक थलमार्ग से एक परिवहन-पंक्ति चालू करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य, प्रशान्त महासागर में स्थित उसकी फौजों, जिनकी हालत बदतर होती जा रही थी, को चीन की मुख्य भूमि पर स्थित उसकी सेनाओं से जोड़ना था । साथ ही, इसका उद्देश्य चीन में उसकी अन्य फौजी कार्यवाहियों को संभव बनाना भी था। 1944 में उन्होंने क्वोमिंताङ क्षेत्रों पर हमला शुरू किया । इसे *हनान-हुनान-क्वाङशी अभियान* के नाम से जाना जाता है ।

मार्च 1944 में, जापानी सेना ने हनान में क्वोमिंताङ फौजों पर हमला किया । मई में उसने उत्तरी हुनान पर तथा अगस्त में दक्षिणी हुनान पर चढ़ाई कर दी । 2 दिसम्बर को, उसने क्वेइचओ प्रान्त की तुशान काउंटी पर कब्जा कर लिया था । इस प्रकार आठ मास की

अल्पावधि में ही जापानी हमलावरों ने हनान, हुनान, क्वाङशी, क्वाङतुङ तथा फूच्येन प्रान्तों के अधिकांश हिस्से पर तथा क्वेइचओ के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया तथा अपने लिए उत्तरपूर्वी चीन से हिन्द-चीन तक थलमार्ग से परिवहन-पंक्ति सुनिश्चित कर ली । क्वोमिंताङ सेना के पाँच लाख से ऊपर सैनिक मारे गए तथा विभिन्न आकारों के 146 शहर उसके हाथ से निकल गए तथा 6 करोड़ की आबादी दुश्मन के कब्जे में चली गई । हमलावरों के भय से त्रस्त तथा बौखलाए हुए क्वोमिंताङ सैनिकों की अनर्थकारी भगदड़ से एक बार फिर जनता पर अकथनीय मुसीबतें टूट पड़ीं ।

इस तरह का भ्रष्टाचार तथा नपुंसकता क्वोमिंताङ की प्रतिक्रियावादी फासीवादी नीति का ही स्वाभाविक नतीजा था ।

समूचे देश की जनता क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की आर्थिक लूट-खसोट, प्रतिक्रियावादी राजनीति तथा फौजी पराजयों को और अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं । उन्हें स्पष्ट तौर से बता दिया गया था कि प्रत्याक्रमण के लिए तैयार होने तथा युद्ध की शीघ्र-समाप्ति का केवल एक ही रास्ता था, और वह था—प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार में व्यापक स्तर पर सुधार किया जाना ।

अप्रैल से अगस्त 1944 तक, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ के साथ समझौते की बातचीत की । जनता के संकल्प तथा इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के साथी लिन पो-छ्वी ने मांग की कि क्वोमिंताङ राजनीतिक जनवाद को व्यावहारिक स्तर पर लागू करे तथा दोनों पार्टियों के बीच विचाराधीन पड़े मुद्दे—जापान-विरोधी फौजों तथा जापान-विरोधी आधार-क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करने की समस्या को निपटाए । परन्तु क्वोमिंताङ ने, न केवल राजनीतिक जनवाद लागू करने के प्रश्न पर बातचीत करने से इन्कार कर दिया, बल्कि आठवीं राह सेना तथा नई चौथी सेना के तीन चौथाई भाग को भंग करने (बाकी को एक निश्चित अवधि के दौरान एकत्रित करने) तथा शत्रु-पंक्तियों के पीछे स्थित जापान-विरोधी जन-सरकारों को भंग करने का भी प्रयास किया । क्वोमिंताङ कट्टरतावादियों द्वारा बाधाएं खड़ी किये जाने के कारण इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला ।

सितंबर 1944 में, छुङकिङ में क्वोमिंताङ द्वारा **राष्ट्रीय राजनीतिक परिषद** की मीटिंग बुलाई गई । इसमें लिन पो-छ्वी ने प्रस्ताव रखा कि राज्य के मामलों पर विचार-विमर्श के लिए एक आपातकालीन सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें सभी जापान-विरोधी पार्टियों तथा ग्रुपों, जापान-विरोधी सैनिकों, स्थानीय सरकारों तथा जन-संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लें; उन्होंने क्वोमिंताङ की एकदलीय तानाशाही को समाप्त करने व जनवादी मिलीजुली सरकार स्थापित करने की मांग भी की । समस्त देश की जनता ने इन प्रस्तावों का दिल खोल कर स्वागत किया तथा जनवादी राजनीतिक ग्रुपों की लीग की उत्तराधिकारी, जनवादी लीग तथा क्वोमिंताङ के ही जनवादी खेमे ने भी इन प्रस्तावों का समर्थन किया ।

सितम्बर 1944 में, जनवादी लीग ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा की । उसका मानना था कि राज्य के मामलों को लेकर शीघ्र ही एक सम्मेलन बुलाया जाए तथा राजनीतिक सुधार लागू करने व युद्धकालीन संकट पर विजय प्राप्ति के लिए एक मिलीजुली सरकार का गठन किया जाए । क्वोमिंताङ के अन्दर भी अनेक जनवादियों ने, जो कट्टरतावादियों के तानाशाही शासन से असंतुष्ट थे, सरकार तथा क्वोमिंताङ के जनवादीकरण की मांग की ।

की गई थी कि दोनों पक्ष दृढ़ता से गृहयुद्ध की रोकथाम करेंगे तथा शांति, जनवाद, एकता व एकीकरण के आधार पर एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, समृद्ध तथा शक्तिशाली नए चीन का निर्माण करेंगे। आन्तरिक शांति की सुरक्षा के उपाय भी समझौते में निहित थे, मसलन देश के शांतिपूर्ण निर्माण पर विचार करने के लिए एक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन करना।

देश के शान्तिपूर्ण निर्माण के लिए जो नीति चाहिए थी, वह जनता की सर्वाधिक विश्वासपात्र प्रतिनिधि—कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्धारित शान्ति, भाईचारे, जनवाद तथा एकता की नीति के अलावा और कुछ न थी। और जनता की इसी सर्वाधिक जरूरी व लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जीजान से प्रयासरत थी।

समझौता-वार्ता के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सी रियायतें दीं। उसने क्वाङतुङ, चच्याङ, दक्षिणी च्याङसू, दक्षिणी आनह्वेइ, मध्य आनह्वेइ, हुनान, हुपे तथा हनान के आठ मुक्त क्षेत्रों से जन-मुक्ति सेना की वापसी तथा 13 लाख संख्या वाली विशाल मुक्ति सेना को पुनर्गठित कर 20 या 24 डिवीजनों तक सीमित करने की बात की। समझौता-वार्ता के दौरान तथा उसके तुरन्त बाद, नई चौथी सेना याङत्सी नदी के साथ लगते कई जिलों से पीछे हट गई तथा लुङहाए रेलमार्ग के उत्तर, उत्तरी च्याङसू तथा उत्तरी आनह्वेइ में स्थित मुक्त इलाकों में एकत्रित हो गई।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वादे के अनुसार समझौते का पूरी ईमानदारी से पालन किया। सारे राष्ट्र ने देश तथा जनता के हितों के प्रति इसकी असीम श्रद्धा को, तथा शान्ति व राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए इसके अथक प्रयासों को देखा।

लेकिन क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने इस समझौते को केवल गृहयुद्ध शुरू करने के लिए एक धूमावरण के तौर पर इस्तेमाल किया। 17 सितंबर, 1945 को जबकि समझौता-वार्ता अभी चल ही रही थी, च्याङ काई-शेक ने अपने चमचों तथा अफसरों में गुप्त रूप से *''डाकू-विनाश निर्देशन पुस्तिका''* वितरित की। 13 तथा 15 अक्तूबर को जब समझौते के दस्तावेज अभी प्रकाशित ही हुए थे उसने क्वोमिंताङ सेनाओं को जन-मुक्ति सेना पर हमला करने का आदेश दिया। नवम्बर, 1945 में उसने छुङकिङ में एक सैनिक सम्मेलन बुलाया जिसमें मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियां करने के बारे में एक विस्तृत योजना तैयार की गई।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने गृहयुद्ध छेड़ने के लिए अपनी 12 लाख 70 हजार फौजों को एकत्रित किया तथा जापानी व कठपुतली सेना के 5 लाख सैनिकों को निर्देशित अथवा पुनर्गठित किया। हपे, शानशी, शानतुङ, स्वेय्वान, छाहाङ, च्याङसू, चच्याङ, हनान, हुपे, आनह्वेइ तथा क्वाङतुङ नामक ग्यारह प्रान्तों के मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर हमला शुरू कर दिया गया। जब नई चौथी सेना उत्तर की ओर पीछे हटने के आदेशों का पालन कर रही थी, क्वोमिंताङ सेनाओं ने बार-बार उसका रास्ता रोका तथा पीछा किया।

सितम्बर 1945 में, जन-मुक्ति सेना चाङच्याखओ पर क्वोमिंताङ के हमले को रोकने में सफल रही तथा अगले महीने के अन्त तक उसने शत्रु सेनाओं को पूरी तरह तितर-बितर कर दिया। अक्तूबर 1945 के मध्य में शानशी प्रान्त की श्याङय्वान, छाङचि, थुनल्यू तथा आसपास की अन्य काउंटियों में हुई मशहूर लड़ाई में, हमलावर शत्रु सेना के 30,000 सैनिकों का सफाया कर दिया गया। इसी महीने के अंत में चाङते से उत्तर की ओर पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के साथ-साथ कूच कर रही 70,000 की एक अन्य क्वोमिंताङ सेना का भी यही हाल हुआ। कुल मिलाकर 1,10,000 शत्रु सैनिकों का, अर्थात् क्वोमिंताङ की हमलावर सेना के

जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के दौरान आधार-क्षेत्रों का मानचित्र

(1944 के उत्तरार्द्ध से 1945 के पूर्वार्द्ध तक)

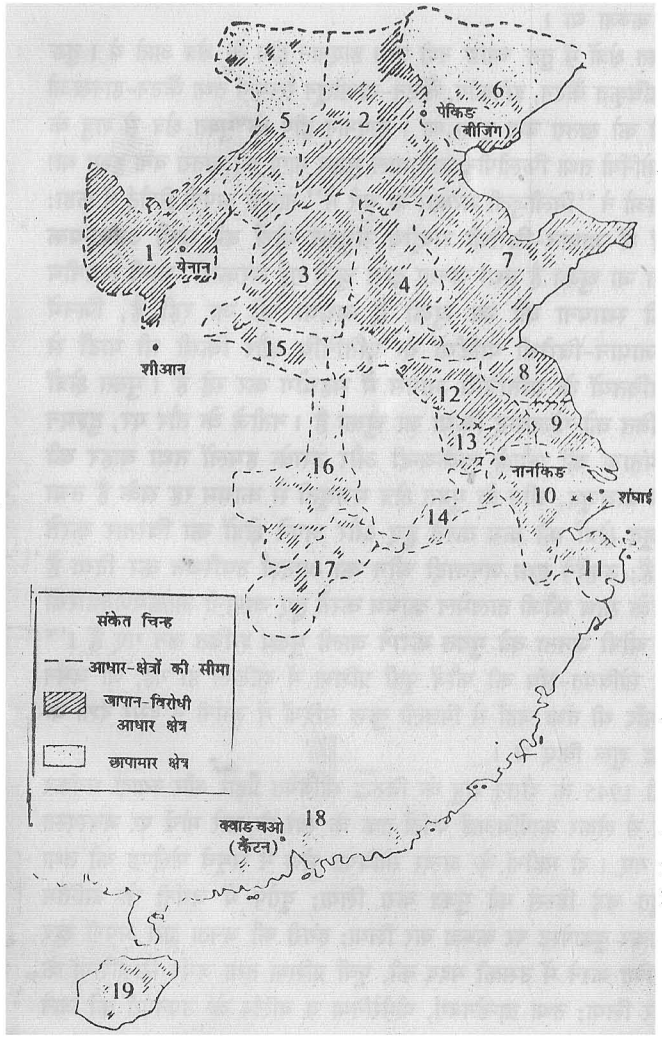

1. शेनशी-कानसू-निङश्या क्षेत्र
2. शानशी-छाहाङ-हपे क्षेत्र
3. शानशी-हपे-हनान क्षेत्र
4. हपे-शानतुङ-हनान क्षेत्र
5. शानशी-स्वेय्वान क्षेत्र
6. हपे-जेहोल-ल्याओनिङ क्षेत्र
7. शानतुङ क्षेत्र
8. उत्तरी च्याङसू क्षेत्र
9. मध्य च्याङसू क्षेत्र
10. च्याङसू-चच्याङ-आनह्वेइ क्षेत्र
11. पूर्वी चच्याङ क्षेत्र
12. ह्वाएफेइ क्षेत्र (ह्वाए नदी के उत्तर में)
13. ह्वाएनान क्षेत्र (ह्वाए नदी के दक्षिण में)
14. मध्य आनह्वेइ क्षेत्र
15. हनान क्षेत्र
16. हुपे-हनान-आनह्वेइ क्षेत्र
17. हुनान-हुपे क्षेत्र
18. तुङ च्याङ नदी क्षेत्र
19. हाएनान द्वीप क्षेत्र

इनमें च्याङसू का अधिकांश हिस्सा, आनह्वेइ तथा हुपे के विशाल भूभाग, हनान तथा चच्याङ के हिस्से तथा हुनान का थोड़ा सा हिस्सा आते थे । ये नानकिङ, शंघाई, ऊहान, श्वीचओ तथा हाङचओ के शत्रु के गढ़ों के लिए खतरा बने हुए थे, तथा थ्येनचिन-फूखओ रेलमार्ग, पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के दक्षिणी हिस्से, ह्वाएनान रेलमार्ग तथा इन इलाकों के स्थल व जल परिवहन-तन्त्र पर इनका कब्जा था ।

दक्षिणी चीन के मुक्त क्षेत्रों में तुङ च्याङ नदी तथा हाएनान द्वीप के क्षेत्र आते थे । तुङ च्याङ नदी क्षेत्र से शत्रु-अधिकृत कैंटन, हांगकांग, कैंटन-खओलून रेलमार्ग तथा कैंटन-हानखओ रेलमार्ग के दक्षिणी हिस्से को खतरा बना हुआ था । हाएनान द्वीप के मुक्त क्षेत्र से शत्रु के वियतनाम, मलाया, डच बोर्नियो तथा फिलीपीन जाने वाले मुख्य मार्गों को खतरा बना हुआ था।

जैसा कि कामरेड माओ ने "मिलीजुली सरकार के बारे में" नामक अपनी रिपोर्ट में कहा:

"सभी मुक्त-क्षेत्रों में जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की सभी आवश्यक नीतियों पर अमल किया जा चुका है तथा जनता द्वारा चुनी गई सरकारों, यानी स्थानीय मिलीजुली सरकारों की स्थापना की जा चुकी है अथवा की जा रही है, जिनमें कम्युनिस्ट तथा अन्य जापान-विरोधी पार्टियों के प्रतिनिधि और किसी भी पार्टी से संबंध न रखने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि आपस में सहयोग कर रहे हैं । मुक्त क्षेत्रों में जनता की समूची शक्ति को गोलबन्द किया जा चुका है । नतीजे के तौर पर, दुश्मन के भारी दबाव, क्वोमिंताङ की फौजी नाकेबन्दी और उसके हमलों तथा बाहर की मदद के पूर्ण अभाव के बावजूद, चीन के मुक्त क्षेत्र मजबूती से कायम रह सके हैं तथा दुश्मन के कब्जे में मौजूद क्षेत्रों को कम करते हुए और अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हुए लगातार बढ़ते रहे हैं; उन्होंने एक जनवादी चीन का आदर्श उपस्थित कर दिया है तथा वे संश्रयकारी देशों के साथ फौजी तालमेल कायम करते हुए जापानी आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ने और चीनी जनता को मुक्त कराने वाली मुख्य शक्ति बन गए हैं ।"[18]

1944 के अन्त में, सोवियत-संघ की फौजें पूर्वी प्रशिया में दाखिल हो गईं, जो जर्मन फासीवादियों की प्रमुख माँद थी तथा जहाँ से पिछली कुछ सदियों में जर्मनी ने दूसरे देशों के विरुद्ध आक्रमणकारी-युद्ध शुरू किए थे ।

जनवरी तथा फरवरी 1945 के दौरान शत्रु के विरुद्ध सोवियत प्रहार और ज्यादा भयंकर हो गया । बाल्टिक सागर से लेकर कार्पेथिआई पर्वतों तक के सारे के सारे मोर्चे पर जबरदस्त सफाया अभियान चलाए गए । दो महीनों के अन्दर सोवियत सेना ने समूचे पोलैण्ड को तथा चेकोस्लोवाकिया के बहुत बड़े हिस्से को मुक्त करा लिया; यूरोप में जर्मनी के अन्तिम संश्रयकारी, हंगरी को हराकर बुडापेस्ट पर कब्जा कर लिया; हंगरी की जनता द्वारा अपनी खुद की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में उसकी मदद की, पूर्वी प्रशिया तथा जर्मन सिलेशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया; तथा ब्रान्डेनबर्ग, पोमेरेनिया व बर्लिन के उपनगरों को जाने वाले मार्गों को खोल दिया ।

इसी दौरान, ब्रिटिश तथा अमरीकी सेनाओं ने भी पश्चिमी मोर्चे पर हमले शुरू कर दिए। फ्रांस से गुजरते हुए तथा राइन नदी को पार करते हुए वे पश्चिमी जर्मनी में दाखिल हो गए तथा एल्बे नदी तक पहुँच गए । चूंकि जर्मन सेना की मुख्य सैन्य-शक्तियां अभी भी पूर्वी मोर्चे पर ही केन्द्रित थीं, इसलिए उन्हें (ब्रिटेन व अमरीका की फौजों को) ज्यादा तीव्र प्रतिरोध का

जाने वाली जमीन पर उनके स्वामित्व को मान्यता दी तथा लगान व सूद में कटौती करने की नीति के स्थान पर जमींदारों की जमीन की जब्ती करने व उसे किसानों में वितरित करने की नीति की घोषणा की । गद्दारों, स्थानीय निरंकुश तत्वों तथा जमींदारों के दावे रद्द कर दिए गए; मध्यवर्ती तत्वों के सन्देह को दूर किया गया, तथा पार्टी में गलत विचारों को सुधारा गया । कृषि सुधारों का किसानों द्वारा बड़े उत्साह से समर्थन किया गया, तथा इससे मुक्त क्षेत्रों की रक्षा करने तथा शान्ति व जनवाद के लिए संघर्ष करने का उनका संकल्प और ज्यादा दृढ़ हो गया । इस प्रकार, प्रतिक्रियावादियों से लड़ने में वे पार्टी की बुनियादी शक्ति बन गए । ●

3.

- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शान्ति, जनवाद, भाईचारे व एकीकरण की नीति।**
- **क्वोमिंताङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बातचीत ।**
- **युद्ध-विराम समझौता तथा राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन ।**

सारे देश की जनता युद्ध के लंबे वर्षों में अथाह दिक्कतों का सामना करने के बाद, अब फिर नए गृहयुद्ध के खतरे को अपने सिर पर मंडराता देख रही थी; इसलिए शान्ति, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, राजनीतिक जनवाद तथा सामाजिक मुक्ति के लिए उसकी उत्कट अभिलाषा थी । समस्त चीनी जनता ने शांतिपूर्ण राष्ट्रीय निर्माण की तत्काल मांग की क्योंकि यही एक रास्ता था जिसके तहत जापानी सैनिकवाद को रोका जा सकता था, युद्ध के घावों पर मरहम लगाई जा सकती थी, चीन की सामाजिक उत्पादक शक्तियों का जीर्णोद्धार व विकास हो सकता था, जनता के अत्यावश्यक हितों की रक्षा की जा सकती थी तथा सुदूर पूर्व में शांति को सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती थी । मध्यम वर्ग तथा उसकी राजनीतिक पार्टियाँ अभी भी अमरीकी सरकार तथा क्वोमिंताङ से आस लगाए बैठी थीं । वे *"अमरीकी किस्म के लोकतन्त्र"* की प्रशंसा करती थीं, अमरीका सरकार की ढोंगपूर्ण "तटस्थता" तथा "मध्यस्ता" के झांसे में थीं तथा गलती से क्वोमिंताङ सरकार की "वैधता" में विश्वास किए बैठी थीं ।

जनता के संकल्प तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दृढ़ता से शांति तथा जनवाद के झंडे को बुलन्द किया तथा गृहयुद्ध टालने व शांति स्थापित करने के लिए रास्ता ढूँढने में लोगों का मार्गदर्शन करने के अथक प्रयास किए ।

25 अगस्त, 1945 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने *"वर्तमान परिस्थिति के बारे में एक घोषणापत्र"* जारी करते हुए, शान्ति, जनवाद तथा एकता के आधार पर सारे देश का एकीकरण करने के लिए जनता का आह्वान किया तथा शांति, जनवाद, एकता तथा एकीकरण की स्थापना करने, व गृहयुद्ध टालने के लिए आपातकालीन उपायों को लागू करने को पार्टी की मूलभूत नीति तथा संघर्ष के प्रथम लक्ष्य के रूप में निर्दिष्ट किया ।

28 अगस्त, 1945 को इस बारे में क्वोमिंताङ से बातचीत करने के लिए कामरेड माओ त्से-तुङ चुङकिङ गए । बातचीत 43 दिनों तक चली तथा 10 अक्तूबर, 1945 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्वोमिंताङ के प्रतिनिधियों ने *"क्वोमिंताङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के सारांश"* पर हस्ताक्षर किए जो **"10 अक्तूबर समझौते"** के रूप में जाना गया । दो दिन बाद प्रकाशित किये गए इस समझौते में व्यवस्था

निहत्था करने के लिए चीनियों की "मदद" करने के बहाने अमरीका ने छिङताओ, थ्येनचिन तथा अन्य शहरों में अपने सैनिक तैनात कर दिए । छिनवाङताओ, शानतुङ प्रायद्वीप तथा अन्य स्थानों पर अमरीकी फौजों ने खुल्लम-खुल्ला चीन के मुक्त क्षेत्रों पर हमला किया तथा चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया ।

अमरीकी सरकार के समर्थन से, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने शत्रु तथा उसकी कठपुतलियों के "शासन" को अक्षुण्ण बनाए रखा तथा उनकी सभी फासीवादी फौजी, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाओं को बिना कोई बदलाव किये अपने में शामिल कर लिया । फलतः क्वोमिंताङ ने चीनी जनता का विरोध करने तथा सुदूर पूर्व में एक नया युद्ध शुरू करने के लिए शत्रु तथा कठपुतलियों की फासीवादी शक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनाए रखा तथा अपने औजारों में बदल लिया ।

इस प्रकार सुदूर पूर्व में युद्ध के वास्तविक रूप से समाप्त होने से पहले ही, अमरीकी साम्राज्यवादियों, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों, गद्दारों तथा जापानी फासीवादियों ने, इस तरह के "सहयोग" तथा "भागेदारी" से एक नए युद्ध के बीज बो दिए थे ।

जापान-विरोधी युद्ध के समाप्त होने पर, चीन के अन्दरूनी अन्तर्विरोधों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया । चीन तथा जापान के अन्तर्विरोध का स्थान, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले व्यापक चीनी जन-समुदाय तथा दूसरी तरफ, अमरीकी साम्राज्यवादियों के समर्थन के तहत क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के नेतृत्व वाले बड़े जमींदार वर्ग तथा बड़े पूँजीपति वर्ग के बीच के अन्तर्विरोध ने ले लिया । अंतर्विरोध का यह मुद्दा पूरी घरेलू परिस्थिति पर छा गया था । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने न केवल जनता की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोक गणराज्य तथा सामाजिक मुक्ति की आकांक्षाओं को साकार होने नहीं दिया, बल्कि उसे गृहयुद्ध तथा दुःख-तकलीफों के अथाह गर्त में भी धकेल दिया ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दृढ़ता से गृहयुद्ध का विरोध करने व उसे रोकने की सुस्पष्ट नीति अपनाई, जिसे शुरू करने की योजनाएँ प्रतिक्रियावादी बना रहे थे । पार्टी को ऐसे युद्ध के आसन्न खतरे का पूरा आभास था । लेकिन जब क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी जनता से उसकी विजय के फल छीनने पर तुले हुए थे, जनता भी प्रतिक्रियावादियों को अपने अभी-अभी मिले अधिकारों पर हाथ न डालने देने के लिए कृत-संकल्प थी । यदि प्रतिक्रियावादी लोगों पर युद्ध थोंप ही देते, तो उनके पास भी हथियार उठाने व जंग लड़ने के अलावा और कोई चारा न था । इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ के हमलों को पूर्णतया नेस्तनाबूद करने को अपना मुख्य कार्यभार समझा, क्योंकि अब यह एक आत्म-रक्षा का सवाल बन गया था ।

इस कालखण्ड के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने मुक्त क्षेत्रों में कृषि-सुधारों के लिए भी अभियान चलाया । जापानी आत्मसमर्पण के बाद, शानशी, हपे, शानतुङ तथा मध्य चीन के विभिन्न मुक्त क्षेत्रों के किसानों ने, गद्दारों का सफाया करने, हिसाब चुकता करने तथा लगान व सूद में कटौती करने की कार्यवाहियां करने के दौरान जमींदारों से जमीनें प्राप्त कर लीं । गद्दार, स्थानीय निरकुंश तत्व तथा जमींदार आदि, किसान संघर्ष पर गालियों की बौछारें करते हुए, शहरों की तरफ भाग गए। मध्यवर्ती तत्व संदेह प्रकट करने लगे । पार्टी में अनेक लोग डांवांडोल हो गए । 4 मई, 1946 को जारी किए गए अपने निर्देश में पार्टी ने किसानों की सभी न्यायसंगत माँगों तथा कार्यवाहियों का दृढ़ता से समर्थन किया, उनके द्वारा प्राप्त की गई या की

सामना नहीं करना पड़ा । पूर्व की ओर से सोवियत लाल सेना तथा पश्चिम की ओर से ब्रिटिश व अमरीकी सेनाएं शत्रु की ओर आगे बढ़ीं तथा 25 अप्रैल, 1945 को मध्य जर्मनी में तोरगू के समीप आपस में मिल गईं । इस प्रकार उत्तर में स्थित जर्मन फौजों को दक्षिण में स्थित फौजों से अलग कर दिया गया ।

फासीवादी जर्मनी की अन्तिम पराजय का समय आ पहुँचा था । अपने अंतिम क्षणों के संघर्ष में जर्मनी ने अत्यन्त घृणास्पद षड्यन्त्र का सहारा लेते हुए, सोवियत-संघ विरोधी गठजोड़ हेतु ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रतिक्रियावादियों के साथ गुप्त समझौता वार्ता शुरू कर रखी थी । लेकिन सोवियत सेना द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने की बदौलत, यह षड्यन्त्र विफल हो गया।

अप्रैल 1945 में, सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा करने के लिए कार्यवाही शुरू की । इस मुहिम की अंतिम लड़ाई में, 41,000 से भी ज्यादा तोपें तथा खन्दक-मोर्टार इस्तेमाल किए गए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत सशस्त्र सेनाओं से फासीवादी हैवान को उसकी अपनी ही माँद में नष्ट करने तथा बर्लिन पर विजय पताका फहराने का आह्वान किया । 2 मई को सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया तथा हिटलर के मुख्यालय (राइखस्ताग) पर लाल झण्डा फहरा दिया । जर्मनी ने हार मान ली तथा बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया ।

जर्मनी के आत्मसमर्पण के ड्राफ्ट पर 7 मई, 1945 को राइमस (Rheims) में हस्ताक्षर हुए । अगले दिन जर्मन उच्च कमान के प्रतिनिधि ने सोवियत सर्वोच्च कमांडर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बर्लिन में अन्तिम रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर दिये ।

सोवियत जनता की जर्मन-फासीवाद पर पूर्ण विजय का महान दिवस आ गया था । 9 मई, 1945 को "जनता के नाम ऐलान" में साथी स्तालिन ने घोषणा की कि इस दिन को सोवियत-संघ के **महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के विजय दिवस** के रूप में मनाया जाएगा ।

द्वितीय विश्वयुद्ध की पूर्ववेला पर, जर्मनी ने पश्चिम में तथा जापान ने पूर्व में विश्व-फासीवाद तथा आक्रमणकारी शक्तियों के दो विशाल अड्डे कायम कर लिये थे । यही वे लोग थे जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू किया था; और इन्होंने ही मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था ।

हिटलरी जर्मनी की भाँति साम्राज्यवादी जापान भी, चीनी जनता, सोवियत जनता तथा पूर्वी राष्ट्रों का शत्रु था; वास्तव में वह, समस्त मानव जाति का अत्यधिक खूंखार शत्रु था ।

अपनी आपराधिक हमलावर योजनाओं में, जापान ने चीन तथा सोवियत-संघ पर हमले को अपने मुख्य कार्यभारों के रूप में रखा था । चीन को विजित करने का उसका प्रयास, सोवियत-संघ पर हमला करने के लिए प्रारंभिक कदम था । 1938 में, हसन झील के पास व्लादीवोस्तक में जापान ने सोवियत क्षेत्र का अतिक्रमण किया । 1939 में जब जापानी सेनाएँ मंगोलियाई जनवादी गणराज्य में घुसीं; तथा खालखिन-गोल नदी पर पहुँचीं, तो उन्होंने सोवियत सीमा को पार करने व साईबेरियाई रेलमार्ग की मुख्य रेल लाइन को काटने का प्रयास किया। लेकिन सोवियत सेना ने दोनों हमलों को पूर्णतया कुचल दिया । 1943 की गर्मियों में, जापान, स्तालिनग्राद का पतन होने की दशा में, सोवियत-संघ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। और निःसन्देह, यह योजना भी विफल हो गई । 1937 में चीन के विरुद्ध जापानी आक्रमणकारी युद्ध के शुरू होने के वक्त से, सोवियत-संघ ने संभावित जापानी हमले के मद्देनजर, सुदूर पूर्व में सदैव शक्तिशाली रक्षात्मक सेनाएँ तैनात किए रखी थीं ।

हिटलरी जर्मनी को बुरी तरह कुचलने व पराजित करने के बाद, यह बेहद जरूरी हो गया था कि इस पूर्वी आक्रमणकारी अड्डे को भी नष्ट किया जाए, ताकि सोवियत-संघ की सुरक्षा की गारंटी की जा सके तथा चीनी जनता के मुक्ति आन्दोलन को मदद मिल सके ।

जर्मनी की पूर्ण पराजय तथा उस द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण से जापान बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। परन्तु अपनी नियति को स्वीकार करने की बजाय जापानी-साम्राज्यवाद अभी भी, चीन की मुख्य धरती को, सर्वप्रथम समूचे उत्तर-पूर्व को, अपने रणनीतिक अड्डे के रूप में तथा वहां तैनात क्वानतुङ सेना की दस लाख सिरफिरी फौजों को अपनी मुख्य सैन्य-शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हुए, आक्रमणकारी-युद्ध को जारी रखने का सपना संजोए था ।

1945 के शुरू में, बरतानवी तथा अमरीकी सरकारों ने, प्रशान्त महासागर में जापान को पराजित करने में पेश आने वाली मुश्किलों के मद्देनजर, याल्टा सम्मेलन में सोवियत-संघ से जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए समझौता किया । पूर्व में स्थित युद्ध के इस स्त्रोत को नेस्तनाबूद करने के लिये तथा भविष्य में दुनिया को तबाही तथा कुर्बानियों से बचाने के लिए सोवियत-संघ ने जर्मनी को पराजित करने के तीन महीने बाद, जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ।

सम्मेलन में फैसला किया गया कि रूसी-जापानी युद्ध में जापान द्वारा हथियाया गया साखालिन द्वीप का दक्षिणी हिस्सा तथा कुरीले द्वीप समूह सोवियत संघ को वापिस मिलने चाहिएं । इस बात पर भी सहमति हुई कि जापानी हमलावर सेनाओं के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, चीन और सोवियत-संघ, छाङछुन रेलमार्ग को अपने साँझे प्रबन्धन में चलाएं तथा लूशुन (पोर्ट आर्थर) बन्दरगाह पर भी उनकी सांझी व्यवस्था हो, तथा ताल्येन (डाएरन) को एक मुक्त बंदरगाह में बदल दिया जाए । इन समझौतों को एक संधि का रूप दिया जाना था।

14 अगस्त को *'मैत्री तथा संश्रय की चीनी-सोवियत संधि'* पर हस्ताक्षर हुए ।

इस संधि के अनुसार—1. दोनों पक्षों ने जापान के खिलाफ लड़ाई में अन्य संश्रयकारी राष्ट्रों को तब तक सहयोग देते रहना था जब तक कि जापान पूरी तरह हार नहीं जाता; 2. उनमें से किसी ने भी अकेले जापान के साथ कोई समझौता-वार्ता या युद्ध-विराम या शांति-संधि नहीं करनी थी; तथा 3. जापान-विरोधी युद्ध समाप्त होने के बाद, जापान द्वारा दोबारा हमले की संभावना को खत्म करने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से सभी संभव उपाय करने थे ।

इसके अतिरिक्त, चीन के छाङछुन रेलमार्ग, ताल्येन बंदरगाह तथा लूशुन बंदरगाह से संबंधित अन्य चीनी-सोवियत समझौते भी सम्पन्न हुए ।

युद्ध में सोवियत-संघ की भागेदारी के कारण जापान द्वारा अपने बचाव की अंतिम योजना भी पूरी तरह विफल हो गई । ●

5.

- **सोवियत-संघ द्वारा जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा ।**
- **चीनी सेना द्वारा मुक्त क्षेत्रों से प्रत्याक्रमण की शुरुआत ।**
- **जापानी प्रतिरोध-युद्ध का विजयी समापन ।**

8 अगस्त, 1945 को सोवियत-संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी ।

सेना ही प्रमुख जापान-विरोधी सेना थी तथा जनता असली विजेता थी, अत: यह कदम उठाना हर तरह से जायज था ।

क्वोमिंताङ फौजें उस समय दूर दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी चीन में थीं । ये एक मात्र जन-सेनाएं ही थीं जो उत्तरी, मध्य तथा उत्तरपूर्वी चीन में शत्रु की घेराबन्दी कर रही थीं तथा उस पर हमले कर रही थीं । जनता के हाथों से विजय के फल छीनने की नीयत से, च्याङ काई-शेक ने जन-मुक्ति सेना की विभिन्न यूनिटों को यह "आदेश" देने की जुर्रत की कि वे *"अगला आदेश मिलने तक जहां भी हों वहीं बनी रहें"* तथा येनान मुख्यालय द्वारा शत्रु तथा कठपुतली सेनाओं के नाम जारी आदेश को बड़ी ही बेशर्मी से लाँछित करते हुए *"एक धृष्टतापूर्ण तथा अवैध कार्यवाही"* करार दिया । वह जन-मुक्ति सेना को "जनता की शत्रु" करार देने की सीमा तक चला गया तथा "फौजी अनुशासन लागू करने" की धमकी दी । यह क्वोमिंताङ द्वारा खुल्लम-खुल्ला गृहयुद्ध शुरू करने के इरादों का स्पष्ट संकेत था ।

च्याङ काई-शेक ने अपनी व्यक्तिगत सेनाओं को "सैनिक कार्यवाहियां तेज करने" तथा "तेजी से आगे बढ़ने" का आदेश जारी किया । लेकिन चूंकि क्वोमिंताङ सेनाएँ अभी भी दूर दक्षिणी-पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी चीन में थीं, अत: उसने शत्रु तथा कठपुतली सेनाओं को *"स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने व जनता की हिफाजत करने"* का आदेश दिया । जबकि इस सब के पीछे उसका असली इरादा—सामंती, दलाल तथा फासीवादी शासन के "कानून" को कायम रखना तथा गद्दारों व देशद्रोहियों के "हितों" की रक्षा करना था ।

15 अगस्त, 1945 को जापानी सेना के कमाण्डर-इन-चीफ याशूजी ओकामूरा ने च्याङ काई-शेक को एक तार भेज कर सूचित किया कि जापानी फौजें नानकिङ खाली कर रही थीं तथा उसके आने तक "कानून व्यवस्था" बनाए रखने के लिए "नाममात्र की सेना" रख छोड़ी थी । इसी तरह नानकिङ कठपुतली सेना ने भी सार्वजनिक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि क्वोमिंताङ सरकार की नानकिङ वापसी तक वे "स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे ।" च्याङ काई-शेक के आदेशों को लागू करने के लिए, पेकिङ के गद्दारों ने *"शांति कायम रखने के लिए कमेटी"* का गठन किया ।

जन-मुक्ति सेना द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्रों के बारे में, च्याङ काई-शेक ने शत्रु तथा कठपुतली सेनाओं को, "उन्हें वापिस लेने तथा हमारी (च्याङ की) सेनाओं के हवाले करने" का आदेश दिया। जिन जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उन्हें तत्काल निरस्त्र करने के बजाय, च्याङ ने उन्हें मुक्त क्षेत्रों की जनता तथा सेनाओं पर हमला करने का आदेश दिया। मुक्त क्षेत्रों पर हमला करने वाली शत्रु तथा कठपुतली सेनाओं का दावा था कि वे *"मिले हुए आदेशों का पालन कर रहे थे"*, "मिले आदेशों" से उनका तात्पर्य था—च्याङ से मिले आदेश।

क्वोमिंताङ सेनाओं के कब्जे वाले क्षेत्रों में केवल छ: प्रतिशत जापानी सेनाओं को निरस्त्र किया गया। जहाँ तक कठपुतली सेनाओं का सवाल था, उन सभी को न केवल शास्त्रास्त्र रखने की अनुमति दी गई, बल्कि उनका "राष्ट्रीय सेना" की यूनिटों के रूप में नामकरण कर दिया गया। इस प्रकार, जापानी तथा कठपुतली सेनाओं, दोनों को क्वोमिंताङ सेनाओं में बदल दिया गया।

चीन को जीतने के अपने मन्सूबों को पूरा करने के लिए अमरीका ने क्वोमिंताङ को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करने के अलावा, अभी भी जापानियों के कब्जे वाले बड़े-बड़े शहरों तथा मुक्त क्षेत्रों की मोर्चा पंक्तियों तक उसकी सेनाओं को पहुँचाने में मदद की । जापानी सेना को

सोवियत-संघ ने लगातार शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री की नीति का अनुसरण किया । उसने शांति के उद्देश्य के लिए अथक प्रयास किए तथा आक्रमणकारी युद्धों व अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया । युद्ध के बाद उसने जो बहुत से सकारात्मक कदम उठाए उनमें, अपनी सशस्त्र सेनाओं में भारी कटौती करना; चीन, कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, तथा युगोस्लाविया से लाल सेना को शीघ्रातिशीघ्र वापिस बुलाना; शान्ति-सुरक्षा एक्ट को लागू करना; तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बार-बार प्रस्ताव पेश करना शामिल हैं ।

सोवियत-संघ अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ मिलकर शान्ति की रक्षा करने का इच्छुक था । उसने हारे हुए देशों जर्मनी, इटली तथा जापान की जनता के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाने का विरोध किया । जिन देशों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था, उनके प्रति उसकी नीति उन्हें शान्ति व जनवाद का उपयोग करने, नागरिक उद्योगों तथा कृषि का विकास करने, विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद बेचने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सशस्त्र सेनाएं गठित करने में उनको सहयोग देने की थी ।

साथ ही, सोवियत-संघ ने अत्यधिक सतर्कता बनाए रखी तथा शांति के शत्रुओं की आपराधिक गतिविधियों का यथासंभव भण्डाफोड़ किया । उसने अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को मजबूत बनाया ताकि किसी भी आक्रमणकारी हमले का पूरी तरह मुकाबला किया जा सके ।

युद्ध की समाप्ति पर अनेक जनवादी जनतन्त्रों का उदय हुआ । उन्होंने पूँजीवादी प्रणाली से पिण्ड छुड़ा लिया तथा सोवियत-संघ के साथ मिल कर समाजवादी शिविर की स्थापना की। इस प्रकार समाजवाद एक देश की सीमाओं को पार करता हुआ एक विश्व-प्रणाली बन गया। सोवियत-संघ के लिए यह एक सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व था कि वह जनवादी जनतन्त्रों के साथ अपने मैत्री पूर्ण सम्बन्धों को मजबूत बनाए ।

संक्षेप में सोवियत-संघ की द्वितीय विश्वयुद्ध में महान विजय; तीन फासीवादी देशों जर्मनी, इटली तथा जापान की पराजय; ब्रिटेन तथा फ्रांस का कमजोर पड़ना; अमरीकी साम्राज्यवाद का अलग-थलग पड़ना; पूर्वी यूरोप में जनवादी जनतन्त्रों का अभ्युदय; औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का उभार तथा विश्व के सभी देशों में शांति आन्दोलन का फैलाव—अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में ये सभी, वे महत्त्वपूर्ण तत्व थे, जिन्होंने चीनी जनता की क्रान्ति की विजय में योगदान दिया । अत: युद्धेतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अमरीकी हस्तक्षेपकारियों व चीनी प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध संघर्ष में, चीनी जनता के अनुकूल थी । ●

2.

● एक नए गृहयुद्ध का खतरा ।

जब जापान सरकार ने 14 अगस्त, 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की तो येनान स्थित जन-मुक्ति सेना के मुख्यालय ने तत्काल, शत्रु तथा कठपुतली सेनाओं को निश्चित समय में आत्मसमर्पण करने के आदेश जारी कर दिये । इसके साथ ही, उत्तरी तथा मध्यचीन स्थित जन-मुक्ति सेना की टुकड़ियों को निर्देश दिए गए कि वे तेजी से आगे बढ़ें, शत्रु तथा कठपुतली सैनिकों को निरस्त करें तथा उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें । चूंकि जन-मुक्ति

बहादुर सोवियत लाल सेना ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय फासीवाद-विरोधी युद्ध की मुख्य सैन्य-शक्ति थी, चार कॉलमों में उत्तरपूर्वी चीन में प्रवेश किया, तथा इससे पहले कि शत्रु सेनाएं अपने ठिकानों पर पूरी तरह पैर जमा पातीं, लाल सेना उन पर बुरी तरह टूट पड़ी ।

इस प्रकार, एक ही वार में जापानी साम्राज्यवादियों के वे सभी रणनीतिक अड्डे, जहां से वे हठधर्मितापूर्वक प्रतिरोध करने का प्रयास कर रहे थे, नष्ट कर दिये गए तथा समूची जापानी क्वानतुङ सेना को निष्क्रिय कर दिया गया ।

जापान के खिलाफ युद्ध में सोवियत-संघ के प्रवेश ने चीनी प्रतिरोध युद्ध को उसकी अंतिम मंजिल—रणनीतिक प्रत्याक्रमण की मंजिल—में पहुँचा दिया ।

9 अगस्त को, सोवियत-संघ द्वारा युद्ध की घोषणा के दूसरे दिन, कामरेड माओ ने अपने वक्तव्य, **"जापानी हमलावरों के खिलाफ युद्ध का अंतिम दौर,"**[9] में चीन की सभी जापान-विरोधी शक्तियों का आह्वान किया कि वे राष्ट्रव्यापी प्रत्याक्रमण शुरू कर दें, मुक्त क्षेत्रों का विस्तार करें, शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों को कम करें तथा सोवियत-संघ व अन्य संश्रयकारी देशों की फौजी कार्यवाहियों के साथ घनिष्ठ तथा कारगर तालमेल कायम करते हुए शत्रु से लड़ें । उन्होंने सशस्त्र कार्य-दल गठित करने का आह्वान किया जो शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों के पृष्ठभाग में गहरे तक घुस जाएं तथा शत्रु की परिवहन व संचार-पंक्तियों को तहस-नहस करने व नियमित सेनाओं की कार्यवाहियों में मदद के लिए जनता को संगठित करें । उन्होंने शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों की जनता का आह्वान किया कि वह तुरन्त भूमिगत सैन्य-शक्तियों का गठन करे, सशस्त्र विद्रोह करे तथा बाहर से हमला कर रही नियमित सेनाओं के साथ तालमेल स्थापित करते हुए शत्रु को नेस्तनाबूद कर दे । इसके साथ ही, वक्तव्य में चीनी जनता को

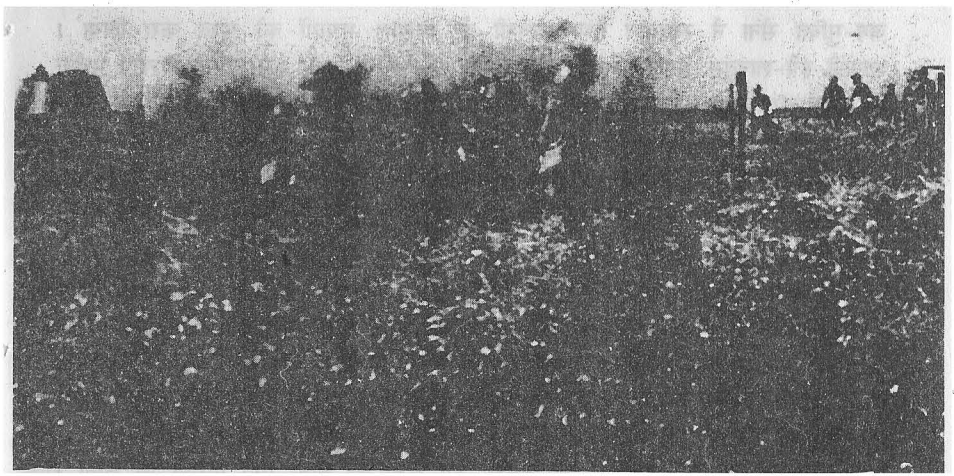

उत्तरपूर्वी चीन में जापानी आक्रमणकारियों पर हमला करती सोवियत लाल सेना
(9 अगस्त, 1945)

गृहयुद्ध के खतरे के बारे में भी आगाह किया गया तथा उसकी रोकथाम करने के लिए भरसक प्रयास करने का आह्वान किया गया ।

10 अगस्त को, चीनी जन-सेना के प्रधान सेनापति चू तेह ने मुक्त क्षेत्रों की सभी सशस्त्र फौजों को शत्रु के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया । मोर्चे पर तैनात जापान-विरोधी सेनाओं ने **पोट्सडम घोषणा**[10] के अनुसार, आसपास के क्षेत्रों में तैनात जापानी तथा कठपुतली सेनाओं से अपने हथियार डाल देने तथा आत्मसमर्पण करने की मांग की; तथा सभी शत्रु-अधिकृत नगरों, कस्बों एवं संचार-पंक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर ली। सोवियत लाल सेना की विशाल युद्ध-क्षमता तथा उस द्वारा तेजी से आगे बढ़ने के कारण, क्वानतुङ सेना, जिसे जापानी सेना की बेहतरीन फौज माना जाता था, बड़ी जल्दी निरस्त कर दी गई तथा जापान को 14 अगस्त को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ा ।

जापानी आत्मसमर्पण के बाद, तथापि, अमरीका की मदद से च्याङ काई-शेक ने जापानी तथा कठपुतली सेनाओं को स्थानीय स्तर पर "कानून-व्यवस्था" बनाए रखने के लिए अपनी-अपनी चौकियों पर तैनात रहने, उनकी घेराबन्दी कर रही **चीनी जन-मुक्ति सेना**[11] का प्रतिरोध जारी रखने तथा चीनी जनता के सामने आत्मसमर्पण न करने का आदेश दिया । अत: जन-मुक्ति सेना का यह कर्त्तव्य हो गया कि वह शत्रु द्वारा कब्जाए इलाकों को वापिस ले, स्वतन्त्र रूप से शत्रु के सैन्य-बलों का आत्मसमर्पण करवाए तथा आत्मसमर्पण से इन्कार करने वालों को नेस्तनाबूद कर दे ।

चीनी जनता को हर विजय एक भयंकर लड़ाई द्वारा अर्जित करनी थी ।

हपे-जेहोल-ल्याओनिङ क्षेत्र में जन-मुक्ति सेना पेकिङ-शानयाङ रेलमार्ग के साथ-साथ आगे बढ़ी तथा सोवियत सेना व उत्तरपूर्वी जापान-विरोधी संश्रयकारी सेना के सहयोग से उत्तरपूर्व को मुक्त करा लिया । शानशी-छाहाङ-हपे क्षेत्र में मुक्ति सेना ने छाहाङ् को मुक्त करा लिया तथा पेकिङ, थ्येनचिन व पाओतिङ की घेराबंदी कर ली । शानशी-स्वेय्वान क्षेत्र में जन-मुक्ति सेना ने स्वेय्वान तथा शानशी के विशाल भूभागों को मुक्त करा लिया । शानशी-हपे-शानतुङ-हनान क्षेत्र की मुक्ति सेना ने पीली नदी के साथ लगते विशाल भूभाग को मुक्त करा लिया । शानतुङ मुक्ति सेना ने शानतुङ प्रान्त की 100 काउंटियों को मुक्त करा लिया । मध्य चीन मुक्ति सेना शत्रु के खिलाफ शांघाई-हाङचओ-निङपो, नानकिङ-ऊहू, चच्याङ-च्याङशी तथा ह्वाएनान रेलमार्गों तथा लुङहाए रेलमार्ग के पूर्वी सेक्शन के साथ-साथ आगे बढ़ी । दक्षिणी चीन जापान-विरोधी सेना ने कैंटन-खओलून तथा छाओचओ-शानथओ रेलमार्गों पर शत्रु पर हमला किया ।

11 अगस्त से 10 अक्तूबर तक के दो महीनों में जन-मुक्ति सेना ने 1 करोड़ 87 लाख 17 हजार आबादी वाला 3,15,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुक्त करा लिया, 190 शहर वापिस ले लिये, तथा 2,30,000 से अधिक शत्रु व कठपुतली सैनिकों को हताहत किया । इस प्रकार मुक्त-क्षेत्रों का विशाल पैमाने पर विस्तार हो गया था । जन-मुक्ति सेना ने बड़े शहरों की घेराबन्दी कर दी थी, लेकिन अमरीकी साम्राज्यवाद के सक्रिय हस्तक्षेप तथा क्वोमिंताङ द्वारा खड़ी की जा रही बाधाओं के कारण, उन सभी को मुक्त नहीं कराया जा सका । जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध इस तरह की विशेष परिस्थितियों में समाप्त हुआ ।

जापानियों ने 2 सितंबर, 1945 को आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये । ●

नए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी । अमरीकी शासक गुट को अच्छी तरह मालूम था कि शांतिपूर्ण तरीकों से विश्व पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सकता था, और वे समझते थे कि एक और युद्ध छेड़े बिना, विश्व पर प्रभुत्व जमाने व बाकी दूसरे देशों को जीतने के उनके इरादों पर पानी फिर जाएगा । फलत: उन्होंने एक नए युद्ध के लिए जोरदार तैयारी करनी शुरू कर दी । चूंकि सोवियत संघ हमेशा एक नए युद्ध का प्रमुख विरोधी तथा शांति का प्रमुख रक्षक रहा था, अत: अमरीकी शासक गुट ने स्वभावत: फैसला किया कि हमले का मुख्य निशाना उसे तथा अन्य शान्ति-प्रिय देशों को बनाया जाए । यही कारण है कि युद्ध के बाद अमरीका ने नाटो (NATO—North Atlantic Treaty Organisation) का गठन किया, सोवियत-संघ के चारों तरफ फौजी अड्डे स्थापित किए, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान को दोबारा हथियारबन्द किया, अपने शस्त्रास्त्रों के जखीरे का विस्तार किया तथा शांति सन्धि के सुझाव को अस्वीकार कर दिया ।

"*साम्यवाद से लड़ने*" की आड़ में, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपनी युद्ध योजनाएं दूसरे देशों, जैसे कि पश्चिमी जर्मनी, जापान और यहां तक कि ब्रिटेन तथा फ्रांस की सशस्त्र सेनाओं तथा इलाकों का इस्तेमाल करने पर आधारित कीं । अमरीकी शासक गुट ने नाटो ब्लाक के देशों के लिए तथा साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित देशों के लिए, युद्ध की तैयारियों से सम्बन्धित कुछ नियम बनाए जिनके अनुसार दूसरे देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाते हुए, अमरीकी साम्राज्यवादी नीतियों को लागू करना था ।

इस प्रकार, ब्रिटेन तथा फ्रांस को आश्रित देशों में बदल देने तथा उनके उपनिवेश छीन लेने से, कब्जा व्यवस्था द्वारा पश्चिमी जर्मनी तथा जापान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह गला घोंट देने व उनकी विदेश एवं घरेलू नीतियों पर नियन्त्रण कर लेने से, सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती थी कि इन देशों की जनता में अमरीका विरोधी उग्र संघर्ष उठ खड़े होंगे ।

नए युद्ध के खतरे ने सभी देशों की जनता को एक शांति आन्दोलन में कूद पड़ने को प्रेरित कर दिया । युद्धेतर काल में शांति-आन्दोलन का उद्देश्य व्यापक जन-समुदाय को युद्ध का विरोध करने के लिए आन्दोलित करना, शान्ति के रक्षकों की संस्थाओं को मजबूत करना, तथा युद्ध भड़काने वालों के षड्यन्त्रों का पर्दाफाश करना था, ताकि शान्ति की रक्षा की जा सके और एक नए युद्ध को टाला जा सके ।

तीन साम्राज्यवादी शक्तियों जर्मनी, इटली तथा जापान की द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजय; ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे उपनिवेशवादी देशों द्वारा युद्धेतर वर्षों का अपना भारी बोझ जो उनके सैन्यीकृत अर्थतन्त्र तथा अमरीकी विस्तारवादी नीति का परिणाम था, उपनिवेशों पर लादने के प्रयासों; अमरीका की उपनिवेशों में घुसपैठ तथा उनमें से अनेकों में फौजी अड्डों की स्थापना; तथा सदियों से चले आ रहे साम्राज्यवादी एवं सामंती शोषण व दमन के कारण उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था में आई और ज्यादा गिरावट—इन सभी ने औपनिवेशिक प्रणाली में संकट पैदा कर दिया तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के उत्थान को गति प्रदान की । उपनिवेशों की जनता ने अत्यधिक दृढ़ संकल्प से अपने साम्राज्यवादी स्वामियों का विरोध किया । उदाहरण के लिए कोरिया तथा वियतनाम की जनता ने अपनी मुक्ति प्राप्त की; भारत, बर्मा तथा इंडोनेशिया को स्वतन्त्रता मिल गई । युद्ध के बाद राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के प्रसार से साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए उनके पृष्ठभाग से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया ।

में, सोवियत-संघ का कुल औद्योगिक उत्पादन 466 तक पहुँच गया, बावजूद इसके कि उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को युद्ध के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ा था ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तथा बाद में प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा दूसरों की कीमत पर, अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा इस संकट से पार पाने के प्रयास विफल हो गए।

विभिन्न पूँजीवादी देशों पर युद्ध-जनित विभिन्न प्रभावों ने उनके आर्थिक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए ।

जर्मनी, इटली तथा जापान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह बरबाद हो गई थी; तथा ब्रिटेन तथा फ्रांस की अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा था । केवल अमरीका को ही युद्ध से विपुल लाभ हुआ था । विश्व बाजार में अपना प्रभाव फैलाने के लिए अमरीका के इजारेदार पूँजीपतियों ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों के दिवालिएपन अथवा पतन से लाभ उठाया एवं तथाकथित ''मार्शल योजना'' के माध्यम से ब्रिटेन तथा फ्रांस के औपनिवेशिक बाजार का बड़ा हिस्सा, तथा पूँजीवादी विश्व में बाजार का बड़ा हिस्सा हथिया लिया । अमरीका से जो कुछ इन देशों को मिला, उसमें से केवल 16 प्रतिशत वे औद्योगिक उपकरण थे जिनकी उन्हें युद्ध के बाद, तत्काल जरूरत थी । इस मदद का बहुत बड़ा हिस्सा, फालतू खाद्य-सामग्री तथा कोयले, आटे व सूती कपड़े जैसे औद्योगिक उत्पाद थे । 1949 से पश्चिमी यूरोप को अमरीकी मदद का स्वरूप आर्थिक की बजाय सैनिक रहा है ।

अमरीका ने पूँजीवादी विश्व बाजार को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा विशाल पैमाने पर दूसरे देशों में अपनी वस्तुओं का ढेर लगा कर और अपने बाजार में विदेशी वस्तुओं के आने पर रोक लगा कर अपने निर्यात को खूब बढ़ाया । इसके अलावा अमरीका ने, पश्चिमी यूरोप के देशों को खाद्य पदार्थों व कच्चे माल के बदले में पूर्वी देशों को औद्योगिक उत्पाद निर्यात करने से भी रोका ।

अमरीका की इस तानाशाहीपूर्ण नीति के कारण, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली तथा जापान के साथ उसके अंतर्विरोध, स्वभावत: और ज्यादा तीव्र हो गए । फलत: पूँजीवादी अर्थव्यवस्था युद्ध-पूर्व काल से भी ज्यादा अस्त-व्यस्त व अस्थिर हो गई ।

पूँजीवादी देशों के औद्योगिक उत्पादन में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, वह युद्ध की तैयारियों की वजह से थी । अमरीका तथा पश्चिम यूरोप के देशों, दोनों ही ने अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध के आधार पर ला खड़ा किया । उनके राजकीय बजटों में शस्त्रास्त्रों में वृद्धि के लिए लगातार बहुत बड़ी राशि निर्धारित की जाने लगी थी; उनके उद्योगों की मुख्य शाखाओं में फौजी स्टोरों के लिए माल की आपूर्ति के ऑर्डर मुख्य भूमिका अदा करते थे । फौजी खर्चों में वृद्धि होने से जनता पर करों का बोझ स्वभावत: बढ़ता गया व मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होता चला गया । युद्ध की तैयारियों में तेजी आने व मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप आई अल्पकालिक आर्थिक समृद्धि के साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी भारी गिरावट आई क्योंकि निर्मित उत्पादों का बहुत बड़ा हिस्सा फौजी आपूर्ति में बदल दिया जाता था या फिर सामरिक महत्त्व के साजोसामान के रूप में स्टोर कर दिया जाता था । फौजी उत्पादन में वृद्धि ने केवल गंभीर आर्थिक संकट का रास्ता ही खोला ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम से साम्राज्यवादी शक्तियों को बेहद निराशा हुई । इसलिए, ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, अमरीकी प्रतिक्रियावादियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शिविर ने एक

● जापान के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध का सारांश ।

''चीन-जापान युद्ध अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती चीन तथा साम्राज्यवादी जापान के बीच बीसवीं सदी के चौथे दशक में चल रहे जीवन-मरण के युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है ।''[12]

चीन-जापान युद्ध चीनी जनता की विजय तथा जापानी साम्राज्यवाद की पराजय के साथ समाप्त हुआ ।

प्रतिरोध युद्ध के दौरान असीम मुश्किलों तथा बाधाओं के बावजूद चीनी जनता की जापान-विरोधी शक्तियां विकसित होती चली गईं । वे *''उत्थान, पराजय तथा फिर उत्थान''* की तीन मंजिलों में से गुजरी । प्रतिरोध-युद्ध में अंतिम विजय मजदूर वर्ग, किसान समुदाय, निम्न-पूँजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा जमींदारों व दलाल-पूँजीपतियों के एक हिस्से के संयुक्त प्रयासों द्वारा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में प्राप्त की गई । परिस्थिति की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त पार्टी, सेना तथा मुक्त क्षेत्रों की जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा साथी माओ त्से-तुङ द्वारा निर्धारित सही राजनीतिक तथा सैनिक कार्यदिशाओं का पूर्णतया अनुसरण किया । जापान-विरोधी युद्ध में विजय के लिए, जनता की विजय के लिए, सर्वहारा के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त—यानी संयुक्त मोर्चे में पार्टी की स्वतंत्रता तथा पहलकदमी को बनाए रखने—का पालन किया गया तथा प्रगतिशील शक्तियों को विकसित करने, मध्यवर्ती शक्तियों को अपनी ओर मिलाने व कट्टरतावादियों को अलग-थलग करने की नीति अपनाई गई । शत्रु पंक्तियों के पीछे स्वतन्त्र रूप से, साहस के साथ छापामार-युद्ध विकसित किया गया, जिससे जापान-विरोधी सेनाएँ विकसित हुईं तथा जापान-विरोधी आधार-क्षेत्र स्थापित किए गए, जहां कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जापान-विरोधी जन-सरकारों ने जनता के हित में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सुधार-कार्यक्रम लागू किए ।

इन कार्यदिशाओं को लागू करने के फलस्वरूप, पार्टी ने 1937 से 1940 तक मुक्त क्षेत्रों में लड़ाई का विशाल मोर्चा खोल दिया । इस प्रकार पार्टी ने मुसीबतों पर विजय पाई तथा 1941-1942 के अत्यन्त कठिन वर्षों में भी, जब जापानी, कठपुतली तथा क्वोमिंताङ सैनिकों ने तीन तरफा हमला कर दिया था, अपने पाँव जमाए रखे । 1943 से आंशिक प्रत्याक्रमण शुरू किए गए, शत्रु-अधिकृत क्षेत्रों को कम किया गया तथा अंतिम आक्रमण के लिए मुक्त क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों में बदल दिया गया ।

प्रतिरोध-युद्ध में चीनी जनता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में विजयश्री प्राप्त की। इससे पक्के तौर पर सिद्ध हो जाता है कि एक औपनिवेशिक या अर्ध-औपनिवेशिक देश, साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध अपने संघर्ष में विजय प्राप्त करने में पूरी तरह समर्थ होता है, जब उसका नेतृत्व एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के हाथ में होता है ।

चीनी जनता की विजय में सोवियत-संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी शक्तियों का भी महान योगदान था ।

प्रतिरोध युद्ध के दौरान सोवियत-संघ द्वारा चीनी जनता को दी गई बेशुमार सहायता तथा सोवियत लालसेना द्वारा जापानी क्वानतुङ सेना के विनाश ने चीनी जनता द्वारा अपने शत्रु पर

विजय पाने में जबरदस्त योगदान दिया । मुसीबत के समय में चीन के प्रति सोवियत सरकार तथा सोवियत जनता की महान मित्रता ने, चीनी जन-क्रान्ति को विजय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चीनी तथा सोवियत जनता के बीच की मैत्री, संश्रय तथा परस्पर सहयोग सुदूर पूर्व में साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध एक दीवार है । ●

नोट

1. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-3, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1975, पृष्ठ-519

2. —वही—पृष्ठ–519

3. —वही—पृष्ठ–519

4. —वही—पृष्ठ–365 से 492 तक ।

5. —वही—पृष्ठ–362

6. —वही—पृष्ठ–485

7. —वही—पृष्ठ–435

8. —वही—पृष्ठ–393

9. —वही—पृष्ठ-525 से 527 तक ।

10. **पोट्सडम घोषणा** :- यह घोषणा 26 जुलाई, 1945 को चीन, बरतानिया और अमरीका ने पोट्सडम सम्मेलन में की थी । इसमें जापान से साधिकार हथियार डाल देने की मांग की गई थी। इसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे—जापानी सैन्यवाद को सदा के लिये समाप्त कर दिया जाए; जापानी सैन्य-शक्तियों को पूर्णतया निरस्त्र कर दिया जाए; जापानी युद्ध-उद्योगों को विघटित कर दिया जाए; जापानी युद्ध-अपराधियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की जाए; काहिरा घोषणा को लागू किया जाए यानि जापान ने जिन प्रदेशों को हथिया लिया था, जैसे कोरिया तथा चीन के मंचूरिया, थाएवान (तैवान) और फङहू द्वीप समूह; उन्हें वह छोड़ दे, तथा जापान का भू-प्रदेश होनशू, हक्काइदो, क्यूशू और शिकोकू द्वीपों और दूसरे छोटे-छोटे द्वीपों तक ही सीमित रखा जाए; और एक जनवादी जापानी सरकार के कायम हो जाने तक संश्रयकारी देशों की सशस्त्र सेनाएं जापान पर अपना कब्जा बनाए रखें । (माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह, पेकिङ, पहला संस्करण-1976, पृष्ठ-38)

11. **जन-मुक्ति सेना** :- यह आठवीं राह सेना, नई चौथी सेना तथा अन्य जापान-विरोधी सशस्त्र जन-सेनाओं को मिलाकर बनाई गई थी ।

12. माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1973, पृष्ठ-200

●●●

ग्यारहवां अध्याय

जापान के आत्मसमर्पण के बाद घरेलू शांति तथा जनवाद के लिए जनता का संघर्ष

(सितंबर 1945 से जून 1946)

1.

● द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ।

2 सितंबर, 1945 को जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण करने से जापानी हमले के खिलाफ चीनी प्रतिरोध-युद्ध तथा द्वितीय विश्वयुद्ध का समापन हो गया तथा चीन व शेष दुनिया के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ ।

विश्व परिस्थिति में बड़े जबरदस्त परिवर्तन हुए । एक ओर, जर्मनी, इटली तथा जापान पराजित हो गए थे; ब्रिटेन तथा फ्रांस कमजोर हो गए थे तथा समूचे साम्राज्यवादी खेमे में अमरीका का आधिपत्य स्थापित हो गया था । दूसरी ओर, फासीवाद विरोधी युद्ध में महान विजय अर्जित करने से सोवियत-संघ पहले से अत्यन्त शक्तिशाली हो गया था; यूरोप में अनेक जनवादी लोकतन्त्रों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था से पीछा छुड़ाकर सोवियत संघ के साथ मिल कर एक शक्तिशाली समाजवादी शिविर कायम किया; तथा औपनिवेशिक व आश्रित देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन नई ऊँचाइयों को छू रहे थे । समूची पूँजीवादी व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा था, तथा समाजवादी व पूँजीवादी शिविरों के शक्ति संतुलन में जबरदस्त परिवर्तन आया था तथा यह परिवर्तन समाजवादी शिविर के पक्ष में था । संक्षेप में युद्धेतर काल में विश्व पूँजीवाद और ज्यादा कमजोर हो गया था तथा समाजवाद लगातार मजबूत होता चला गया था । पूरी की पूरी परिस्थिति प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ तथा दुनिया की जनवादी शक्तियों के अनुकूल थी ।

यदि 1929 में विश्व के विभिन्न देशों के औद्योगिक उत्पादन को 100 मान लिया जाए तो पूँजीवादी देशों का औसत उत्पादन 1946 में 107 तथा 1949 में 130 था । 1946 में अमरीका का उत्पादन 153 था; ब्रिटेन का 118; फ्रांस का 63, इटली का 72, पश्चिमी जर्मनी का 35; तथा जापान का 51 था । 1929 से 1946 तक के 17 वर्षों के दौरान औद्योगिक देशों में औद्योगिक उत्पादन कमोबेश उसी स्तर पर रहा जो विश्व आर्थिक संकट शुरू होने से पहले था । एकमात्र अमरीका में ही काफी वृद्धि प्रकट हुई, लेकिन यह उस द्वारा युद्ध के दौरान तीव्र गति से फौजी उद्योगों का विस्तार करने के कारण हुई थी । ब्रिटेन ने नगण्य वृद्धि दर्ज की, जबकि फ्रांस में 37 प्रतिशत की कमी आई । तीन पराजित देशों में सामान्य रूप से गिरावट आई : इटली में 28 प्रतिशत, जर्मनी में 65 प्रतिशत तथा जापान में 49 प्रतिशत । लेकिन 1946

फैले हुए सैन्य-विन्यास के कारण, जैसे ही क्वोमिंतांङ किसी एक क्षेत्र के विरुद्ध अपेक्षाकृत कुछ बरतर सैन्य-शक्ति केन्द्रित करती थी, उसके कब्जे वाले दूसरे क्षेत्रों में अनेक कमजोर ठिकाने अनारक्षित छूट जाते थे तथा प्रत्याक्रमण के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करते थे ।

दुश्मन तत्वों को नष्ट करने की च्याङ की नीति, उसे अपनी व्यक्तिगत फौजों को छोड़कर, बाकी सभी क्वोमिंतांङ फौजों के विरुद्ध लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाने की दिशा की तरफ ले गई । फलतः क्वोमिंतांङ खेमे की केन्द्रीय सेनाओं तथा स्थानीय सेनाओं में संगीन अंतर्विरोध पैदा हो गए थे । सिर्फ उन लोगों को ही महत्त्वपूर्ण फौजी पदों पर नियुक्त किया जाता, जिन्हें च्याङ अपना विश्वासपात्र समझता था । सैन्य-विन्यास पूर्णतया उसकी अपनी कमान में था तथा यह काम एक अक्षम चीफ-ऑफ-स्टाफ द्वारा किया जाता था । इससे दो जुड़वां बुनियादी कमजोरियां उभरीं—अंदरूनी अनबन तथा एकीकृत कमान की कमी ।

अमरीका में बना साजोसामान एक तरह से तो क्वोमिंतांङ सेनाओं के लिए लाभकारी था, लेकिन दूसरे लिहाज से, यह उनके लिए एक बोझ भी था । यन्त्रीकृत सेनाओं के लिए अच्छी संचार-पंक्तियों की जरूरत थी, जिनकी चीन में बेहद कमी थी । जब ऐसी फौजें मुक्त क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में पहुँचती थी, तो उनके वाहन किसी काम नहीं आते थे । फलतः वे पूरी शक्ति के साथ कार्यवाही नहीं कर पाती थीं ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने, सेना तथा देश भर की जनता के जुझारू संकल्प तथा जीत के प्रति उनके आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाया । समस्त जनता ने, पार्टी के झण्डे तले एकजुट होकर, इस व्यापक पैमाने के क्रान्तिकारी युद्ध को, भौतिक तथा नैतिक, दोनों तरह का समर्थन प्रदान किया । ●

2.

- **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सक्रिय रक्षा की रणनीति अपनाया जाना ।**
- **क्वोमिंतांङ के चौतरफे तथा केन्द्रित हमलों को जन-मुक्ति सेना द्वारा पूर्णतया विफल कर दिया जाना ।**

युद्ध के आरंभिक चरणों में जब क्वोमिंतांङ सेनाएं बहुत से मुक्त क्षेत्रों में काफी भीतर तक घुस आई थीं, जन-मुक्ति सेना अनेक शहरों तथा स्थानों से पीछे हट गई थी । शत्रु द्वारा लंबी दीवार के दक्षिण में चौतरफा हमला, जून 1946 के अंत में उस समय शुरू किया गया, जब मध्य मैदान इलाके में जन-मुक्ति सेना की घेराबन्दी करके उस पर आक्रमण किया गया। इसके बाद दक्षिणी शानशी, उत्तरी च्याङसू, दक्षिण-पश्चिमी शानतुङ, शानतुङ प्रायद्वीप, पूर्वी हपे, पूर्वी स्वेय्वान, दक्षिणी छाहाङ, जेहोल तथा दक्षिणी ल्याओनिङ पर हमले किये गये । जन-मुक्ति सेना ने सक्रिय रक्षात्मक कार्यवाही की रणनीति अपनाई तथा शत्रु को अन्दर गहरे तक घुसपैठ करने का लालच देने के लिए अपनी ही पहलकदमी पर अनेक कस्बों तथा इलाकों को खाली कर दिया । इसके बाद उसने अत्यधिक श्रेष्ठ तथा शत्रु से कई गुणा बरतर सैन्य-शक्ति केन्द्रित की तथा शत्रु की कुछ कमजोर अथवा अकेली पड़ी यूनिटों को चुनकर, चलायमान लड़ाई लड़कर, एक के बाद एक करके उनका सफाया कर दिया और ऐसा करने का उद्देश्य रणनीतिक परिस्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाना था ।

दसवें हिस्से का सफाया कर दिया गया । इन सभी हमलों का मुँहतोड़ जवाब केवल इसीलिए दिया जा सका क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने शान्ति तथा जनवाद के लिए प्रयास करने के दौरान शत्रु द्वारा हमले की संभावनाओं के प्रति पूरी सतर्कता बरती थी तथा दूसरी ओर, क्वोमिंतांङ सैनिक युद्ध करते-करते बुरी तरह शिथिल हो चुके थे ।

क्वोमिंतांङ की गृहयुद्ध की नीति का समूचे देश की जनता ने विरोध किया। नवम्बर 1945 में छुङकिङ में एक **गृहयुद्ध विरोधी सभा** स्थापित की गई तथा सभी तबकों के लोगों का गृहयुद्ध को रोकने के लिए आह्वान किया गया। उसी साल एक दिसम्बर को, युन्नान की राजधानी खुनमिङ के विद्यार्थियों ने गृहयुद्ध के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया।

अपनी सेनाओं की पुनः तैनाती की खातिर समय हासिल करने के लिए तथा जनता के जबरदस्त दबाव को देखते हुए, उसके समक्ष थोड़ा झुकने का ढोंग करने के लिए, क्वोमिंतांङ तथा उसके अमरीकी आकाओं को विवश होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य जनवादी पार्टियों द्वारा पेश की गई मांगें स्वीकार करनी पड़ीं तथा 10 जनवरी, 1946 को "युद्ध-विराम समझौते" पर हस्ताक्षर करने पड़े । उसी दिन क्वोमिंतांङ तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों ने युद्ध-विराम के आदेश जारी कर दिए, जिन्हें 13 जनवरी की मध्य रात्रि से प्रभावी होना था । समझौते के अनुसार, पेकिङ में फौजी मध्यस्थता के लिए एक कार्यकारी मुख्यालय स्थापित किया गया, जिसमें तीन कमिश्नर थे जो कि क्वोमिंतांङ, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अमरीका सरकार के प्रतिनिधि थे । जॉर्ज सी.मार्शल, अमरीकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि के रूप में चीन आया था । कहने को तो वह क्वोमिंतांङ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच "मध्यस्थता" करने के लिए आया था, लेकिन असल में उसका उद्देश्य "मध्यस्थता" के धूमावरण के पीछे युद्ध की तैयारियों को तेज करने में क्वोमिंतांङ की मदद करना था ।

उसी वक्त, जब युद्ध-विराम के बारे में आदेश जारी किए गए थे, छुङकिङ में **राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन**[1] शुरू हुआ, जिसमें क्वोमिंतांङ, कम्युनिस्ट पार्टी, नौजवान पार्टी (यूथ पार्टी) तथा जनवादी लीग के प्रतिनिधियों व निर्दलीय गण्यमान्य व्यक्तियों ने देशभर के वामपंथी, दक्षिणपंथी तथा मध्यमार्गी राजनीतिक ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिक्रियावादी बहुमत में थे, सम्मेलन ने पाँच प्रस्ताव पास किए जिनसे शांति, एकता, जनवाद तथा एकीकरण को बढ़ावा मिला । ये प्रस्ताव सरकार के पुनर्गठन, राष्ट्रीय असेम्बली, देश के शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम, संविधान के मस्विदे तथा फौजी समस्याओं के बारे में थे । ये प्रस्ताव केवल जनता के अत्यधिक दबाव तथा विकट संघर्ष के फलस्वरूप ही पारित हो पाए थे । फौजी समस्याओं तथा संविधान के मस्विदे से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से कटु वाद-विवाद का विषय थे ।

फौजी प्रश्न के सम्बन्ध में क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादियों तथा उनके पिछलग्गुओं—नौजवान पार्टी ने *"सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण"* का प्रस्ताव पेश किया । क्वोमिंतांङ की हाँ में हाँ मिलाते हुए, नौजवान पार्टी के एक प्रतिनिधि छन ची-थ्येन ने जोर दिया कि *"सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न राजनीतिक जनवादीकरण के प्रश्न से पहले हल होना चाहिए"* तथा यह कि *"हथियार डालने से पहले जनवाद तथा संवैधानिक सरकार के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती ।"* इसका अर्थ था, कि क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादी जनता की सशस्त्र सेनाओं को जनवाद लागू करने के बहाने खत्म कर देना चाहते थे ।

राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन में आमतौर से वही रुख अख्तियार किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का था । उन्होंने शांति तथा जनवाद का समर्थन, व गृहयुद्ध तथा तानाशाही का विरोध किया । लेकिन जिस मिलीजुली सरकार का प्रस्ताव उन्होंने रखा, वह यूरोपीय या अमरीकी किस्म की संसदीय प्रणाली से कुछ भी भिन्न न था । तथा उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर एक निराकार (काल्पनिक) दृष्टि डाली, कोई यथार्थ विश्लेषण नहीं किया कि सेनाएं किस किस्म के राज्य से सम्बद्ध होंगी, एक जनवादी राज्य से या फिर एक तानाशाही राज्य से ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए एक आधारभूत सिद्धान्त तथा मूल योजना पेश की । इस तथ्य के मद्देनजर कि संसार में कोई भी राज्य कभी भी निराकार रूप में अस्तित्व में नहीं रहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट किया कि दो प्रकार के राज्य थे जिनसे सशस्त्र सेनाएं सम्बद्ध हो सकती थीं । एक जनवादी राज्य में, राष्ट्रीयकरण के बाद सशस्त्र सेनाएँ जनवादी शासनतन्त्र का अंग बन जाती हैं, तथा तानाशाही में वे तानाशाही शासनतन्त्र का अंग बन जाती हैं । कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीयकरण के पहले तरीके की समर्थक थी ।

प्रथम, सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण से पहले राज्य का जनवादीकरण किया जाना चहिये था, अर्थात् क्वोमिंतांङ की एकदलीय तानाशाही को समाप्त करके, उसके स्थान पर एक जनवादी मिलीजुली सरकार की स्थापना करना जरूरी था । सशस्त्र सेनाओं का भी सेना तथा जनता के बीच तथा अफसरों एवं सैनिकों के बीच आपसी सहयोग के सिद्धान्त पर, जनवादीकरण किया जाए । राज्य तथा सशस्त्र सेनाओं का जनवादीकरण—सशस्त्र सेनाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए दो पूर्व शर्तें थीं ।

दूसरे, जनवादी मिलीजुली सरकार तथा एक संयुक्त सर्वोच्च कमान की स्थापना के उपरान्त, कम्युनिस्ट पार्टी जन-मुक्ति सेना को तुरन्त सरकार के सुपुर्द कर देगी, बशर्ते कि क्वोमिंतांङ भी अपनी सभी सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में ऐसा ही करे। वास्तव में सशस्त्र सेनाओं के प्रश्न के समाधान की मूलभूत योजना इस प्रकार थी कि क्वोमिंतांङ तथा मुक्त क्षेत्रों, दोनों की सशस्त्र सेनाएं अपने आपको एक साथ जनवादी मिलीजुली सरकार के हवाले कर देंगी ।

फौजी मामलों से संबंधित समझौते में बहुत से सिद्धान्त निर्धारित किये गये । इसका पहला सिद्धान्त—*"सेना तथा राजनीतिक पार्टियों को अलग-अलग रखने के बारे में"* था । इसके अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्ति सेना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक संघर्ष के साधन के तौर पर नहीं कर सकता था । दूसरे सिद्धान्त—*"फौजी सत्ता तथा नागरिक सत्ता को अलग रखने"* में व्यवस्था थी कि सामरिक सेवा में नियुक्त किसी भी अधिकारी को एक ही समय में नागरिक अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । तीसरे सिद्धान्त—*"फौजी कमान में राजनीति"* में व्यवस्था थी कि क्वोमिंतांङ की फौजी परिषद का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मन्त्रालय के रूप में पुनर्गठन किया जाए, तथा यह मंत्रालय कार्यकारी ध्वान के अधीन हो तथा देश की सभी सशस्त्र सेनाओं का संचालन करे । चौथे—*"समस्त देश की सशस्त्र सेनाओं के न्यायसंगत तथा समानता के आधार पर पुनर्गठन"* में व्यवस्था थी कि पुर्नगठन के बाद समूचे देश की सशस्त्र सेनाएं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेना का रूप ले लेंगी ।

जहां तक संविधान के मस्विदे का संबंध था, क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादियों तथा उनके पिछलग्गुओं ने सोचा कि सभी कुछ उनके अनुकूल था । वे क्वोमिंतांङ के एकाधिकार वाली

जरूरी था । लड़ाइयों के बीच के अन्तराल को ठीक ढंग से फौजी तथा राजनीतिक प्रशिक्षण देने में प्रयोग करना, तथा हर लड़ाई के बाद, उस लड़ाई के अनुभव के सारांश को सारी यूनिट के सामने रखना जरूरी था । अपने से बेहतर साजोसामान से लैस शत्रु सेना को पराजित करने के लिए आमने-सामने की हाथापाई की लड़ाई, रात के समय की लड़ाई तथा लगातार लंबी खिंचने वाली लड़ाई के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना जरूरी था । शत्रु के एक हिस्से को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित करने तथा विभिन्न शत्रु यूनिटों को एक-एक करके नष्ट कर देने का सिद्धान्त, जन-मुक्ति सेना की स्थापना के दिन से ही उसकी उत्कृष्ट परम्परा का अंग रहा था । इसके अतिरिक्त, तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के दौरान, जन-मुक्ति सेना की बेहतर सैन्य-शक्ति ने, केन्द्रित सैन्य-शक्ति द्वारा चलायमान लड़ाई को युद्ध की मुख्य किस्म के रूप में अपनाना तथा बिखरी हुई सैन्य-शक्ति के साथ छापामार लड़ाई को युद्ध की सहायक किस्म के रूप में अपनाना संभव बनाया ।

इस प्रकार, हालांकि समस्त युद्ध की परिस्थिति के लिहाज से जन-मुक्ति सेना की सैन्य-शक्ति अपेक्षाकृत कमतर थी, परन्तु हरेक अलग-अलग लड़ाई में शत्रु का सामना नितान्त बरतर सैन्य-शक्ति से किया जाता था और इस प्रकार विजय को सुनिश्चित किया जाता था । समय बीतने के साथ-साथ युद्ध के हर पहलू में बरतरी जन-मुक्ति सेना के हाथों में आ जानी थी, जो अपनी क्षतिपूर्ति शत्रु के पूरे के पूरे साजोसामान से तथा पकड़े गए अधिकांश शत्रु सैनिकों से करती थी ।

क्वोमिंतांङ को हराने के लिए ये मुख्य रणनीतिक सिद्धान्त, जन-मुक्ति सेना द्वारा पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा अध्यक्ष माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में, घरेलू तथा विदेशी शत्रुओं के खिलाफ दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षों के दौरान विकसित किये गए थे । च्याङ काई-शेक को इन सिद्धान्तों की पूरी जानकारी थी तथा इनका सामना करने के लिए उसने अनेक उपायों का भी अध्ययन किया था, परन्तु वह कोई हल नहीं निकाल पाया था । और इसके पीछे जो कारण था, वह बेहद सीधा-सादा था । जन-मुक्ति सेना की रणनीति तथा कार्यनीति, लोकयुद्ध की उपज थी; कोई भी प्रतिक्रान्तिकारी सेना इनसे लाभ नहीं उठा सकती थी ।

क्वोमिंतांङ ने मुक्त क्षेत्रों पर चौतरफा हमला करके कम्युनिस्ट-विरोधी गृहयुद्ध छेड़ने का दुस्साहस, मुख्यतः अपनी अपेक्षाकृत सैनिक श्रेष्ठता के बल पर किया था । लेकिन सैनिक दृष्टिकोण के लिहाज से क्वोमिंतांङ की भी अनेक लाइलाज कमजोरियाँ थीं । राष्ट्रव्यापी युद्ध की माँगों के तकाजे के फलस्वरूप, उसकी नीति मध्य मैदानी भाग, उत्तरी च्याङसू प्रान्त, छङते, आनतुङ तथा हारबिन पर कब्जा करने, छिङताओ-चीनान रेलमार्ग व ताथुङ-फूचओ रेलमार्ग पर नियन्त्रण करने तथा दक्षिण में नानकिङ से लेकर उत्तर पूर्व में छाङछुन तक एक संचार-पंक्ति (परिवहन पंक्ति) चालू करने की थी । यह संचार-पंक्ति (परिवहन पंक्ति) बहुत दूर तक फैली हुई थी तथा इसके दोनों और विशाल पर्वतश्रेणियां तथा ऊँची चोटियां थीं । उत्तर-पूर्व, पाँच सौ किलोमीटर लंबी सप्लाई-लाइन के अंतिम छोर पर पड़ता था । चूंकि क्वोमिंतांङ ने सिर्फ 16 लाख सैनिकों के दम पर, इतने ज्यादा क्षेत्रों तथा इतनी लंबी संचार-पंक्तियों (परिवहन-पंक्तियों) व उन पर स्थित सभी नगरों पर कब्जा करने का प्रयास किया था, अतः उसे अपनी सैन्य-शक्ति को अनेक रक्षक टुकड़ियों के रूप में विभाजित करना पड़ा । जिसके फलस्वरूप उसे मानव-शक्ति की कमी का सामना करना पड़ा । अपने दूर तक

संयुक्त मोर्चा गठित किया जा सकता था । चीनी जनता की क्रान्ति की सफलता के लिए यह एक बेहद महत्त्वपूर्ण तत्व था । प्रतिक्रियावादियों की मूलभूत कमजोरी उनके राजनीतिक रुख के प्रतिक्रियावादी स्वरूप में निहित थी । कोई भी शक्ति कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी पराजय होनी निश्चित थी, यदि वह जनता के प्रति क्रूर तथा प्रतिक्रियावादी थी ।

क्वोमिंताङ हमले को पराजित करने के लिए, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने एक सही रणनीतिक योजना तैयार की, जिसके अनुसार मुख्य उद्देश्य शत्रु की प्रभावकारी शक्ति को नेस्तनाबूद करना था, न कि किसी विशेष कस्बे या क्षेत्र की सुरक्षा करना । अत: जब एक मुहिम में क्वोमिंताङ सेना बड़े पैमाने पर हमला करती थी तथा जन-मुक्ति सेना के विरुद्ध अनेक दिशाओं से एक साथ आगे बढ़ती थी, तब जन-मुक्ति सेना को दुश्मन की सैन्य-शक्ति के एक हिस्से के खिलाफ पूर्णतया बरतरी हासिल करने के लिए तथा अनुकूल अवसर चुनकर उस हिस्से का सफाया करने के लिए, अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित करना होता था । दुश्मन फौज का चुना गया हिस्सा ऐसा होना चाहिये था, जो अपेक्षाकृत कमजोर हो, जिसे कुमुक भेजने की कम व्यवस्था हो, तथा जिसने ऐसी जगह पड़ाव डाला हुआ हो, जहां का धरातल तथा जनता उसके प्रतिकूल हों । इसी दौरान, जन-मुक्ति सेना को कम सैन्य-शक्ति इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की बाकी सैन्य-शक्ति को उलझाए रखना होता था, ताकि उन्हें घिरी हुई शत्रु फौज के पास जल्दी कुमुक पहुँचाने से रोका जा सके । विजय प्राप्ति के बाद, अगला कदम दुश्मन फौज के अन्य हिस्सों को नेस्तनाबूद करना हो या फिर अगली लड़ाई की तैयारी के लिए लड़ाई स्थगित कर अपनी फौजों को विश्राम करवाना हो, इसका फैसला लड़ाई की वास्तविक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिया जाता था । कार्यनीतिक स्तर पर, जब शत्रु फौज के एक हिस्से को घेरने व नेस्तनाबूद करने के लिए अपेक्षाकृत बरतर सैन्य-शक्ति को केन्द्रित करना होता था, तब हमले में भाग लेने वाली विभिन्न यूनिटों को शत्रु को एक ही वार में नेस्तनाबूद करने के लिए सभी ठिकानों पर अपनी फौजें तैनात नहीं करनी होती थीं । इससे हमला करने वाली विभिन्न यूनिटों की आक्रामक शक्ति पर अनिवार्य रूप से बुरा असर पड़ता था तथा शत्रु का विनाश होने में देरी होती थी, या फिर शत्रु को नष्ट करना ही मुश्किल हो जाता था । इसके बजाय, केन्द्रित बरतर सैन्य शक्ति को, घेरे में पड़ी टुकड़ी के सबसे कमजोर हिस्से को चुनकर, भीषण प्रहार करना होता था तथा निश्चित रूप से विजय हासिल करनी होती थी । विजय प्राप्त करने के तुरन्त बाद, हमले के क्षेत्र का विस्तार करना तथा शत्रु टुकड़ियों को एक-एक करके पराजित करना अत्यन्त जरूरी था ।

इस तरह की रणनीतिक योजना के दो फायदे होते थे—पूर्ण विनाश करना तथा तत्काल फैसला करना । केवल पूरी तरह विनाश करके तथा शत्रु की प्रभावकारी शक्ति को नष्ट करके ही जन-मुक्ति सेना शत्रु को कारगर रूप से आघात पहुँचा सकती थी । और यही एक रास्ता था जिससे जन-मुक्ति सेना की क्षतिपूर्ति यथेष्ट रूप से की जा सकती थी, इसकी मानव-शक्ति तथा शस्त्रास्त्रों की समस्या का समाधान किया जा सकता था तथा शत्रु फौज का मनोबल पूरी तरह से तोड़ा जा सकता था, जबकि जन-मुक्ति सेना का मनोबल इससे बढ़ना था । सिर्फ तत्काल फैसले की लड़ाई ही, शत्रु की कुमुकों से टकराए बिना उसे नेस्तनाबूद कर सकती थी।

क्रान्तिकारी युद्ध एक दीर्घकालीन युद्ध था तथा लड़ाइयां लगातार काफी बड़ी मात्रा में चलती रहीं । इस बात के मद्देनजर, सैनिकों के प्रशिक्षण पर लगातार ध्यान दिया जाना बेहद

"राष्ट्रीय असेम्बली" में क्वोमिंताङ द्वारा गढ़ा गया **"5 मई संविधान मस्विदा"**[12] पारित करवाना चाहते थे ताकि क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के फासीवादी राजनीतिक अभिभावकत्व को फासीवादी **"संवैधानिक सरकार"**[13] में बदला जा सके । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रतिक्रियावादी प्रयास के विरुद्ध बेहद कड़ा रुख अपनाया ।

संविधान के मस्विदे के बारे में प्रस्ताव में यह व्यवस्था थी कि **विधान ग्वान,** जो एक जनवादी राज्य की संसद के समकक्ष थी तथा सीधे जनता द्वारा चुनी जानी थी; राजसत्ता की शक्ति का सर्वोच्च संगठन होनी थी तथा कार्यकारी ग्वान जो कि मन्त्रीमण्डल के समकक्ष होनी थी, राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई होनी थी । कार्यकारी ग्वान को विधान ग्वान के प्रति जवाबदेह होना था तथा विधान ग्वान को कार्यकारी ग्वान के किसी भी निर्णय को मंजूर करने, वीटो करने अथवा किसी भी निर्णय पर अविश्वास मत व्यक्त करने का अधिकार होना था । **निरीक्षण ग्वान (Control Yuan),** जिसका चुनाव प्रान्तीय विधान सभाओं तथा राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्रों द्वारा किया जाना था, राज्य की सर्वोच्च निरीक्षण इकाई होनी थी तथा उसे कार्यकारी ग्वान के कार्यकलापों को मंजूर करने, महाभियोग चलाने व देख-रेख करने का अधिकार होना था । **न्यायिक ग्वान** को सर्वोच्च न्यायालय होना था । **परीक्षा-ग्वान** को नागरिक कर्मचारियों की तथा व्यवसायों से संबंधित लोगों की परीक्षाओं की व्यवस्था करनी थी। प्रस्ताव में प्रान्तीय स्वायत्तता प्रणाली की भी व्यवस्था थी, जिसके तहत एक प्रान्त को अपना अलग प्रान्तीय संविधान बनाने का अधिकार था, बशर्ते कि वह राष्ट्रीय संविधान का उल्लंघन न करता हो । संसदीय प्रणाली, मंत्रीमण्डलीय प्रणाली तथा स्थानीय स्वायत्तता की प्रणाली ने मूलत: संविधान के मस्विदे के प्रश्न का समाधान कर देना था ।

तीन अन्य प्रस्तावों में विभिन्न जनवादी पार्टियों की सरकार में भागेदारी तथा क्वोमिंताङ की एकदलीय तानाशाही का उन्मूलन, एक जनवादी संविधान तैयार करने हेतु राष्ट्रीय असेम्बली बुलाने तथा जनवादी मिलीजुली सरकार द्वारा अमल में लाई जाने वाली कुछ खास नीतियों की बात कही गई थी ।

ये पाँचों प्रस्ताव, वास्तव में क्वोमिंताङ की तानाशाहीपूर्ण शासन-व्यवस्था, गृहयुद्ध की नीति तथा सामंती, दलाल तथा फासीवादी राजनीतिक अभिभावकत्व वाली शासकीय प्रणाली का खण्डन थे । मौजूदा परिस्थितियों में ये प्रस्ताव मूलत: समस्त देशवासियों की शांति तथा जनवाद के लिए आकांक्षाओं के अनुरूप थे । वे जनता की राजनीतिक विजय तथा प्रतिक्रियावादियों की राजनीतिक पराजय के द्योतक थे । यही कारण है कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रतिक्रियावादी आग-बबूला हो गए थे जब कि जनता ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की सफलता का सर्वत्र गर्मजोशी से स्वागत किया । ●

4.

● अमरीका सरकार के समर्थन से क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों द्वारा कम्युनिस्ट-विरोधी गृहयुद्ध की तैयारियाँ ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमेशा की भाँति अपने वचन पर खरे उतरते हुए 10 जनवरी, 1946 को जन-मुक्ति सेना की सभी यूनिटों को युद्ध-विराम के आदेश जारी कर दिए तथा

जनता के साथ मिलकर राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों को लागू करने में जुट गई।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की दृष्टि में, तथापि युद्ध-विराम समझौता तथा राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्ताव, मात्र राजनीतिक दांव-पेच थे, ताकि कम्युनिस्टों के खिलाफ फौजी कार्यवाहियाँ करने में सुविधा हो सके । अमरीकी साम्राज्यवादियों की मदद के दम पर खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए, चीनी प्रतिक्रियावादियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा जन-मुक्ति सेना को अपने षड्यन्त्रों को साकार करने के रास्ते में, मुख्य बाधाओं के रूप में देखा । केवल प्रतिक्रान्तिकारी गृहयुद्ध की तैयारी हेतु समय प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने जनता की शान्ति के लिए माँग को स्वीकार करने का स्वांग रचा ।

जब राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन अभी चल ही रहा था, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के विशेष एजेन्टों ने छाङपाए हाल में 'छुङकिङ निवासियों की एसोसिएशन' द्वारा आयोजित एक सभा पर हमला बोल दिया । इस सभा का आयोजन समाज के विभिन्न तबकों के लोगों ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के समर्थन के लिए किया था । इन विशेष एजेन्टों ने सम्मेलन में भाग लेने आए अनेक प्रतिनिधियों के आवास-स्थलों की भी तलाशी ली । 10 फरवरी को, सम्मेलन की समाप्ति के उपरान्त, छुङकिङ में च्याओचाङखओ के स्थान पर राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सफल समापन की खुशी में आयोजित की गई एक सभा पर क्वोमिंताङ के एजेन्टों ने हमला किया तथा क्वो मो-रो तथा ली खुङ-पो समेत कई वक्ताओं को घायल कर दिया । यह घटना च्याओचाङखओ कांड के नाम से कुख्यात हुई । बाद में, क्वोमिंताङ ने चीन के अनेक हिस्सों में, सोवियत-विरोधी, कम्युनिस्ट-विरोधी, तथा जनवाद-विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए । 20 फरवरी, 1946 को, उसके एजेन्टों ने पेकिङ में फौजी मध्यस्थता के लिए स्थापित किए गए कार्यकारी मुख्यालय को तहस-नहस कर दिया । राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों के विरुद्ध की गई इन सभी घृणित कार्यवाहियों में एजेन्टों ने आम नागरिकों का छद्म वेश धारण किया हुआ था ।

मार्च 1946 में क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अपने पूर्ण अधिवेशन में संविधान के मस्विदे से सम्बन्धित उन बुनियादी जनवादी सिद्धान्तों को खुल्लमखुल्ला नकार दिया, जिनमें संसदीय प्रणाली, मंत्रीमण्डलीय प्रणाली तथा प्रान्तीय स्वायत्तता की प्रणाली अपनाने के लिए प्रावधान था, तथा जिन्हें राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन में एक समझौते के तहत स्वीकृति प्रदान की गई थी । इन सिद्धान्तों में डॉ० सुन यात-सेन की अवधारणाओं का जनवादी सार निहित था तथा मौजूदा हालात में ये सिद्धान्त चीन को जनवादी संविधानवाद के मार्ग पर ले जाते । इन सिद्धान्तों का विशेष महत्त्व था क्योंकि इन्हीं के द्वारा चीन में तानाशाही की जगह एक जनवादी राजनीतिक प्रणाली स्थापित की जा सकती थी । इसलिए ये सिद्धान्त एक धुरी बन गए थे जिसके इर्द-गिर्द चीनी जनवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी डॉ० सुन यात-सेन की अवधारणाओं को पूर्णरूपेण तिलांजलि दे रहे थे । वे चाहते थे कि संविधान, *"राज्य की स्थापना के लिए सिद्धान्तों की रूपरेखा"* तथा **"पाँच शक्ति"** संविधान" के आधार पर तैयार किया जाए । उन्होंने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन में संविधान के मस्विदे के बारे में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को रद्द करने के लिए अपने इस दावे को एक बहाने के रूप में प्रयोग किया । उन्होंने *"ताकत तथा योग्यता के बीच*

होना तथा व्यापक जन-समुदाय का समर्थन या विरोध, ऐसे तत्व थे जिनका स्थाई तथा दूरगामी प्रभाव पड़ना था ।

चीनी प्रतिक्रियावादियों द्वारा शुरू किया गया गृहयुद्ध एक प्रतिक्रान्तिकारी युद्ध था जो गद्दाराना, निरंकुश तथा जन-विरोधी था । कम्युनिस्ट-विरोधी युद्ध करने के लिए प्रतिक्रियावादियों को जनता का पहले से भी ज्यादा नृशंसतापूर्ण ढंग से शोषण तथा दमन करना पड़ता । इस प्रकार उन्हें अपने शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों की निहत्थी जनता के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ना पड़ता । लोगों को सेना में जबरन भर्ती करना तथा उसके फलस्वरूप सेना का मनोबल गिरना, ये एक प्रतिक्रान्तिकारी युद्ध के अनिवार्य परिणाम थे, जिसमें सैनिक हर वक्त अपने हथियार डालने को तैयार रहते थे । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की यह एक अत्यन्त गंभीर कमजोरी थी । फलतः क्वोमिंताङ सेनाएँ युद्ध से ऊबने लगीं, तथा क्वोमिंताङ नियन्त्रित क्षेत्रों की जनता ने युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया । इसके अतिरिक्त क्वोमिंताङ के विभिन्न गुटों तथा धड़ों में तीव्र अंतर्विरोध थे तथा क्वोमिंताङ सेना के अफसरों व जवानों में जबरदस्त आपसी द्वेष था । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था का अर्थतन्त्र, नौकरशाह-पूँजीवाद पर आधारित था, जिसका राष्ट्रीय अर्थतन्त्र पर एकाधिकार था । यह नौकरशाह-पूँजीवाद केवल श्रमिकों, किसानों तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग का ही दमन नहीं करता था, बल्कि राष्ट्रीय-पूँजीपति वर्ग के हितों को भी चोट पहुँचाता था । इसलिए क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी शासन को पलटने की मांग केवल श्रमिकों, किसानों तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग तक ही सीमित नहीं थी । राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का भी क्वोमिंताङ के विरुद्ध संघर्षों में शामिल होना अथवा तटस्थ रहना संभव था । दूसरी ओर, मुक्ति युद्ध एक न्यायसंगत क्रांतिकारी युद्ध था, जिसे समस्त जनता का समर्थन प्राप्त था । इस लिहाज से, मुक्त क्षेत्रों की सेना तथा जनता काफी ज्यादा लाभदायक स्थिति में थे। इसी दौरान, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती भूस्वामित्व को किसानों के भूमि पर स्वामित्व में बदलने की नीति पर अमल किया तथा शहरों में नौकरशाह पूँजी को जब्त करने व राष्ट्रीय उद्योग तथा वाणिज्य को सुरक्षा प्रदान करने की नीति अपनाई । विरोधियों की तादाद कम करने के लिए पार्टी, कृषि-सुधारों के दौरान गरीब किसानों तथा खेत मजूदरों पर भरोसा करते हुए, मध्यम किसानों को साथ लेकर चली तथा व्यवहार के दौरान, एक तरफ धनी किसानों, मध्यम या छोटे जमींदारों तथा दूसरी ओर, देशद्रोहियों, बुरे शरीफजादों तथा निरंकुश तत्वों के बीच फर्क किया । शहरों में, पार्टी ने मजदूर वर्ग पर भरोसा करते हुए निम्न-पूँजीपति वर्ग के व्यापक जन-समुदाय के साथ संश्रय स्थापित किया तथा प्रतिक्रियावादियों को अलगाव में डालने के लिए मध्यवर्ती शक्तियों को भी अपने साथ मिलाने का प्रयास किया । इन नीतियों ने समस्त जनता का समर्थन प्राप्त किया, जन-मुक्ति सेना का पृष्ठभाग सुदृढ़ किया, तथा क्रांतिकारी युद्ध की देशव्यापी विजय का राजनीतिक आधार तैयार कर दिया ।

क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की उम्मीदें अमरीकी सहायता पर टिकी हुई थीं । इससे उनकी अन्तर्निहित कमजोरी, भय तथा खोए हुए आत्मविश्वास का पता चलता था, तथा यह इस बात का सूचक था कि वे जानते थे कि अमरीकी सहायता पर निर्भर रहने के अलावा उनके पास और कोई चारा न था ।

घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सुस्पष्ट विश्लेषण से यह बात साफ हो जाती थी कि चीन में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, बड़े ही व्यापक पैमाने पर जनता का जनवादी

जन-मुक्ति सेना का पृष्ठभाग अभी पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो पाया था ।

सैनिक शक्ति की तुलना करें तो राजनीतिक योग्यता तथा जनता के साथ अपने सम्बन्धों के सिवाय, क्वोमिंताङ फौज हर तरह से जन-मुक्ति सेना से श्रेष्ठ थी । अत: ज्योंही युद्ध शुरू हुआ, च्याङ काई-शेक ने एक ही झटके में मुक्त-क्षेत्रों को नेस्तनाबूद कर देने के इरादों से अपनी 16 लाख की नियमित सेना को, मुक्त क्षेत्रों की जनता तथा सेना के विरुद्ध एक भयंकर तथा चौतरफे, हमले में झोंक दिया । शत्रु मुक्त क्षेत्रों पर सभी दिशाओं से टूट पड़ा । अत: युद्ध के इस आरंभिक चरण में, मुक्त क्षेत्रों की सेना तथा जनता ने रक्षात्मक लड़ाई लड़ने का फैसला किया ।

चीनी प्रतिक्रियावादियों तथा उनके अमरीकी आकाओं ने अपनी ताकत को वास्तविकता से ज्यादा करके आँका था तथा मुक्त क्षेत्रों की सेना व जनता की ताकत को वास्तविकता से कम करके आंका था ।

उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान-विरोधी युद्ध की समाप्ति के बाद से शांति और जनवाद के लिए जो प्रयास किए थे, वे उसकी कमजोरी, कायरता तथा अक्षमता के सूचक थे । उन्हें तो केवल संख्या तथा साजोसामान के लिहाज से श्रेष्ठ अपनी सेना ही नजर आ रही थी । अत: जनता की शांति-अभिलाषा का तिरस्कार करते हुए, उन्होंने युद्ध-विराम समझौते तथा राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों की धज्जियाँ उड़ा दीं तथा अपनी सैनिक सता व विशेषत: अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता के बल पर कूदते हुए, गृहयुद्ध छेड़ने का दुस्साहस कर लिया । किन्तु प्रतिक्रियावादी अपने हिसाब-किताब में भारी गलती खा गए।

तथापि, कुछ लोग बाहरी दिखावे से भयभीत हो गए । थोड़े से मुट्ठीभर बेशर्म राजनीतिज्ञ, जैसे कि नौजवान पार्टी का छङ ची तथा राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का छाङ छुन-माए, जो काफी अर्से से अवसरवादी तथा सट्टेबाजी का रवैया अपनाते चले आ रहे थे, एक भी क्षण गंवाए बिना क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के खेमे में जा मिले । लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अनुभवी व्यक्तियों में भी, क्रान्ति के मित्रों समेत, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यह संदेह होना शुरू हो गया कि इतनी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए, जन-मुक्ति सेना, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को परास्त भी कर पाएगी या नहीं ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रकार के निराशावाद तथा सन्देहों को सफलतापूर्वक दूर किया । युद्ध के आरंभ में ही पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा साथी माओ त्से-तुङ ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिस्थिति का मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों की रोशनी में वैज्ञानिक विश्लेषण किया तथा पूर्णतया स्पष्ट किया कि जनता को न केवल क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को हराना चाहिए था, बल्कि जनता उन्हें निश्चित तौर पर हरा सकती थी । जनता को उन्हें हराना ही चाहिए था क्योंकि क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने जो लड़ाई शुरू की थी वह चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा जनता की लोक गणराज्य की आकांक्षाओं के खिलाफ थी । यदि जनता ने प्रतिक्रान्तिकारी युद्ध का विरोध क्रान्तिकारी युद्ध से नहीं किया तो अमरीकी तथा चीनी प्रतिक्रियावादियों ने उसे अपना गुलाम बना लेना था । जनता क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को हरा सकती थी, क्योंकि सैनिक श्रेष्ठता तथा अमरीकी सहायता ऐसे तत्व थे जिनका मात्र अस्थायी प्रभाव पड़ना था, जबकि युद्ध का एक न्यायपूर्ण युद्ध होना अथवा अन्यायपूर्ण युद्ध

अन्तर करने'' तथा ''पाँच शक्तियों'' के विभाजन के लिए शोर मचाया । इसके पीछे उनका तर्क था कि प्रशासकीय सत्ता *''उनके हाथ में होनी चाहिए जिनके पास योग्यता है''* तथा राजनीतिक सत्ता *''उनके हाथ में होनी चाहिये, जिनके पास शक्ति है ।''* उन्होंने समूचे देश की जनता को अपमानित करते हुए कहा—चूंकि उसके पास ''योग्यता नहीं'' है, अत: वह देश का शासन चलाने में सक्षम नहीं है । उनकी धारणाओं के अनुसार जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं किसी भी तरह की राजनीतिक ताकत से विहीन हो जातीं । वास्तव में, **राजनीतिक सत्ता एक ठोस तत्व है; सरकारी संस्थाएँ, अदालतें, फौज, पुलिस तथा सशस्त्र बल इसकी विशिष्ट अभिव्यक्तियां होती हैं । जो भी इन का नियन्त्रण करता है, उसके पास राजनीतिक सत्ता तथा प्रशासनिक अधिकार, दोनों ही होते हैं; क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं होता । असली जनवाद वही होता है जिसमें जनता की शक्ति ही सरकार की शक्ति बनती है।** यदि जनता और उसके प्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि जनता के पास कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है । शक्ति को योग्यता से अलग रखने के डॉ० सुन यात-सेन के विचारों की आड़ में क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी राज्य तन्त्र को हथिया रहे थे, सामंती तथा दलाल तानाशाही स्थापित कर रहे थे, तथा सारे राष्ट्र को फासीवाद के निर्मम जुए तले जकड़ रहे थे ।

अप्रैल 1946 में, राष्ट्रीय राजनीतिक परिषद की एक मीटिंग में, च्याङ काई-शेक ने पुन: तथाकथित *''वैध सरकारी प्रणाली''* का हवाला देते हुए कहा कि इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए । ''वैध सरकारी प्रणाली'' असल में *''राजनीतिक अभिभावकत्व के समय के अंतरिम संविधान''* के अलावा और कुछ न थी । इस अंतरिम संविधान को 1931 के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था तथा च्याङ काई-शेक का कहना था कि इसी के आधार पर राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था । लेकिन, वास्तव में राष्ट्रीय सरकार की वैध प्रणाली तो बहुत पहले 12 अप्रैल, 1927 को ही समाप्त कर दी गई थी जब च्याङ काई-शेक और उसका गुट क्वोमिंताङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के खिलाफ हो गए थे । 1931 का राष्ट्रीय सम्मेलन केवल च्याङ गुट का सम्मेलन था, जिसमें क्वोमिंताङ के दूसरे गुटों के प्रतिनिधियों तक ने भाग नहीं लिया था, जनता के भाग लेने की बात तो बहुत दूर थी । वह सम्मेलन बुलाकर च्याङ काई-शेक ने अपने फासीवादी राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित कानून तैयार करने का तथा अपनी फासीवादी तानाशाही के आधार पर गृहयुद्ध का विस्तार करने का प्रयास किया ताकि जनता का कत्लेआम किया जा सके व अपने सभी विरोधियों से छुटकारा पाया जा सके।

10 जनवरी, 1946 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्रीय समिति ने, देशभर में जन-मुक्ति सेना की सभी यूनिटों को युद्ध-विराम के आदेश जारी कर दिए । लेकिन उस समय तक भी काफी बड़ी तादाद में जापानी तथा कठपुतली सेनाएं मौजूद थीं जो युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए मुक्ति सेना को भड़काने की कार्यवाहियाँ कर रही थीं । सभी झगड़ों को समाप्त करने के उद्देश्य से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ''तीन सदस्यों की समिति'' तथा ''पेकिङ कार्यकारी मुख्यालय'' के सामने प्रस्ताव रखा कि सभी जापानी तथा कठपुतली सैनिकों को निरस्त्र करने के लिए क्वोमिंताङ तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को तुरंत संयुक्त उपाय करने चाहिएं । इन उपायों के लागू होने से निश्चित रूप से घरेलू शांति को बढ़ावा मिलता । लेकिन

यह एक ऐसा कार्यभार था जिसे केवल एक जन-सरकार तथा एक जनवादी सर्वोच्च कमान ही अंजाम दे सकती थी । अत: कम्युनिस्ट पार्टी ने क्वोमिंताङ सरकार तथा फौजी परिषद के तत्काल पुनर्गठन की माँग की ।

लेकिन, चूंकि च्याङ काई-शेक तथा क्वोमिंताङ युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर करते समय ईमानदार नहीं थे, अत: वे इसका उल्लंघन करते रहे । 7 जनवरी, 1946 को, युद्ध-विराम आदेश जारी करने से पहले च्याङ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अपने लिए लाभदायक ठिकानों पर कब्जा कर लें, तथा आदेश लागू होने वाले दिन, उसके लागू होने से तुरन्त पहले, उसने अपने सैनिकों को पुन: आदेश दिया कि वे "सामरिक महत्त्व के ठिकानों पर कब्जा कर लें ।" प्रकट में तो उसने युद्ध-विराम आदेश जारी किया, लेकिन गोपनीय रूप से उसने युद्ध शुरू करने के आदेश जारी किए ।

युद्ध-विराम समझौते में कहा गया था कि देश के सभी हिस्सों में लड़ाई तुरन्त रुक जानी चाहिए । चूंकि उत्तर-पूर्व भी चीन का ही एक भाग था, इसलिए वह कोई अपवाद न था । तथापि, उत्तर-पूर्व में क्वोमिंताङ सेनाएं, युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए, जनवादी संश्रयकारी सेना पर अपने हमले जारी रखे रहीं । यह तो लड़ाई के मोर्चों पर गंभीर क्षति उठाने तथा समस्त राष्ट्र के दबाव के कारण ही था कि क्वोमिंताङ को उस क्षेत्र के लिए एक विशेष युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा । लेकिन च्याङ काई-शेक अभी भी इसे लागू न करने पर अड़ा हुआ था । क्योंकि वह जनवादी संश्रयकारी सेना पर हमले करने तथा उत्तर-पूर्व की जनता द्वारा स्थापित स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार का तख्ता उलटने पर आमादा था । वह किसी भी कीमत पर वहां युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं था ।

शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से जन-मुक्ति सेना ने स्वेच्छा से छाङछुन खाली कर दिया । लेकिन क्वोमिंताङ सेनाओं ने अपना हमला जारी रखा । सफिङच्ये की लड़ाई में बहुत बड़ी तादाद में उनका सफाया हो गया । 6 जून, 1946 को क्वोमिंताङ को मजबूर होकर युद्ध रोकना पड़ा । लेकिन बाद में, उसने उत्तर-पूर्व के सभी बड़े शहरों तथा रेलमार्गों के साथ लगते सभी क्षेत्रों से, एक निश्चित समयावधि के अन्दर, जन-मुक्ति सेना की वापसी की माँग की।

क्वोमिंताङ ने लंबी दीवार के दक्षिण में काफी समय से घिरी मध्य चीन की 60,000 की तादाद वाली जन-मुक्ति सेना की "घेराबन्दी करने तथा उसका सफाया करने" के लिए 3,00,000 सैनिक भेजने की योजना बनाई । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने क्वोमिंताङ को चेतावनी दी कि यदि यह कार्यवाही न रोकी गई तो इसकी राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया होगी तथा पूर्ण रूप से गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा । लेकिन क्वोमिंताङ ने 26 जून, 1946 को, जब नानकिङ में अभी बातचीत चल ही रही थी, अपनी योजनानुसार कार्यवाही कर दी तथा जन-मुक्ति सेना को घेरा तोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा ।

युद्ध-विराम आदेश की मुख्य धाराओं में से एक, सभी सेनाओं के आवागमन पर रोक लगाने की थी । लेकिन युद्ध-विराम आदेश जारी होने के दिन से लेकर मई, 1946 के अन्त तक, क्वोमिंताङ ने गृहयुद्ध की तैयारी हेतु अपनी 13 लाख फौजों को मोर्चों पर इधर-उधर तैनात किया तथा पश्चिमी हपे, दक्षिणी शानशी, दक्षिणी हनान तथा उत्तरी हुपे में किलेबन्दियों का निर्माण किया ताकि मुक्त क्षेत्रों की घेराबन्दी तथा नाकाबन्दी की जा सके ।

जनवरी से जून 1946 तक, क्वोमिंताङ सेना ने मुक्त क्षेत्रों में 4158 स्थानों पर 4385

बारहवां अध्याय

तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध में रणनीतिक रक्षा जन-मुक्ति सेना द्वारा क्वोमिंताङ के फौजी हमलों का मुँह-तोड़ जवाब

(जुलाई 1946 से जून 1947)

1.

● क्रान्तिकारी युद्ध के राजनीतिक तथा फौजी सिद्धान्त ।

जुलाई 1946 में, दुनिया के अव्वल दर्जे के देशद्रोही गुट, च्याङ काई-शेक गुट ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति, अमरीका की मदद से, जनता की इच्छाओं को रौंदते हुए मुक्त क्षेत्रों की जनता पर राष्ट्रव्यापी गृहयुद्ध थोंप दिया ।

युद्ध शुरू होने के समय शत्रु की शक्ति तुलनात्मक रूप से काफी श्रेष्ठ थी । उसके पास 43 लाख सैनिक तथा 30 करोड़ आबादी थी । इसके अलावा, देश के सभी बड़े शहरों तथा अधिकांश रेलमार्गों पर उसका नियंत्रण था, तथा वह संसाधनों से भरपूर था । इसके अतिरिक्त, 10 लाख जापानी सैनिकों का सारे का सारा साजोसामान भी क्वोमिंताङ ने हड़प लिया था । लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व, अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा दी जा रही मदद थी; उन्होंने क्वोमिंताङ सेनाओं को शस्त्रास्त्र दिए व प्रशिक्षित किया; साथ ही मुक्त क्षेत्रों पर हमले करने के लिए उन्हें मोर्चे पर भी पहुँचाया । क्वोमिंताङ के लिए बड़े शहरों की रक्षा करने के बहाने अथवा मुक्त क्षेत्रों में दूर तक घुसपैठ करने में क्वोमिंताङ फौजों की मदद करने के बहाने, अमरीकी फौजें चीन की धरती पर उतारी गईं । अमरीकी सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को बहुत सा जरूरी साजोसामान उपलब्ध करवाया । यह एक सच्चाई थी कि कम्युनिस्ट-विरोधी गृहयुद्ध की तैयारियां काफी अर्से से चल रही थीं। यह केवल अमरीकी साम्राज्यवादियों के पूर्ण समर्थन का ही नतीजा था कि क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने कुछ ही महीनों में मुक्त क्षेत्रों को नेस्तनाबूद करने की दुराशा पाले हुए, देशव्यापी गृहयुद्ध आरंभ करने का दुस्साहस किया ।

दूसरी ओर, चीनी जन-मुक्ति सेना के पास कुल मिलाकर लगभग 12 लाख सैनिक थे। शत्रु-सेनाएँ जन-सेनाओं से साढ़े तीन गुणा ज्यादा थीं तथा उनके शस्त्रास्त्र भी अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे । उस समय मुक्त क्षेत्रों की आबादी, 13 करोड़ से कुछ ही ऊपर थी तथा मोटे तौर पर यह क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों की आबादी की तुलना में एक तिहाई थी । इसके अतिरिक्त, मुक्त क्षेत्रों में, अभी तक कृषि-सुधार पूरी तरह लागू नहीं हो पाए थे तथा न ही वहां पर सामन्ती प्रतिक्रियावादी ताकतों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सका था । फलत:

दिखावा करते हुए, "चीनी गणराज्य के संविधान का मस्विदा" तैयार किया । इस संविधान के मस्विदे को 5 मई, 1936 को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया जिसके कारण इसका नाम "5 मई के संविधान का मस्विदा" पड़ा ।

3. संवैधानिक सरकार:- डॉ० सुन यात-सेन ने अपनी रचना—"राज्य की स्थापना के सिद्धान्तों की रूप रेखा" में "राज्य की स्थापना की प्रक्रिया" को तीन कालखण्डों में विभाजित किया—सैनिक सरकार, राजनीतिक अभिभावकत्व तथा संवैधानिक सरकार । काफी समय से, च्याङ काई-शेक के नेतृत्व में क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी "सैनिक सरकार" तथा "राजनीतिक अभिभावकत्व" का राग अलाप रहे थे तथा "संवैधानिक सरकार" की स्थापना को टालने के लिए तथा एक प्रतिक्रान्तिकारी तानाशाही स्थापित करने के लिए, इन्हें एक आड़ के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे तथा इस प्रकार जनता को हर प्रकार की आजादी से वंचित कर रहे थे ।

4. पाँच शक्तियाँ :- इनमें कार्यकारी, विधान, निरीक्षण, न्यायिक तथा जाँच (परीक्षा) विभाग शामिल थे ।

●●●

हमले किए, 40 शहरों तथा 2577 गाँवों व कस्बों पर कब्जा कर लिया । इन हमलों में **इस्तेमाल** फौजों की कुल संख्या 27 लाख 70 हजार थी ।

17 जून को च्याङ काई-शेक ने बड़े ही निरंकुश ढंग से माँग रखी कि चीनी **कम्युनिस्ट** पार्टी राजनीतिक बातचीत शुरू करने से पहले उसकी पूर्णतया बेसिर पैर की शर्तों को स्वीकार करे । उसने उत्तर-पूर्वी चीन के लगभग सभी के सभी नौ प्रान्तों, च्याङसू-आनह्वेइ क्षेत्र, जेहोल तथा हपे के प्रान्तों, लुङहाए तथा थ्येनचिन-फूखओ रेलमार्गों तथा वेइहाएवेइ व येनथाए की बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेने की जिद की ।

इस अवधि के दौरान तथा बाद में अमरीका सरकार की मध्यस्थता ने, क्वोमिंताङ की युद्ध की तैयारियों में भरसक मदद की ।

चीन सबसे बड़ा औपनिवेशिक बाजार था जिस पर अमरीकी एकाधिकारवादी पूँजीपति एकमात्र अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, तथा उसे एक अमरीकी उपनिवेश में बदल देना, अमरीकी साम्राज्यवादियों की मुख्य युद्धेतर नीतियों में से एक थी । अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्होंने क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि गृहयुद्ध के माध्यम से चीनी जनता पर हमला किया जा सके । वास्तव में, यह केवल उन्हीं की मदद का परिणाम था कि क्वोमिंताङ कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध शुरू करने में सक्षम हो सकी । और इसी आधार पर अमरीका तथा क्वोमिंताङ में युद्ध की सक्रिय तैयारी के लिए गठजोड़ और ज्यादा गहरा हो गया ।

दिसम्बर 1945 में जॉर्ज सी०मार्शल चीन आया । कहने को तो वह चीन के गृहयुद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन असल में उसने युद्ध को तेज करने में क्वोमिंताङ का साथ दिया । जब राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का अधिवेशन जारी था, उसने चीनी सरकार में च्याङ काई-शेक की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक योजना तैयार की । 7 फरवरी, 1946 को अमरीकी स्टेट डिपार्टमैन्ट ने क्वोमिंताङ को एक सोवियत-विरोधी नोट भेजा, जिससे चीन में प्रतिक्रियावादियों को सोवियत संघ, कम्युनिस्टों तथा जनवाद के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को तेज करने का प्रोत्साहन मिला । अमरीकी सरकार ने अलबर्ट सी० वेडेमेयर को क्वोमिंताङ सरकार की फौजों को उत्तर-पूर्व की बन्दरगाहों तक ले जाने में मदद देने का आदेश दिया तथा क्वोमिंताङ सरकार को बेहिसाब फौजी साजोसामान सप्लाई किया । 14 जून, 1946 को अमरीकी विदेश मंत्री जेम्स बायरनेस ने अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया, जिसके तहत च्याङ काई-शेक को 10 साल तक फौजी मदद दी जानी थी तथा घोषणा की कि अमरीका चीन से अपनी सेनाएँ नहीं हटाएगा । छिङवाङताओ तथा छिङताओ में अमरीकी सैनिकों ने चीनी जन-मुक्ति सेना को ललकारा तथा क्वोमिंताङ सेना के अग्रिम दस्तों के रूप में लड़े ।

1949 में जारी अमरीकी श्वेत पत्र—"**चीन के साथ अमरीका के संबंध**"—में अमरीका सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चीन में अपनी साम्राज्यवादी नीति को स्वीकार किया । युद्ध के बाद चीन को लेकर अमरीका के सामने तीन संभावित कार्यदिशाएं थीं । पहली थी—"**अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर चीन से बाहर निकल जाना ।**" अमरीका सरकार ऐसा करने के लिए तैयार न थी, क्योंकि अमरीका के लिए ऐसा करना अपने "*अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों*" (दूसरे शब्दों में—दुनिया पर दादागिरी) तथा चीन के प्रति अपनी

"पारंपरिक" (अर्थात्—हमलावर) नीति का परित्याग करना होता । दूसरी थी—अमरीका बहुत बड़े पैमाने पर फौजी हस्तक्षेप करके, कम्युनिस्टों का विनाश करने में राष्ट्रवादियों की मदद कर सकता था । लेकिन अमरीका सरकार को यह भी भली-भांति मालूम था कि चीनी जनता अत्यधिक देशभक्त थी तथा चीन की प्रभुसत्ता के किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का उस द्वारा दृढ़ता से विरोध किया जाना था । इसके अतिरिक्त अमरीकी जनता ने भी चीन के विरुद्ध लड़ाई की कभी भी अनुमति नहीं देनी थी । अत: अमरीका की यह रास्ता अपनाने की हिम्मत नहीं हुई । पहला रास्ता अपनाने को अनिच्छुक होने तथा दूसरा रास्ता अपनाने का साहस न होने के कारण, अमरीका सरकार ने तीसरा रास्ता अपनाया । वह था—चीन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर क्वोमिंताङ का आधिपत्य जमाने में उसकी मदद करना । ये वे साम्राज्यवादी मंसूबे थे, जिन्हें मन में संजोये जॉर्ज सी०मार्शल चीन में मध्यस्थता करने आया था । इस प्रकार चीन के प्रति अपनी नीति के अनुसार, अमरीका सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से क्वोमिंताङ की मदद करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसका अस्थाई समझौता करवाया, ताकि *"राष्ट्रीय सरकार न केवल बनी रहे, बल्कि उसके प्रभाव-क्षेत्र में भी वृद्धि हो सके ।"* अमरीकी मध्यस्थता का उद्देश्य था क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की ताकत में वृद्धि करना ताकि कम्युनिस्ट-विरोधी गृहयुद्ध शुरू किया जा सके । साथ ही उनका उद्देश्य चीन में क्वोमिंताङ के बर्बर शासन को कायम रखने में उसकी मदद करना था, ताकि चीनी जनता को गुलाम बनाने के लिए उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके ।

अमरीकी सरकार की क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को फौजी मदद से तथा उसके द्वारा चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण गृहयुद्ध भड़क उठा, फैलता चला गया तथा उसे रोकना मुश्किल हो गया । यह अमरीका सरकार ही थी जिसने चीन को गृहयुद्ध, विभाजन, आतंक तथा भुखमरी के कगार पर धकेला । चीन में प्रतिक्रियावादी अलग-थलग पड़ गए थे तथा मुश्किलों में फँस गए थे । विदेशी साम्राज्यवादियों की मदद के बिना, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद गृहयुद्ध लड़ने का वे कभी भी साहस नहीं कर सकते थे । अमरीका सरकार से अनेक प्रकार की व्यावहारिक मदद में लगातार होती वृद्धि से, च्याङ काई-शेक पहले से भी ज्यादा उद्दण्ड होता चला गया । अमरीका की मध्यस्थता की नीति, जिसका एकमात्र उद्देश्य छल-कपट से च्याङ काई-शेक की मदद करना था, चीन में गृहयुद्ध भड़कने का मूल कारण थी ।

जापान-विरोधी युद्ध के बाद, यह अवश्यम्भावी था कि क्वोमिंताङ ने कम्युनिस्ट-विरोधी, जन-विरोधी गृहयुद्ध शुरू करने से बाज नहीं आना था । जब तक साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादी—सामन्त वर्ग तथा नौकरशाह-पूँजीपति वर्ग, चीन में मौजूद थे, गृहयुद्ध के लिए आर्थिक आधार विद्यमान था । तो भी वर्गों की तुलनात्मक ताकत तथा क्रांतिकारी ताकतों द्वारा चलाया गया संघर्ष, खास परिस्थितियों में यह तय करने में, एक खास भूमिका अदा कर सकते थे कि गृहयुद्ध होगा या नहीं । जापान-विरोधी युद्ध के बाद, देशभर के लोग शांति तथा जनवाद की माँग कर रहे थे तथा गृहयुद्ध एवं तानाशाही का विरोध कर रहे थे । जनता ने क्वोमिंताङ को इस बात के लिए राजी करने का भरसक प्रयास किया कि वह शांति स्वीकार करे तथा शांतिपूर्ण परिस्थितियों में सुधार लागू करे । गृहयुद्ध भड़कने से पहले, जनता ने शान्ति कायम रखने का हर संभव प्रयास किया । चीनी जनता के नेक इरादों तथा माँगों को पूरा करने के लिए, अन्तिम क्षणों में भी शांति की रक्षा के लिए तथा जनता की नजरों में क्वोमिंताङ के

युद्धवादी उद्देश्यों की पोल खोलने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने खूब जोर लगाया, तथा युद्ध टालने व शांति कायम करने के संघर्ष में देशभर की जनता का मार्गदर्शन करते हुए अत्यधिक सहनशीलता का परिचय दिया ।

यद्यपि यह संघर्ष गृहयुद्ध को शुरू होने से रोकने में नाकामयाब रहा, तथापि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, इस समय के दौरान, सारे देश के लोगों को इस बारे में व्यापक तथा गहन शिक्षा प्रदान की । "10 अक्तूबर समझौते" तथा "राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन" के प्रस्तावों के माध्यम से, पार्टी ने अपनी नीतियों का प्रचार किया तथा जनता को इस तथ्य से अवगत करवाया कि पार्टी शान्ति तथा जनवाद के लिए अथक संघर्ष कर रही थी । युद्ध-विराम समझौते को तथा राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों को रद्द करने की क्वोमिंताङ की दुर्भावना का पर्दाफाश करके व मध्यस्थता की आड़ में गृहयुद्ध भड़काने की अमरीकी साजिश का भण्डाफोड़ करके कम्युनिस्ट पार्टी ने सारे देश की जनता को लगातार समझाया कि उसे शांति, क्वोमिंताङ तथा अमरीका सरकार के बारे में पाले हुए भ्रमों को त्याग देना चाहिए तथा उसे महसूस कराया कि शान्ति, जनवाद, स्वाधीनता तथा जीने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों का तख्ता पलटना होगा तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों को अपने देश से बाहर खदेड़ना होगा । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों की विश्वासघाती कार्यवाहियों का चीनी जनता के सामने पर्दाफाश किया गया । शान्ति के लिए जनता की मांग को प्रतिक्रियावादी जितना अधिक ठुकराते गए, उतना ही अधिक वे राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ते गए ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत पहले से ही गृहयुद्ध शुरू करने के लिए क्वोमिंताङ की पीठ थपथपाने की अमरीकी साजिश का पता चल चुका था, इसलिए पार्टी ने विचारधारात्मक तथा संगठनात्मक स्तर पर पर्याप्त रूप से तैयारियाँ कर ली थीं । क्वोमिंताङ की गृहयुद्ध की तैयारी के लिए प्रतिक्रियावादी नीति की पोल खोलने के साथ-साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुक्त क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए तथा अभी तक एक-दूसरे से अलग-अलग पड़े इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए सेना तथा जनता का नेतृत्व किया । पार्टी ने मुक्त क्षेत्रों की जनता को क्वोमिंताङ एजेन्टों के विरुद्ध संघर्ष चलाने, लगान व सूद में कटौती करने, कृषि-सुधारों को आगे बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने तथा मितव्ययता अमल में लाने के लिए आन्दोलन चलाने में नेतृत्व प्रदान किया । ये सभी तथा अन्य कदम उठाने का उद्देश्य यह था कि प्रतिक्रियावादी जब देशव्यापी गृहयुद्ध शुरू करें तो वे पूरी तरह पराजित कर दिये जाएं तथा युद्ध-पिपासु अपने किये का फल भोगें । ●

नोट

1. राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन:- विस्तृत विवरण के लिए देखें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976, के "च्याङ काई-शेक के आक्रमण को चकनाचूर कर डालो" शीर्षक अध्याय का दूसरा नोट, पृष्ठ-141 से 147 तक ।

2. 5 मई के संविधान का मस्विदा:- जनता की आँखों में धूल झोंकने तथा अपना फासीवादी शासन सुदृढ़ करने के लिए क्वोमिंताङ ने सन् 1936 में "राजसत्ता जनता को वापिस लौटाने" का

से आक्रमण की रणनीति पर उतर आने में, बेहद मुख्य भूमिका निभाई । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने **''कृषि-कानून की रूपरेखा''** तैयार की थी, तथा **''वर्गों का विश्लेषण कैसे करें ?''** एवं **''कृषि संघर्षों के दौरान पैदा हुई समस्याओं के समाधान के उपाय''** प्रकाशित किये थे । साथी माओ के **''शानशी-स्वेय्वान मुक्त क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाषण,''** साथी रन पी-श की **''कृषि-सुधारों संबंधी कुछ समस्याएं''** शीर्षक रचनाओं तथा अन्य रचनाओं में पार्टी की कृषि नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था ।

''कृषि-कानून की रूपरेखा'' में यह व्यवस्था की गई थी कि सामन्ती व अर्ध-सामन्ती भूमि-प्रणाली को खत्म कर दिया जाए तथा **''जमीन जोतने वाले को''** के सिद्धान्त को साकार किया जाए ।

कृषि सुधारों में, गरीब किसानों तथा खेत-मजदूरों पर पूर्णतया भरोसा करना तथा उन्हें संगठित करने में उनकी मदद करना बुनियादी महत्त्व का काम था, ताकि वे लोग अन्दोलन की रीढ़ की हड्डी बन सकें । मध्यम किसानों के साथ जुड़ना तथा उन्हें गरीब किसानों व खेत-मजदूरों के साथ एकजुट हो जाने के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी था, ताकि एक ठोस मजदूर-किसान संश्रय स्थापित किया जा सके । किसान समुदाय को गोलबन्द करने का सही तरीका यह था कि उनके अन्दर गहराई तक सैद्धान्तिक तथा शैक्षणिक कार्य चलाया जाए जो उनके खुद के अनुभवों पर आधारित हो; उनसे घुला-मिला जाए तथा गरीब किसानों व खेत मजूदरों के सक्रिय तत्वों के साथ निकटतम संबंध स्थापित करके उनके माध्यम से जनता को आन्दोलित किया जाए; तथा धीरे-धीरे विस्तार करने व तेजी लाने की नीति अपनाते हुए किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाए । मध्यम किसानों के साथ तालमेल कायम करते समय निम्न उसूलों का पालन करना जरूरी था—किसानों का वर्ग निर्धारित करते समय अत्यन्त सावधानी बरतने की जरूरत थी, इस बात का तो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना था कि किसी मध्यम किसान का धनी किसान के रूप में वर्गीकरण न कर दिया जाए । जमीन के समान बंटवारे को लेकर मध्यम किसानों की राय पर ध्यान दिया जाना था तथा यदि वे किसी बात पर एतराज करते तो उन्हें रियायत दी जानी थी । उन्हें गरीब किसानों को आबंटित की गई जमीन से ज्यादा जमीन रखने की इजाजत दी जा सकती थी । मध्यम किसानों के सक्रिय तत्वों को किसान सभाओं तथा स्थानीय सरकारों में शामिल होने तथा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था; तथा भूमि कर लगाते समय तथा युद्ध कार्य व अन्य कार्यभार सौंपते समय ईमानदारी से काम लेना अनिवार्य था ।

जहां तक धनी किसानों की बात थी, उनकी फालतू जमीन तथा सम्पत्ति को जब्त किया जाना था । क्योंकि पुराने किस्म के धनी किसान भी आमतौर पर जबरदस्त सामंती शोषण करते थे तथा जिन हालात में उनके मजदूर काम करते थे, वे भी सामंती थे । उनके कब्जे में औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा तथा अधिक उपजाऊ जमीन थी । इसके अतिरिक्त, उस समय तक क्रान्तिकारी युद्ध के नतीजे अनिश्चित थे, और धनी किसानों की सहानुभूति प्रतिक्रियावादियों के साथ थी, जबकि लोकयुद्ध किसानों से—फौजी सेवा, खाद्य-रसद आपूर्ति तथा स्वैच्छिक काम के रूप में—व्यापक सहयोग की मांग करता था ताकि उसका विजयश्री के साथ समापन किया जा सके ।

जुलाई 1946 से फरवरी 1947 तक, आठ महीने लड़ाई लड़ने के बाद, जिसमें जन-मुक्ति सेना ने दुश्मन को अत्यधिक नुकसान पहुँचाया, शत्रु के चौतरफे आक्रमण को रोक दिया गया।

पहले चार महीनों के दौरान, मध्यवर्ती मैदानी इलाके की जन-मुक्ति सेना ने कामरेड ली श्येन-न्येन की कमान में श्वानह्वाथ्येन के स्थान पर शत्रु की घेराबन्दी तोड़ने में सफलता हासिल की । इसके बाद यह सेना दक्षिणी शेनशी व पश्चिमी हनान तथा सछ्वान व शेनशी के बीच के सीमान्त-क्षेत्र में चली गई तथा इसने पूर्वी हुपे तथा पश्चिमी आनह्वेइ के क्षेत्रों में छापामार लड़ाई जारी रखी । कामरेड वाङ चन की कमान में जन-मुक्ति सेना की एक अन्य टुकड़ी, हुपे, हनान, शेनशी तथा कानसू के चार प्रान्तों से गुजरने के बाद तथा शत्रु की घेराबन्दियों को बार-बार विफल करते हुए, सितंबर में शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र में लौट आई । इस प्रकार जन-मुक्ति सेना की घेराबंदी करके उसे नेस्तनाबूद करने की क्वोमिंतांङ की योजना का दिवाला पिट गया । पूर्वी चीन में मुक्ति सेना की उत्तरी च्याङसू इकाई ने चलायमान रक्षा की अनेक सफल लड़ाइयां लड़ीं; पहले याङत्सी नदी के उत्तर तथा बड़ी नहर (Grand Canal) के पूर्व में स्थित क्षेत्र में, और फिर ह्वाएइन, ह्वाएआन, ल्येनश्वेइ तथा श्वेइनिङ के क्षेत्र में। शानशी-हपे-शानतुङ-हनान मुक्त क्षेत्र की मुक्ति सेना ने, पहले लुङहाए रेलमार्ग के खाएफङ-श्वीचओ सेक्शन पर, तथा फिर दक्षिण-पश्चिमी शानतुङ में तिङथाओ के स्थान पर, शत्रु के विरुद्ध बड़े व्यापक पैमाने पर लड़ाई छेड़ी । थाएय्वे पहाड़ों की टुकड़ियां शानशी-स्वेय्वान मुक्त-क्षेत्र की जन-मुक्ति सेना के साथ, जो कि उत्तरी शानशी में कार्यवाही कर रही थी, घनिष्ठ तालमेल स्थापित करते हुए दक्षिणी शानशी में लड़ीं । शानतुङ प्रान्त में जन-मुक्ति सेना ने छिङताओ-चीनान रेलमार्ग पर शत्रु से लोहा लिया । शानशी-छाहाङ-हपे मुक्त क्षेत्र की सेना ने चाङच्याखओ पर पूर्व तथा पश्चिम, दोनों तरफ से किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर-पूर्वी चीन की जनवादी संश्रयकारी सेना ने दक्षिणी ल्याओनिङ के क्वानथ्येन इलाके में शत्रु फौजों का सफाया कर दिया ।

दूसरे चार महीनों के दौरान, पूर्वी चीन की जन-मुक्ति सेना ने च्याङसू में, श्वीछ्येन की मुहिम में, दक्षिणी शानतुङ में चाओच्वाङ तथा ईश्येन की मुहिमों में व मध्य शानतुङ में लाएऊ की मुहिम में शत्रु के खिलाफ बड़े विस्तृत पैमाने पर सफाया कार्यवाहियां कीं तथा शानतुङ को उत्तर तथा दक्षिण की तरफ से दोतरफे हमले में दबोचने की शत्रु की योजना को मिट्टी में मिला दिया । शानशी-हपे-शानतुङ-हनान मुक्तक्षेत्र की जन-मुक्ति सेना ने उत्तरी हनान, दक्षिण-पश्चिमी शानतुङ, पूर्वी हनान तथा उत्तर-पश्चिमी आनह्वेइ की अनेक लड़ाइयों में शत्रु-सेनाओं का विनाश किया । दक्षिण-पश्चिमी शानशी की मुहिम में शानशी-स्वेय्वान क्षेत्र की जन-मुक्ति सेना तथा शानशी-हपे-शानतुङ-हनान क्षेत्र की जन-मुक्ति सेना की थाएय्वे पर्वतीय यूनिटों ने मिलकर शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त-क्षेत्र के खिलाफ पश्चिम की तरफ बढ़ रही शत्रु सेना के पीली नदी को पार करने के प्रयासों को चकनाचूर कर दिया । शानशी-छाहाङ-हपे क्षेत्र की जन-मुक्ति सेना ने पाओतिङ के दक्षिण में स्थित पेकिङ-हानखओ रेलमार्ग के साथ लगते इलाके पर हमला किया । उत्तर-पूर्वी जनवादी संश्रयकारी सेना की यूनिटों ने उत्तर-पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी मोर्चों पर जन-मुक्ति सेना के साथ तालमेल स्थापित करते हुए लड़ाइयां लड़ीं । उत्तर में स्थित यूनिटों ने सुंगाड़ी क्षेत्र पर तीन बार हमला किया तथा दक्षिण में दूसरी यूनिटों ने लिनच्याङ पर शत्रु के चार हमलों को विफल कर दिया । इस प्रकार

शत्रु की दक्षिण में आक्रमणात्मक तथा उत्तर में रक्षात्मक कार्यवाही करने की योजना विफल कर दी गई, तथा उत्तर-पूर्वी चीन में शत्रु के हमले का अन्त कर दिया गया ।

जन-मुक्ति सेना ने शत्रु से छीने गए शस्त्रास्त्रों से खुद को सज्जित किया तथा युद्धबन्दियों को पुन: शिक्षित करके अपनी मानव-शक्ति की क्षति को पूरा किया । शत्रु ने मुक्त क्षेत्रों के अनेक शहरों तथा इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी । कुछ शहर तथा इलाके सक्रिय रक्षात्मक कार्यवाही करने की पूर्व-नियोजित रणनीतिक योजना के अनुसार स्वेच्छा से खाली कर दिए गए थे, तथा क्वोमिंताङ को उनमें से प्रत्येक की रक्षा करने के लिए सेनाएँ तैनात करनी पड़ीं । फलत: मुक्त क्षेत्रों पर हमला करने में झोंके गए क्वोमिंताङ सैनिकों की तादाद में वृद्धि होने के बावजूद भी, उसकी चलायमान सैन्य-शक्ति बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तथा प्रथम पंक्ति के हमलों के लिए उसकी युद्धक-क्षमता बेहद कमजोर हो गई थी। इस प्रकार युद्ध के चलते जन-मुक्ति सेना अपेक्षाकृत विशाल तथा शक्तिशाली होती चली गई, जबकि क्वोमिंताङ सेना छोटी तथा अपेक्षाकृत कमजोर होती चली गई ।

मार्च 1947 के बाद से, शत्रु को अपने चौतरफा हमले को रोककर उसके स्थान पर केन्द्रीकृत हमले करने की नीति अपनानी पड़ी । जिसके कारण युद्ध कांटे की टक्कर वाली स्थिति में पहुँच गया, जिसमें शत्रु के आंशिक आक्रमण का मुकाबला आंशिक प्रत्याक्रमण से किया गया । शत्रु ने शानतुङ तथा उत्तरी शेनशी को अपना मुख्य निशाना बनाया ।

शत्रु को एक नई रणनीति अपनाने को बाध्य होना पड़ा, वह पूर्व तथा पश्चिम से दो शक्तिशाली कॉलमों में, पीली नदी के दक्षिण तथा पश्चिम के क्षेत्रों में कार्यवाही कर रही जन-मुक्ति सेना के विरुद्ध आगे बढ़ा । योजना यह थी कि पहले जनता की सैन्य-शक्तियों को उनकी मोर्चेबन्दियों से परे धकेल दिया जाए तथा फिर एक-एक करके नष्ट कर दिया जाए । कू चू-थुङ की कमान में 4,50,000 शत्रु सैनिकों ने, जो क्वोमिंताङ की हमलावर सेना का दो तिहाई थे, शानतुङ मुक्त क्षेत्र पर हमला किया, तथा 2,30,000 से ऊपर शत्रु सैनिकों ने (जो स्थानीय जन-मुक्ति सेना की यूनिटों की तुलना में दस गुणा थे) हू चुङ-नान की कमान में उत्तरी शेनशी मुक्त क्षेत्र पर हमला किया । बड़ी भीषण लड़ाई के बाद, आखिरकार जन-मुक्ति सेना शानतुङ तथा उत्तरी शेनशी पर शत्रु के केन्द्रीकृत हमले को ध्वस्त करने में सफल हुई।

शत्रु ने 6 अप्रैल, 1947 को बड़े व्यापक पैमाने पर शानतुङ मुक्त-क्षेत्र पर हमला किया। ईमङ, मङइन तथा लाएमङ की तीन बड़ी मुहिमों में शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्तियों का सफाया कर दिया गया । मङइन की लड़ाई खासतौर से असाधारण थी, क्योंकि उसमें क्वोमिंताङ के हमले की मुख्य दिशा को ध्वस्त कर दिया गया था तथा उसकी सिरफिरी यूनिटों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था । अब युद्ध में पहलकदमी जन-मुक्ति सेना के हाथ में आनी शुरू हो गई थी । इससे पूर्वी चीन के युद्ध-क्षेत्र में शक्ति-संतुलन में बदलाव आया, तथा इस विजय व अन्य युद्ध-क्षेत्रों में अर्जित विजयों के फलस्वरूप जन-मुक्ति सेना के राष्ट्रव्यापी प्रत्याक्रमण हेतु रास्ता तैयार हो गया ।

13 मार्च, 1947 को शत्रु ने बड़े व्यापक पैमाने पर उत्तरी शेनशी पर हमला किया । येनान, वायाओपाओ, य्वीलिन तथा अन्य स्थानों पर लड़ी गई अनेक सिलसिलेवार लड़ाइयों के बाद इस केन्द्रीकृत हमले को ध्वस्त कर दिया गया ।

आक्रमण शुरू किया ।

जूलाई 1947 में, शानशी-हपे-शानतुङ-हनान आधार-क्षेत्र की जन-मुक्ति सेना ने ल्यू पो-छङ तथा तङ श्याओ-फिङ नामक साथियों के नेतृत्व में पीली नदी तथा लुङहाए रेलमार्ग को पार करते हुए दक्षिण की ओर कूच किया, वे ताप्ये पहाड़ों में पहुँचे तथा मध्यवर्ती मैदानी मुक्त क्षेत्र की स्थापना की । इस प्रकार ऊहान तथा नानकिङ के मध्य में स्थित इस मुक्त क्षेत्र के रूप में, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी शासन के सीने में खंजर घोंप दिया गया । अगस्त में शानशी-हपे-शानतुङ-हनान की जन-मुक्ति सेना की एक अन्य यूनिट ने दक्षिणी शानशी के रास्ते पीली नदी पार की, तथा पश्चिमी हनान और हनान व शेनशी के मध्य के सीमान्त-क्षेत्र समेत एक विशाल भूभाग को मुक्त करा लिया, और इस प्रकार उसने पश्चिमी हनान में शत्रु के मुख्य शहर, लोयाङ को अलग-थलग कर दिया तथा तुङक्वान के नजदीक पहुँच गई ।

अगस्त में पूर्वी चीन स्थित जन-मुक्ति सेना ने कामरेड छन ई तथा सू य्वी की कमान में मध्य शानतुङ से इसी प्रान्त के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से पर हमला किया तथा लुङहाए रेलमार्ग को पार करते हुए दक्षिण की तरफ ह्वाए नदी तक आगे बढ़ गई और शत्रु के दो महत्त्वपूर्ण ठिकानों—चङचओ तथा खाएफङ—को अलग-थलग कर दिया । तब से जन-मुक्ति सेना ने बाहरी सैन्य-पंक्ति पर कार्यवाहियां करनी शुरू कर दीं तथा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में याङत्सी नदी, पश्चिम में हान नदी तथा पूर्व में समुद्र तट के साथ लगते विशाल क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आक्रमण शुरू कर दिया ।

इसी दौरान, जन-मुक्ति सेना ने भीतरी सैन्य-पंक्तियों पर भी इसी तरह आक्रमण शुरू कर दिया । उत्तर-पश्चिम में मुक्ति सेना ने येनान तथा शेनशी-कानसू-निङश्या मुक्त क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग को वापिस ले लिया तथा इसे पीली नदी के पूर्व में स्थित मुक्त क्षेत्र से जोड़ दिया। पूर्वी चीन में शानतुङ का अधिकांश भाग मुक्त करा लिया गया तथा उसे हपे-शानतुङ-हनान मुक्त क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया । इसके इलावा पूर्वी चीन मुक्ति सेना ने पूर्वी आनह्वेइ में मुक्त क्षेत्र की पुन: स्थापना की तथा उसे मध्यवर्ती मैदान मुक्त क्षेत्र के साथ जोड़ दिया । उत्तर पूर्व में एक वर्ष की लड़ाई के बाद, जन-मुक्ति सेना ने उत्तर-पूर्व की 99 प्रतिशत धरती को मुक्त करा लिया, तथा शत्रु के पास उसके चन्द महत्त्वपूर्ण ठिकाने भर रह गए थे । उत्तरी चीन के मुक्त क्षेत्र में, मात्र थाएय्वान को छोड़कर, शत्रु के सभी महत्त्वपूर्ण स्थलों पर कब्जा कर लिया गया था । इस प्रकार शानशी-छाहाङ-हपे मुक्त क्षेत्र को शानशी-हपे-शानतुङ-हनान मुक्त क्षेत्र के साथ मिलाना तथा फिर उन्हें शानतुङ व शानशी-स्वेय्वान मुक्त क्षेत्रों के साथ जोड़ना संभव हो पाया ।

भीतरी तथा बाहरी सैन्य-पंक्तियों पर किये गए इन व्यापक स्तर के आक्रमणों में क्वोमिंताङ फौजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया । युद्ध के पहले वर्ष में शत्रु को चौतरफे हमले की नीति को त्याग कर केन्द्रित हमले की नीति अपनाने को विवश होना पड़ा, तथा दूसरे वर्ष में चौतरफी रक्षात्मक नीति को त्याग कर केन्द्रित रक्षा की नीति अपनाने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद की छत्रछाया में शुरू किये गए फौजी हमले की करारी मात हुई ।

सभी मुक्त क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर किये गए कृषि-सुधारों ने, क्वोमिंताङ के हमले का सफलतापूर्वक मुँहतोड़ जवाब देने में तथा जन-मुक्ति सेना द्वारा शीघ्र ही रक्षा

1947 से 1950 के दौरान जन-मुक्ति सेना के मोर्चे का मानचित्र

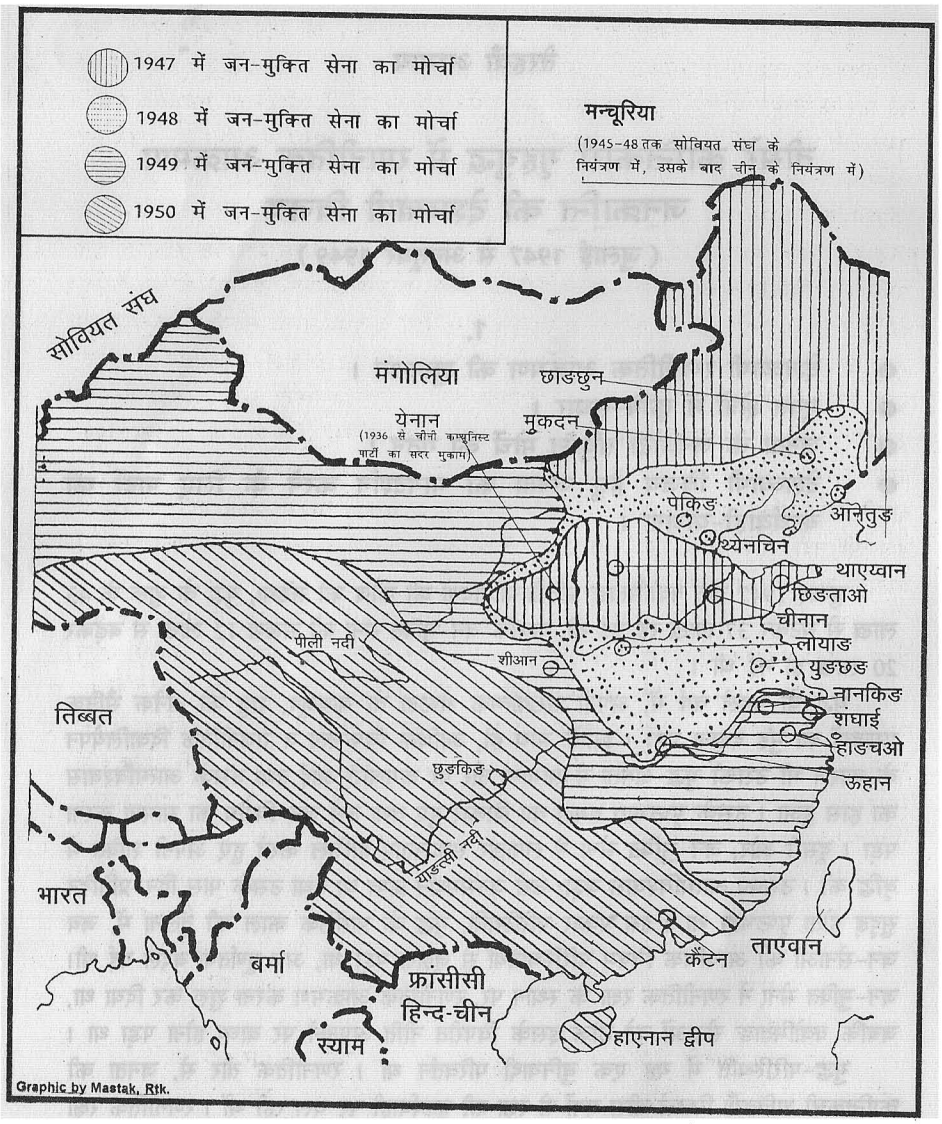

का मुक्त क्षेत्रों को नष्ट करने का षड्यन्त्र विफल हो गया, मुक्त क्षेत्रों को विशाल पैमाने पर आपस में जोड़ दिया गया तथा उन्हें अपेक्षाकृत स्थिरता प्रदान की गई । साथ ही, इससे क्रान्तिकारी युद्ध शत्रु-इलाके के अन्दर, खूब गहरे तक फैल गया, जिससे क्रान्ति के प्रभाव एवम् दायरे का विस्तार हुआ व उसकी देशव्यापी विजय की नींव रखी गयी ।

जन-मुक्ति सेना ने पीली नदी पार करके दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए अपना देशव्यापी

इसी दौरान जन-मुक्ति सेना ने उत्तर-पूर्वी चीन, शानशी-छाहाङ्-हपे क्षेत्र तथा शानशी-हपे शानतुङ-हनान क्षेत्र में शत्रु के खिलाफ, जो अब रक्षात्मक कार्यवाही पर उतर आया था, प्रत्याक्रमण शुरू किया । इससे विभिन्न युद्ध-क्षेत्रों में युद्ध की परिस्थिति में बुनियादी परिवर्तन आया ।

1947 की ग्रीष्म ऋतु में, उत्तर-पूर्वी जनवादी संश्रयकारी सेना ने उत्तरपूर्व, जेहोल तथा पूर्वी हपे में विभिन्न युद्ध-मोर्चों पर शत्रु पर आक्रमण किया तथा शत्रु को चीनी छाङछुन रेलमार्ग तथा पेकिङ-शनयाङ रेलमार्ग के आसपास दो तंग गलियारों में धकेल दिया तथा उसे केन्द्रीकृत रक्षात्मक कार्यवाही अपनाने पर मजबूर कर दिया ।

शानशी-छाहाङ्-हपे क्षेत्र की जनमुक्ति सेना ने शच्याच्वाङ के बाहरी क्षेत्र में, थ्येनचिन-फूखओ रेलमार्ग के उत्तरी सेक्शन के आसपास के इलाके तथा पाओतिङ के उत्तर में स्थित इलाके में अपनी आक्रमणात्मक कार्यवाहियां जारी रखीं ।

इस एक साल के दौरान, जन-मुक्ति सेना ने कुल मिलाकर 11,20,000 नियमित तथा अनियमित शत्रु सैनिकों का सफाया कर दिया, जबकि उसकी अपनी नियमित सेना की संख्या 12 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई । इस प्रकार शत्रु के रणनीतिक आक्रमण को पूर्णतया धराशायी कर दिया गया ।

क्वोमिंतांङ सेनाओं को हरेक युद्ध क्षेत्र में मात खानी पड़ी । प्रतिक्रियावादी अब 1946 के **चौतरफा हमला** करते समय जैसे अथवा मार्च 1947 में केन्द्रीकृत हमला करते समय जैसे **दम्भी नहीं रह** गए थे । उन्होंने जनमुक्ति सेना की ताकत तथा कार्यनीति का गलत आकलन किया था तथा मुक्ति सेना के रणनीतिक रूप से पीछे हटने की कार्यवाही को कायरता तथा कुछ शहरों व इलाकों के अस्थायी परित्याग को उसकी वास्तविक असफलताएँ समझने की भूल की थी । उनकी पूर्ण पराजय इस एकदम गलत अनुमान का स्वाभाविक परिणाम थी ।

अत्यधिक सैनिकों की क्षति के कारण क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादियों के पास रणनीतिक आक्रमण से रणनीतिक रक्षा पर उतर आने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा ।

तब से सारे देश में युद्ध की परिस्थिति शत्रु के आंशिक आक्रमण तथा जन-मुक्ति सेना के आंशिक प्रत्याक्रमण से बदलकर, शत्रु के पूर्णतया रक्षात्मक कार्यवाही पर उतर आने तथा जन-मुक्ति सेना के पूर्णतया आक्रमणात्मक कार्यवाही पर उतर आने की मंजिल तक पहुँच गई। दूसरे शब्दों में, जन-मुक्ति सेना अब हमलावर क्वोमिंतांङ सेनाओं को दृढ़ता से तथा पूर्णतया नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार थी । ●

3.

- **क्वोमिंतांङ अधिकृत क्षेत्रों का और ज्यादा औपनिवेशीकरण ।**
- **क्वोमिंतांङ की राजनीतिक धोखाधड़ी का दिवालियापन ।**

क्वोमिंतांङ पर आए फौजी संकट के साथ-साथ, क्वोमिंतांङ अधिकृत क्षेत्रों में आर्थिक संकट भी छा गया । और यह उसके अधिकार वाले क्षेत्रों के औपनिवेशीकरण तथा कम्युनिस्ट-विरोधी युद्ध के कारण था ।

जापान के आत्मसमर्पण के बाद क्वोमिंतांङ ने अमरीका से बहुत बड़ी मात्रा में फालतू

सामान, राहत सामग्री तथा फौजी साजोसामान उधार के रूप में प्राप्त किया तथा इसके साथ ही जापानियों व उनकी कठपुतलियों से भी काफी मात्रा में युद्ध-सामग्री उसके हाथ लगी । वित्तीय दृष्टि से तो यह क्वोमिंताङ सरकार का "स्वर्ण युग" था ।

जापान के आत्मसमर्पण के समय से लेकर, जुलाई 1947 तक अमरीका ने क्वोमिंताङ को 400 करोड़ अमरीकी डालर से भी अधिक का साजोसामान सप्लाई किया ।

क्वोमिंताङ सरकार ने जापानियों तथा उनकी कठपुतलियों से विभिन्न वित्तीय संस्थान, सारे के सारे सोने, चाँदी व नकदी समेत अपने कब्जे में ले लिये । यह सम्पदा बर्बर ताकत तथा नृशंस आर्थिक लूट के जरिये चीनी जनता से लूटी गई थी । इसके अतिरिक्त क्वोमिंताङ सरकार ने वे सभी साजोसामान, व्यापारिक कम्पनियाँ तथा वाणिज्यिक संस्थान भी अपने हाथ में ले लिए, जिन्हें जापानी सेना ने चीनी जनता से जबरन छीना था । इसके साथ ही बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान भी क्वोमिंताङ ने अपने कब्जे में ले लिये, जिन्हें जापानियों ने काफी लंबे समय के दौरान जबरी श्रम तथा जबरी कब्जे के द्वारा चीन में स्थापित किया था । शत्रु तथा कठपुतलियों की इन परिसम्पतियों का कुल मूल्य अमरीकी सरकार के अनुमान से लगभग 180 करोड़ डालर था। इस *"अधिकार में लेने"* के फलस्वरूप सन् 1947 में नौकरशाह-पूँजीपति उद्यमों का उत्पादन, देश के कुल उत्पादन की तुलना में इस प्रकार था : कोयला-38.8 प्रतिशत; विद्युत उर्जा-83.3 प्रतिशत; इस्पात-90 प्रतिशत; सूती तकले-37.6 प्रतिशत; करघे-60.1 प्रतिशत; तेल, लोहा तथा अलौह धातुएँ-100 प्रतिशत । संक्षेप में समस्त देश की कुल औद्योगिक पूँजी का 70 से 80 प्रतिशत "चार बड़े घरानों" के कब्जे में था । इसके अतिरिक्त, क्वोमिंताङ ने उन सभी कृषि-संस्थानों, उनके साथ लगती जमीन व उनकी परिसंपत्तियों पर भी अधिकार कर लिया, जिन्हें जापानियों द्वारा चीनी जनता से छीना गया था । इस प्रकार यह सारी की सारी संपदा, जिसे चीनी जनता ने अपना खून-पसीना बहाकर निर्मित किया था, जापानियों के हाथों से "चार बड़े घरानों" के हाथों में चली गई

चीनी नौकरशाह पूँजी के अमरीकी एकाधिकारवादी पूँजी के साथ गठजोड़ ने क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का और अधिक औपनिवेशीकरण कर दिया, तथा यह उसके आसन्न विनाश की पूर्वसूचना थी ।

अमरीकी साम्राज्यवादियों की मूलभूत नीति चीन को अमरीकी उपनिवेश में बदलने तथा उसे सोवियत संघ के विरुद्ध एक अमरीकी अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की थी । इसी साम्राज्यवादी उद्देश्य के मद्देनजर अमरीकी सरकार ने, गृहयुद्ध जारी रखने में क्वोमिंताङ की मदद की, जबकि क्वोमिंताङ ने इस सहायता के बदले में राष्ट्रीय सम्प्रभुता का सौदा किया ।

जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध की समाप्ति के बाद क्वोमिंताङ सरकार ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक देशद्रोहपूर्ण संधियाँ तथा समझौते संपन्न किये, जिनमें से 4 नवंबर, 1948 को संपन्न हुई—**"चीन-अमरीका मैत्री, वाणिज्य व जहाजरानी सन्धि"** सर्वाधिक कुख्यात संधि थी । इस संधि द्वारा अमरीकियों को चीन की समूची धरती पर रहने-बसने, घूमने-फिरने, वाणिज्य-व्यापार करने तथा सभी प्रकार के व्यवसायों के प्रबन्धन के विशेषाधिकार प्रदान किए गए । इस प्रकार अमरीका को चीन की अर्थव्यवस्था में अबाध विशेषाधिकार प्राप्त हो गए ।

जापान के आत्मसमर्पण के बाद, अमरीकी निगमों द्वारा या अमरीकी पूँजीपतियों तथा

तेरहवाँ अध्याय

तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध में रणनीतिक आक्रमण जनक्रान्ति की देशव्यापी विजय

(जुलाई 1947 से अक्तूबर 1949)

1.

- **देशव्यापी रणनीतिक आक्रमण की शुरुआत ।**
- **मुक्त क्षेत्रों में कृषि-सुधार ।**
- **जनता के जनवादी संयुक्त मोर्चे का गठन ।**
- **देशव्यापी विजय हेतु जनता का मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी की कार्यवाही-योजना ।**

जुलाई 1947 तक क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की फौज की संख्या, युद्ध के शुरू के 43 लाख से घटकर 37 लाख रह गई थी, जबकि जन-मुक्ति सेना की संख्या 12 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई थी ।

युद्ध के पहले वर्ष में, अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद, शत्रु को अनेक सैनिक पराजयों का मुंह देखना पड़ा । इसके साथ ही, आर्थिक विफलता व राजनीतिक दिवालियेपन के कारण भी उसकी युद्ध-क्षमता में सामान्य तौर पर कमजोरी आई तथा उसके आत्मविश्वास का ह्रास हुआ । उसके पृष्ठभाग हमले का शिकार हुए तथा उसे जन-विरोध का सामना करना पड़ा । दूसरी ओर, जन-मुक्ति सेना ने लगातार सफलताएं हासिल करते हुए अपनी शक्ति में वृद्धि की । उसका आत्मविश्वास बढ़ा; उसे जनसमर्थन प्राप्त था तथा उसके पास दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ होता पृष्ठभाग था । इस प्रकार परिस्थिति, युद्ध के प्रारंभिक काल की तुलना में, जब जन-सेनाओं को अत्यधिक विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ा था, अब पूर्णतया बदल गई थी। जन-मुक्ति सेना ने रणनीतिक रक्षा के स्थान पर, रणनीतिक आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जबकि क्वोमिंताङ सेनाओं को ठीक इसके विपरीत नीति अपनाने पर बाध्य होना पड़ा था ।

युद्ध-परिस्थिति में यह एक बुनियादी परिवर्तन था । रणनीतिक तौर से, जनता की क्रान्तिकारी शक्तियाँ पिछले बीस वर्षों से रक्षा की कार्यवाही पर चल रही थीं । रणनीतिक रक्षा की नीति के स्थान पर रणनीतिक आक्रमण की नीति का अपनाया जाना प्रतिक्रियावादी शासन के आसन्न पतन का पूर्वाभास था ।

जन-मुक्ति सेना ने बाहरी सैन्य-पंक्तियों पर कार्यवाहियां करने की नीति पर अमल किया। उसने व्यापक पैमाने पर हमला शुरू किया तथा क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में अन्दर तक घुसपैठ कर गई व इस प्रकार युद्ध को याङत्सी नदी के इलाकों तक ले आई । इस नीति से क्वोमिंताङ

कालावधि में उनके फौजी हमलों की भाँति उनकी राजनीतिक धोखाधड़ी को भी पूर्ण विफलता का मुँह देखना पड़ा ।

●

नोट

1. चीन-अमरीका मैत्री, वाणिज्य व जहाजरानी संधि :- इस संधि के विस्तृत विवरण के लिए पढ़ें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976, के **'चीनी क्रान्ति के नए ऊंचे उभार का स्वागत'** शीर्षक अध्याय का पाँचवां नोट, पृष्ठ-200-201

2. अप्रैल-मई 1949 तक गिरते-गिरते ''स्वर्ण-य्वान'' की कीमत एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 30 लाख से एक करोड़ स्वर्ण य्वान के बीच रह गई थी ।

●●●

चीनी नौकरशाह-पूँजीपतियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जाने वाले संस्थानों अथवा ''चार बड़े घरानों'' द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा चीन में अमरीकी जिन्सों का अम्बार लगाकर, उसे अमरीकी एकाधिकार वाले बाजार में बदल दिया गया । 1946 में चीन के कुल आयात का (तस्करी द्वारा लाये गये सामान को छोड़कर) 51.2 प्रतिशत अमरीकी जिन्सें थीं, जबकि 1936 में उनका हिस्सा केवल 22.6 प्रतिशत था । 1946 में चीन के कुल निर्यात का 57.2 प्रतिशत अमरीका ने हजम कर लिया जबकि 1937 में यह केवल 19.7 प्रतिशत था ।

''चार बड़े घरानों'' ने जापानियों तथा कठपुतलियों से हथियाये गए उद्योगों को अमरीकी एकाधिकारवादी पूँजी के हवाले कर दिया । इन उद्यमों की सारी की सारी पूँजी, तकनीक, प्रबन्धन तथा कर्मियों का प्रशिक्षण, सब कुछ अमरीकी नियन्त्रण के तहत कर दिया गया । इसके अलावा अमरीका ने चीन में फैक्ट्रियाँ स्थापित कीं, तथा उसके लिए क्वोमिंताङ सरकार द्वारा लागू ''संशोधित कम्पनी कानून'' के तहत अमरीकी पूँजी को सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गईं । अमरीकी पूँजी तथा चीनी नौकरशाह-पूँजी ने करों की चोरी करने, सत्ता तथा कच्चे माल पर एकाधिकार करने तथा बाजार व परिवहन सुविधाओं पर नियन्त्रण करने के लिए क्वोमिंताङ की सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया, तथा इस प्रकार चीन के राष्ट्रीय उद्योग तथा वाणिज्य का पूरी तरह गला घोंट दिया ।

क्वोमिंताङ द्वारा कब्जाई गई धन-संपदा शीघ्र ही गृहयुद्ध की भेंट चढ़ गई, लेकिन गृहयुद्ध की आग भड़कती ही चली गयी तथा उसके बुझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे । युद्ध जारी रखने के लिए क्वोमिंताङ सरकार ने जनता को अनाज देने, कर देने तथा सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए बाध्य करके; अन्धाधुन्ध तरीके से कागजी-मुद्रा जारी करके तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेहिसाब वृद्धि करके अत्यन्त नृशंसतापूर्वक जनता को लूटा। फलतः क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों में अभूतपूर्व आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया । चूंकि कागजी मुद्रा छापेखानों से धड़ाधड़ बाहर आ रही थी, अतः चावल तथा अन्य उपभोक्ता जिन्सों की कीमतें डोर कटी पतंग की भाँति आसमान छूने लगीं । **युद्धपूर्व स्तर की तुलना में, जापान के आत्मसमर्पण की पूर्व-संध्या पर कीमतें 1800 गुना बढ़ गई थीं तथा अप्रैल 1947 तक 60,000 गुना ।** जापान-विरोधी युद्ध की पूर्व-संध्या पर क्वोमिंताङ सरकार द्वारा जारी ''राष्ट्रीय मुद्रा'' की राशि 1.4 अरब चीनी डॉलर थी, जापान के आत्मसमर्पण के समय यह 500 अरब चीनी डॉलर तथा अप्रैल 1947 में यह राशि 16000 अरब चीनी डालर से भी अधिक तक पहुँच गई थी ।

1948 तक, शंघाई में कीमतें युद्धपूर्व काल के मुकाबले 30 लाख गुना बढ़ गई थीं । आसमान छूती कीमतों के चलते, लेन-देन के माध्यम के रूप में ''राष्ट्रीय मुद्रा'' की साख पूर्णतया समाप्त हो गई थी । फलतः व्यापारिक लेन-देन, कागजी-मुद्रा से भरी टोकरियों के माध्यम से होने लगा । 19 अगस्त, 1948 को क्वोमिंताङ सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत **''स्वर्ण-य्वान''** ने ''राष्ट्रीय मुद्रा'' का स्थान ले लिया तथा विनिमय दर, 30 लाख चीनी डॉलर या 0.25 अमरीकी डॉलर के बदले एक ''स्वर्ण य्वान'' तय की गई तथा घोषणा की गई कि कुल मिलाकर केवल 50 करोड़ ''स्वर्ण-य्वान'' की नयी मुद्रा जारी की जाएगी । तथापि नई मुद्रा के चलन में आने के पहले दिन से ही, युद्ध घाटा पूरा करने के लिए इसे बेहिसाब मात्रा में जारी किया गया तथा जनता के पास जितने भी अमरीकी

डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राएँ थीं, उन्हें उनके बदले में "स्वर्ण-ख्वान" लेने के लिए बाध्य किया गया। गंभीर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, तथा उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए हाय-तौबा मच गई । 1 अक्तूबर, 1948 तक जारी किए गए "स्वर्ण ख्वानों" की मात्रा इनकी निर्धारित मात्रा से छः गुणा अधिक हो गई थी । इसके बेहिसाब मात्रा में जारी किये जाने तथा मूल्य नियंत्रण में असफलता के कारण **"स्वर्ण-ख्वान" को भी इसकी पूर्ववर्ती मुद्रा की भाँति रद्द घोषित कर दिया गया ।**[2]

गृहयुद्ध शुरू करने के बाद, क्वोमिंतांङ ने राष्ट्रीय उद्योग तथा वाणिज्य का दमन तेज कर दिया । **जापान-विरोधी युद्ध से पहले शंघाई में 5,400 फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन 1947 में इनमें से केवल 582 कार्यरत थीं । 1949 के आरंभ तक, 80 प्रतिशत से अधिक मशीन फैक्ट्रियों ने उत्पादन करना बन्द कर दिया था । 1947 में, थ्येनचिन की लगभग 70 प्रतिशत तथा छिङतांओ की 50 प्रतिशत फैक्ट्रियों ने काम करना बन्द कर दिया था ।**

इस दौर में, क्वोमिंतांङ की राजनीतिक धोखाधड़ी का भी दिवाला पिट गया ।

मार्च 1946 में, क्वोमिंतांङ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी के पूर्ण अधिवेशन में, च्याङ काई-शेक ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों को रद्द करने हेतु योजनाएं घड़ने के लिए अपने प्रतिक्रियावादी पिछलग्गुओं को इकट्ठा किया । षड्यन्त्र यह रचा गया कि एक बोगस संविधान तैयार करने के लिए "राष्ट्रीय असेम्बली" बुलाई जाए ताकि जनता की आँखों में धूल झोंकी जा सके । 11 अक्तूबर, 1946 को जनमुक्ति सेना ने अपनी रणनीतिक योजना के तहत चाङच्याखओ को खाली कर दिया । च्याङ काई-शेक इस "जीत" से पगला गया तथा उसी दिन उसने "राष्ट्रीय असेम्बली" बुलाने का आदेश जारी कर दिया ।

क्वोमिंतांङ द्वारा एकतरफा तौर पर बुलाई गई तथाकथित "राष्ट्रीय असेम्बली" का अधिवेशन 15 नवम्बर से 25 दिसम्बर, 1946 तक चला । राजनीतिक सलाह-मशविरे के सिद्धान्त का यह सरासर उल्लंघन था ।

असेम्बली ने एक क्वोमिंतांङ संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी । जनरोष को शान्त करने के लिए, च्याङ काई-शेक ने अपने पिछलग्गुओं को समझाया कि वे अपने द्वारा तैयार किये गये पूर्णतया फासीवादी तथा तानाशाही पूर्ण "5 मई के संविधान के मस्विदे" को पारित न करें, बल्कि छद्म रूप से एक फासीवादी संविधान—"चीन गणराज्य का संविधान"—को पारित कर दें । तथापि, जनता की सत्ता, केन्द्रीय सरकार व स्थानीय सरकारों के बीच के सम्बन्धों तथा विधानपालिका व कार्यपालिका के बीच के सम्बन्धों के विषय में अपने प्रावधानों को लेकर बोगस संविधान भी पूर्णरुपेण तानाशाहीपूर्ण निकला । राजसत्ता जनता में निहित न होकर, सरकार में; स्थानीय सरकारों के पास न होकर, केन्द्रीय सरकार के पास; तथा विधानपालिका में न होकर कार्यपालिका में निहित होनी थी । बोगस संविधान में जनता के "अधिकारों" की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन साथ ही यह एहतियात भी बरती गई थी कि आपातकाल की स्थिति में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अधिकारों पर कानूनी पाबन्दी लगाई जा सके । अतः जनता के अधिकारों का सुविवेचित प्रावधान, वास्तव में एक कागजी कानून से अधिक कुछ भी न था; यह एक ऐसा साबुन का बुलबुला था, जिसे प्रतिक्रियावादी सरकार जब चाहे किसी भी ऐरे-गैरे सरकारी कानून से नष्ट कर सकती थी । बोगस संविधान में यह व्यवस्था भी की गई थी कि राष्ट्रपति हर 6 वर्ष बाद चुना जाना था,

आर्थिक कारोबारों तथा सरकारी संस्थानों के सभी महत्त्वपूर्ण पदों से बाहर कर दिया गया। वहां की जनता ने यह महसूस करते हुए कि एक अत्याचारी के स्थान पर दूसरा अत्याचारी आ गया था, स्वायत्तता तथा अपने प्रान्त के आर्थिक मामलों के प्रबन्धन के अधिकारों की माँग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी मांग की, कि क्वोमिंतांङ अनिवार्य जिन्सों की बिक्री के लिए एकाधिकारवादी प्रणाली को समाप्त करे तथा ताएवान में स्थानीय लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों के पद दिए जाएँ, वगैरा-वगैरा । उनकी माँगें उचित तथा न्यायसंगत थीं । 28 फरवरी, 1947 को वहां पर स्वायत्तता के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके तहत एक अन्तरिम स्वायत्त शासन-व्यवस्था की स्थापना की गई, तथा ताएवान की राजनीतिक प्रणाली के सुधार के लिए एक कार्यक्रम स्वीकार किया गया ।

मुख्य भूमि पर, क्वोमिंतांङ ने सभी देशभक्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलनों को कुचलने के लिए आतंकवादी हथकंडे इस्तेमाल किए । 18 मई, 1947 को क्वोमिंतांङ सरकार ने *"सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थाई उपाय"* नामक एक आदेश जारी किया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि विद्यार्थियों, मजदूरों तथा व्यापारियों की सभी हड़तालों, जलूसों तथा प्रदर्शनों (जिनमें दस से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे) से निपटने के लिए तथा उन सभी याचिकाओं से निपटने के लिए जो संबंधित अधिकारियों की अवहेलना करते हुए उच्चतर अधिकारियों को पेश की जाएंगी, *"आपातकालीन उपाय किये जाएंगे तथा कारगर कदम उठाए जाएंगे ।"*

क्वोमिंतांङ के सैनिकों, पुलिस, फौजी पुलिस व खुफिया एजेन्टों की विद्यार्थियों एवम् नागरिकों के साथ सभी स्थानों पर झड़पें शुरू हो गईं । निहत्थे विद्यार्थियों तथा नागरिकों से निपटने के लिए क्वोमिंतांङ सरकार गिरफ्तारियों, मार-पिटाई, जेलों में ठूंसने तथा कत्लेआम जैसे सभी प्रकार के नृशंस हथकंडों पर उतर आई । तथापि, दमन निष्फल सिद्ध हुआ और क्वोमिंतांङ अधिकृत-क्षेत्रों में विद्यार्थियों का देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, जन-संघर्षों का हरावल दस्ता बन गया तथा उसने प्रत्येक देशवासी की सहानुभूति तथा समर्थन जीत लिया ।

क्वोमिंतांङ ने सभी प्रान्तों में भड़क उठे किसान विद्रोहों को कुचलने की खातिर व्यापक पैमाने पर "दण्ड" अभियान चलाए लेकिन ये सब बेकार सिद्ध हुए । बल्कि कई स्थानों पर तो क्वोमिंतांङ की सुरक्षा कोर और यहां तक कि उसकी नियमित सेना ने भी विद्रोह कर दिया। फलतः हर अभियान के साथ, किसानों की सशस्त्र सेनाएं ज्यादा ताकतवर तथा विशाल होती चली गईं ।

ताएवान के स्वायत्तता आन्दोलन के खिलाफ क्वोमिंतांङ ने फौजी-आतंकवाद की नीति अपनाई । वहां पर 10,000 से अधिक लोगों को कत्ल कर दिया गया । यद्यपि आन्दोलन को कुचल दिया गया, पर क्वोमिंतांङ प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध ताएवान की जनता का वैरभाव और ज्यादा गहरा तथा तीव्र हो गया । जन-विरोधी प्रतिक्रियावादियों ने स्वयं को समूची जनता से घिरा पाया । राजनीतिक तथा फौजी, दोनों ही मोर्चों पर हालात उनके प्रतिकूल हो गए थे। उन्हें गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा था ।

अपना शासन कायम रखने के लिए, फौजी दमन तथा राजनीतिक धोखाधड़ी ही प्रतिक्रियावादियों के दो मुख्य हथकण्डे रहे थे । तथापि जुलाई 1946 से जून 1947 की

कर लिया था । शंघाई में हुई हड़तालों का आकार, सन् 1925 के 30 मई, काण्ड के वक्त हुई हड़तालों से भी ज्यादा विशाल था । छुङकिङ, थ्येनचिन, ताङशान तथा छिनवाङथाओ मे भी मजदूरों द्वारा इसी प्रकार की हड़तालें आयोजित की गईं ।

इसी प्रकार किसानों को भी व्यापक स्तर पर संगठित किया गया । क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में लगान, करों तथा विभिन्न लेवियों की अदायगी के विरुद्ध संघर्ष तथा जोर-जबरदस्ती (बेगार), देशद्रोहियों व स्थानीय निरंकुश तत्वों के विरुद्ध संघर्ष काफी बड़े पैमाने पर फैल गए । साथ ही चावल के लिए दंगे-फसाद भी बुरी तरह फैल गए । च्याङसू, चच्याङ, दक्षिणी आनह्वेइ तथा हुनान के विस्तृत इलाकों के दसियों लाख किसानों ने हथियार उठा लिये तथा क्वोमिंताङ फौजों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया । सछ्वान की 130 से भी अधिक काउंटियों में से हर एक में, एक या दूसरे समय किसान विद्रोह हुए । शीखाङ में किसान सेना की संख्या पाँच लाख तक पहुँच गई । मेहनतकशों, हस्तशिल्पकारों, शहर के कंगालों तथा भगौड़े सैनिकों ने भी इन संघर्षों में हिस्सा लिया ।

इस कालखण्ड के दौरान ताएवान की जनता के संघर्षों का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। ताएवान, चीन के समृद्धशाली प्रान्तों में से एक है । पिछले पचास वर्षों से ताएवान की जनता जापानी हमलावरों के कब्जे में थी तथा मुक्ति के लिए लालायित थी । जापान के आत्मसमर्पण के बाद, क्वोमिंताङ ने ताएवान में जापानी स्वामित्व वाले सभी उद्यमों तथा परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया तथा मनमाने तरीके से जनता को लूटा । क्वोमिंताङ ने ताएवान को अपना उपनिवेश तथा ताएवानी जनता को अपना गुलाम समझा । वहां के स्थानीय लोगों को

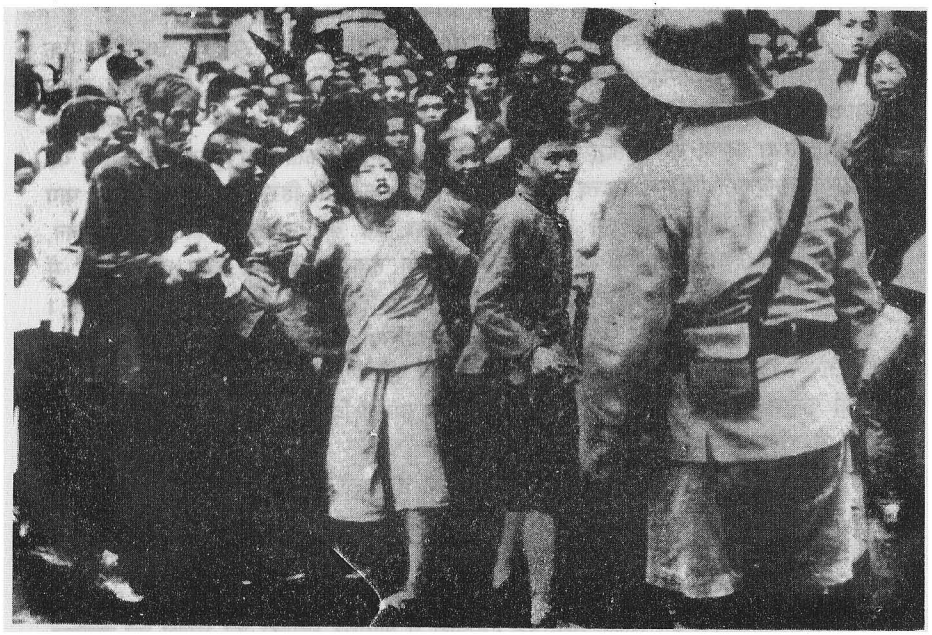

अकाल पड़ने के कारण हुए दंगों का एक दृश्य

तथा यदि उसे दोबारा चुन लिया जाए तो वह अपने पद पर लगातार बना रह सकता था, तथा सारे देश की थल, जल व वायु सेना की कमान उसके हाथ में होगी, तथा उसे आपातकालीन आदेश जारी करने का तथा विधानपालिका द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का (रद्द करने का) अधिकार होगा । इस प्रकार क्वोमिंताङ तानाशाह ने समस्त राजसत्ता पर काबिज हो जाना था, जबकि जनता के पास लेशमात्र अधिकार भी नहीं होने थे । इसके अतिरिक्त, और बातों के साथ-साथ बोगस संविधान ने क्षेत्रीय स्वायत्तता के सिद्धान्त को भी रद्द कर दिया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के स्वायत्तता के अधिकार तथा विधानपालिका के अनुसमर्थन (ratification) व वीटो के अधिकारों को भी रद्द कर दिया था ।

अतः इस संविधान के विषय में क्वोमिंताङ के *'राजनीति विज्ञान ग्रुप'* का मुखपत्र—*ता कुङ पाओ'* भी यह माने बिना नहीं रह सका कि *''यह संविधान सारी शक्तियां एक व्यक्ति में तथा सभी विचार एक दिमाग में केन्द्रित कर देता है ।''*

मुक्ति से पहले के 40 वर्षों के दौरान, एक के बाद एक किसी भी प्रतिक्रियावादी सरकार ने असल में संविधान की जरूरत नहीं समझी थी, परन्तु इनमें से प्रत्येक जब मरणासन्न अवस्था में होती थी, तो अपने आप को एक बोगस संविधान के माध्यम से बचाने का प्रयास करती थी । प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार भी कोई अपवाद न थी । क्रान्तिकारी शक्तियों के आक्रमणों से लड़खड़ाते हुए उसने क्रान्ति का प्रतिरोध करने व जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए एक बोगस संविधान तैयार किया । क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने इस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए कि उनका प्रतिक्रियावादी शासन जड़ तक गल-सड़ चुका था, एक बोगस संविधान का सहारा लिया । लेकिन यह भी निःसन्देह उनकी इच्छा भर ही रह गई; बोगस संविधान तीन साल तक भी प्रकाशित नहीं किया जा सका तथा इससे पहले ही उसे, उसके प्रणेताओं—क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों—सहित दफन कर दिया गया ।

18 अप्रैल, 1947 को क्वोमिंताङ ने अपनी सरकार के ''पुनर्गठन'' की घोषणा की ।

पुनर्गठन के बाद, च्याङ काई-शेक ने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ दावा किया कि नई सरकार *''उदार''* तथा *''बहुदलीय''* थी तथा उसने इसे *''राजनीतिक अभिभावकत्व से संविधानवाद में संक्रमण''* का नाम दिया । इस तमाशे के मुख्य अभिनेता छाङ छुन, चङ ची, छाङ छुन-माए तथा वाङ युन-ऊ थे । छाङ छुन नौकरशाह-दलाल-पूँजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीति विज्ञान ग्रुप का मुखिया था तथा जापान-परस्त गुट का पुराना सदस्य था । चङ ची एक परजीवी था, जो गद्दार वाङ चिङ-वेइ के सिर पर कूदता था । छाङ छुन-माए उत्तरी गुट के शाही अफसरों का अवशेष था तथा साथ ही वह एक अत्यन्त प्रतिक्रियावादी एवम् दुर्बोध सौदेबाज (metaphysics-monger) था । वाङ युन-ऊ एक ऐसा राजनीतिज्ञ था जिसके कोई उसूल न थे । ये पक्के देशद्रोही, सामंती अवशेष तथा निर्लज्ज राजनीतिज्ञ प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन के समर्थक थे; राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों व युद्ध-विराम आदेशों को निरस्त करने में सहभागी थे, तथा अमरीकी शासकों के चहेते थे । अचानक इनका काया पलट हो गया था और ये *''उदार''* तथा *''युगपुरुष''* बन गए थे । जिस *''बहुदलीय''* सरकार की च्याङ काई-शेक शेखी बघारता था, उसमें क्वोमिंताङ के अलावा, दो अन्य *''पार्टियां''*—नौजवान पार्टी तथा जनवादी समाजवादी पार्टी—शामिल थीं, जिनका जन्म चीनी जनवादी लीग में दरार पड़ने से हुआ था । ये पार्टियां अपनी आत्मा बेचने

के लिए तैयार बैठी थीं । क्वोमिंताङ सरकार की डोर अमरीकी साम्राज्यवादियों के हाथ में थी । क्वोमिंताङ युद्ध-सरकार, पार्टी-दादा तथा धन्ना-सेठ, क्वोमिंताङ सरकार की धुरी थे, जबकि नौजवान पार्टी व जनवादी पार्टी तो सिर्फ भाड़े के राजनीतिज्ञ थे, जिनके माध्यम से च्याङ अपने ऊपर लगे तानाशाही के कलंक को धोने की कोशिश करता था । "पुनर्गठन" के बाद, नौजवान पार्टी, जनवादी समाजवादी पार्टी के सदस्यों तथा अनेक अन्य *"गण्यमान्य व्यक्तियों"* को राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों, कार्यकारी य्वान के प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों के पद प्रदान किये गये । नौजवान पार्टी ने कृषि तथा वन मंत्रालय एवम् वित्त मंत्रालय में पद प्राप्त करने के बाद, संसाधन कमीशन तथा चीन पुनर्निमाण कपड़ा कंपनी पर कब्जा करने के लिए वैसी ही निर्लज्जता व छलकपट से काम लिया, जिस तरह क्वोमिंताङ के अधिकारी करते थे। सितंबर 1947 के आसपास क्वोमिंताङ सरकार में पदों की खींचातानी को लेकर जनवादी समाजवादी पार्टी दो धड़ों में विघटित हो गयी तथा दोनों धड़े एक दूसरे की निहायत घटिया ढंग से छीछालेदर करने लगे । इस तरह के लोगों तथा पार्टियों के गठजोड़ से पुनर्गठित क्वोमिंताङ सरकार बनाई गई थी । इस पर भी, च्याङ काई-शेक की धृष्टता तो देखिए कि वह अपनी सरकार को "उदार" तथा "बहुदलीय" बताता था ।

क्वोमिंताङ सरकार ने अपना पुनर्गठन क्यों किया ? उत्तर बिल्कुल सीधा सा है—अमरीकी प्रतिक्रियावादियों से कर्जा लेने के लिए, ताकि गृहयुद्ध जारी रखा जा सके व फासीवादी तानाशाही कायम रह सके ।

नवम्बर 1947 में छाङ छुन ने अमरीका सरकार से चार वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की । अमरीकी सहायता के एवज में क्वोमिंताङ सरकार को स्वेच्छा से अपने वित्तीय तथा अन्य आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए, अमरीकी विशेषज्ञों को स्वीकार करना था । मार्च 1948 में अमरीकी कांग्रेस ने क्वोमिंताङ को कुल 57 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता देने का बिल पास किया । ●

4.

● देशभक्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलन का उत्थान ।

क्वोमिंताङ के फौजी हमले की पराजय के साथ ही क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तथा उसकी राजनीतिक धोखाधड़ी का दिवाला पिट गया। जनता, जिसके मन में क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के प्रति घोर शत्रुता थी तथा जिसका उनके साथ मेल-मिलाप होने का प्रश्न ही नहीं उठता था, लड़ने को उठ खड़ी हुई थी, जिससे क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों में देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ने लगा था । इन क्षेत्रों का देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन तथा मुक्त क्षेत्रों का सशस्त्र संघर्ष—दो क्रान्तिकारी मोर्चे बन गए थे ।

सितम्बर 1946 में, प्रगतिशील अमरीकी संगठनों ने **"अमरीकियो, चीन छोड़ो !"** सप्ताह मनाने का आह्वान किया तथा जल्दी ही यह लहर समस्त चीन में फैल गई तथा एक व्यापक आन्दोलन शुरू हो गया, जिसके समर्थकों ने घोषणा की कि जब तक सभी अमरीकी सैनिक चीन की धरती को खाली नहीं करते, आन्दोलन जारी रहेगा । उन्होंने यह मांग भी की, कि अमरीका क्वोमिंताङ की किसी भी प्रकार की सहायता करना बन्द कर दे । यह आन्दोलन

देशभर के बड़े-शहरों में फैल गया तथा खासतौर से शंघाई तथा छुङकिङ में तो यह आंदोलन अभूतपूर्व बुलन्दियों पर पहुँच गया ।

1 दिसंबर, 1946 को, राष्ट्रीय असेम्बली के अधिवेशन के दौरान शंघाई में स्टाल लगाकर व फेरी लगाकर सामान बेचने वालों का संघर्ष फूट पड़ा । चूंकि शहर की अधिकांश जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रास्ते के किनारे बनी छोटी-छोटी दुकानों तथा फेरी लगाने वालों पर निर्भर करती थी, अतः शंघाई में छोटे-छोटे दुकानदारों तथा फेरी लगाने वालों की काफी बड़ी संख्या थी । बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से, क्वोमिंताङ सरकार ने फेरी लगाने तथा पटरी पर बने स्टालों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए, जिससे इन छोटे-छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई । खुद को जिन्दा रखने के अधिकार हेतु लड़ने के लिए उन्होंने शंघाई के अधिकारियों को याचिका पेश की, लेकिन बदले में उनका क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया गया । तथापि, शंघाई की जनता उनके साथ सहानुभूति जताते हुए, उनके संघर्ष के समर्थन में उठ खड़ी हुई तथा देश के अन्य भागों की जनता ने भी ऐसा ही किया । चीनी-अमरीकी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के सबसे बड़े केन्द्र शंघाई में ऐसी घटना का होना मात्र संयोग नहीं था, बल्कि यह प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन के गंभीर संकट का प्रतीक था ।

दिसंबर 1946 के अन्त में देशभर के छात्रों ने अमरीकी सैनिकों द्वारा किये जा रहे जुल्मों, जिनमें पेकिङ विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर बलात्कार करना भी शामिल था, के विरोध में प्रदर्शनों तथा हड़तालों की एक विशाल मुहिम छेड़ दी । इन संघर्षों में देश के बड़े तथा मध्यम दर्जे के शहरों के 5 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया ।

मई 1947 में, जब क्वोमिंताङ सरकार अपना "पुनर्गठन" कर रही थी, छात्रों का एक और देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन फूट पड़ा, जो कि और अधिक विशाल था तथा और ज्यादा व्यापक पैमाने पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला था । इस आन्दोलन का नारा था—**"भुखमरी, गृहयुद्ध तथा जुल्म के विरुद्ध संघर्ष करो ।"** अपनी व्यापकता तथा दृढ़ता के कारण यह विद्यार्थी आन्दोलन विशिष्ट महत्त्व का था । इसमें देश के सभी हिस्सों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रतिक्रियावादियों का हर कदम पर डट कर मुकाबला किया । मसलन, प्रतिक्रियावादियों ने विद्यार्थियों के हड़ताल करने के हक पर पाबन्दी लगा दी; जवाब में विद्यार्थियों ने पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हड़ताल का आयोजन कर दिखाया । प्रतिक्रियावादियों ने, याचिका पेश करने के लिए विद्यार्थियों के नानकिङ जाने पर पाबन्दी लगा दी, लेकिन विद्यार्थी रेलगाड़ी को स्वयं चला कर वहाँ पहुँच गए । क्वोमिंताङ की सेना, पुलिस, फौजी पुलिस तथा खुफिया पुलिस ने विद्यार्थियों पर हमला किया, लेकिन विद्यार्थियों ने उनके हाथों से हथियार छीन लिए ।

इस कालखण्ड के दौरान, शहरों में मजदूरों की हड़तालों का भी ताँता लग गया । अगस्त 1945 से सितम्बर 1946 तक, शंघाई में फैक्ट्रियों की तालाबन्दी, पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों की बर्खास्तगी तथा आसमान छूती कीमतों के विरोध में 1920 हड़तालें हुईं । इन संघर्षों में कुल मिलाकर 11 लाख 85 हजार लोगों ने भाग लिया, जबकि इसमें रिक्शा चालकों की हड़तालों में शामिल हड़तालियों की संख्या तथा उन हड़तालों में शामिल श्रमिकों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है, जिनके विवादों को मजदूरों तथा पूँजीपतियों ने आपसी बातचीत द्वारा हल

करने की सहमति प्रकट की, जो युद्ध बन्द करने तथा शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा समाधान के इच्छुक थे। अजेय जन-मुक्ति सेना को याङत्सी नदी पार करने तथा नानकिङ को, जो पिछले बाईस वर्षों से क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों का गढ़ था, मुक्त कराने में तीन दिन से ज्यादा का समय नहीं लगा। नानकिङ की मुक्ति से प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन का अंत हो गया। फिर जन-मुक्ति सेना बहादुरी से दो युद्ध-मोर्चों पर (याङत्सी के दक्षिण में तथा उत्तर-पश्चिम की तरफ) आगे बढ़ गई तथा दुश्मन की बची-खुची सैन्य-शक्तियों का सफाया कर दिया। थाएय्वान, हाङचओ, ऊहान, शीआन, शंघाई, लानचओ, कैंटन, क्वेइयाङ, क्वेइलिन, छुङकिङ तथा छङतू नामक बड़े-बड़े शहरों को बारी-बारी से मुक्त करा लिया गया। हुनान, स्वेइय्वान, सिनच्याङ, शीखाङ तथा युन्नान के प्रान्तों को शान्तिपूर्वक मुक्त करा लिया गया। 1949 के अन्त तक, अकेले तिब्बत को छोड़कर, चीन की सारी मुख्य-भूमि को मुक्त करा लिया गया था।

ल्याओशी-शनयाङ, ह्वाए-हाए तथा पेकिङ-थ्येनचिन की विशाल मुहिमों के बाद, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के दिन तो पहले ही गिने-चुने रह गए थे। नई विजयों के मद्देनजर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति ने, मार्च 1949 में अपना दूसरा पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया। अधिवेशन में राष्ट्रव्यापी विजय प्राप्त करने के लिए तथा उस विजय के बाद अपनाई जाने वाली पार्टी की बुनियादी नीतियों के बारे में निर्णय किये गए।

अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया कि देशव्यापी विजय के बाद पार्टी के कार्य का गुरुत्व-केन्द्र गाँवों से हटकर शहरों में आ जाना चाहिये। 1927 में, प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध

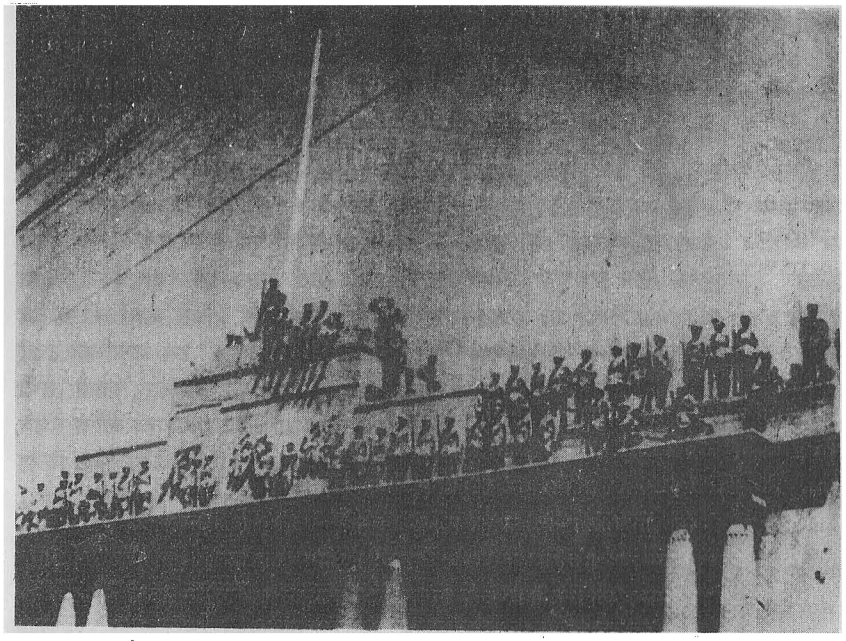

जन-मुक्ति सेना द्वारा नानकिङ स्थित च्याङ काई-शेक के राष्ट्रपति कार्यालय पर कब्जा (23 अप्रैल, 1949)

कृषि-सुधारों का उद्देश्य सामंती जमींदारों को व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक वर्ग के रूप में समाप्त करना था। उन्हें एक वर्ग के रूप में समाप्त करने के लिए कदम-दर-कदम आगे बढ़ना तथा विवेक से काम लेना जरूरी था। आन्दोलन ने स्थानीय निरंकुश तत्वों पर हमले, हिसाब-किताब साफ करने तथा लगान व सूद कम करने से शुरू होना था तथा कृषि-सुधारों को लागू करने की दिशा में केवल उसी समय आगे बढ़ना था, जब राजनीतिक वातावरण, जन-समुदाय तथा कार्यकर्ता वगैरा, जैसी परिस्थितियां पूर्णतया इसके अनुकूल होतीं। जमींदारों तथा धनी किसानों के बीच, बड़े जमींदारों तथा मध्यम व छोटे जमींदारों के बीच, तथा आम जमींदारों व स्थानीय निरंकुश तत्वों के बीच फर्क करना जरूरी था। कृषि-सुधारों के ढाँचे के अन्तर्गत हर तबके के साथ अलग-2 ढंग से बर्ताव किया जाना जरूरी था।

जमीन का बंटवारा निम्न तरीके से होना था—समूची सार्वजनिक भूमि तथा जमींदारों के स्वामित्व वाली जमीन को स्थानीय किसान सभा ने अपने कब्जे में ले लेना था तथा उस इलाके की बाकी जमीन को भी उसमें मिलाकर, सारी जमीन को प्रति व्यक्ति के आधार पर बराबर-बराबर दोबारा बांट दिया जाना था। क्षेत्रफल तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी, सभी जमीनों का संपूर्ण पुनर्निधारण किया जाना था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मोटे तौर पर दूसरे के बराबर जमीन का टुकड़ा मिल सके।

"कृषि-कानून की रूपरेखा" के लागू होने के एक साल के अन्दर-अन्दर मुक्त क्षेत्रों के 10 करोड़ किसानों को जमीन मिल गई। कृषि-सुधारों के बाद, कृषि-उत्पादन की बहाली तथा विकास के लिए पार्टी ने किसानों का स्वेच्छा से परस्पर-सहयोग तथा सहकारिता समितियां बनाने के आन्दोलन में मार्गदर्शन किया। कृषि-सुधारों ने कृषि-उत्पादन बढ़ाने का काम ही नहीं किया, बल्कि मुक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के हालात भी पैदा कर दिये। जमीन मिलने के बाद किसानों ने बड़े उत्साह से युद्ध में भाग लिया तथा मुक्ति युद्ध का सक्रिय समर्थन किया। फलतः कृषि-सुधारों ने जन-मुक्ति सेना के पृष्ठभाग को और ज्यादा सुदृढ़ किया तथा उसके रक्षा से आक्रमण की कार्यवाही पर उतर आने के लिए रास्ता तैयार किया। इस प्रकार, इसने क्रान्तिकारी युद्ध की देशव्यापी विजय की राजनीतिक आधारशिला भी रखी।

कृषि-सुधारों के साथ-साथ चीनी कम्युनिस्टों पार्टी ने दोष-निवारण आन्दोलन भी चलाया ताकि अपने संगठनों को निचले स्तर तक सुव्यवस्थित एवम् सुसंगठित किया जा सके, पार्टी सदस्यों के देहाती इलाकों में काम करने के तरीकों में सुधार लाया जा सके तथा दुश्मन तत्वों (जनता के दुश्मनों) को पार्टी से निष्कासित किया जा सके। इस कदम ने कृषि-समस्या हल करने में तथा जन-मुक्ति युद्ध को समर्थन देने में निर्णायक भूमिका निभाई। पार्टी की शुद्धता बरकरार रखकर, दुश्मन तत्वों से पिण्ड छुड़ा कर तथा काम करने के गलत तरीके को खत्म करके ही, पार्टी व्यापक मेहनतकश जनता के पक्ष में खड़ी हो सकती थी, तथा उसे आगे की ओर ले जा सकती थी। और केवल ऐसा करके ही पार्टी की कृषि-संबंधी नीतियां दृढ़ता से व सही तरीके से लागू की जा सकती थीं तथा जन-मुक्ति सेना का पृष्ठभाग बखूबी मजबूत किया जा सकता था।

क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में देशभक्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलन—जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संगठित व प्रभावित था तथा विद्यार्थी आन्दोलन जिसकी अग्रिम पंक्ति में था—ने जनक्रान्ति का दूसरा मोर्चा खोल दिया तथा देशव्यापी क्रान्ति के बढ़ते ज्वार का हिस्सा बन गया।

जन-मुक्ति सेना के रणनीतिक आक्रमण के प्रथम वर्ष के दौरान क्वोमिंताङ अधिकृत क्षेत्रों में देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन का फैलना जारी रहा । मई 1948 तक, जापानी हमलावर सेनाओं के पुनरुत्थान के लिए अमरीकी सहायता के खिलाफ संघर्ष ने राष्ट्रव्यापी स्वरूप अख्तियार कर लिया । लाखों की तादाद में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा स्टाफ कर्मियों ने इस संघर्ष में शिरकत की तथा समाज के सभी तबकों की अत्यधिक सहानुभूति तथा हार्दिक समर्थन प्राप्त किया । समूचे देश की जनता ने अपनी उम्मीदें कम्युनिस्ट पार्टी पर टिका दीं तथा लोग जनता के क्रान्तिकारी युद्ध की सम्पूर्ण विजय की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे ।

10 अक्तूबर, 1947 को चीनी जन-मुक्ति सेना ने एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें *''च्याङ काई-शेक का पतन हो ! सारे देश को मुक्त करो!''* का नारा दिया गया । इस नारे का उद्देश्य प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन-प्रणाली तथा उसकी समूची आधारशिला को ही नष्ट करना था । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा जन-मुक्ति सेना ने समूचे देश की जनता का आह्वान किया कि वह नव-जनवादी क्रान्ति को सफलता के मुकाम तक ले जाए । प्रथम, जो लोग साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा अफसरशाह-पूँजीवाद के विरोधी थे, उन सभी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एकजुट होकर, सामंती-दलाल-फासीवादी तानाशाही के स्थान पर जनता के जनवादी शासन की स्थापना करनी थी । दूसरे, प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन व्यवस्था का समूचा आधार ध्वस्त करना था, नौकरशाह-पूँजीपति करोबारों को जब्त करना था तथा सामंती कृषि-व्यवस्था का उन्मूलन करना था ।

क्या इस मोड़ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई इस नव-जनवादी क्रान्ति की कार्यदिशा के प्रति कोई शंका बनी हुई थी ? हाँ, ऐसे लोग थे । युद्ध भड़कने पर, क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के एक तबके तथा बुद्धिजीवियों के उच्च वर्ग के मन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चल रही नव-जनवादी क्रान्ति के भविष्य के प्रति सन्देह बना रहा तथा वे क्वोमिंताङ तथा अमरीका सरकार के प्रति भ्रम पाले रहे । इस तबके का प्रतिनिधित्व चाङ पो-छुन तथा लो लुङ-ची करते थे ।

उन्होंने ''तटस्थ'', ''स्वतन्त्र'' और ''तीसरी-पार्टी'' होने का रुख अपनाया तथा क्रान्ति व प्रतिक्रान्ति के बीच सुधारवादी मध्य मार्ग के लिए प्रयास करने लगे । उन्होंने यह दुःस्वप्न पाला कि मध्यमार्गी पूर्णरुपेण स्वतंत्र स्थिति में होंगे तथा दोनों पक्ष उनका समर्थन करेंगे तथा यह कि एक सुधारवादी राजनीतिक कार्यदिशा अपनाने से क्वोमिंताङ के प्रतिक्रियावादी शासन के अन्तर्गत, जिसका पूर्ण समर्थन अमरीकी साम्राज्यवादी कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा जनवाद को प्राप्त किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ शासन व्यवस्था के ढाँचे तथा उसकी समस्त नींव को बनाए रखकर भी, उनका उद्देश्य पूरा हो सकता था ।

परन्तु जब जन-मुक्ति सेना ने व्यापक पैमाने पर हमला शुरू कर दिया तथा युद्ध को क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों में ले गई, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने अपने आतंकवादी हथकण्डों को और ज्यादा प्रचण्ड कर दिया तथा न केवल कम्युनिस्ट पार्टी की, बल्कि अन्य जनवादी दलों की भी कानूनी मान्यता खत्म कर दी । ऐसा होने पर, ये तीसरे रास्ते वाले दिवालिए हो गए । 27 अक्तूबर, 1947 को चीन जनवादी संघ को भंग करने का आदेश जारी करके, क्वोमिंताङ सरकार ने तीसरे मार्ग की मृत्यु का घण्टा बजा दिया ।

सभी कुछ च्याङ के व्यक्तिगत नियंत्रण में आ गया था । इसके अतिरिक्त, उसने छाङ छुन को लगातार प्रतिरोध के लिए दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी सैन्य-शक्तियां एकत्रित करने का भी आदेश दिया । चच्याङ में, अपने जन्म-स्थान फङह्वा में ''सेवा निवृत्ति'' में रहते हुए, वह उन्मत हो युद्ध की तैयारियों में जुटा था । यहां तक कि वह अपनी छिन्न-भिन्न सेना की क्षतिपूर्ति हेतु 25 लाख रंगरूटों को भर्ती करने की आपराधिक योजना को कार्यरूप देने की हद तक जा पहुँचा था । संक्षेप में, क्वोमिंताङ सरकार, उसके वित्त तथा सेना पर अभी भी, वास्तविक तौर पर, च्याङ काई-शेक का ही नियंत्रण था।

दूसरी तरफ ली चुङ-रन ने कामरेड माओ द्वारा प्रस्तुत आठ शर्तों को शान्ति-वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने का स्वांग रचा । इसके बाद, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने साथी चओ एन-लाई की अध्यक्षता में इस वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का गठन किया। बातचीत 1 अप्रैल को शुरू हुई । चूंकि प्रतिक्रियावादी नानकिङ सरकार ही प्रति-क्रान्तिकारी गृहयुद्ध शुरू करने के लिए पूर्णतया जिम्मेवार थी, अतः वह चीनी जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार बहुत पहले ही खो चुकी थी । फिर भी उसे शान्ति-वार्ता में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी गई, क्योंकि अभी भी कुछ प्रतिक्रियावादी सशस्त्र सेनाओं पर उसका कब्जा था । यदि क्वोमिंताङ ने यह महसूस किया होता कि उसकी बची-खुची सैन्य-शक्तियां अब किसी किस्म का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थीं, तथा इस प्रकार, आठ शर्तों के आधार पर बातचीत द्वारा समझौता करने को राजी हो जाती, तो जनता को कम मुसीबतें झेलनी पड़तीं तथा जनता के क्रान्तिकारी उद्देश्य के पूरा होने में मदद मिलती ।

आधे महीने की बातचीत के पश्चात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल ने **अन्दरूनी शान्ति-समझौते**[4] का अन्तिम संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जो आठ शर्तों पर आधारित था । समझौते के पहले अनुच्छेद, जो युद्ध-अपराधियों को सजा देने से संबन्धित था, में व्यवस्था की गई थी कि **''सभी युद्ध-अपराधियों को, चाहे वे कोई भी क्यों न हों, युद्ध-अपराधी होने के अभियोग से बरी किया जा सकता था तथा उनके साथ नरमी का बरताव किया जा सकता था, बशर्ते वे सचमुच अपनी करनी से यह साबित कर दें कि उन्होंने सच्चे दिल से, सही और गलत के बीच फर्क किया था तथा अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था तथा इस सबसे चीनी जनता के मुक्ति-कार्य की प्रगति में और अन्दरूनी समस्याओं के शान्तिपूर्ण हल में मदद मिली हो ।''** इस अत्यधिक उदार व्यवस्था ने, च्याङ काई-शेक तथा उसके कट्टर अनुयायियों को छोड़कर, बाकी सभी युद्ध-अपराधियों के लिए अपने सराहनीय कामों द्वारा अपने अपराधों का प्रायश्चित्त करना संभव कर दिया । चीनी जनता ने उन्हें नया जीवन शुरू करने का यह एक आखिरी मौका प्रदान किया था । परन्तु, 21 अप्रैल को नानकिङ सरकार द्वारा यह समझौता अस्वीकार कर दिया गया ।

इस समझौते को नामंजूर करने का स्पष्ट मतलब था कि जिस प्रति-क्रान्तिकारी युद्ध को क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने खुद ही छेड़ा था, उसे वे अन्त तक चलाने पर तुले हुए थे । इस प्रकार क्वोमिंताङ की शान्ति कायम करने की ढकोसलेबाजी का पूर्णतया पर्दाफाश हो गया।

21 अप्रैल, 1949 को चीनी जन-मुक्ति सेना समूचे देश को मुक्त कराने हेतु, याङत्सी नदी पार करके आगे बढ़ी तथा इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी चीन की तरफ भी आगे बढ़ी । जन-मुक्ति सेना ने उन स्थानीय क्वोमिंताङ सरकारों तथा सैनिक गुटों से क्षेत्रीय शान्ति-समझौते

इन प्रस्तावों का एकमात्र उद्देश्य थोड़ी राहत प्राप्त करना था, ताकि च्याङ काई-शेक क्रान्तिकारी शक्तियों पर नए हमले करने व उन्हें कुचलने के लिए फिर से तैयारी कर सके। 14 जनवरी को वर्तमान परिस्थिति के बारे में दिये गए अपने वक्तव्य में कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि च्याङ काई-शेक की शर्तों का उद्देश्य युद्ध को जारी रखना था, फलतः ये शर्तें शान्ति के लिए कदापि न थीं । उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यद्यपि जन-मुक्ति सेना के लिए प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ की बची-खुची सशस्त्र सेनाओं को थोड़े समय में ही नष्ट कर देना पूर्णतया संभव तथा न्यायोचित था, फिर भी, युद्ध को शीघ्र समाप्त करने, सच्ची शान्ति प्राप्त करने तथा जनता के दुख-तकलीफों को कम करने हेतु, कम्युनिस्ट पार्टी नानकिङ स्थित क्वोमिंताङ सरकार के साथ-साथ, स्थानीय क्वोमिंताङ सरकारों व फौजी ग्रुपों के साथ भी निम्नलिखित आठ शर्तों के आधार पर शान्ति-वार्ता शुरू करने को तैयार थी:

- ❑ युद्ध-अपराधियों को सजा देना,
- ❑ बोगस "विधि सम्मत सत्ताधिकार" को रद्द कर देना,
- ❑ बोगस संविधान को रद्द कर देना,
- ❑ तमाम प्रतिक्रियावादी सेनाओं का जनवादी उसूलों के आधार पर पुनर्गठन करना,
- ❑ नौकरशाही-पूँजी को जब्त कर लेना,
- ❑ कृषि-सुधारों को लागू करना,
- ❑ वतनफरोश सन्धियों को रद्द करना,
- ❑ एक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन बुलाना, जिसमें प्रतिक्रियावादी तत्वों को शामिल न किया जाए, तथा एक जनवादी मिलीजुली सरकार बनाना जो प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ की नानकिङ सरकार और उसके अधीन सभी स्तरों की सरकारों के हाथ से सारी की सारी सत्ता ले ले ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मत था कि केवल इन आठ शर्तों के पालन से ही वास्तविक शान्ति स्थापित हो सकती थी । यदि क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादी इन शर्तों को अस्वीकार करते, तो इससे यह सिद्ध हो जाता कि उनकी तथाकथित "शान्ति" जिसके लिए वे इतना शोर मचा रहे थे, और कुछ नहीं, महज एक धोखाधड़ी थी ।

जैसा कि आशा थी, इन आठ शर्तों के प्रस्ताव ने च्याङ काई-शेक के *"शान्ति अभियान"* की पोल खोल दी । 21 जनवरी, 1949 को च्याङ काई-शेक ने, अमरीका की सलाह पर *"कुछ विशेष कारणों से राज्य का कामकाज देखने में असमर्थ होने के कारण,"* अपनी "सेवानिवृत्ति" की घोषणा की, तथा "उप-राष्ट्रपति" ली चुङ-रन को अपना कार्यभार सौंप दिया । वास्तव में तो यह अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा गढ़ा गया *"श्रम-विभाजन"* था । अब ली चुङ-रन ने *"शान्ति-दूत"* की भूमिका अदा करनी थी तथा च्याङ काई-शेक पर्दे के पीछे खिसक कर युद्ध की तैयारियां कर सकता था । "पद छोड़ने" से पहले च्याङ ने प्रति-क्रान्तिकारी युद्ध जारी रखने के लिए अनेक नए इन्तजाम किये थे तथा थाएवान (तैवान), फूच्येन, च्याङशी, क्वाङतुङ व सछ्वान में अपने अनेक पिट्ठुओं को तैनात कर दिया था । उसने वेइ थाओ-मिङ के स्थान पर छन छङ को थाएवान का गवर्नर नियुक्त किया था । क्वोमिंताङ सरकार के कब्जे में जो सोने-चांदी की सिल्लियाँ थीं, उनका एक हिस्सा थाएवान (तैवान) तथा अमोए भेज दिया गया था, तथा थाएवान में राज्य-कोष एवम् गोला-बारूद का भंडार,

चीन जनवादी संघ के भंग होने पर, मध्यमार्गी राजनीतिक पार्टियों ने स्वयं को पुनर्गठित किया । 1948 के बसन्त में क्वोमिंताङ के अन्दर के कई जनवादी संगठनों ने मिलकर क्वोमिंताङ की क्रान्तिकारी कमेटी का गठन किया । इस संस्था के बड़े-बड़े नेताओं द्वारा जनवादी लीग का एक नया मुख्यालय हांगकांग में स्थापित किया गया । ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे तथा क्वोमिंताङ की प्रतिक्रियावादी नीतियों व चीन के प्रति अमरीका की आक्रामक नीति का विरोध करते थे । इसी समय दूसरी जनवादी पार्टियों ने भी अपेक्षाकृत ज्यादा सकारात्मक राजनीतिक रवैया अपनाना शुरू कर दिया । लेकिन चाङ पो-छुन, लो लुङ-ची व उनके जोड़ीदार अभी भी अपने प्रतिक्रियावादी तृतीय-मार्ग के रुख पर अड़े हुए थे ।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न जनवादी पार्टियों व ग्रुपों के राष्ट्रीय क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे के गठन के लिए परिस्थितियां कदम-दर-कदम अनुकूल बनती जा रही थीं।

1 मई, 1948 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मई दिवस के नारों में जनता का एक नया राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा, ताकि जनवादी मिलीजुली सरकार की स्थापना पर विचार किया जा सके । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी तत्व भाग नहीं लेंगे । देश की समस्त जनता ने पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन किया । सभी जनवादी पार्टियों ने ऐसा सम्मेलन बुलाने के हक में सन्देश भेजे । इस प्रकार, **'चीनी जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन'** जिसे सितंबर 1949 में आयोजित किया गया, जनता के जनवादी संयुक्त मोर्चे का संगठनात्मक स्वरूप बन गया ।

चीनी जनता की क्रान्ति एक नई मंजिल में प्रवेश कर गई थी । सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से, जनता के लिए राष्ट्रव्यापी जीत हासिल करने का समय आ पहुँचा था । भविष्य की नई तथा महान विजय के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु, उत्तरी शेनशी में 25 दिसंबर, 1947 को पार्टी की केन्द्रीय समिति की एक मीटिंग हुई । इसमें कामरेड माओ ने **'वर्तमान परिस्थिति तथा हमारे कार्यभार'** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी युद्ध की मौजूदा स्थिति का सही विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा क्रांतिकारी युद्ध में और भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के लिए अनिवार्य सैनिक, राजनैतिक व आर्थिक कार्यभार प्रस्तुत किए ।

आरंभ में कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि चीनी जनता का क्रान्तिकारी युद्ध, इन अर्थों में एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ पहुँचा था कि जन-मुक्ति सेना रणनीतिक रक्षा की मंजिल से रणनीतिक आक्रमण की मंजिल में प्रवेश कर गई थी । जन-मुक्ति सेना की मुख्य सैन्य-शक्ति पहले ही क्वोमिंताङ अधिकृत-क्षेत्रों में घुस चुकी थी तथा मुक्त क्षेत्रों की अपेक्षा, लड़ाई मुख्यतया वहीं हो रही थी । जन-क्रान्ति को विजय-पथ पर अग्रसर करते हुए, जन-मुक्ति सेना ने अमरीकी साम्राज्यवाद तथा क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावाद के प्रतिक्रान्तिकारी मंसूबों को खाक में मिला दिया था । यह च्याङ काई-शेक के बीस वर्षों के प्रतिक्रान्तिकारी शासन तथा 100 साला साम्राज्यवादी शासन को विकास से सर्वनाश की ओर ले जाने वाला मोड़ था । इस परिवर्तन का बड़ा महत्त्व था । चूँकि सशस्त्र संघर्ष चीनी क्रान्ति के संघर्ष का मुख्य तरीका था, जन-मुक्ति सेना द्वारा रणनीतिक रक्षा की मंजिल से निकलकर रणनीतिक आक्रमण की मंजिल में प्रवेश करना इस बात का प्रमाण था कि चीनी क्रान्ति को जल्दी ही देशव्यापी विजयश्री प्राप्त होनी थी । साथ ही इससे विश्व के सभी दबे-कुचले राष्ट्रों को, खासकर पूर्व के राष्ट्रों को,

प्रेरणा तथा जबरदस्त समर्थन मिलना था ।

दूसरे, उन्होंने उस मुख्य तरीके का सारांश प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा जन-मुक्ति सेना ने क्वोमिंताङ को पराजित करना था । प्रत्येक मुहिम में सैन्य-शक्तियों को अत्यधिक बरतर संख्या में केन्द्रित किया जाना था ताकि पूरी तैयारी तथा संपूर्ण गारंटी के साथ चलायमान लड़ाई में शत्रु की मानव-शक्ति का कदम-दर-कदम सफाया किया जा सके । युद्ध के दूसरे वर्ष के दौरान, जन-मुक्ति सेना ने पहले ही शच्याच्वाङ, सफिङ, लोयाङ तथा खाएफङ जैसे छोटे व मध्यम दर्जे के शहरों पर कब्जा कर लिया था; शत्रु के दुर्गों को तहस-नहस करने की कार्यनीति सीख ली थी तथा अपनी खुद की तोपखाना व इंजीनियर इकाइयों का गठन कर लिया था । इस अनुभव के आधार पर, साथी माओ ने सही वक्त पर जोर देकर स्पष्ट किया कि भविष्य में जन-मुक्ति सेना मोर्चेबद्ध लड़ाई तथा शत्रु के बड़े किलों को तहस-नहस करने की तकनीक़ पर जोर देगी, ताकि और अधिक शहरों पर कब्जा करने की तैयारी की जा सके। शहरों पर एक-एक करके कदम-दर-कदम कब्जा करना था तथा इसमें काफी विवेक से काम लेना जरूरी था । पहले छोटे तथा मध्यम आकार के शहरों पर, फिर बड़े शहरों पर; पहले उन शहरों पर, जहां शत्रु की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, फिर मौका लगते ही, उन शहरों पर, जहां शत्रु की सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत थी, और फिर अन्त में, जब हालात अनुकूल हों, तो उन शहरों पर कब्जा करना था जहां शत्रु की सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी ।

तीसरे, उन्होंने कृषि-सुधारों तथा पार्टी के दोष-निवारण आन्दोलन के बारे में महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए, जो कि उस समय चलाए जा रहे थे । कृषि-सुधार के बुनियादी उसूल इस प्रकार थे : गरीब किसानों तथा खेत-मजदूरों की मांगों को पूरा करना कृषि-सुधार कार्यक्रम का सबसे बुनियादी कार्यभार था । मध्यम किसानों के साथ सुदृढ़ एकता कायम करना व उनके हितों को चोट न पहुँचाना, दूसरा मुख्य उसूल था । इन दो बुनियादी उसूलों का दृढ़ता से पालन करके ही कृषि-सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता था तथा मध्यम किसानों के हितों को नुकसान पहुँचाने के भटकाव को—जो कि पार्टी में पहले से ही मौजूद था—समय रहते दूर किया जा सकता था ।

पार्टी-संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए पार्टी में से दुश्मन-तत्वों को निकाल बाहर करना तथा पार्टी में जारी गलत कार्यशैली को ठीक करना जरूरी था ताकि पार्टी व्यापकतम मेहनतकश जन-समुदाय के पक्ष में खड़ी होने तथा आगे बढ़ने में उनका नेतृत्व करने के योग्य बन सके, और यह भूमि समस्या को हल करने तथा क्रान्तिकारी युद्ध हेतु समर्थन जुटाने के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण था ।

चौथे, क्रान्तिकारी युद्ध के तीव्र विकास से और ज्यादा शहर मुक्त होने थे । ज्यादा बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए, सही कृषि नीति के साथ-साथ, एक सही शहरी नीति होनी भी जरूरी थी । रिपोर्ट में पार्टी के आर्थिक कार्यक्रम की स्पष्ट व्याख्या की गई थी । सामंती जमींदार वर्ग से जब्त जमीन किसानों को देना; अफसरशाह-पूँजी, जिसका स्वामित्व मुख्यतः "चार बड़े घरानों" के हाथ में था, को लोक गणराज्य के सुपुर्द कर देना; तथा राष्ट्रीय उद्योग व वाणिज्य को सुरक्षा प्रदान करना—नव-जनवादी क्रान्ति के आर्थिक कार्यक्रम में ये तीन मुख्य घोषणाएँ थीं ।

"चार बड़े घरानों" के नेतृत्व वाला अफसरशाह-पूँजीवाद प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ

जन-मुक्ति सेना द्वारा पेकिङ की घेराबन्दी किये जाने के साथ ही, शहर की शान्तिपूर्ण मुक्ति के लिए बातचीत शुरू हो गई थी । परन्तु ठीक थ्येनचिन की मुक्ति की पूर्व संध्या तक, पेकिङ में स्थित शत्रु सेना अपने शान्तिपूर्ण पुनर्गठन की शर्तों को मानने से हठपूर्वक इंकार करती रही थी । जन-मुक्ति सेना की प्रचण्ड शक्ति, थ्येनचिन की अविलंब मुक्ति, शत्रु सेना के अफसरों व सैनिकों का गिरता आत्मविश्वास तथा पेकिङ की व्यापक जनता के शान्ति के लिए दृढ़ समर्थन ने, अन्ततः पेकिङ की शान्तिपूर्ण मुक्ति को संभव बनाया । पेकिङ की शान्तिपूर्ण मुक्ति पार्टी द्वारा पेश किये गए शान्तिपूर्ण तरीकों से युद्ध को समाप्त करने की नीति की पहली महान विजय थी । इस विजय ने याङत्सी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया ।

इन तीन बड़ी मुहिमों के अन्त तक, जन-मुक्ति सेना ने क्वोमिंताङ की 15 लाख सिरफिरी फौजों का सफाया कर दिया था, और समूचे उत्तर-पूर्व, उत्तरी चीन के बड़े हिस्से तथा निचली याङत्सी के उत्तर में स्थित विशाल इलाकों को मुक्त करा लिया था, तथा इस प्रकार निर्णायक सैनिक विजयश्री प्राप्त कर ली थी । राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से, क्वोमिंताङ भी विभाजित, छिन्न-भिन्न तथा पूर्णतया बिखरने के कगार पर खड़ी थी । ये हालात, जन-मुक्ति सेना के लिए समूचे देश को मुक्त कराने हेतु याङत्सी नदी को पार कर, दक्षिण की ओर कूच करने के लिए बेहद अनुकूल थे । यह पूर्णतया स्पष्ट था कि बची-खुची क्वोमिंताङ सेनाओं के खिलाफ कुछ और व्यापक पैमाने के हमलों के बाद, क्वोमिंताङ का समूचा प्रतिक्रियावादी शासनतन्त्र चकनाचूर हो जाना था ।

क्वोमिंताङ शासन के इस संकट ने प्रतिक्रियावादियों के खेमे में और ज्यादा अन्तर्विरोध पैदा कर दिये । च्याङ काई-शेक के लिए अपना शासन बचाए रखना मुश्किल हो गया । हपे, छाहाड़, शानतुङ, क्वाङतुङ, च्याङशी, क्वाङशी तथा हुनान के स्थानीय क्वोमिंताङ सिपहसालारों ने खुद को बचाए रखने के लिए अर्ध-स्वतन्त्रता का सपना देखा तथा इस अर्ध-स्वतन्त्रता के आधार पर अमरीकी सहायता पाने की आस लगाई । क्वोमिंताङ के अनेक मठाधीशों तथा हू श व दूसरे अमरीका-परस्त बुद्धिजीवियों के समर्थन से 1948 के बसन्त में बोगस राष्ट्रीय असेम्बली बुलाई गई तथा उसमें ली चुङ-रन को "उप-राष्ट्रपति" चुना गया । फिर भी, अमरीका सरकार ने महसूस किया कि च्याङ काई-शेक को जबरदस्ती "सेवा-निवृत" करने से भी क्वोमिंताङ का विखंडन तेज ही होना था । यदि च्याङ काई-शेक का समर्थन नहीं करना, तो फिर किसे समर्थन दिया जाए ? इस सवाल को लेकर अमरीकी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं थी । न ही अमरीका इस बात का फैसला कर सका कि क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों को लड़ाई जारी रखनी चाहिये या फिर शान्ति-वार्ता की गुहार करनी चाहिये। इस प्रकार, क्वोमिंताङ की प्रतिक्रियावादी सरकार के लड़खड़ाने तथा छिन्न-भिन्न होने से, चीन के प्रति अमरीका की नीति का भी पूर्णतया दिवाला पिट गया ।

इन विषम हालातों में, च्याङ काई-शेक ने 1949 के नव वर्ष के अवसर पर, शान्ति के लिए एक संदेश जारी किया । उसने शान्ति-वार्ता के लिए चीनी जनता के सामने निम्नलिखित शर्तें पेश कीं : *बड़े जमींदारों तथा बड़े-पूँजीपतियों के सत्ताधिकार को कायम रखना; क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की बोगस सरकार तथा बोगस संविधान की वैधता को [illegible] रखना; प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ-सेना को निश्चित रूप से बनाए रखना, आदि-आदि।*

करा लिया तथा उसके दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया । जनता के क्रान्तिकारी युद्ध की यह एक और निर्णायक विजय थी । पूर्वी चीन तथा याङत्सी नदी के उत्तर में मध्यवर्ती मैदान में शत्रु की बची-खुची फौजों ने तेजी से पीछे की ओर हटना तथा नदी के दक्षिण की तरफ भागना शुरू कर दिया । इस प्रकार क्वोमिंताङ सरकार के शासन-केन्द्रों—नानकिङ व शंघाई—को जन-मुक्ति सेना से सीधा खतरा पैदा हो गया ।

इसी दौरान, 5 दिसंबर, 1948 से 31 जनवरी, 1948 तक, चौथी रणांगन सेना तथा उत्तरी चीन जन-मुक्ति सेना की दूसरी सेना ने मिलकर विशाल **पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम** चलाई । इस मुहिम के शुरू होने से पहले, जन-मुक्ति सेना ने शत्रु को कुछ अलग-अलग शहरों, जैसे—पेकिङ, थ्येनचिन व चाङच्याखओ आदि में घेर लिया था । पहले चाङच्याखओ पर कब्जा किया गया । इसके बाद, जब थ्येनचिन की रक्षार्थ तैनात रक्षक-सेना के कमाण्डर छन छाङ-च्ये ने शहर की शान्तिपूर्ण मुक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब जन-मुक्ति सेना ने शहर पर बड़ा हमला शुरू किया । उत्तरी चीन का यह पहला औद्योगिक तथा वाणिज्यिक शहर था, जिसे पूर्णतया मुक्त कराने में मात्र दो दिन लगे और यह कार्य 15 जनवरी, 1949 को संपन्न हुआ । प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ के 1,30,000 सैनिकों को धराशायी कर दिया गया तथा छन छाङ-च्ये को बन्दी बना लिया गया । दूसरी तरफ, फू च्वो-ई की कमान में पेकिङ की रक्षा के लिए तैनात दो लाख शत्रु सैनिकों ने जन-मुक्ति सेना द्वारा रखे गए शान्तिपूर्ण पुनर्गठन के प्रस्ताव को मान लिया । चीन की प्राचीनकालीन राजधानी, पेकिङ की मुक्ति की घोषणा 31 जनवरी, 1949 को की गई । पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम में, पुनर्गठित सेनाओं समेत, निष्क्रिय किये गये शत्रु सैनिकों की संख्या 5,20,000 तक जा पहुँची ।

लाल सेना के पेकिङ में दाखिल होने पर उसका स्वागत करती पेकिङ की जनता (1949)

सरकार का आर्थिक आधार था । जापान-विरोधी युद्ध के दौरान तथा जापान के आत्मसमर्पण के उपरान्त, इसका सितारा खूब चमका, तथा इसने नव-जनवादी क्रान्ति के लिए पर्याप्त भौतिक हालात प्रदान किए । पार्टी की यह सुस्पष्ट नीति थी कि अफसरशाह-पूँजी को जब्त करके उसे लोक गणराज्य के सुपुर्द कर दिया जाए, तथा अफसरशाह-पूँजीवादी अर्थप्रणाली को समाजवादी अर्थप्रणाली में बदल दिया जाए । नव-जनवादी क्रान्ति का उद्देश्य साम्राज्यवाद, सामंतवाद, तथा अफसरशाह-पूँजीवाद का तख्ता उलटना था, लेकिन सामान्यतः पूँजीवाद को खत्म करना उसका उद्देश्य नहीं था । चीन के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, क्रान्ति की राष्ट्रव्यापी जीत के बाद भी यह जरूरी था कि छोटे तथा मध्यम दर्जे के पूँजीवादी उद्योग पर्याप्त लंबे समय तक बने रहें, तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में श्रम-विभाजन के अनुसार, उन हिस्सों को विकसित किया जाए जो राष्ट्रीय कल्याण तथा जनता की जन-जीविका के लिए लाभकारी थे। छोटे तथा मध्यम आकार के पूँजीवादी उद्यमों की उपस्थिति तथा विकास से कोई खतरा पैदा नहीं होना था क्योंकि अफसरशाह-पूँजी की जब्ती से लोक गणराज्य के पास समाजवादी स्वरूप का एक विशाल राजकीय अर्थतन्त्र होना था, जिसने समूचे राष्ट्र की मुख्य आर्थिक शिराओं पर नियंत्रण रखना था । इस राजकीय अर्थतन्त्र का निर्णायक महत्त्व होना था तथा इसने लोक गणराज्य के आर्थिक जीवन में मुख्य भूमिका अदा करनी थी ।

रिपोर्ट में क्वोमिंताङ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा निम्न-पूँजीपति वर्ग के उच्च तबके के प्रतिक्रियावादी राजनीतिक रुझान की तथा इन वर्गों के प्रति पार्टी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई एहतियाती नीति की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई थी । उनके प्रतिक्रियावादी राजनीतिक रुझानों से संघर्ष करने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तथा दोनों बातों को किसी भी हालत में आपस में उलझाया नहीं जाना था । जिन इलाकों में नव-जनवादी राजसत्ता विद्यमान थी, वहाँ इन वर्गों की दृढ़ता से रक्षा की जानी थी । पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं की इस बात के लिए सख्त आलोचना की गई थी कि उन्होंने छोटे तथा मध्यम दर्जे के पूँजीवादी उद्यमों के प्रति अति "वामपंथी" नीति अपनाने की भूल की थी ।

पाँचवें, उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा चीनी जनता ने राजनीतिक मोर्चे पर एक महान विजय हासिल की थी क्योंकि क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे का और ज्यादा विस्तार हो गया था तथा उसमें अभूतपूर्व सुदृढ़ता आ गई थी । चूँकि अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों के अपराधों का चीनी जनता के सामने पूरा पर्दाफाश हो गया था, चूँकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सही कृषि तथा शहरी नीतियों पर अमल किया था, तथा चूँकि जन-मुक्ति सेना ने महान विजय प्राप्त की थी, इसलिए पार्टी ने समस्त देश की जनता का विश्वास जीत लिया था । यही क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का आधार था । समूची जनता के बेहद विशाल बहुमत वाले व्यापक संयुक्त मोर्चे के बिना, चीन की नव-जनवादी क्रान्ति के लिए सफल होना असंभव था । इसके अतिरिक्त, यदि इस संयुक्त मोर्चे को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सुदृढ़ तथा शक्तिशाली नेतृत्व नहीं मिलता, तो शायद किसी भी प्रकार की कोई विजय प्राप्त करना संभव न होता । केन्द्रीय समिति ने समूची पार्टी से पिछले अनुभव से सीख लेने को कहा । सन् 1927 में, जब क्रान्ति का सितारा बुलन्दियों पर था, पार्टी के नेतृत्वकारी संगठन में बैठे आत्मसमर्पणकारियों ने क्रान्ति के नेतृत्व को तिलांजलि

दे दी थी, तथा इस प्रकार क्रान्ति की हार हो गई थी । दूसरी ओर, जापान-विरोधी युद्ध के दौरान, चूंकि पार्टी में आत्मसमर्पणवाद के खिलाफ संघर्ष किया गया था, तथा जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में, सर्वहारा की स्वतन्त्रता तथा पहलकदमी को बनाए रखने के सिद्धान्त का पालन किया गया था, तथा इस प्रकार प्रतिरोध युद्ध की महान विजय को सुनिश्चित बनाया गया ।

नए क्रांतिकारी हालातों में राष्ट्रव्यापी विजय हेतु जनता का मार्गदर्शन करने के लिए यह रिपोर्ट, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक दस्तावेज था । रिपोर्ट में युद्ध के रक्षात्मक कार्यवाही की मंजिल से आक्रमणात्मक कार्यवाही की मंजिल में प्रवेश करने के बाद, पार्टी द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न मूल नीतियों की व्याख्या की गई थी । ये नीतियां थीं : सैनिक मामलों, कृषि-सुधार, पार्टी के सुदृढ़ीकरण, आर्थिक मामलों तथा संयुक्त मोर्चे से सम्बन्धित नीतियाँ । इस प्रकार यह रिपोर्ट एक कार्यवाही-योजना थी जिसके आधार पर पार्टी समस्त जनता का नेतृत्व करते हुए, उसे अन्तिम विजय दिला सकती थी । ●

2.

- **नए मुक्त क्षेत्रों तथा नगरों के विषय में पार्टी की नीतियाँ ।**
- **पार्टी के अनुशासन को मजबूती प्रदान करना तथा पार्टी कमेटी प्रणाली को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना ।**

आक्रमणात्मक कार्यवाही की मंजिल में प्रवेश करने के बाद जन-मुक्ति सेना ने जल्दी ही एक के बाद एक, अनेक शहरों व विशाल क्षेत्रों को मुक्त करा लिया तथा 3 करोड़ की आबादी वाले मध्यवर्ती मैदान मुक्त क्षेत्र की स्थापना की । उस वक्त मुक्त क्षेत्रों की कुल आबादी 16 करोड़ से ज्यादा थी । जन-मुक्ति सेना ने किलेबन्दियों पर टूट पड़ने की तकनीक में काफी महारत हासिल कर ली थी, जिससे बहुत से मध्यम आकार के शहरों को वापिस ले लिया गया था या मुक्त करा लिया गया था, जिनमें उत्तरपूर्व में आनशान व सफिङ, शानतुङ में वेइश्येन, हपे में शच्याच्वाङ, शानशी में युनछङ व लिनफन, शेनशी में पाओची, हनान में खाएफङ व लोयाङ तथा हुपे में श्याङ्याङ जैसे मजबूत किलेबन्दियों वाले शहर भी शामिल थे ।

पार्टी की केन्द्रीय समिति ने समूची पार्टी का आह्वान किया कि नये मुक्त क्षेत्रों तथा शहरों के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियों के अध्ययन तथा उन्हें सही ढंग से लागू करने पर पूरा ध्यान दिया जाए । नए क्षेत्रों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति को औपचारिक रूप देने व उसे लागू करने के लिए, केन्द्रीय समिति ने निम्नलिखित मूलभूत कार्य प्रणाली तय की, जिसका सारी पार्टी ने अनुसरण करना था : विभिन्न क्षेत्रों के विशेष हालातों का ठोस विश्लेषण करना, ताकि कार्यभार तय किये जा सकें तथा इन हालातों के अनुसार कार्य-प्रणाली निश्चित की जा सके। शहर तथा देहात के बीच, पुराने तथा अर्ध-पुराने मुक्त क्षेत्रों के बीच, छापामार क्षेत्रों तथा नए मुक्त क्षेत्रों के बीच फर्क किया जाना था ।

नए मुक्त क्षेत्रों के विषय में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि उन पर पक्का नियंत्रण कायम रह सकता था । यदि उत्तर हाँ में था, तो निम्नलिखित बातों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना था । एक ओर, जनता की जनवादी राजसत्ता स्थापित करने के लिए, सभी प्रति-क्रांतिकारी सशस्त्र सेनाओं को दृढ़ता से नेस्तनाबूद कर देना था; सभी प्रति-क्रांतिकारी

आबादी 7 लाख थी तथा यहां क्वोमिंताङ की एक लाख रक्षक फौजें तैनात थीं, और यह शहर अनेक आधुनिक किलेबन्दियों द्वारा आरक्षित था । वहां का धरातल रक्षा के अनुकूल था, परन्तु आक्रमण के लिए प्रतिकूल था । फिर भी, आठ दिन तक लगातार हमला करने के बाद, जन-मुक्ति सेना ने शहर को पूर्णतया मुक्त करा लिया । यह शत्रु की मुख्य सैन्य-शक्तियों की व्यापक स्तर पर घेराबन्दी व सफाये की तथा बड़े शहरों को मुक्त कराने की शुरुआत थी । चीनान की मुक्ति ने यह साबित कर दिया कि कोई भी रक्षात्मक योजना जन-मुक्ति सेना की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती थी ।

12 सितंबर से 2 नवंबर, 1948 तक, उत्तरपूर्वी चीन स्थित जन-मुक्ति सेना ने, विशाल **ल्याओशी-शनयाङ मुहिम** चलाई । पहले उसने चिनचओ को मुक्त कराया, इस प्रकार उत्तर-पूर्व में स्थित शत्रु यूनिटों तथा लंबी दीवार के दक्षिण में स्थित शत्रु यूनिटों को जोड़ने वाला सम्पर्क सूत्र काट दिया गया तथा स्थल मार्ग से शत्रु की वापसी का रास्ता रोक दिया गया। इसके बाद, छाङछुन को मुक्त कराया गया । शनयाङ इलाके में स्थित शत्रु ने पश्चिमी ल्याओनिङ की ओर भागना शुरू कर दिया तथा ताहू व काले पर्वतों के क्षेत्र में उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया । इस प्रकार शनयाङ तथा समूचे उत्तर-पूर्वी चीन को मुक्त करा लिया गया । उत्तर-पूर्व, जहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक शहर तथा समस्त देश के अत्यधिक समृद्ध उत्पादक इलाके स्थित थे, स्थाई रूप से जनता के अधिकार में आ गया । ल्याओशी-शनयाङ मुहिम में, 4,70,000 से ऊपर क्वोमिंताङ सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया गया । जनता के क्रान्तिकारी युद्ध की यह एक निर्णायक विजय थी, क्योंकि इसके बाद, गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ जन-मुक्ति सेना, संख्या की दृष्टि से भी क्वोमिंताङ सेना से बरतर होनी आरंभ हो गई । शत्रु का कुल सैन्य-बल घटकर 29 लाख रह गया, जबकि जन-मुक्ति सेना की संख्या बढ़कर तीस लाख हो गई ।

इस समय तक, उत्तर-पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती मैदान, पूर्वी चीन तथा उत्तर-पूर्वी चीन की जन-मुक्ति सेना की विभिन्न रणांगन सेनाओं का क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी रणांगन सेना के रूप में पुनर्गठन किया जा चुका था। इनमें से प्रत्येक की कमान में कई-कई फौजी कोरें थीं। इन यूनिटों का जन-मुक्ति सेना के सदर मुख्यालय की प्रत्यक्ष कमान के अधीन उत्तरी चीन की तीन फौजी कोरों की यूनिटों के साथ-साथ एकीकृत पुनर्गठन किया गया।

6 नवंबर, 1948 से 10 जनवरी, 1949 तक, दूसरी तथा तीसरी रणांगन सेनाओं ने मिलकर विशाल **ह्वाए-हाए मुहिम** चलायी । जन-मुक्ति सेना ने च्याङसू में श्वीचओ के पूर्व में नयेनच्वाङ के क्षेत्र में ह्वाङ पो-थाओ की कमान वाली 1,70,000 सैनिकों की शत्रु फौज का पूरी तरह सफाया कर दिया । स्वयं ह्वाङ भी कार्यवाही के दौरान मारा गया । फिर, उत्तरी च्याङसू में सूश्येन के दक्षिण-पश्चिम में श्वाङत्वेइची के इलाके में, ह्वाङ वेइ की फौज के 1,20,000 सैनिकों को घेरकर उनका सफाया कर दिया गया । ये लोग मध्य चीन से कुमुक के रूप में बड़ी तेजी से आए थे । खुद ह्वाङ वेइ को बंदी बना लिया गया । तू य्वी-मिङ के मातहत, 2,50,000 सैनिकों वाली तीन शत्रु सेनाएं, श्वीचओ छोड़कर पूर्वी हनान में युङछङ की तरफ भाग गईं । उन्हें युङछङ के उत्तरपूर्व में नष्ट कर दिया गया तथा तू य्वी-मिङ को बंदी बना लिया गया । यह मुहिम दो महीने पाँच दिन तक चली । जन-मुक्ति सेना ने शत्रु की साढ़े पाँच लाख फौजों को ध्वस्त कर दिया, ह्वाए नदी के उत्तर में स्थित सभी इलाकों को मुक्त

प्रदेशों को बनाए रखने के लिए व राष्ट्रव्यापी जीत प्राप्त करने के लिए पार्टी अनुशासन को मजबूत करना बुनियादी तौर पर जरूरी था । देशभर में क्रांतिकारी परिस्थितियों की मांग थी कि राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक मामलों पर पार्टी पूरी तरह एकजुट दिखाई दे ।

तदनुसार, जनवरी 1948 में पार्टी की केन्द्रीय समिति ने निर्देश जारी किए कि समूची पार्टी में अनुशासन को मजबूत किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि सभी स्थानीय संगठन नियमित अन्तराल से, अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट केन्द्रीय समिति को भेजें ।

साथ ही, केन्द्रीय समिति ने पार्टी-कमेटी प्रणाली को ठोस आधार प्रदान करने का फैसला भी किया । इसके अनुसार, पार्टी समितियों को सभी स्तरों पर, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य करना था तथा पार्टी के कुछ नेतृत्वकारी संगठनों में कुछ व्यक्तियों द्वारा सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिये जाने तथा सभी जरूरी समस्याओं को उन द्वारा अकेले ही हल किये जाने (जैसा कि देखने में आया था) की गलती से पीछा छुड़ाना था । फैसले में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया कि पार्टी-कमेटी प्रणाली सामूहिक नेतृत्व सुनिश्चित करने व कुछ व्यक्तियों द्वारा हर चीज अपने हाथ में ले लेने को रोकने के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली थी । सभी महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर पार्टी कमेटी में पूरा विचार-विमर्श होना तथा सुस्पष्ट फैसले होने के बाद, उन्हें अलग-अलग हल करना जरूरी था । दूसरी ओर, साँझे नेतृत्व व व्यक्तिगत जिम्मेदारी, दोनों में से किसी एक पर भी इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाना था कि दूसरे का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए । अर्थात्---दोनों में तालमेल जरूरी था ।

केन्द्रीय समिति की इन हिदायतों पर तुरन्त अमल किया गया । फलतः सारी पार्टी में जबरदस्त एकजुटता पैदा हुई, नेतृत्व और अधिक केन्द्रीकृत हुआ तथा जनता के साथ पार्टी के सम्बन्ध और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए ।

केन्द्रीय समिति द्वारा दिसंबर 1947 में आयोजित सम्मेलन तथा बाद में पार्टी द्वारा किए गए काम से, पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी विजय के लिए जनता की अगुवाई करने हेतु जरूरी हालात पैदा हुए । ●

3.

- **तीन बड़ी मुहिमें : ल्याओशी-शनयाङ[1], ह्वाए-हाए[2] तथा पेकिङ-थ्येनचिन[3]।**
- **सारे देश में जनता के क्रान्तिकारी युद्ध की मौलिक विजय ।**
- **पार्टी के नेतृत्वकारी केन्द्र का देहाती इलाके से शहर में स्थानांतरण ।**
- **जन क्रान्ति की विजय के बाद समाजवाद में संक्रमण की बुनियादी नीति ।**

युद्ध के तीसरे वर्ष में, युद्ध-परिस्थिति में एक अन्य क्रान्तिकारी परिवर्तन आया । जन-मुक्ति सेना द्वारा चलाई गई तीन बड़ी मुहिमों के फलस्वरूप चीनी जनक्रान्ति की देशव्यापी विजय कर सुनिश्चित हो गई थी । इन मुहिमों में क्वोमिंताङ की मुख्य सैन्य-शक्तियों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया था । ये मुहिमें थीं : ल्याओशी-शनयाङ मुहिम, ह्वाए-हाए मुहिम तथा पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम ।

प्रथम, 16 सितंबर, 1948 को जन-मुक्ति सेना ने पूर्वी चीन में शानतुङ प्रान्त की राजधानी चीनान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी । चीनान एक रणनीतिक महत्त्व का शहर था, इसकी

संगठनों को भंग करके उनके नेताओं अथवा सरगनाओं को गिरफ्तार कर लेना था; एवं अफसरशाह-पूँजी तथा प्रमुख प्रति-क्रांतिकारियों की सम्पत्तियों को जब्त कर लेना था । दूसरी ओर, कानून का पालन करने वाले सभी राष्ट्रीय औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों, तथा उन सभी सार्वजनिक व निजी सम्पत्तियों को, जो जब्ती सूची में नहीं थीं, संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी थी । सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने व अफरा-तफरी से बचने के लिए, क्वोमिंताङ सरकार के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों में से, जहां तक संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा को नौकरी में रहने देना था । जनता की राजनीतिक जागरूकता व उसके संगठित होने के अनुसार कदम-ब-कदम जरूरी सामाजिक सुधार लागू किए जाने थे ।

शहरों में सामाजिक सुधार का कार्य तथा तरीका देहात में कृषि-सुधारों से बिल्कुल अलग किस्म का था । नए मुक्त शहरों में सामाजिक सुधार लागू करते हुए, सबसे जरूरी काम था---अफसरशाह-पूँजी को जब्त करना । जब्त किये गए अफसरशाह-पूँजीपति उद्यमों को विघटित नहीं किया जाना था; बल्कि उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना था तथा यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करना था कि वे उत्पादन जारी रखें या दोबारा शुरू कर दें । शहरों में दोबारा काम शुरू करने व उत्पादन के विकास की कुंजी श्रमिक वर्ग के हाथों में होनी थी । इसलिए सभी सार्वजनिक तथा निजी उद्यमों में जनवादी सुधार लागू करना, श्रमिकों का स्तर उचित रूप से ऊँचा करना तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करना जरूरी था ।

नए मुक्त क्षेत्रों में कृषि सुधार लागू करने के लिए तीन शर्तें जरूरी थीं :

(1) प्रतिक्रियावादी सशस्त्र सेनाएँ पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दी जाएं तथा आस-पड़ौस में शांति तथा कानून-व्यवस्था की बहाली की जाए ।

(2) जनसमुदाय के बुनियादी तबके का बहुत बड़ा बहुमत जमीन के बंटवारे की माँग करता हो ।

(3) स्थानीय स्तर पर कृषि सुधार सही ढंग से लागू करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता होने चाहिएं थे ।

जब कृषि-सुधार का कार्य पूरा हो जाता तब भूमि के स्वामित्व के अधिकार को परिभाषित किया जाना था, तथा जनता की समस्याओं को पुनः व्यवस्थित करना तथा हल्का करना जरूरी था । जब भी संभव हो, किसानों को मदद प्रदान करनी थी, ताकि वे कृषि उपज में वृद्धि कर सकें । उन इलाकों में, जहाँ के हालात अभी कृषि-सुधार के अनुकूल न थे, लगान व सूद में कटौती की सामाजिक नीति व अनाज तथा बीजों की आपूर्ति की पुनः व्यवस्था करना तथा समानता के आधार पर कर लगाने की वित्तीय नीति लागू करना जरूरी था ताकि जिन लोगों को अपने पक्ष में किया जा सकता था उन्हें अपने पक्ष किया जा सके तथा जिन्हें तटस्थ बनाया जा सकता था, उन्हें तटस्थ बनाया जा सके । क्वोमिंताङ सशस्त्र सेनाओं को नष्ट करने व शासक जमींदारों को चकनाचूर करने के लिए, ऐसा करना जरूरी था ।

क्रांतिकारी युद्ध में तीव्र विजय के उपरांत, पार्टी ने अनेक क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिनकी आबादी 16 करोड़ से ऊपर थी तथा उनमें से काफी को एक-दूसरे से जोड़ दिया गया था । इसके अलावा, वह दिन भी निकट आ रहा था जब पार्टी ने समस्त राष्ट्र की जनता की जनवादी राजसत्ता की नेतृत्वकारी पार्टी बन जाना था । पहले से ही जीते जा चुके

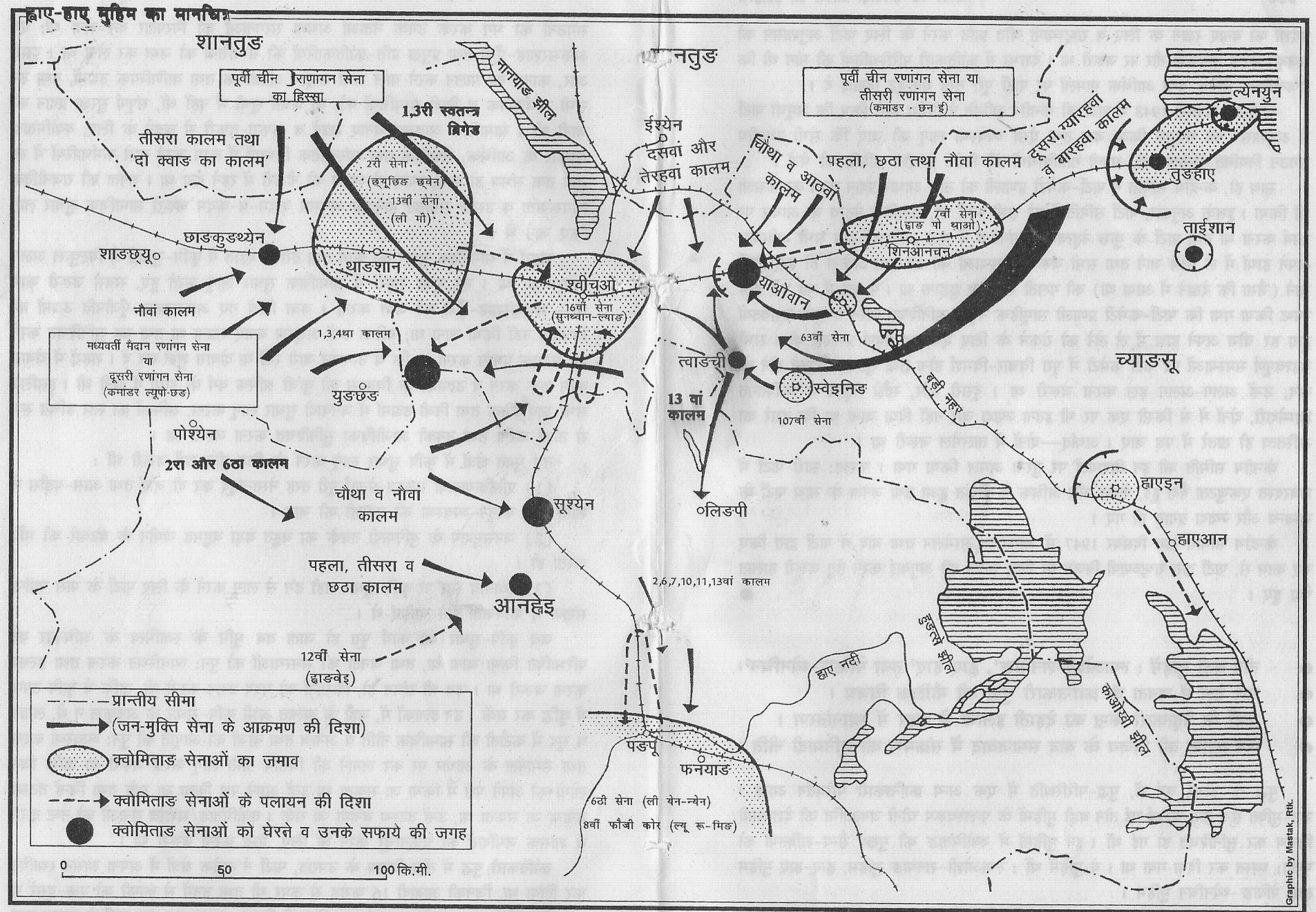

ह्वाए-ह्वाए मुहिम का मानचित्र

नोट : इस मुहिम को पूर्वी चीन रणांगन सेना और मध्यवर्ती मैदान रणांगन सेना तथा पूर्वी चीन व मध्यवर्ती मैदान की प्रादेशिक फौजों ने संयुक्त रूप से चलाया था। इसमें क्वोमिताङ के साढ़े पाँच लाख से भी अधिक सैनिकों का सफाया कर दिया गया था। यह मुहिम चीनी जन-मुक्ति युद्ध की तीन सबसे बड़ी निर्णायक मुहिमों में से एक थी तथा 6 नवम्बर 1948 से 10 जनवरी, 1949 तक चली थी।

में निर्धारित वापसी को स्थगित कर दिया जाए ।[2] लूशुन क्षेत्र चीन की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा जापानी हमले को रोकने के लिए विशेष रणनीतिक महत्त्व का क्षेत्र था । इस नए समझौते से उत्तरी चीन का समुद्र तट सुरक्षित हो गया तथा पश्चिमी प्रशान्त महासागर में जापानी सैन्यवादियों तथा उनके संश्रयकारियों के हमलावर षड्यन्त्रों को भारी धक्का लगा ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दो विरोधी शिविरों की मौजूदगी का आर्थिक परिणाम यह था कि एकमात्र सर्वव्यापी विश्व बाजार का विखंडन हो गया था तथा दो समानान्तर व विरोधी विश्व बाजारों का आविर्भाव हो गया था, यानि कि समाजवादी शिविर का बाजार, जिसमें सोवियत-संघ, चीनी लोक गणराज्य तथा दूसरे जनता के लोकतन्त्र आते थे, तथा साम्राज्यवादी शिविर का बाजार, जिसमें पूँजीवादी देश तथा उनके अनेक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े उपनिवेश व अधीन राष्ट्र आते थे ।

युद्धेतर काल में, समाजवादी शिविर के देशों ने आर्थिक सहयोग तथा परस्पर सहायता समझौतों के माध्यम से आपस में आर्थिक संबंध बनाए, लेकिन अमरीकी साम्राज्यवादियों ने नाकेबंदी तथा प्रतिबन्धों की नीतियों का अनुसरण किया तथा उम्मीद लगाई कि इस तरह वे सोवियत-संघ, चीन तथा दूसरे जनता के लोकतन्त्रों का गला घोंट देंगे । परन्तु इसका असर बिल्कुल उलटा हुआ । नया समाजवादी बाजार और अधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली हो गया।

समाजवादी बाजार के देशों के बीच के आर्थिक संबंध एक नई किस्म के थे । इन संबंधों की विशेषताएं थीं : सभी संबन्धित देशों की समानता का आदर करना, एक-दूसरे की संप्रभुता तथा आजादी की सुरक्षा, एक-दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान, परस्पर विश्वास तथा मैत्री, निकट आर्थिक संबंध तथा आपस में आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों की पुनर्स्थापना तथा अधिक विकास के लिए सामूहिक प्रयास करना ।

1949 से 1952 के काल में, सोवियत-संघ तथा दूसरे जनता के लोकतन्त्रों के साथ चीन के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई । इन देशों के साथ चीन के व्यापार का प्रतिशत, 1950 में कुल विदेशी व्यापार के 26 प्रतिशत से बढ़कर 1952 में 72 प्रतिशत हो गया । इन देशों से आयात ने चीन के आर्थिक निर्माण में अत्यधिक सहायता की । औद्योगिक उपकरण तथा साजोसामान पूर्णतया अथवा मुख्यतया इन्हीं देशों से आयात किये गये, जबकि चीन की कृषि उपज, पशु उत्पाद, खनिज तथा हस्तशिल्प, लगभग सब कुछ इन्हीं देशों को निर्यात किया गया।

समाजवादी शिविर के समृद्ध संसाधनों ने, शिविर के प्रत्येक देश को अपने आर्थिक विकास के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी, वह मुहैया की । इन देशों के मध्य सम्पन्न हुए दीर्घावधि आर्थिक समझौतों ने उनमें सहयोग के एक नए दौर का सूत्रपात किया । ऐसे दीर्घावधि आर्थिक समझौते इसलिए संभव हुए क्योंकि इन सभी देशों ने अपने आर्थिक निर्माण के लिए दीर्घावधि योजनाएँ तैयार तथा लागू की थीं । इन समझौतों से इन देशों के मध्य उपकरणों, कच्चे माल तथा जिन्सों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो गया ।

युद्धेतर काल में सोवियत-संघ के विदेश व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन आया । उसके विदेश व्यापार का बड़ा भाग (1952 में 80 प्रतिशत) समाजवादी शिविर के देशों के साथ सम्पन्न होता था । विशेषकर सोवियत संघ द्वारा अत्यधिक सहायता दिए जाने के फलस्वरूप ही, चीन तथा दूसरे जनता के लोकतंत्रों का आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से तीव्र सुदृढ़ीकरण हुआ ।

की असफलता के बाद, पार्टी ने कामरेड माओ के नेतृत्व में, अपने काम के गुरुत्व-केन्द्र को अस्थाई तौर पर शहरों से देहात में स्थानांतरित कर दिया था तथा देहात में क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र स्थापित किये थे एवं क्रान्तिकारी सैन्य-शक्ति संगठित की थी, ताकि शहरों को घेरा जा सके, और अन्ततः उन्हें मुक्त कराया जा सके । बीस वर्षों के अथक संघर्ष के बाद, यह काम अब पूरा हो गया था । अतः अब पार्टी के काम का गुरुत्व-केन्द्र देहात से शहरों में स्थानांतरित किया जाना था तथा शहरों ने देहात का नेतृत्व करना था ।

इस स्थानांतरण से कई नई समस्याएँ पैदा होनी थी, जिनका हल ढूंढ़ना जरूरी था । प्रशासनिक मामले कैसे निपटाए जाएं तथा एक शहर का निर्माण कैसे किया जाए ? पार्टी को यह सब अभी सीखना था । लम्बे समय तक देहात में रहने के कारण, पार्टी औद्योगिक उत्पादन की दोबारा बहाली तथा उसके विकास के बारे में परिचित न थी, जो कि शहरों का मुख्य कार्यभार था । इसने अभी उत्पादन की तकनीक तथा प्रबन्धन के तरीके सीखने थे । साथ ही वाणिज्य, बैंकिंग तथा अन्य किस्मों के काम भी सीखने थे, जिनका उत्पादन से निकट का संबंध था । शहरों में उत्पादन बहाल करके तथा विकसित करके ही जनता की शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता था । शहरों के प्रशासन तथा निर्माण की कुंजी श्रमिक वर्ग पर भरोसा करने में थी । पार्टी के कार्यभार का गुरुत्व-केन्द्र देहात में होने के कारण पार्टी भौगोलिक दृष्टि से काफी लम्बे समय तक श्रमिक वर्ग से कटी रही थी । शहरों में सुचारू रूप से काम करने हेतु पार्टी के लिए, अपने वर्ग पर पूरे दिल से भरोसा करना तथा शेष शहरी मेहनतकश जनता, बुद्धिजीवियों तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से एकता कायम करना अत्यंत आवश्यक था, ताकि शत्रु को पराजित किया जा सके, तथा ऐसे शहरों का निर्माण किया जा सके, जो जनता के हों । उद्योगों का निम्नलिखित क्रमानुसार विकास किया जाना था : प्रथम, राजकीय उद्यम, दूसरे, निजी स्वामित्व वाले उद्यम, तथा तीसरे, दस्तकारी उद्योग ।

अधिवेशन में आगे चलकर यह भी स्पष्ट किया गया कि क्रान्ति की देशव्यापी विजय के बाद, तीव्रगति से उत्पादन के पुनरुद्धार तथा विकास का काम किया जाए, ताकि विदेशी साम्राज्यवाद से निपटा जा सके तथा कदम-दर-कदम चीन को कृषि-प्रधान देश से औद्योगिक देश में, नव-जनवादी राज्य से समाजवादी राज्य में रूपान्तरित किया जा सके । तदनुसार अधिवेशन ने सही आर्थिक नीति को परिभाषित किया, जिसे पार्टी ने इन कार्यभारों को पूरा करने के लिए लागू करना था ।

क्रान्ति की विजय के बाद, पार्टी की आर्थिक नीति वास्तविक हालात के आधार पर तय की गई थी, अर्थात् औद्योगिक कारोबार चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केवल 10 प्रतिशत थे, जबकि कृषि लगभग 90 प्रतिशत थी । यह एक अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामंती समाज की अर्थव्यवस्था थी । यह वह बुनियादी आरंभिक बिन्दु था, जहाँ से चीनी क्रान्ति की विजय के बाद पार्टी ने आने वाले काफी लम्बे समय तक, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना था ।

प्रथम, यद्यपि चीन के आधुनिक उद्योग का अनुपात, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुल परिमाण का दस प्रतिशत था, पर यह अत्यधिक केन्द्रित था, तथा पूँजी का अधिकांश व मुख्य भाग चीनी नौकरशाह-पूँजीपतियों के हाथों में था । क्रान्ति की विजय के बाद, इस पूँजी को जब्त करने तथा इसे सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व वाले लोक गणराज्य को सौंप देने से देश के

मुख्य उद्योग-धन्धे लोक गणराज्य के नियंत्रण में आ जाने थे तथा इस राजकीय अर्थव्यवस्था ने, जिसका स्वरूप समाजवादी होना था, समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्वकारी तत्व बन जाना था । जो कोई भी इस बात को नजरअन्दाज करता, उसने निश्चय ही दक्षिणपंथी अवसरवादी गलतियां करनी थीं ।

दूसरे, बिखरी हुई कृषि तथा दस्तकारी, जो व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित थी तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का 90 प्रतिशत थी, आने वाले काफी लंबे समय तथा इनका मूल स्वरूप वैसा ही बना रहना था । जो कोई भी इस बात को नजरअन्दाज करता, उसने निश्चय ही ''वामपंथी'' अवसरवादी गलतियां करनी थीं । दूसरी तरफ उन्हें अपने आप आगे बढ़ने के लिए छोड़ देना भी गलत था । बिखरी हुई, व्यक्तिगत कृषि व दस्तकारी को, बड़ी संजीदगी से, कदम-ब-कदम और सक्रियता के साथ, आधुनिकीकरण तथा सामूहीकरण की तरफ विकसित किया जा सकता था और अवश्य किया जाना चाहिये था । सहकारी अर्थव्यवस्था को संगठित, प्रोत्साहित तथा विकसित करना बेहद जरूरी था ताकि मेहनतकश जनता का, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के स्थान पर धीरे-धीरे सामूहिक अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए, मार्गदर्शन किया जा सके । केवल इसी तरीके से समाजवादी समाज में कदम-ब-कदम पदार्पण किया जा सकता था तथा राजसत्ता पर सर्वहारा के नेतृत्व को सुदृढ़ किया जा सकता था। जो कोई भी इस बात को नजरअन्दाज करता, उसने निश्चय ही दक्षिणपंथी अवसरवादी गलतियां करनी थीं ।

तीसरे, चीन का निजी पूँजीवादी उद्योग भी एक ऐसी शक्ति था, जिसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता था । चूंकि चीन के राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग और उसके प्रतिनिधियों ने अक्सर जनता के जनवादी क्रान्तिकारी संघर्षों में भाग लिया था और चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई थी, इसलिए क्रान्ति की विजय के बाद, जहां तक भी संभव हो सके, शहरी तथा ग्रामीण पूँजीपति वर्ग के सकारात्मक तत्वों को, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने के काम में शामिल करना बेहद जरूरी था । लेकिन पूँजीवाद में मुक्त प्रतिस्पर्द्धा तथा मुक्त व्यापार के क्षेत्रों पर अंकुश जरूरी था, ताकि उनका अबाध व अनियंत्रित विकास व फैलाव न हो । प्रतिबन्ध लगाने की इस नीति का, पूँजीपति वर्ग द्वारा, विभिन्न दर्जों और विभिन्न रूपों में, निश्चत तौर पर विरोध होना था । फलतः जनता के जनवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में, प्रतिबन्ध लगाना और प्रतिबन्धों का विरोध करना वर्ग-संघर्ष का मुख्य रूप होना था । ऐसा सोचना कतई गलत था कि पूँजीवाद पर प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत नहीं थी । यह एक दक्षिणपंथी अवसरवादी दृष्टिकोण होना था । दूसरी तरफ, यह सोचना भी कतई गलत था कि निजी पूँजीवाद को बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता था।

राजकीय स्वामित्व वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था के नेतृत्व में, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का सहकारिता के माध्यम से रूपान्तरण करना तथा निजी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का राजकीय-पूँजीवाद के माध्यम से रूपान्तरण करना—यही वह संबंध था जो **चीनी लोक गणराज्य की अर्थव्यवस्था के पाँच मुख्य तत्वों**[5] के बीच रहना था ।

मजदूर वर्ग व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व, तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजदूर वर्ग के नियंत्रण के तहत राजकीय स्वामित्व वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था की अग्रणी भूमिका ने, चीन के कदम-दर-कदम समाजवाद में पर्दापण को सुनिश्चित करना था ।

दो विशाल देशों, चीन व सोवियत-संघ, की समृद्धि पर ही प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि मानवता के भविष्य तथा विश्व-शान्ति व न्याय की विजय को भी प्रभावित करेगी ।''

हमले के विरोध तथा शान्ति की रक्षा के लिए, मैत्री, संश्रय तथा परस्पर सहयोग की चीन-सोवियत संधि व अन्य समझौतों में व्यवस्था की गई थी कि जापानी सैनिकवाद के पुनरुत्थान तथा जापान द्वारा अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा, जो हमले की कार्यवाहियों में जापान के साथ गठजोड़ कर सकता हो, पुनः हमले व शान्ति के उल्लंघन को रोका जाए । संधि के अनुसार:

''अनुबन्ध करने वाले एक पक्ष पर जापान द्वारा अथवा उसके किसी अन्य सहयोगी राज्य द्वारा हमला किये जाने तथा इस प्रकार उसके (अनुबन्धित पक्ष) युद्ध में उलझ जाने की हालत में, अनुबन्ध करने वाला दूसरा पक्ष, उसके पास मौजूद हर प्रकार के संसाधनों से, तुरन्त फौजी तथा दूसरी मदद मुहैया करेगा ।''

इसका अर्थ था कि यदि जापानी सैन्यवादी तथा उनके संश्रयकारी चीन पर हमला करने की जुर्रत करें, तो उन्हें दो विशाल देशों, चीन व सोवियत-संघ से करारा जवाब मिले । चीन तथा सोवियत-संघ के बीच की मैत्री, संश्रय, परस्पर सहायता तथा आपसी सहयोग, ये सुदूरपूर्व में शान्ति के स्तंभ थे तथा विश्व-शान्ति को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व थे ।

सन्धि तथा समझौते, चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा समाजवादी निर्माण के कार्यभारों को संपन्न करने के लिए भी विशेष महत्त्व के थे । चीन को ऋण देने के समझौते के अनुसार, सोवियत-संघ ने चीन को पाँच वर्ष की अवधि में, 30 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण देना था (एक प्रतिशत सलाना ब्याज की दर पर) । विभिन्न प्रकार की दूसरी आर्थिक व तकनीकी सहायता भी थी, जैसे कि—बिजली घरों, अभियान्त्रिकी के कारखानों, खनन, रेल-यातायात तथा रेलों वगैरह के लिए उपकरण । चीन सरकार के निमन्त्रण पर बहुत से सोवियत विशेषज्ञ चीन आए । अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की पवित्र भावना से ओतप्रोत इन विशेषज्ञों ने पूर्णतया निःस्वार्थ भावना से काम किया तथा खुले दिल से चीन को उद्योग, परिवहन, कृषि, जल-संसाधन तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में अपना उन्नत तकनीकी अनुभव प्रदान किया ।

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा चीन के विरुद्ध लगातार हमले तथा जापानी प्रतिक्रियावादी गुट के साथ गठजोड़ करके, जापानी सैनिकवाद के पुनरुत्थान को तीव्रता प्रदान करने व एक नया युद्ध शुरू करने के उनके प्रयासों ने चीन की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा कर दिया तथा एशिया व विश्व की शान्ति को भंग कर दिया ।

सितंबर 1952 में, चीनी तथा सोवियत सरकारों के प्रतिनिधियों ने, दोनों देशों से संबंधित, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं पर मास्को में विचार-विमर्श किया । इस वार्ता के दौरान, 14 फरवरी, 1950 को संपन्न, चीनी छाङछुन रेलमार्ग, लूशुन बंदरगाह (पोर्ट आर्थर), तथा ताल्येन (डाएरन) से संबन्धित चीन-सोवियत समझौते पर भी विचार-विमर्श हुआ । इस बारे में यह सहमति हुई कि समझौते में निर्धारित तिथि को सोवियत संघ, संयुक्त रूप से प्रशासित चीनी छाङछुन रेलमार्ग के अपने सारे अधिकार, बिना मुआवजे के चीन को लौटा दे। साथ ही, सोवियत सरकार, चीन के इस सुझाव पर भी सहमत हो गई कि संयुक्त रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले **लूशुन के चीनी नौसैनिक अड्डे से सोवियत सैनिकों की, सन्धि**

डेनमार्क, बर्मा, इंडोनेशिया, स्विटजरलैंड, फिनलैंड तथा पाकिस्तान ने भी **राजनयिक संबंध**[1] कायम कर लिये ।

सोवियत-संघ, चीन तथा दूसरे जनता के लोकतन्त्रों ने सोवियत-संघ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली तथा संयुक्त समाजवादी शिविर का गठन किया । इस शिविर का निर्माण, तथा सबसे अधिक, सोवियत-संघ की मौजूदगी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति थी जो चीन के आर्थिक पुनरुद्धार तथा समाजवादी निर्माण के अनुकूल थी ।

चीनी लोक गणराज्य ने हमेशा दृढ़ता से सोवियत-संघ की अगुवाई वाले समाजवादी शिविर का साथ दिया तथा दोनों देशों के बीच के मैत्री संबंधों को मजबूत करने के भरपूर प्रयास किये। 16 दिसंबर, 1949 को अध्यक्ष माओ त्से-तुङ ने सोवियत-संघ की यात्रा की । दोनों देशों के राजनीतिक इतिहास में यह एक बेहद महत्त्वपूर्ण घटना थी । कामरेड माओ तथा कामरेड स्तालिन ने वार्ता में सीधे हिस्सा लिया तथा मैत्री, संश्रय तथा परस्पर सहयोग की चीनी-सोवियत संधि; चीन के छाङछुन रेलमार्ग, लूशुन बन्दरगाह (पोर्ट आर्थर) तथा ताल्येन (डाएरन) बंदरगाह के बारे में चीनी-सोवियत समझौता; तथा चीन को ऋण देने संबंधी चीन-सोवियत समझौता—ऐतिहासिक महत्त्व के इन तीनों समझौतों/संधियों पर 14 फरवरी, 1950 को मास्को में हस्ताक्षर हुए । चीनी सरकार की तरफ से विदेश मंत्री चओ एन-लाई ने तथा सोवियत-संघ की सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ए०वाई० विशिन्सकी (A.Y. Vyshinsky) ने हस्ताक्षर किये । इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने से, चीनी जनता तथा सोवियत जनता, साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध महान संघर्ष में तथा विश्व-शान्ति को सदैव बनाए रखने हेतु अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो गई। साथ ही अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हो गए । 17 फरवरी, 1950 को, मास्को रेलवे स्टेशन पर अपने विदाई भाषण में कामरेड माओ ने कहा :

"सभी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोवियत तथा चीनी जनता के बीच की मैत्री जिसे एक संधि द्वारा पुष्ट किया गया है, शाश्वत, अटूट तथा अविभाज्य होगी ।"

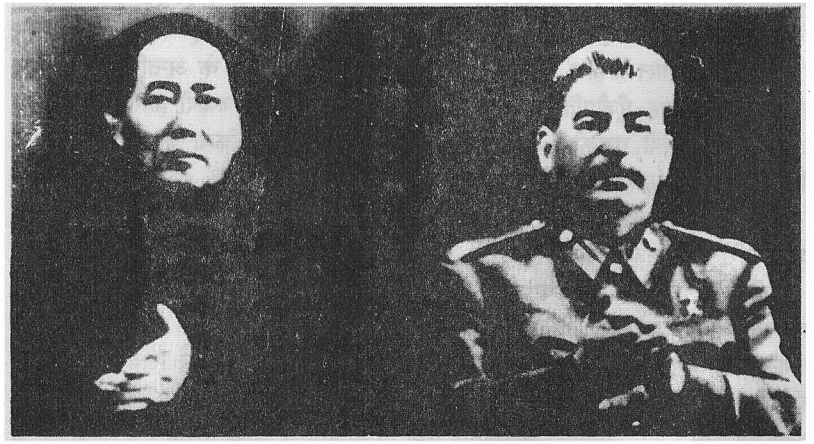

कामरेड माओ त्से-तुङ एवं कामरेड जोसेफ स्तालिन

ये सिद्धान्त, बाद में आम कार्यक्रम में सूत्रबद्ध की गई आर्थिक नीति की आधारशिला बने।

अन्त में, अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया कि देशव्यापी विजय प्राप्त करना तो दस हजार ली (पाँच हजार किलोमीटर) लम्बे अभियान का मात्र पहला कदम होना था और आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा लम्बा था तथा काम और ज्यादा विशाल एवम् कठिन था । नव-जनवादी क्रान्ति की विजय के पश्चात भी चीन में दो बुनियादी अन्तर्विरोध जारी रहने थे—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी जनता तथा साम्राज्यवादियों के बीच का अन्तर्विरोध तथा देश के अन्दर सर्वहारा तथा पूँजीपति वर्ग के बीच का अन्तर्विरोध । अतः पार्टी के सभी सदस्यों का आह्वान किया गया कि वे अपनी राजनीतिक सतर्कता को बढ़ाएं तथा ठण्डे दिमाग से काम लें, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा ऐसी कार्यशैली अपनाएं जिससे वे हर बाधा तथा हर मुश्किल का सामना कर सकें । सभी सशस्त्र दुश्मनों को चकनाचूर करने के बाद, ऐसे शत्रु भी बने रहेंगे जो हथियारबन्द नहीं होंगे और वे अनिवार्य तौर पर छुपे रूप में जबरदस्त संघर्ष करेंगे । इसलिए ऐसे शत्रुओं को किसी भी हालत में कमजोर समझने की भूल नहीं करनी थी । पार्टी सदस्यों को पूँजीपति वर्ग की "मीठी गोलियों" से भी लगातार होशियार रहने को कहा गया, ताकि वे उनकी सिद्धान्तहीन चापलूसी से कमजोर अथवा पथभ्रष्ट न हो जाएँ ।

इस अधिवेशन में क्रान्ति की विजय के बाद देश में मौजूद रहने वाले अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों का भी विश्लेषण किया गया । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी चरित्र की राजकीय स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था की नेतृत्वकारी भूमिका पर बल दिया गया । इसके साथ ही विभिन्न आर्थिक तत्वों के प्रति पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न विशिष्ट नीतियों को भी निर्धारित किया गया । इसी आधार पर, चीन के समाजवाद में पदार्पण के बुनियादी सिद्धान्तों को तय किया गया ।

●

4.

- **पार्टी का मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवादी अधिनायकत्व वाले राज्य का सिद्धान्त ।**
- **चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन तथा आम कार्यक्रम का निर्धारण ।**
- **चीनी लोक गणराज्य की स्थापना ।**
- **चीनी क्रान्ति की विजय का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व ।**

1949 में जन-मुक्ति सेना ने क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों की बची-खुची फौजी शक्तियों को इतनी तेजी तथा दृढ़ता से नष्ट कर दिया, जैसे पतझड़ में हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती है । क्रान्ति ने समूचे देश में बुनियादी विजय प्राप्त कर ली थी । विभिन्न जनवादी पार्टियों तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन को बुलाने तथा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की तैयारी करने के कार्यों में भाग लिया । इस परिस्थिति में अनेक सवाल मुंह बाए खड़े थे, जिनका कम्युनिस्ट पार्टी को जवाब देना था । ये सवाल थे :

❑ चीनी लोक गणराज्य किस तरह का राज्य होगा ?

- ❑ ऐसे राजा में विभिन्न वर्गों की क्या स्थिति होगी तथा उनके आपसी संबंध कैसे होंगे?
- ❑ अन्ततः, इसका भविष्य क्या होगा ?

कामरेड माओ ने 1 जुलाई, 1949 को प्रकाशित—**"जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बारे में"** शीर्षक अपने लेख में इन सभी सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया ।

स्वरूप की दृष्टि से चीनी लोक गणराज्य कम्युनिस्ट पार्टी तथा मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता का जनवादी अधिनायकत्व होना था तथा श्रमिकों व किसानों के संश्रय पर आधारित होना था । असीम कठिनाइयों में से गुजरने के बाद ही चीनी जनता ने इस रास्ते की खोज की थी । 1840 के अफीम युद्ध में चीन की हार होने के समय से ही चीन के प्रगतिशील व्यक्तियों ने पश्चिमी पूँजीवादी देशों से राष्ट्रीय मुक्ति का तरीका सीखने हेतु असंख्य मुसीबतें उठाई । तब से लेकर, 1911 की क्रान्ति के कुछ वर्षों बाद तक, उन्होंने पूँजीवादी गणराज्य की तर्ज पर तथा पूँजीवाद की दिशा में चीन के लिए रास्ता ढूंढने का लगातार प्रयास किया था । परन्तु चीन में पूँजीवादी गणराज्य तथा पूँजीवादी समाज की स्थापना करना असंभव सिद्ध हुआ था, क्योंकि चीनी पूँजीपति वर्ग विदेशी साम्राज्यवाद तथा घरेलू सामंतवाद को हराकर जीत हासिल करने हेतु जनता की अगुवाई करने में सक्षम न था । फलतः चीनी जनता की नजरों में पूँजीवादी गणराज्य तथा पूँजीवादी जनवाद का कार्यक्रम दिवालिया साबित हो चुका था ।

अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के बाद ही चीन के प्रगतिशीलों ने पूँजीवाद के पतन तथा समाजवाद के शानदार भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया । उन्हें पक्का यकीन हो गया कि समाजवाद ही, न कि पूँजीवाद, चीन की समस्याओं के समाधान की कुंजी था । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, 1921 में अपने जन्म के समय से ही, जनता की जनवादी क्रान्ति के, अर्थात्—नव-जनवादी क्रान्ति के नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा ली थी । चार क्रान्तिकारी युद्धों से गुजरने के बाद, आखिरकार 1949 में जनक्रान्ति की महान विजय हुई थी। इस विजय से यह स्पष्ट हो गया कि नव-जनवाद से समाजवाद की ओर जाने का रास्ता ही चीन की मुक्ति का एकमात्र रास्ता था, तथा श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में लोक गणराज्य की स्थापना ही राज्य का एकमात्र स्वरूप था, जिसे चीन में स्थापित किया जा सकता था । इतिहास ने सिद्ध कर दिया था कि पूँजीवादी जनवाद का स्थान, श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवाद ने लेना था तथा पूँजीवादी गणराज्य का स्थान लोक गणराज्य ने लेना था । इस कारण चीनी लोक गणराज्य का स्वरूप श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में जनता का जनवादी अधिनायकत्व होना था तथा उसे श्रमिक-किसान संश्रय पर आधारित होना था ।

जनता के जनवादी अधिनायकत्व ने एक निश्चित किस्म का वर्ग संश्रय होना था । श्रमिक वर्ग तथा किसान समुदाय के बीच के संश्रय ने इस अधिनायकत्व का आधार होना था । व्यापक किसान समुदाय ने समाजवादी क्रान्ति में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा करनी थी तथा समाजवादी निर्माण के दौरान खेती-बाड़ी ने औद्योगिक विकास का आधार बनना था । अतः पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के काल के दौरान ऐसे संश्रय पर भरोसा करना बेहद जरूरी था । मजदूर-किसान संश्रय के अभाव में समाजवाद को साकार करना असंभव था ।

जनता के जनवादी अधिनायकत्व में मेहनतकश जनता तथा मेहनत न करने वाले लोगों, अर्थात्—मजदूर वर्ग तथा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के दरम्यान भी संश्रय स्थापित होना था । लोक गणराज्य में, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा उसकी पार्टियों के प्रतिनिधि, क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्रों

चौदहवां अध्याय

पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति की विजय के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुनः बहाली तथा रूपान्तरण

(अक्तूबर 1949 से 1952)

1.

- **चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के बाद समाजवादी शिविर की बढ़ती शक्ति ।**
- **दो विश्व बाजारों का प्रादुर्भाव ।**

चीनी लोक गणराज्य की स्थापना से, मुख्यतः चीनी क्रान्ति की पूँजीवादी-जनवादी मंजिल का समापन हो गया तथा इसकी दूसरी मंजिल, समाजवादी मंजिल का शुभारंभ हो गया । इस मंजिल का कार्यभार चीन में एक समाजवादी समाज का निर्माण करना था ।

चीन में लोक गणराज्य की स्थापना के बाद पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण काल आरंभ हो गया । समाजवादी समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी था कि इस कालावधि में समाजवादी औद्योगीकरण किया जाए तथा कृषि, दस्तकारी तथा पूँजीवादी उद्योगों व वाणिज्य का समाजवादी रूपान्तरण किया जाए । परन्तु इसका यह मतलब नहीं था कि ये दोनों विशाल कार्य, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के तुरंत बाद, हर क्षेत्र में शुरू हो जाने थे । इस कालावधि के पहले कुछ वर्षों में यह जरूरी था कि सबसे पहले, लम्बे गृहयुद्ध द्वारा दिए गए घावों पर मरहम लगाई जाए तथा सामाजिक सुधार लागू किये जाएं, अर्थात्—कृषि-सुधार लागू किये जाएं तथा विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में जनवाद व सामंतवाद के बीच के अन्तर्विरोधों को हल किया जाए, नौकरशाह-पूँजीपति कारोबारों को जब्त करके उन्हें समाजवादी कारोबारों का रूप दिया जाए, समाजवादी राजकीय अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार किया जाए तथा शहरों में निजी पूँजीवाद का समाजवादी रूपान्तरण करना शुरू किया जाए ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा रूपान्तरण के लिए, घर तथा बाहर, दोनों जगह अनुकूल परिस्थितियों का होना जरूरी था । ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं ।

चीनी लोक-गणराज्य की स्थापना का पूरे विश्व की जनता ने स्वागत किया । चीनी जनता के महानतम तथा सच्चे मित्र सोवियत-संघ ने चीनी लोक गणराज्य के जन्म के अगले ही दिन उसे मान्यता प्रदान कर दी तथा उसके साथ राजनयिक संबंध कायम कर लिये । जनता के लोकतन्त्रों—बुल्गारिया, रुमानिया, हंगरी, कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैन्ड, [illegible], जर्मन जनवादी गणराज्य (पूर्वी जर्मनी), अल्बानिया तथा वियतनामी जनवादी गणराज्य—ने भी जल्दी ही चीनी लोक गणराज्य को मान्यता प्रदान कर दी । इन देशों के अलावा भारत, स्वीडन,

शासन को उखाड़ फेंका (साम्राज्यवादियों ने चीन में लगभग 100 वर्षों तक तथा क्वोमिंताङ ने 22 वर्षों तक शासन किया था), तथा जनता के जनवादी अधिनायकत्व के तहत, महान चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की । तब से चीनी जनता स्वयं अपनी भाग्य-विधाता है ।

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा शस्त्रास्त्रों से लादे गये क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों पर चीनी जनता की विजय में बहुत सी बातों ने योगदान दिया । क्रान्तिकारी लोकयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शुरू हुआ था, जब शान्ति, जनवाद तथा समाजवाद के शिविर की ताकत बढ़ रही थी तथा विश्व-साम्राज्यवाद का और ज्यादा ह्रास हो रहा था । इस प्रकार युद्धेतर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति चीनी जनता के अनुकूल तथा चीनी एवम् अमरीकी प्रतिक्रियावादियों के प्रतिकूल थी । जापानी हमले के खिलाफ आठ वर्ष तक चले प्रतिरोध-युद्ध में फौलाद बन चुकी चीनी जनता ने अपनी राजनीतिक चेतना व सांगठनिक योग्यता का बहुत ज्यादा विकास कर लिया था तथा शक्तिशाली मुक्त-क्षेत्रों एवम् जन-मुक्ति सेना का निर्माण कर लिया था, जिन्होंने अन्दरूनी तथा बाहरी प्रतिक्रियावादी शत्रुओं को हराने हेतु, चीनी जनता को ठोस आधार प्रदान किया । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त की रोशनी में, प्रतिक्रियावादियों को हराने के लिए राजनीतिक तथा सैनिक नीतियों, एवम् समूची जनता की मुक्ति के लिए ग्रामीण व शहरी नीतियों को सही तरीके से सूत्रबद्ध किया । इसके फलस्वरूप, चीनी जन-मुक्ति सेना तेजी से रक्षा से आक्रमण की कार्यवाही पर उतर आयी तथा असुविधाजनक स्थिति से सुविधाजनक स्थिति में आ गई । इस प्रकार नव-जनवादी क्रान्ति की विजय हुई तथा समाजवाद में संक्रमण की मंजिल की शुरुआत हो गई ।

●

नोट

1. **ल्याओशी-शनयाङ मुहिम :-** विस्तृत जानकारी के लिए देखें, माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976 का **'ल्याओशी-शनयाङ मुहिम के लिए फौजी कार्यवाही संबंधी नीति'** शीर्षक अध्याय, पृष्ठ-435 से 446 तक ।

2. **ह्वाए-हाए मुहिम :-** देखें, उपरोक्त ग्रन्थ का **'ह्वाए-हाए मुहिम के लिए फौजी कार्यवाही संबंधी नीति'** शीर्षक अध्याय, पृष्ठ-469 से 476 तक ।

3. **पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम :-** देखें, उपरोक्त ग्रन्थ का **'पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम के लिए फौजी कार्यवाही संबंधी नीति'** शीर्षक अध्याय, पृष्ठ-491 से 500 तक ।

4. **अन्दरूनी शान्ति समझौता :-** देखें, माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976 के **'सेना को देशव्यापी पेशकदमी के लिए आदेश'** शीर्षक अध्याय का नोट-1, पृष्ठ 660 से 673 तक ।

5. **चीनी लोक गणराज्य की अर्थव्यवस्था के पाँच मुख्य तत्व :-** ये तत्व इस प्रकार थे : 1. राजकीय स्वामित्व वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था, 2. सहकारी अर्थव्यवस्था, 3. राजकीय-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, 4. निजी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा 5. व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ।

6. **जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बारे में :-** विस्तृत जानकारी के लिए देखें, माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976 के पृष्ठ-695 से 722 तक ।

●●●

के कालखण्ड की तुलना में, ज्यादा संख्या में शामिल होंगे, तथा वे लोग समाजवाद के निर्माण हेतु मजदूर वर्ग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राजनीतिक संश्रय बनाए रखेंगे । भूतकाल में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने आधुनिक उद्योग का विकास किया था, पुरानी जनवादी क्रान्ति का नेतृत्व किया था, तथा कुछ हद तक नव-जनवादी क्रान्ति में भी भाग लिया था। देशव्यापी विजय के पश्चात, इसने मजदूर वर्ग के नेतृत्व को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की थी । इसके अतिरिक्त यह वर्ग संक्रमणकाल के दौरान एक निश्चित भूमिका अदा कर सकता था क्योंकि इसके पास आधुनिक विज्ञान एवं संस्कृति का अच्छा ज्ञान था तथा बुद्धिजीवियों व विशेषज्ञों का एक अच्छा खासा विशाल भंडार था । समाजवादी क्रान्ति के दौरान, मजदूर वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग के बीच की मैत्री ने पूँजीपति वर्ग के सदस्यों को शिक्षित करने तथा पुनः गढ़ने में सक्रिय भूमिका अदा करनी थी । परन्तु राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग क्रान्ति का नेतृत्व नहीं कर सकता था, और न ही उसे राजसत्ता में मुख्य स्थान मिलना चाहिये था ।

जनता के जनवादी अधिनायकत्व वाले राज्य ने जनता के लिए जनवाद लागू करना था तथा प्रतिक्रियावादियों के ऊपर अधिनायकत्व लागू करना था । इसने जनता की रक्षा करनी थी तथा उन्हें जनवादी हक हासिल होने थे । सिर्फ जनता का अपना राज्य कायम होने पर ही, जनता जनवादी तरीका लागू करके अपने को शिक्षित कर सकती थी तथा अपना पुनः संस्कार कर सकती थी, एवम् घरेलू व विदेशी प्रतिक्रियावादियों के असर से अपना पिण्ड छुड़ा सकती थी, पुराने समाज की विरासत—बुरी आदतों और बुरे विचारों—से छुटकारा प्राप्त कर सकती थी तथा आगे प्रगति करना जारी रख सकती थी । किसानों को शिक्षित करना एक गंभीर समस्या थी । किसान छोटे स्वामी थे । उन्हें समाजवाद के मार्ग पर ले जाने के लिए काफी समय एवम् काफी मेहनत की जरूरत थी । राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के सदस्यों को शिक्षित करना तथा उनका पुनः संस्कार करना भी जरूरी था, ताकि उन्हें मजदूर वर्ग का नेतृत्व स्वीकार के लिए जागृत किया जा सकता । बाद में, जब निजी कारोबारों के राष्ट्रीयकरण का समय आना था, तब उन्हें शिक्षित करने तथा उनका पुनः संस्कार करने के काम को एक कदम और आगे बढ़ाना था ताकि पूँजीवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके ।

चीन में साम्राज्यवाद के पालतू कुत्तों—जमींदार वर्ग, नौकरशाह-पूँजीपति वर्ग, तथा इन दोनों वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों—को जनता के जनवादी अधिनायकत्व वाले राज्य में, उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाना था । फिर भी, यदि ये लोग बगावत या तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल नहीं होते तो उन्हें भी अपनी जीविका चलाने तथा श्रम के जरिये अपने आपको आत्मनिर्भर श्रमिकों के रूप में ढाल लेने के लिए जमीन अथवा काम दिये जाने थे ।

चूंकि साम्राज्यवादी तथा घरेलू प्रतिक्रियावादी अभी मौजूद थे तथा देश में अभी वर्ग भी मौजूद थे, अतः जनता के राज्य-तन्त्र की शक्ति को बढ़ाना, यानि कि जनता की सेना, जनता की पुलिस तथा जनता की अदालतों को मजबूत करना एक बेहद फौरी तथा महत्त्वपूर्ण कार्यभार था, ताकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके तथा जनता के हितों की रक्षा की जा सके, तथा इस आधार के ऊपर चीन को कदम-ब-कदम एक समाजवादी व साम्यवादी समाज में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके । और वह समय आने पर, वर्गों ने खत्म हो जाना था तथा राज्य-मशीनरी ने भी अपनी उपयोगिता पूरी कर समाप्त हो जाना था ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोक गणराज्य ने सोवियत-संघ, जनता की लोकशाहियों तथा सभी देशों की जनता से एकता स्थापित करनी थी । इसने सोवियत-संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे का अंग होना था । चीनी जनता के लिए सच्ची मित्रता तथा मदद केवल इसी शिविर से ली जानी थी, साम्राज्यवादी शिविर से नहीं । दोनों शिविरों के बीच तटस्थता या ढुलमुलपन का सवाल ही पैदा नहीं होना था ।

लोक गणराज्य की स्थापना हेतु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशन में, जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन आयोजित किया गया, चीनी जनता का अंतरिम घोषणापत्र (provisional charter)—सामान्य कार्यक्रम—सूत्रबद्ध किया गया, तथा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की गई ।

काफी समय पहले, 1 मई, 1948 को पार्टी की केन्द्रीय समिति ने एक नये राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन को आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसमें प्रतिक्रियावादियों को भाग नहीं लेने दिया जाना था । इस आह्वान का देश के सभी जनवादी वर्गों तथा पार्टियों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया । इसी वर्ष के 25 नवंबर को विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि ऐसा सम्मेलन आयोजित करने तथा इसमें प्रतिनिधित्व की गुंजाइश के सवाल पर विचार-विमर्श करने हेतु उत्तर-पूर्व में इकट्ठे हुए । सभी प्रतिनिधि इस बात पर एकमत थे कि नए चीन की स्थापना के लिए, नव-जनवाद इसका राजनीतिक आधार होना चाहिये तथा नए राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी लोग साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा नौकरशाह-पूँजीवाद के पूर्ण विरोधी होने चाहिएं । अतः यह फैसला किया गया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि केवल निम्नलिखित श्रेणियों से ही होने चाहियें : मजदूर वर्ग, किसान समुदाय, निम्न-पूँजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग तथा प्रतिक्रियावादी वर्गों से अलग हो चुके देशभक्त जनवादी तत्व। पेकिङ, थ्येनचिन, नानकिङ, शंघाई तथा ऊहान के सफलतापूर्वक मुक्त होने के बाद, बचे-खुचे क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों का सफाया करने, जनता की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति की पुनर्स्थापना तथा विकास करने, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को मजबूत करने तथा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना करने हेतु, 21 सितंबर, 1949 को, पेकिङ में, चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के पहले सत्र का आयोजन किया गया । जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का स्वरूप व्यापक प्रतिनिधित्व वाला था तथा यह समूचे देश की इच्छा का द्योतक था। सम्मेलन राष्ट्रीय जन-कांग्रेस की, जिसका आयोजन अभी होना था, सभी शक्तियों का उपयोग कर रहा था तथा उसके कार्यों का निपटारा कर रहा था ।

सम्मेलन में चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का सामान्य कार्यक्रम, चीनी लोक गणराज्य की केन्द्रीय जन-सरकार का मूलभूत-कानून (Organic Law) तथा चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का मूलभूत कानून (Organic Law) स्वीकृत किया गया ।

सामान्य कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी कि चीनी लोक गणराज्य का स्वरूप, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवादी अधिनायकत्व का होना चाहिये, जो मजदूर-किसान संश्रय पर आधारित हो तथा देश के सभी जनवादी वर्गों तथा सभी राष्ट्रीयताओं को एकजुट करके बना हो । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पाँच तत्वों के दरम्यान आपसी संबंधों के सवाल पर सामान्य कार्यक्रम में व्यवस्था की गई थी कि राजकीय स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था की अगुवाई में, अर्थव्यवस्था के पाँचों तत्व श्रम का विभाजन करें तथा उसमें तालमेल स्थापित करें, तथा कुल

हमलावर नीतियों के दिवालिएपन की घोषणा कर दी थी, तथा साथ ही चीन को गुलाम बनाने के उनके षड्यन्त्रों को विफल कर दिया था । फलतः इस क्रान्ति की विजय ने साम्राज्यवादियों पर करारी चोट की तथा उनकी ताकत को कमजोर कर दिया, पूँजीवाद के आम संकट को और गहरा कर दिया, पूँजीवादी शासन के आसन्न अंत की घोषणा कर दी, तथा समूची दुनिया की मेहनतकश जनता की अन्तिम विजय को गति प्रदान की । इसके अतिरिक्त, विजय प्राप्ति के बाद, चीनी जनता दृढ़ता से शान्ति, जनवाद तथा समाजवाद के शिविर के पक्ष में खड़ी हुई तथा उसने स्वयं को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण शक्ति सिद्ध किया, तथा इस प्रकार हमलावर साम्राज्यवादी शिविर के खिलाफ शान्ति, जनवाद तथा समाजवाद के शिविर का पलड़ा भारी कर दिया ।

दूसरे, चीनी क्रान्ति एक ऐसी क्रान्ति थी, जो पूर्व में साम्राज्यवादी दमन के शिकार, 60 करोड़ जनसंख्या वाले, सबसे बड़े अर्ध-औपनिवेशिक देश में घटित हुई थी । इस क्रान्ति की विजय से पूर्व के दबे-कुचले राष्ट्रों को हौंसला तथा प्रेरणा मिली तथा इसने विजय में उनके विश्वास को मजबूत कर दिया । वे स्थान जहां साम्राज्यवादियों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अंधी लूट मचाई हुई थी, साम्राज्यवाद-विरोधी क्रान्तिकारी तूफानों का केन्द्र बन चुके थे, या बनते जा रहे थे ।

तीसरे, चीनी जन-क्रान्ति की विजय मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लिए एक नई विजय थी । इसने यह सिद्ध कर दिया कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद ही, चीनी जनता की मुक्ति के लिए तथा दूसरे सभी दबे-कुचले लोगों की मुक्ति के लिए, एकमात्र सच्चा पथ-प्रदर्शक था । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, साथी माओ त्से-तुङ के नेतृत्व में, मार्क्सवादी-लेनिनवादी रुख, दृष्टिकोण तथा तरीका अपनाते हुए, चीनी क्रान्ति के सवाल को वैज्ञानिक तथा सिलसिलेवार ढंग से हल किया । अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के बाद, यह एक और महान क्रान्ति थी, परन्तु यह अलग किस्म की थी, क्योंकि यह साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीड़ित देश में घटित हुई थी । इसने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद एक गतिशील शक्ति था तथा यह केवल साम्राज्यवादी देश में ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक अथवा अर्ध-औपनिवेशिक देशों में भी सफलतापूर्वक क्रान्ति का मार्गदर्शन कर सकता था ।

चीन में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विजय ने, एशिया तथा शेष विश्व के दबे-कुचले देशों के मजदूर वर्ग तथा व्यापक जनता को, जनवादी क्रान्ति के रास्ते पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने तथा विजय प्राप्ति के बाद समाजवाद के रास्ते पर और आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया । ●

● तीसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध का सारांश

जून 1946 में, च्याङ काई-शेक गुट ने—दुनिया के सबसे बड़े गद्दार गुट ने—विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति अमरीका की मदद से; चीनी जनता की शान्ति के लिए इच्छा को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शान्ति कायम रखने के लिए किये गए प्रयासों को, तथा विश्वभर की जनवादी जनता के विरोध को दरकिनार करते हुए ; अभूतपूर्व पैमाने पर प्रति-क्रान्तिकारी गृहयुद्ध छेड़ दिया । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, चीनी जनता ने चार वर्षों के बहादुराना संघर्ष के बाद, साम्राज्यवादियों तथा क्वोमिंताङ के काले एवम् प्रतिक्रियावादी

मिलाकर सामाजिक अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करें। **इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग के नेतृत्व को तथा आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी स्वरूप वाली राजकीय स्वामित्व की अर्थव्यवस्था के नेतृत्व को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। चीनी लोक गणराज्य की समाजवाद में संक्रमण करने की यह एक मुख्य गारंटी थी।**

चीनी लोक गणराज्य की केन्द्रीय जन-सरकार के मूलभूत कानून में राजसत्ता के जिस स्वरूप की व्यवस्था की गई थी, वह जनता के जनवादी अधिनायकत्व के स्वरूप से मेल खाता था, अर्थात्—यह जनवादी केन्द्रीयतावाद पर आधारित जन-कांग्रेसों की प्रणाली था। यह प्रणाली, जिसमें जनता के लिए पूर्ण जनवाद तथा साथ ही प्रतिक्रियावादी वर्गों के प्रति प्रभावकारी अधिनायकत्व सुनिश्चित किया गया था, पूँजीवादी संसदीय प्रणाली से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ थी।

चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के मूलभूत कानून में व्यवस्था की गई थी कि जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन, समस्त जनता के जनवादी संयुक्त मोर्चे का सांगठनिक ढाँचा होना चाहिये, तथा इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न जनवादी पार्टियों तथा जन-संगठनों के माध्यम से देश के सभी जनवादी वर्गों तथा सभी राष्ट्रीयताओं को एकताबद्ध करना था, ताकि जनता के जनवादी अधिनायकत्व के तहत चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की जा सके तथा उसे मजबूत बनाया जा सके।

जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन ने माओ त्से-तुङ को केन्द्रीय जन-सरकार के अध्यक्ष तथा चू तेह, ल्यू शाओ-ची, सुङ छिङ-लिङ तथा कुछ दूसरे लोगों को उपाध्यक्ष के रूप में चुना। नए राज्य का उद्घाटन 1 अक्तूबर, 1949 को संपन्न हुआ। अध्यक्ष माओ त्से-तुङ ने चीनी लोक गणसज्य तथा केन्द्रीय जन-सरकार की स्थापना की घोषणा करते हुए समूचे विश्व के नाम पर संदेश जारी किया। इसके बाद चीनी इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ।

चीनी लोक-गणराज्य की स्थापना से, मुख्यतया, चीनी क्रान्ति की पहली मंजिल, यानि कि नव-जनवादी क्रान्ति की मंजिल पूरी हो गई तथा इसने दूसरी मंजिल, यानि कि समाजवादी क्रान्ति की मंजिल की शुरुआत की घोषणा कर दी।

चीनी जन-क्रान्ति की विजय तथा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना से चीन के इतिहास में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। 1917 की अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति तथा 1945 में फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय के बाद से, विश्व-इतिहास में यह एक सबसे बड़ी घटना था। चीनी जनता की जनवादी क्रान्ति का इन अर्थों में भी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व था कि इसने अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति द्वारा समूची मानव जाति पर डाले गए प्रभाव का विस्तार किया तथा उसे और गहरा किया।

प्रथम, चीनी जन-क्रान्ति की विजय से, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश ने सोवियत-संघ तथा दूसरी लोकशाहियों का अनुसरण करते हुए, विश्व-पूँजीवाद की बेड़ियां तोड़ दी थीं तथा अपनी मुक्ति हासिल कर ली थी। विश्व की एक चौथाई आबादी तथा विपुल संसाधनों के साथ, चीन पहले एक महत्त्वपूर्ण बाजार था, जिसे कब्जाने के लिए साम्राज्यवादियों में होड़ मची थी। चीनी क्रान्ति की विजय ने अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों की

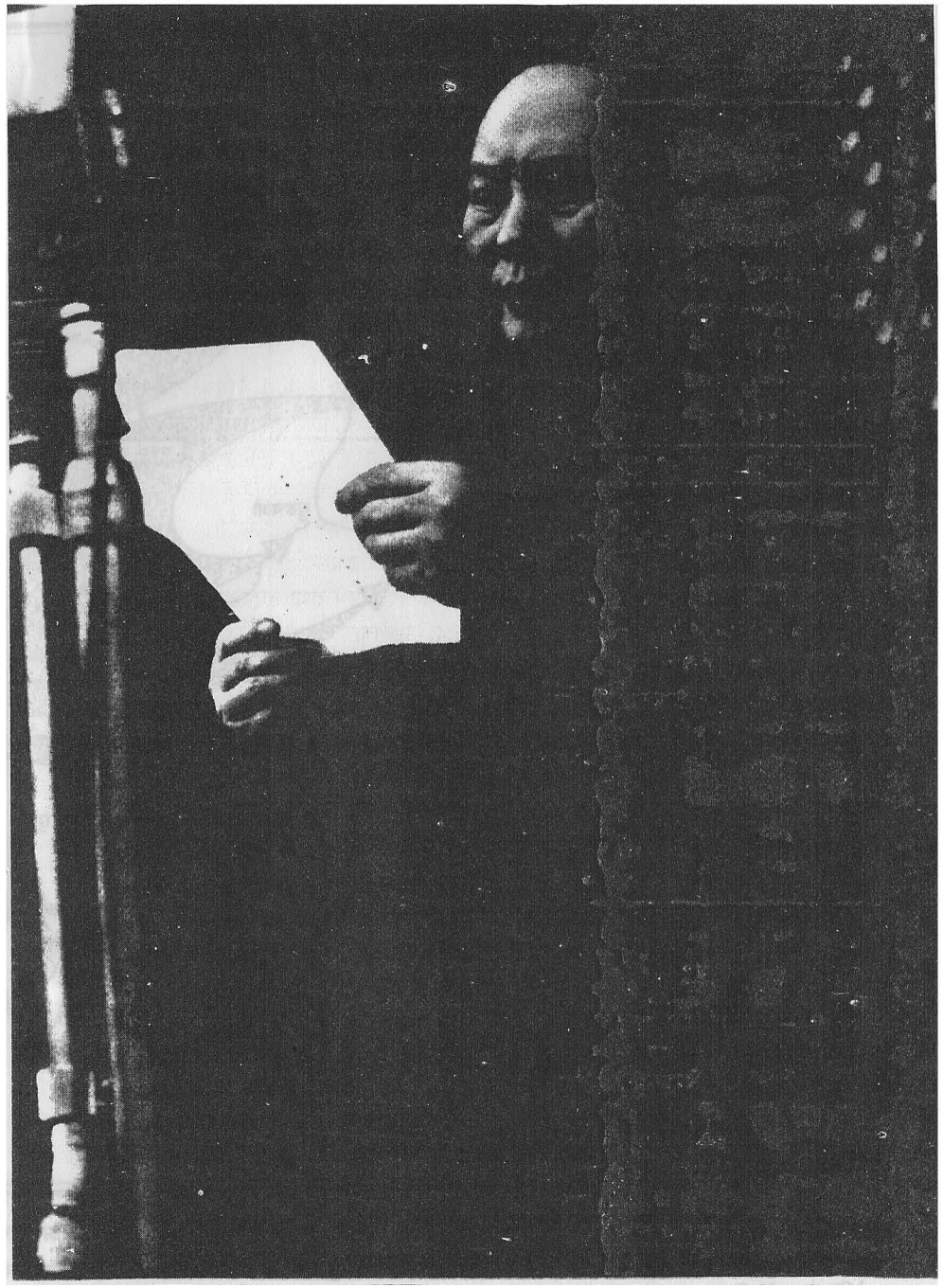

कामरेड माओ त्से-तुङ 1 अक्तूबर, 1949 को थ्येनआनमन चौक से चीनी लोक गणराज्य की स्थापना का ऐलान करते हुए

पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम का मानचित्र

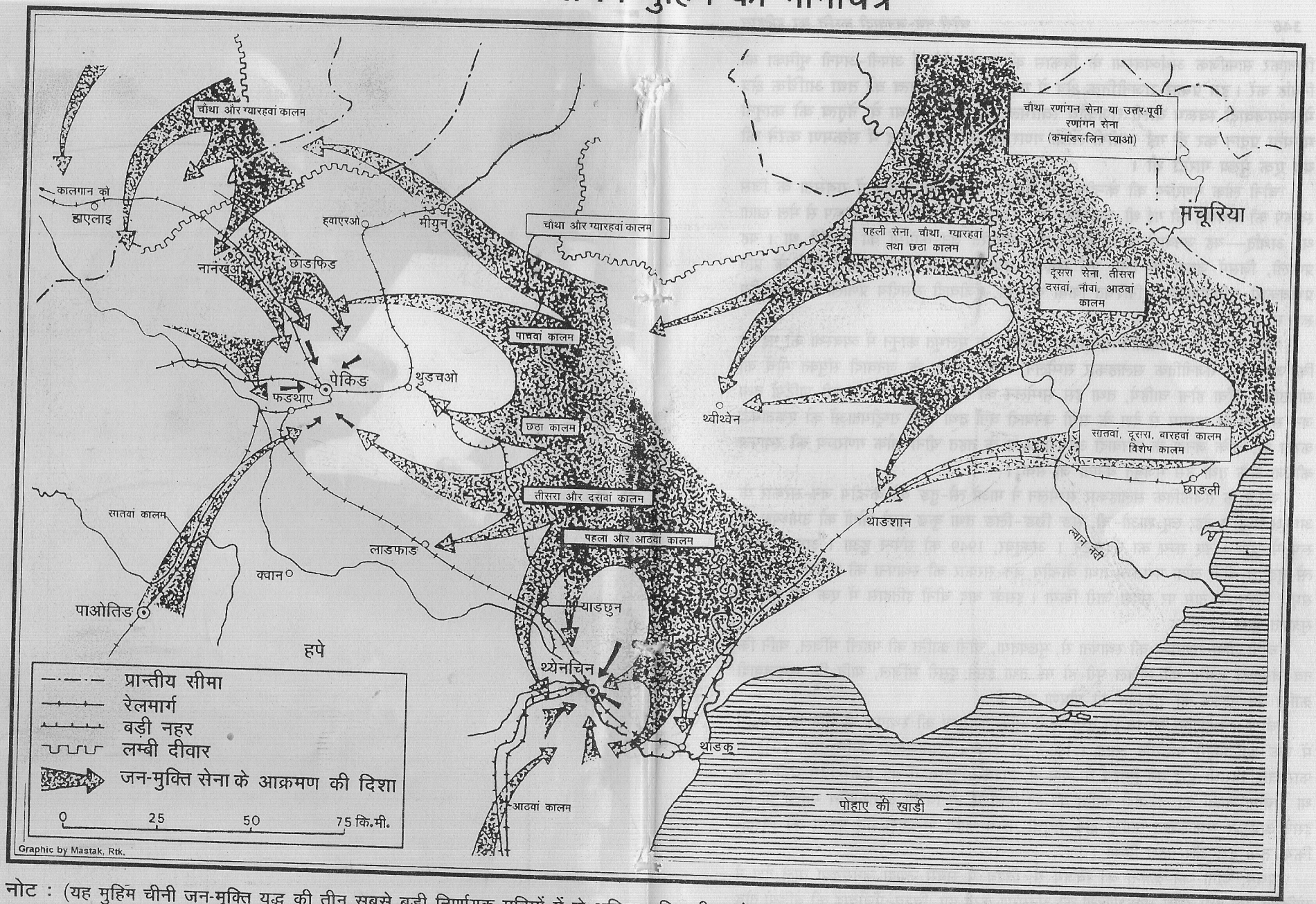

नोट : (यह मुहिम चीनी जन-मुक्ति युद्ध की तीन सबसे बड़ी निर्णायक मुहिमों में से अन्तिम मुहिम थी। इसे उत्तर पूर्वी रणांगन सेना तथा उत्तरी चीन की जन-मुक्ति सेना की दो फौजी फारमेशनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। इस मुहिम में क्वोमितांङ के 5,20,000 से अधिक सैनिकों का या तो सफाया कर दिया गया या फिर उन्हें पुनर्गठित किया गया तथा पेकिङ, थ्येनचिन व चाङच्याखओ नामक महत्त्वपूर्ण नगरों को मुक्त करा लिया गया।

2½ साल से भी अधिक समय के दौरान, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगभग स्थिर रहीं । 1953 में पूरी स्थिरता आ गई । आकाश छूती कीमतों का खतरा, जो दस साल से भी अधिक समय से जनता के सिर पर मंडरा रहा था, सदा-सदा के लिए खत्म कर दिया गया ।

आर्थिक पुनरुद्धार, राजस्व तथा व्यय के सन्तुलन, तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता ने, विशाल पैमाने पर आर्थिक निर्माण के लिए एक ठोस आधारशिला रखी तथा इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का दौर पूरा हो गया । 1953 में एक नए ऐतिहासिक दौर का सूत्रपात हुआ, जब आर्थिक रचना के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का दौर शुरू हुआ । ●

5.

- **ट्रेड यूनियन आन्दोलन का नव विकास ।**
- **पार्टी का सुदृढ़ीकरण तथा निर्माण ।**

मजदूर वर्ग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपने वर्षों के बहादुराना संघर्ष से साबित कर दिया था कि वह केवल चीनी क्रान्ति में ही नेतृत्वकारी शक्ति नहीं था, बल्कि नए चीन के निर्माण की भी नेतृत्वकारी शक्ति था ।

1948 में जब श्रमिकों की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई, उस समय जन-मुक्ति सेना समस्त देश को मुक्त कराने में जोर-शोर से जुटी हुई थी । इस तथ्य के मद्देनजर पार्टी ने श्रमिक वर्ग के लिए मुक्त क्षेत्रों तथा क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों में विशेष कार्यभार निर्धारित किए । कांग्रेस के बाद, चीनी श्रमिक वर्ग, पार्टी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर हो गया। मुक्त क्षेत्रों के श्रमिकों ने क्रांतिकारी युद्ध की सहायता के लिए उत्साहपूर्वक उत्पादन करना जारी रखा । क्वोमिंताङ नियंत्रित क्षेत्रों के श्रमिकों ने, सभी तबकों की जनता को एकजुट करके, संयुक्त मोर्चे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया । नगरों की मुक्ति से पहले, मजदूरों ने फैक्ट्रियों तथा जन-सम्पत्ति को दुश्मन द्वारा नष्ट कर दिये जाने से बचाने की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ले ली । मुक्त शहरों में, उन्होंने नौकरशाह-पूँजीपति उद्यमों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने तथा उन्हें समाजवादी उद्यमों में रूपान्तरित करने में जन-सरकार की मदद की ।

श्रमिकों द्वारा शत्रु से फैक्ट्रियाँ तथा खदानें छीनने के बाद, अब उनका मुख्य कार्यभार उत्पादन का पुनरुद्धार तथा विकास करना था । उत्पादन के पुनरुद्धार के दौरान जनवादी सुधारों को लागू करना जरूरी था । इन सुधारों के बाद, उत्पादन-वृद्धि तथा मितव्ययता के अभ्यास के लिए जन-आन्दोलन चलाया गया, ताकि उत्पादक क्षमता बढ़े, विकसित अनुभव का प्रचार हो, व्यापार लेखा-प्रणाली लागू हो तथा श्रम उत्पादकता का स्तर ऊँचा हो सके ।

मुक्ति के बाद के तीन वर्षों के दौरान, श्रमिकों के बीच व्यापक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा अभियान चलाए गए । 80 प्रतिशत से भी ज्यादा श्रमिकों ने ऐसे अभियानों में हिस्सा लिया, जिनमें से 2,23,000 आदर्श श्रमिक उभर कर सामने आए तथा 4,89,000 जायज सुझावों को स्वीकार किया गया । अर्थव्यवस्था का तीव्र पुनरुद्धार मुख्यतः श्रमिकों की इस उत्साहवर्द्धक प्रतिस्पर्द्धा के कारण संभव हुआ ।

मुक्ति के बाद के आरंभिक वर्षों में, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के साथ व्यवहार के दौरान,

समाजवादी शिविर के देशों के बीच आर्थिक संबंधों की तुलना में साम्राज्यवादी बाजार को देखिए, जहाँ अमरीका के शासक गुट ने कच्चा माल लूटा, जिन्सों के बाजारों पर कब्जा किया तथा अन्य देशों के लोगों को गुलाम बनाया । अपने खुद के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, अमरीका ने अपना निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाते हुए विदेशी बाजारों को अपने सामान से पाट दिया तथा बदले में न के बराबर खरीद की । युद्ध की समाप्ति से 1952 तक, अमरीका का औसत वार्षिक निर्यात 1250 करोड़ डॉलर था, जबकि उसका औसत वार्षिक आयात केवल 720 करोड़ डॉलर था, आयात पर निर्यात की अधिकता औसतन 500 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष थी। लातीनी अमरीका तथा एशियाई देशों के साथ असमान व्यापार संबंधों को और तेज किया गया। मिसाल देखिए, अमरीका चिल्ली में ताँबे के उत्पादन पर, बोलीविया में टिन तथा ब्राजील में कॉफी के उत्पादन पर कब्जा किए हुए था तथा इन चीजों को अत्यधिक कम कीमत पर खरीदता था, जबकि वह अपना माल इन्हें अत्यधिक ऊँची कीमतों पर बेचता था । अमरीका ने इस प्रकार अन्य पूँजीवादी देशों तथा अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया । इसलिए साम्राज्यवादी शिविर के देशों के बीच व्यापार संबंध, समाजवादी शिविर के देशों के बीच के व्यापार संबंधों से बिल्कुल भिन्न थे । इससे साम्राज्यवादी देशों के बीच तथा साम्राज्यवादी व औपनिवेशिक देशों के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो गए, तथा उसने साम्राज्यवादी बाजार के विखंडन को सन्निकट ला दिया ।

समाजवादी शिविर की जबरदस्त ताकत तथा समाजवादी बाजार के आविर्भाव व विकास ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सृजन किया जो चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा विकास के बेहद अनुकूल थी । ●

2.

- **मुक्ति के बाद शुरू के वर्षों में आर्थिक परिस्थिति ।**
- **राज्य के वित्तीय तथा आर्थिक काम में एकीकृत प्रबन्धन तथा नेतृत्व को लागू करना ।**
- **राज्य के वित्त तथा अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु मौलिक मोड़ के लिए बुनियादी नीति ।**

चीनी लोक गणराज्य को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा रूपान्तरण का कार्य पूरा करने में वित्त तथा अर्थनीति को लेकर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये कठिनाइयां दो स्त्रोतों से आईं । प्रथम, क्वोमिंताङ प्रतिक्रियावादियों ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था । उद्योग पूर्णरुपेण दिवालिएपन के कगार पर खड़ा था तथा अधिकांश श्रमिक बेरोजगार हो चुके थे । लगभग सभी खदानों में बाढ़ का पानी भरा पड़ा था तथा रेल-यातायात ठप्प होकर रह गया था । कृषि की दशा भी ऐसी ही चिन्ताजनक थी । क्वोमिंताङ के शासन काल में, चीन, जो एक कृषि-प्रधान देश था, अपने अधिकांश अनाज तथा रूई के लिए विदेशी आयात पर निर्भर करता था । मुक्ति पूर्व के वर्षों में दर्ज किये गए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में, 1949 में कोयले का उत्पादन 50 प्रतिशत, लोहे तथा इस्पात का 80, सूती वस्तुओं का 25, अनाज का 26 तथा कपास का उत्पादन 48 प्रतिशत कम हो गया । युद्ध पूर्व उच्चतम स्तर के

मुकाबले भारवाही पशुओं की संख्या में 16 प्रतिशत तथा मुख्य कृषि उपकरणों में 30 प्रतिशत की कमी आई । मुद्रास्फीति की लपटें दस वर्षों से कहर मचाए हुए थीं तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बाजार सट्टेबाजों के रहमोकरम पर रह गए थे । **क्वोमिंतांङ नियंत्रित क्षेत्रों में कीमतों में अगस्त 1937 से अगस्त 1948 तक 60 लाख गुणा वृद्धि हुई** तथा मुद्रा अवमूल्यन एवं आकाश छूती कीमतों की भयानक परछाइयां आम जनता के सिर पर मंडरा रही थीं ।

विजय के बाद आर्थिक दिक्कतें भी सामने आईं । 1949 में मुक्ति संग्राम द्रुत गति से चला तथा अनेक स्थान लड़ाई किए बिना ही मुक्त करा लिए गए । सभी पुराने सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों को, जिन्होंने जन-मुक्ति सेना का मुकाबला करने से गुरेज किया था, उन्हें नौकरी में रखने की नीति से सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया था । राजस्व के मामले में पुराने मुक्त क्षेत्रों को युद्ध तथा नए मुक्त क्षेत्रों की सहायता के लिए बड़ी मात्रा में अनाज देना पड़ा, जबकि नए मुक्त क्षेत्रों के थोड़े से हिस्सों में ही सार्वजनिक अनाज की उगाही शुरू की गई थी । चूँकि नए मुक्त क्षेत्रों में लड़ाई अभी समाप्त ही हुई थी, शहर और देहात के बीच जिन्सों का आदान-प्रदान पुनः शुरू होने में अभी कुछ समय लगना था । अतः शहरों में टैक्सों द्वारा प्राप्त राजस्व बहुत थोड़ा था । इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार के राजस्व तथा खर्च में संतुलन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गया था ।

ऐसी आर्थिक दिक्कतों से पार पाने के लिए पार्टी तथा सरकार ने सर्वप्रथम राजस्व तथा खर्च के संतुलन तथा मुद्रा एवं जिन्स-कीमतों में स्थिरता लाने पर ध्यान दिया । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा विकास के लिए ये पूर्व शर्तें थीं ।

पार्टी तथा सरकार ने पूँजीपतियों की विघटनकारी गतिविधियों के विरुद्ध भीषण संघर्ष शुरू कर दिया । सट्टेबाजी के विरुद्ध लड़ाई में, जो 1949 के उत्तरार्द्ध से 1950 तक चली, सट्टेबाजों कर करारी चोट की गई, जिन्होंने अनेक अवसरों पर कीमतों को उछाला था ।

मार्च 1950 में, केन्द्रीय जन-सरकार ने "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा वित्त के एकीकृत नियन्त्रण पर निर्णय" (Decision On Unified Control of National Economy and Finance) प्रकाशित किया, जिसका निचोड़ यूँ था : राजस्व तथा व्यय का एकीकृत नियंत्रण, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता सामग्रियों का एकीकृत इस्तेमाल, तथा मुद्रा का एकीकृत नियंत्रण । राजस्व तथा व्यय के एकीकृत नियंत्रण के फलस्वरूप, राष्ट्रीय राजस्व के मुख्य हिस्से यथा, केन्द्रीय जन-सरकार के राजस्व (राज्य द्वारा इकट्ठा किया गया अनाज, टैक्स, गोदामों में पड़ी सामग्री, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का मुनाफा तथा उनके मूल्यह्रास फंडों का कुछ हिस्सा) को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा बड़े निर्माण कार्यों पर राज्य खर्च की मुख्य मदों की पूर्ति में लगाया गया । एकीकृत उपयोग से, देश की सभी मुख्य उपभोक्ता सामग्रियों (अनाज, सूती कपड़ा, औद्योगिक उपकरण) को संकेन्द्रित कर उनका सार्थक उपयोग किया गया । मुद्रा के एकीकृत नियंत्रण में व्यवस्था की गई कि, उस हिस्से को छोड़ कर जिसका तत्काल इस्तेमाल करना था, सारी सुलभ नकदी (ready cash) जो अभी तक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, सरकारी संस्थाओं तथा फौजी यूनिटों में बिखरी पड़ी थी, उसे राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में जमा किया जाना था तथा इसका इस्तेमाल व आबंटन चीनी जनता के बैंक (People's Bank of China) के एकीकृत नियन्त्रण के अन्तर्गत किया जाना था । इस फैसले ने वित्तीय तथा आर्थिक कठिनाइयों पर काबू

अधिवेशन के आह्वान को सफलतापूर्वक साकार कर दिया । यह सफलता उस समय अर्जित की गई जब चीनी जनता अमरीकी हमले के प्रतिरोध तथा कोरिया की सहायता के लिए अभियान चला रही थी ।

वित्त व अर्थव्यवस्था में बेहतरी के लिए बुनियादी मोड़ से अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हुआ, राजस्व व व्यय में संतुलन स्थापित हुआ तथा उपभोक्ता जिन्सों की कीमतों में स्थिरता आई ।

1. अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार :- 1952 के अंत तक औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन का केवल पुनरुद्धार ही नहीं हुआ था, बल्कि यह युद्ध पूर्व के उच्चतम स्तर को भी पार कर गया था । उस वर्ष इसका कुल परिमाण 1949 के आँकड़े से 77.5 प्रतिशत अधिक था, तथा आधुनिक उद्योग के उत्पादन का परिमाण 278.6 प्रतिशत अधिक था । 1949 में आधुनिक उद्योग का उत्पादन परिमाण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के कुल परिमाण का 17 प्रतिशत था; 1952 में यह 26.7 प्रतिशत तक पहुँच गया । पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ा । 1949 में कुल औद्योगिक उत्पादन में पूँजीगत वस्तुओं का अनुपात 29 प्रतिशत था, जबकि 1952 में यह बढ़कर 39.7 प्रतिशत हो गया । समाजवादी उद्योग का विकास द्रुत गति से हुआ । कुल मिलाकर उद्योग में समाजवादी तथा अर्ध-समाजवादी सेक्टर का अनुपात 1949 के 36.7% से बढ़कर 1952 में 61 प्रतिशत हो गया, जबकि निजी उद्योग का अनुपात 63.3 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत रह गया ।

1952 में कृषि उत्पादन 1949 के उत्पादन से 48.5 प्रतिशत अधिक था, अनाज का उत्पादन 44.8 प्रतिशत अधिक था, तथा कपास का उत्पादन 193.4 प्रतिशत अधिक था । अनाज न केवल घरेलू खपत के लिए पर्याप्त था, बल्कि निर्यात के लिए भी फालतू बच गया था । कपास का उत्पादन भी घरेलू माँग की पूर्ति के लिए पर्याप्त था । कृषि ने द्रुत गति से विकास करते उद्योग को ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल मुहैया कराया। इसने लोगों की अनाज की बढ़ती माँग को पूरा किया तथा निर्मित वस्तुओं के निरंतर बढ़ते उत्पादन के लिए बाजार मुहैया किया ।

2. बजट का संतुलन :- मुक्ति के बाद के तीन वर्षों के दौरान राजकीय राजस्व में लगातार वृद्धि हुई, तथा 1952 में बजट पूरी तरह संतुलित हो गया । 1949 के राजकीय राजस्व को 100 मानते हुए 1952 में यह 239 हो गया था । राजस्व में यह वृद्धि उत्पादन के विस्तार से आई । उदाहरण के लिए, 1950 में राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों तथा सहकारी समितियों से करों तथा मुनाफे के रूप में प्राप्त राजस्व, सरकार के कुल राजस्व का मात्र 34 प्रतिशत था, 1952 में यह बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया । खर्चों की मद में, हालाँकि उस वक्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की मजबूती के लिए तथा अमरीका-प्रतिरोध-कोरिया-सहायता-आन्दोलन के समर्थन के लिए काफी राशि आबंटित करना जरूरी था, फिर भी 1952 में बजट का आधे से अधिक व्यय आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर हुआ ।

3. उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता :- मार्च 1950 में सारे देश में थोकभाव का सूचकांक 100 लेते हुए, जब आर्थिक तथा वित्तीय कार्य के एकीकृत नियंत्रण को लागू किया गया; तब दिसंबर 1950 में सूचकांक 85.4; जून 1951 में 91, दिसंबर 1951 में 96.6 जून 1952 में 92.4 तथा दिसंबर 1952 में 90.6 रहा । इससे पता चलता है कि लगभग

के नेतृत्व पर सीधा हमला करने के समान था । अत: *सान फान* तथा *ऊ फान* आन्दोलन खास तौर से ऐसे संघर्ष थे, जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व को बनाए रखने व उसे सुदृढ़ करने के लिए चलाए गए थे ।

सान फान आन्दोलन से सरकारी संगठनों की शुद्धि हुई, सरकार तथा जन साधारण के बीच निकट संबंध स्थापित हुए, सरकारी काम-काज में अनुशासन मजबूत हुआ तथा कार्यकुशलता बढ़ी, तथा सरकारी खर्चे में भारी कमी आई । *ऊ फान* आंदोलन ने पूँजीपति उद्योगपतियों तथा व्यापारियों की गैरकानूनी गतिविधियों पर पर्याप्त अंकुश लगाया तथा पूँजीवादी उद्योग व वाणिज्य को राजकीय योजनाओं के दायरे में ले आया ।

1949 से 1952 के तीन वर्षों के दौरान, जन-सरकार ने अनेक बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर काम किया । रेल निर्माण तथा जल-सफाई व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई ।

चीन जैसे विशाल देश में, यदि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों को एक आर्थिक इकाई के रूप में पिरोना था तो संचार व परिवहन सुविधाओं का होना अनिवार्य था । इसलिए 1950 के पूर्वार्द्ध के बाद, जब सभी पुराने रेलमार्गों की मरम्मत करके उन्हें यातायात के लिए पुन: खोल दिया गया, तो सरकार ने नए रेलमार्ग बिछाने के लिए विशाल धन राशि आबंटित की । बनाए गए रेलमार्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे : लुङहाए रेलमार्ग का लानचओ तक विस्तार तथा छङतू-छुङकिङ रेलमार्ग को पूरा करना । छिङ वंश के अन्तिम वर्षों से लेकर मुक्ति तक के अनेक दशकों से सछ्वान की जनता इस रेलमार्ग के पूरा होने का सपना देखती आ रही थी। लेकिन, मुक्ति के दो साल बाद ही रेलमार्ग पूरा कर दिया गया । इन रेलमार्गों ने दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया ।

इसी दौरान, सरकार ने देश में 42,000 किलोमीटर लम्बी नहरों के बड़े हिस्से की मरम्मत का काम हाथ में लिया । ह्वाए तथा युङतिङ जैसी नदियों, जिनमें भयंकर बाढ़ आती थी, के समूचे मार्ग पर नियंत्रण परियोजनाएं शुरू की गईं । *ह्वाए नदी परियोजना* तथा *चिङच्याङ बाढ़ रोको परियोजना,* ये दोनों ही अपने विस्तार की दृष्टि से तथा कार्यान्वन की दृष्टि से चीनी इतिहास में सचमुच अभूतपूर्व थीं । पीली नदी तथा याङत्सी नदी जैसी विशाल नदियों की बाढ़ का हल अल्पकालिक जल संरक्षण परियोजनाओं के जरिये नहीं निकाला जा सकता था । इनकी बाढ़ रोकने के लिए अस्थाई उपाय किये गये । इन तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 170 करोड़ घनमीटर मिट्टी की खुदाई की गई, जो 10 पनामा नामक नहरों, अथवा 23 स्वेज नहरों की खुदाई के बराबर थी । इन सफलताओं से उपेक्षा के वे हालात बदल गए थे, जिनमें प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार के शासन के तहत जल-संरक्षण व्यवस्था फंस गई थी । बाढ़ का भय, जो हजारों सालों से चीनी जनता का पीछा कर रहा था, अधिकांशत: समाप्त कर दिया गया तथा विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के पुनरुद्धार तथा वहां के निवासियों की संरक्षा को सुनिश्चित कर दिया गया ।

पार्टी के सही नेतृत्व, देशभर की जनता के महान प्रयासों, खासतौर से श्रमिकों तथा किसानों के प्रयासों की बदौलत तथा सोवियत-संघ व जनता के जनतंत्रों द्वारा दी गई नि:स्वार्थ सहायता से, मुक्ति के तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार बुनियादी तौर पर पूरा कर लिया गया । चीन के राष्ट्रीय वित्त तथा अर्थव्यवस्था ने बेहतरी के लिए एक बुनियादी मोड़ काटा, तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के तीसरे पूर्ण

पाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात् राजस्व तथा खर्च को संतुलित किया व उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य स्थिर किए । इससे विवेकपूर्ण उपयोग तथा आबंटन के लिए, देश के वित्तीय संसाधनों तथा सामग्रियों का संकेन्द्रीकरण हुआ, तथा राजस्व व खर्चे में लगभग संतुलन आ गया । फलत: मुद्रा तथा जिन्सों की कीमतें धीरे-धीरे स्थिर हो गईं ।

जून 1950 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति का तीसरा पूर्ण अधिवेशन पेकिङ में बुलाया गया । अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रीय वित्त तथा अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, अगले तीन वर्षों या कुछ आगे तक, पार्टी तथा जनता के कार्यभारों को निर्धारित करना था । पार्टी ने कामरेड माओ त्से-तुङ की रिपोर्ट **"राज्य की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु एक मौलिक बदलाव के लिए प्रयास"** पर चर्चा की तथा उसे स्वीकृति प्रदान की ।

कामरेड माओ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा समय में चीन में सुनियोजित ढंग से आर्थिक निर्माण करने की परिस्थितियाँ अभी उत्पन्न नहीं हो पाई हैं । वित्त तथा अर्थव्यवस्था में बेहतरी हेतु बुनियादी बदलाव लाने के लिए, अर्थात् राष्ट्रीय अथव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए तीन शर्तें जरूरी थीं : 1. कृषि-सुधारों को पूरा करना, 2. मौजूदा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों का समुचित पुनर्समायोजन करना, तथा 3. सरकारी संगठनों के खर्चों में भारी कटौती करना । उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ घोषणा की :

"आप सभी की तरह, मुझे भी पूरा विश्वास है कि अपनी अथक मेहनत से हम लगभग तीन सालों के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे । तब हमारे देश की समस्त वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति में बुनियादी सुधार आ जाएगा ।"

अधिवेशन ने कामरेड माओ की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की तथा समस्त पार्टी व समस्त जनता का आह्वान किया कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक प्रयास करें ।

3.

- **अमरीका के प्रतिरोध तथा कोरिया की सहायता के लिए महान आन्दोलन।**
- **जनता के जनवादी अधिनायकत्व का सुदृढ़ीकरण ।**

अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार तथा रूपान्तरण में तत्परता से जुटी चीनी जनता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य सुरक्षा तथा पक्की शान्ति का बने रहना एक अपरिहार्य जरूरत थी ।

जून 1950 में, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने कोरिया के विरुद्ध अपना आक्रमणकारी युद्ध शुरू कर दिया तथा इसके साथ ही अमरीकी सातवें बेड़े ने ताएवान पर भी कब्जा कर लिया। समस्त कोरिया को विजित करना तथा फिर चीन पर चढ़ाई करना, उनके समूचे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के उन्मादपूर्ण षड्यन्त्र का हिस्सा था । कोरियाई युद्ध के आरंभ से ही, चीनी जनता ने शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया था, तथा अमरीका को सख्त चेतावनी दी गई थी कि वह कोरिया के विरुद्ध अपना आक्रमण रोक दे तथा ताएवान से अपनी फौजें हटा ले। सुझाव तथा चेतावनी को अनसुना करते हुए, अमरीकी हमलावर कोरिया में आगे बढ़ गए तथा

अपने आक्रमण की मुख्य दिशा चीन की उत्तरपूर्वी सीमा की ओर मोड़ दी । इस प्रकार चीन की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया । चीनी जनता ने शांति की रक्षा करने के लिए हथियार उठा लिए । चीनी जनता के स्वयंसेवकों (Chinese People's Volunteers) की फौज गठित की गई तथा उसने अमरीकी हमले के विरुद्ध कोरियाई जन-सेना के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ने हेतु व सुदूर पूर्व में शांति की रक्षा के लिए 25 अक्तूबर को सीमा पार की। चीनी जनता के उत्साहजनक समर्थन से चीनी स्वयंसेवकों की फौज एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करती चली गई तथा 31 मई, 1951 को शत्रु को अड़तीसवीं समानांतर (38th Parallel -एक स्थान का नाम, सं०) के नजदीक तक वापिस पीछे धकेल दिया, जहां से उसने अपना आक्रमणकारी युद्ध आरंभ किया था । तब से लेकर, चीनी जनता के स्वयंसेवकों तथा कोरियाई जन-सेना ने सक्रिय रक्षा की मोर्चेबद्ध युद्ध की रणनीति अपनाई तथा समूचे कोरिया में किलेबन्दियों की एक अभेद्य शृंखला का निर्माण कर दिया तथा इस प्रकार मोटे तौर पर मोर्चे को 38वीं पैरेलल पर स्थिर कर दिया । तथापि दिसम्बर 1951 से, अमरीकी हमलावरों ने, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन तथा मानवता का तिरस्कार करते हुए व्यापक पैमाने पर जीवाणु-युद्ध छेड़ दिया । लेकिन यह जघन्य कुकृत्य भी उनकी सैनिक कार्यवाहियों की भाँति बेकार सिद्ध हुआ ।

चीनी तथा कोरियाई जनता को अमरीकी हमले के विरुद्ध युद्ध में इसलिए उलझने को बाध्य होना पड़ा था ताकि कोरियाई प्रश्न का न्यायोचित तथा तर्कसंगत आधार पर शांतिपूर्ण समाधान हो सके, अत: उन्होंने तथा उनकी सरकारों ने जून 1951 में सोवियत-संघ द्वारा प्रस्तुत युद्ध-विराम प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी । चीनी व कोरियाई सेनाओं तथा विश्व शान्ति-आन्दोलन की जबरदस्त ताकत तथा अमरीकियों की हार के कारण साम्राज्यवादी शिविर में उत्पन्न हुए गंभीर अन्तर्विरोधों के मद्देनजर, अमरीकी साम्राज्यवादियों को भी विवशतापूर्वक वैसा ही करना पड़ा । लेकिन, चूंकि अमरीकी साम्राज्यवादी विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाने को आमादा थे, अत: शान्ति समझौता करने की उनकी कोई वास्तविक मन्शा न थी । अत: यह स्वाभाविक ही था कि कोरिया में युद्ध-विराम वार्ता ने, एक काफी लंबे तथा उलझे हुए भयंकर सैनिक तथा राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेना था । अभी फौजी सीमा-रेखा तय करने तथा युद्ध-स्थगन की वार्ता चल ही रही थी कि अमरीकी साम्राज्यवादियों ने सशस्त्र दबाव तथा अन्य घृणित हथकण्डों के जरिये वार्ता का रुख अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, परन्तु वे इसमें सफल न हो सके । फिर जब समझौता लगभग हो ही गया था, बड़ी ही बेशर्मी से उन्होंने, युद्ध बंदियों की वापसी के प्रश्न पर विलंबकारी तथा विघ्नकारी हथकण्डे अपनाए । चीन तथा कोरिया ने बारम्बार शत्रु के "सैनिक दबाव" तथा ओछे षड्यन्त्रों को ध्वस्त किया, उसकी गुस्ताखी का करारा जवाब दिया तथा उसकी कुचालों को निष्फल किया, और इस प्रकार अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए यह असंभव बना दिया कि जो चीज वे युद्ध के मैदान में प्राप्त करने में सफल न हुए थे, उसे वे वार्ता की मेज पर हथिया लें । साथ ही, चीन तथा कोरिया ने शांतिपूर्ण समझौते की नीति के प्रति अत्यधिक निष्ठा एवम् धैर्य का परिचय दिया। अन्तत: कोरियाई युद्ध-विराम वार्ता, जो दो वर्ष तक चलती रही, समझौते के मुकाम पर पहुँची। 27 जुलाई, 1953 को कोरिया के पानमुनजोम नामक स्थान पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।

यद्यपि अमरीका ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का काफी बड़ा हिस्सा कोरियाई युद्ध में झोंका

संतुलन बनाएं ।

अक्तूबर 1951 में जनता के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की प्रथम राष्ट्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में फैसला किया गया कि व्यापक पैमाने पर आर्थिक उत्पादन शुरू करने के लिए, जन-सरकार को उत्पादन वृद्धि व मितव्ययता हेतु, राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़ने के लिए दीर्घ प्रयास करने चाहिएं ।

ऐसे आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची तथा नौकरशाही के विरुद्ध कठोर संघर्ष चलाने की आवश्यकता थी, क्योंकि भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची, उत्पादन-वृद्धि तथा मितव्ययता के आड़े आते थे, जबकि नौकरशाही वो अड्डा थी, जहाँ भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची फलते-फूलते थे । इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए, 1951 की सर्दियों तथा 1952 के पूर्वार्द्ध में सरकारी कर्मचारियों के मध्य ***सान फान आंदोलन***[3] चलाया गया।

क्रांतिकारी शासन के अंतर्गत भी भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची तथा नौकरशाही का अस्तित्व बना रहा था । इसके दो मुख्य कारण थे । प्रथम, क्रांति की विजय के बाद, पार्टी ने क्वोमिंताङ सरकार के संगठनों तथा उद्यमों के सभी कर्मचारियों को ले लेने की नीति अपनाई थी । इनमें से बहुतों को स्वयं का सैद्धान्तिक रूप से पुन: संस्कार करने का समय न मिला था । दूसरे, बहुत से कार्यकर्ता, क्रांति की विजय के बाद वर्ग-संबंधों में आए परिवर्तन को स्पष्ट तौर से समझने में असफल रहे तथा पतनशील पूँजीवादी विचारों द्वारा किये जा रहे क्षय तथा हमले के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सतर्क न थे । पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के दूसरे पूर्ण अधिवेशन द्वारा दी गई चेतावनी, कि पूँजीपतियों की 'मीठी गोलियों' के प्रति सतर्क रहो, की उन्होंने या तो उपेक्षा की या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया । चूँकि भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची तथा नौकरशाही एक पतनशील पूँजीवादी दृष्टिकोण के प्रतीक थे, अत: *सान फान* आन्दोलन, वस्तुत: इस दृष्टिकोण के विरुद्ध संघर्ष था ।

सान फान आन्दोलन के समानान्तर, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के बीच ***ऊ फान आन्दोलन***[4] चलाया गया । मुक्ति के बाद के तीन वर्षों के दौरान पूँजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग के विरुद्ध लगातार किये गए हमलों का यह सटीक जवाब था । अनेक पूँजीपति उद्योग तथा वाणिज्य को नियंत्रित करने की पार्टी की नीति पर प्रहार कर रहे थे । वे संसाधन तथा निर्माण के लिए तभी सरकारी आर्डर लेने को तैयार होते थे जब बाजार में मन्दी होती थी तथा कच्चे माल की आपूर्ति में कमी होती थी । लेकिन जब बाजार में तेजी, तथा कच्चे माल की उपलब्धता सुविधाजनक होती, वे सभी नियंत्रणों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते तथा खुले बाजार में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचते । उनमें से कुछ ने तो गैरकानूनी तरीकों से बेतहाशा मुनाफा कमाने की हद ही कर दी । "पाँच बुराइयों" (देखें नोट-4) को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने सरकारी संगठनों तथा उद्यमों में कार्यरत कार्यकर्ताओं पर भयंकर हमला बोल दिया । विशाल पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा गबन के काण्डों में से अधिकतर, सरकारी संगठनों तथा उद्यमों में कार्यरत पँजीपति वर्ग के एजेन्टों द्वारा कानून-तोड़ने वाले पूँजीपतियों से मिलीभगत करके किए गए थे । यह स्थिति अपराधियों द्वारा केवल कानून तथा अनुशासन के उल्लंघन का प्रश्न नहीं थी, बल्कि मुख्य तौर से पूँजीवादी वर्ग के क्षयकारी प्रभाव तथा क्रांतिकारी शिविर पर उसके भयंकर हमले का परिणाम थी । पूँजीपति वर्ग ने दु:स्वप्न पाला था कि जनता को क्रांति के फलों से वंचित कर दिया जाए । यह श्रमिक वर्ग

अब प्रति व्यक्ति औसत जमीन का 90 प्रतिशत, प्रत्येक गरीब किसान तथा खेत-मजदूर के पास था । इस प्रकार उनकी अत्यन्त फौरी मांगों को बुनियादी तौर पर पूरा कर दिया गया था ।

कृषि-सुधारों ने, सामंती-प्रणाली का खात्मा कर दिया, जिसकी पिछले दो हजार वर्षों से चीन में तूती बोलती आ रही थी; जमींदार वर्ग का सफाया कर दिया, जो चीन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों तथा साम्राज्यवाद का मुख्य आधार था; तथा ग्रामीण उत्पादक शक्तियों को मुक्त किया व इस प्रकार देश के औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया ।

इसी काल के दौरान, पार्टी के मार्गदर्शन में चीनी जनता ने उद्योग तथा वाणिज्य का रूपान्तरण भी किया । यह रूपान्तरण तीन मूल प्रश्नों के इर्द-गिर्द केन्द्रित था : सार्वजनिक तथा निजी हितों के बीच संबंध, पूँजी तथा श्रम की बीच एवं उत्पादन तथा विपणन के बीच संबंध, और इन सभी का पुनर्समायोजन करना जरूरी था ।

सार्वजनिक तथा निजी हितों के बीच पुनर्समायोजन का अर्थ था कि राजकीय अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन में निजी अर्थव्यवस्था को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए । इस लिहाज से सरकार ने यह नीति अपनाई कि जो निजी फैक्ट्रियाँ आत्मनिर्भर थीं तथा जो राष्ट्रीय कल्याण तथा जनता की जीविका के लिए लाभप्रद थीं, उन्हें संसाधन तथा निर्माण (processing and manufacture) के आर्डर देकर, अथवा किन्हीं अन्य तरीकों से उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने को प्रोत्साहित करके, उनकी मदद की जाए तथा उन्हें विधि-सम्मत मुनाफा कमाने की इजाजत दी जाए । उन्हें संसाधन तथा निर्माण के लिए आर्डर मुहैया कराकर, राज्य ने निजी उद्यमों पर राजकीय अर्थव्यवस्था के नेतृत्व को मजबूत किया तथा उत्पादन व विपणन की व्यवस्था पर भी अपना नेतृत्व मजबूत किया, तथा निजी उद्यमों की अनेक समस्याओं को हल किया, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादों का विपणन । इसके साथ ही निजी उद्यमों को जायज मुनाफा कमाने से भी नहीं रोका गया । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूपान्तरण का यह पहला चरण था ।

जून 1952 में, शंघाई में निजी स्वामित्व की फैक्ट्रियों द्वारा किए गए कुल व्यापार का 80 प्रतिशत हिस्सा संसाधन, निर्माण तथा खरीद के लिए दिये गये सरकारी ऑर्डर थे । थ्येनचिन तथा कैंटन में यह अनुपात क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत था ।

श्रम तथा पूँजी के बीच सम्बन्धों में, मुक्ति के बाद के कुछ वर्षों में दोनों पक्षों में भटकाव आए थे । एक तरफ, कुछ पूँजीपतियों ने श्रमिकों को उनके जरूरी जनवादी अधिकार प्रदान करने से हठपूर्वक इन्कार कर दिया था; दूसरी ओर, कुछ श्रमिकों ने जरूरत से ज्यादा मांगें प्रस्तुत की थीं । दोनों भूलों को सुधारने के लिए, यह जरूरी था कि पूँजीपतियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया जाए कि वे श्रमिकों के अनिवार्य जनवादी अधिकारों को स्वीकार करें तथा यह कि उत्पादन के विकास से जनता की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी—इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाए । सलाह मशविरे द्वारा पूँजी तथा श्रम के बीच के तनाव को दूर किया गया तथा उनके सम्बन्धों को अनुबन्धों द्वारा नियमित किया गया ।

उत्पादन तथा विपणन के मध्य सम्बन्धों की पुनर्व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के सभी निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों से आग्रह किया गया कि वे अपने योजना-तन्त्र को मजबूत करें, उत्पादन में अंधाधुंध तरीके तथा अराजकता को दूर करें, तथा उत्पादन व विपणन के मध्य

था, अन्य देशों के सैनिक भी उसके साथ थे तथा उसके 10 लाख से भी अधिक सैनिक मारे गए थे एवं 20 अरब अमरीकी डॉलर खर्च हो गए थे, तो भी वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा; जबकि कोरिया तथा चीन की सशस्त्र सेनाएं युद्ध के दौरान लगातार मजबूत होती चली गईं एवं उन्होंने अनेक शानदार सफलताएँ अर्जित करके अमरीकी साम्राज्यवादियों को युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया । चीनी तथा कोरियाई जनता की विजय ने, जनवादी कोरियाई लोक गणराज्य की रक्षा करने व चीन की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को मजबूत करने के अतिरिक्त, निःसन्देह, सिद्ध कर दिया कि अपनी आजादी तथा रक्षा के लिए लड़ता हुए एक जागृत देश अजेय होता है । इस विजय से अमरीका तथा समस्त साम्राज्यवादी शिविर के मुँह पर करारा तमाचा पड़ा तथा सुदूर पूर्व व विश्व में शांति को सुनिश्चित किया जा सका । चीन के आर्थिक पुनरुद्धार तथा निर्माण के निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने हेतु यह सब जरूरी था ।

चीन को अपने समाजवादी निर्माण के लिए पूर्ण शांति की आवश्यकता थी; किसी भी असंभाव्यता से निपटने के लिए व अपने समाजवादी निर्माण की रक्षा के लिए उसे आधुनिक हथियारों से लैस एक सेना की जरूरत भी थी । इस उद्देश्य के लिए पार्टी ने, जब अमरीकी हमले के प्रतिरोध तथा कोरिया की सहायता के लिए आन्दोलन चल रहा था, उसी दौरान जन-मुक्ति सेना का उसके बुनियादी आधार पर ही आधुनिकीकरण किया । जन-मुक्ति सेना का रूपान्तरण करके उसे थल, जल तथा आकाश में एक जबरदस्त फौजी ताकत बना दिया गया । जन-मुक्ति सेना में, आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक व आधुनिक फौजी विज्ञान सीखने के लिए आन्दोलन चलाया गया । सेना को नियमित किया गया, उसकी कमान, संगठन, प्रशिक्षण तथा अनुशासन को एकीकृत किया गया । साम्राज्यवादियों के अचानक हमलों का सामना करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए जरूरी किलेबन्दियों का भी निर्माण किया तथा रिजर्व सेना के लिए योजना तैयार की । जन-मुक्ति सेना का सर्वोच्च कार्यभार साम्राज्यवादी हमलों से देश की रक्षा करना तथा समाजवादी निर्माण की सुरक्षा करना था ।

हालांकि देश के भीतर प्रतिक्रियावादी वर्गों का तख्ता पलट दिया गया था, फिर भी वे हार मानने को कतई तैयार न थे । मुक्ति के बाद के आरंभिक वर्षों में, अभी भी काफी तादाद में प्रति-क्रान्तिकारी नए मुक्त क्षेत्रों में भरे पड़े थे । पुराने मुक्त क्षेत्रों में भी प्रति-क्रांतिकारी छुपे बैठे थे । उन्होंने दंगे करने, तोड़-फोड़ की विभिन्न कार्यवाहियाँ करने तथा जनता के क्रान्तिकारी सक्रिय तत्वों व कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए "राजनीतिक" डाकुओं के भूमिगत, प्रति-क्रान्तिकारी दस्ते व गैंग बना लिये थे । जनता के शासन को सुदृढ़ करने व आर्थिक निर्माण की रक्षा के लिए, चीनी जनता ने दिसंबर 1950 में, प्रति-क्रांतिकारियों के दमन के लिए एक राष्ट्र-व्यापी अभियान छेड़ा । पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड माओ द्वारा निर्धारित नीति,—**"रिंग लीडरों को सजा तथा उनके द्वारा बाध्य सह-अपराधियों के लिए माफी; जो स्पष्ट तौर से गलती स्वीकार कर लें, उनके प्रति नरमी तथा जो ऐसा करने से इन्कार करें उनके प्रति सख्ती; वे जो सेवा करें उसे उनके अपराधों का प्रायश्चित माना जाये तथा खासतौर से विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाए"**—का पालन करते हुए तथा साथ ही केन्द्रीय जन-सरकार द्वारा जारी प्रति-क्रान्तिकारियों की सजा को निर्धारित करने वाले अधिनियमों के तहत, सभी डाकुओं, खुफिया एजेन्टों, प्रतिक्रियावादी

पार्टियों तथा ग्रुपों के खास सदस्यों तथा प्रतिक्रियावादी गुप्त समितियों के प्रमुखों को दण्डित किया गया, जो कि अभी भी जनता में आतंक फैलाए हुए थे । उन कुख्यात रिंग लीडरों को भी सख्त सजाएं दी गईं, जिन्होंने देश तथा जनता के विरुद्ध गंभीर अपराध किये थे ।

प्रति-क्रान्तिकारियों के दमन में भारी सफलता के फलस्वरूप, पार्टी तथा जन-सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, जनता की एकता मजबूत हुई, जनता का जनवादी अधिनायकत्व सुदृढ़ हुआ तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार तथा विकास सुनिश्चित हुआ ।

इसी प्रकार, जनता की जनवादी शासन व्यवस्था के निर्माण में भी महान सफलताएँ अर्जित की गईं ।

सामान्य कार्यक्रम के अनुसार, देश की बुनियादी राजनीतिक व्यवस्था, जनता की असली जनवादी कांग्रेसों की व्यवस्था थी, जिन्हें आम चुनाव के माध्यम से चुना जाता था । चीनी लोक गणराज्य के प्रारंभिक वर्षों में, जब मुख्य भूमि पूरी तरह मुक्त नहीं थी, देश के बड़े हिस्से में कृषि-सुधार अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए थे तथा व्यापक जनता पूरी तरह संगठित नहीं की जा सकी थी, राष्ट्रव्यापी स्तर पर सार्विक मताधिकार (Universal Franchise) के आधार पर चुनाव करा पाना असंभव था । इन हालात के मद्देनजर ये फैसला किया गया कि 'जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन' राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के कर्त्तव्यों को पूरा करे तथा उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करे तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधि सम्मेलन, कदम-दर-कदम स्थानीय जन-कांग्रेसों के कर्त्तव्यों का निर्वाह करें तथा उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करें । इस संक्रमण काल के दौरान ऐसे अंतरिम उपाय बहुत जरूरी थे ।

मुक्ति के बाद के तीन वर्षों के दौरान, समस्त देश के विभिन्न प्रान्तों, नगरपालिकाओं, काउंटियों तथा कस्बों में जन-प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित तथा स्थापित किए गए । टाउनशिप जन-प्रतिनिधि सम्मेलनों के प्रतिनिधियों का विशाल बहुमत सीधे जनता द्वारा चुना गया था, तथा काउंटियों व नगरपालिकाओं के जन-प्रतिनिधि सम्मेलनों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया गया । इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, आमतौर पर कुल प्रतिनिधियों का 80 प्रतिशत थे ।

लगभग सारा जरूरी कार्य जिसे जनता तथा उसकी राजसत्ता ने अपने हाथ में लिया, मसलन—कृषि-सुधार, **अमरीका-प्रतिरोध तथा कोरिया-सहायता आन्दोलन,** प्रति-क्रांतिकारियों का दमन, जनवादी सुधारों के लिए अभियान, तथा उत्पादन वृद्धि के लिए देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, इन सभी मुद्दों पर जन-सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया तथा जनसाधारण को ऐसे अभियानों में हिस्सा लेने के लिए गोलबन्द किया गया । इस प्रकार जनता की राजनीतिक चेतना, देशभक्ति, क्रांतिकारी सतर्कता एवं उत्पादक पहलकदमी में अतीव वृद्धि हुई ।

इस संक्रमणकालीन संस्था ने, जिसने जन-कांग्रेस के रूप में कार्य किया, सारी जनता को एकबद्ध करने, जनता के जनवादी अधिनायकत्व को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने, अमरीकी हमले का प्रतिरोध करने तथा कोरिया की सहायता करने एवम् अन्य विशाल कार्यभारों को पूरा करने में एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की ।

इस कालखण्ड के दौरान श्रमिकों तथा मेहनतकश जनता के अन्य तबकों के बीच जनवादी सुधार लागू किए गए । उनकी पाँतों में छुपे हुए बचे-खुचे सामंती तत्वों का सफाया किया गया, प्रति-क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया गया, पुराने शिल्पियों को एकबद्ध किया गया व

वह जमीन अपने पास रखने की अनुमति दी गई । दूसरे हिस्से को, जिसके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी, उसे जमीन के बंटवारे के वक्त हिस्सा दिया गया । इस तरह, कुल मिलाकर मध्यम किसानों की कुल औसत जमीन कृषि-सुधारों से पहले की जमीन से ज्यादा हो गई । पार्टी की नीति यह भी थी, कि धनी किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाए । कृषि-सुधार कानून में निम्नलिखित प्रावधान थे: (1) धनी किसानों की अपनी जमीन जिस पर वे खुद ही खेती करते थे या मजदूरों द्वारा खेती करवाते थे, तथा उनकी अन्य सम्पत्तियों को अतिक्रमण से बचाया जाना था; (2) धनी किसानों द्वारा लगान पर दिये गए जमीन के छोटे टुकड़ों पर हाथ नहीं डालना था, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में इस प्रकार लगान पर दी गई जमीन के कुछ हिस्से का या सारी की सारी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता था; (3) अर्ध-जमींदार किस्म के धनी किसान, जिन्होंने जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा लगान पर दिया हुआ था, उनकी लगान पर दी हुई जमीन का अधिग्रहण किया जाना था । इस प्रकार कृषि-सुधारों के बाद धनी किसानों के पास, प्रति व्यक्ति की औसत जमीन से, सामान्यतः दुगुनी जमीन रह गई ।

कृषि-सुधार प्रक्रिया मोटे तौर से इस प्रकार थी : प्रथम, पार्टी की नीति के बारे में समझाने व किसानों की राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए, किसान सभाओं अथवा किसान सम्मेलनों के माध्यम से किसानों में प्रचार किया गया । दूसरे, व्यापक जन-समुदाय स्वयं ही उठ खड़ा हुआ तथा जमींदारों के विरुद्ध अथक संघर्ष छेड़ दिया । स्थानीय निरंकुश तत्वों के विरुद्ध तथा लगान में कमी व जमानतों की वापसी के लिए संघर्ष के बाद, जमींदारों की जमीन तथा संपत्ति को जब्त कर लिया गया तथा उसे उन किसानों में बाँट दिया गया जिनके पास जमीन तथा उत्पादन के औजार नहीं थे । इस प्रकार कृषि-सुधारों का अंतिम चरण पूरा हुआ । इलाके में

1951 के कृषि-सुधारों के दौरान पुराने जमींदारों द्वारा जारी किये गये जमीन के पट्टे जलाते चीनी किसान

उनका पुनः संस्कार किया गया, पुरानी घिसी-पिटी तथा तर्कहीन प्रणाली को खत्म करके नई जनवादी व्यवस्था को अपनाया गया । इन सुधारों से श्रमिकों तथा अन्य मेहनतकश जनता की राजनीतिक चेतना तथा उत्पादक पहलकदमी को ऊँचा उठाने में मदद मिली ।

इसी कालावधि के दौरान बुद्धिजीवियों का सैद्धांतिक रूप से पुनः संस्कार करने के लिए अभियान चलाया गया । समाजवादी निर्माण के विशाल तथा कठिन कार्य के लिए अधिक से अधिक बुद्धिजीवियों के योगदान की जरूरत थी, अतः बुद्धिजीवियों के लिए यह जरूरी था कि वे अपना खुद का पूर्ण रूप से पुनः संस्कार कर लें तथा धीरे-धीरे जीवन के प्रति सर्वहारा दृष्टिकोण को आत्मसात कर लें । इस मुहिम ने जन-आंदोलन का रूप ले लिया, जो बुद्धिजीवियों की स्व:शिक्षा तथा स्व-पुनर्संस्कार के लिए आलोचना तथा आत्मालोचना के शिक्षण-तरीके पर निर्भर था । इस मुहिम में, बुद्धिजीवियों पर साम्राज्यवादी, सामंती तथा अफसरशाह-पूँजीपति वर्ग के प्रभावों का पूरी तरह पर्दाफाश किया गया तथा इन प्रभावों को अधिकतर दूर कर दिया गया, पूँजीवादी तथा निम्न-पूँजीवादी विचारों की आलोचना की गई तथा इस प्रश्न का—**''बुद्धिजीवी किसकी सेवा करे ?''** सही आरंभिक उत्तर दिया गया। अधिकांश बुद्धिजीवी समाजवादी व्यवस्था के समर्थक बन गए तथा वे पूरी सक्रियता से मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अध्ययन में जुट गए । थोड़े समय बाद, इनमें से कुछ कम्युनिस्ट बन गए । इस प्रकार बुद्धिजीवियों के मध्य सर्वहारा विचारों की नेतृत्वकारी भूमिका और ज्यादा मजबूत तथा सुदृढ़ हुई ।

इस कालावधि के दौरान राष्ट्रीयताओं से संबंधित कार्य में भी सफलताएँ प्राप्त की गईं।

अल्पसंख्यकों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का 6% थी, लेकिन वे देश के 60% इलाके में बसते थे, जिसका अधिकतर हिस्सा औद्योगिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध था ।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुसार राष्ट्रीयता के प्रश्न का समाधान पूर्ण जनवादीकरण था। एक बहु-राष्ट्रीय देश में इसके लिए बुनियादी कार्यदिशा इस प्रकार होनी थी कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के वास्तविक आपसी-सहयोग पर आधारित क्षेत्रीय स्वायत्तता स्थापित की जाए, राजनीति तथा अर्थनीति में राष्ट्रीय समानता के सिद्धान्त का सम्मान किया जाए तथा विभिन्न राष्ट्रीयताओं की ऐतिहासिक विशिष्टताओं तथा मतभेदों को ध्यान में रखा जाए । प्रथम, चूंकि चीन श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में एक लोक गणराज्य था, अतः यह राष्ट्रीय सवाल को पूर्णतया जनवादी तरीकों से हल करने में सक्षम था । दूसरे, राष्ट्रीयताओं के बीच में समानता, मैत्री तथा परस्पर सहयोग के विचार से आरंभ करते हुए, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत को लागू करके अल्पसंख्यकों के स्वायत्तता के अधिकार की रक्षा की गई । राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की दो विशेषताएं थीं। इससे अल्पसंख्यक जनता को अपने मामलों का स्वयं संचालन करने तथा अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अपने विकास में वृद्धि करने का अधिकार मिला । समान दर्जे तथा समान अधिकारों के आधार पर इसने सभी भ्रात्रीय (fraternal) राष्ट्रीयताओं को एक बड़े परिवार के रूप में एकबद्ध कर दिया ताकि वे देश के साँझे प्रशासन तथा विकास में हिस्सा ले सकें । मातृभूमि के विशाल परिवार में मिलकर रहना सभी राष्ट्रीयताओं की सामूहिक अभिलाषा तथा ऐतिहासिक विकास का अपरिहार्य नतीजा था । तीसरे, हान राष्ट्रीयता, जिसका अपेक्षाकृत ऊँचा आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्तर था, अन्य राष्ट्रीयताओं की सहायता करे, तथा अन्य राष्ट्रीयताएं इस सहायता का महत्त्व महसूस करें । हान अन्धराष्ट्रवाद

इस तथ्य के मद्देनजर कि जनता का क्रांतिकारी युद्ध मुख्यतया सम्पन्न हो चुका था तथा गरीब किसानों की जमीन की कमी तथा उत्पादन के साधनों की कमी को सरकारी ऋणों द्वारा दूर किया जा सकता था, पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में धनी किसानों को निष्प्रभावी करने की नीति अपनाई गई । धनी किसानों की फालतू जमीन तथा सम्पत्ति को जब्त करने की नीति की बजाय, अधिवेशन ने उनकी अर्थव्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने की नीति अपनाई । फलतः जमींदार और ज्यादा अलग-थलग पड़ गए तथा देहाती इलाकों में उत्पादन के पुनरुद्धार में तेजी आ गई ।

30 जून, 1950 को केन्द्रीय जन-सरकार ने चीनी लोक गणराज्य का कृषि-सुधार कानून लागू किया, जिसके मार्गदर्शन में सभी नव-मुक्त क्षेत्रों की जनता ने कृषि-सुधार के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया । 1952 के अंत तक, बुनियादी तौर पर समस्त देश में कृषि-सुधार लागू कर दिए गए, केवल अल्पसंख्यक क्षेत्रों को ही अपवाद स्वरूप छूट मिली थी । सुधारों के फलस्वरूप 70 करोड़ मू (एक मू=आधा एकड़) जमीन 30 करोड़ किसानों में बाँटी गई, तथा 3 करोड़ टन अनाज, जो पहले प्रतिवर्ष लगान के रूप में जमींदारों को चला जाता था, उस पर किसानों का अधिकार हो गया, तथा वे उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते थे । कृषि-सुधारों के सफल समापन के बाद, पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने, स्वैच्छिक तथा पारस्परिक हितों पर आधारित सहकारिता तथा परस्पर-सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन आरंभ किया । किसानों के मध्य सहकारिता का पहले से ही एक लम्बा इतिहास था, लेकिन आपसी-सहायता तथा सहकारिता का जन-आन्दोलन वाला रूप, पार्टी के नेतृत्व में, लोक गणराज्य की स्थापना के बाद ही, अस्तित्व में आया । 1951 के अन्त तक 300 से ज्यादा सहकारी समितियाँ बन गई थीं । 1952 में इनकी तादाद बढ़कर 4000 हो गई । कृषि-सुधार, परस्पर-सहायता तथा सहकारिता के आधार पर, तथा पार्टी व सरकार के सशक्त नेतृत्व तथा सहायता द्वारा, किसानों ने उत्पादन-वृद्धि के लिए व्यापक स्तर पर देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन आरंभ कर दिया । अब वे अपनी खुद की बेहतरी के लिए तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे । किसानों के माल-असबाब में बड़ी भारी तादाद में कृषि उपकरणों तथा भारवाही पशुओं का इजाफा हुआ । कृषि तकनीक का धीरे-धीरे विकास हुआ तथा कुल मिलाकर कृषि उत्पादन का द्रुत वेग से पुनरुद्धार तथा विकास हुआ । पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा निर्धारित सही कार्यदिशा के कार्यान्वन से कृषि-सुधारों में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई, यानि कि गरीब किसानों व खेत-मजदूरों पर निर्भर करते हुए, मध्यम किसानों से एकता कायम करके, धनी किसानों को तटस्थ करने की कार्यदिशा अपनाई गई, ताकि शोषण की सामंती प्रणाली को कदम-ब-कदम समाप्त किया जा सके तथा कृषि-उत्पादन को बढ़ाया जा सके । कृषि-सुधार एक भयंकर वर्ग संघर्ष था । अतः किसानों को पूर्ण रूप से लामबंद करना अनिवार्य था, ताकि वे स्वयं ही कार्यवाही करने की पहलकदमी करें । जन समुदाय को तीव्रता से तथा व्यापक पैमाने पर लामबंद करने के लिए कार्यदलों का निर्माण किया गया, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, कदम-ब-कदम गरीब किसानों तथा खेत-मजदूरों की किसान सभाएं गठित करने में मदद की तथा बाद में मध्यम किसानों को शामिल करने हेतु इन सभाओं का विस्तार किया गया। पार्टी की नीति थी कि मध्यम किसानों के हितों की दृढ़ता से रक्षा की जाए । मध्यम किसानों का एक हिस्सा, जिसके पास इलाके में प्रति व्यक्ति से औसतन ज्यादा जमीन थी, उसे

तथा स्थानीय राष्ट्रवाद, दोनों ही गलत थे । अन्धराष्ट्रवाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की खास विशिष्टताओं, देश के समाजवादी निर्माण में उनकी भूमिका (जो वे अदा कर सकते थे), उनके विकास व उन्नति तथा समानता व स्वायत्तता के उनके अधिकार की अवहेलना करता था । स्थानीय राष्ट्रवाद, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के सामूहिक तथा दूरगामी हितों, समस्त राष्ट्र के हितों तथा एक-दूसरे से प्राप्त किये जा सकने वाले बहुमूल्य अनुभवों एवं सहायता की अवहेलना करता था । चौथे, जनवादी सुधारों तथा समाजवादी निर्माण लागू करने के तरीके तथा कदम सभी राष्ट्रीयताओं के लिए एक समान नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्रत्येक की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उनके मतभेद, उनकी आकांक्षाएँ, उनकी राजनीतिक चेतना और यहां तक कि उनके बीच भूतकाल में जो अवरोधक (barriers) विद्यमान थे, इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी था । राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के बीच सुधार लागू करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करना तथा अल्पसंख्यकों को अपनी समस्याओं पर स्वयं ही विचार करने की अनुमति देना, जरूरी था । राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के उच्च वर्ग के लोगों के साथ लंबे समय तक जुड़ना तथा सहयोग करना, तथा कार्यों के विषय में उनके साथ लगातार सलाह-मशविरा करना भी बेहद जरूरी था। सिलसिलेवार कदमों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के बीच सुधार लागू करने की यह नीति, चीन में राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान हेतु वस्तुगत स्थितियों की माँग का प्रतिबिम्ब थी ।

मुक्ति के बाद, राज्य-संचालित व्यापार उद्यमों की स्थापना सुदूर, पिछड़े जिलों में की गई, जहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बसते थे । इस प्रकार उन्हें उत्पादन के औजार तथा दैनिक जरूरत की वस्तुएं मुहैया कराई गईं तथा उनसे स्थानीय उत्पाद खरीदे गए । क्रय-विक्रय, दोनों ही वाजिब दामों पर किये गये । जहाँ अल्पसंख्यकों ने रजामन्दी प्रकट की, उनके कृषि-क्षेत्रों में कृषि-सुधार लागू किये गये तथा उनके चरागाही क्षेत्रों में अन्य सुधार लागू किए गए । जन-सरकार ने उनकी कृषि तथा पशुपालन के विकास में विभिन्न तरीकों से मदद की । हर काउंटी में स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, जिससे आबादी में निरंतर वृद्धि होने लगी । अल्पसंख्यक क्षेत्रों की संचार व्यवस्था में सुधार लाया गया तथा कुछ जगहों पर आधुनिक उद्योग स्थापित किए गए । भीतरी मंगोलिया तथा सिनच्याङ में लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुओं व तेल कारखानों के विशाल आधार-क्षेत्र स्थापित किए गए । पार्टी सदस्यों की सक्रिय लेकिन सावधानीपूर्वक भर्ती करने, तथा विशाल संख्या में एवं व्यापक आधार पर अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की नीति पर चलते हुए, पार्टी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अपनी पैठ बना ली तथा बहुत से स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया । जन-सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अल्पसंख्यकों की सहायता की तथा अनेक राष्ट्रीयताओं की लिपिबद्ध भाषाओं के आविष्कार अथवा सुधार के लिए उन्हें सहयोग देने पर भी विशेष बल दिया । उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओं, आदतों तथा धर्मों का पूरा सम्मान किया गया । इस प्रकार, सभी राष्ट्रीयताएँ देश के एक बड़े परिवार में एकबद्ध हो गईं तथा उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था व संस्कृति के क्षेत्र में शानदार तथा अभूतपूर्व प्रगति की । मार्क्सवादी-लेनिनवादी राष्ट्रीय सिद्धान्त तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय नीति ने वह रास्ता रौशन कर दिया था जिस पर चलकर चीन की सभी राष्ट्रीयताएँ आगे बढ़ सकती थीं।

मई, 1951 में केन्द्रीय जन-सरकार तथा तिब्बत की स्थानीय सरकार के बीच तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के उपायों पर समझौता सम्पन्न हुआ ।

समझौते में व्यवस्था थी—कि तिब्बत की स्थानीय सरकार दृढ़ता से साम्राज्यवादी प्रभावों से अपना पिण्ड छुड़ाए तथा जन-मुक्ति सेना को तिब्बत में दाखिल होने में सक्रिय सहयोग दे; तिब्बत में सभी विदेशी मामलों का संचालन केन्द्रीय जन-सरकार करे; दूसरे शब्दों में, तिब्बत की स्थानीय सरकार साम्राज्यवादियों के साथ अपने सम्बन्धों को तोड़ दे तथा एक बार फिर से चीनी लोक गणराज्य के विशाल परिवार में सम्मिलित हो जाए । जहाँ तक तिब्बत के अन्दरूनी मामलों का सम्बन्ध था, समझौते में व्यवस्था थी कि उसकी मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था तथा दलाई लामा का रुतबा व प्राधिकार वैसे के वैसे ही रहेंगे तथा तिब्बती जनता की धार्मिक आस्थाओं को पूरा संरक्षण दिया जाएगा । तिब्बत में सामाजिक सुधारों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार की बाध्यता न थी । बल्कि, उम्मीद की गई कि तिब्बत की स्थानीय सरकार ही स्वेच्छा से सुधारों को लागू करेगी । यदि जनता सुधारों की माँग करे, मामला सलाह-मशविरे से हल किया जाना था ।

इस समझौते से तिब्बती जनता सदा-सदा के लिए साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्त हो गई तथा उन्हें राष्ट्रीय समानता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के पूर्ण अधिकार मिल गए । मुक्ति के बाद, पार्टी द्वारा तिब्बत में एक देशभक्तिपूर्ण, साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चा स्थापित करने से तिब्बती जनता तथा देश की अन्य राष्ट्रीयताओं के बीच सम्बन्ध मजबूत हुए । राष्ट्रीय निर्माण के साथ-साथ, नए तिब्बत के निर्माण के लिए शीखाङ-तिब्बत तथा छिङहाए-तिब्बत राजमार्गों का पहले के अगम्य तिब्बती पठार के आर-पार निर्माण किया गया । तिब्बत के बड़े नगरों के बीच अतिरिक्त राजमार्ग बनाए गए तथा वायु सेवा शुरू की गई । तिब्बत में, बड़े पैमाने पर, संसाधनों की खोज का काम शुरू हुआ । ऐसी उम्मीद की गई कि तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के फलस्वरूप, तिब्बती जनता अंधेरे से रोशनी में आएगी, धीरे-धीरे तिब्बत की आबादी बढ़ेगी तथा इसकी अर्थव्यवस्था व संस्कृति का और ज्यादा विकास होगा । यह तिब्बती जनता, समूचे तौर पर चीनी जनता, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के राष्ट्रीय सिद्धान्त तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय नीति की जीत थी ।

राष्ट्रीय कार्य में सफलता तथा चीन में विभिन्न राष्ट्रीयताओं की महान एकता ने चीन की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को मजबूत किया तथा चीनी लोक गणराज्य में जनता के जनवादी अधिनायकत्व को सुदृढ़ किया । ●

4.

- **कृषि-सुधारों का संपूर्ण होना ।**
- **उद्योग एवम् वाणिज्य का रूपान्तरण ।**
- **''सान फान'' तथा ''ऊ फान'' आन्दोलन ।**
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कार्य का समापन ।**

अमरीका-प्रतिरोध तथा कोरिया-सहयोग आन्दोलन को विजयश्री मिलने, व जनता की राजसत्ता के और ज्यादा सुदृढ़ीकरण के बाद, चीनी जनता ने पार्टी के निर्देशन में कृषि-प्रणाली को सुधारने का बीड़ा उठाया ।

".....चीन की राष्ट्रीयताओं की एकता की ताकत में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि यह सतत बढ़ती मैत्री तथा परस्पर सहायता; तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध, राष्ट्रीयताओं के अन्दर जनता के सार्वजनिक शत्रुओं के विरुद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र के अंधराष्ट्रवाद व स्थानीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष पर आधारित है.....।"

संविधान, समानता के आधार पर, राष्ट्रीयताओं के बीच मैत्री, परस्पर सहायता तथा सहयोग को सुनिश्चित करता है ।

संविधान के अध्याय दो के पाँचवें खण्ड में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रावधान है, अर्थात् ऐसे क्षेत्र, जहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की सघन सामूहिक आबादी है, वहां स्वायत्तशासी क्षेत्रों, स्वायत्तशासी चओं, या स्वायत्तशासी काउंटियों की स्थापना करना तथा स्वशासन के संगठनों की स्थापना करना, ताकि इन क्षेत्रों की जनता संविधान तथा कानून में तय मान दण्डों की सीमा के अन्तर्गत अपने स्वायत्तता के अधिकार का इस्तेमाल कर सके, तथा जो तरीके व कदम उन्हें स्वीकार्य हों, उन द्वारा, अपनी ही राष्ट्रीय विशिष्टताओं के मद्देनजर अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास कर सके ।

संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट है कि संक्रमणकाल के दौरान देश का बुनियादी कार्यभार पूरा करने के लिए देश की सभी राष्ट्रीयताओं की ठोस एकता का होना एक महत्त्वपूर्ण शर्त है । विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच मैत्री, परस्पर सहायता तथा सहयोग का सुदृढ़ीकरण तथा विकास जनता के जनवादी अधिनायकत्व को और ज्यादा मजबूत करेगा तथा समाजवाद के उद्देश्य को आगे बढ़ायेगा ।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुसार समाज की अधिरचना (Superstructure) उसके आर्थिक आधार की ही एक उपज होती है, परन्तु एक बार अस्तित्व में आने के बाद, यह प्रतिक्रिया कर सकती है तथा आर्थिक आधार के विकास को आगे ले जा सकती है । किसी देश का संविधान अधिरचना का एक महत्त्वपूर्ण रूप विधान होता है जो स्थापित आर्थिक आधार की कारगर तरीके से हिफाजत तथा विकास करता है । यही कारण है कि समाजवाद-निर्माण तथा जनता की समृद्धि के लिए संघर्ष में चीनी लोक गणराज्य का संविधान एक सर्वाधिक प्रभावशाली हथियार बन गया है ।

राष्ट्रीय जन-कांग्रेस में, चीनी जनता के महान नेता, कामरेड माओ त्से-तुङ को चीनी लोक गणराज्य का अध्यक्ष चुना गया, कामरेड ल्यू शाओ-ची, चओ एन-लाई, चू तेह, छन युन तथा विभिन्न राष्ट्रीयताओं, जनवादी वर्गों तथा जनवादी पार्टियों के नेतृत्वकारी सदस्यों को भी चुना गया या फिर उन्हें सरकार में महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकारी पद किए गए । ●

3.

● समाजवादी क्रांति में राष्ट्रव्यापी उभार

1955 की सर्दियों तथा 1956 के उत्तरार्द्ध में समाजवादी क्रान्ति में उभार आया, जो पहले देहात में प्रकट हुआ ।

देश के औद्योगिक विकास की तीव्र प्रगति के लिए कृषि की सही प्रगति भी जरूरी थी। चूँकि कृषि सहकारिता के बिना समाजवादी औद्योगीकरण नहीं लाया जा सकता था, इसलिए

निजी उद्यमों के श्रमिकों ने पार्टी की संयुक्त मोर्चे की नीति को सही तरीके से लागू किया, तथा कठिनाइयों पर विजय पाने में पूँजीपतियों की मदद की व इस प्रकार उन निजी उद्यमों का पुनरुद्धार किया जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा जनता के जीवनयापन के लिए लाभप्रद थे । बाद में, जब पूँजीपतियों ने श्रमिक वर्ग के विरुद्ध *"पाँच बुराइयों"* वाला भयंकर हमला बोला, श्रमिकों ने पार्टी के नेतृत्व में *ऊ फान* आन्दोलन चलाया, हमले का प्रतिकार किया तथा निजी उद्यमों को राजकीय योजनाओं के दायरे में ले आए ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, श्रमिक संगठनों ने दसियों लाख श्रमिकों का आह्वान किया कि वे स्वेच्छा से आर्थिक निर्माण में हाथ बटाएँ । इसका उद्देश्य एक ओर तो राज्य की उत्पादन-योजनाओं को पूरा करना, उद्यमों के लिए धन राशि इकट्ठा करना तथा राष्ट्र की पूँजी में वृद्धि करना था; तथा दूसरी ओर, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करना, श्रम-बीमा योजना लागू करना तथा उनके काम-काज करने के और रहन-सहन के हालात में सुधार लाना था । इस प्रकार व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से सम्बद्ध कर दिया गया, श्रमिकों की जन-जीविका में सुधार को उत्पादन-वृद्धि के साथ, श्रमिक आन्दोलन को कम्युनिस्ट आन्दोलन के साथ तथा आर्थिक निर्माण को साम्यवाद के साथ सम्बद्ध कर दिया गया । ट्रेड यूनियनों ने, श्रमिकों को शिक्षित करते हुए, यह बात समझने में उनकी मदद की कि उनके तत्कालिक आंशिक हित दीर्घकालीन व्यापक हितों की तुलना में गौण हैं तथा उन्हें बहादुरी से एक कम्युनिस्ट समाज के शानदार भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए ।

पार्टी को सुदृढ़ करने व पार्टी संगठनों को मजबूत बनाने के लिए, 1951 में पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा आयोजित **'संगठनात्मक काम के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन'** में फैसला लिया गया कि 1951 के उत्तरार्द्ध से सभी पार्टी संगठनों की सामान्य तौर पर जाँच की जाए। पार्टी सदस्यों की विशाल संख्या तथा एक क्षेत्र की मुक्ति तथा दूसरे क्षेत्र की मुक्ति के बीच समय के अन्तर तथा कार्यकर्ताओं में योग्यता के विभिन्न स्तरों को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया कि पार्टी के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा होने में तीन वर्ष लग जाने थे । बुनियादी तौर पर तरीका यह था कि आधारभूत पार्टी संगठनों के सदस्यों को साम्यवाद तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में शिक्षित किया जाए तथा इसके आधार पर प्रत्येक सदस्य की गहरी परीक्षा ली जाए ।

इस परीक्षण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के निर्माण का कार्य शुरू किया गया तथा इस प्रकार पार्टी की पाँतों में वृद्धि हुई । पार्टी के सुदृढ़ीकरण तथा पार्टी निर्माण के कार्य ने सैद्धांतिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक दृष्टि से समस्त पार्टी को और ज्यादा शुद्ध तथा एकताबद्ध कर दिया तथा इसकी गुणवत्ता व जुझारू शक्ति में और ज्यादा वृद्धि की व इस प्रकार पार्टी राष्ट्रीय निर्माण के कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने व संगठित करने में सक्षम हुई । ●

नोट

1. बाद में निम्नलिखित देशों ने चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए : नार्वे, युगोस्लाविया, अफगानिस्तान, नेपाल, यमन, श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य, कंबोडिया, इराक, ब्रिटेन तथा नीदरलैण्ड ।

2. कोरिया में युद्ध विराम व हिंद चीन में शांति की पुनर्स्थापना, तथा चीन की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के मजबूत होने के बाद, सुदूर पूर्व में परिवर्तित हालात के मद्देनजर, 12 अक्तूबर, 1954 को सोवियत-संघ तथा चीन में यह सहमति हुई कि लूशुन के नौसैनिक अड्डे से सोवियत सैनिक हटा लिए जाएं तथा ताल्येन का प्रशासन पूरी तरह चीन को सौंप दिया जाए।

3. ***सान फान* आन्दोलन** :- यह "तीन बुराइयों"—भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची तथा नौकरशाही के विरुद्ध एक आन्दोलन था ।

4. ***ऊ फान* आन्दोलन** :- यह आन्दोलन, "पाँच बुराइयों"—सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेना, कर चोरी, सरकारी सम्पत्ति की चोरी, सरकारी ठेकों में धाँधलेबाजी तथा आर्थिक सूचनाओं की चोरी के विरुद्ध था ।

●●●

उत्साह तथा रचनात्मकता को पूरा अवसर प्रदान कर सकता है तथा इस आधार पर अत्यधिक केन्द्रीकृत तथा एकीकृत नेतृत्व का उपयोग कर सकता है ।

संविधान के अनेक अनुच्छेदों में जनता के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है ।

संविधान में उल्लिखित जनता के मौलिक अधिकार तथा कर्त्तव्य जनता के जनतंत्र की प्रणाली की श्रेष्ठता को प्रकट करते हैं । लोगों द्वारा राज्य के मामलों में हिस्सा लेते वक्त तथा राजनीतिक गतिविधियां चलाते वक्त, संविधान में उनके निम्नलिखित अधिकारों व स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है । उन्हें अभिव्यक्ति, प्रकाशन (Press), सभा करने, संगठन बनाने व प्रदर्शन करने की आजादी का अधिकार है । यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का उल्लंघन करता है तो उन्हें उस कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है । उन्हें वोट डालने व चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है । उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा उनके घरों की आजादी अलंघनीय है । उत्पादक श्रम करने व सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलाने के उनके अधिकारों को भी परिभाषित किया गया है । उन्हें काम करने व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है । मेहनतकश जनता को आराम करने तथा मनोरंजन का अधिकार है तथा बुढ़ापे में व बीमारी अथवा अशक्तता की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ।

दूसरी ओर, प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों का स्वेच्छा से निर्वाह करे । इन कर्त्तव्यों में संविधान तथा कानून का पालन करना, श्रम-अनुशासन का पालन करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आचार-संहिता का पालन करना, सार्वजनिक सम्पत्ति का सम्मान व रक्षा करना, तथा नियमानुसार टैक्स अदा करना, सैनिक सेवा करना व मातृभूमि की रक्षा करना शामिल हैं ।

नागरिकों के ये कर्त्तव्य तथा अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए तथा अविभाज्य हैं । अधिकारों के बिना कर्त्तव्यों की बात सोची ही नहीं जा सकती, ठीक इसी प्रकार कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों की बात भी नहीं सोची जा सकती । प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के पूर्ण उपभोग का अधिकार है, लेकिन उसके लिए पूरी ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना भी जरूरी है ।

(3) संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सभी राष्ट्रीयताओं को मैत्री व समानता के आधार पर परस्पर सहयोग तथा सहायता करनी चाहिए । राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के स्वशासन के अधिकार की तथा उनकी राष्ट्रीयताओं का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करने के अधिकार की, मातृभूमि के राष्ट्रीय निर्माण के साथ तालमेल बिठाते हुए रक्षा की जानी थी ।

सामान्य सिद्धान्तों के अनुच्छेद-3 के अनुसार सभी राष्ट्रीयताएँ समान हैं । किसी भी राष्ट्रीयता से भेदभाव करना या उसका दमन करना या ऐसे काम जो राष्ट्रीयताओं की एकता को क्षति पहुँचाते हों, वर्जित हैं ।

चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के पश्चात, देश में सभी राष्ट्रीयताओं को स्वतंत्र तथा समान राष्ट्रों के एक महान परिवार में एकीकृत कर दिया गया । उनके बीच मैत्री तथा सहयोग के नए संबंध स्थापित किए गए । इस क्षेत्र में प्राप्त सफलताएँ संविधान में अभिव्यक्त हुई है, जिसका प्रस्तावना में उल्लेख है :

(2) संविधान में अनुबन्ध किया गया है कि राज्य-प्रणाली जन-कांग्रेसों की प्रणाली है। प्रथम अध्याय के पहले दो अनुच्छेदों में वर्णित है कि **"चीनी लोक गणराज्य, जनता का जनवादी राज्य है"** तथा **"राज्य की समूची शक्ति जनता में निहित है ।"** चूँकि शासकीय शक्ति जनता के हाथों में है, इसलिए उसके लिए यह जरूरी था कि वह सरकारी संगठनों की स्थापना तथा इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सही संगठनात्मक किस्मों को अपनाए । जन-कांग्रेस सरकारी संगठनों की बुनियादी किस्म है ।

राष्ट्रीय जन-कांग्रेस राजसत्ता का सर्वोच्च संगठन तथा एकमात्र वैधानिक संस्था है । राज्य के सभी केन्द्रीय संगठन इस द्वारा गठित किए जाते हैं, इस द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है तथा इस द्वारा उन्हें खत्म भी किया जा सकता है । यह राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं पर निर्णय लेती है, राज्य के बजट व वित्तीय रिपोर्ट की छानबीन करती है तथा इन्हें स्वीकृति प्रदान करती है, तथा सामान्य राजक्षमादानों (amnesties), युद्ध तथा शांति के प्रश्नों, तथा राज्य के दूसरे महत्त्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेती है । यह राज्य की वैधानिक तथा कार्यकारी शक्तियों को एकबद्ध करती है तथा इसके हाथों में राजसत्ता की उच्चतम शक्ति केन्द्रित होती है । जन-कांग्रेसों द्वारा इस्तेमाल की गई सत्ता सीधे जनता से प्राप्त होती है । क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर होता है । **ये कांग्रेसें पूरी तरह जनता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा सुनिश्चित करती हैं कि समूची राज्य-शक्ति की स्वामी जनता है ।**

राज्य के संगठनों में, जो सभी के सभी जन-कांग्रेसों से उद्‌भूत होते हैं, इस सिद्धांत का पालन किया जाता है कि स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं तथा निम्न स्तर की सरकारें उच्च स्तर की सरकारों के अधीन हैं, ताकि सारे देश में केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीकृत तथा एकीकृत नेतृत्व को सुनिश्चित किया जा सके । केन्द्रीकृत तथा एकीकृत नेतृत्व के इस सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रीय जन-कांग्रेस द्वारा पारित सभी कानूनों तथा आज्ञप्तियों, तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए इस द्वारा निर्धारित सभी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं व नीतियों का सभी राजकीय संगठनों द्वारा कड़ाई से पालन करना व उन्हें कार्यान्वित करना जरूरी है ।

संविधान में स्थानीय जन-कांग्रेसों, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन-परिषदों, तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों के संगठनों के कार्यों तथा शक्तियों के बारे में भी समुचित व्यवस्था की गई है । यह सुनिश्चित किया गया है कि समस्त देश के लिए तय योजनाओं तथा कार्यभारों को लागू करते वक्त, विभिन्न इलाकों की पहलकदमी को पूरा अवसर सुलभ हो सके ।

राज्य के संगठनों ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, सरकारी कर्मचारियों ने जनता की निष्ठापूर्वक सेवा करनी है, तथा जनता पर धौंस नहीं जमानी या उसके कल्याण की अवहेलना करते हुए उस पर नौकरशाही नहीं चलानी—संविधान के प्रथम अध्याय, (जिसमें सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख है), में यह सब पूर्णतया तथा पक्के तौर पर निश्चित किया गया है ।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजकीय मशीनरी तथा राज्य-प्रणालियां और ज्यादा संपूर्ण हो गई थीं, तथा जनता का जनवादी जीवन और ज्यादा विकसित हो गया था । ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि समाजवाद निर्माण के महान उत्सव में देश सभी सामाजिक शक्तियों को एकबद्ध तथा लामबंद कर सकता है, तथा समस्त जनता व सभी स्थानीय राजकीय संगठनों के

पंद्रहवां अध्याय

आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रान्ति की बुनियादी विजय

(1953 से जून 1956)

1.

- **संक्रमणकाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आम कार्यदिशा ।**
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-1957)।**
- **काओकाङ तथा राओ शू-श के पार्टी-विरोधी गिरोह का पार्टी द्वारा सफाया ।**

चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के बाद, चीनी क्रान्ति पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति की मंजिल से समाजवादी क्रान्ति की मंजिल में प्रवेश कर गई, यानि कि यह पूँजीवाद से समाजवाद के संक्रमणकाल में दाखिल हो गई । मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुसार पूँजीवादी समाज तथा समाजवादी समाज के बीच एक संक्रमणकाल का होना जरूरी है । ऐसे काल का अस्तित्व इसलिए अनिवार्य है क्योंकि समाजवाद की संपूर्ण विजय के लिए जरूरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को पैदा करने तथा गैर-समाजवादी आर्थिक तत्वों को समाजवादी उसूलों के अनुसार ढालने के लिए समय की जरूरत होती है । कोई देश आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से जितना अधिक पिछड़ा हुआ होगा, संक्रमणकाल की अवधि उतनी ही अधिक होगी । समाजवाद की संपूर्ण विजय के लिए जरूरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक हालात उत्पन्न करने के लिए तथा व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित विशाल कृषि तथा हस्तशिल्प के रूपान्तरण, तथा साथ ही पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के रूपान्तरण के लिए चीन को एक काफी लंबे संक्रमणकाल की जरूरत थी ।

1952 में ही, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने संक्रमणकाल के लिए आम कार्यदिशा प्रस्तुत कर दी । 1954 में, राष्ट्रीय जन-कांग्रेस ने इस कार्यदिशा को स्वीकृति प्रदान कर दी तथा इसे संविधान में शामिल कर लिया गया । अतः इस कार्यदिशा को संक्रमणकाल में साकार करना देश का मूलभूत कार्यभार बन गया ।

संक्रमणकाल में देश की आम कार्यदिशा इस प्रकार थी—धीरे-धीरे देश का समाजवादी औद्योगीकरण किया जाए तथा अपेक्षाकृत काफी लंबे समय के दौरान कृषि, दस्तकारी तथा पूँजीवादी उद्योगों व वाणिज्य का समाजवादी रूपान्तरण किया जाए ।

चूँकि चीन आर्थिक दृष्टि से एक बेहद पिछड़ा हुआ देश था, अतः समाजवादी औद्योगीकरण के बिना देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना करना असंभव हो जाता । भूतकाल में जो भी थोड़ा बहुत उद्योग देश में था, वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा

हिस्सा था । भारी उद्योग का अनुपात तो और भी कम था । यह सच है कि पुनरुद्धार के दौर के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ने आगे कदम बढ़ाया, किन्तु यह अभी भी एक निर्धन तथा पिछड़ा हुआ कृषि-प्रधान देश था । समाजवादी औद्योगीकरण बेहद जरूरी था ताकि चीन में एक शक्तिशाली उद्योग हो जो सभी प्रकार के औद्योगिक उपकरणों का उत्पादन करने में सक्षम हो, व इसका स्वरूप पूर्णत: समाजवादी हो ।

कुल मिलाकर, उद्योग का विकास भारी उद्योग पर आधारित होता है, तथा इसकी विकास-दर औद्योगिक विकास की सामान्य दर को तय करती है । अत: भारी उद्योग का विकास किसी भी देश के समाजवादी औद्योगीकरण की कुंजी है । चीन में, एक ऐसे देश में जिसकी आबादी 60 करोड़ थी, तथा जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था, समाजवादी औद्योगीकरण लागू करने तथा इसे एक व्यापक औद्योगिक प्रणाली प्रदान करने के लिए, भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता देना जरूरी था ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक जटिल सुव्यवस्थित संपूर्ण इकाई होती हैं, जिसमें भारी उद्योग के अतिरिक्त, अनेक अन्य आर्थिक शाखाएं यथा—कृषि, हल्के उद्योग, वाणिज्य, संचार तथा परिवहन वगैरा समाहित होती हैं, जो लोगों की जरूरतों की पूर्ति करती हैं, निर्माण के लिए धनराशि एकत्र करती हैं अथवा समूचे समाज से तालमेल स्थापित करते हुए पुनरुत्पादन करती हैं । अत:, जबकि मुख्य जोर भारी उद्योग के विकास पर दिया जाना चाहिये, उपरोक्त शाखाओं तथा साथ ही, सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यों का भी तदनुरूप विकास, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिये ।

कृषि तथा हस्तशिल्पों का समाजवादी रूपान्तरण संक्रमणकाल के प्राथमिक कार्यभार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था । चूँकि कृषि-सुधारों के समापन के बाद, कृषि में लघु किसान अर्थव्यवस्था अभी भी अत्यधिक प्रभुत्वकारी स्थान बनाए हुए थी । बिखरी हुई तथा पिछड़ी होने के कारण लघु किसान अर्थव्यवस्था कृषि-उत्पादक शक्तियों को अवरुद्ध कर रही थी तथा ऐसी व्यवस्था द्वारा उत्पादित जिन्सों का बिखरा स्वरूप देश के योजनाबद्ध आर्थिक निर्माण से मेल नहीं खाता था । इसके अतिरिक्त, लघु किसान अर्थव्यवस्था अस्थिर थी, क्योंकि यह निरंतर वर्ग विभेदीकरण की ओर ले जाती थी ।

चीन में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण शाखा थी । यह उद्योग को कच्चा माल तथा अनाज मुहैया कराती थी । किसान, निर्मित वस्तुओं के लिए विशालतम बाजार मुहैया कराते थे तथा चीन के निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उपज थी । अत: कृषि के विकास ने उद्योग के विकास को खूब प्रभावित किया ।

यह सुस्पष्ट था कि लघु किसान अर्थव्यवस्था राज्य तथा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकती थी । पुनरुत्पादन के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के अनुसार, हर वर्ष बढ़ते संग्रह के अभाव में आधुनिक समाज आगे नहीं बढ़ सकता था, और यह वृद्धि हर वर्ष फैलते पुनरुत्पादन पर निर्भर करती थी । देश के उद्योग का विकास फैलते पुनरुत्पादन (Expanded Reproduction) के मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार किया गया, तथा उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि की गई । तथापि लघु-किसान अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से के लिए पुनरुत्पादन का वार्षिक प्रसार असंभव था । यह एक जाना माना तथ्य है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग तथा कृषि के मध्य एक सही अनुपात रखा जाना चाहिए । समाजवादी

स्वामित्व का स्थान समाजवादी स्वामित्व ले ले, जो कि अन्तत: देश में स्वामित्व की एकमात्र किस्म होनी थी । संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अर्थव्यवस्था के राजकीय तत्व, जिनका स्वामित्व समस्त जनता के हाथों में है तथा जिनका स्वरूप समाजवादी है, तथा अर्थव्यवस्था के सहकारिता वाले तत्व, जिनका स्वरूप श्रमिक वर्ग के सामूहिक स्वामित्व की मात्रा अनुसार समाजवादी अथवा अर्ध-समाजवादी है, के अतिरिक्त देश में एकल श्रमिक जनता के स्वामित्व वाली तथा पूँजीवादी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था भी विद्यमान है, तथा ये दोनों निजी-स्वामित्व की किस्में हैं । संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्य वैयक्तिक श्रमिक जनता के जमीन, उत्पादन के साधनों तथा अन्य सम्पत्ति के कानून-सम्मत स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करता है । साथ ही, यह उन्हें स्वयं को, स्वेच्छा से तथा कदम-दर-कदम सहकारी समितियों में गठित करने तथा आंशिक सामूहिक स्वामित्व की मंजिल से गुजरते हुए पूर्ण सामूहिक स्वामित्व की मंजिल तक पहुँचने के लिए भी प्रोत्साहित करता है । राज्य पूँजीपतियों के उत्पादन के साधनों तथा अन्य संपत्ति के कानून-सम्मत स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करता हैं । साथ ही, यह पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य को प्रेरित करता है कि वे स्वयं को धीरे-धीरे राजकीय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूपाकारों में ढाल लें तथा अन्तत: समस्त जनता के स्वामित्व वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित हो जाएं ।

कृषि तथा हस्तशिल्पों के समाजवादी रूपान्तरण के लिए मुख्य संक्रमणकालीन किस्म सहकारी समिति है, जो श्रमिक वर्ग के आंशिक सामूहिक स्वामित्व पर आधारित होती है, तथा कृषि उत्पादकों की प्रारंभिक सहकारी समितियों की तरह जिसकी मुख्य विशेषता जमीन का एकीकरण व एकीकृत प्रबन्धन होती है । पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण के लिए संक्रमणकालीन किस्म राजकीय-पूँजीवाद है । इन संक्रमणकालीन किस्मों ने, जिनका संविधान में भी उल्लेख किया गया था, देश के समाजवादी रूपान्तरण पर गहरा असर डाला ।

दूसरे, जैसा कि संविधान में निर्धारित किया गया है, देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समाजवादी रूपान्तरण शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाएगा । संविधान के सामान्य सिद्धान्तों में कहा गया है कि **"चीनी लोक गणराज्य जनता का जनवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथ में है, तथा यह श्रमिकों तथा किसानों के संश्रय पर आधारित है।"** इससे देश में बुनियादी सामाजिक-सम्बन्धों तथा वर्ग-संबंधों की स्पष्ट झलक मिलती है । लोक जनवादी राज्य चीन के समाजवाद में शांतिपूर्वक पदार्पण करने की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गारंटी है । श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में लोक जनतन्त्र की राज्य-प्रणाली स्थापित की गई तथा चीन की समाजवादी राजकीय अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन व्यापक होती चली गई, तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में अगुवा शक्ति बन गई तथा इसने पूँजीवाद के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, श्रमिक वर्ग व राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के बीच भी संश्रय था । देश का कदम-दर-कदम समाजवादी रूपान्तरण करने हेतु ऐसे राजकीय ढाँचे तथा सामाजिक शक्तियों पर भरोसा किया जा सकता था । निस्सन्देह, पाबन्दी के दौरान तथा बाद में, पूँजीवाद के खात्मे के वक्त, वर्ग-संघर्ष अपरिहार्य था, लेकिन सरकारी प्रशासन के नियंत्रण, राजकीय स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था के नेतृत्व तथा मेहनतकश जनता की देखरेख ने, शान्तिपूर्ण संघर्ष द्वारा इस लक्ष्य को साकार करना संभव कर दिया ।

चीनी सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया कि शक्ति के इस्तेमाल के साथ-साथ, थाएवान को शांतिपूर्ण उपायों द्वारा मुक्त कराने की संभावना भी विद्यमान थी । सरकार ने थाएवान में क्वोमिंताङ के सभी जिम्मेदार सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों से देशभक्ति की अपील की तथा थाएवान की शांतिपूर्ण मुक्ति में सहायता करने के लिए उनका आह्वान किया । तथापि, एक बात स्पष्ट कर दी गई थी कि चाहे किसी भी प्रकार के तरीके इस्तेमाल करने पड़ें, थाएवान की मुक्ति चीन का घरेलू मामला था । किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाना था ।

चीन के आर्थिक निर्माण के विकास तथा जनता के जीवनयापन में सुधार को लगातार सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ते जनता के जनवादी अधिनायकत्व से तथा सरकारी मशीनरी के बढ़ते विस्तार से अलग करके नहीं देखा जा सकता ।

मुक्ति के बाद, शुरू के कुछ वर्षों में, जब विभिन्न स्तरों पर जन-कांग्रेसों के आयोजन के लिए हालात परिपक्व नहीं थे, चीन सरकार ने स्थानीय जन-प्रतिनिधि सम्मेलनों के आयोजन का अंतरिम उपाय अपनाया ताकि वे कदम-दर-कदम स्थानीय जन-कांग्रेसों के रूप में काम करें तथा विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन-सरकारों का चुनाव करें । 1953 में, सार्वजनिक मतदान प्रणाली के आधार पर देश के विभिन्न भागों में चुनाव हुए । **मूल स्तर पर चुनावों** के संपन्न होने के बाद, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन-कांग्रेसों का आयोजन किया गया जिनमें काउंटी स्तर की तथा उससे ऊपरी स्तर की कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों (Deputies) को चुना गया । इसी आधार पर राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ ।

15 सितंबर, 1954 को पेकिङ में, चीनी लोक गणराज्य की प्रथम राष्ट्रीय जन-कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया । चीन को समाजवादी देश बनाने के कार्यभार को कानूनी जामा पहनाया गया तथा इसे चीनी लोक गणराज्य के संविधान में लिख दिया गया । संविधान में संक्रमणकाल के दौरान चीन की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियों की स्पष्ट व्याख्या की गई है, तथा इस प्रकार देश में समाजवादी निर्माण की पूर्ण विजय सुनिश्चित कर दी गई है । संविधान को चीन में समाजवाद को साकार करने हेतु निर्देशित किया गया है । दूसरे शब्दों में यह संविधान समाजवाद-निर्माण के लिए है, तथा इसमें चीनी जनता के बुनियादी हितों तथा आकांक्षाओं को कानूनी जामा पहनाया गया है ।

(1) देश में समाजवाद लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथा उपायों की संविधान में स्पष्ट व्याख्या की गई है । संविधान के अनुच्छेद-4 के अनुसार :

चीनी लोक गणराज्य, राजकीय संगठनों तथा सामाजिक शक्तियों पर निर्भर करते हुए, तथा समाजवादी औद्योगीकरण व समाजवादी रूपान्तरण के माध्यम से, शोषण की सभी प्रणालियों के कदम-दर-कदम उन्मूलन तथा एक समाजवादी समाज के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद में निर्धारित नीति को लागू करने के लिए, अध्याय एक के अन्य अनुच्छेदों में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो संविधान का अनिवार्य अंग हैं ।

अब प्रश्न कृषि, हस्तशिल्पों तथा पूँजीवादी उद्योग व वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण के लिए परिवर्तन की सही किस्म के इर्द-गिर्द तथा शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद को साकार करने के इर्द-गिर्द घूमता है ।

प्रथम, समाजवादी समाज के निर्माण का अर्थ है—सभी किस्म के गैर समाजवादी

निर्माण में उद्योग तथा कृषि, दोनों शामिल होते हैं । समाजवाद साकार करने के लिए, इन दो आर्थिक शाखाओं में निकट संबंध होना जरूरी था । इस प्रकार के सही अनुपात के बिना, खासतौर से जब कृषि एवं उद्योग, दोनों एक-दूसरे के विरोधी आर्थिक आधारों पर आमने-सामने खड़े थे, यानि कि—एक ओर तो विकसित समाजवादी उद्योग था तथा दूसरी ओर, लघु किसान अर्थव्यवस्था पर आधारित एक बिखरी तथा पिछड़ी कृषि-प्रणाली—तब ऐसे में समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का खतरा था, तथा समाजवाद के निर्माण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ।

लघु किसान अर्थव्यवस्था पर आधारित कृषि को आधुनिक कृषि में रूपान्तरित करने के लिए चीनी जनता के सामने दो रास्ते थे—पूँजीवादी रास्ता तथा समाजवादी रास्ता । पूँजीवादी रास्ते ने किसानों के बीच ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करनी थी, थोड़े से सट्टेबाजों तथा शोषकों ने तरक्की करके पूँजीपति वर्ग में पहुँच जाना था, जब कि बहुत बड़ी तादाद को शोषित तथा दबी-कुचली अवस्था में धकेल दिया जाना था । समाजवादी रास्ते में वैयक्तिक किसान परिवारों को विकसित सहकारी समितियों मे एकजुट किया जाना था, जो नई तकनीक से लैस थीं, तथा जिनका स्वरूप समाजवादी था, तथा इस प्रकार किसान समुदाय ऐसा जीवन व्यतीत करने के योग्य बन जाता, जिसमें भौतिक कल्याण और संस्कृति में लगातार सुधार हो रहा था । चूँकि चीन लम्बे समय तक, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लघु-कृषक अर्थव्यवस्था बने रहने की अनुमति नहीं दे सकता था और न ही इसे सहज रूप से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में विकसित होने की अनुमति दे सकता था; अत: ऐसे में एक ही संभव रास्ता था कि कृषि का समाजवादी रूपान्तरण किया जाए तथा इसे समाजवादी रास्ते पर लाया जाए ।

कृषि के समाजवादी रूपान्तरण का एक ही रास्ता था, वह था—सहकारी समितियों द्वारा। प्रथम, परस्पर-सहयोग दल, जो समाजवाद के भ्रूण का कार्य करें, संगठित किये जाने थे । इन्होंने फिर अर्ध-समाजवादी सहकारी समितियों में विकसित हो जाना था तथा बाद में पूर्णरुपेण समाजवादी सहकारी समितियों में बदल जाना था । यह परिवर्तन, जो समाजवादी तत्वों में निरंतर वृद्धि करके उन्हें पूर्ण समाजवादी सहकारिता की अवस्था में ले जाता, ही एकमात्र रास्ता था, जिसके तहत देश की लघु किसान अर्थव्यवस्था का रूपान्तरण किया जा सकता था।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्पों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा अभी भी अदा कर रहे हैं । हस्तशिल्पी विशाल किसान समुदाय के साथ निकटता से जुड़े हुए थे तथा उन्हें उत्पादन के मुख्य औजार व उपभोक्ता सामग्री मुहैया कराते थे । लेकिन हस्तशिल्प उत्पादन, जो वैयक्तिक अर्थव्यवस्था की एक किस्म था तथा उत्पादन के निजी स्वामित्व के साधनों पर आधारित था; धनाभाव से पीड़ित था, इसका दायरा सीमित था एवं यह रूढ़िवाद तथा श्रेणीवाद से बुरी तरह दूषित था । फलत: इसकी उत्पादन-क्षमता बेहद सीमित थी । अकेला दस्तकार, न तो सुनियोजित उत्पादन कर सकता था और न ही तकनीकी सुधार ला सकता था । इससे सहज ही विवेकशून्य उत्पादन तथा सट्टेबाजी होती थी, जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय निर्माण की योजना पर भी बुरा असर डालती थी।

वैयक्तिक अर्थव्यवस्था पर आधारित हस्तशिल्पों का समाजवादी रूपान्तरण भी सहकारिता के माध्यम से ही होना था, अर्थात् उन्हें आपूर्ति तथा विपणन ग्रुपों, आपूर्ति तथा विपणन सहकारी समितियों व उत्पादकों की सहकारी समितियों के तीन चरणों से गुजरना था, तभी

जाकर एकल दस्तकारों के निजी स्वामित्व का स्थान सामूहिक स्वामित्व ले सकता था ।

चीन में संक्रमणकाल के दौरान पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य का समाजवादी रूपान्तरण भी बुनियादी कार्यभार का एक महत्त्वपूर्ण अंग था । पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के प्रति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति यूँ थी : इससे लाभ उठाया जाए, इस पर नियंत्रण रखा जाए व इसका रूपान्तरण किया जाए । पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य का उपभोग करना जरूरी था, चूँकि इन्होंने निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने, देश के औद्योगीकरण के लिए धनराशि एकत्र करने, उपभोक्ता सामग्रियों के प्रसार को व्यापक बनाने, रोजगार मुहैया करने तथा कुशल श्रमिकों व प्रशासनिक कर्मियों को प्रशिक्षित करने में सहायक होना था । तथापि, नियंत्रण भी जरूरी था क्योंकि पूँजीवाद सदा मुनाफे के चक्कर में रहता था, तथा इसकी नैसर्गिक भाड़े की प्रवृत्ति स्वभावत: इसे सट्टेबाज गतिविधियों व "पांच बुराइयों" की ओर ले जाती थी । अन्तत: रूपान्तरण का सर्वोपरि महत्त्व था क्योंकि पूँजीवाद के उत्पादन संबंधों का उत्पादन की शक्तियों के विकास से वैर था तथा उत्पादन में इसकी अराजकता का समाजवादी अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास से मेल नहीं बैठता था । अत: यह जरूरी था कि धीरे-धीरे पूँजीवादी स्वामित्व का स्थान समस्त जनता का स्वामित्व ले ले ।

पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य का रूपान्तरण राजकीय पूँजीवाद के माध्यम से किया जा सकना था । राज्य के प्रशासनिक संगठनों द्वारा लागू नियंत्रणों, राजकीय स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदत्त नेतृत्व व श्रमिकों की देखरेख द्वारा निजी पूँजीवाद को राजकीय पूँजीवाद की धारा में लाया जा सकता था । राजकीय पूँजीवाद एक खास किस्म का पूँजीवाद था जिसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य राज्य तथा जनता की जरूरतें पूरी करना था, तथा पूँजीपतियों को मुनाफा कमाने की खुली छूट न थी । इसकी तीन किस्में थीं । प्रारंभिक किस्म के अंतर्गत राज्य एक निजी उद्यम के उत्पादों की केवल खरीद तथा विपणन करता था, मध्यम किस्म के तहत निजी उद्यमों को संसाधन तथा निर्माण के आर्डर दिये जाते थे, तथा विकसित किस्म के तहत राज्य तथा निजी पूँजी का संयुक्त स्वामित्व एवं संचालन होता था ।

एकल पूँजीपतियों तथा उनके एजेन्टों के पुनर्संस्कार के साथ-साथ ही उनके उद्यमों का भी रूपान्तरण किया जाना था । एक ओर, पूँजीवादी उद्यमों को धीरे-धीरे प्रगतिशील समाजवादी उद्यमों में बदला जाना था; दूसरी ओर, पूँजीपतियों तथा उनके एजेन्टों का सैद्धान्तिक स्तर पर पुनर्संस्कार किया जाना था, ताकि जहाँ तक संभव हो सके वे देश के समाजवादी रूपान्तरण में सक्रिय तथा उपयोगी भूमिका निभा सकें ।

पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य का उपयोग, उस पर पाबन्दी तथा उसका रूपान्तरण, संक्रमणकाल के दौरान श्रमिक वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष का एक नया रूप था । समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास तथा श्रमिक वर्ग की बढ़ती शक्ति ने, निस्सन्देह, समाजवाद का निर्माण जल्दी करने तथा पूँजीपतियों का एक वर्ग के रूप में सफाया करने में सहायक सिद्ध होना था।

संक्रमणकाल में पार्टी द्वारा निर्धारित आम कार्यदिशा को साकार करने के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-57), एक महत्त्वपूर्ण कदम थी।

1951 के आरंभ में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करनी आरंभ कर दी तथा 1953 में योजनाबद्ध आर्थिक निर्माण शुरू हो गया । यद्यपि इस

फैलाना, एशियाई देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना तथा नये तनाव उत्पन्न करना था । इस सैनिक गठजोड़ के समर्थन से, अमरीकी हमलावरों ने एशियाई जनता पर अपनी धौंस जमाने व उनके मुक्ति आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया ।

अमरीकी हमलावरों ने तीन अड्डों से चीन में सशस्त्र हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था—थाएवान, कोरिया तथा हिन्दचीन । कोरिया तथा हिन्द चीन में युद्ध की आग बुझा दिये जाने के बाद, अमरीकी हमलावरों ने थाएवान में तैनात च्याङ काई-शेक गुट के माध्यम से, चीन के विरुद्ध अपनी युद्धक तैयारियों तथा विनाशक कारगुजारियों में तेजी ला दी । 2 दिसम्बर, 1954 को उन्होंने गद्दार च्याङ काई-शेक के गिरोह के साथ एक *"परस्पर प्रतिरक्षा समझौते"* पर हस्ताक्षर किए, तथा यहाँ तक प्रयास किया कि जापान व दक्षिण कोरिया के प्रतिक्रियावादी तत्व, गद्दार च्याङ काई-शेक के गिरोह के साथ मिलकर एक *"उत्तर-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा गठबन्धन"* बनाएं तथा उसे *दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि संगठन* के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि चीन में सशस्त्र हस्तक्षेप बढ़ाया जा सके ।

थाएवान चीन का अभिन्न अंग है; उस पर अमरीकी साम्राज्यवादियों का हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । थाएवान की मुक्ति एक ऐसा मामला है, जिसका संबंध चीन की प्रभुसत्ता से है तथा यह चीन का घरेलू मामला है, अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाएगा । चीनी जनता थाएवान को मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्प है । जब तक थाएवान को मुक्त नहीं करा लिया जाता, चीन की क्षेत्रीय अखंडता अधूरी रहेगी, उसके शान्तिपूर्ण निर्माण के लिए शान्त वातावरण नहीं होगा, तथा सुदूर पूर्व में तथा पूरे विश्व में शान्ति की कोई गारंटी न होगी । अन्य देशों के संप्रभुता के अधिकारों का अतिक्रमण करने, उनके इलाके पर कब्जा करने तथा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से विश्व शाँति को खतरा उत्पन्न होता है । जबकि थाएवान को मुक्त कराने हेतु तथा अमरीकी हमले के विरुद्ध चीनी जनता का न्यायोचित संघर्ष विश्व-शांति की रक्षा के लिए है । 21 अगस्त, 1954 को चीन की केन्द्रीय जन-सरकार ने थाएवान की मुक्ति के लिए संघर्ष करने हेतु तथा राष्ट्रीय मुक्ति के पुनीत आन्दोलन का विजयपूर्ण समापन करने हेतु समस्त राष्ट्र का आह्वान किया । इस आह्वान के जवाब में, चीन की सभी जनवादी पार्टियों तथा सभी जनवादी संगठनों ने 22 अगस्त को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें विधिवत् घोषणा करते हुए पूरी दुनिया को यह बताया गया कि थाएवान चीन का हिस्सा था तथा चीनी जनता थाएवान को मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्प थी । यह ऐलान 60 करोड़ चीनी जनता के संकल्प तथा दृढ़ इच्छा की अभिव्यक्ति था ।

थाएवान की मुक्ति के लिए तैयारी करने तथा शान्ति की रक्षा के लिए नवंबर, 1954 से चीनी जन-मुक्ति सेना ने ताछन, क्वोमोए तथा ईच्याङशान द्वीपों पर स्थित च्याङ काई-शेक के फौजी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किये । ईच्याङशान द्वीप को 19 जनवरी तथा ताछन द्वीप को 13 फरवरी, 1955 को मुक्त करा लिया गया । इन विजयों का थाएवान की मुक्ति के लिए बड़ा जबरदस्त महत्त्व था तथा इससे पूर्णरुपेण सिद्ध हो गया कि कोई भी ताकत चीनी जनता के, थाएवान तथा मुख्य भूमि के अन्य द्वीपों को मुक्त कराने के संघर्ष में बाधक नहीं बन सकती थी ।

चीनी जनता ने सदा शांति का पक्ष लिया तथा इसकी प्राप्ति के लिए सभी प्रयास किए।

2.

- **चीन की शान्ति नीति ।**
- **थाएवान (तैवान) की मुक्ति के लिए चीनी जनता का संघर्ष ।**
- **प्रथम राष्ट्रीय जन-कांग्रेस ।**
- **चीनी लोक-गणराज्य का संविधान ।**

चीनी जनता अपनी मातृभूमि को एक महान समाजवादी देश बनाना चाहती है । वे शांतिपूर्ण श्रम में जुटे हुए हैं तथा वे शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चाहते हैं ।

चीनी लोक गणराज्य अपनी स्थापना के समय से ही, विशाल सोवियत-संघ तथा अन्य लोक जनतंत्रों के साथ, विश्व-शान्ति की रक्षा व हमलावर युद्ध की रोकथाम के सामूहिक उद्देश्य के लिए निकट रूप से जुड़ा रहा है । उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों तथा दूसरे पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत किया है तथा कुछ पश्चिमी देशों के साथ सामान्य संबंध स्थापित किए हैं । वह जापान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने व व्यापार बढ़ाने का इच्छुक है तथा यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के सभी देशों के साथ शान्तिपूर्ण सहयोग की स्थापना करने का इच्छुक है ।

चीन विश्व शांति की रक्षा व अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है । कोरिया के विरुद्ध साम्राज्यवादी हमले के विरोध में चीनी जनता ने अमरीका-प्रतिरोध तथा कोरिया-सहयोग का महान आंदोलन चलाया, तथा चीनी जनता के स्वयंसेवकों तथा कोरियाई जन-सेना द्वारा चलाए संघर्ष ने जुलाई 1953 में अमरीका को युद्ध-विराम सन्धि करने पर मजबूर कर दिया । चीन, सोवियत संघ तथा अन्य देशों ने जिनेवा सम्मेलन में भाग लिया, तथा अमरीकी सरकार द्वारा लगाए जा रहे अवरोधों को दूर करते हुए, अन्ततः हिन्द-चीन में शान्ति की पुनर्स्थापना हेतु समझौता सम्पन्न कराया । इस सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आई तथा विश्व-शांति सुदृढ़ हुई । जून 1954 में, चीनी प्रधानमंत्री ने भारत तथा बर्मा के प्रधानमंत्रियों से अलग-अलग बातचीत की तथा संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के परस्पर सम्मान, एक-दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने, अनाक्रमण, समानता तथा परस्पर-हित, तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया, तथा पुष्टि की गई कि ये पाँच मूल सिद्धान्त चीन-भारत तथा चीन-बर्मा के सम्बन्धों का मार्गदर्शन करेंगे । इन सिद्धान्तों को विश्वभर में लोकप्रियता प्राप्त हुई है ।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने फिर भी लगातार युद्ध तथा आक्रमण की नीति का अनुसरण किया । उन्होंने हमले के लिए विभिन्न सैनिक तथा राजनीतिक गिरोह एवं गठबन्धन बनाए । यूरोप में, अमरीकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने आक्रमणकारी *"उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन" (नाटो)* की स्थापना की तथा पेरिस में एक समझौता किया जिससे जर्मन सैनिकवाद के पुनरुत्थान का रास्ता प्रशस्त हो गया तथा पश्चिमी देशों के आक्रमणकारी फौजी ब्लॉक में पश्चिमी जर्मनी को शामिल कर लिया गया ।

एशिया में, अमरीका ने मनीला में आठ राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें *"दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि"* संपन्न हुई । वास्तव में, यह औपनिवेशिक राज्यों के बीच एक ऐसा सैनिक गठजोड़ था जिसका उद्देश्य चीनी लोक गणराज्य के विरुद्ध शत्रुता की भावनाएँ

दीर्घावधि-निर्माण-योजना को तैयार करने के मार्ग में अनेक बाधाओं से जूझना पड़ा, तो भी आर्थिक निर्माण के दो वर्षों के अभ्यास के फलस्वरूप, अनुभव का खजाना इकट्ठा हो गया। अनेक परिवर्द्धनों तथा परिवर्तनों के बाद, अन्ततः पंचवर्षीय योजना का मस्विदा तैयार कर लिया गया । मार्च 1955 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी गहन जाँच-पड़ताल की गई तथा फैसला किया गया कि केन्द्रीय समिति द्वारा जरूरी संशोधनों के बाद इसे राष्ट्रीय जन-कांग्रेस में चर्चा के लिए व देश के लिए योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाए । 30 जुलाई, 1955 को प्रथम राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेखांकित मूल कार्यभार दो शीर्षकों के अंतर्गत रखे गए, देश का समाजवादी औद्योगीकरण तथा गैर-समाजवादी आर्थिक तत्वों का रूपान्तरण । शुरू में यह जरूरी था कि औद्योगिक निर्माण करके चीन के समाजवादी औद्योगीकरण की नींव रखी जाए, इसमें भारी उद्योग पर विशेष जोर देना था, अर्थात् विद्युत, कोयला, लोहा तथा इस्पात, तेल तथा अलौह धातुओं जैसे उद्योगों तथा इनके साथ ही बुनियादी रसायन उद्योगों को स्थापित करना व इनका विस्तार करना तथा मशीन-निर्माण उद्योग को स्थापित करना । ऐसी स्थिति में, यह व्यवस्था की गई कि कुल पूँजी निवेश का 40.9 प्रतिशत उद्योग में लगाया जाए तथा उद्योग-निर्माण में होने वाले निवेश का 88.8 प्रतिशत उन उद्योगों में लगाया जाए, जो उत्पादन के साधनों का निर्माण करते थे । भारी उद्योग के विकास के साथ-साथ ही सूती वस्त्र उद्योग तथा अन्य हल्के उद्योगों, संचार तथा परिवहन की स्थापना भी करनी थी, एवं कृषि को लाभ पहुँचाने के लिए मध्यम आकार के व लघु उद्योगों की स्थापना भी करनी थी ।

समाजवादी औद्योगीकरण की इस साहसिक नीति के लागू होने के फलस्वरूप, औद्योगिक उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ा । पाँच वर्षों के दौरान, औद्योगिक उत्पादन में औसतन 14.7 प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई, फलतः 1957 तक कुल दुगुनी वृद्धि हुई । विकास की यह दर जो समाजवादी देशों में ही संभव थी, एक ऐसी चीज थी, जिसके बारे में पूँजीवादी देश स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे ।

फिर वैयक्तिक अर्थ-प्रणाली पर आधारित हस्तशिल्पों तथा कृषि का एवं निजी उद्योग व वाणिज्य का रूपान्तरण करना था । कृषि में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाना था तथा लघु कृषक अर्थव्यवस्था के आरंभिक रूपान्तरण के लिए अर्ध-समाजवादी सहकारी समितियों का मुख्य ढाँचे के रूप में प्रयोग किया जाना था । इस आधार पर कृषि में तकनीकी सुधार लागू किए जाने थे, प्रति यूनिट क्षेत्रफल के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि होनी थी, तथा कृषि उत्पादन का और अधिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना था । इसी दौरान, उन किसानों की क्षमताओं का विकास करने पर भी बल दिया जाना था, जो अपने बलबूते पर काम करते थे । योजना इस प्रकार बनाई गई कि कृषि उत्पादन तथा उसकी पार्श्ववर्ती पांतों (सहायक-क्षेत्रों) में औसत सलाना वृद्धि 4.3% होनी थी। निजी उद्योग तथा वाणिज्य के रूपान्तरण के लिए, जरूरतों को तथा संभावना की मात्रा को देखते हुए, निम्न कदम उठाए गए : राज्य तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त कारोबारों को धीरे-धीरे व्यापक बनाना, निजी उद्यमों को संसाधन तथा निर्माण के लिए ज्यादा आर्डर देना, उनके उत्पादों को एकमात्र सरकार द्वारा खरीदे जाने तथा विपणन करने का पुख्ता इंतजाम करना तथा

निजी स्वामित्व की दुकानों को राजकीय उद्यमों तथा राजकीय सहकारी समितियों के लिए आढ़तिये (कमीशन एजेन्ट) के रूप में काम करने को प्रेरित करना तथा इस प्रकार निजी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्ष के दौरान निजी उद्योग तथा वाणिज्य का राजकीय पूँजीवाद के विभिन्न रूपाकारों में, बुनियादी तौर पर समूचे देश में, रूपान्तरण कर दिया जाए।

योजना के पूर्ण समापन पर, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के कुल परिमाण में आधुनिक उद्योग का अनुपात 1952 के 26.7 प्रतिशत से बढ़कर 1957 में 36 प्रतिशत हो जाना था। औद्योगिक उत्पादन के कुल परिमाण में उत्पादन के साधनों का अनुपात 1952 के 39.7 प्रतिशत से बढ़कर 1957 में 45.4 प्रतिशत हो जाना था। अर्थव्यवस्था के समाजवादी तत्व में भी महत्त्वपूर्ण ठोस वृद्धि होनी थी। राजकीय स्वामित्व, सहकारिता स्वामित्व तथा संयुक्त राजकीय-निजी स्वामित्व के उद्योगों के उत्पादन का अनुपात, देश के औद्योगिक उत्पादन के कुल परिमाण में, 1952 के 61 प्रतिशत से बढ़कर 1957 में 87.8 प्रतिशत हो जाना था। 1957 में खुदरा व्यापार के कुल परिमाण का 78.9 प्रतिशत राजकीय स्वामित्व की सहकारी समितियों तथा संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों द्वारा संचालित किया जाना था।

संक्रमणकाल में आम कार्यदिशा को साकार करने हेतु चीनी जनता का मार्गदर्शन करते समय, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य, चीन में एक महान समाजवादी समाज का निर्माण करना था। यह क्रान्ति पूँजीवादी-जनवादी क्रांति की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा गहन क्रान्ति होनी थी, क्योंकि इसके परिणामवश देश में शोषण का पूर्ण खात्मा हो जाना था। अतः एक प्रचंड वर्ग संघर्ष अपरिहार्य था।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करना तथा इसके भाईचारे व एकता को सुदृढ़ बनाना, संक्रमणकाल में आम कार्यदिशा को साकार करने की बुनियादी गारंटी थी। फरवरी 1954 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन में, पार्टी सदस्यों तथा गैर-पार्टी लोगों को आगाह किया गया कि साम्राज्यवादियों ने, घर में बैठे प्रतिक्रियावादियों के साथ मिलकर जिनका सम्बन्ध उन वर्गों से था जिनका सफाया किया जा चुका था अथवा किया जा रहा था, चीनी क्रांति के लक्ष्य को खंडित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना था।

इन भावी तोड़-फोड़ करने वालों को यह अच्छी तरह मालूम था कि चीनी जनता के लक्ष्य को नुकसान पहुँचाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद ढुलमुल व बेईमान तत्वों का इस्तेमाल करके पार्टी पर हमला किया जाए। उन्होंने पार्टी में फूट तथा पार्टी के ह्रास पर अपनी बड़ी-बड़ी उम्मीदें टिकाएँ रखीं।

चौथे पूर्ण अधिवेशन ने पार्टी के सभी सदस्यों का आह्वान किया कि वे क्रान्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना को और अधिक मजबूत करे तथा शत्रु के षड्यन्त्रों के विरुद्ध व पार्टी में राजनीतिक स्वार्थजीवियों के संभावित आविर्भाव के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ाएं। पार्टी के अन्दर एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए तथा पार्टी को नष्ट करने व दो फाड़ करने पर आमादा शत्रु के कुचक्रों को कुचलने के लिए पार्टी के अन्दर संकीर्णतावाद, विभागवाद तथा क्षेत्रीयतावाद जैसे भ्रान्तिपूर्ण विचारधारात्मक रुझानों के खिलाफ संघर्ष छेड़ना जरूरी था, क्योंकि ऐसे भ्रान्तिपूर्ण विचारों से ओत-प्रोत पार्टी सदस्यों को शत्रु अपनी ओर आकर्षित कर सकता था

व उन्हें अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। चौथे पूर्ण अधिवेशन में पार्टी विरोधी तत्वों को अंतिम चेतावनी दी गई—जो लोग जानबूझकर पार्टी की एकता को तोड़ेंगे, पार्टी का डट कर विरोध करते रहेंगे तथा धृष्टतापूर्वक अपनी गलतियों पर अड़े रहेंगे या फिर इस हद तक गिर जाएंगे कि संकीर्णतावादी तथा फूट-परस्त गतिविधियों में संलिप्त होंगे या पार्टी के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली अन्य गतिविधियां चलाएंगे, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी तथा उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता था।

दो राजनीतिक स्वार्थजीवियों—काओ कांङ व राओ शू-श के पार्टी-विरोधी गिरोह का षड्यन्त्र, जिसका भण्डाफोड़ चौथे पूर्ण अधिवेशन से पहले तथा बाद में हुआ, पार्टी के अंदर चल रहे भयंकर वर्ग-संघर्ष का तीखा प्रतिबिम्ब था।

इस पार्टी विरोधी गिरोह की यह विशिष्टता थी कि उन्होंने पार्टी की केन्द्रीय समिति के विरुद्ध किसी तरह के कार्यक्रम का कोई प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि षड्यन्त्रपूर्ण उपायों से सर्वोच्च सत्ता हथियाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि साथी माओ त्से-तुङ के नेतृत्व वाली केन्द्रीय समिति में, पार्टी के सभी सदस्यों तथा समूची जनता की पूरी आस्था थी। यदि वे केन्द्रीय समिति के नेतृत्व का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते तो समूची पार्टी तथा समस्त राष्ट्र के सामने उनके प्रतिक्रियावादी चरित्र का एकदम भण्डाफोड़ हो जाता तथा उन्हें अपमानजनक पराजय का मुँह देखना पड़ता।

इसलिए वे सार्वजनिक रूप से पार्टी को विघटित व दो फाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने दोहरी चाल चली, वे पार्टी द्वारा निर्धारित सही कार्यदिशा के प्रति आस्था प्रकट करते रहे, लेकिन असल में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को अन्जाम देने के लिए चोरी-चोरी षड्यन्त्र रचते रहे। उन्होंने संकीर्णतावादी गतिविधियाँ चलाईं, अफवाहें फैलाईं तथा झूठे आरोप लगाए, लोगों को एक-दूसरे के विरुद्ध भड़का कर आपसी शत्रुता पैदा की, रिश्वत देकर अपने अनुयायी बनाने का प्रयास किया, तथा जब भी मौका हाथ आया पार्टी के अंदर फूट के बीज बोए। उन्होंने पार्टी के एकीकृत नेतृत्व का विरोध किया, तथा अपने नेतृत्व के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों या विभागों को *"स्वतन्त्र राजशाही"* समझने लगे। और यह सब कुछ पार्टी तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता को हड़पने की तैयारी के रूप में हो रहा था। जमींदारों तथा पूँजीपतियों सरीखे षड्यन्त्र तथा कुचालें चलकर, उन्होंने स्वयं को पूरी तरह सिद्धांतहीन षड्यन्त्रकारियों का गिरोह साबित कर दिखाया। यह षड्यन्त्रकारी गिरोह, उस वक्त के वर्ग संघर्ष के विशेष हालात के अन्तर्गत, पार्टी के अन्दर से ही पैदा हुआ था। इसमें संदेह की रत्तीभर भी गुँजाइश नहीं थी कि उनकी पार्टी-विरोधी गतिविधियाँ साम्राज्यवादियों तथा पूँजीपति वर्ग के प्रतिक्रियावादियों को रास आईं, और यदि पार्टी तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता इन षड्यन्त्रकारियों के हाथ लग जाती तो इससे प्रतिक्रियावादी शासन की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता। अतः वे असल में, पार्टी के अन्दर साम्राज्यवादियों तथा पूँजीपतियों के एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे थे।

फरवरी 1954 में पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन से लेकर, मार्च 1955 में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन तक, समूची पार्टी ने, केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन में, जिसका नेतृत्व साथी माओ त्से-तुङ कर रहे थे, काओ काङ तथा राओ शू-श के पार्टी-विरोधी गिरोह के षड्यन्त्र का पूर्णतया भण्डाफोड़ कर दिया तथा उसे चकनाचूर कर दिया। ●

अमरीका के हित में, शीआन घटना को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का पक्षपोषण किया । इसका कारण था सुदूरपूर्व में उस समय अपने-अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने वाले जापानी साम्राज्यवाद और अमरीकी साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर्विरोध ।

त्वान छी-रुइ - त्वान छी-रुइ ग्वान श-खाए का मातहत था और उत्तरी युद्ध-सरदारों के आनह्वेइ गुट का मुखिया था । ग्वान की मृत्यु के बाद उसने एक से अधिक बार पेकिङ सरकार पर कब्जा जमाया।

तङ छुङ-श्यां – पृ० 69

ताङ शङ-च (थाङ शङ-च) - एक जनरल था, जिसने उत्तरी अभियान में क्रान्ति का साथ दिया था ।

ताए ची-थाओ – पृ० 70

तातू नदी – पृ० 165

तान – एक तान 50 किलोग्राम के बराबर होता है ।

तीन तरह का सफाया करने की नीति – पृ० 250 तथा 256

तीन मार्गदर्शक सिद्धान्त – पृ० 229 तथा 233

तुङ मङ ह्वेइ (थुङ मङ ह्वेइ) - "थुङ मङ ह्वेइ" या चीनी क्रान्तिकारी लीग (पूँजीपति वर्ग, निम्न-पूँजीपति वर्ग और छिङ सरकार के विरोधी भूस्वामी शरीफजादों के एक अंश का संयुक्त मोर्चा संगठन) की स्थापना 1905 में "शिङ चुङ ह्वेइ" और दो अन्य दलों—"ह्वा शिङ ह्वेइ" (चीन पुनरुद्धार सोसाइटी) तथा "क्वाङ फू ह्वेइ" (विदेशी जुआ उतार फेंकने के लिए संगठित सोसाइटी)—को मिलाकर की गई थी । इसने पूँजीवादी क्रान्ति का कार्यक्रम पेश करते हुए इन मांगों को बुलन्द किया था : "तातारों को खदेड़ बाहर किया जाए, चीन की पुनर्स्थापना की जाए, गणराज्य की स्थापना की जाए और जमीन की मिलकियत का समानीकरण किया जाए ।" चीनी क्रान्तिकारी लीग के काल में डॉ० सुन यात-सेन ने गुप्त संस्थाओं और छिङ सरकार की "नई सेना" के सहयोग से छिङ सरकार के खिलाफ अनेक हथियारबन्द विद्रोह कराए । इन स्थानों में हुए हथियारबन्द विद्रोह मशहूर थे : 1906 में फिङश्याङ, ल्यूयाङ और लीलिङ में; 1907 में छाऊचओ के ह्वाङकाङ, छिनचओ और चननानक्वान (वर्तमान यओईक्वान - अनु०) में; 1908 में युन्नान के होखओ में; 1911 में क्वाङचओ में और ऊछाङ में ।

थाएफिङ स्वर्गिक राज्य - थाइफिङ स्वर्गिक-राज्य का युद्ध छिङ वंश के सामन्ती शासन तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में किया गया एक क्रान्तिकारी किसान युद्ध था । जनवरी 1851 में हुङ श्यू-छ्वेन, याङ श्यू-छिङ तथा इस क्रान्ति के अन्य नेताओं ने क्वाङशी की क्वेइफिङ काउन्टी के चिनथ्येन गांव में विद्रोह कर दिया और थाइफिङ स्वर्गिक राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। 1852 में विद्रोही सेना ने क्वाङशी से उत्तर की ओर बढ़कर हुनान, हुपे, च्याङशी और आनह्वेइ से गुजरते हुए अभियान किया तथा 1853 में नानकिङ शहर पर अधिकार कर लिया । इसके बाद इस सैन्य-दल का एक हिस्सा नानकिङ से उत्तर की ओर बढ़ता गया और थ्येनचिन के निकट पहुंच गया । परन्तु थाइफिङ सेना ने जिन प्रदेशों पर कब्जा किया, वहां उसने मजबूत आधार-क्षेत्र नहीं बनाया, और नानकिङ को राजधानी बना लेने के बाद इस सेना के नेतृत्वकारी ग्रुप ने अनेक राजनीतिक और फौजी गलतियां कीं; इसलिए वह छिङ सरकार की प्रतिक्रान्तिकारी सेना तथा बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी आक्रमणकारियों के संयुक्त प्रहार का मुकाबला न कर सकी और आखिरकार 1864 में पराजित हो गई ।

दलाल-पूँजीपति – पृ० 22

दक्षिणी आनह्वेइ कांड – पृ० 229

द्वैत क्रान्ति का सिद्धान्त – यह सिद्धान्त कामरेड लेनिन ने दिया था तथा कामरेड माओ ने इसे आगे विकसित किया । इसके अनुसार क्रान्ति दो मंजिलों में होगी । पहली मंजिल नव-जनवादी क्रान्ति की होगी तथा अगली मंजिल समाजवादी क्रान्ति की होगी ।

'दीर्घकालीन युद्ध के बारे में' – पृ० 212, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें—विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा प्रकाशित, 'माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाओं के ग्रन्थ-2' का उपरोक्त शीर्षक

देश की कृषि सहकारिता का समाजवादी औद्योगीकरण के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए, एक नीति लागू करनी पड़ी । यदि 50 करोड़ से अधिक किसानों को समाजवादी निर्माण में हिस्सा लेने का अवसर न दिया जाता तो अनाज व औद्योगिक कच्चे माल में हम पिछड़ जाते, तथा देश का औद्योगीकरण बड़ी गहरी कठिनाइयों में फंस जाता ।

कृषि सहकारिता की उच्च लहर चलने से पहले ही अधिकांश किसान समाजवादी रास्ते पर चलने की पहल कर चुके थे । प्रथम, जबकि व्यापक किसान समुदाय का जीवन-यापन कृषि-सुधारों के बाद कुछ सुधर गया था, परन्तु अभी भी उनमें बहुत से ऐसे थे जो अपर्याप्त कृषि योग्य भूमि, निरन्तर आती प्राकृतिक आपदाओं तथा पिछड़ी कृषि-तकनीक वगैरा के कारण ठीक हालत में नहीं थे । यही वजह है कि किसानों का विशाल बहुमत समाजवादी रास्ता अपनाने का इच्छुक था । दूसरे, पहली पंचवर्षीय योजना के निर्देशन में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लम्बी छलाँगें भर रही थी, विशेषकर समाजवादी औद्योगीकरण के क्षेत्र में । इस तथ्य ने भी, कृषि सहकारिता के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया । तीसरे, परस्पर-सहायता, तथा सहकारिता का आन्दोलन पिछले कई वर्षों से चल रहा था । विभिन्न स्थानों में जो अनेक सहकारी समितियाँ स्थापित की गई थीं, उन्होंने उत्पादन की वृद्धि में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया था तथा किसानों के व्यापक तबकों ने उनकी प्रशंसा की थी । परस्पर सहायता तथा सहकारिता के आन्दोलन ने, जो समस्त देश में फैल रहा था, सहकारी समितियों की स्थापना के लिए संगठनात्मक आधार स्थापित कर दिया था । किसानों ने सहकारी समितियों की स्थापना में बहुत उत्साह दिखाया, कभी-कभी तो उन्होंने नेतृत्व से स्वीकृति लिए बिना, स्वतः ही सहकारी समितियाँ स्थापित कर लीं । यही वे वस्तुगत परिस्थितियां थीं, जिन्होंने कृषि सहकारिता के विकास को संभव बनाया ।

तथापि, कृषि सहकारिता के इस प्रश्न को लेकर पार्टी में कुछ दक्षिणपंथी रूढ़िवादी विचार थे, जिन्हें न तो किसानों की समाजवादी रास्ते पर चलने की पहलकदमी पर भरोसा था और न ही देहात में पार्टी की ताकत पर यकीन था । ऐसे विचारों वाले सदस्यों ने पार्टी की केन्द्रीय समिति की इस नीति को, कि कृषि सहकारिता, समाजवादी औद्योगीकरण के विकास के साथ कन्धे-से-कन्धा मिला कर चले, नामन्जूर कर दिया । इसके विपरीत, उन्होंने जोर दिया कि कृषि सहकारिता को औद्योगीकरण की अपेक्षा बेहद धीमी गति से आगे बढ़ाया जाए । अतः उन्होंने अपने व्यावहारिक कार्य में "सम्पीड़न" (Compression) की कार्यदिशा अपनाई तथा कृषि उत्पादकों की बहुत सी सहकारी समितियों को भंग कर दिया ।

जुलाई 1955 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रादेशिक, म्युनिसिपल तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रीय कमेटियों के सचिवों के सम्मेलन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट "*कृषि सहकारिता का प्रश्न*" में साथीमाओ ने इस प्रकार के दक्षिणपंथी भ्रांतिपूर्ण विचारों तथा कार्यों की विश्लेषणात्मक तथा व्यापक आलोचना की तथा कृषि सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए सही नीति तथा कार्य प्रणाली निश्चित की । इस नीति तथा कार्यप्रणाली को सातवीं केन्द्रीय समिति के अक्तूबर में आयोजित छठे पूर्ण अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया तथा पार्टी के फैसले के रूप में नोट कर लिया गया ।

कृषि में सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए नीति के विषय में कहा गया कि इसके लिए व्यापक योजना तथा ज्यादा सक्रिय नेतृत्व होना चाहिए । व्यापक योजना को व्यावहारिक

रूप से लागू करने के लिए, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने देश को तीन अलग-अलग किस्म के इलाकों में बाँटा । पहला इलाका था, जहाँ परस्पर-सहायता तथा सहकारिता आन्दोलन अपेक्षाकृत प्रगति कर चुका था; दूसरा इलाका था, जहाँ आन्दोलन अभी विकसित होना शुरू ही हुआ था; तथा तीसरा इलाका था, जहाँ आंदोलन अभी अपेक्षाकृत कमजोर था । इन इलाकों के बीच जो अन्तर थे उन पर ध्यान देना जरूरी था, तथा सहकारिता-आंदोलन की गति का विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना आवश्यक था ।

योजना का कार्यभार लागू करते हुए, कस्बों तथा गाँवों पर विशेष ध्यान देना जरूरी था क्योंकि ये व्यापक योजना के आधार होने थे ।

नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, पार्टी की केन्द्रीय समिति ने सभी स्तरों पर स्थानीय पार्टी कमेटियों को हिदायत दी कि वे अपने प्रयास कृषि सहकारिता आन्दोलन की अगुवाई करने पर केन्द्रित करें । उन्हें ग्रामीण समस्याओं के महत्त्व को समझना था तथा तत्परता से ग्रामीण कार्यों के नेतृत्व की कला में सुधार करना था ।

कृषि सहकारिता आन्दोलन के विकास से संबंधित कार्यप्रणाली के लिए गरीब किसानों तथा नए मध्यम किसानों के निम्न तबके के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक मजबूत धुरी का होना जरूरी था तथा इस धुरी में **पुराने मध्यम किसानों**[1] के निम्न तबकों से भी कुछ सक्रिय कार्यकर्ता शामिल किए जाने थे । किसान समुदाय को निम्न ढँग से संगठित करना था : प्रथम, पूरी तरह से विचार-विमर्श तथा बहस होनी थी; फिर उनकी राजनीतिक चेतना के स्तर के अनुसार उनका ग्रुपों में विभाजन किया जाना था जिन्हें सहकारी समितियाँ स्थापित करनी थीं या फिर उन्हें पहले से ही मौजूद सहकारी समितियों में शामिल कर लिया जाना था । जो लोग फौरी तौर पर सहकारी समितियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें बाहर रहने की अनुमति दी जानी थी ।

सहकारी समितियों का गठन करते समय, अच्छा खाते-पीते मध्यम किसानों में से, जो वाकई स्वेच्छा से सहकारिता में शामिल होना चाहते थे, उन्हें छोड़कर बाकी को अभी फौरी तौर पर सहकारी समितियों में नहीं लेना था, और उन्हें बाध्य करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था । मध्यम किसानों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने थे, चाहे वे किसी सहकारी समिति में हों अथवा न हों, और उनके हितों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचानी थी ।

सहकारी समितियों की स्थापना से पहले, जनता में सैद्धांतिक आधार स्थापित करने के लिए, संगठन व कार्यकर्ताओं के मामले में तैयारी करनी जरूरी थी । सहकारी समितियों की स्थापना के बाद निरीक्षण का काम शुरू करना जरूरी था । सहकारी समितियों की जाँच-पड़ताल वर्ष में एक बार नहीं, बल्कि दो-तीन बार होनी थी, ताकि उनमें निरंतर सुधार हो सके तथा उन्हें मजबूत बनाया जा सके । किसी सहकारी समिति की स्थापना व निरीक्षण के समय सदस्यों की निजी संपत्ति (जमीन, भारवाही पशु तथा कृषि उपकरण) के विषय में ऐसा रवैया अपनाया जाना था जिससे सहकारी समिति का विकास तथा सुदृढ़ीकरण हो ।

कृषि उत्पादकों की सहकारी समितियों ने उत्पादन योजनाओं, श्रम-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन तथा सैद्धांतिक कार्य से संबंधित अनेक ब्यौरेवार उपाय करने थे ।

जब किसी जिले में सहकारिता का काफी हद तक विस्तार हो गया हो तथा सहकारी समितियों का पहले से ही सुदृढ़ीकरण किया जा चुका हो, सिर्फ तभी पूर्ववर्ती जमींदारों तथा

सातवीं कांग्रेस – पृ० 267

चीनी लोक गणराज्य का संविधान – पृ० 378, 380 से 384

चीनी लोक गणराज्य की अर्थव्यवस्था के पाँच मुख्य तत्व – पृ० 348

चीनी लोकतन्त्र की क्रान्तिकारी जन-सरकार - देखें छाए थिङ-खाए

चीनी समाज में वर्गों का विश्लेषण - विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-1, का उपरोक्त शीर्षक अध्याय । पृ० - 3 से 19 तक ।

चुनई कांफ्रेन्स – पृ० 164

चू फेइ-त - क्वोमिंताङ युद्ध-सरदार, च्याङशी प्रान्त का क्वोमिंताङ गवर्नर ।

छन तू-श्यू - छन तू-श्यू पहले पेकिङ विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था और "नवयुवक" नामक पत्रिका के सम्पादक के रूप में मशहूर हो गया था । वह चीनी-कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था । 4 मई आन्दोलन के समय मशहूर हो जाने के कारण और पार्टी के प्रारम्भिक काल में उसकी (पार्टी की) अपरिपक्वता के कारण, छन तू-श्यू पार्टी का महासचिव बन गया । 1924-27 की क्रान्ति के अन्तिम काल में, पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी विचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व छन तू-श्यू करता था, एक आत्मसमर्पणवादी कार्यदिशा का रूप धारण कर लिया । "वर्तमान परिस्थिति और हमारे कार्य" ("माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं", ग्रन्थ-4) में कामरेड माओ त्से-तुङ ने बताया है कि उस समय "आत्मसमर्पणवादियों ने किसान जनता, शहरी निम्न-पूँजीपति वर्ग और मध्यम-पूँजीपति वर्ग में तथा खास तौर पर सैन्य-शक्तियों में पार्टी के नेतृत्व को खुद ही त्याग दिया । इस वजह से वह क्रान्ति असफल रही ।" 1927 में क्रान्ति की हार के बाद, छन तू-श्यू और मुट्ठीभर दूसरे आत्मसमर्पणवादी क्रान्ति के भविष्य के बारे में अपना विश्वास खो बैठे और विघटनवादी बन गए । उन्होंने प्रतिक्रियावादी त्रात्सकीवादी दृष्टिबिन्दु अपनाया और त्रात्सकीवादियों के साथ मिलकर एक छोटा सा पार्टी-विरोधी गुट कायम किया । परिणामस्वरूप नवम्बर 1929 में छन तू-श्यू को पार्टी से निकाल दिया गया । 1942 में उसकी मृत्यु हो गई ।

छाए थिङ-खाए - छाए थिङ-खाए क्वोमिंताङ की 19वीं राह सेना का डिप्टी कमाण्डर तथा उसकी एक फौजी कोर का कमाण्डर था । 19वीं राह सेना के दो अन्य नेता थे—छन मिङ-शू और च्याङ क्वाङ-नाए । 18 सितम्बर की घटना के बाद इस सेना को, जो च्याङशी में लाल सेना से लड़ रही थी, शंघाई स्थानान्तरित कर दिया गया । शंघाई और समूचे देश में जनता के उमड़ते हुए जापान-विरोधी उभार का 19वीं राह सेना पर बड़ा गहरा असर पड़ा । 28 जनवरी, 1932 की रात को जब जापानी मैरीन-सैनिकों ने शंघाई पर आक्रमण किया तो 19वीं राह सेना और शंघाई की जनता ने उनका संयुक्त रूप से प्रतिरोध किया । लेकिन, च्याङ काई-शेक और वाङ चिङ-वेइ के विश्वासघात के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में च्याङ काई-शेक के आदेशों पर 19वीं राह सेना को फिर लाल सेना से लड़ने के लिए फूच्येन भेज दिया गया । लेकिन सेना के नेताओं को कदम-ब-कदम ऐसी लड़ाई की निरर्थकता का आभास होने लगा। नवम्बर 1933 में ली ची-शन तथा अन्य लोगों के मातहत क्वोमिन्ताङ की शक्तियों से सहयोग करके उन्होंने सार्वजनिक रूप से च्याङ काई-शेक से सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा की, फूच्येन में "चीनी लोकतंत्र की क्रान्तिकारी जन-सरकार" की स्थापना कर दी और जापान का प्रतिरोध करने तथा च्याङ काई-शेक का विरोध करने के लिए लाल सेना से समझौता कर लिया । च्याङ काई-शेक की सेनाओं के हमले से 19वीं राह सेना और फूच्येन की जन-सरकार का पतन हो गया । उसके बाद से छाए थिङ-खाए और अन्य लोग कदम-ब-कदम कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग करने की स्थिति की ओर बढ़ते गए ।

जन-मुक्ति सेना – पृ० 280

जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बारे में – पृ० 340, विस्तृत जानकारी के लिए देखें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976 के पृ० 695 से 722 तक ।

जापान-विरोधी मुक्त क्षेत्र – पृ० 272

टी०वी०-सुङ - टी० वी० सुङ क्वोमिन्ताङ का एक अमरीका-परस्त सदस्य था । उसने भी,

की ''क्वानतुङ सेना'' ने शनयाङ पर अधिकार कर लिया । ''जरा भी प्रतिरोध न किया जाए'' के च्याङ काई-शेक के आदेश के अन्तर्गत शनयाङ और उत्तर-पूर्व के अन्य क्षेत्रों में स्थित चीनी सेनाएं (उत्तर-पूर्वी सेना) शानहाएक्वान के दक्षिण में हट गई और फलस्वरूप जापानी सैन्य-दल ने तेजी से ल्याओनिङ, चीलिन और हेलुङच्याङ प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । जापानी डाकुओं के आक्रमण की यह कार्यवाही ''18 सितम्बर की घटना'' के नाम से जानी जाती है ।

दक्षिणी आनह्वेइ – पृ० 229
लूकओछ्याओ घटना – पृ० 199-200
शीआन – पृ० 187 तथा 190

चाओ हङ-थी - चाओ हङ-थी हुनान का शासक था, जो उत्तरी युद्ध-सरदारों का एजेन्ट था । 1926 में उत्तरी अभियान सेना ने उसका तख्ता पलट दिया ।

चाङ क्वो-थाओ—चाङ क्वो-थाओ चीनी क्रान्ति का एक गद्दार था । क्रान्ति के प्रति सट्टेबाजी का रवैया अपनाते हुए उसने अपनी जवानी के दिनों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शिरकत की थी। पार्टी के अन्दर उसने अनेक गलतियां करके अत्यन्त गम्भीर अपराध किए । उसका सबसे कुख्यात अपराध यह था कि 1935 में उसने इस पराजयवादी और विघटनवादी नीति की वकालत करते हुए, कि लाल सेना सछ्वान-शीखाङ सीमान्त क्षेत्र के अल्पसंख्यक-जातीय क्षेत्र में हट जाए, लाल सेना के उत्तर की ओर अभियान का विरोध किया, और पार्टी व केन्द्रीय कमेटी के विरुद्ध खुलेआम गद्दाराना कार्यवाहियां कीं, स्वयं अपनी बोगस केन्द्रीय कमेटी स्थापित कर ली तथा पार्टी की एकता व लाल सेना की एकता को तहस-नहस कर दिया, जिससे चौथी मोर्चा-सेना को भारी क्षति पहुंची ; कामरेड माओ त्से-तुङ और पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की धैर्यपूर्ण शिक्षा के फलस्वरूप चौथी मोर्चा-सेना और उसके कार्यकर्ताओं का विशाल समुदाय जल्दी ही केन्द्रीय कमेटी के सही नेतृत्व के अन्तर्गत आ गया और उन्होंने बाद के संघर्षों में बड़ी गौरवशाली भूमिका अदा की । लेकिन चाङ क्वो-थाओ लाइलाज साबित हुआ और 1938 के ब सन्त में वह अकेला ही शेनशी-कानसू-निङश्या सीमान्त क्षेत्र से भागकर क्वोमिन्ताङ की खुफिया पुलिस में शामिल हो गया ।

चाङ च्वो-लिन - चाङ च्वो-लिन युद्ध-सरदारों के फङथ्येन गुट का मुखिया था । 1924 में दूसरे चली-फङथ्येन युद्ध में ऊ फेइ-फू को पराजित करने के बाद, वह उत्तरी प्रान्तों का सबसे शक्तिशाली युद्ध-सरदार बन गया । 1926 में उसने ऊ फेइ-फू के साथ गठजोड़ कायम करके पेकिङ पर कब्जा जमा लिया । जून 1928 में जब चाङ च्वो-लिन पेकिङ से उत्तर-पूर्वी चीन की ओर पीछे हट रहा था, तो रास्ते में जापानी साम्राज्यवादियों द्वारा, जिनके हाथ की वह सदैव कठपुतली बना रहा, रखे गए बम से उसकी हत्या कर दी गई ।

चाङ श्वे-ल्याङ - शीआन घटना के सूत्रधार, क्वोमिंताङ की उत्तरपूर्वी सेना के कमांडर । साथ ही देखें—याङ हू-छङ ।

चार बड़े घराने - पृ० 174
चीन की राष्ट्रीय मुक्ति का हरावल दस्ता– पृ० 196

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी

स्थापना – पृ० 26
प्रथम कांग्रेस – पृ० 26
दूसरी कांग्रेस – पृ० 29
तीसरी कांग्रेस – पृ० 39
चौथी कांग्रेस – पृ० 51
पाँचवीं कांग्रेस – पृ० 94
छठी कांग्रेस – पृ० 199
छठी कांग्रेस का दस-सूत्री कार्यक्रम – पृ० 139

धनी किसानों को, जिन्होंने काफी समय पहले से शोषण करना बन्द कर दिया हो तथा जो ईमानदारी से श्रम में जुटे हुए हों, को सहकारी समिति में शामिल किया जाना था, तथा ऐसा विभिन्न कालखण्डों में तथा विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत, अलग-अलग ग्रुपों में किया जाना था।

पार्टी में से दक्षिणपंथी भ्रान्तिपूर्ण विचारों को दूर करने के बाद, पार्टी की सही नीति तथा कार्यशैली ने जनता में अपना स्थान बना लिया, तथा कुछ ही महीनों के अन्दर देहात में कृषि सहकारिता की एक जबरदस्त लहर उठी । जून 1956 तक, 91.7 प्रतिशत किसान परिवार सहकारी समितियों में शामिल हो गए थे तथा उनमें से अधिकांश उन्नत सहकारी समितियों में शामिल हुए थे । आन्दोलन के व्यापक विस्तार में केवल गरीब किसानों के विशाल समुदाय ने ही सक्रियता से सरकारी समितियों को नहीं अपनाया, बल्कि अनेक मध्यम किसान भी इनमें सम्मिलित हुए । यह मांग एकल किसान परिवारों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अक्सर समूचे गाँव के गाँव तथा जिले के जिले सामूहिक रूप से सहकारिता की माँग करने लगे, तथा समूचे गरीब किसान वर्ग व निम्न-मध्यम किसान वर्ग ने भी सहकारिता की माँग की । सहकारिता आन्दोलन अभूतपूर्व ऊँचाइयों को छूने लगा ।

कृषि सहकारिता में उभार से शहर में निजी पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण में तीव्रता आ गयी । मौजूदा घटनाचक्र ने पूँजीपति वर्ग के सामने यह सच्चाई उजागर कर दी कि यदि वे समाजवादी रूपान्तरण को अधिकाधिक अंगीकार करेंगे तथा अपने हितों को देशहित से सम्बद्ध करेंगे, तभी वे अपने भाग्य के स्वयं विधाता बन सकते थे । परिस्थिति निम्न तरीके से विकसित हुई थी : (1) 1953 से, राज्य ने अनाज तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पादों की योजनाबद्ध तरीके से खरीद तथा आपूर्ति का काम शुरू किया था तथा उनके उचित मूल्य तय किए थे, तथा इस प्रकार, असल में इन जिन्सों में पूँजीवादी सट्टेबाजी से बाजार का पिण्ड छूट गया था । (2) देश के जबरदस्त औद्योगिक विकास से, अर्थव्यवस्था के समाजवादी सेक्टर का तेजी से विकास हुआ, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी सेक्टर का अनुपात कुल मिला कर दिन-ब-दिन घटने लगा । (3) कृषि सहकारिता आंदोलन के विकास के साथ ही, विशाल किसान समुदाय ने समाजवादी मार्ग अपनाते हुए पूँजीवादी रास्ते का परित्याग कर दिया था । यही वे हालात थे, जिनके चलते 1956 के शुरू में पूँजीपति उद्योग एवं वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण में ज्वार आया ।

पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण के शुरू के कुछ वर्षों के दौरान, अधिकतर निजी उद्यमों ने वस्तुओं के संसाधन तथा निर्माण के सरकारी ठेके लेकर, राजकीय पूँजीवाद का मध्यवर्ती स्वरूप धारण कर लिया । 1954 से राज्य ने विधिपूर्वक, संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों के माध्यम से, पूँजीवादी उद्योग का रूपान्तरण करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार, अधिकतर बड़े निजी उद्यम, संयुक्त उद्यम बन गए थे । लेकिन इतना ही पर्याप्त न था । अब केवल एकल फैक्ट्रियों तथा दुकानों ने ही परिवर्तन का मार्ग नहीं चुना, बल्कि उद्योग तथा वाणिज्य के सभी व्यवसायों ने परिवर्तन का मार्ग अपना लिया । सभी व्यवसायों को संयुक्त राजकीय-निजी स्वामित्व के दायरे में लाना, पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण में, एक नई किस्म थी ।

प्रथम, सभी व्यवसायों का संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में परिवर्तित हो जाना, एकल फैक्ट्रियों तथा दुकानों से श्रेष्ठ था । इससे फैक्ट्रियों के बीच की सीमा रेखाएँ समाप्त हो गईं,

उनमें से कइयों को एक उद्यम में विलीन कर दिया गया ताकि राज्य की एकीकृत नियोजन व समग्र प्रबन्धन की नीति ऐसे उद्यम के उत्पादन के विषय में लागू की जा सके । सभी व्यवसायों का समाजवादी सिद्धांत के अनुसार रूपान्तरण करते हुए विभिन्न उद्यमों की श्रम-शक्ति, उनके तकनीकी कर्मचारियों, उपकरणों तथा अन्य साजोसामान (Installations), धनराशि तथा कार्यकर्ताओं का एकीकृत ढँग से अनुभाजन किया जा सकता था तथा विवेकसम्मत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि श्रम की उत्पादकता का स्तर ऊँचा हो सके । संक्षेप में, सभी व्यवसायों का संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में परिवर्तन राजकीय-पूँजीवाद की सर्वोतम किस्म था ।

दूसरे, संयुक्त राजकीय-निजी स्वामित्व की किस्म के विकास के साथ ही पुनर्लाभ (redemption) का तरीका भी बदल गया । सभी व्यवसायों द्वारा संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में परिवर्तित होने से पहले, पुनर्लाभ का स्वरूप लाभ के बंटवारे का था; परिवर्तन के बाद इसका स्वरूप एक निश्चित ब्याज (fixed interest) का हो गया । संयुक्त राजकीय-निजी प्रबंधन के दौर में, पूँजीपतियों के निजी शेयरों पर ब्याज की एक निश्चित दर तय कर दी गई। 8 फरवरी, 1956 को राज्य परिषद (State Council) ने व्यवस्था की कि वार्षिक ब्याज 1 से 6 प्रतिशत तक होना चाहिए । 18 जून को राज्य परिषद ने 5 प्रतिशत की एक समान वार्षिक ब्याज दर तय कर दी । निश्चित ब्याज के लागू होने से, व्यापार में लाभ हो रहा हो या घाटा, पूँजीपति को लाभांश के रूप में एक निश्चित रकम मिलनी तय थी । इस प्रकार, जब तक राष्ट्रीयकरण के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो जाती, राज्य ने प्रतिवर्ष पूँजीपतियों को उनके उद्यमों की खरीद के एवज में एक निश्चित नकद रकम (लाभांश) प्रदान करनी थी । दूसरी ओर, जो पूँजीपति तथा उनके सहयोगी काम कर सकते थे, राज्य ने उन्हें पदों पर नियुक्त करना था, तथा जो काम नहीं कर सकते थे, उनके लिए उचित प्रबन्ध किया जाना था । यह व्यवस्था उद्यमों की खरीद का एक जरूरी हिस्सा थी ।

निश्चित ब्याज की प्रणाली से पूँजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण पर सख्त रोक लग गई । इस प्रकार, संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में, जिन्होंने यह प्रणाली अपनाई, उत्पादन के संबंधों में भारी परिवर्तन आ गया । संयुक्त उद्यमों में पूँजीपतियों का स्वामित्व केवल उन द्वारा प्राप्त की जाने वाली निश्चित ब्याज की राशि तक ही सीमित था । वे संयुक्त उद्यमों को सीधे अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, न ही वे उन्हें बेच सकते थे । उत्पादन के साधन सीधे राज्य के अधीन थे । उद्यमों के प्रबन्धन में पूँजीपतियों की भूमिका, पूँजीपति के रूप में न होकर, राजकीय नेतृत्व के अन्तर्गत एक आम कर्मचारी के रूप में थी ।

उद्यमों के उत्पादन के साधनों पर राज्य के सीधे नियंत्रण से, समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार उनके प्रशासन व प्रबन्धन से तथा पूँजीपतियों के लाभांश की एक निश्चित दर तय हो जाने से, इस प्रकार के उद्यमों का स्वरूप अर्ध-समाजवादी हो गया । जब पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य ने यह निर्णायक कदम उठाया, तो इसका अर्थ था कि पूँजीवाद का स्थान समाजवाद ने ले लिया था ।

तीसरे, सभी व्यवसायों को राजकीय-निजी स्वामित्व के तहत लाने के बाद, कुछ निश्चित आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यभारों को अन्जाम देने के लिए विशेष राजकीय-स्वामित्व वाली कुछ विशेष कम्पनियों की स्थापना की गई । उनका आर्थिक कार्यभार परिसम्पत्तियों की सूची तैयार करना व उद्यमों का पुनर्गठन करना था । 8 फरवरी, 1956 को राज्य-परिषद द्वारा जारी

विवरणिका

अर्ध-भूमिधर किसान – पृ० 70

अष्टपदी निबन्ध – पृ० 256

आठ शक्तियों की संयुक्त सेना का आक्रमणकारी युद्ध – पृ० 21

आत्म बलिदानी लीग (आत्म बलिदान संघ) – ''आत्म-बलिदान संघ'' ''शानशी प्रान्त में राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए आत्म-बलिदान संघ'' का संक्षिप्त नाम था, जो 1926 से लेकर जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के प्रारम्भिक काल तक की अवधि में शानशी प्रान्त में कायम किया गया एक जापान-विरोधी स्थानीय जन-संगठन था । इस संगठन ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ घनिष्ठ सहयोग कायम किया और वहां जापान-विरोधी लड़ाइयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । दिसम्बर 1939 में येन शी-शान ने शानशी प्रान्त के पश्चिमी हिस्से में इस संघ का खुल्लमखुल्ला दमन शुरू कर दिया तथा कम्युनिस्टों, उक्त संघ के कार्यकर्ताओं और अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी ।

आन्दोलन

4 मई आन्दोलन - पृ० 12, विस्तृत जानकारी हेतु पढें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2 का उपरोक्त शीर्षक अध्याय, पृ० 417 से 421 तक ।

30 मई – पृ० 70

9 दिसंबर 1935 का आंदोलन - पृ० 180

अमरीका-प्रतिरोध-कोरिया-सहायता – पृ० 355

आवेदन – पृ० 180

ऊ फान – पृ० 365 तथा 370

सान फान – पृ० 365 तथा 370

इक्कीस माँगें – पृ० 22

ऊ फेइ-फू - उत्तरी युद्ध-सरदारों में ऊ फेइ-फू सबसे प्रसिद्ध युद्ध-सरदारों में से था । वह चली गुट (चली प्रान्त के गुट) में था । उसके साथ छाओ खुन भी था जो 1923 में संसद के सदस्यों को घूस देकर जैसे-तैसे राष्ट्रपति बन बैठा था । ऊ फेइ-फू के समर्थन से छाओ खुन चली गुट का मुखिया बन गया था; इस प्रकार दोनों को साधारणत: ''छाओ-ऊ'' कहा जाता था । 1920 में आनह्वेइ गुट के युद्ध-सरदार त्वान छी-रुइ को हराकर ऊ फेइ-फू ने, आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद के एजेन्ट की हैसियत से उत्तरी युद्ध-सरदारों की सरकार पर अपना नियंत्रण जमा लिया । 7 फरवरी, 1923 को उसने ही पेकिङ-हानखओ रेलवे के हड़ताली मजदूरों का कत्लेआम करने की आज्ञा दी थी । 1924 में चाङ च्वो-लिन के साथ युद्ध करते हुए, जो आम तौर पर ''चली और फङथ्येन गुटों के बीच का युद्ध'' के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हार खानी पड़ी और उसे पेकिङ के शासन से हटा दिया गया । लेकिन 1926 में जापानी और अंग्रेज साम्राज्यवादियों के उकसावे पर वह चाङ च्वो-लिन के साथ हो लिया और फिर सत्तारूढ़ हो गया । जब उत्तरी अभियान सेना 1926 में क्वाङतुङ से उत्तर की ओर बढ़ी, तो वह पहला दुश्मन था जिसका तख्ता उलट दिया गया ।

ऊहान – हुपे प्रान्त में ऊछाङ, हानखओ तथा हानयाङ नामक शहरों का संयुक्त नाम ।

कमालवाद – पृ० 222 तथा 233

क्वोमिंताङ प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस – पृ० 47

क्रान्ति

1911 की क्रान्ति – पृ० 21

थाएफिङ क्रान्ति – पृ० 21

घटनाएं

18 सितंबर 1931 की घटना - 18 सितम्बर 1931 को उत्तर-पूर्वी चीन में तैनात जापान

तालिका - 7 (लालसेना में भर्ती का विवरण—1934)

उम्र के अनुसार	प्रतिशत	विभिन्न सामाजिक तबकों के अनुसार	प्रतिशत
16 वर्ष से नीचे	1	किसान	68
16 से 23 वर्ष	51	मजदूर तथा कारीगर	30
24 से 40 वर्ष	44	कर्मचारी	1
40 वर्ष से ऊपर	4	अन्य तबके	1

तालिका-8

उत्तरी, उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी चीन के आधार-क्षेत्रों में जनसंगठनों की सदस्य संख्या

छापामार आधार-क्षेत्र	किसान सभा	मजदूर संघ	युवा दस्ते (Youth Pioneers)	बाल दस्ते (Children Vangaurd)	महिलायें	आत्म-रक्षा दस्ते	मिलिशिया (नागरिक सेना)	जनसंख्या
शान्शी-छाहाड़-हपे	8,57,761	2,34,683	2,80,854	6,28,872	7,00,535	38,18,491	6,19,861	1,90,00,000
शान्शी-हपे-हनान-शानतुङ	26,70,000	23,625	2,73,969	10,70,000	3,34,673	10,87,510	3,56,318	1,34,70,000
उत्तर-पश्चिमी शान्शी	1,25,000	55,000	70,000	24,264	89,000	7,00,000	50,000	20,00,000
शानतुङ	10,70,000	2,00,000	4,00,000	4,80,000	5,00,000	13,56,982	5,00,000	1,80,00,000
शान-कान-निङ (1938)	4,21,000	45,000	1,68,000	28,087	1,73,800	?	2,24,355	14,00,000

स्रोत : **Long March to Power by James Pinckney Harrison, Praeger Publishers, USA, 1972.**

किये गए एक निर्देश के अनुसार, संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों की मौजूदा परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध तथा उनका मूल्यांकन न्यायोचित तथा विवेकसम्मत सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना था । इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की गई थी कि जब निजी उद्यमों को संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में तब्दील करने की स्वीकृति मिल जाए, तो उत्पादन व प्रबन्धन की मौजूदा मूल-प्रणाली को बदलने से पहले पर्याप्त तैयारी की जानी जरूरी थी । विशेष कंपनियों का राजनीतिक कार्यभार यह था कि वे पूँजीवादी तत्वों को नए साँचे में ढालें । पूँजीपतियों के प्रति शिक्षण का एक रचनात्मक तरीका अपनाया गया । उन्हें मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अध्ययन करने, समाज-सुधार आन्दोलनों में हिस्सा लेने व आपस में आलोचना तथा आत्मालोचना करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उनके शोषकों वाले दृष्टिकोण को धीरे-धीरे मेहनतकश जनता—जो अपने श्रम के दम पर जीवन-निर्वाह करती है—के दृष्टिकोण में बदला जा सके।

उद्यमों के रूपान्तरण के कार्य को विचारधारात्मक पुनः संस्कार के साथ जोड़ा गया । उद्यमों का रूपान्तरण होने के बाद ही पूँजीवादी तत्वों को पता चला कि पूँजीवादी प्रबन्धन तथा नियन्त्रण में कितनी बुराइयाँ थीं । और केवल सैद्धांतिक पुनः संस्कार ही एकमात्र ऐसा उपाय था, जो उन्हें शोषण के विचारों का परित्याग करने को तैयार कर सकता था, उन्हें शोषकों से मेहनतकशों में बदल सकता था, तथा उन्हें उद्यमों के रूपान्तरण में सक्रियता से जुटने को प्रेरित कर सकता था, और इस प्रकार भविष्य में राष्ट्रीयकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सकता था ।

श्रमिक वर्ग द्वारा पूँजीपति वर्ग के साथ दीर्घकालिक संयुक्त मोर्चे की स्थापना, जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बढ़ते सुदृढ़ीकरण, तथा पार्टी द्वारा कदम-दर-कदम रूपान्तरण तथा उद्यमों को खरीदने की नीति अपनाये जाने के फलस्वरूप, सामान्य घटना-क्रम शान्तिपूर्ण ढंग से रूपान्तरण को स्वीकार करने वाले राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हक में था ।

जनवरी 1956 से, देश में पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के समाजवादी रूपान्तरण का आन्दोलन आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा । कुछ ही महीनों में देशभर के बड़े तथा मध्यम दर्जे के शहरों के सभी निजी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यम, संयुक्त राजकीय-निजी उद्यमों में बदल गए तथा इन क्षेत्रों में सभी हस्तशिल्पों ने सहकारी समितियाँ स्थापित कर लीं ।

इस प्रकार, देहात में कृषि के समाजवादी रूपान्तरण में उभार से देश के 91 प्रतिशत से ज्यादा किसान परिवार 'कृषि उत्पादकों की सहकारी समिमियों' में शामिल हो गए थे । पूँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य एवं निजी हस्तशिल्पों के समाजवादी रूपान्तरण के ज्वार से, बड़े तथा मध्यम आकार के शहरों में सभी निजी उद्योग तथा वाणिज्य, संयुक्त राजकीय-निजी स्वामित्व के अधीन कर दिए गए थे तथा सभी निजी हस्तशिल्पों को 'उत्पादकों की सहकारी समितियों' में संघटित कर दिया गया था ।

इन जबरदस्त सफलताओं का अभिप्राय यह था कि लघु-कृषक अर्थव्यवस्था के विलुप्त होने से पूँजीवाद का आधार केवल देहात में ही नहीं खिसका था, बल्कि शहरों में भी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी । खास तौर से उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में समाजवादी क्रांति देशभर में पूरी कर ली गई थी । इस प्रकार शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा पूँजीवाद को खत्म करने की क्रान्ति सम्पन्न हुई । यह महान योगदान इस बात का प्रमाण था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शान्तिपूर्ण रूपान्तरण के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त को शानदार तरीके

से लागू किया था ।

आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रान्ति की बुनियादी विजय का अर्थ यह नहीं था कि यह क्रान्ति संपूर्ण हो गई थी । और इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं था कि वर्ग-संघर्ष समाप्त हो गया था । समाजवादी क्रान्ति, इतिहास में अत्यधिक गहन तथा दूरगामी क्रांति होती है; राजनीतिक, आर्थिक तथा सैद्धांतिक दृष्टि से यह अत्यधिक संपूर्ण क्रान्ति (thoroughgoing revolution) होती है । स्वामित्व की प्रणाली में बदलाव से पूँजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के बीच का वर्ग-संघर्ष खत्म नहीं हुआ था । इन दो मार्गों के बीच का संघर्ष—समाजवाद बनाम पूँजीवाद—एक दीर्घकालीन संघर्ष है । यही वजह है कि, आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति पूरी होने के अलावा राजनीतिक तथा सैद्धांतिक मोर्चों पर भी समाजवादी क्रांति की संपूर्ण विजय सुनिश्चित करना अनिवार्य था ताकि समाजवादी प्रणाली सुदृढ़ हो सके तथा समाजवादी क्रांति की संपूर्ण विजय हो सके । समस्त संक्रमणकाल के दौरान पार्टी का यह एक ऐतिहासिक मिशन है । ●

नोट

1. चीनी लोक गणराज्य के निर्वाचन-कानून में राज-सत्ता के प्रारंभिक स्तर, टाउनशिपों, कस्बे म्युनिसिपल जिलों तथा उन नगरपालिकाओं में, जिन्हें जिलों में नहीं बांटा गया है—प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है, तथा काउंटी के स्तर से ऊपर के स्तर के लिए, अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है ।

2. **पुराने मध्यम किसान :-** ये वे किसान हैं जो कृषि-सुधार से पहले मध्यम किसान थे । नए मध्यम किसान वे हैं, जो कृषि-सुधार के उपरान्त मध्यम किसान के स्तर तक ऊपर उठ गए हैं ।

●●●

तालिका - 6

पाँचवें दशक के उत्तरार्द्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक ढाँचा

सातवीं केन्द्रीय समिति	– 44 सदस्य तथा 33 वैकल्पिक सदस्य
राजनीतिक ब्यूरो	– माओ त्से-तुङ, चू तेह, ल्यू शाओ-ची, रन पी-श, चओ एन-लाई, छन युन, काङ शङ, लिन पो-छ्वी, (1949 में फङ छन, तुङ फी-ऊ व काओ काङ भी शामिल किये गए)
सचिवालय	– माओ त्से-तुङ, चू तेह, ल्यू शाओ ची, चओ एन-लाई, रन पी-श (1950 में रन पी-श की मृत्योपरान्त छन-युन)

केन्द्रीय समिति के प्रमुख विभाग

फौजी कमीशन (Military Affairs Committee)	
अध्यक्ष	– माओ त्से-तुङ
उपाध्यक्ष	– चू तेह तथा चओ एन लाई
सदस्य	– फङ त-ह्वाए, ल्यू पो-छङ, हो लुङ, लिन प्याओ, ये च्येन-इङ तथा छन ई
कार्य समिति (Work Committee)	
(मार्च 1947-मई 1948)	– ल्यू शाओ-ची
संगठन—निर्देशक	– फङ छन
उप-निर्देशक	– आन ची वन (An Tzu-wen)
सलाहकार	– ल्यू शाओ-ची तथा रन पी-श
प्रचार विभाग	
निर्देशक	– लू थिङ-ई
उप निर्देशक	– श्वी त-ली, छन पो-ता, हू श्याओ-मू तथा वाङ च्या-श्याङ
प्रेस	– माओ त्से-तुङ
सामाजिक मामले	– काङ शङ (लगभग 1950 के बाद ली खओ-नुङ)
कार्यकर्ता शिक्षा विभाग	– ल्यू शाओ-ची
संयुक्त मोर्चा मामले	– ली वेइ-हान (सलाहकार—चओ एन-लाई)
वित्त एवं अर्थ विभाग	– ली फू-चुन
युवा विभाग	– फङ वन-पिन
महिला विभाग	– छाए चाङ
शहरी विभाग	– काङ शङ
अल्पसंख्यक विभाग	– छन युन
भूमि-सुधार (किसान विभाग)	– ल्यू शाओ-ची
क्षेत्रीय ब्यूरो	
उत्तर-पूर्वी चीन	– फङ छन (1945-46), लिन प्याओ (1946-49), काओ काङ (1949-54)
उत्तरी चीन	– पो ई-पो
उत्तर-पश्चिमी चीन	– शी चुङ-शुन
मध्य चीन	– तुङ पी-वेइ
पूर्वी चीन	– राओ श्वी-श
मध्य-दक्षिणी चीन	– लिन प्याओ

[स्रोत (तालिका 2, 3 व 6) : **Long March to Power by James Pinckney Harrison, Praeger Publishers, USA, 1972.**]

तालिका - 1

(1921 से 1949 के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या)

वर्ष	सदस्य संख्या	वर्ष	सदस्य संख्या
1921 (प्रथम कांग्रेस)	57	1934	300,000
1922 (दूसरी कांग्रेस)	123	1937	40,000
1923 (तीसरी कांग्रेस)	342	1940	800,000
1925 (चौथी कांग्रेस)	980	1941	763,447
1925 (नवंबर)	10,000	1942	736,151
1926 (जुलाई)	30,000	1944	853,420
1927 (अप्रैल)	57,963	1945 (अप्रैल)	12,11,128
1927 (उत्तरार्द्ध)	10,000	1946	13,48,320
1928	40,000	1947	27,59,456
1930	122,318	1948	30,65,533
1933	300,000	1949	45,00,000

(स्रोत : एडगर स्नो की पुस्तक 'दि अदर साइड ऑफ रिवर', न्यूयार्क–1961, पृष्ठ-344-45)

तालिका - 2

(पाँचवीं कांग्रेस के समय कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक ढाँचा, अप्रैल-मई, 1927)

केन्द्रीय समिति - 29 सदस्य तथा 11 वैकल्पिक सदस्य

राजनीतिक ब्यूरो - छन तू श्यू, छ्वी छ्यू पाए, छाए हो-सन, चाङ क्वो-थाओ, चओ एन-लाई, ली ली-सान, थान फिङ-शान, ली वेइ-हान, सू चाओ-छङ

महासचिव - छन तू-श्यू (7 अगस्त, 1927 के बाद छ्वी छ्यू पाए)

केन्द्रीय समिति के विभिन्न विभागों के इन्चार्ज -

संगठन - छन तू श्यू
प्रचार - छाए हो-सन (पहले फङ सू-च)
फौजी मामले - चओ एन-लाई
श्रम विभाग - सू चाओ-छङ
महिला विभाग - श्याङ चिङ-य्वी (श्रीमती छाए हो-सन)
किसान विभाग - छ्वी छ्यू-पाए (पहले माओ त्से-तुङ)

तालिका - 3

(छठी कांग्रेस के बाद पार्टी संगठन का ढाँचा, जून-1920)

केन्द्रीय समिति - 23 सदस्य तथा 13 वैकल्पिक सदस्य

राजनीतिक ब्यूरो - श्याङ छुङ-फा, ली ली-सान, छ्वी छ्यू-पाए, चओ एन-लाई, छाए हो-सन, चाङ क्वो-थाओ तथा श्याङ इङ ।

केन्द्रीय समिति के प्रमुख विभागों के इन्चार्ज

प्रचार विभाग - ली ली-सान
संगठन - ली वेइ-हान
फौजी मामले - चओ एन-लाई
विशेष मामले (बाद में सामाजिक मामले) - चओ एन-लाई (बाद में कू शुन-चाङ)
महिला विभाग - तङ इङ-चओ (श्रीमती चओ एन-लाई)
श्रम विभाग - श्याङ इङ
किसान विभाग - फङ पाए (अगस्त-1929 से लो ची-य्वान)

तालिका - 4

(आठवीं राह सेना व नई चौथी सेना का सांगठनिक ढाँचा)

आठवीं राह सेना

मुख्यालय - येनान
कमांडर - चू तेह
उप कमांडर - फङ त-ह्वाए
चीफ ऑफ स्टाफ - ये च्येन-इङ
राजनीतिक विभाग के निर्देशक - वाङ च्या-श्याङ (रन पी-श 1937-38)

115वीं डिवीजन (भूतपूर्व-पहली मोर्चा सेना)

कमांडर - लिन प्याओ
उप कमांडर - न्ये रुङ-छन
राजनीतिक कमिसार - लो रुङ-ह्वान
343वीं ब्रिगेड - छन क्वाङ
344वीं ब्रिगेड - श्वी हाए-तुङ

120वीं डिवीजन (भूतपूर्व-दूसरी मोर्चा सेना)

कमांडर - हो लुङ
उप कमांडर - श्याओ खओ
राजनीतिक कमिसार - क्वान श्याङ-इङ
358वीं ब्रिगेड - श्याओ खओ
359वीं ब्रिगेड - वाङ छन

129वीं डिवीजन (भूतपूर्व चौथी मोर्चा सेना)

कमांडर - ल्यू पो-छङ
उप कमांडर - श्वी श्याङ-च्येन
राजनीतिक कमिसार - तङ श्याओ-फिङ
385वीं ब्रिगेड - श्वी श्याङ-च्येन
386वीं ब्रिगेड - छन कङ

नई चौथी सेना

कमांडर - ये थिङ (1941 से छन ई)
उप कमांडर - श्याङ इङ (1941 से चाङ युन-ई)
राजनीतिक विभाग के निर्देशक - य्वान क्वो फिङ (1941 से तङ ची-ह्वेइ)
राजनीतिक कमिसार - श्याङ इङ (1941 से ल्यू शाओ-ची)

तालिका - 5

(तीसरे गृहयुद्ध के दौरान के दौरान जन-मुक्ति सेना के विस्तार का ब्यौरा)

	जून, 1946	जून, 1947	जून, 1948	जून, 1949	जून, 1950
नियमित सैनिक	6,12,000	10,00,000	14,90,000	21,00,000	—
छापामार	6,65,000	9,50,000	13,10,000	19,00,000	—
कुल योग	12,77,000	19,50,000	28,00,000	40,00,000	50,00,000

स्रोत :- Gittings, Role, PP.60, 205, 304 and Mao, SW (Peking Ed.), Vol. - IV, PP-145,272

चीन का राजनैतिक मानचित्र

अध्याय । पृ० 183 से 344 तक ।

'नव जनवाद के बारे में' – पृ० 223, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें—विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा प्रकाशित, 'माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-2' का उपरोक्त शीर्षक अध्याय । पृ० 601 से 685 तक ।

नव-जनवादी क्रान्ति – अर्ध-सामंती, अर्ध-औपनिवेशिक देशों में या अर्ध-सामंती, औपनिवेशिक देशों में सर्वहारा के नेतृत्व में और चार वर्गों—मजदूर, किसान, निम्न-पूँजीपति और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग —के अधिनायकत्व में, सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाली क्रान्ति ।

नौजवान पार्टी - यह कुछ निर्लज्ज फासीवादी राजनितिज्ञों की पार्टी थी । इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत-संघ के विरोध को अपना प्रतिक्रान्तिकारी पेशा बना लिया था तथा ये सत्तारूढ़ प्रतिक्रियावादी गुटों और साम्राज्यवादियों से वित्तीय मदद लेते थे ।

पहाड़ी दुर्ग प्रवृत्ति – पृ० 256

प्रान्तीय संविधान – पृ० 43

पाओ-च्या प्रणाली – पृ० 221 तथा 233

पाओनुङ प्रणाली – पृ० 69

पाँच मई के संविधान का मस्विदा – पृ० 297

पाँच शक्तियाँ – पृ० 298

पुराने मध्यम किसान – पृ० 390

पूर्वी हपे कम्युनिस्ट विरोधी स्वायत्त-शासन - जापान के उकसावे से 25 नवम्बर, 1935 को क्वोमिंताङ गद्दार इन रू-कङ ने पूर्वी हपे की 22 काउन्टियों में ''पूर्वी हपे कम्युनिस्ट-विरोधी स्वायत्त-शासन'' के नाम से एक कठपुतली सत्ता की स्थापना की थी । यह ''पूर्वी हपे की घटना'' के नाम से जानी जाती है ।

पैट्रिक जे० हरले - पैट्रिक जे० हरले अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी का एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिज्ञ था, जिसे 1944 के अन्त में चीन में अमरीकी राजदूत नियुक्त किया गया था । च्याङ काई-शेक की कम्युनिस्ट-विरोधी नीति का समर्थन करने की वजह से उसे चीनी जनता के दृढ़ विरोध का सामना करना पड़ा और नवम्बर 1945 में मजबूर होकर त्यागपत्र देना पड़ा । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग न करने की घोषणा हरले ने 2 अप्रैल 1945 को वाशिंगटन में अमरीकी विदेश विभाग के प्रेस सम्मेलन में की थी। इस घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए 'माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-3' में ''हरले और च्याङ के युगल-अभिनय की टांय-टांय फिस'' शीर्षक लेख देखिए ।

पोट्सडम घोषणा – पृ० 280

फङ पाए – पृ० 69

फङ च्वी-शाङ—फङ च्वी-श्याङ फङश्थेन गुट का युद्ध-सरदार था । 1926 के सितम्बर में क्रान्तिकारी उत्तरी अभियान सेना के ऊहान पहुंचने पर, उसने स्वेच्वान प्रान्त में अपनी कमान के सैन्य-दल सहित उत्तरी युद्ध-सरदारों के गुट से अपने सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा कर दी और क्रान्ति की पांतों में शिरकत की । 1927 के प्रारम्भ में उसकी सेना उत्तरी अभियान सेना से तालमेल कायम करके हनान पर हमला करने के लिए शेनशी से आगे बढ़ी । 1927 में च्याङ काई-शेक और वाङ चिङ-वेइ द्वारा क्रान्ति के साथ गद्दारी किए जाने पर यद्यपि फङ च्वी-श्याङ ने कम्युनिस्ट-विरोधी कार्यवाहियों में हिस्सा लिया, तो भी उसके तथा च्याङ काई-शेक गुट के बीच हितों का टकराव हमेशा बना रहा । 19 सितम्बर, 1931 को जापान द्वारा चीन पर हमला होने पर वह प्रतिरोध का पक्षपोषक था और मई 1933 में उसने चाङच्याखओ में जनता की जापान-विरोधी संश्रयबद्ध सेना के निर्माण में कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग किया । च्याङ काई-शेक और जापानी आक्रमणकारियों के दबाव के फलस्वरूप अगस्त में उसके प्रयास निष्फल हो गए । अपनी जिन्दगी के अन्तिम वर्षों में वह कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग के दृष्टिबिन्दु पर कायम रहा ।

फन – पृ० 23

फाङ च मिन – पृ० 139

मन्चूक्वो – जापान द्वारा उत्तर-पूर्वी चीन में स्थापित कठपुतली राज्य ।

मन्चूरिया – पृ० 23

मा चान-शान - मा चान-शान क्वोमिन्ताङ की उत्तर-पूर्वी सेना का एक अफसर था जिसका सैन्य-दल हेलुङच्याङ में तैनात था । 18 सितम्बर की घटना के बाद ल्याओनिङ से हेलुङच्याङ की ओर बढ़ने वाले जापानी आक्रमणकारियों से उसने तथा उसके सैनिकों ने लोहा लिया ।

मिली जुली सरकार के बारे में – पृ० 267, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें—विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा प्रकाशित, 'माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-3' का उपरोक्त शीर्षक अध्याय । पृ० 365 से 492

मुहिमें

''कुतरने'' की मुहिम – पृ० 254
''गाँव तलाशी'' मुहिम – पृ० 254
दूसरी कम्युनिस्ट विरोधी मुहिम – दक्षिणी आनह्वेइ कांड
दोष-निवारण मुहिम – पृ० 239
पहली कम्युनिस्ट विरोधी मुहिम – पृ० 222
पेकिङ-थ्येनचिन मुहिम – पृ० 330, 331 तथा 348
ल्याओशी-शनयाङ मुहिम – पृ० 330, 331 तथा 348
''सफाया'' मुहिम – पृ० 253
ह्वाए-हाए मुहिम – पृ० 330, 331 तथा 348

मौत से न डरने वाली जापान-विरोधी पलटन – पृ० 222 तथा 233

भूमिधर-किसान – पृ० 69

य्वान श-खाए – पृ० 22

याङ हू-छङ - जनरल याङ हू-छङ चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक फौजी नेता थे, जिन्होंने चाङ श्वे-ल्याङ के साथ मिलकर शीआन घटना का सूत्रपात किया । इसलिए शीआन घटना के इन दो सूत्रधारों के नाम मिलकर साधारण बोलचाल में ''चाङ-याङ'' हो गए । जब च्याङ काई-शेक को रिहा किया गया, तो चाङ ने उसे नानकिङ पहुंचाया; लेकिन चाङ को तुरन्त नजरबन्द कर दिया गया । अप्रैल 1937 में याङ को भी क्वोमिन्ताङ प्रतिक्रियावादियों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया और उन्हें मजबूर होकर विदेश जाना पड़ा । जब प्रतिरोध-युद्ध आरम्भ हुआ, तो अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए याङ चीन लौट आए । लेकिन च्याङ काई-शेक ने उन्हें शेष जीवन के लिए जेल में डाल दिया । सितम्बर 1949 में जब जन-मुक्ति सेना छुङकिङ के पास पहुंच रही थी, तो च्याङ ने वहां उन्हें एक नजरबन्दी कैम्प में मरवा डाला ।

यासूजी ओकामूरा - यासूजी ओकामूरा उन जापानी युद्ध-अपराधियों में से एक था जिनका चीन के खिलाफ आक्रमण के अपराधों का सबसे लम्बा और घृणित इतिहास था । 1925 से लेकर 1927 तक उसने एक उत्तरी युद्ध-सरदार सुन छ्वान-फाङ के फौजी सलाहकार के रूप में काम किया । 1928 में जब जापानी फौजों ने चीनान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, तो उसने इस युद्ध में जापान की पैदल फौज की एक रेजीमेन्ट के कमान्डिंग अफसर की हैसियत से हिस्सा लिया । वह चीनान कत्लेआम का एक जल्लाद था । 1932 में उसने जापानी अभियान सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया, जिसने शंघाई पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया । 1933 में उसने देशद्रोही क्वोमिन्ताङ सरकार के साथ हुए ''थाङकू समझौते'' पर जापान सरकार की तरफ से दस्तखत किए । 1937 से लेकर 1945 तक, वह क्रमशः जापान की 11वीं फौजी कोर, उत्तरी चीन मोर्चा सेना और छठी मोर्चा सेना का कमाण्डर तथा चीन में जापानी अभियान सेना का कमाण्डर-इन-चीफ रहा । उसने चीन में ''सब कुछ जला डालने, सबको मार डालने और सब कुछ लूट लेने'' की अत्यन्त बर्बरतापूर्ण नीति को लागू किया । अगस्त 1945 में येनान

नागरिक सेना – पृ० 252

सुदूरपूर्व का म्यूनिख – पृ० 220

सुन छ्वान-फाङ - सुन छ्वान-फाङ एक युद्ध-सरदार था जिसका शासन पाँच प्रान्तों—च्याङसू, चच्याङ, फूच्येन, च्याङशी और आनह्वेइ—में फैला हुआ था । वह शंघाई के मजदूरों के विद्रोहों के खूनी दमन के लिए जिम्मेदार था । 1926 की सर्दियों में उसकी मुख्य सैन्य-शक्ति को उत्तरी अभियान सेना ने च्याङशी प्रान्त के नानछाङ और च्योच्याङ में तहस-नहस कर दिया ।

सू चाओ-चङ – पृ० 69

श्याङ – पृ० 139

श्या तओ-इन – पृ० 138

शरद फसल विद्रोह - सुप्रसिद्ध शरद-फसल विद्रोह, जिसका नेतृत्व कामरेड माओ त्से-तुङ ने किया, हुनान-च्याङशी सीमान्त क्षेत्र की श्यूश्वेइ, फिङश्याङ, फिङच्याङ और ल्यूयाङ काउन्टियों की जनता की सशस्त्र शक्तियों ने सितम्बर 1927 में किया था । उन्होंने मजदूर-किसानों की क्रान्तिकारी सेना की पहली फौजी कोर की पहली डिवीजन की स्थापना की । कामरेड माओ त्से-तुङ इस सेना का नेतृत्व करके उसे चिङकाङशान पहाड़ों में ले गए, और वहां उन्होंने हुनान-च्याङशी सीमान्त क्रान्तिकारी आधार-क्षेत्र की स्थापना की ।

शाम्येन - शाम्येन क्वाङचओ शहर का एक भाग है, जिसे बरतानवी साम्राज्यवादियों ने पट्टे पर लिया था । जुलाई 1924 में वहां के बरतानवी साम्राज्यवादी अधिकारियों ने यह नया पुलिस आदेश निकाला कि उस इलाके में आते-जाते समय सभी चीनियों को पास दिखाने होंगे, जिनमें उनके फोटो भी लगे होंगे। किन्तु विदेशी वहां स्वच्छंदता से आ-जा सकते थे । इस अयुक्तिसंगत नियम के विरुद्ध शाम्येन के मजदूरों ने 15 जुलाई से हड़ताल कर दी । अन्त में बरतानवी साम्राज्यवादियों को विवश होकर इस आदेश को रद्द करना पड़ा ।

शिक्षार्थी प्रणाली – पृ० 22

हू हान-मिन - हू हान-मिन क्वोमिन्ताङ का एक कुख्यात राजनीतिज्ञ था, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग करने की सुन यात-सेन की नीति का विरोधी था और 12 अप्रैल, 1927 को च्याङ काई-शेक द्वारा किए गए प्रतिक्रान्तिकारी राजविप्लव में उसका सह-अपराधी था । बाद में सत्ता की छीना-झपटी में उसका च्याङ काई-शेक से संघर्ष हो गया और च्याङ काई-शेक ने उसे नजरबन्द करा दिया । 18 सितम्बर की घटना के बाद रिहा होने पर वह नानकिङ छोड़कर क्वाङचओ चला गया, जहां उसने क्वाङतुङ और क्वाङशी के युद्ध-सरदारों को काफी लम्बे अरसे तक च्याङ काई-शेक की नानकिङ सरकार के विरुद्ध भड़काए रखा ।

हो इङ-छिन - हो इङ-छिन एक क्वोमिन्ताङ युद्ध-सरदार था और क्वोमिन्ताङ के जापान-परस्त गुट का दूसरा सरगना था । शीआन घटना के समय उसने गृहयुद्ध छेड़ने के लिए बड़ी सक्रियता से एक षड्यंत्र रचा । लुङहाए रेलमार्ग से होकर शेनशी पर हमला करने के लिए उसने क्वोमिन्ताङ सेना को बटोरा। च्याङ काई-शेक की जगह लेने की इच्छा से उसने शीआन पर बमबारी करके च्याङ को वहां मार डालने की योजना भी बनाई थी ।

श्रम अनुबंध प्रणाली – पृ० 22

श्रेणी दृष्टिकोण (Guild Outlook) – 16वीं सदी में एक ही व्यवसाय से जुड़े लोगों की संस्थाओं को गिल्ड (Guild) कहा जाता था । तथा ऐसी संस्थाओं का दृष्टिकोण सिर्फ अपने व्यवसाय तथा अपने लोगों की भलाई तक सीमित होता था । वर्गीय दृष्टिकोण की तुलना में यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है।

श्रेणी-समाजवाद – इस तरह के समाजवाद की 19वीं सदी में पैरवी की जाती थी । इसके अनुसार उद्योग का स्वामित्व राज्य के हाथ में तथा प्रबन्धन मजदूरों की परिषद के हाथ में होना चाहिये । यह भी एक प्रकार का संकीर्णतावाद था ।

●●●

बनाने की सम्भावना पैदा हो गई । 1935 में अबीसीनिया पर अपने आक्रमण के बाद इटली भी लीग आफ नेशन्स से अलग हो गया ।

राष्ट्रीय मुक्ति का दस-सूत्री कार्यक्रम – पृ० 207 तथा 232

लम्बा अभियान – पृ० 162

ली ता-चाओ – पृ० 23

लूतिङ पुल – पृ० 165

लू शुन – पृ० 23

"वामपंथी" मुहिमजोई – पृ० 138

वाङ चिङ-वेइ - वाङ चिङ-वेइ क्वामिंताङ के जापान-परस्त गुट का सरगना था । 1931 से वाङ चिङ-वेइ जापानी साम्राज्यवादियों के आक्रमण के प्रति सुलह-समझौते का रुख अपनाता आ रहा था। दिसम्बर 1938 में उसने छुङकिङ छोड़ दिया, खुलेआम जापानी हमलावरों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा नानकिङ में एक कठपुतली सरकार कायम की ।

संधियाँ

चीन-अमरीका मैत्री, वाणिज्य व जहाजरानी संधि – विस्तृत जानकारी हेतु पढें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4, विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976, के **'चीनी क्रान्ति के नए ऊँचे उभार का स्वागत'** शीर्षक अध्याय का पाँचवां नोट । पृ० 200-201

मैत्री, संश्रय तथा परस्पर सहयोग की चीन-सोवियत संधि – पृ० 350

समझौते

चार शक्ति – पृ० 198

हो उमेजू – पृ० 179 तथा 195

समाजवादी पार्टी (जनवादी समाजवादी पार्टी) - "जनवादी समाजवादी पार्टी" अगस्त 1946 में "जनवादी संवैधानिक पार्टी" और "राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी" को आपस में मिलाकर बनाई गई थी । इसके सदस्य मुख्य रूप से उत्तरी युद्ध-सरदारों के जमाने के प्रतिक्रियावादी राजनीतिबाज और सामन्ती समाज के अवशेष थे ।

संवैधानिक सरकार – पृ० 298

सशस्त्र कार्य-दल – पृ० 248, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें—'Behind the Enemy Lines' —विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ द्वारा प्रकाशित पुस्तक ।

सामूहिक सौदाकारी (सामूहिक सौदेबाजी) – मजदूरों द्वारा अपनी माँगों के लिए सामूहिक स्तर पर की जाने वाली समझौता-वार्ता । ट्रेड यूनियनों या अन्य संगठनों के माध्यम से सामूहिक रूप से की जाने वाली समझौता-वार्ताएं ।

सिद्धान्तकार कौन हैं – पृ० 240

सी०सी०गुट – पृ० 171

सेनाएं

आठवीं राह सेना – पृ० 202 तथा 394

उत्तरपूर्वी जापान-विरोधी संश्रयबद्ध सेना – पृ० 194

उन्नीसवीं राह सेना - देखें छाए थिङ-खाए

कोरियाई क्रान्तिकारी जन सेना – पृ० 194

चीन की राष्ट्रीय मुक्ति का हरावल दस्ता – पृ० 196

जनमुक्ति सेना – पृ० 280

नई चौथी सेना – पृ० 202 तथा 394

में प्रकाशित जापानी युद्ध-अपराधियों की सूची में उसका नाम पहले नम्बर पर था । जन-मुक्ति युद्ध के दौरान वह च्याङ काई-शेक का खुफिया फौजी सलाहकार था और उसने मुक्त क्षेत्रों पर च्याङ के हमलों की योजना बनाई थी । जनवरी 1949 में उसे प्रतिक्रियावादी क्वोमिंताङ सरकार द्वारा निरपराध करार दिया गया तथा रिहा कर दिया गया और वह जापान वापस लौट गया । 1950 में उसने च्याङ काई-शेक के अनुरोध पर तथाकथित क्रान्तिकारी व्यवहार अनुसन्धान प्रतिष्ठान के सीनियर ट्रेनिंग अफसर का पद मंजूर कर लिया । 1955 में उसने जापानी थलसेना व नौसेना के भूतपूर्व सैनिकों को संगठित करके एक "सहयोद्धा संघ" (जिसे बाद में सेवा-निवृत्त सहयोद्धा संघ के नाम से पुकारा जाने लगा) बनाया और जापानी सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने के लिए चलाई जाने वाली प्रतिक्रियावादी गतिविधियों में बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की ।

युद्ध

1894 का चीन-जापान युद्ध – पृ० 21

अफीम युद्ध - पृ० 20

ई हो थ्वान युद्ध - ई हो थ्वान युद्ध 1900 में चीन के उत्तरी भाग में किसानों व दस्तकारों द्वारा छेड़ा गया एक स्वत:स्फूर्त विशाल आन्दोलन था, जिसमें किसानों व दस्तकारों ने अपनी रहस्यपूर्ण गुप्त संस्थाओं का निर्माण करके साम्राज्यवादियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलाया । लेकिन आठ साम्राज्यवादी ताकतों की संयुक्त सेनाओं ने पेकिङ व थ्येनचिन पर कब्जा करके इस आन्दोलन को अकथनीय बर्बरता के साथ कुचल दिया।

रन पी-श - कामरेड रन पी-श चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध सदस्यों और उसके प्राथमिक संगठनकर्ताओं में से एक थे । वे 1927 में आयोजित पार्टी की पांचवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के समय से ही पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे । 1931 में उन्हें छठी केन्द्रीय कमेटी के चौथे पूर्ण अधिवेशन में राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य चुन लिया गया । 1933 में वे हुनान-च्याङशी सीमान्त क्षेत्र की प्रान्तीय पार्टी-कमेटी के सचिव और साथ ही लाल सेना के छठे सेना-ग्रुप के राजनीतिक कमिसार भी थे । जब छठे सेना-ग्रुप तथा दूसरे सेना-ग्रुप को मिला दिया गया और उन्होंने दूसरी मोर्चा-सेना का रूप ले लिया, तो कामरेड रन पी-श को उसका राजनीतिक कमिसार नियुक्त कर दिया गया । जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के प्रथम वर्षों में वे आठवीं रांह सेना के राजनीतिक विभाग के प्रधान निर्देशक रहे । 1940 में वे पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सचिवालय में काम करने लगे । 1945 में पार्टी की सातवीं केन्द्रीय समिति के प्रथम पूर्ण अधिवेशन में उन्हें फिर राजनीतिक ब्यूरो और सचिवालय का सदस्य चुन लिया गया । 27 अक्तूबर 1950 को कामरेड रन पी-श का पेकिङ में देहान्त हो गया ।

राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन – विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें—माओ त्से-तुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ-4', विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह पेकिङ, पहला संस्करण-1976, के "च्याङ काई-शेक के आक्रमण को चकनाचूर कर डालो" शीर्षक अध्याय का दूसरा नोट । पृ० 141 से 147 तक ।

राजनीति विज्ञान ग्रुप – पृ० 232

राज्यक्षेत्रातीत अधिकार – पृ० 69

राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) - लीग आफ नेशन्स एक ऐसा संगठन था जिसे प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बरतानिया, फ्रांस, जापान तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों ने सौदेबाजी के जरिए दुनिया का नए सिरे से बंटवारा करने और अपने बीच के अन्तर्विरोधों को कुछ समय के लिए पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से गठित किया था । 1931 में जापानी साम्राज्यवादियों ने चीन के उत्तर-पूर्व पर अधिकार कर लिया और 1933 में जापान ने लीग आफ नेशन्स को छोड़ दिया, ताकि वह ज्यादा सुविधा से अपने आक्रमण का विस्तार कर सके। उसी वर्ष जर्मन फासीवादी सत्तारूढ़ हो गए और वे भी लीग आफ नेशन्स से अलग हो गए, ताकि वे आक्रमणकारी युद्ध की तैयारियां सुविधापूर्वक कर सकें । 1934 में जब फासीवादी आक्रमणकारी युद्ध का खतरा बढ़ रहा था, सोवियत संघ लीग आफ नेशन्स में शामिल हुआ । इस प्रकार दुनिया का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए बने इस साम्राज्यवादी संगठन को विश्वशान्ति के हितों की सेवा करने योग्य संगठन

(पृष्ठ क्रमांक : 406 से जारी)

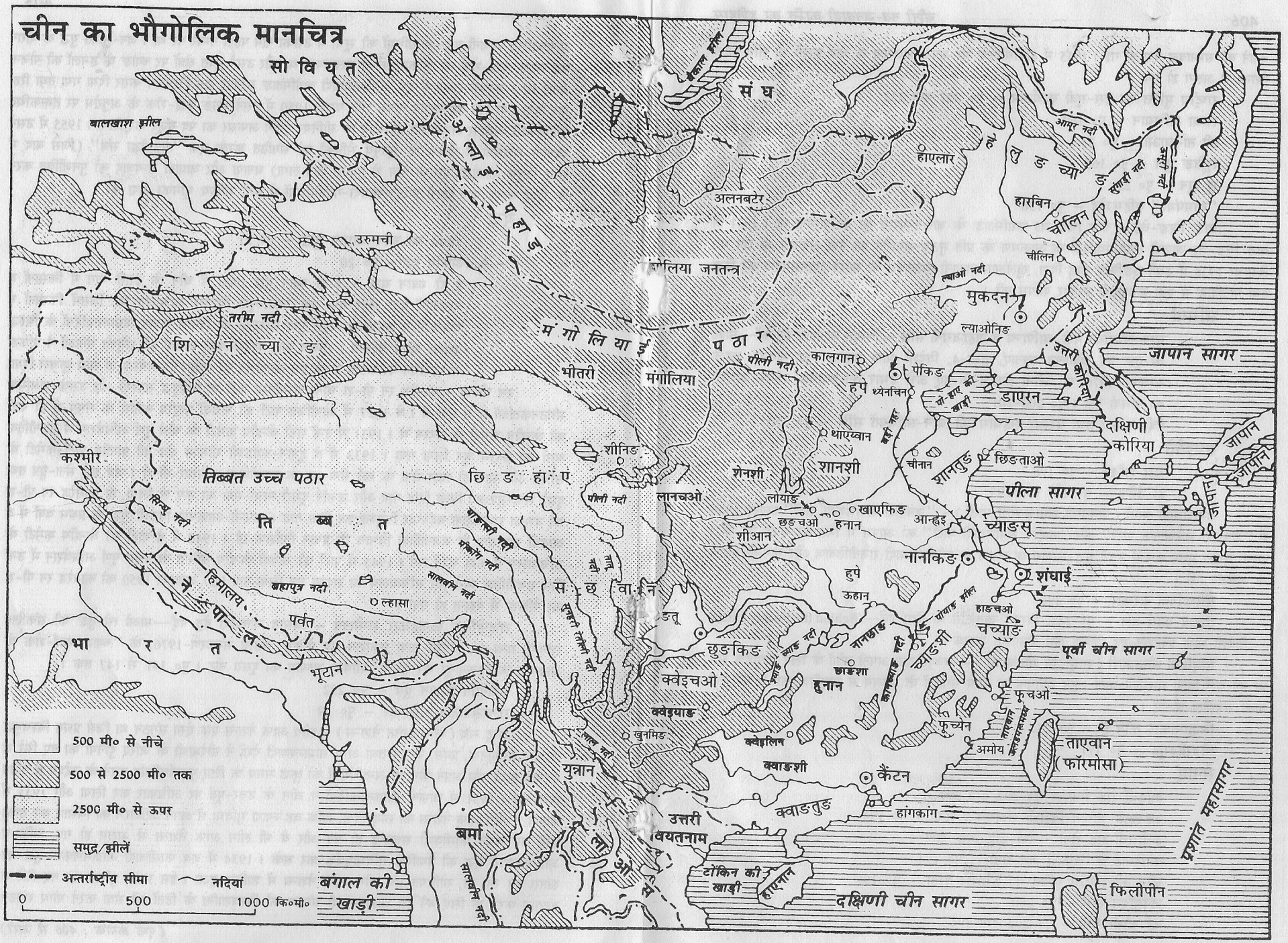

चीन का भौगोलिक मानचित्र